वैश्विक कूटनीति

(रचनाकार से साक्षात्कार)

लेखक व संपादक : सिद्धेश्वर

वैश्विक कूटनीति
सिद्धेश्वर

वैश्विक कूटनीति

(रचनाकार से साक्षात्कार)

सिद्धेश्वर

प्रकाशक
सरदार पटेल साहित्य प्रकाशन
दिल्ली- 92

वैश्विक कूटनीति

(रचनाकार से साक्षात्कार)

रचनाकार	:	सिद्धेश्वर
प्रकाशक	:	सरदार पटेल साहित्य प्रकाशन 'दृष्टि', यू-207 शकरपुर, विकास मार्ग, दिल्ली-110092 दूरभाष-011-22530652 मो. 9811281443
c	:	प्रकाशक
प्रथम संस्करण	:	वर्ष 2018
शब्द संयोजन	:	अमित कुमार, सुशीला सदन, रोड नं.-17, राजीव नगर, पटना
छायांकन	:	डॉ. शाहिद जमील, सी-84, बैंक रोड, मस्जिद के नजदीक, पटना-1
मुद्रक	:	लोकवाणी प्रिंटिंग प्रेस, पटना 29, शशि पैलेस, नाला रोड, पटना मो॰: 9801772460
पृष्ठ	:	304
मूल्य	:	आठ सौ रुपए मात्र (Rs Eight Hundred Only)

VAISHVIK KUTNEETI

Rachnakar Se Sakkshatkar: Prashnottar

Edited By Sidheshwar

Rs-800/

सिद्धेश्वर : एक नज़र

पूरा नाम : सिद्धेश्वर प्रसाद
संक्षिप्त नाम : सिद्धेश्वर
पिता का नाम : स्व. इन्द्रदेव प्रसाद
माता का नाम : स्व. फूलझार प्रसाद
पत्नी का नाम : श्रीमति बच्ची प्रसाद
जन्म तिथि : 18 मई, 1941
जन्म स्थान : ग्राम+पत्र.-बसनियावाँ, भाया-हरनौत, जिला-नालंदा, बिहार(भारत)
शैक्षिक योग्यता : सन् 1962 में पटना विश्वविद्यालय से श्रम एवं समाज कल्याण विषय में स्नातकोत्तर
तकनीकी शिक्षा : सन् 1973 में भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग से एस.ए.एस. (Subordinate Accounts Service)
सरकारी सेवा : भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय महालेखाकार, राँची एवं पटना में लेखा परीक्षक से प्रोन्नति प्राप्त करते हुए वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर छतीस वर्षो तक सेवा प्रदान करने के पश्चात् सन् 2000 के 31 मई से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर वृहतर एवं व्यापक समाज व राष्ट्रहित में सार्वजनिक जीवन में प्रवेश।
सार्वजनिक सेवा : 1.भारतीय रेलवे के रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य
2. बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त अध्यक्ष पद पर 15 सितंबर, 2008 से 14 सितंबर, 2011 तक कार्यरत।
अभिरुचि : समाज व साहित्य सेवा तथा पत्रकारिता, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए संघर्षशील तथा रचनात्मक लेखन से जुड़ाव।
रचनाएँ प्रकाशित :1.सामाजिक-'आरक्षण','कल हमारा है', 'समता के सपने', 'आत्ममंथन', बिहार के कुर्मी (निबंध संग्रह) एवं बिहार के कुर्मी (निर्देशिका)
2.स्मृति-'यादें'(भोला प्र. सिंह 'तोमर' की स्मृति में)
3.हाइकु काव्य संग्रह-'पतझड़ की सांझ', 'सुर नहीं सुरीले', 'कवि और कविता'

4. सेन्र्यु काव्य संग्रह-'जागरण के स्वर', 'बुजुर्गो की जिंदगी'
5. काव्य संग्रह-'यह सच है'
6. जीवनी- 'एक स्वप्नद्रष्टा की अंतर्कथा',
'डॉ. मोहन सिंह: एक तपस्वी मन'
7. शैक्षिक-'समकालीन यथार्थबोध' एवं 'समकालीन संपादकीय'

जीवनी-साहित्य : 1.'सिद्धेश्वर:व्यक्तित्व और विचार'-प्रो. रामबुझावन सिंह
2.'सिद्धेश्वर:अंकों से अक्षर तक' डॉ. ब्रह्मचारी सुरेन्द्र कुमार

रचनाएँ प्रकाश्य:साक्षात्कार-1.'हिंदी के जीवंत हस्ताक्षर', डॉ. बलराम तिवारी द्वारा संपादित
2. 'इंसानियत की धुँआती आँखें'
3. 'राष्ट्रीय राजनीति'
4. 'उम्मीद जताते न्यायिक एवं आर्थिक फैसले'
5.'वैश्विक कूटनीति'

राजनीति : 'आम आदमी की आवाज'
आत्मकथा-'जीवन रागिनी' तथा हाइकु में 'मेरी जीवन-यात्रा'
संस्मरण-1.'हमें अलविदा ना कहे' 2.'जो जीवित हैं हमारे जेहन में'
संपादन- 'राष्ट्रीयता के विविध आयाम' दो भाग में

सम्मान : देश के विभिन्न सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संगठनों द्वारा पुरस्कृत एवं सम्मानित।

विदेश यात्रा : 13-15 जुलाई, 2007 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन में बिहार सरकार की ओर से भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल होकर सम्मेलन के शैक्षिक सत्र में 'वैश्वीकरण, मीडिया और हिंदी' विषय पर आलेख पाठ एवं परिचर्या में सक्रिय भागीदारी।

संप्रति : राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय विचार मंच, दिल्ली
संस्थापक संपादक, 'विचार दृष्टि', दिल्ली

संपर्क : 'दृष्टि', यू. 207, शकरपुर, विकास मार्ग, दिल्ली-92
दूरभाष: 011-22530652, मो.-9431037221
'संस्कृति' ए-164, पार्क रोड, ए.जी. कॉलोनी, शेखपुरा,
पत्रा.-आशियाना नगर, पटना-800025,
मो.-9431037221, मो.-9472243949

अनुक्रम

पृष्ठ

सिद्धेश्वर : एक नजर..3
अनुक्रम..5
समर्पण..6
प्राक्कथन 7
अभिमत 1. महेन्द्र प्रसाद सिन्हा..22
2. डॉ.(प्रो.) एल. एन. शर्मा..26
शुभाशंसा 1. डॉ. साधु शरण..30
2. डॉ. लखन लाल सिंह 'आरोही'..33

प्रथम अध्याय

वैश्विक प्रश्नोत्तर..37

द्वितीय अध्याय

प्रष्टाओं का परिचय

	पृष्ठ		पृष्ठ
(1)डॉ. एल. एन शर्मा	297	(2)डॉ. साधु शरण	297
(3)डॉ. मधु वर्मा	298	(4)श्री नरेन्द्रपति तिवारी	298
(5)श्री उपेन्द्रनाथ सागर	299	(6)श्री विजय कुमार सिंह	299
(7)श्री मदन कुमार	300	(8)श्री शिव बालक प्रसाद	300
(9)श्री लखन सिंह	300	(10)श्री मुरारी प्रसाद सिंह	301
(11)श्री राजवंश सिंह	301	(12)डॉ. शाहिद जमील	301
(13)श्री उमेश्वर प्रसाद सिंह	302	(14)डॉ. गोपाल शरण सिंह	302
(15)श्री सुरेश कुमार सिन्हा	302	(16)डॉ. अमर सिंह वधान	303
(17)प्रो. राज चतुर्वेदी	303	(18)श्री मनोज कुमार	303
(19)पल्लवी सिंह चौहान	304	(20)श्री पंचशील जैन	304

समर्पण

भारत की विदेश मंत्री माननीया सुषमा स्वराज, जिन्होंने पुरुषों की
भीड़ में कई देशों के अपने समकक्षों के साथ सफल बैठक
कर आतंकवाद व द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की
और कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचारों का अच्छा
आदान-प्रदान किया, जिन्होंने विदेश नीति और सुरक्षा
चुनौतियों से निपटने में उल्लेखनीय कौशल,
कल्पनाशीलता और अपनी व्यक्तिगत छाप
छोड़ते हुए प्रभावशाली साबित हुईं और
युद्ध की बात करके डरा-धमका रहे
चीन की धौंसबाजी का जवाब
संयम का परिचय देते हुए
कूटनीति से दिया,
जिनके अथक प्रयास से आतंकवाद के सवाल पर पाकिस्तान
को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग कर दिया और
जिनकी व्यक्तिगत ईमानदारी और वक्तृत्वकला पर
खासतौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के पटल पर
किसी को शक नहीं और जिन्होंने विश्व
में भारत की साख को मजबूत बनाने
का काम किया, को सहृदयता से
यह कृति सादर समर्पित।

(सिद्धेश्वर)

प्राक्कथन

अंतरराष्ट्रीय समुदाय अपने-अपने देश के साथ आर्थिक, व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों को लेकर असमंजस में बने रहते हैं। सभी देशों की सरकार के नीति-नियंताओं को कूटनीतिक कार्रवाई की ओर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र के कुल 193 देशों में से अधिकांश देशों में इधर हाल के वर्षों में घटित घटनाओं खासतौर पर भारत-पाक के बीच संबंधों में आई खटास से संबंधित मुझसे साक्षात्कार के दौरान प्रबुद्धजनों के द्वारा मेरे समक्ष प्रस्तुत 230 प्रश्नों के दो टूक जवाब हमने बड़े सलीके से देने का प्रयास किया है, ताकि उनकी जिज्ञासाएँ पूरी हो सकें। आतंकवाद की जननी पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर को लेकर निरंतर आतंकियों की हैवानियत के बाद भारतीय सैनिकों के लक्षित हमले (सर्जिकल स्ट्राइक) के पूर्व और बाद की घटनाओं पर पूछे गए प्रश्नोत्तर देने में हमने अपनी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान-साधना के अनुसार कोई कोर-कसर नहीं उठा रखी है।

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विगत ढाई-तीन वर्षो में तकरीबन साठ-सत्तर देशों की यात्रा के दौरान अपनी कूटनीतिक चाल से प्रायः सभी देशों का ध्यान खींचने में सफलता हासिल की है जिसका नतीजा है कि पाकिस्तान आज प्रायः सभी देशों से अलग-थलग पड़ गया। संयुक्त राष्ट्र पर हावी औपनिवेशिक मानसिकता पर मैंने अपने उत्तर में पी-5 यानी परमानेंट-5 के पाँच देशों- अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चीन जिनके पास वीटो पावर है संयुक्त राष्ट्र की 1945 में हुई स्थापना के वक्त से ही वे उसकी सुरक्षा परिषद् के स्थाई सदस्य बने हुए हैं और उनका 'वीटो पावर' इनकी दबंगई का ब्रह्मास्त्र है। इसके आगे बाकी 188 संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के सारे हथियार बेकार हो जाते हैं।

राजनीतिक और वैश्विक प्रसंगों के वर्तमान संदर्भो के अनुरूप मैंने प्रस्तुत पुस्तक में संग्रहित प्रष्टाओं के 230 प्रश्नों के उत्तर में व्याख्या की है जिसमें राजनीतिक और वैश्विक कूटनीति से जुड़ी जिज्ञासाओं के सवाल-जवाब सहज अंदाज में प्रस्तुत करने की मैंने कोशिश की है।

भारत सरकार ने इधर दो-ढाई सालों में अपनी विदेश नीति पर मुख्य ध्यान देना शुरू किया या यूँ कहें कि देश की जनता का ध्यान खींचना

शुरू किया है। भारत के प्रधानमंत्रियों ने हमेशा विदेशी दौरे किए, पर नरेन्द्र मोदी ने जब न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया, तो उन्होंने भारत की विदेश नीति में एक नया आयाम जोड़ दिया। चाहे अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्रिटेन, वह विदेशों में रहने वाले भारतीयों को संबोधित करने का कोई मौका नहीं चुके। इसके पीछे एक बड़ी सोच भारत के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने की रही जहाँ विश्व के अन्य देश भारत को अगली उभरती विश्व शक्ति के रूप में पहचानना शुरू करें। भारत ने विगत दो वर्षो में पशिचम एशिया की नीति पर बड़ी मेहनत की है, जिसका सफल परिणाम आने वाले वर्षो में दिखेगा। चाहे वह अरब खाड़ी क़े देशों से पूँजी निवेश लाने की बात हों या फिर पाकिस्तान को अलग-थलग करने की रणनीति। भारत की एक्ट मिडिलईस्ट नीति की कूटनीति में हमें बड़ी सफलता हाल ही में देखने को तब मिली जब सऊदी अरब ने भारत के हज कोटे में बढ़ोतरी कर भारत से जाने वाले हजयात्रियों की संख्या को बढ़ाकर 170250 कर दिया जो कि विश्व के किसी भी देश की संख्या से ज्यादा है। यह इसलिए भी सराहणीय है, क्योंकि यह कदम 30 साल बाद सऊदी अरब ने वर्तमान सरकार के आग्रह के बाद उठाया।

एक्टमिडिल ईस्ट नीति में एक सबसे महत्वपूर्ण कदम तब होगा जब भारत इस्लामिक सहयोग संस्था (ओआईसी) का पर्यवेक्षक सदस्य बने। ओआईसी एक ऐसी संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है जिसके 57 मुस्लिम देश सदस्य हैं।

मौजूदा दौर की राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक कूटनीति के बीच इस दुनिया में जहाँ बंदूकों की होड़ लगी हुई है, बम-बारूदों की बहसें जारी हैं और इस उन्माद को पोसता हुआ विश्वास फैला है, जरूरत है एक ऐसी आवाज की जो हमारे अंदर की सर्वोच्च को संबोधित हो, जो हमें खुशियों से बात कर सके और हमारे संदेहों और हमारे भय से बात कर सके। हमने उत्तर में अपने विचारों के साथ-साथ जनता की भावनाओं और राष्ट्र के विरूद्ध किए जा रहे गंभीरतम अपराध और षड्यंत्र को बेहतरीन तरीके से रेखांकित करने का प्रयास किया है।

जब हमारी नजर अफगानिस्तान की ओर जाती है, तो हम पाते हैं कि अफगानिस्तान लंबे अरसे से क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों की राजनीति का शतरंज बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर रूस एक तिकड़ी बना रहा है जो भारत के लिए चिंता का सबब है, कारण कि उसे

कठिन समय में दोस्ती निभाए रूस के नए रूख के साथ मित्रता बनाए रखने का जतन करते कूटनीतिक संगति बिठानी पड़ रही है।

दरअसल, रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान और भारत के अफगानिस्तान में अपने सामरिक आर्थिक हित हैं। इसलिए वे उसपर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहते हैं। रूस को भय है कि ईराक और सीरिया के बाद आईएसआईएस अफगानिस्तान में घूसपैठ का मंसूबा मास्को के लिए खतरा है। इसलिए वह अफगानिस्तान में सक्रिय तालिबान को उसके दुश्मन आईएसआईएस से भिड़ाना चाहता है। यह लोहे से लोहे को काटने की पुरानी तरकीब है।

अपने देश के हित के अनुरूप करने में भारत सरकार का प्रयास अद्भूत है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। बची-खुची कसर नरेन्द्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर से देश की स्वतंत्रता के 71वें दिवस के अवसर पर बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान और सिंध की चर्चा कर पूरी कर दी जिससे पाक को विश्वास हो चुका है कि पाक अधिकृत कश्मीर तो हाथ से निकल ही रहा है, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान और सिंध को संभालना भी अब कठिन हो चुका है। इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी कूटनीति में सफल रहे हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कूटनीति में विफल, क्योंकि वह विश्व में पाकिस्तान को अलग-थलग होने से बचा न सके। दूसरी ओर भारत में कुछ नेता व बुद्धिजीवी सनकी लोग हैं, क्योंकि वे अपनी मनमानी करने के लिए छल-प्रपंच, अनाप-सनाप भरे दुष्प्रचार और भारत के बाहरी शत्रुओं से साठ-गांठ करने से भी नहीं हिचकते। उनका काम है केवल मोदी-विरोध अभियान चलाना। ऐसी बौद्धिकता देश के लिए खतरनाक है। यह देश के लिए दुःखद शैक्षिक-वैचारिक परिदृश्य सूचक है कि बुद्धिजीवी ही अँधविश्वास में डूबे हैं। हमें इस हानिकारक प्रवृत्ति से मुक्त होने की जरूरत है। हमें इसे सरकार पर न छोड़कर समाज को ही आवाज उठानी चाहिए और इसकी पहल करनी चाहिए, क्योंकि यह वैचारिक भ्रष्टाचार है, जो आर्थिक भ्रष्टाचार से कहीं अधिक घातक है। इसे समझना और उपाय ढूँढ़कर पहल करना हम सजग नागरिकों का दायित्व बनता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर बनाने के जो प्रयास किए, उससे उम्मीद जगी थी, लेकिन पठानकोट और उड़ी में हमले कर पाकिस्तान ने उस पर पानी फेर दिया। भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों की दृष्टि से उक्त घटनाक्रम खतरनाक मोड़ का संकेत देता है। दरअसल, पाकिस्तान की शर्त यही है कि

वह भारत का विरोध करे। यह उसकी ग्रंथि है। वह इससे उबर नहीं सका है और न ही निकट भविष्य में उबर पाएगा। कारण उसकी आंतरिक स्थिति बहुत ही खराब है। अपनी आंतरिक स्थिति से ध्यान हटाने के लिए वह भारत का हौवा खड़ा करता रहता है।

बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती ताकत, भारत सरकार की सफल कूटनीति ने आर्थिक हितों की पूर्ति और शक्ति-संतुलन बिठाने के लिए अमेरिका को भारत के निकट आने को विवश करने का काफी हद तक श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इसलिए जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने नेतृत्व के दम पर वैश्विक क्षितिज पर भारत की साख को मजबूती दी है। 20 जनवरी, 2017 को जब से अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे समय में अमेरिका का कमान संभाला है जब नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत भी वैश्विक कूटनीति में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं और उसे इसमें कामयाबी भी मिल रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता की दावेदारी के साथ खुद को एक जिम्मेदार नाभिकीय शक्ति के रूप में उभारकर भारत विश्व समुदाय में एक ऐसी छवि निर्मित कर रहा है कि उसे एक महाशक्ति के रूप में देखा जाए। भारत का ध्यान तेजी से प्रगति करते एशियाई महाद्वीप में चीन की चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करने पर है।

मौजूदा समय में दुनिया जिन बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है उनमें आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती है। इस आतंकवाद की जड़ें मुस्लिमों की कट्टरता में निहित हैं। ट्रंप ने इसको लेकर कड़े बयान दिए हैं। भले ही वह इन बयानों को लेकर मीडिया और अमेरिकी समाज के एक वर्ग की ओर आलोचना का शिकार हुए हों, लेकिन यह एक सच्चाई है कि आतंकवाद अमेरिका और भारत सहित पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे वक्त भारत की अपेक्षा होगी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान के प्रति नीर-क्षीर रूख अपनाएँ और पाकिस्तान स्थित उन आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करें, जो भारत के लिए खतरा बने हुए हैं। ट्रंप की सफलता काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगी कि वह राष्ट्रपति के रूप में राजनीतिक परिपक्वता का प्रदर्शन कर पाते हैं या नहीं। अपनी आक्रामक शैली और बेबाक विचारों से उन्होंने प्रचार में तो बढ़त हासिल कर ली, लेकिन दुनिया के सर्वशक्तिशाली देश के एक सर्वोच्च पद पर रहते हुए उन्हें जिम्मेदारी भरा बर्ताव करना होगा।

यह बात किसी से छिपी नहीं है कि पिछले कई दशक से भारत के लोग और हमारी सेना के जवान पाक जैसे देश के झूठ, धोखाधड़ी और हिंसा के शिकार होते रहे हैं, जिसकी दुनिया में ख्याति यही है कि वह आतंकवाद का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी उसने इसी को भुनाने की कोशिश की है। दुनिया के सबसे बड़े और खूँखार आतंकवादी की जड़ें पाकिस्तान में ही मिलती हैं। वह सरगना चाहे अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल का हत्यारा हो, न्यूयॉर्क के विश्व व्यापार केंद्र (वर्ल्ड ट्रेड सेंटर) के जुड़वा टावर पर हमला करवाने वाला मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन हो, जैश-ए-मोहम्मद का संस्थापक अजहर मसूद हो या भारत का ही कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम या लश्कर-ए-तय्यबा का हाफिज सईद हो। ये मुट्ठी भर आतंकी ही आतंकवाद के कुख्यात सुपरस्टार हैं। सारे के सारे पाकिस्तान की उर्बर भूमि में पाले, पोसे और बढ़ाए गए। इसके बाद भी भारत और यहाँ के लोग पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने के पहले सैकड़ों बार सोचते हैं, बहस करते हैं।

कहना नहीं होगा कि पाकिस्तान शत्रुदेश नहीं है, बल्कि आतंकी देश है, जिसके आतंकी गुर्गो ने भारत में घुसपैठ करके विश्व इतिहास के जघन्यतम आतंकी हमलों को अंजाम दिया है और हमेशा समाधान निकालने की बजाय पीठ में छूरा घोंपने और आतंकी करतूतें करने का रास्ता चुना है इसने उसके द्वारा प्रायोजित पत्थर फेंकने वाले लोगों की सेना खड़ी कर दी है जो हिंसा पर उतारू हो जाते हैं।

आखिर तभी तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रति सख्त रूख अपना लिया है। अभी-अभी विगत 28 फरवरी, 2017 को अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए ट्रंप ने जहाँ एक ओर कंसास की शूटिंग घटना में मारे गए भारतीय अभियंता श्रीनिवास कुचीमोटला की हत्या और उसके एक साथी आलोक मदसानी को बुरी तरह घायल करने की घटना पर गहन शोक प्रकट किया और अमेरिकी काँग्रेस में श्रीनिवास के लिए एक मिनट का मौन भी रखा गया, वहीं ट्रंप ने अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता पर जोर दिया। यही नहीं उन्होंने अपने को शांति और एकता का पक्षधर बताते हुए कहा कि अमेरिका का राष्ट्रपति होने के नाते उनके लिए अमेरिकी पहले हैं और वे ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि अमेरिकी कंपनियाँ अपना कच्चा माल अमेरिका से ही खरीदें, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरह प्रतिभा आधारित आव्रजन नीति अपनाएगा।

यह तो भारतीय व्यवसाय विशेषज्ञ, इंजीनियर, चिकित्सक के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि इसे वे अपने कौशल का इस्तेमाल अमेरिकी जरूरतों और भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग को ऊँचाई देने के लिए कर रहे हैं।

जहाँ तक पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते का सवाल है उससे हमें उसी की भाषा में बात करनी होगी जो वह समझता है। भारत को मसूद अजहर, दाउद इब्राहिम और हाफिज सईद तथा आईएसआई के कर्ताधर्ता जैसों को छद्म तरीकों से निशाना बनाना होगा और पाक सेना को उलझाए रखना होगा। संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर बलूचों के लिए आवाज उठाने से पाक फौज की भारत के मामले में टांग अड़ाने की क्षमता कम होगी। भारत द्वारा सिंधु जल संधि के पूरे प्रावधानों का उपयोग करने के इरादे से ही पाक घबरा गया है। यह करके दिखाना होगा।

इसी प्रकार वैश्विक आतंक से रिश्ता, बलूचिस्तान व अधिकृत कश्मीर में मानवाधिकार की स्थिति, पाक में अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति यह सब जोर-शोर से उठाए तो पाक बचाव की मुद्रा में होगा। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब आदि को आतंकवाद के हमारे दृष्टिकोण पर सहमत कराकर पाक के इस्लामी कार्ड की धार भोथरी कर दी है। यह हमें बड़े पैमाने पर और करना होगा।

पड़ोसी देश चीन को संकेत देना होगा कि हम दक्षिण चीन सागर विवाद, तिब्बतियों को सक्रिय समर्थन, भारतीय बाजार में चीनी सामान जैसे मुद्दों पर उसे तकलीफ दे सकते हैं। जापान से मजबूत रिश्ते कायम कर चीन पर दबाव बना सकते हैं। जापान से एक ओर जहाँ हमें तकनीक और पूँजी मिलेगी, वहीं दूसरी ओर जापान को भारतीय बाजार मिलेगा। जिस प्रकार पड़ोसी देश बांग्लादेश और श्रीलंका का भरोसा हमने जीता है, उसी प्रकार अफगानिस्तान और नेपाल को भी और करीब लाना होगा। हमारे खिलाफ साजिशों की पाक से कीमत वसूलनी होगी। शायद यही एकमात्र भाषा पाक समझता है।

भारत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के केंद्र में सत्ता संभालने के बाद वैश्विक हालात ऐसे बने कि पड़ोसी देश पाकिस्तान को भारत के खिलाफ आतंकियों के इस्तेमालवाली रणनीति की समीक्षा के लिए मजबूर होना पड़ा है। लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा के प्रमुखों पर पाकिस्तान ने जिस प्रकार शिकंजा कसा है उससे प्रथमदृष्टया ऐसा लगता है कि वैचारिक और व्यावहारिक रूप से भारत और पाकिस्तान एक ही दिशा में कदम बढ़ा रहे

हैं। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस्लामी देशों से आने वाले गैर-अमेरिकी नागरिकों पर प्रतिबंध लगाने के फरमान के बाद पाकिस्तान हाफिज सईद को नजरबंद करने पर मजबूर हुआ है, फिर भी भारत को अभी भी फूँक-फूँक कर कदम बढ़ाना होगा।

लोहा गरम हो तो चोट ज्यादा प्रभावी होती है। भारत की आक्रामकता और विश्व समुदाय की सख्ती से पाकिस्तान तक यह संदेश पहुँच चुका है कि अगर वह आतंकवाद को पोषित करना बंद नहीं करता तो दुनिया में वह अलग-थलग पड़ जाएगा। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि चीन को आर्थिक गलियारे और अपने उत्तर पश्चिमी मुस्लिम प्रांत शिनजियांग पर पाक आतंकियों से खतरा लग रहा है। लिहाजा वह भी पाक के आतंकियों से लेकर कट्टरपंथी राजनीतिक दलों की ओर अपना रूख सख्त करेगा। नतीजतन अमेरिका और चीन के दबाव में पाकिस्तान भारत के प्रति अपने रवैए और रणनीति को बदलने के लिए मजबूर होगा। चीन के नए सेनाध्यक्ष को भी अब लगने लगा है कि यदि भारत के साथ तनाव दूर करना है तो लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा के खिलाफ कार्रवाई करनी ही होगी। अब जब पाकिस्तान ही हाफिज को अपना दुश्मन मानने लगा है तो संयुक्त राष्ट्र में हाफिज आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर बार-बार वीटो देने वाले चीन को अब कोई जवाब नहीं सूझ रहा है।

अंत में मै कहना चाहूँगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा नीति वाक्य कहता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस नीति पर अमल जारी है। तमाम देश अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस नीति पर आँख मूँद कर भरोसा करते हैं। इसी नीति का एक व्यापक रूप यह है कि अगर दुश्मन का दुश्मन खुद का भी दुश्मन हुआ और ज्यादा खतरनाक हुआ तो क्या करेंगे? निःसंदेह तब पहले दुश्मन को दोस्त बनाना ही समझदारी होगी। आज की वैश्विक कूटनीति और जरूरत इस सिद्धांत को अपनाने पर जोर देती है। इसी के चलते दो विपरीत विचारधारा के राष्ट्र समाज एक ही मकसद को पूरा करने के लिए साथ आ जाते हैं। भले ही दो देशों के द्विपक्षीय संबंध गड़बड़ हों, लेकिन व्यापक हित में एक साझे दुश्मन से लड़ने के लिए वे एक साथ खड़े हो जाते हैं। दुनिया के इतिहास में सोवियत संघ और अमेरिका, अमेरिका और जापान, जर्मनी और फ्रांस जैसे कई ऐसे उदाहरण हैं जो साझे मनोरथ के लिए अपने बीच की दुश्मनी को परे करके एक-दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। यही है वैश्विक कूटनीति के जरिए ऐसे

साधनों को विकसित करने की राह जिनसे उन्हें शक्ति संघर्षों में सफलता हासिल हो सके।

वैश्विक कूटनीति के मामलों में कभी-कभी कठोर रवैया अपनाना समय का तकाजा होता है। यह सर्वथा उचित है कि मोदी सरकार जैसी दृढ़ता अन्य अनेक मोर्चो पर प्रदर्शित कर रही है वैसी ही विदेश नीति के मामले में भी दिखा रही है। यह बदलते भारत का एक और संकेत है। यह आज की आवश्यकता है कि चीन और अमेरिका के साथ ही पूरी दुनिया को यह संदेश जाए कि वह दौर बीत गया जब भारत अपने हितों की रक्षा को लेकर नरम-मुलायम स्वर में बात करता था। जिस तरह अमेरिका को यह संदेश देना आवश्यक था कि वह कश्मीर के मामले में बीच-बचाव करने की अपनी इच्छा अपने पास रखे उसी तरह चीन को भी यह बताना जरूरी था कि अरुणाचल प्रदेश पर उसकी व्यर्थ की दलीलों को कोई भाव नहीं मिलने वाला और यदि वह गैर-जरूरी टिका-टिप्पणी करते रहता है तो उसे उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। इसी प्रकार कश्मीर पर अमेरिका के दशकों पुराने रूख में आए बदलाव को देखते हुए भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि गुलाम कश्मीर और गिलगिट-बाल्टिस्तान समेत पूरा कश्मीर हमारा है। इनमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। यह किसी को सोचना भी नहीं चाहिए कि भारत अपने किसी हिस्से को यूं ही जाने देगा।

इसी प्रकार चीन से मिल रहे कूटनीतिक संकेत बहुत उत्साहित करने वाले नहीं हैं। चाहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर की आतंकी साबित करने के प्रस्ताव पर चीन का अड़ंगा हो या परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी में भारत के प्रवेश में पैदा किए जाने वाले अवरोध, चीन की इन कुटिल चालों से भारत में उसकी नकारात्मक छवि ही बनी है। भारत को यही लगा कि अमेरिका के साथ बढ़ती उसकी सामरिक साझेदारी और जापान एवं वियतनाम से गलबहियाँ बढ़ाने की कोशिशों को लेकर चीन की चिंताओं की परिणति इन कदमों के रूप में देखने को मिली है।

इसके मद्देनजर मुझे नहीं लगता कि भारत को चीन से राजनीतिक-कूटनीतिक विकल्प से इतर किसी अन्य प्रतिक्रिया की अपेक्षा करनी चाहिए। समझदारी का तकाजा तो यही है कि कुछ ऐसा न किया जाए जिससे हालात खराब हों, क्योंकि चीन द्वारा सैन्य पलटवार की आशंका हमेशा बनी रहती है, लेकिन उसके निहितार्थ और अंतिम परिणाम पर निश्चित ही गौर करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य के बिना रणनीति से कुछ हासिल नहीं होता।

चीन अपनी सामरिक-रणनीतिक व्यवहारिकता के लिए मशहूर है। उसे यह अवश्य ही समझना चाहिए कि दलाई लामा का अरुणाचल प्रदेश का दौरा या और कहीं का, चीन को चिढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अरुणाचल के लोगों को संदेश देने के लिए है। यह महज नजरिए का फरक है।

इधर हाल में सीरियाई गृह युद्ध की वर्तमान स्थिति में अमेरिका और रूस जिस तरह से आमने-सामने आ गए हैं उससे निकट भविष्य में भारत के लिए दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसी प्रकार डेडिकेटेड एयर फ्रेट कॉरिडोर अफगानिस्तान के लिए व्यापार हेतु एक अवसर और एक नई पहल है तथा भारत के लिए एक कूटनीतिक उपलब्धि भी। लेकिन क्या पाकिस्तान और चीन इस पहल को सफल होने देंगे? कुछ समय पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने अमेरिकी काँग्रेस से कहा था कि पाकिस्तान नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान में भारत का प्रभाव बढ़े।

मेरा मानना है कि मोदी सरकार के कार्यकाल का तीन वर्ष गुजरने के बाद हर कोई कम से कम एक बात पर जरूर सहमत होगा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय कूटनीति और वैश्विक कूटनीति ने परंपरा से हटने का भरपूर माद्दा दिखाया है और इनकी सरकार ने अगर सर्जिकल स्ट्राइक कर तथा वन बेल्ट वन रोड (ओबीओआर) सम्मेलन का बहिष्कार कर यह साबित किया है कि वह राष्ट्रीय हितों के मुद्दों को नए नजरिए से देख रही है। दुनिया के नक्शे में इस देश को चमकाने के लिए बतौर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीन वर्षो के अपने कार्यकाल में 57 विदेश यात्राएँ कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कई ऐसे देशों की यात्राएँ भी कीं जहाँ का रूख अरसे से किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। कूटनीतिक मसलों में उनकी सूझबूझ मंजे हुए राजनीति की छाप छोड़ती है। वह पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिसने 2015 में ब्रिटेन यात्रा के दौरान वहाँ की संसद को संबोधित किया और उनके भाषण से अँग्रेज इतने प्रभावित हुए कि खड़े होकर तालियाँ बजाने लगे। साठ वर्षो में पहली बार अक्टूबर, 2016 में उन्होंने आयरलैंड की यात्रा की। इसी प्रकार 2015 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चीन और रूस से घिरे मंगोलिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हुए। 34 वर्षो बाद 2015 में किसी भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पड़ोसी देश भूटान को विदेश दौरे के लिए चूना और यह दौरा बेहद अहम इसलिए था, क्योंकि इससे पहले के प्रधानमंत्रियों ने भूटान को नजरअंदाज किया जिससे उसका झुकाव चीन की तरफ हो रहा था।

सच तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विदेश नीति को लेकर एक ही एजेंडा 'इंडिया फर्स्ट' पर जोर रहा। दरअसल, पुरानी मित्रता में नए रंग भरना मोदी सरकार की अभी तक की कूटनीति की एक विशेष खासियत रही। इस प्रकार निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इन तीन सालों में विदेश नीति और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में उल्लेखनीय कौशल, कल्पनाशीलता और अपनी व्यक्तिगत छाप छोड़ी है। निश्चित रूप से विदेश नीति के मोर्चे पर नरेन्द्र मोदी सरकार का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। हालांकि यह बात सरकार के आलोचकों के गले नहीं उतरेगी, लेकिन आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, तो आपको महसूस होगा कि तीन साल पहले नई दिल्ली के बारे में बनी धारणा अब काफी हद तक बदली है। नरेन्द्र मोदी ने भारतीय हितों की इतनी मजबूती से पैरवी की जिसने तमाम विश्लेषकों को भी चौंकाया, क्योंकि जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तो विदेश नीति के मोर्चे पर उन्हें कुछ भी अनुभव नहीं था। फिर भी इस दौरान वैश्विक मामलों में उन्होंने भारत की पूछ बढ़ाई है और यहाँ तक कि उनके विरोधी भी उन्हें इसका श्रेय अन्दर ही अन्दर स्वीकार कर रहे हैं। भारत तो अब उन रास्तों से भी परहेज नहीं कर रहा जिनसे अतीत में बचता आया है जिसका परिणाम यही होता था कि भारत की सैन्य कार्रवाई से भी पाकिस्तान साफ इन्कार कर देता था। लंबे समय तक पाकिस्तान ही सीमा पर भारत के धैर्य की परीक्षा लेता आया है, लेकिन अब तस्वीर उलट गई है। पिछले 26 एवं 27 जून, 2017 को जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहली मुलाकात हुई तो उसके पहले ही हिजबुल आतंकी सैयद सलाहुद्दीन को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने की अमेरिका की पहल को भारत में भरपूर सराहा गया, क्योंकि इससे कश्मीर घाटी में आतंक का फन कुचलने में भारत की मुहिम को बल मिलेगा। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने माना कि अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम के अलावा जनसंहारक हथियारों से दुनिया को अस्थिर करने पर आमादा देशों और उनको शह देने वाले मुल्कों से सख्ती से निपटने की दरकार है।

विगत तीन साल से अमेरिका को खुले दिल से लुभाने की नरेन्द्र मोदी की नीति भारत में अभी भी एक सियासी जोखिम ही मानी जा रही है, मगर मेरा मानना है कि यही वह राह है जिसपर मोदी ने चलने की ठानी है। ओबामा से लेकर ट्रंप तक सफर खासा लंबा रहा है, लेकिन मोदी की सफलता इसी बात में छिपी है कि उन्होंने दोनों पक्षों की ओर से इसे

फलदायी बनाया है। इससे मंजिल और करीब आती नजर आ रही है।

इसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तेल अवीव में मुलाकात आपसी सहयोग और व्यापार की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उचित संदेश जाएगा। आजादी के बाद इन सत्तर सालों में नरेन्द्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इजरायल की यात्रा की है। रक्षा और साइबर क्षेत्र में इजरायल काफी उन्नत है। आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई में इजरायल और भारत स्वाभाविक सहयोगी साबित हो सकते हैं। इजरायल अमेरिका के बाद भारत का न केवल सबसे बड़ा रक्षा संबंधी उपकरणों का आपूर्तिकर्ता है, बल्कि इसका एक कोण पाकिस्तान और चीन की भारत विरोधी नीतियों से जुड़ता है। इजरायल ने भारत को ड्रोन विमान ही नहीं दिए हैं, बल्कि हाल में 630 करोड़ डॉलर का बराक मिसाइल सौदा किया है। प. एशिया के एकमात्र लोकतांत्रिक देश इजरायल के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस दौरे से लोकतंत्र मजबूत होगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इजरायल यात्रा भारत-इजरायल रिश्तों को सार्वजनिक करने की दिशा में एक अहम कदम है। इसे भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद एक अहम कूटनीतिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। अबतक भारत इजरायल के साथ अपने संबंधों को छुपाकर रखता आया है, ताकि अरब देशों से भारत के संबंधों पर असर न पड़े। दरअसल, मौजूदा वक्त में भारत इजरायल से सैन्य साज-सामग्री खरीदने वाला सबसे प्रमुख देश है। रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा मामले में ही नहीं, बल्कि डेयरी, सिंचाई, ऊर्जा और बहुत से तकनीकी क्षेत्रों में भी इजरायल भारत के साथ साझेदारी कर रहा है।

कहा जाता है कि इजरायल देश के साथ गहरे रिश्तों की कीमत 50 अरब मूल्यों की नाराजगी लेकर करना बहुत महंगा सौदा है, क्योंकि मध्य-पूर्व में लाखों भारतीय काम करते हैं और भारत तेल आयात के मामले में भी उनपर निर्भर है। ऐसी स्थिति में भारत अरब देशों की नाराजगी मोल नहीं ले सकता, लेकिन जहाँ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इजरायल के साथ अपने संबंधों को छुपाकर नहीं रखना चाहते थे, वहीं इजरायली प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित इसलिए थे, क्योंकि उन्हें अमेरिका के अलावा एक अन्य दोस्त की तलाश थी जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनके साथ खड़ा हो सके। ऐसे में भारत के समक्ष चुनौती संतुलन साधने की है।

भारत का कूटनीतिक दबाव विश्व की महाशक्तियों पर पड़ा है जिसका परिणाम अब साफ नजर आने लगा है। चीन पाक के बचाव में आ गया है, क्योंकि उसका कहना है कि पाक ने वैश्विक प्रयास में आतंकवाद के खिलाफ जबरदस्त कुर्बानी दी है। चीन उसका सबसे बड़ा हितैषी बना हुआ है जिसके पीछे उसकी अपनी स्वार्थपूर्ति है। इसे पूरा विश्व समझ रहा है। अब विश्व की महाशक्तियाँ आतंकवाद के मामले पर और अब पाक को छूट देने के हक में नहीं हैं। देखना यह है कि ट्रंप की चेतावनी एवं 16 अरब 26 करोड़ रुपए की मदद रोकने के बाद पाक अपनी हरकतों को रोकता है या नहीं। इस बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी पर पाक आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करता है तो कश्मीर घाटी का माहौल और बेहतर होगा। फिर भी भारत को कश्मीर घाटी में सुरक्षा को और बेहतर बनाना चाहिए।

भले ही नरेन्द्र मोदी द्वारा अबतक रिकॉर्ड विदेश दौरे की आलोचना होती रही हो, लेकिन एक बात तो तय है कि दुनिया में भारत अब किसी परिचय का मुहताज नहीं रहा है, भारत ने विकसित और विकासशील देशों के साथ जिस तालमेल के साथ आगे कदम बढ़ाया है वह न सिर्फ काबिलेतारीफ है, बल्कि बेमिसाल भी है। भारत ने जो सख्ती चीन और पाकिस्तान के साथ अपनाई है वह भी एकदम उचित है, क्योंकि ये दोनों देश भारत के हितों पर चोट पहुँचाने की कोशिश करते रहते हैं। नरेन्द्र मोदी की विदेश नीति का ही यह नतीजा है कि भारत को अमेरिका, रूस, फ्रांस समेत विश्व के अधिकांश शक्तिशाली देश आज परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों के समूह(एनएसजी) में शामिल करने के लिए एकमत दिखाई दे रहे हैं। भारत ने जो नई एवं संतुलित विदेश नीति अपनाई है वह अपने आप में साहसिक है।

दरअसल, नरेन्द्र मोदी में दुर्लभ कूटनीतिक गुण की वजह से विदेशी समकक्षों के साथ निजी रिश्तों में गर्मजोशी उनकी खास थाती बन गई है जिसके परिणामस्वरूप वह तुनकमिजाज नेताओं का भी दिल जीत सकते हैं। बेहतरीन संवाद कौशल, दूरदर्शिता और भारत को आगे ले जाने की असीम उत्कंठा उनमें प्रत्यक्ष दृष्टिगत होती है। चाहे अमेरिकी ट्रंप हों या ओबामा या रूस के पुतिन, मोदी ने सभी के साथ बेहतरीन निजी रिश्ते बनाने में सफलता हासिल की है। विगत तीन सालों के दौरान मोदी ने वैश्विक समुदाय में भारत को अग्रणी देशों की पंक्ति में लाकर खड़ा रख दिया है। हाल में अमेरिका, इजरायल और जी-20 के लिए जर्मनी की यात्रा में उन्होंने अपने कूटनयिक कौशल की छटा बिखेरी है। इजरायल के साथ प्रगाढ़ होते संबंधों में भारत को

सैन्य, कृषि, ऊर्जा, सामुद्रिक, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस में अत्याधुनिक तकनीक का लाभ मिलेगा। इससे भारत जर्मनी, अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे तकनीक समृद्ध देशों का मुकाबला कर सकता है। हाल में बढ़ी चीनी चुनौती के मद्देनजर जापान और अमेरिका के साथ चल रहा मालाबार अभ्यास भी मोदी के कूटनयिक कौशल को दर्शाते हुए इस पर मुहर लगाता है कि भारत महाशक्ति बनने की राह पर है।

अमेरिका जिस तरह भारत का समर्थन कर रहा है और इजरायल जैसे अब तक अछूते किंतु मजबूत राष्ट्र भारत की मैत्री को हाथों-हाथ लिया है, वह एक तरह से देश की वैश्विक कूटनीति की विजय दर्शा रही है। जहाँ पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पनामागेट घोटाला के आरोप में पाक के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को त्याग पत्र देने के बाद की स्थिति का सवाल है मुझे लगता है कि शरीफ की विदाई पाकिस्तान के अस्थिर राजनीतिक परिदृश्य और लड़खड़ाते लोकतंत्र को और कमजोर ही करेगी। अब इसके आसार अधिक हैं कि पाकिस्तानी सेना के जनरल लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर कर बिना किसी जवाबदेही के सत्ता का रसास्वादन करते रहेंगे।

वैश्विक समुदाय से कई दशकों से उतार-चढ़ाव का रिश्ता रखने वाला उत्तर कोरिया जल्दी ही अमेरिका तक परमाणु हमले करने की क्षमता हासिल कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की नई पाबंदियों के बाद उसने यह धमकी फिर से दी है कि अमेरिका के मित्र देशों -जापान और दक्षिण कोरिया को भी निशाना बना सकता है। उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनातनी लंबे समय से चल रही है, लेकिन पिछले एक सप्ताह यानी अगस्त 2017 के प्रथम सप्ताह से ऐसी आशंकाएँ गहन हो गई हैं कि उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच युद्ध हो सकता है, जिसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी हो सकता है। पाबंदियों पर चीन के समर्थन ने भी स्थिति को उलझा दिया है, क्योंकि मित्र देश होने के नाते वही उत्तर कोरिया पर कूटनीतिक दबाव बना सकता है, हालांकि उसने भी यह कह दिया है कि उत्तर कोरिया की कारगुजारियों के लिए अमेरिका द्वारा चीन की ओर अंगुली उठाना बेमानी है।

वैसे भी देखा जाए तो तानाशाही के बावजूद उत्तर कोरिया शेष दुनिया से कटा नहीं है। उत्तर कोरिया के 166 देशों से कूटनीतिक संबंध हैं और 47 देशों में उसके दूतावास हैं, जिससे पता चलता है कि दुनिया से वह अलग-थलग नहीं है। उत्तर कोरिया पिछले कुछ महीने से अमेरिका तक वार

करने वाली मिसाइल बनाने का दावा करता रहा है। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होता है, तो मानवता को भयावह परिणाम देखने पड़ सकते हैं।

भूटान के दावे वाले डोकलाम में भारत और चीन की सेनाओं के बीच जारी तनातनी जिस तरह से खत्म हुई वह भारतीय कूटनीति की एक बड़ी कामयाबी है। इससे न केवल भारत का अंतरराष्ट्रीय कद बढ़ेगा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की छवि एक ऐसे नेता के तौर पर और उभरेगी जो भारतीय हितों की रक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। भारत ने राजनीतिक एवं कूटनीतिक परिपक्वता का सराहणीय प्रदर्शन करने के साथ संयम और दृढ़ता का जो परिचय दिया उसके कारण ही चीन अपने मनमाने रवैए को छोड़ने के लिए विवश हुआ। मुझे विश्वास है कि भारत ने चीन पर जो कूटनीतिक जीत हासिल की उसका संदेश उसके पड़ोसी देशों के साथ-साथ अपनी समूची विश्वबिरादरी को भी जाएगा। चीन ने जिस तरह अपना चेहरा बचाते हुए अपने कदम पीछे खींचे उसका एक मनोवैज्ञानिक लाभ यह भी होगा कि भारत की आमजनता 1962 की कड़वी यादों को भूलकर आत्मविश्वास से लैस होंगी। इस सबके बावजूद चीन से सतर्क रहने में ही समझदारी है।

भारत ने चीनी अपेक्षाओं के विपरीत डोकलाम में लगातार डटे रहते हुए तथा अनावश्यक बयानबाजी से दूर रहते हुए शांतिपूर्ण ढंग से कूटनीतिक रूप से गतिरोध को सुलझाने का परिपक्व प्रयास किया जिसके परिणामस्वरूप घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तर पर चीन की छवि को काफी नुकसान पहुँचा जबकि भारतीय कूटनीति का पश्चिम सहित वैश्विक समर्थक मिला। दरअसल, डोकलाम मामले को गर्म कर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन की आंतरिक कमजोरियों को छिपाकर फिर से अगले कालावधि का राष्ट्रपति पद पाना चाहते थे, परंतु भारतीय सेना के अटल इरादों ने शी जिनपिंग के उपरोक्त योजना को ध्वस्त कर दिया। इसके पीछे कारण यह भी था कि अगले माह यानी सितंबर 2017 में चीन में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाग लेने के लिए शर्त रख दिया था कि पहले चीन डोकलाम मुद्दे को सुलझाए। इस कारण ब्रिक्स के सम्मेलन को सफल बनाने के लिए चीन के लिए यह आवश्यक हो गया था। इस बीच चीनी धमकियों को जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने सीमा पर युद्ध की तैयारी पूरी कर ली थी। सीमा पर भारतीय सेना की तैयारी ने युद्ध की बात करके डरा-धमका रहे चीन पर ही उल्टा दबाव बना दिया और भारत ने संयम कूटनीति से दिया।

इतना ही नहीं विगत सितंबर, 2017 के प्रथम सप्ताह में चीन में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के मंच से भागीदार देशों ने जिस तरह से आतंकवाद को एक मुद्दे की तरह उठाया, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीकावाले और ब्रिक्स देशों ने जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तयबा और हिजबूल मुजाहिदीन की कड़ी निंदा करके पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया कि ब्रिक्स आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है। चीन की धरती पर हुए ब्रिक्स सम्मेलन में पाक पोषित आतंक, आतंकी संगठनों की निंदा भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत है। एशिया में शक्ति संतुलन और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का यह कदम मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि चीन की जमीन से पाक को कठघरे में खड़ा करने वाली आवाज उठना साधारण बात नहीं।

अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं वैश्विक कूटनीति से संबंधित प्रष्टाओं द्वारा कुल 226 प्रश्न मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए जिनके प्रश्नोत्तर देकर उनकी जिज्ञासाओं को मैंने पूरा करने का यथासंभव प्रयास किया। मैं आभारी हूँ ऐसे सभी प्रबुद्ध प्रश्नकर्ताओं के जिन्होंने हमें वैश्विक कूटनीति जैसे विषय पर मेरे समक्ष प्रश्न प्रस्तुत कर मुझसे उत्तर की अपेक्षा की।

'संस्कृति',ए-164,ए.जी.कॉलोनी,
शेखपुरा, पटना-25
मो. 9431037221

(सिद्धेश्वर)
पूर्व अध्यक्ष
बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना
संस्थापक-संपादक, 'विचार दृष्टि', दिल्ली
राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय विचार मंच

अभिमत

प्रधानमंत्री की सूझबूझ और सफल वैदेशिक कूटनीति

□महेन्द्र प्रसाद सिन्हा

प्रस्तुत पुस्तक 'वैश्विक कूटनीति ' के रचयिता सिद्धेश्वर जी की सहजता, उनका खुलापन तथा आत्मीयता ही उनके व्यक्तित्व की विशेषता है जिसका हर कोई कायल है। स्वैच्छिक संस्थाओं तथा उसके आयोजन के प्रति लगाव व समर्पण का भाव जैसा सिद्धेश्वर जी में देखने को मिलता है वह विरले ही किसी ऐसे स्तर के व्यक्ति में होता है। इनके सरीखे बहुआयामी लेखक, जिनके लेख समसामयिक विषयों से लेकर संस्मरण तथा निबंध प्राय: हर पत्र-पत्रिका में सतत पढ़ने को मिलता है। साहित्य और संस्कृति का यह प्रतिनिधि अपनी गतिशीलता एवं कुंठामुक्त उन्मुक्त व्यवहार की वजह से अपने मित्रों, साहित्य-सेवियों, संगठनकर्ताओं एवं विद्वतजनों का विशाल इनका परिवार है। भारतीय राजनीति और वैश्विक कूटनीति पर इनकी पकड़ काफी गहरी है। भारतीय साहित्य के विलक्षण लोकयात्री सिद्धेश्वर जी अपना पूरा जीवन अपनी शर्तो पर जी रहे हैं। एक लंबे समय से राजनीति की विडंबनाओं पर अपनी कलम चलाने वाले सिद्धेश्वर जी ने जहाँ एक ओर 'आम आदमी की आवाज' नाम्नी अपनी पुस्तक में भारतीय राजनीति की मौजूदा स्थिति पर अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं, वहीं 'राष्ट्रीय राजनीति' पुस्तक में राष्ट्रीय मुद्‌दों सहित भारतीय राजनीति से जुड़ें प्रश्नों के उत्तर इन्होंने दिए हैं और साथ ही प्रस्तुत पुस्तक 'वैश्विक कूटनीति' अंतरराष्ट्रीय कूटनीति से संबंधित प्रश्नों के उत्तर से पाठकों को वैश्विक कूटनीति की अद्यतन स्थिति से लोगों को अवगत कराया है जिसे समकालीन अंतररराष्ट्रीय कूटनीति की बेतुकी और अनचाही दस्तकों, आहटों और करवटों को बड़ी शिद्‌दत से महसूस किया जा सकता है। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर के विदेशी राजनेताओं खासतौर पर पाकिस्तान, चीन आदि के राजनेताओं के फरेबी और सत्तालोलूप मुकुट और मुखौटों की दिलचस्प अदा इस पुस्तक में देखी जा सकती है। सिद्धेश्वर जी को आज भी जो सही लगता है उसे कहते हैं और लिखते हैं। वह गलत हो सकते हैं, पर बेईमान और गोटी-बिकाऊ धूर्त दरबारी

नहीं है। दरअसल, वह एक ऐसे इंसान है जिसने अबतक की जीवन-यात्रा में दुनियादारी की परवाह नहीं की और न कभी पद-प्रतिष्ठा, ऐशो आराम के पीछे भागे।

सिद्धेश्वर जी का समग्र व्यक्तित्व वास्तव में इनके अनुभवों और सोच का परिणाम है। वह अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा सीखते हैं वो सब उनके मन में संचित हो जाते हैं और वे उनके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं। उसे ही वे अपनी बुद्धि अथवा विवेक के अनुसार हर हाल में पूर्ण होते देखना चाहते हैं। उनके अंतर्मन की यही बात इनकी कृतियों सहित इनके उत्तर में दिखाई देती है। आज इनके पाठक इनके दिल की वही आवाज अथवा अंतर्मन की बात सुनना-पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि इनके ये विचार सदुपयोगी और सकारात्मक भरे होते हैं।

वैश्विक स्तर पर एक देश के साथ दूसरे देशों के जो संबंध रहे हैं उस पर तो सिद्धेश्वर जी की पैनी दृष्टि गई ही है, मगर भारत के साथ दूसरे देशों के संबंध पर इन्होंने प्रस्तुत पुस्तक 'वैश्विक कूटनीति' में खासतौर पर भारत के साथ विगत कई सालों या कहा जाए तो भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद से हो जो कूट संबंध चले आ रहे हैं उसपर इन्होंने विस्तार से चर्चा की है। चीन ने अपनी आक्रामक विस्तारवादी नीति के माध्यम से वर्चस्व स्थापित करने के लिए रणनीतिक दृष्टि बेहद महत्वपूर्ण माने जाने डोकलाम के पठार को, जो भूटान का हिस्सा है, को लेकर भारत चीन के बीच तनातनी का कूटनीतिक समाधान निकला। मनोवैज्ञानिक युद्ध के महारथी चीन को थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि उसके भारत पर लगातार युद्ध की धमकी देकर दबाव डालने की रणनीति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सूझबूझ और सफल वैदेशिक कूटनीति के चलते बेअसर रही। सिद्धेश्वर जी ने डोकलाम की इस समस्या के समाधान पर प्रस्तुत पुस्तक में जो अपने विचार व्यक्त किए हैं वे द्रष्टव्य हैं-

'भारत ने चीनी अपेक्षाओं के विपरीत डोकलाम में लगातार डटे रहते हुए तथा अनावश्यक बयानबाजी से दूर रहते हुए शांतिपूर्ण ढंग से कूटनीतिक रूप से गतिरोध को सुलझाने का परिपक्व प्रयास किया जिसके परिणामस्वरूप घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तर पर चीन की छवि को काफी नुकसान पहुँचा जबकि भारतीय कूटनीति को पश्चिम सहित वैश्विक समर्थन मिला। दरअसल, डोकलाम मामले को गर्म कर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन की आंतरिक कमजोरियों को छिपाकर फिर से अगले कालावधि का राष्ट्रपति पद

पाना चाहते थे, परंतु भारतीय सेना के अटल इरादों ने शी जिनपिंग के उपरोक्त योजना को ध्वस्त कर दिया। इसके पीछे कारण यह भी था कि अगल माह यानी सितंबर, 2017 में चीन में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाग लेने के लिए शर्त रख दिया था कि पहले चीन डोकलाम मुद्दे को सुलझाए। इस कारण ब्रिक्स के सम्मेलन को सफल बनाने के लिए चीन के लिए यह आवश्यक हो गया था।'

इस बीच चीनी धमकियों को जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने सीमा पर युद्ध की तैयारी पूरी कर ली थी। सीमा पर भारतीय सेना की पूरी तैयारी ने युद्ध की बात करके डरा-धमका रहे चीन पर ही उल्टा दबाव बना दिया और भारत ने संयम का परिचय देते हुए उसकी धौंसबाजी का जवाब कूटनीति से दिया।

सिद्धेश्वर जी की महत्ता इस बात में निहित है कि उनकी रचनाओं में साहित्यिक गहराई और मनोवैज्ञानिक बारीकियाँ इस कदर व्यक्त हुई हैं कि पाठकों के लिए वे सुलझी, सुगम और आकर्षक हैं, पेंचीली और उलझन पैदा करने वाली नहीं है। इसके अतिरिक्त इनकी कृतियों में जीवन-दर्शन का सहज आभास होता है, कारण कि कोई भी आदर्श ऊपर से चिपका दिया गया नहीं है। दरअसल, वह स्वयं आदर्श की प्रतिमूर्ति हैं। सत्यनिष्ठा तो इनमें कूट-कूट कर भरी है। यदि पैसा बटोरना ही उनका ध्येय होता, तो चिकनी-चुपड़ी बातों से शोहरत और दौलत दोनों इन्होंने बटोर ली होती, पर एक सच्चे ईमानदार लेखक की तरह इन्होंने अपनी आत्मा का सौदा नहीं किया। अपनी रूह की आवाज को दबाकर समाज के बनावटी मायालोक में रहना इन्हें कतई मंजूर नहीं है। इसलिए तो वह आज भी हर तरह के शोषण और गलत कदम का विरोध करते हुए न्याय का सशक्त पक्ष लेकर सत्ताधीशों, पूँजीपतियों, सामंतों, ढोंगी समाज-सुधारकों और पाखंडियों से सदैव लोहा लेते रहे हैं। इन्होंने न तो कभी किसी की चाटुकारिता कर अपने उठने का प्रयास किया और न ही किसी को गिराने की। हाँ, इन्होंने वहीं किया जिसे उनकी बुद्धि और विवेक ने उचित समझा।

प्रस्तुत पुस्तक के लेखक की यह विशेषता है कि न केवल ये अपने सामाजिक दायित्व के प्रति सतर्क हैं, बल्कि अपने लेखन से ये दूसरों को भी सहभागी बना लेते हैं और कुछ आदर्शों, मूल्यों और मान्यताओं को महत्व देते हैं। साक्षात्कार विधा की यह पुस्तक 'वैश्विक कूटनीति' को आँकना सहज-सुलभ कार्य नहीं है, फिर भी मेरी जानकारी की लघु सीमा में ही

आँकना संभव हो सका है। सिद्धेश्वर जी के दायरे और अनुभव में जो कुछ भी इन्होंने वैश्विक कूटनीति में देखा, समझा उसे हूबहू शब्दबद्ध करने की कोशिश की है। किसी भी इंसान की विकास-यात्रा आज की पीढ़ी के लिए खासतौर पर अंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations) विषय के विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों के लिए यह कृति उपयोगी सिद्ध होगी, क्योंकि कृतिकार ने बड़े मनोवैज्ञानिक और सहज ढंग से वैश्विक कूटनीति का विश्लेषण किया है जो अपने आप में अनूठा बन पड़ा है। इस दृष्टि से देखा जाए, तो इस कृति का साहित्य-संसार में तहेदिल से स्वागत होगा। भविष्य में स्वस्थ-प्रसन्न रहकर लेखक ऐसे कई नए कीर्तिमान स्थापित करें, यही मेरी शुभकामना है।

संपर्क:
ग्राम+पत्रा.-माहूली, पटना
रूकुनपुरा, बेली रोड,
पटना

महेन्द्र प्रसाद सिन्हा
पूर्व अधिकारी
डाक एवं तार विभाग
भारत सरकार,पटना

अभिमत

वैश्विक कूटनीति की सफलता पर उत्तरदाता की टिप्पणी अत्यंत मार्मिक और प्रासंगिक

□ प्रो.(डॉ.) एल. एन. शर्मा

दुश्मन को दोस्त बनाने की कला में माहिर भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विदेश यात्रा के मामले में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को पीछे छोड़ दिया। सोवियत संघ का झुकाव भारत की ओर था तथा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहयोगी अमेरिका था। नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका से ऐसी मित्रता की कि वह पाकिस्तान के विरूद्ध हो गया और उसकी आर्थिक सहायता रोक दी। इसी प्रकार मुस्लिम देशों की नाराजगी के बावजूद मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री को न केवल अपना दोस्त बनाया, बल्कि इजराइल के कई समझौते देशहित में किए। इन सभी घटनाओं का भाई सिद्धेश्वर बड़ी बारिकी से उत्तर देते हुए वैश्विक कूटनीति को सफल बताया है।

भारतीय लोकतंत्र में मध्य एवं निम्न वर्ग के लोगों की विवशता और अपनी अस्मिता की चिंता जिस तरह राजनैतिक हथियार बनती है यह विडंबना प्रस्तुत पुस्तक–'राष्ट्रीय राजनीति' में देखने को मिलती है। शिक्षा, रोजगार, संपत्ति, ऋण, बूढ़ों की पेंशन, बेरोजगार युवाओं का भत्ता आदि के लिए वर्तमान दौर की राजनीतिक व्यवस्था में आमजन को जो जद्दोजहद करना पड़ता है उसे बड़ी संवेदना के साथ उत्तरदाता ने अपने प्रश्नोत्तर में रेखांकित किया है। राजनैतिक विडंबनाएँ, नेताओं की स्वार्थवृत्ति और उनके चरित्र के दोहरेपन की विसंगतियाँ आमजन के जीवन को और भी त्रासद बनाती हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता के गुस्से का भी अच्छा परिणाम नहीं निकलता है। सिद्धेश्वर जी ने इसका भी खुलासा करते हुए अपने उत्तर में कहते हैं–'जनता पार्टी को भी 1977 में जनता ने आपातकाल से क्रोधित होकर ही चुना था। फिर 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी की जीत के उदाहरण भी आपके सामने हैं। इसी प्रकार लालू–राबड़ी सरकार के 15 साल के जंगलराज से जब बिहार की जनता परेशान हो गई और हर तबके में गुस्सा आना शुरू हो गया, तब यहाँ के मतदाताओं ने हर हाल में चुनाव में उन्हें पराजित करने का मन

बना लिया जिसका परिणाम यह हुआ कि चुनाव आने पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की सरकार बनी। जनता के गुस्से से उपजा कई दलों के नेताओं का मिश्रित समूह फिर नतीजे देने में नाकाम रहा। इन सभी घटनाओं से तो इसी धारणा को मजबूती मिलती है कि लोकतंत्र में जनता के गुस्से का अच्छा परिणाम नहीं निकलता है।'

जहाँ तक वैश्विक कूटनीति का सवाल है अंतरराष्ट्रीय समुदाय अपने-अपने देश के साथ आर्थिक, व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों को लेकर असमंजस में बने रहते हैं। सभी देशों की सरकार के नीति-नियंताओं को कूटनीतिक कार्रवाई की ओर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। प्रश्नकर्ताओं की ओर से संयुक्त राष्ट्र के कुल 193 देशों में से अधिकांश देशों में इधर हाल के वर्षो में घटित घटनाओं खासतौर पर भारत-पाक के बीच के संबंधों में आई खटास से संबंधित सवालों के दो टूक जवाब सिद्धेश्वर जी ने बड़े सलीके से दिये हैं। आतंकवाद की जननी पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर को लेकर निरंतर आतंकियों की हैवानियत के बाद भारतीय सैनिकों के लक्षित हमले (सर्जिकल स्ट्राइक) के पूर्व और बाद की घटनाओं पर पूछे गए प्रश्नोत्तर देने में सिद्धेश्वर जी ने अपनी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान-साधना का पूरा परिचय दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विगत दो वर्षो में साठ-सत्तर देशों की यात्रा के दौरान अपनी कूटनीतिक चाल से प्राय: सभी देशों का ध्यान खींचने में सफलता हासिल की है उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान आज सभी देशों से अलग-थलग पड़ गया। सिद्धेश्वर जी ने नरेन्द्र मोदी की कूटनीति की सफलता पर अपने बेवाक टिप्पणी देते हुए जो उत्तर दिए हैं वे अत्यंत मार्मिक और प्रासंगिक हैं।

संयुक्त राष्ट्र पर हावी औपनिवेशिक मानसिकता से संदर्भित प्रश्न का उत्तर देते हुए सिद्धेश्वर जी कहते हैं-'संयुक्त राष्ट्र पर औपनिवेशिक मानसिकता आज भी हावी है, क्योंकि पी-5 यानी परमानेंट-5 के पाँच देशों अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस और चीन जिनके पास 'वीटो पावर' है संयुक्त राष्ट्र की 1945 में हुई स्थापना के ही समय से उसकी सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्य बने हुए हैं और उनका 'वीटो पावर' इनकी दबंगई का ब्रह्मास्त्र है। इसके आगे बाकी 188 संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के सारे हथियार बेकार हो जाते हैं।'

राजनीतिक और वैश्विक प्रसंगों की वर्तमान संदर्भो के अनुरूप व्याख्या करने के लिए मशहूर सिद्धेश्वर जी की यह नवीनतम पुस्तक है 'राष्ट्रीय राजनीति' और 'वैश्विक कूटनीति' जिसमें उन्होंने भारतीय राजनीति

और वैश्विक कूटनीति से जुड़ी जिज्ञासाओं के सवाल-जवाब सहज अंदाज में प्रस्तुत किये हैं।

सिद्धेश्वर जी की पूरी कृति में इनकी कलम के निशाने पर हैं हुक्मरान, सियासतदान और सिसकती लोकतांत्रिक व्यवस्था। इन्होंने किसी को नहीं बख्शा है। हिंदी जगत में अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए मशहूर तथा हिंदी के जीवंत हस्ताक्षर सिद्धेश्वर ने बड़ी संजीदगी से भारतीय राजनीति की मौजूदा स्थिति से पाठकों को रूबरू कराया है और सामयिक परिस्थितियों को रेखांकित किया है। इस दुर्लभ साक्षात्कार को प्रकाशित करने के लिए मंगल कामनाएँ। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यथार्थ पर आधारित राजनीति के विभिन्न पहलुओं को समेटे हुए वस्तुस्थिति तथा जमीनी सच्चाई से सिद्धेश्वर जी के उत्तर साक्षात्कार कराते हैं। साक्षात्कार के दौरान इनके समक्ष जो प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं उनके उत्तर में राजनीति का पूरा संसार प्रतिबिंत होता है। एक प्रश्न का उत्तर पढ़ने पर आगे दूसरे प्रश्न का उत्तर पढ़ने की लालसा जागृत हो जाती है। पाठकों की जिज्ञासा उमड़ती-घुमड़ती रहती है कि राजनीति से संबंधित आगे के प्रश्नों पर उनके उत्तर क्या होंगे? अगली कड़ी का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि आजादी के सत्तर साल के बाद भी राजनीतिक परिदृश्य में हाशिए के लोग अबतक हाशिए पर हैं। राजनेताओं द्वारा कही गई उद्धार की बातें एक छलावा से अधिक कुछ नहीं हैं।

अपने समय और समाज की ज्वलंत समस्याओं और जनमानस को उद्वेलित कर रहे सिद्धेश्वर भारतीय राजनीति की मौजूदा स्थिति पर जब अपने विवेकपूर्ण चिंतन का स्वर मुखर करते नजर आते हैं तो आश्वस्ति होती है कि अभी गणतंत्र में विचारों की कमी नहीं है। वैचारिक लेखन के माध्यम से वह पाठकों का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। दरअसल, समाज को चेतनशील बनाने का कार्य निष्ठा से इनके उत्तर में करता दिखाई देता है और व्यवस्था परिवर्तन का सूत्र पाठकों के भीतर रखने में सहायता करता है।

साक्षात्कार के आधार पर तैयार प्रश्नोत्तरी के सभी पुस्तकों को जब मैंने पढ़ा तो मन प्रफुल्लित इसलिए हुआ कि यदि समाज में कहीं समरसता, अनेकता में एकता, विविधता, वैश्विक कूटनीति और राष्ट्रीय राजनीति की विसंगतियाँ देखने को मिलती हैं तो उसका श्रेय सिद्धेश्वर जी जैसे साहित्यकारों के सत्प्रयास को जाता है, क्योंकि इनकी कृतियों के उत्तर ऐसी भाषा में दिए गए हैं कि संपूर्ण जन समुदाय को उनकी अपनी अंतरात्मा की भाषा जान पड़ती है। इनके उत्तरों से ऐसा जान पड़ता है कि खराब-से-खराब

परिस्थितियों में भी आशा बची रहती है और जीवित रहना प्रयास करने योग्य है। *इनके उत्तर में परिपक्व अभिव्यक्ति* देखने को मिलती है और अनुभव की ताजगी पठनीयता को बनाए और बचाए रखती है, क्योंकि ये जो कुछ लिखते हैं वह अनुभवों व स्मृतियों के आख्यान हैं। किसी न किसी रूप में लेखक अपने लेखन के रूप में मौजूद रहता है। सिद्धेश्वर जी अपनी जिजीविषा के साथ जीवित रहते हैं। वे लंबे समय से लिखते रहे हैं। आखिर तभी तो कथासम्राट मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि 'मनुष्य स्वभाव से देवतुल्य है। जमाने के छल-प्रपंच और परिस्थितियों के वशीभूत होकर वह अपना देवत्व खो बैठता है। साहित्य इसी देवत्व को अपने स्थान पर प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करता है उपदेशों से नहीं, नसीहतों से नहीं, भावों को स्पंदित करके, मन के कोमल तारों पर चोट लगाकर, प्रकृति से सामंजस्य उत्पन्न करके।' सिद्धेश्वर जी अपने साहित्य के माध्यम से यही तो कर रहे हैं। उन्होंने साक्षात्कार की इस कृति के माध्यम से लोगों के भावों को स्पंदित किया है।

मौजूदा दौर की राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक कूटनीति के बीच इस दुनिया में जहाँ बंदूकों की होड़ लगी हुई है, बम-बारूदों की बहसें जारी हैं, जरूरत है एक ऐसी आवाज की, जो हमारे अंदर की सर्वोच्च को संबोधित हो, जो हमें खुशियों से बात कर सके और जो हमारे संदेहों और हमारे भय से बात कर सके। हमारे सहपाठी सिद्धेश्वर जी एक ऐसी ही आवाज हैं जिन्होंने अपने उत्तर में अपने विचार के साथ-साथ जनता की भावनाओं और राष्ट्र के विरूद्ध किए जा रहे गंभीरतम अपराध और षड्यंत्र को बेहतरीन तरीके से रेखांकित किया है जिसके लिए वह हमारी हार्दिक बधाई के पात्र हैं। हमारी मंगलकामना है कि वह दीर्घायु हों, ताकि उनकी कलम से ऐसी ही कृतियाँ पाठकों के सामने आ सकें। मुझे विश्वास है कि हर दृष्टि से मुकम्मल उनकी कृतियों का साहित्य जगत में स्वागत होगा।

संपर्क:
मकान सं. ए/32, पिपुल्स कोऑपरेटीव
लोहियानगर, पटना-20
दूरभाष-0612-2350140

डॉ. (प्रो.) एल.एन.शर्मा
पूर्व अध्यक्ष, स्नातकोत्तर
राजनीति विज्ञान विभाग
पटना विश्वविद्यालय
पटना

शुभाशंसा

सोचने और कहने की निर्भीकता अद्वितीय

◻ डॉ. साधु शरण

भारतीय समाज के मौजूदा माहौल में व्यावसायिक मानसिकता न रखने वाले सिद्धेश्वर जी का अनिवार्य योगदान साहित्य और उसके जरिए समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए योगदान करना रहा है। वैसे हिंदी साहित्य की कविता, संस्मरण, निबंध आदि विधाओं में तो इनकी अबतक डेढ़ दर्जन पुस्तकें आ चुकी हैं, मगर साक्षात्कार जैसी महत्वपूर्ण विधा में हधर हाल के वर्षो में आई पाँच पुस्तकों में से प्रस्तुत पुस्तक–'इंसानियत की धुँआती आँखें' दूसरी है जिसमें जिज्ञासू विद्वत्‌जनों ने इनसे साक्षात्कार के दौरान सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व आध्यात्मिक, नैतिक, वैचारिक तथा प्राकृतिक विषयों से संबंधित प्रश्न इनके समक्ष उत्तर हेतु प्रस्तुत किए हैं। सिद्धेश्वर जी के द्वारा इन प्रश्नों के जो उत्तर दिए गए हैं वे अत्यंत प्रशंसनीय हैं, क्योंकि वे विद्वतापूर्ण हैं और इनका कथन पूर्णतया सत्य है जिनमें इनकी विचारधारा परिलक्षित होती है।

इसी प्रकार सिद्धेश्वर जी के जो अनुभव रहे हैं और अपने समय में भारतीय समाज और संस्कृति को जिस रूप में इन्होंने देखा और समझा है वे इनके उत्तर में स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं, क्योंकि वे किसी खेमे या गुट अथवा किसी खास आंदोलन में बँधकर नहीं रहे। इनका सृजन एक स्वाभिमानी लेखक की तरह है। साक्षात्कार में दिए गए सहज उत्तर की तरह इनका सरल, सौम्य, स्वभाव व व्यक्तित्व भी बड़ा प्रभावकारी है।

कभी महालेखाकार कार्यालय में हमारे सहकर्मी रहे सिद्धेश्वर जी को हमने बहुत करीब से देखा है और इधर विगत कई दशक से इनके कार्यक्रमों में भागीदारी के चलते इनके व्यक्तित्व में हमने जो एक और विशेषता देखी है वह यह कि वे कभी लघुत्व (Inferiority Complex) से पीड़ित नहीं हुए। यही कारण है कि इन्होंने सार्वजनिक जीवन जीने के क्रम में भी किसी भी राजनीतिज्ञों की जी–हुजूरी नहीं की और न उनके आगे–पीछे कभी लगे रहे। राजनेताओं के यहाँ इनका आना–जाना नहीं के

बराबर रहा, बल्कि सच तो यह है कि नीतीश कुमार जैसे कद्दावर नेता पटना के पुरन्दरपुर स्थित इनके 'बसेरा' निवास में इनसे मिलने जाया करते थे और सिद्धेश्वर जी एक प्याली चाय से उनका स्वागत करते रहे।

हमेशा से भीड़ के आदमी रहे सिद्धेश्वर जी को कभी भीड़ से या रसूखदार राजनेताओं से इन्हें कभी डर नहीं रहा। इनके इसी स्वभाव की वजह से आज भी इनके निवास पर लोग इनसे मिलने जाया करते हैं और इनसे बातचीत कर उन्हें काफी संतुष्टि मिलती है, क्योंकि इनकी मनोवैज्ञानिक पकड़ गहरी सौंदर्यानुभूति, जीवन के व्यापक रूप में देखने की प्रवृत्ति भावाव्यक्ति की मुखर शक्ति और भाषा पर इनका असाधारण अधिकार देखने को मिलता है और जिसकी अनुगूँज प्रश्नोत्तर में भी सुनाई पड़ती है। इसी वजह से इनके सभी मित्र और शुभेच्छु इनकी प्रतिभा का लोहा मानते हैं। इसलिए मैं इन्हें आधुनिक जीवनधारा का विरल साहित्यकार मानता हूँ। साक्षात्कार के जरिए तो इनकी प्रतिभा जहाँ मुखरित हुई है, वहीं इनकी अगाध विद्वता, सूक्ष्म चिंतन, अनोखी सूझ और परंपरा के समानांतर सोचने और कहने की निर्भीकता अद्वितीय है। साथ ही इनकी और संभावनाओं को जानने-समझने, इनके सृजन-कर्म और इनके संस्कार-स्वभाव की जानकारी मिलती है। देश और काल का सही ढंग से आकलन करने के लिए शायद ही कोई सर्वग्राह्य उपलब्धि अन्यत्र प्राप्त होगी जैसी इनके साक्षात्कार में देखने को मिलती है। सिद्धेश्वर जी अपने स्वभाव में सदैव बने रहने वाले व्यक्ति हैं। प्रस्तुत साक्षात्कार में उन्होंने जीवन की नई चुनौतियों को संवेदना के यथार्थ से रूपांतरित किया है और उत्तर को अपने ढंग का बौद्धिक धरातल प्रदान किया है जिनमें नए जीवन-मूल्यों का सार भी है, प्राचीनता है, तो नवीनता भी और श्रेष्ठता है, तो सक्रियता भी। सच मानिए सिद्धेश्वर जी का सृजन-व्यक्तित्व अपेक्षाकृत मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। मेरे चिंतन, अध्ययन और वैचारिक संप्रेषण के केंद्र में वे सदैव विराजमान हैं, क्योंकि भोग, लिप्सा और महत्वाकांक्षा ने ईमानदारी, सच्चाई, वफादारी और भाई-चारे का आज जिस तेजी से शील-हरण कर लिया है, सिद्धेश्वर जी न तो अपने समय से आँख मोड़ते हैं और न परंपरा एवं जातीय स्मृति की गरिमा से विरक्त होना पसंद करते हैं। उन्होंने शाश्वत जीवन की बहकी उत्तेजना को भी यथार्थ की संवेदना में ढाल कर उसे तीखे व्यंग्य से करुणा में परिणत कर दिया है। सिद्धेश्वर जी सामाजिक प्रश्न के उत्तर में कहते हैं-अहंकार चाहे धन-संपत्ति का हो या रसूख का, संवेदनाओं का हनन कर

देता है। आज देखने में तो आ रहा है कि दबंगई, आर्थिक एवं चारित्रिक भ्रष्टाचार के मामलों में अधिकारी, नेता, मंत्री, विधायक, सांसद एवं उद्योगपतियों के लाड़ले ही अधिकतर लिप्त रहते हैं जिसका प्रमुख कारण है कि पद-प्रतिष्ठा और सत्ता की हनकवाले परिजनों पर उनका दृढ़ विश्वास रहता है कि वह उन्हें बचा ही लेंगे। इसी प्रकार रिश्वतखोरी की प्रवृत्ति ने तो व्यवस्था के हर क्षेत्र में झंडे गाड़ दिए हैं। घूस के लालच में तो पुलिसवाले भी संवेदनहीन हो जाते हैं और वह कोर्ट-कचहरी में देर-सबेर मुक्त हो जाते हैं। ऐसे में संवेदनाएँ कहाँ तक जीवित रह सकती हैं।

सिद्धेश्वर जी की सजगता में सामाजिक जीवन मूल्यों की चिंता है और उनकी सक्रियता में युग-वेदना की चिंता। इनकी राष्ट्रीयता राजनैतिक नहीं है और इनका राष्ट्रबोध विश्वबोध की मानव-चेतना से ओत-प्रोत है। साक्षात्कार के दौरान इनके द्वारा प्रस्तुत उत्तर पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि इनके उत्तरों में उद्दाम जीवनीशक्ति है, जीवनरूपों का विस्तृत और बारीक चित्रण है, उनमें मूल्यों का तारतम्य तथा सम्यक जीवन दृष्टि एवं परिपूर्ण जीवन विवेक है। इनके उत्तर का उद्येश्य वस्तुतः रचना का चिरस्थायी महत्व बनाए रखने का है। सिद्धेश्वर जी से मैं लंबे अरसे से वैचारिक और रचनात्मक रूप से जुड़ा हूँ। सिद्धेश्वर जी सतत प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं समाज को बदलने की आहट को अपनी पारखी निगाहों से परीक्षण करते हुए 18 मई, 2017 को सिद्धेश्वर जी छिहत्तर की आयु पार कर सतहतरवें में प्रवेश कर गये हैं। हम उनके शतायु होने की कामना करते हुए प्रस्तुत कृति की शुभाशंसा आमजन के लिए करता हूँ।

डॉ. साधु शरण
पूर्व विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान
जैतपुर महाविद्यालय, बी.आर.अंबेडकर
बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार

संपर्क :
गीता भवन, रोड नं.-1
उत्तरी पटेल नगर
पटना-25
दूरभाष- 0612-2287204

शुभाशंसा

प्रश्नोत्तर में जीवन की उत्कट-तीव्रता और अनुभव की तीव्र-तीक्ष्णता

□डॉ. लखन लाल सिंह 'आरोही'

सिद्धेश्वर जी समाज के प्रबुद्धजनों से लेकर सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं तक के दिलों की धड़कन हैं और आज भी सभा-संगोष्ठियों में मुक्त भावों के साथ सुने जाते हैं, क्योंकि वे उन्हें नेह की डोर से बाँधे हैं। समाज, साहित्य और पत्रकारिता में किया गया इनका योगदान अविस्मरणीय के साथ-ही-साथ प्रतियोगितात्मक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिद्धेश्वर जी अपनी कृतियों में विविध आयामों को दर्शाया है, जिसे पढ़कर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि देश और समाज की दुर्दशा को देखने, परखने और साहित्यिक कृतियों के रूप में पाठकों के समक्ष रखने के लिए इस लेखक के पास एक बहुआयामी और जनोन्मुखी अंर्तदृष्टि है।

सिद्धेश्वर जी की 'जीवन रागिनी' नाम्नी आत्मकथा मनभावन इसलिए लगी, क्योंकि यह प्रतिष्ठित साहित्यकार एवं पत्रकार अपनी उम्र का 77वाँ पड़ाव पार कर रहे इनकी जीवन-यात्रा पर केंद्रीत है और इस प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से जुड़ी यादें मन को छू गईं। दरअसल, साहित्यिक पठनीयता सुधी पाठकों की संवेदनशीलता पर निर्भर करती है। उसका रचनाकार से भावात्मक तादात्मय होता है। कलम के धनी शब्द साधक सिद्धेश्वर जी द्वारा लिखित आत्मकथा में इनके बचपन से लेकर आज तक की जीवन-यात्रा तारतम्यता के साथ रेखांकित है जो रोचक तो है ही गुणवत्तापूर्ण भी।

प्रस्तुत आत्मकथा बहुत प्रभाव डालने वाली है पाठकों पर, क्योंकि सिद्धेश्वर जी ने इसे गहराई से लिखा है। इस आत्मकथा की यह खूबी है कि केवल प्रचलित-प्रचारित पर ही मुकुट पहनाकर, ताली बजाकर भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय वक्त की धूल और गर्दिश के धुएँ को हटाकर पाठकों को चमकदार साहित्यिक रत्नों से रू-ब-रू कराती है। आत्मकथाकार ने बड़ी मार्मिक और हृदय में प्रवेश करने वाली बात-भावना

को प्रस्तुत किया है। यह आत्मकथा इनके जीवन संगीत से परिपूर्ण है और पाठक को अंत तक अपने सम्मोहन में बाँधे रखती है। हास्य और मार्मिकता दोनों तत्वों से मिलकर बनी यह आत्मकथा हँसते-हँसाते अचानक मर्म को छू लेती है और एक पाठक भी आत्मकथाकार की तरह ही गंभीर हो उठता है, क्योंकि उनके जीवन और कर्म से जुड़े अनेक छुए-अनछुए हुए पहलुओं से अवगत कराया गया है। भारतीय संस्कृति के सौन्दर्य से सजी और कला से लेकर साहित्य की विभिन्न विधाओं का यह सुन्दर गुलदस्ता है जो देर तक और दूर तक महकता है।

जहाँ तक साहित्य की साक्षात्कार विधा का सवाल है सिद्धेश्वर जी से किए साक्षात्कार के दौरान प्रष्टाओं के प्रश्नोत्तर को संग्रहित कर पाँच पुस्तकें तैयार हैं। जबतक साक्षात्कार में तर्को और तथ्यों का समावेश न हो, तबतक उसमें रोचकता नहीं आती। एक प्रश्नावली तैयार कर लेने भर से साक्षात्कार नहीं हो जाता। साक्षात्कर्ता को चाहिए कि साक्षात्कृत व्यक्ति को प्रश्नों के ब्यूह में बाँधकर अपने मतलब की बात निकाल ले, जिसमें डॉ. अरुण कुमार भगत, कुमार शैलेन्द्र, डॉ. ब्रह्मचारी, सुरेन्द्र कुमार, डॉ. बलराम तिवारी, रामविलास मेहता, डॉ. शाहिद जमील, डॉ. आनंदवर्द्धन, अर्जुन भाई, अवधेश जी, मनोज कुमार, मदन कुमार, नृपेन्द्र प्रति तिवारी, अखिलेश्वर प्रसाद, डॉ. अमलेश वर्मा जैसे प्रष्टा सफल दिखाई देते हैं।

आंतरिक उथल-पुथल को समझने और इस समझ से संकल्पबद्ध होकर निकलने का एक तरीका यह है कि हम किसी समझ-बूझ वाले प्रबुद्धजन के समक्ष अपने प्रश्न प्रस्तुत कर उनसे उत्तर की अपेक्षा करें। उनके उत्तर से संतुष्ट न होने पर भी प्रश्नकर्ता उनसे जुड़ा होता है। बहुत गंभीर और जिम्मेदारी से प्रश्नतकर्ता धीरे-धीरे बाहर और भीतर की लड़ाइयों को समझ लेते हैं और यह प्रश्नोतरी निकटतम अतीत की पड़ताल, वर्तमान संकटों की समझ और आगे के दिशा निर्धारण का एक साधारण प्रयास है जिसे संवाद भी कह सकते हैं। मै मानता हूँ कि प्रश्न ही चीजों को समझने और सुलझाने की पहली सीढ़ी है। इस लिहाज से साक्षात्कृत सिद्धेश्वर जी ने भी प्रष्टाओं की अनेक आशंकाओं एवं अब तक अलक्षित तथ्यों का तर्कपूर्ण उत्तर देने में सफल हुए हैं और प्रश्नोत्तर को संग्रहित करने के बाद पाँच पुस्तकें प्रकाशित कर एक बेहतरीन थाती को संजोया है। इन्होंने भारतीय समाज और राष्ट्रीय राजनीति एवं अंतरराष्ट्रीय कूटनीति सहित न्यायिक एवं आर्थिक फैसले के सामाजिक चेतना को स्वीकृत करा के राष्ट्रवादी संस्कार

के स्वरूप में प्रज्ज्वलित करने की रचनात्मकता को निर्धारित किया है।

इतिहास और वर्तमान के पूरे सच को समझने के लिए पाठकों का ध्यान साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, वैचारिक पत्रकारिता एवं नैतिक स्तरों पर लोगों के व्यवहार सदियों से चली आ रही कहावतों, मुहावरों, रंग एवं सामाजिक भेदों आदि का विस्तृत वर्णन कर लेखन की चेतना को ताकत प्रदान की है। आखिर तभी तो आजादी के सत्तर वर्ष पूरा होने के बाद सारी स्थितियों को समझने का प्रयास करते हुए साहित्यिक-सामाजिक एवं राजनीतिक स्रोतों पर विचार करना जरूरी लगता है, ताकि अहिंसक रूप से जितना संभव हो सके खुलकर जन-संघर्ष के लिए लोगों को प्रेरित किया जा सके।

वस्तुत: सिद्धेश्वर जी ने अपने उत्तर में प्रस्तुत सोच और विश्लेषण के जरिए नई पीढ़ी को नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया है। इस दृष्टि से देखा जाए तो इनके उत्तर बताते कम हैं, मगर जताते-जगाते ज्यादा हैं। सिद्धेश्वर जी हमारे समय की पूर्व निर्धारित विचार प्रणाली से मुक्त वास्तविक अनुभूति के रचनाकार हैं। समय बोध के प्रति सदैव सचेत रहने वाले सिद्धेश्वर जी सरल स्वभाव के विरल व्यक्ति हैं। अक्षरों के लिए भी उनके यहाँ पर्याप्त समय और जगह है। वे अपने किसी भी साधारण अनुभव को असाधारण अभिव्यक्ति प्रदान कर देने में सिद्धहस्त हैं। उनकी कृतियों और साक्षात्कार के दौरान प्रस्तुत उत्तर में जीवन की उत्कट-तीव्रता और अनुभव की तीव्र-तीक्ष्णता दिखाई देती है। इस मायने में सिद्धेश्वर जी हमारे समय की ऐंद्रिय बोध-चेतना और अभिव्यक्ति की असाधारणता के साहित्यकार हैं। कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि प्रखर मानवतावादी विचारक सिद्धेश्वर जी से बहुत कुछ सीखा-समझा जा सकता है। सामान्य बातचीत और दूरभाष- चर्चाओं में उनकी प्रतिबद्धता तथा सक्रियता प्राय: देखी जाती रही है। देश, काल और परिस्थिति के मुताबिक इनकी कृतियों में खासतौर पर 'राष्ट्रीय राजनीति', 'आम आदमी की आवाज' और 'वैश्विक कूटनीति' में राजनीतिक हस्तक्षेप की सघनता का विचार-विस्तार साफ-साफ देखा जा सकता है। दु:ख, दर्द, प्रेम, वात्सल्य, संघर्ष और विरोधाभासी विडंबनाएँ इनकी रचनाओं में बेहद ही सहज हैं। सिद्धेश्वर जी तथाकथित संभ्रांतता से मुक्त हमेशा प्रतिष्ठा के प्रति सजगता और निडरता से भरे रहते हैं। यही उनके व्यक्तित्व की मासूमियत भरी खास पहचान बन गई है। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके कर्मों से निखरता है। सिद्धेश्वर जी का

व्यक्तित्व उनके अच्छे कर्मों का ही प्रताप है कि उन्हें लोग सम्मान व प्रतिष्ठा देते हैं। इनके जीवन का रहस्य ईमानदारी और निष्पक्ष आचरण है। आखिर तभी तो प्रस्तुत आत्मकथा के तीसरे अध्याय में अपने दाम्पत्य जीवन के प्रसंग में अपनी अर्द्धांगिनी के बारे में सिद्धेश्वर जी कहते हैं– 'मेरी अर्द्धांगिनी निरर्थक आस्थाओं से भ्रमित नहीं हैं और न अर्थ की दृष्टि से बंदनी। उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से हमारे सपनों को सप्त रंग देकर नई राहें खोली हैं जिसके परिणामस्वरूप मेरे पास कामयाबी के शिखर को छूने की अपार क्षमता आई।'

मुझे लगता है सिद्धेश्वर जी ने अपनी आत्मकथा के माध्यम से जो संवाद बनाया है और नई संभावनाएँ तलाशी हैं वह ज्ञान के विस्तार की एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है और हम अपने आपको आधुनिक और प्रासंगिक बनाए रख सकते हैं। आत्मकथाकार ने अपने निजी अनुभवों को लेकर नई जानकारियाँ और नई दृष्टि दी है। इसी प्रकार साक्षात्कार के दौरान प्रस्तुत प्रश्नों के उत्तर में इन्होंने सजीव और प्रेरक विवरण प्रस्तुत किया है। निश्चय ही आत्मकथा के साथ साक्षात्कार की पाँच पुस्तकों का प्रकाशन भारत से जुड़े साहित्य को समृद्ध करने का कार्य किया है। मेरे ख्याल से नए भारत के निर्माण के लिए इनके साहित्य को जन-जन तक पहुँचाने की आवश्यकता है। इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए कि इस वटवृक्ष की शाखाएँ दूर-दराज के क्षेत्रों में कैसे पहुँचे, ताकि इस समृद्ध साहित्य का लाभ समाज के आखिरी जन को भी मिल सके। इन पुस्तकों में सिद्धेश्वर जी द्वारा प्रस्तुत बहुमूल्य विचारों और मार्गदर्शन के लिए मैं इन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। इन पुस्तकों का प्रसार ज्यादा से ज्यादा हो तथा लेखक दीर्घायु हों इसके लिए हमारी मंगलकामना है।

डॉ. लखन लाल सिंह 'आरोही'
अध्यक्ष, अंगिका अकादमी
बिहार, पटना

संपर्क:
पूर्व प्राध्यापक, हिंदी विभाग
तिलकामांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर
ग्राम– पत्रा.–
जिला–बाँका (बिहार)
मो.

प्रथम अध्याय :
वैश्विक प्रश्नोत्तर

(1) प्रश्न : क्या भारत का आने वाले दिनों में संयुक्त राष्ट्र परिषद् में स्थायी सदस्यता मिल पाएगी?

उत्तर : देखिए, भाई विजय जी, यह इतना आसान नहीं है, किंतु जब से संयुक्त राष्ट्र ने सुरक्षा परिषद में विस्तार व सुधार पर चर्चा के लिए दस्तावेज को स्वीकार कर लिया गया है यह आशा बँधी है कि अब आज न कल भारत को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता मिल सकती है।

दरअसल, दिक्कत यह है कि सुरक्षा परिषद के अमेरिका, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन तो भारत को स्थाई सदस्यता दिलाने के पक्ष में हैं, लेकिन भारत के खिलाफ इन दिनों चीन के साथ रूस भी हो गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में भारत की स्थायी सदस्यता पारित हो भी गई, तो चीन मंजूर नहीं करेगा और वह अपने विशेषाधिकार के तहत वीटो लगा देगा।

(2) प्रश्न : रूस तो पहले भारत का भरोसेमंद और पुराना सहयोगी रहा है। पहले तो वह भारत की स्थायी सदस्यता दिलाने के पक्ष में था। अब क्यों विरोध कर रहा है?

उत्तर: इधर हाल के वर्षो में रूस को यह लगने लगा है कि भारत की राजनीति अब अमेरिका की तरफ झुक गई है। इस आधार पर रूस को ऐसा लगता है कि यदि भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिल जाती है, तो मौका आने और जरूरत पड़ने पर भारत अमेरिका के पक्ष में रूस के खिलाफ वोटिंग कर सकता है।

(3) प्रश्न : क्या आप ऐसा समझते हैं कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बनी केंद्र सरकार के आने के बाद भारत का रूझान अमेरिका की तरफ बढ़ा है और रूस से कम हुआ है?

उत्तर : यद्यपि सप्रंग सरकार – दो के समय से ही मनमोहन सिंह की सरकार अमेरिका की तरफ झुक गई थी, मगर नरेन्द्र मोदी सरकार के आने के बाद भारत का रूझान अमेरिका की तरफ स्पष्ट दिखने लगा है और रूस की तरफ कम होता दिखाई दे रहा है। वर्ष 2010 और 2015 में अमेरिकी

राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा में उन्होंने भारत की रूझान की वजह से भारत सरकार को और यहाँ तक कि हमारी संसद में स्थाई सदस्यता दिलाने का ओबामा ने आश्वासन दे रखा था। अब देखना यह है कि आगे उसका रूख क्या होता है। मुझे लगता है कि रूस भी आज न कल भारत को सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता दिलाने में साथ देगा।

(4) प्रश्न : क्या आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शैली ने भी विदेशी धरती पर अलग ही असर छोड़ा है?

उत्तर : हाँ, मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शैली ने भी विदेशी धरती पर अपना अलग ही असर छोड़ा है। जैसे इस बीच, संयुक्त राष्ट्र परिषद के विस्तार के संदर्भ में भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र का सहमत होना एक देश की बड़ी सफलता के पीछे यह भी रहा कि संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में नरेन्द्र मोदी अपना पक्ष बहुत सलीके से रखा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार संबंधी अरसे से चली आ रही माँग को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व के तमाम शीर्ष नेताओं के समक्ष प्रत्येक बैठक में और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को बार-बार उठाया है। मोदी की अतिसक्रिय विदेश नीति और अमेरिका, चीन, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया के साथ ही तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, खजाकिस्तान, किर्गीस्तान और उज्बेकिस्तान समेत मध्य एशिया के अनेक देशों की उनकी यात्राओं के चलते यह सफलता मिल गई। मोदी के जोरदार प्रयासों का ही परिणाम था कि संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का फैसला किया।

नरेन्द्र मोदी विश्वभर में अब जाना-पहचाना चेहरा है। सभी देशों की रुचि दिखती है कि वह क्या चाहते हैं। अपने देश को जिस दिशा में वे ले जा रहे हैं, उस सबके बारे में भी सभी जानना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नरेन्द्र मोदी हिंदी में ही बोलते हैं और प्राय: सभी विषयों पर अपनी बात स्पष्ट ढंग से रखते हैं और उनकी भाषा भी क्लिष्ट नहीं होती। मुझे तो लगता है कि उनकी जिह्वा पर साक्षात् सरस्वती बसती है।

(5) प्रश्न : बीते कोई दो वर्ष के दौरान विदेश नीति के मोर्चे पर नरेन्द्र मोदी ने क्या किया है?

उत्तर : यह नरेन्द्र मोदी ही हैं जिनके अथक प्रयास से पहली दफा संयुक्त राष्ट्र ने गंभीरता से सुरक्षा परिषद् के विस्तार के मुद्दे पर विधिवत् सहमति जताई है। सुरक्षा परिषद के विस्तार संबंधी दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र आमसभा के 69वें सत्र में चर्चा के लिए स्वीकार किया गया जिस पर जमैका

के राजदूत कोर्टनी के नेतृत्व में आम सभा के 70वें सत्र में चर्चा हुई।

निःसंदेह भारत आज एशिया के साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया में चालक की सीट पर विराजमान हो गया है। आज भारत यून पीस किपिंग ऑपरेशंस में सबसे ज्यादा योगदान करने वाला देश है। मोदी जी के प्रयास से ही आज भारत के पक्ष में अनेक मित्र देश आगे आ गए हैं, जो भारत के लिए अभियान छेड़े हुए हैं।

बीते कोई दो वर्ष के दौरान नरेन्द्र मोदी ने अपनी पहलकदमी से मंजे हुए विश्लेषकों और राजनीतिक पर्यवेक्षकों तक को कई बार हैरत में डाला है।

(6) प्रश्न : विश्व विरादरी के समक्ष खुद को पीड़ित पक्ष के तौर पर जाहिर करने में पाकिस्तान कितना सफल हुआ है?

उत्तर : पाकिस्तान विश्व विरादरी के समक्ष खुद को पीड़ित पक्ष के तौर पर जाहिर करने में सफल हुआ है, ऐसा मुझे नहीं लगता।

(7) प्रश्न : क्या पाकिस्तान निकट भविष्य में भारत के खिलाफ तमाम नकारात्मक रूख दिखाना जारी रखेगा?

उत्तर : सच मानिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बिना अधिकारवाले प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है जिनका दरवाजा इस्लामाबाद के मेयर तक से ज्यादा नहीं है। ऊफा में बनी समझ के उपरांत जिस प्रकार नवाज शरीफ अपनी ही सेना तथा अन्य आतंकवादी तत्वों के दबाव में आए, उससे उनकी विश्वसनीयता नहीं रह गई। आखिर कोई प्रधानमंत्री अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान नहीं कर पाए और भारत के साथ बनी समझ के अनुसार कुछ नहीं कर पाए, तो स्पष्ट है कि उनकी किसी का परवाह नहीं है।

सच तो यह है कि जैसे-जैसे संयुक्त राष्ट्र आम सभा सत्र नजदीक आएगा पाकिस्तान नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तनाव की स्थिति बना देगा, ताकि कश्मीर मुद्दे पर विश्वभर का ध्यान खींच सके। यानी विश्व बिरादरी के सामने खुद को पीड़ित पक्ष के तौर पर जाहिर करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगा। हालांकि पाकिस्तान के इस कपटी और नकारात्मक खेल ही इस प्रकार की स्थिति पैदा करके फायदा उठाने में संलग्न रहता है। मुझे लगता है कि विश्व के शक्तिशाली एवं विकसित राष्ट्र खासतौर पर अमेरिका का दबाव पाकिस्तान पर पड़ेगा, तो वह नकारात्मक रूख अपनाने से बाज आएगा।

(8) प्रश्न : क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दो बार अमेरिका जाने से भारत आने वाले निवेश में बढ़ोतरी हो रही है या बढ़ोतरी होगी?

उत्तर : भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पिछले 2014 में अमेरिका गए थे और उनके वहाँ भाषण बहुत लोकप्रिय हुए थे। अमेरिका में नरेन्द्र मोदी का जैसा स्वागत हुआ था, अभूतपूर्व था। 2015 के 27 सितंबर को वह फिर अमेरिका गए। आपने जो सवाल किया है उसके जवाब में कहा जा सकता है कि अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के जाने का अमेरिका से विदेशी निवेश आने का सीधा संबंध नहीं है। भारत में महत्वपूर्ण विदेशी निवेश सिंगापुर और मारीशस से भी आ रहा है, जहाँ नरेन्द्र मोदी नियमित तौर पर नहीं जा रहे हैं।

वर्ष 2014-15 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करीब 30.93 अरब डॉलर का था, इसके पहले साल के मुकाबले इसमें 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। समझने की बात यह है कि विदेशी निवेश सिर्फ किसी नेता के दौरे की वजह से नहीं आता। विदेशी निवेश आने की ठोस आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक वजहें होती हैं। भारत और अमेरिका के आर्थिक रिश्तों का सच यह है कि अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार कौन है। अमेरिका की शीर्ष कंपनियों के आइटम चीन में बनते हैं। फिर वहाँ से उन्हें पूरी दुनिया में बेचा जाता है। एप्पल फोन चीन के कारखानों में बनते हैं, पर उनका मुनाफा एप्पल अमेरिका के मुनाफे में जाता है, जो उन फोनों को बड़ा ब्रांड बनाकर बेचती है।

(9) प्रश्न : अमेरिका के लिए चीन एक फैक्ट्री है जो भारत को वह मुकाम हासिल नहीं है। क्या 'मेक इन इंडिया' के तहत भारत को वह मुकाम हासिल हो सकता है?

उत्तर : आपने सही कहा कि अमेरिका के लिए चीन एक फैक्ट्री है जो भारत को वह मुकाम हासिल नहीं है, मगर भारत 'मेक इन इंडिया' के तहत यह मुकाम हासिल करना चाहता है। चीन की आर्थिक हालात इन दिनों बहुत खराब है। इसकी वजह यह है कि चीन में विकृत पूँजीवाद, समाजवाद के नाम पर महत्वपूर्ण लोग भरपूर दोहन कर रहे हैं। पर नीचे के आम आदमी मजदूर को कुछ खास नहीं मिल पा रहा है। बहुत से लोग साम्यवादी विचारक तो अब चीन को साम्यवादी तक नहीं मानते, पूँजीवाद का विकृत चेहरा मानते हैं। चीन से मिल रही खबरों के अनुसार वहाँ के तमाम धनी लोग अपना काम-धंधा चीन से उठाकर कहीं और ले जाना चाहते हैं। अस्थिरता कारोबार

की पहली दुश्मन है। अस्थिरता अब चीन से पक्के तौर पर जुड़ी रहने वाली है। यह स्थिति भारत के 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के लिए अच्छी हो सकती है, बशर्ते कि चीन के संकट को भारत अपने लिए मौकों में तब्दील कर ले। अब सवाल यह है कि अमेरिका में भारत की तरफ से क्या नई कार्य योजना प्रस्तुत की जाती है और चीन में फैक्ट्री के मुकाबले भारत में फैक्ट्री लगाना क्यों बेहतर है, इस सवाल का ठोस जबाव क्या दिया जाता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। भारत के तमाम अधिकारी इस काम को बखूबी कर सकते हैं। और अगर यह जबाव कारगर साबित होता है तो फिर अमेरिका से विदेशी निवेश आएगा। अमेरिका की फोर्ड, जनरल मोटर्स, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियों की उपस्थिति भारत में है। पर 'मेक इन इंडिया' के तहत जरूरी है कि फैक्ट्री लगाई जाएँ ना कि सॉफ्टवेयर बनाने वाले दफ्तर यानी अमेरिका की कार कंपनियाँ, बाइक कंपनियाँ, पिज्जा, बर्गर कंपनियाँ यहाँ निवेश लेकर आएँ, ताकि यहाँ के कम पढ़े-लिखे लोगों को भी रोजगार मिल सके। भारत की राजनीतिक-सामाजिक स्थिरता की शानदार मार्केटिंग ऐसे निवेशकों को बड़ी तादाद में लाने में सफल हो सकती है। मोदी की नियमित यात्राएँ इस मार्केटिंग की पृष्ठभूमि तैयार कर सकती है, पर ठोस परिणाम सिर्फ उनसे नहीं आएँगे और सब नहीं आएँगे। उसके लिए हर राज्य को अपने यहाँ निवेश का बेहतर माहौल तैयार करना होगा।

(10) प्रश्न : क्या योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और बढ़ावा मिलने से भारत के स्वास्थ्य बाजार को भी देश-विदेश में खासा बढ़ावा मिला है?

उत्तर : आप इस बात से अवगत हैं कि भारतीय प्रयासों में सबसे बड़ा प्रयास नरेन्द्र मोदी की वह अपील रही जिसमें उन्होंने विश्व समुदाय से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने का आह्वान किया था। इससे पूर्व कभी भी संयुक्त राष्ट्रसंघ के इतिहास में किसी प्रस्ताव को इस कदर शीघ्रता से स्वीकार नहीं किया गया था और न ही इस अंदाज में सदस्य देशों ने एकमत होकर किसी प्रस्ताव के साथ इस कदर एकजुटता दिखलाई थी। न केवल इस विश्व संस्था, जिसे इसके 192 सदस्यों का समर्थन हासिल था, ने योग की बावत प्रस्ताव पारित किया, बल्कि 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने संबंधी मोदी के प्रस्ताव को भी स्वीकार किया। केवल पाकिस्तान ही ऐसा रहा जिसने इस्लाम धर्म का नाम लेते हुए विश्व योग दिवस नहीं मनाए जाने की बात कही। भारत से लेकर फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस तथा चीन समेत 192

देशों में योग दिवस पूरे उत्साह और जोर-शोर से मनाया गया। मोदी का विश्वभर में सिर चढ़कर बोल रहा था।

आर्थिक स्तर पर योग की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता, आयोजन और संयुक्त राष्ट्र की स्वीकृति से भारत के स्वास्थ्य बाजार को प्रोत्साहन मिला है। आयुष मंत्रालय के मुताबिक भारत का बाजार 7.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जिसमें अकेले स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का हिस्सा ही 40 प्रतिशत से अधिक है। मैं कह सकता हूँ कि योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा मिलने से भारत के स्वास्थ्य बाजार को भी देश-विदेश में खासा बढ़ावा मिला है।

(11) प्रश्न : जब लाखों की संख्या में मुस्लिम बहुल देशों से भारत में शरणार्थी पहुँचते हैं, तो कहीं इस वेश में ऐसा तो नहीं कि अलगाववादी या कट्टरपंथी दहशतगर्द प्रवेश कर रहे हैं?

उत्तर : इसमें कोई संदेह नहीं कि लाखों की संख्या में विभिन्न देशों से खासतौर पर मुस्लिम देशों के शरणार्थी भारत में पहुँच रहे हैं। बांग्लादेश से आने वाले नाजायज घुसपैठिए शरणार्थियों की बाढ़ ने हमें इस बारे में अति यथार्थवादी नजरिया अपनाने को बाध्य किया है। कुछ नीति-निर्धारकों का तो यह मानना है कि ये शरणार्थी न तो प्रताड़ित राजनैतिक विपक्षी हैं और ना ही जनजातीय या सांप्रदायिक अल्पसंख्यक, गरीबी के मारे और भारत की तुलनात्मक खुशहाली से ललचाए ये शरणार्थी यहाँ का रूख करते हैं। इसके अतिरिक्त, चिंता इस बात को लेकर हमें है कि जब लाखों की संख्या में शरणार्थी यहाँ पहुँचते हैं, तो यह तय करना मुश्किल होता है कि कहीं इस वेश में अलगाववादी या कट्टरपंथी दहशतगर्द तो प्रवेश नहीं कर रहे? ये सारी आपत्ति-आशंकाएँ सीरियाई शरणार्थियों के संदर्भ में भी उठाई जा रही हैं। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि कहीं न कहीं सीरियाई शरणार्थियों के प्रति संदेह और आक्रोश की जड़ें गोरे ईसाई नस्लवाद में गहरे दबी हैं।

भारत सरकार द्वारा हाल ही प्रकाशित एक बयान से पता चलता है कि उच्च न्यायालय के एक सवाल के जवाब में कहा गया है कि हम किसी भारतीय नागरिक को सीरिया या इराक में इस्लामी राज्य के विरूद्ध संघर्ष में भाग लेने के लिए विदेश यात्रा की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि इससे देश में सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ने की आशंका प्रबल है। ऐसा करने से कुछ अनाम

मित्र देशों के साथ हमारे संबंध खराब होने का जोखिम भी पैदा हो सकता है। याद रहे कि बहाबी इस्लाम के जिस खूँखार अवतार का प्रसार और *पालन-पोषण सऊदी अरब से हुआ है, उसी की लगाई आग की लपटों में* अफगानिस्तान, सोमालिया, सूडान, यमन, सीरिया, इराक और पाकिस्तान झुलस रहे हैं। इसलिए शरणार्थी समस्या सिर्फ बेघर हताहतों तक सीमित रहने वाली नहीं।

(12) प्रश्न : आईएसआईएस के खिलाफ क्या केवल प्रस्ताव पारित करने से आतंकवाद मिटेगा या कार्रवाई करने से?

उत्तर : आतंकवाद तो अब सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, बल्कि दुनिया का अच्छा-खासा भाग भी इसकी चपेट में आ चुका है। एक तरफ इस्लामिक स्टेट (आईएस) जैसे संगठन कहर ढा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एन्ड सीरिया (आईएसआईएस) विश्व के सारे आतंकियों की जड़ बन चुके हैं। इन संगठनों पर किस प्रकार रोक लगाई जाए, यह पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है।

धार्मिक कट्टरता या मजहबी उन्माद के नाम पर किसी निर्दोष की जान ले लेना किसी भी धर्म में नहीं सिखाया जाता है, बावजूद इसके धीरे -धीरे पूरा विश्व मजहब के नाम पर कुछ लोगों की ऐसी दहशतगर्दी को स्तब्ध होकर देख रहा है। धर्म विशेष के नाम पर होने वाली ऐसी घटनाएँ अब चौंकाती नहीं हैं, पर विश्व को ऐसे लोगों की सोच के प्रति चौकन्ना अवश्य कर रही हैं कि यदि शीघ्र ही कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए, तो यह विनाशलीला बहुतों को लील जाएगी।

दरअसल, शुरुआत से ही आईएसआईएस पश्चिम एशिया में व्यापक हिंसा में लिप्त रहा है। इराक और सीरिया दोनों ने ही इन संगठनों का दर्द भोगा है। जहरीला भौगोलिक, राजनीतिक परिदृश्य पूरे क्षेत्र को उत्तेजित कर रहा है। इसलिए उसके राजनीतिक सैन्य और आध्यात्मिक दृष्टि से प्रतिकार करना जरूरी है।

हमारा मानना है कि आईएसआईएस जैसे खूँखार संगठनों के गिरफ्त में भारत नहीं आ सकता। इस तरह के संगठन इस्लाम को ढाल बनाकर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए इस्लामी कट्टरपंथियों का मुकाबला मुस्तैदी से करना होगा। जहाँ तक संयुक्त राष्ट्रसंघ में आतंकवाद पर होने वाली चर्चा का सवाल है, तो मेरे ख्याल से आईएसआईएस के बढ़ते तांडव पर मुश्किल से यहाँ कोई चर्चा होगी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव 137

आतंकवाद के *खिलाफ* है और उसी के खिलाफ काउंटर टेरेरिज्म भी आता है। दूसरी बात यह है कि आईएसआईएस के खिलाफ केवल प्रस्ताव (Resolution) बनाने और उसे पारित कराने से क्या होगा? जब कदम ही नहीं उठाना चाहते, तो इनके खिलाफ तो ये बातें बेमानी हो जाती हैं। जब तक बड़े-बड़े देश हिम्मत करके कार्रवाई हेतु अपने कदम नहीं बढ़ाएँगे , तबतक ऐसी बीमारियाँ तो फैलती रहेंगी।

जहाँ तक भारत के द्वारा आईएसआईएस के खिलाफ कदम उठाने का प्रश्न है मेरे ख्याल से जो भी आदमी आईएसआईएस में भर्ती होने के लिए जा रहा है या जो इस तरह की गतिविधियों में लगा हुआ है या वहाँ से आया है या पकड़ा जा रहा है उसको सख्त से सख्त सजा देनी होगी। इसके लिए विशेष टेररिस्ट कोर्ट होने चाहिए जो बिना वक्त गंवाए बेझिझक इनको सजा सुनाए। किसी भी तरह से ऐसे मामलों को लटकाकर नहीं रखना होगा। इसके अतिरिक्त सभी तरह के आतंकवाद पर कड़ी नजर रखनी होगी।

(13)प्रश्नः क्या आर्थिक संकट से चीन की छवि को धक्का लगा है?

उत्तरः अगस्त, 2015 में शंघाई कंपोजिट इंडेक्स ने 8.5 फीसदी का गोता खाया और चीन के लोगों की बचत के खरबों युआन डूब गए। अगस्त में गिरे शेयर बाजारों ने चीन के नेतृत्व के समक्ष विचित्र चुनौतियाँ पेश की हैं। तीन दशक पहले सुधारों के प्रारंभ होने के बाद से पहली बार शेयर की कीमतों को दबाए रखने के लिए सरकार के हस्तक्षेपों तथा निवेशकों के बीच विश्वास को बहाल करने की कोशिशें विफल रही हैं, जो प्रदर्शित करती हैं कि किस प्रकार कभी ताकतवर रहे देश की स्थिति निर्बल हो गई है और निश्चित रूप से चीन की छवि को धक्का लगा है। जब शेयर बाजार वहाँ ध्वस्त हो गया, तो सामान्य लोगों को पैसे का नुकसान हुआ। इसलिए इस संकट ने चीन के आम लोगों की भावनाओं को छुआ जिसके परिणामस्वरूप लोगों की नजरों में व्याप्त सर्वशक्तिमान देश की छवि को भारी धक्का पहुँचा है। आर्थिक प्रबंधन होने की चीन की ख्याति को काफी नुकसान पहुँचा है। चीन में शेयर बाजार की गिरावट ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को बड़ा संकेत दिया है और इस मुद्दे को लेकर कि क्या चीन की अर्थव्यवस्था संभल जाएगी, चीन एवं दुनिया भर में बड़ी बहसों को जन्म दे दिया है कि चीन आर्थिक संकट की दिशा में बढ़ रहा है।

(14) प्रश्न : पड़ोसी देश नेपाल को मिले नए संविधान में वहाँ के हर नागरिक के लिए समान अवसर नहीं प्रदान किए जाने से क्या इस लोकतांत्रिक उपलब्धि पर सवाल नहीं खड़ा करता है?

उत्तर : हमारे पड़ोसी देश नेपाल को आखिरकार उसका नया संविधान मिल गया है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में जिस प्रकार पूरी तराई इलाका हिंसा की आग में जल उठा और वहाँ फौजें उतार दी गईं वह इस लोकतांत्रिक उपलब्धि पर अवश्य सवाल खड़ा करता है। क्योंकि इस नए संविधान में वहाँ के हर नागरिक को समान अवसर नहीं प्रदान किए गए हैं। भारत से किए गए तमाम वादों की अनदेखी करते हुए संविधान में तराई की आबादी-थारू और जनजाति समुदायों को जिस प्रकार कमजोर बनाने की कोशिश दिखती है वह नेपाल के भविष्य के लिए सुखद संकेत नहीं दे रहे हैं।

नेपाल ने खुद को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश घोषित तो किया है, लेकिन मधेशी तथा तराई में बसने वाले समाज के बड़े हिस्से को दूसरी श्रेणी के नागरिक बनाए जाने की वजह से उनमें आक्रोश और हिंसा की आग भड़क उठी। हिंसा के इस वर्तमान जुनून में सौ से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। संविधान की आड़ में देश के मैदानी इलाके में रहने वाले मधेशी तथा अन्य समुदायों के खिलाफ खुला भेदभाव किए जाने के बाद विश्वास का माहौल ही खत्म हो गया है। कारण की चुनाव क्षेत्रों के निर्धारण मे मधेशी बहुल इलाकों में जो कतरब्योत की गई है उसका सीधा असर संसद में उनके प्रतिनिधित्व पर पड़ेगा। पहाड़ों पर रहने वाले नेपालियों को संसद में अगर सौ सीटें दी गई हैं, तो मधेशियों और जनजाति की उतनी ही आबादी के लिए महज पैसठ सीटें देकर जानबूझकर असंतुलन बनाया गया जिससे नेपाल के करीब आधे हिस्से को सत्ता से वंचित रखने का प्रयास हुआ। अफसोस की बात इसलिए है कि नेपाल के संविधान निर्माताओं ने यह आत्मघाती कदम उठाकर अपने घर में श्रीलंका जैसे हालात बना रखे और चीन की शह पर भारत को अँगूठा दिखाया। दरअसल, संविधान निर्माताओं को यह याद नहीं रहा कि माओवादियों के आतंक से कराहते नेपाल को मुक्ति दिलाने और लोकतांत्रिक सोच बनाने में वस्तुत: भारत ने ही भाई की भूमिका निभाई थी। लेकिन उन्हें यह याद रखने चाहिए कि भारत से सटी उसकी खुली सीमा के अंदर अगर लोकहिंसा की लपटें फैलती हैं, तो उसका असर हम पर नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा हो जब इस नए संविधान में आवश्यक संशोधन कर

पहाड़ियों पर रहने वाले अन्य नेपालियों के बराबर मधेशियों एवं जनजाति समाज के नागरिकों को भी संसद में समान सांसदों के लिए आवश्यक अवसर प्रदान कर नेपाल में शांति का माहौल बनाया जाए।

संविधान लोकतंत्र की आत्मा होती है जिसमें देश के हर वर्ग और समुदाय की अभिन्न आवाज होती है। इसे महज लोकतंत्र का ठप्पा लगाने वाले मोहर की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नेपाल में आज यही हो रहा है। वहाँ संविधान को ऐसे हथियार में बदलने की कोशिश की जा रही है जिससे वहाँ समाज को दो टुकड़ों में बाँट अनंत काल तक लोकतांत्रिक सत्ता सुख भोगने का इंतजाम कर लिया जाए। नेपाल के घाटी और समतल इलाकों में रहने वाले मधेशी और थारू एवं जनजाति समुदायों की हैसियत दोयम दर्जे के बनाने के तमाम इंतजामों से लैस है यह नया संविधान। तमाम संवैधानिक पदों, प्रशासनिक और सैन्य सेवाओं से इन्हें अलग रखा जाता है। हैरत की बात है कि जहरीली राजनीति कर रहे वहाँ के नेता इसका ठीकरा भी भारत के सिर फोड़ना चाहते हैं और उसपर हस्तक्षेप का आरोप लगा रहे हैं। मगर संतोष की बात यह है कि नेपाल के वरिष्ठ माओवादी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री बाबू राम भट्टराई ऐसे चंद असरदार नेता हैं, जो इस गलती को स्वीकार कर रहे हैं और संघर्ष में भी मधेशियों के साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं।

(15) प्रश्न : अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की चमक यह प्रमाणित करती है कि संसार में उसकी प्रतिष्ठा और उपादेयता बढ़ी है और वह तेजी से वैश्विक भाषा बनती जा रही है, मगर हमारे देश में हिंदी माथे की बिंदी नहीं बन पा रही है। वैश्विक भाषा बनने को अग्रसर हिंदी अपने देश में आखिर कबतक बेगानी बनी रहेगी?

उत्तर : निःसंदेह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की चमक यह प्रमाणित करती है कि पूरी दुनिया में उसकी प्रतिष्ठा और उपादेयता बढ़ी है, इंटरनेट, सोशल मीडिया और कम्प्यूटरों में हिंदी के इस्तेमाल में बहुत तेजी आई है। एक आँकड़े के मुताबिक आज विश्व में 50 करोड़ से अधिक लोग हिंदी बोलते और इससे कहीं अधिक ज्यादा समझते हैं। आज दुनिया के 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई हो रही है। दुनिया के सर्वशक्तिशाली देश अमेरिका में हिंदी की धूम मची है। यहाँ 30 से अधिक विश्वविद्यालयों के भाषायी पाठ्यक्रमों में हिंदी

को महत्वपूर्ण दर्जा हासिल है। अमेरिका में बोली जाने वाली सबसे अधिक दस भाषाओं में हिंदी भी है और इसे बोलने वालों की संख्या 6.5 लाख से ऊपर है। अमेरिकी कम्युनिटी सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका में हिंदी 105 फीसद रफ्तार से आगे बढ़ रही है।

अमेरिका के अतिरिक्त यूरोपीय देशों में भी हिंदी का तेजी से विकास हो रहा है। इंग्लैंड के लंदन, कैंब्रिज और यॉर्क विश्वविद्यालयों में हिंदी के चाहने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। जर्मनी के हीडलवर्ग लोआर के लाइपंजिंग, बर्लिन के हम्बोल फिट और बॉन विश्वविद्यालय में भी हिंदी भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसी प्रकार रूस में एक दशक से कई विश्वविद्यालयों में हिंदी साहित्य पर शोध हो रहा है। रूस में हिंदी ग्रंथों का जितना अनुवाद हुआ है उतना शायद ही विश्व में किसी भाषा का हुआ हो। एशियाई देश जापान में हिंदी भाषा का बहुत अधिक सम्मान है। जापान के दो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ओसाका और टोकियो में स्नातक और स्नातकोतर पर हिंदी पढ़ाई की व्यवस्था है। गुयाना ओर मॉरीशस में भी भारतीय मूल के लोगों की संख्या सर्वाधिक होने की वजह से यहाँ प्राथमिक स्तर से लेकर स्नातक स्तर तक हिंदी के पठन-पाठन की समुचित व्यवस्था है। मॉरीशस में बहुत पहले ही हिंदी सचिवालय की स्थापना हो चुकी है और ढेरों हिंदी पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। इसी तरह फिजी, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका में भी हिंदी का जलवा कायम है। विगत वर्षो में खाड़ी देशों में हिंदी का तेजी से प्रचार-प्रसार हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात में हिंदी में एफएम चैनल लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। गौरतलब है कि हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, फ्रांस, नार्वे, जापान, इटली, रूस और जर्मनी आदि देश अपनी भाषा को लेकर बेहद संवेदनशील हैं, फिर भी इन देशों में हिंदी को भरपूर स्नेह और सम्मान मिल रहा है। यह हिंदी भाषा के लिए बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। आज दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ भारतीयों की उपस्थिति न हो और वहाँ हिंदी का विस्तार न हो रहा हो।

अब तो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भी अपने-अपने देशों में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए सरकारों का दबाव इसलिए बढ़ा रही हैं, ताकि हिंदी के जरिए एशियाई देशों में उनकी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। यह स्वीकारने में कतई हिचक नहीं कि बाजार और सिनेमा ने भी हिंदी की स्वीकार्यता को नई ऊँचाई दी है। इस प्रकार हिंदी तेजी से वैश्विक भाषा बनती जा रही है।

वैश्विक स्तर पर तो हिंदी को बढ़ावा मिल रहा है, पर जब हम अपने देश के स्तर पर हिंदी की स्थिति को देखते हैं, तो सवाल उठता है कि क्या हिंदी का विकास अपेक्षानुरूप है? क्या हिंदी का विस्तार संतोषप्रद है? इन सवालों का सीधा जवाब है नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि तकनीक, मीडिया, मनोरंजन और विज्ञापन में हिंदी की बढ़त स्वागतयोग्य है, पर इस तथ्य को भी नकारा नहीं जा सकता कि यह सब कुछ बाजार की जरूरतों को पूरा करने की प्रक्रिया का परिणाम है। देश में संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो जाने तथा विदेशों में प्रचार-प्रसार के बावजूद हमारी हिंदी भाषा ज्ञान-विज्ञान, अनुसंधान, प्रशासन और न्याय की भाषा नहीं बन सकी है। 1968 में भारतीय संसद ने संकल्प लिया था कि हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं विकास के लिए भारत सरकार द्वारा गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, लेकिन यह सच है कि ऐसे प्रयास खानापूर्ति से अधिक कोई भूमिका नहीं निभा सके। दरअसल, इसके लिए सही नियत और समुचित नीतियों की आवश्यकता है। सरकार और समाज को इन बिंदुओं पर आत्ममंथन कर बेहतरी के लिए ठोस उपाय करने की जरूरत है। हिंदी के विकास के निमित्त सरकारी व गैरसरकारी संस्थाओं द्वारा तमाम तरह के सभा-सम्मेलन के आयोजन के बाद भी हमारे देश में हिंदी की स्थिति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है।

(16) प्रश्नःअमेरिका का वर्तमान दौर में एक साथ हिंसा और विरोध प्रदर्शन के दौर से गुजरने का क्या कारण है?

उत्तर: यूँ तो अमेरिकी समाज में व्याप्त रंगभेद की जड़ें एक अरसे से गहरी हैं, किंतु बराक ओबामा के रूप में अश्वेत राष्ट्रपति के होने के बावजूद रंगभेद की मानसिकता में कमी आती नहीं दिख रही है। दुर्भाग्य से अमेरिका के सारे नेता सार्वजनिक तौर पर रंगभेद के विरूद्ध बातें तो करते हैं, पर वास्तव में समाज ही नहीं, शासन-प्रशासन के अंदर व्याप्त रंगभेदी मानसिकता का अंत हो, इसके लिए शिद्दत से काम नहीं करते। अन्यथा अभी-अभी अचानक अमेरिका जो भयावह सामाजिक तनाव में फँस गया, वह नहीं होता।

अमेरिका के डलास में दो अश्वेतों के, श्वेत द्वारा मारे जाने के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शनों में एक अश्वेत पूर्व फौजी ने पाँच पुलिसवालों की हत्या कर दी जिसके बाद ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि पुलिस को उस पूर्व फौजी के अंत के लिए रोबोट बम का इस्तेमाल तक करना पड़ा। यह कब तक रुकेगा, कहना कठिन है। राष्ट्रपति बराक ओबामा की शांति की अपील भी

अपेक्षित असर नहीं डाल सकी। अश्वेतों की जिंदगी भी कीमती है के नारे के साथ अश्वेत समुदाय न्ययॉर्क से लेकर वाशिंगटन, मिनेपोलिस और सेन फ्रांसिस्को समेत अनेक शहरों में प्रदर्शन कर रहा है।

दरअसल, अमेरिका में हथियार रखने की छूट है इसलिए भी हिंसक घटनाएँ अधिक होती हैं। पुलिस को जबरन इनके हथियार छिनना पड़ा। अमेरिका से नस्ली पूर्वाग्रहों को मिटाने के लिए व्यापक अभियान की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अमेरिका में हथियार रखने की आजादी को भी खत्म करना होगा। पिछले दिनों अमेरिका को ओरलैंडो तथा अन्य शहरों में हुए आतंकी हमले के कारण भी हथियार रखने की आजादी ही रही है। हालांकि रंगभेद को मिटाना तो क़ठिन है, लेकिन हथियारों को नियंत्रित करने के लिए केवल एक विधेयक पारित करने की आवश्यकता है। फिर भी यह नहीं हो पा रहा है।

(17) प्रश्न : क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के आम आदमी के लिए वैश्वीकरण लाभ का सौदा है?

उत्तर : मुझे नहीं लगता कि वैश्वीकरण भारत के आम आदमी के लिए लाभ का सौदा है, क्योंकि वैश्वीकरण बड़ी कंपनियों को अधिक लाभ पहुँचाता है और आम आदमी को बहुत ही मामूली लाभ मिलता है।

ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय संघ से बाहर आने का निर्णय भारत के लिए सबक है, क्योंकि इंग्लैंड के उद्योगों की तरह हमारे देश के उद्योग भी वैश्वीकरण से लाभान्वित हुए हैं, मगर जिस तरह इंग्लैंड के उद्योगों को यूरोपीय संघ की सदस्यता से भारी लाभ हुआ है, हंगरी तथा पोलैंड के सस्ते श्रमिक मिले हैं तथा इंग्लैंड में निर्मित माल को वे यूरोपीय देशों में बेच सके हैं, उससे अर्थशास्त्र के अनुसार इंग्लैंड में उद्योगों को हुए लाभ से इंग्लैंड की सरकार को अधिक टैक्स मिलना चाहिए था, जिसका उपयोग इंग्लैंड की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकता था, लेकिन इंग्लैंड ने पाया कि उन्हें जो लाभ हुआ, उससे ज्यादा नुकसान हंगरी के रास्ते श्रमिकों के आने से हुआ है। इसी के परिणामस्वरूप इंग्लैंड ने यूरोपीय संघ से बाहर आने का फैसला किया।

मुझे लगता है कि इंग्लैंड द्वारा लिए गए निर्णय भारत के लिए सबक है, क्योंकि इंग्लैंड में आने वाले विदेशी निवेश में भारतीय उद्यमी तीसरे नंबर पर हैं, फिर भारत के आम आदमी को उससे तो कोई फायदा नहीं मिल रहा है। हमारे उद्यमियों द्वारा इंग्लैंड के उद्योगों को खरीदा जा रहा

है, जैसे टाटा ने कार निर्माता जैगुआर को खरीदा है जिससे टाटा को भले फायदा हो रहा हो, भारत के आम आदमी को तो उससे कोई लाभ नहीं मिलने को है। जिस प्रकार चीन में बना सस्ता माल भारत में प्रवेश कर चुका है और तमाम छोटे उद्योगों को चौपट कर चुका है, जिस प्रकार इंग्लैंड के कर्मी के रोजगार को हंगरी और पोलैंड के कर्मियों ने हड़प लिया है, उसी तरह असम, बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के कर्मियों के रोजगारों को बांग्लादेश और नेपाल के कर्मी हड़प रहे हैं।

इसलिए भारत की जनता भी मूलरूप से वैश्वीकरण से खुश नहीं है, यद्यपि अभी सरकारी प्रचार की खुमार इस सच्चाई को दबाए हुए है। भारत सरकार को चेतना चाहिए। 'मेक इन इंडिया' के ख्याली पुलाव से भारत के आम आदमी को ज्यादा समय तक भुलावे में नहीं रखा जा सकता। जो हश्र आज इंग्लैंड की वैश्वीकरण समर्थक सरकार को हुआ है, वह कल भारत की वैश्वीकरण समर्थक सरकार का अवश्य होगा।

(18) प्रश्न : जब चर्चा चली है वैश्विक स्तर पर हिंदी की स्थिति की तब लगे हाथ आपसे यह जान लें कि हिंदी की प्रगति और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने के लिए विश्व हिंदी सम्मेलन का क्या योगदान रहा? आपने न्यूयॉर्क में आयोजित आठवें विश्व हिंदी सम्मेलन में बिहार की ओर से सम्मिलित होकर उसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। 8वें सम्मेलन तक हिंदी की कितनी प्रगति हो पाई है और राष्ट्रसंघ में हिंदी को मान्यता दिलाने के प्रयास में सम्मेलन कहाँ तक आगे बढ़ा है? अपने संस्मरण में आपसे विस्तार से हम जानना चाहेंगे।

उत्तर : राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति मेरी निष्ठा और समर्पित भाव से इसकी सेवा की वजह से अमेरिका के न्यूयॉर्क में विगत 13-15 जुलाई, 2007 तक आयोजित 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन में मैं सम्मिलित हुआ, वरना आज के इस आपाधापी, पहुँच-पैरवी और राजनीति में चमचागिरि के दौर में मुझ सरीखे एक साधारण सामाजिक कार्यकर्ता व साहित्य सेवी को बिहार सरकार की ओर से भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल होकर विश्व हिंदी सम्मेलन में शामिल होने का मौका कहाँ से मिलता।

बिहार सरकार की ओर से विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने का पत्र

जब मिला, तो मैं दिल्ली में था और मेरी श्रीमति जी ने मुझे दूरभाष पर सूचना देते हुए पहली गाड़ी पकड़कर पटना आने का फरमान इसलिए जारी किया, क्योंकि मात्र एक सप्ताह का ही समय बच रहा था और इसी अवधि में मुझे पासपोर्ट और अमेरिकन वीसा भी प्राप्त करना था। खैर, पहली गाड़ी से पटना आया और बी. एन. कॉलेज पटना के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष तथा बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् के निदेशक के पद पर रहे प्रो. रामबुझावन बाबू को साथ लेकर पासपोर्ट लेने का प्रयास करने लगा। बिहार सरकार में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के शीर्ष अधिकारी के. डी. सिन्हा के सौजन्य से एक पत्र लेकर पासपोर्ट कार्यालय पहुँचा और दूसरे ही दिन पासपोर्ट लेने के बाद उसी दिन हम दोनों हवाई जहाज से दिल्ली पहुँचकर अमेरिकन वीसा प्राप्त करने के लिए विदेश मंत्रालय और अमेरिका के भारत स्थित राजदूत कार्यालय का चक्कर लगाने के बाद मात्र दो दिनों में ही हमदोनों को वीसा भी मिल गया और ब्रिटिश एयरवेज से लंदन पहुँचा और फिर वहाँ से दूसरे ब्रिटिश एयरवेज से न्यूयॉर्क पहुँच गया।

भारतीय विद्या भवन के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा न्यूयॉर्क में आयोजित 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन में बिहार सरकार की ओर से भारतीय प्रतिनिधि-मंडल में शामिल सात सदस्यों में प्रो. रामबुझावन बाबू के अलावा डॉ. वीणा रानी श्रीवास्तव, डॉ. किरण घई, प्रो. सुखदा पाण्डेय, प्रो. उषा, किरण खान तथा श्री जिया लाल आर्य थे।

न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के सभागार में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने अपने भाषण का अधिकांश वाक्य हिंदी में बोलकर यह संकेत दिया कि हिंदी को अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। जरूरत केवल इस बात की है कि भारत सरकार सभी समर्थ देशों से संपर्क स्थापित कर एक सघन अभियान चलाए और संयुक्त राष्ट्र की आगामी बैठक में मान्यता दिलाने हेतु सभी प्रक्रिया को पूरा करे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर तत्कालीन विदेश राज्यमंत्री आनंद शर्मा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में भी इसी आशय का संकेत दिया।

मैं इस मायने में अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि सम्मेलन के प्रथम दिन यानी 13 जुलाई, 2007 के अपराह्ण सत्र में फैशन इंस्टिच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सभागार में श्रीमति मृणाल पाण्डेय की अध्यक्षता तथा जनमत चैनल के श्री राहुल देव के संचालन में 'वैश्वीकरण, मीडिया और

हिंदी' विषय पर आयोजित परिचर्चा में मुझे भी अपना आलेख प्रस्तुत करने तथा परिचर्चा में भाग लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ।

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि न्यूयॉर्क में विश्वभर के हिंदी प्रेमियों ने एकत्रित होकर इस सम्मेलन को भारतवासियों के ललाट पर आत्मगौरव के प्रतीक चिह्न के रूप में सिद्ध किया और यह आयोजन हिंदी को समृद्ध बनाने एवं राष्ट्र संघ में हिंदी को मान्यता दिलाने में एक संकल्पवान कदम माना जाएगा। विश्वास है परायी भाषा और अँग्रेजी के वर्चस्व के नीचे दबी हमारी समस्त भारतीय भाषाओं के लिए मुक्ति का एक प्रकाश भी होगा यह सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में मैंने यह भी देखा कि प्रतिनिधियों द्वारा जहाँ अलग-अलग समूह में तस्वीर खिंचवाने की होड़ लगी थी, वहीं परिसर के आगे लगे एक प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प के एक पिस्तौल की नाल में एक गांठ लगी थी, जिससे इस बात का संकेत मिल रहा था कि हिंसा अब नहीं चाहिए। मेरा भी मानना है कि हिंसा सचमुच नहीं चाहिए, किंतु शर्त है कि पिस्तौल के नाल की गांठ कभी न खुले। मगर आपको याद होगा कि वह गांठ अभी अफगानिस्तान में खुल जाती है, तो कभी इराक, सीरिया व लेबनान तथा यमन में। हाँ, एक गाँठ यहाँ मुझे जरूर खुलती नजर आई, जो हिंदी को लेकर अबतक बनी हुई थी। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आठवें विश्व हिंदी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में इसके पहले कभी हिंदी की ऐसी गूँज सुनाई पड़ी होगी। इसलिए यह कोई विराम नहीं, बल्कि प्रस्थान बिंदु है।

हमें लगता है कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों व विभागों में हिंदी की बदहाली देखकर ही विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजकों के मन में यह ख्याल आया होगा कि सात समंदर पार विदेशों में जहाँ हिंदी बोली और समझी जाती है, वहीं इस आयोजन से शायद स्वदेश में हिंदी की दशा सुधर जाए। नागपुर से चलकर विश्व हिंदी सम्मेलन का आठवां पड़ाव न्यूयॉर्क में इस आशा के साथ पहुँचा कि हिंदी परदेश में सम्मानित होगी, तो भारत देश के लोगों के दिलों में हिंदी का खोया स्वाभिमान जाग उठेगा, मगर आठवें विश्व हिंदी सम्मेलन में पधारे भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को अँग्रेजी में बातचीत करते हुए जब मैंने देखा और सुना, तो सारी आशाओं पर पानी फिरता नजर आया। कारण कि चाहे उद्‌घाटन सत्र हो या शैक्षिक सत्र या होटल का परिसर प्रायः अधिकांश स्थलों पर यहाँ तक कि हवाई यात्रा करते समय अधिकतर प्रतिनिधियों को मैंने अँग्रेजी में बातचीत करते देखा। मुझसे रहा न गया, तो

कुछ लोगों को बातचीत के दौरान मैंने टोका भी और कहा, ''क्या आप हिंदी में बात नहीं कर सकते? आप हिंदी सम्मेलन में हिंदी को बढ़ावा देने के ख्याल से पधारे हैं।' देखा, उनकी भृकूटी मुझपर तन-सी गई, मगर चाहकर भी वे अपनी शर्मिंदगी छिपा न सके। अँग्रेजी बोलकर अपने वर्चस्व-स्थापना की उनकी रही-सही भावना भी जाती रही। दरअसल, ऐसे लोग हीन भावना से ग्रस्त होते हैं। यह उनकी बीमारी है जो अँग्रेजियत मानसिकता के चलते छूट न पा रही है और हम चाहकर भी हिंदी को अपने माथे की बिंदी नहीं बना पा रहे हैं।

सच तो यह है सरकारी खर्चे पर दुनिया के कल्पना-लोक की उड़ान का आनंद प्राप्त करना ही ऐसे सम्मेलनों में प्रतिनिधियों की भागीदारी को विशेष बना देता है और जिन लोगों ने जुगाड़-तुगाड़, सिफारिश और ऊँची पहुँच-पैरवी के बल पर यात्रा का टिकट लेकर वे उद्येश्यों को भूल गए और उद्‌घाटन सत्र में तस्वीर आदि खिंचवाने के बाद ही भारत से जाने वाले अधिकतर प्रतिनिधि न्यूयॉर्क और उसके आसपास के दर्शनीय स्थलों में हिंदी का भविष्य तलाशने निकल गए। यह तो कहिए कि अमेरिका और अन्य करीबी देशों के प्रवासी भारतीय और हिंदी प्रेमियों ने ही सभागार में अपनी उपस्थिति दर्ज कर भारतीय प्रतिनिधियों को जलालत से बचा लिया, कारण कि आठवें विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रवासी भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या करीब पाँच सौ से अधिक थी।

हमारी सांस्कृतिक पहचान और सांस्कृतिक अस्मिता की कोई सार्थकता है, तो विदेशों में बसे इन्हीं प्रवासी भारतीय समाज के चलते जिनके द्वारा हिंदी भाषा बोली जा रही है और जो संस्कृति उनके जरिए बरकरार है उसकी 'संवाहिका सेतु' के रूप में हिंदी ही है जिसे विश्व मंच पर रूपायित करने के लिए हम पिछले 32 वर्षों से विश्व हिंदी सम्मेलन करते आ रहे हैं। न्यूयॉर्क का आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन उसी सफर की एक कड़ी थी। भाषा और संस्कृति के बीच सीधा रिश्ता है इसलिए प्रयास हो कि भाषा की संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृति और भारतीय संस्कृति साथ-साथ चले।

(19) प्रश्न: अभी-अभी 32 साल बाद भारत के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 10 से 12 सितंबर, 2015 तक दसवां विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ। भाषा केंद्रित इस सम्मेलन के विषयों की चर्चा करते हुए हिंदी को संयुक्त राष्ट्र में मान्यता दिलाने के प्रयास में कहाँ तक प्रगति हुई? आपसे यह जानकारी चाहेंगे।

उत्तर: अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन के बाद जोहांसवर्ग में 9वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था जिसका विषय 'भाषा की अस्मिता और हिंदी का वैश्विक संदर्भ' था, किंतु इस सम्मेलन का रंग बहुत फिका बताया गया। फिर भोपाल में 10 सितंबर से 12 सितंबर, 2015 तक उसके लाल परेड ग्राउन्ड पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उद्घाटन से प्रारंभ हुआ। अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री ने अँग्रेजी, हिंदी और चीनी इन तीन भाषाओं को सबसे ज्यादा प्रभावी और तरक्की करती हुई बताया, मगर उद्घाटन-सत्र में ही उद्घोषिका ने बारह-तेरह भाषिक अशुद्धियाँ कीं। जबकि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस सम्मेलन को साहित्य-केंद्रित की जगह भाषा-केंद्रित कहा। इस सम्मेलन के आरंभ के पूर्व विदेश राज्यमंत्री वी. के. सिंह हिंदी लेखकों के संबंध में खाने-पीने को लेकर जो अशालीन बातें कहीं थीं, उसकी निंदा-भर्त्सना की गयी। पता नहीं क्यों श्रेष्ठ साहित्यकारों के लिए प्रसिद्ध शहर भोपाल के सम्मेलन साहित्य रहित, जीवन रहित, अनुभव रहित, विचार रहित लोगों से पटा था। पहली बार इस सम्मेलन में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल जैसी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों के अतिरिक्त राजनेताओं का जमावड़ा था, साहित्यकारों की संख्या कम थी। इससे यह सवाल खड़ा होता है कि क्या सरकार संस्कृति निष्ठ हिंदी की जगह बाजार निष्ठ हिंदी चाहती है? हिंदी बाजार की भाषा बनकर समृद्ध नहीं हो सकती भले ही व्यापक हो सकती है। हिंदी आज एशियाई बाजारों में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा बन गई है। अभिजात्य वर्ग हिंदी के नाम पर आँख-मुँह चाहे जितना सिकोड़ें, मगर हिंदी अपने सारे अपमान के बावजूद तेजी से बाजार पर कब्जा करती रही है। इसके लिए इंटरनेट और सोशल-मीडिया को धन्यवाद दिया जा सकता है। फेसबुक पर तो हिंदी का कब्जा है ही अँग्रेजीदां भी अपनी बात दूर-दूर तक पहुँचाने के लिए हिंदी बोल रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अपनी सरलता के कारण हिंदी की स्वीकार्यता विश्व में बढ़ी है। विश्व हिंदी सम्मेलन को लेकर स्वाभाविक ही अखिल भारतीय उल्लास बढ़ा है, लेकिन इसके साथ ही हमें हिंदी की मौजूदा जरूरतों के मद्देनजर विज्ञान आधारित और हिंग्लिश से मुक्त करने पर जोर दिया जाना चाहिए। इस मायने में दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन के दूसरे दिन 12 अलग-अलग विषयों पर दो चरणों में बारह शैक्षिक सत्रों में हिंदी के विद्वानों, साहित्यकारों और पत्रकारों ने इसी संदर्भ में अपनी बातें रखीं जो स्वागतयोग्य कही जाएँगी।

नागपुर के प्रथम सम्मेलन से भोपाल के दशवें हिंदी सम्मेलन तक आते-आते इसका सफर 40 वर्ष का हो गया है फिर भी हमारे देशवासियों और खासकर यहाँ के नौकरशाहों व नेताओं की अँग्रेजियत मानसिकता जस की तस है।

दरअसल, इन दिनों कला व साहित्य के क्षेत्र में पनप रही राजनीति का ही परिणाम है कि हिंदी की यह दुर्दशा देखी जा रही है। भारत में वर्षो की गुलामी और अँग्रेजियत मानसिकता का ही परिणाम है कि यहाँ पर स्वदेशी समस्या का विदेशी समाधान खोजा जाता है, विश्व हिंदी सम्मेलनों में हिंदी के भविष्य और भविष्य में हिंदी पर परिचर्चा भी ऐसी ही कवायद है जिसमें बीमारी जाने बिना चिकित्सा के प्रयास जारी हैं। सच तो यह है कि मिथ्याभिमान में हम भारत के लोग यह भूल बैठे हैं कि जब हम ही अपनी भाषा का तिरस्कार करेंगे, तो उसे गैर कहाँ तक सम्मान दे पाएँगे? संयुक्त राष्ट्र के कपाल पर कल हिंदी का तिलक लग भी जाए, तो क्या उसके अपने घर में माथे की बिंदी बनने में अभी बहुत वक्त नहीं लगेगा?

(20)प्रश्नःक्या डेढ़ साल में दूसरी बार अमेरिका की यात्रा पर गए भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वैश्विक मामलों में अपनी छाप मोड़ने में समर्थ हुए? यदि हाँ, तो किस बल के बूते?

उत्तरः हाँ, अपने डेढ़ साल के कार्यकाल में दूसरी बार अमेरिकी यात्रा पर गए भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी न्यूयॉर्क में अपना असर और छाप छोड़ने में कामयाब रहे। प्रधानमंत्री को न्यूयॉर्क में विभिन्न मंचों पर जिस तरह महत्ता मिली और वह अमेरिकी मीडिया का भी ध्यान खींचने में सफल रहे उससे सक्षम वैश्विक नेता के रूप में उनका उभार और पुख्ता हुआ है। निःसंदेह नरेन्द्र मोदी की इस कामयाबी के पीछे एक कारण यह भी है कि वह पिछले तीस वर्षो में भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बहुमत के बल पर केंद्रिय सरकार में सत्ता की बागडोर संभाली है। इसके अतिरिक्त कहीं न कहीं संपर्क और संवाद की उनकी शैली ने भी उनकी प्रभावशाली रूप में उभरने में मदद की है।

यह सामान्य बात नहीं कि जब चीन के राष्ट्रपति शी जिन पिंग भी अमेरिका में हों तब शीर्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शीर्ष अधिकारी भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात करने में विशेष रुचि दिखाई और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित सतत विकास सम्मेलन को संबोधित कर एक वैश्विक नेता की तरह से विश्व की समस्याओं को सुलझाने के तौर-तरीकों पर बात की

और सभी देशों के एकजुट होकर आगे आने की आवश्यकता जताई। इसके अतिरिक्त उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अन्य दावेदारों- जर्मनी, जापान और ब्राजील के शासनाध्यक्षों से मुलाकात की और एक बार फिर यह रेखांकित किया कि इस सुरक्षा परिषद् में सुधार क्यों आवश्यक हो गया है। उनकी इस पहल के परिणाम आने में वक्त तो लगेगा, लेकिन इसमें दो राय नहीं हो सकती कि विश्व के प्रमुख राष्ट्र मोदी की इस पहल की अनदेखी नहीं कर सकते।

(21) प्रश्न : दुनिया का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश होने के बाद भी भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता क्यों नहीं मिल पा रही है?

उत्तर : भारत न केवल संयुक्त राष्ट्र परिषद की स्थायी सदस्यता की हैसियत रखता है, बल्कि वीटो पाने की उसमें पात्रता भी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है। सवा अरब की आबादीवाले इस देश में अल्पसंख्यक धर्मावलंबियों के वही संवैधानिक अधिकार है, जो बहुसंख्यक हिंदुओं के हैं। भारत ने साम्राज्यवादी मंशा के दृष्टिगत कभी किसी दूसरे देश की सीमा पर अतिक्रमण नहीं किया, जबकि चीन ने न सिर्फ तिब्बत में अतिक्रमण किया है, बल्कि उसकी नस्लीय पहचान मिटाने में भी लगा है। चीन की विस्तारवादी नीति से पूरी दुनिया अवगत है। भारत भी उसकी इस नीति की चपेट में आ चुका है। भारत ने इसके ठीक विपरीत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भी अहम भूमिका निभाई है, फिर भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता हासिल करने में बाधा बने चीन की पेंच अपनी जगह बदस्तूर है।

यह अलग बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 70वें सत्र आते-आते सुरक्षा परिषद् में सुधार व विस्तार की माँग को औपचारिक विचार-विमर्श के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से मंजूर किया और भारत, जापान, जर्मनी व ब्राजील ने सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता के लिए मुहिम तेज की दी है, क्योंकि हाल के वर्षो में वैश्विक संघर्ष और संकट को देखते हुए ऐसा किया जाना पहले से अधिक जरूरी हो गया है।

यदि सुरक्षा परिषद् में बदलाव की खिड़कियाँ खुलती हैं, तो भारत सहित जापान, जर्मनी तथा ब्राजील जैसे कुछ देशों को स्थाई सदस्यता मिल सकती है। अभी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन तथा रूस को ही सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता के साथ महासभा द्वारा बहुमत के लिए निर्णय निरस्त

करने को भी अधिकार उसे प्राप्त है। यही विशेषाधिकार (वीटो) पाँच देशों की शक्ति से विभाजन नहीं होने दे रहा है। परिणामस्वरूप सुरक्षा परिषद् में जन्म से लेकर अब तक असमानता बनी हुई है।

(22)प्रश्न:आजादी के बाद से अबतक के समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति आपको कैसी नजर आ रही है?

उत्तर: आजादी के बाद से अबतक के समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति सबसे मजबूत नजर आ रही है। नि:संदेह यह कहने में मुझे कोई हिचक नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुनिया के सामने भारत का जो चित्र प्रस्तुत किया है उससे हर देशवासी का सिर गर्व से ऊँचा हो गया है। आतंकवाद को जड़ से उन्मूलन का सवाल हो अथवा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थाई सदस्यता का सवाल हो, प्रधानमंत्री ने जिस तार्किक ढंग से संयुक्त राष्ट्रसंघ के मंच से दुनिया के हर देश का समर्थन माँगा है वह काबिलेतारीफ कहा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कश्मीर का मुद्‌दा उठाते हुए भारत के विरूद्ध विषवमन कर जो परंपरागत और अपनी विकृत मानसिकता का परिचय दिया और बकवास किया, उसका जबाव भारत की ओर से कड़े शब्दों में स्पष्ट किया गया कि कश्मीर से सेना हटाने में नहीं, पाकिस्तान से आतंकवाद मिटाने में ही हल निहित है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को मजबूत ही नहीं कर रहे, बल्कि अब सशक्त भारत का लोहा पूरी दुनिया भी मानने लगी है। देश के अंदर भी इस बात को लोग स्वीकार कर रहे हैं कि इसकी अंतरराष्ट्रीय स्वीकारोक्ति भी तेजी से बढ़ती जा रही है।

हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की करिश्माई भाषण शैली, मिलनसारिता और देशभक्ति से ओत-प्रोत परदेशी सभाओं में जुटी अनिवासी युवा भारतीय भीड़ का जुनून क्या इस बात का प्रमाण नहीं कि आजादी के बाद भारत अब दुनिया में सबसे लोकप्रिय और तेजी से उभरता देश है?

(23) प्रश्न:ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होने के फैसले को आप कितना सही मानते हैं? इसके कितने गंभीर नतीजे हो सकते हैं? भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा?

उत्तर : ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होने के फैसले को हम कितना सही मानते हैं यह जानना उतना जरूरी नहीं है जितना कि यह जानना

कि ब्रिटिश समुदाय के लोग क्या चाहते रहे हैं। पिछले सात-आठ वर्षो से ब्रिटेन में विकास की रफ्तार ठहरी-सी है और लोग अपनी समस्याओं के लिए यूरोपीय समुदाय की नीतियों को जिम्मेदार मान रहे हैं। आखिर तभी तो ब्रिटेन के लोगों ने यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय वहाँ हुए जनमत संग्रह में लिया । ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की माँग को लेकर हुए जनमत संग्रह के नतीजे बता रहे हैं कि बड़े शहरों के लोगों ने यूरोपीय संघ में बने रहने के पक्ष में मत व्यक्त किए। करीब 75 प्रतिशत युवा भी इसी विचार के समर्थन में आगे आए, लेकिन छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, खासकर कामगारों ने इसके खिलाफ वोट दिया। यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा स्काटलैंड के लोगों ने यूरोपीय संघ के पक्ष में मत दिए। दरअसल, ब्रिटेन में एक भाव गहरा रहा था कि अन्य देशों के नागरिकों के कारण आम ब्रिटिश नागरिकों की आर्थिक तरक्की रूक गई है। जनमत संग्रह का नतीजा सामने आने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने यह कहते हुए त्यागपत्र देने की घोषणा की कि अलगाव की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए नए नेतृत्व की जरूरत है।

जहाँ तक ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होने के नतीजे का सवाल है इसकी एक झलक तो जनमत संग्रह का फैसला आने वाले दिन ही मिल गई। जैसे ही यह खबर आई कि ब्रिटेन के लोगों ने यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय लिया है, पूरी दुनिया के शेयर बाजार गिर गए जिससे एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर के निवेशकों को करीब दो खरब डॉलर का नुकसान हुआ। ब्रिटेन विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था में है और वहाँ होने वाला कोई भी परिवर्तन दुनिया भर में असर डालेगा। जहाँ तक भारत का संबंध है यहाँ की अर्थव्यवस्था की जड़ें गहरी और मजबूत होने की वजह से वे इस घटनाक्रम को सहन कर सकती है। भारत के अर्थशास्त्रियों को भी विश्वास है कि ब्रिटेन के निर्णय से उपजी आर्थिक उथल-पुथल से देश की अर्थव्यवस्था उबर जाएगी, क्योंकि एक तो भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है इसलिए दुनिया भर के निवेशकों का रूख भारत की ओर है और दूसरे यह कि ब्रिटेन के साथ भारत के आर्थिक रिश्ते पहले से मजबूत हैं। हाँ, इतना जरूर है कि भारतीय कंपनियों को यूरोपीय देशों में नए सिरे से अपने लिए जगह बनानी होगी।

ब्रेक्जिट यानी इंग्लैंड के यूरोपियन यूनियन (इयू) से बाहर आने के बाद वहाँ के उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। पिछले दशक में इंग्लैंड के

उद्योगों को यूरोपीय संघ की सदस्यता से भारी लाभ हुआ है। उन्हें हंगरी तथा पोलैंड के सस्ते श्रमिक मिले हैं तथा इंग्लैंड में निर्मित माल को वे यूरोपीय देशों में बेच सके हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार, इंग्लैंड में उद्योगों को हुए लाभ से इंग्लैंड सरकार को अधिक टैक्स मिलना चाहिए था, जिसका उपयोग इंग्लैंड की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकता था। इसे 'ट्रिकल डाउन' यानी रिसाव की थ्योरी कहते हैं। इंग्लैंड ने पाया कि ट्रिकल डाउन से उन्हें जो लाभ हुआ, उससे ज्यादा नुकसान हंगरी के रास्ते श्रमिकों के आने से हुआ है। इसलिए उन्होंने यूरोपीय संघ से बाहर आने का निर्णय लिया है। दरअसल, वैश्वीकण बड़ी कंपनियों को अधिक लाभ पहुँचाता है और आम आदमी को बहुत ही मामूली लाभ। इंग्लैंड द्वारा लिए गए निर्णय भारत के लिए सबक है, क्योंकि इंग्लैंड के उद्योगों की तरह हमारे देश के उद्योग भी वैश्वीकरण से लाभान्वित हुए हैं। हमारे उद्यमियों द्वारा इंग्लैंड के उद्योगों को खरीदा जा रहा है, जैसे टाटा ने कार निर्माता जैगुआर को खरीदा है। इंग्लैंड में आने वाले विदेशी निवेश में भारतीय उद्यमी तीसरे नंबर पर हैं, फिर भारत के आम आदमी के लिए वैश्वीकरण घाटे का सौदा है। चीन में बना सस्ता माल भारत में प्रवेश कर रहा है और हमारे तमाम छोटे उद्योगों को चौपट कर चुका है। जिस तरह इंग्लैंड के कर्मी के रोजगार को हंगरी के कर्मियों ने हड़प लिया है, उसी तरह असम, बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के कर्मियों के रोजगारों को बांग्लादेश एवं नेपाल के कर्मी हड़प रहे हैं। इसलिए भारत की जनता भी मूल रूप से वैश्वीकरण से खुश नहीं है, यद्यपि अभी सरकारी प्रचार का खुमार इस सच्चाई को दबाए हुए है।

भारत सरकार को चेतना चाहिए। मेक इन इंडिया के ख्याली पुलाव से भारत के आम आदमी को ज्यादा समय तक भुलावे में नहीं रखा जा सकेगा। जो हश्र आज इंग्लैंड की वैश्वीकरण समर्थक सरकार का हुआ है, वह कल भारत की वैश्वीकरण समर्थक सरकार का अवश्य होगा।

हालांकि यूरोपीय संघ से ब्रिटेन का अलग होने की प्रक्रिया पूरी होने में दो साल लगेंगे, क्योंकि जब आखिरी वक्त में ऐसा होगा, तब लाखों ब्रिटिश नागरिक स्वदेश लौटेंगे और यूरोपीय संघ के लाखों लोग ब्रिटेन छोड़ेंगे। 1957 में स्थापित यूरोपीय संघ की 43 साल बाद सदस्यता छोड़ने के बाद ब्रिटेन ने अपने लिए निश्चित ही मुश्किल रास्ता चुना है। राजनीतिक स्थिरता के बावजूद अर्थव्यवस्था कमजोर होने के भय से वहाँ के लोगों को बड़ा फैसला

लेने पर मजबूर किया। सबसे मुश्किल सवाल यह है कि अकेले आगे बढ़ने की चुनौतियों का सामना ब्रिटेन कैसे कर पाएगा, खासतौर पर तब जब हाल के वर्षो में प्रधानमंत्री के पद से सशक्त डेविड कैमरन भी त्यागपत्र दे चुके हैं। ऐसे में ब्रिटेन खुद को कैसे बनाए रखेगा, यह एक बड़ा सवाल है।

कहानियों से भरे इतिहास का देश ब्रिटेन को संवैधानिक सरकार, वैश्विक साम्राज्य, शाही जलसा और फासीवाद की खिलाफत देखने को मिली है। अज्ञात देश में प्रवेश कर रहे ब्रिटेन को वर्तमान हालात को देखते हुए अनुमान है कि कई साल बीत जाएँगे नई चीजों को सीखने व संभालने में। उधर चीर असंतुष्ट उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड ने भी दबे सुरों में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का पुराना साथ छोड़ बतौर स्वायत्त गणतंत्र अपनी यूरोपीय संघ (ईयू) की सदस्यता कायम रखने पर जनमत संग्रह करवाने का तराना फिर छेड़ दिया है।

(24) प्रश्न : ब्रिटेन तथा भारत के संविधान में जनमत संग्रह का प्रावधान नहीं होते हुए भी दोनों देशों में जनमत संग्रह को इतना महत्व दिए जाने का कौन सा कारण है?

उत्तर : ब्रिटेन में जनमत संग्रह के बाद प्रधानमंत्री डेवीड कैमरीन ने यूरोपीय संघ से अलग होने के साथ ही प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र देने की घोषणा की। अब सवाल उठता है कि ब्रिटेन के संविधान में जनमत संग्रह का कोइ प्रावधान नहीं होते हुए भी डेविड कैमरीन ने यूरोपीय संघ से अलग होने का इतना बड़ा फैसला क्यों लिया?

दरअसल, लोकतंत्र में जनमत संग्रह का बड़ा वजन होता है और उसके विरूद्ध जाने का साहस प्राय: किसी में नहीं होता, क्योंकि जनमत संग्रह लोकतंत्र के प्रारंभिक स्वरूप का अवशेष है। आज की तिथि में केवल स्वीटजरलैंड ही ऐसा देश है, जहाँ अभी भी जनमत संग्रह के रूप में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अवशेष मिलते हैं अर्थात यदि संविधान का संशोधन करना हो, तो उसके लिए जनमत संग्रह अनिवार्य है। वैसे तो भारतीय संविधान में भी जनमत संग्रह का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इसका यह आशय नहीं कि सरकार किसी संवेदनशील मुद्‌दे पर जनता की राय न ले सके। ब्रिटेन इसका ज्वलंत उदाहरण है। ब्रिटिश संविधान में जनमत संग्रह का कोई प्रावधान नहीं, लेकिन हेराल्ड विलसन सरकार ने 1975 में ब्रिटेन में पहला जनमत संग्रह इस बात पर करवाया था कि ब्रिटेन को यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में रहना है या नहीं। उसके लिए उनको पहले संसद से रेफरेंडम एक्ट, 1975

पारित करवाना पड़ा। अभी-अभी डेविड कैमरीन को भी यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए पिछले वर्ष संसद से यूरोपियन यूनियन रेफोरेंडम एक्ट 2015 पारित करवाना पड़ा।

सच तो यह है कि ऐसे जनमत संग्रह का महत्व इसलिए है, क्योंकि जनमत संग्रह का परिणाम केवल जनता का मूड जानने का एक साधन है, वह सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं। प्रधानमंत्री कैमरीन यदि चाहें तो जनमत संग्रह के परिणाम की उपेक्षा कर संसद में पुनः इस पर निर्णय के लिए जा सकते हैं।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में संघ, राज्य या स्थानीय सरकारों को किसी विषय पर जनमत संग्रह कराने की बाध्यता तो नहीं, लेकिन यदि कोई सरकार किसी विषय पर दलगत दृष्टिकोण से अलग हटकर जनता की राय जानना चाहे तो उसकी कोई मनाही भी नहीं। जैसे हाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के सवाल पर अपने ट्विट में जनमत संग्रह कराने की बात की।

(25)प्रश्नः चीन के मैदानी बंदरगाह गैरांग से नेपाल तक रेलवे लाइन बिछाने के चीन का प्रस्ताव क्या आर्थिक कारणों से है या आर्थिक से ज्यादा राजनयिक?

उत्तरः चीनी अधिकारी ने तिब्बत से नेपाल होते हुए भारत तक हिमालय के आर-पार रेललाइन बिछाने का जो प्रस्ताव दिया है वह आर्थिक से ज्यादा राजनयिक है, क्योंकि भले ही इस प्रस्ताव पर व्यापार और वाणिज्य की चासनी चढ़ी हुई है, मगर मुझे लगता है कि चीन के मैदानी बंदरगाह गैरांग से नेपाल तक रेलवे लाइन बिछाने का यह प्रस्ताव नेपाल के साथ भारत के राजनयिक संबंधों को साधने के लिए है, क्योंकि अमेरिकी परमाणु करार से लेकर एनएसजी (न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप) तक भारत का विरोध करने वालों और समय-समय पर घुसपैठ करने वाला चीन अगर भारत का हित जताते हुए कोई प्रस्ताव रख रहा है, तो स्पष्ट तौर पर इसमें उसका ज्यादा स्वार्थ हो सकता है। वह स्वार्थ तिब्बत को चीन और दक्षिणी एशिया का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाते हुए उस समस्या के अंतरराष्ट्रीय पहलू की हवा निकालने का भी है। चीन के अधिकारी ने दावा किया है कि उसने जिस गौरांग बंदरगाह से नेपाल तक रेल बिछाने का समझौता नेपाल के निवर्तमान प्रधानमंत्री के. पी. ओली के चीन के तरफ झूकते हुए किया गया था जिसकी स्थिति ल्हासा के मुकाबले ज्यादा सुविधाजनक है। वह समुद्र तल

से ल्हासा की तुलना में एक हजार मीटर कम ऊँचाई पर है। रेलवे स्टेशनों की ऊँचाई के इन आँकड़ों में दरअसल चालाक राजनय छुपा हुआ है। भारत को चीन के इस प्रस्ताव पर खूब सोच-विचार कर ही कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिए।

(26)प्रश्नः क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत ने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम की सदस्यता लेने में जल्दबाजी कर दी या इसने अति उत्साह में ऐसा कर दिया? क्या इस अति उत्साह में भारत के इंटर कांटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम की बलि नहीं चढ़ गयी?

उत्तरः हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने एमसीटीआर(मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम) की सदस्यता लेने में जल्दबाजी कर दी, क्योंकि एमसीटीआर के सदस्य देश 300 किमी की रेंज से ज्यादा और 500 कि.ग्रा. से अधिक भार के मिसाइल नहीं बना सकते, यानी भारत अब हजारों किमी की रेंजवाले इंटर कांटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (आइसीबीएम) नहीं बना सकेगा।

अमेरिका, इजरायल और रूस के बाद भारत अब दुनिया का चौथा देश है, जिसके पास मिसाइल रक्षा कवच प्रणाली है। पिछले साल 2015 की शुरुआत में 'अग्नि-पाँच' मिसाइल परीक्षण की सफलता को देख कर पाकिस्तान और चीन में घबराहट थी कि भारत की मारक क्षमता बढ़ती जा रही है। 'डीआरडीओ' में आर्मामेंट रिसर्च बोर्ड के अध्यक्ष एस. के. सालवान ने अप्रैल, 2016 में बयान दिया था कि अगली तैयारी 10 हजार की.मी. तक मार करने वाली अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण की है। इस बयान से अमेरिका और यूरोपीय देशों के कान खड़े हुए थे। भारत से 16 हजार कि.मी. की दूरी पर बसा अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि एशिया में चीन की तरह एक और शक्ति 'इंटर कांटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल' की ताकत के साथ खड़ी मिले। इसे देखते हुए अमेरिका की भी यह कोशिश रही कि उसके पहले भारत को 'एमसीटीआर' की सदस्यता के बहाने नकेल पहना दी जाए। इसलिए 'एमसीटीआर' की सदस्यता के लिए भारत को थोड़ा और रूकना चाहिए था, मगर अतिउत्साह में भारत के 'आइसीबीएम' कार्यक्रम की बली चढ़ गयी। कम-से-कम भारत को एमसीटीआर की सदस्यता लेने से बचना चाहिए था जिसके बारे में डीआरडीओ में आर्मामेंट रिसर्च बोर्ड के अध्यक्ष एस के सालवान ने बयान दिया था, ताकि 10 हजार किमी तक मार करने वाली अंतरमहाद्विपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण

की जा सके। सच तो यह है कि चीन और पाकिस्तान की भी भारत एमसीटीआर की सदस्यता में दिलचस्पी नहीं दिखाने की मुख्य वजह भी यही है। इजरायल, रोमानिया, स्लोवाक रिपब्लिक, *पाकिस्तान*, चीन, उत्तर *कोरिया* ने एमसीटीआर की सदस्यता अबतक नहीं ली है और पिछले एक दशक में इन देशों ने लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज बढ़ायी है। अमेरिका के पास 13 हजार किमी की दूरी तक की अंतरद्विपीय बैलिस्टिक मिसाइल हैं। इसी प्रकार रूस के पास भी अधिकतम 12,600 कि.मी. की रेंज का मिसाइल है।

(27) प्रश्न : इसरो के भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा वर्ष 2016 में एक साथ किए गए बीस उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण को आप किस दृष्टि से देखते हैं?

उत्तर : भारत अपनी बुद्धि और कौशल के लिहाज से दुनिया का एक ऐसा उदीयमान देश है जिसके इसरो के वैज्ञानिकों ने विगत 2016 में एक साथ बीस उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण करके पूरी दुनिया को यह जता दिया है कि यदि हम धर्म और जाति के आधार पर बने आपसी मतभेद भुलाकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम करेंगे, तो हमारी समृद्धि और सफलता को कोई रोक नहीं सकता। दरअसल, सैंतालिस साल पहले बने इसरो ने डॉ. विक्रम सारा भाई जैसे महान वैज्ञानिकों के उस सपने की लंबी छलांग दी है, जो उन्होंने कभी एक गरीब और विकासशील देश के लिए संकोच के साथ देखा था। आखिरकार इंतजार पूरा हुआ और हमारे ध्रुवीय रॉकेट मिशन (पीएसएलवीसी -34) ने हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफल उड़ान भरी और इसी के साथ उसने एक साथ 20 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण करके एक अभिनव रिकार्ड बना दिया। हालांकि रूस ने 2014 में एक साथ 37 उपग्रह लांच किए थे, लेकिन उसने आठ साल पहले गर्व के साथ बनाए गए अपने ही रिकार्ड को पुराना करते हुए यह जता दिया है कि वह मंजिल भी दूर नहीं है।

अब हमारी ध्रुवीय रॉकेट की प्रौद्योगिकी परिपक्व हो चुकी है और इसकी विश्वसनीयता ही वह आधार है कि दूसरे राष्ट्र भी हमसे प्रक्षेपण कराते हैं। आखिर तभी तो 28 सितंबर, 2015 को भारतीय उपग्रह एस्टोसैट के साथ ही 13 अमेरिकी उपग्रह, दो कनाडा के उपग्रह और जर्मनी व इंडोनेशिया के एक-एक उपग्रहवाले इस ध्रुवीय रॉकेट अभियान (मिशल पीएसएल-सी-34) में भारत के दो विश्वविद्यालयों के दो छात्र उपग्रह लांच

किए गए। इससे दुनिया देख रही है कि नासा जैसे संस्थानवाला देश अमेरिका भी हम पर भरोसा कर रहा है और हमारे साथ सहकार कर रहा है जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बधाई के पात्र इसलिए हैं, क्योंकि उनमें देश की तरक्की का वैसा ही जज्बा है जैसा आजादी की पीढ़ीवाले नेताओं में था।

अब इसरो अपने आप में एक महाशक्ति देशवाली संस्था बन गया है। उसकी रॉकेट प्रणाली दुनिया भर में अद्वितीय है। जैसे-जैसे उसकी विश्वसनीयता बढ़ रही है, भारत का भी कद बढ़ रहा है। इससे इसरो की कामर्सियल इकाई 'एंट्रिक्स' ने न केवल करीब 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर की कमाई की है, बल्कि अरबों डॉलर के अंतरिक्ष प्रक्षेपण बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकेगा और विश्व में भी धमक बढ़ेगी। आज की वैश्विक परिस्थिति में ऐसी उच्च तकनीकी आत्मनिर्भरता अलग मायने रखती है। अचरज नहीं होगा कि यदि इसरो जल्द ही अपने क्रायोजेनिक इंजन के बूते देश की धरती से अंतरिक्ष में भारतीय यात्री भेजने में भी सफल होता नजर आए।

(28) प्रश्न : भारतीय कूटनीतिक दृष्टि से भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पिछले जून, 2016 में हुई छह दिनों में पाँच देशों की यात्रा को आप किस रूप में आँकते हैं? खासतौर पर मोदी की चौथी अमेरिकी यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही?

उत्तर : भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विगत जून, 2016 के छह दिनों में अमेरिका, अफगानिस्तान, मैक्सिकों, स्वीट्जरलैंड और कतर पाँच देशों की यात्रा की। नरेन्द्र मोदी की दो साल में चौथी अमेरिकी यात्रा को इस मायने में ऐतिहासिक कहा जाएगा, क्योंकि इस दौरान वह अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को एक नई ऊँचाई तक ले गए। आपको याद होगा जिस अमेरिकी संसद एक समय उनके अमेरिका प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी उसने ही बतौर भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को न केवल मंत्रमुग्ध होकर सुना बल्कि अभूतपूर्व तरीके से मोदी की सराहना की। यह सामान्य बात नहीं कि उनके भाषण में 66 बार सांसदों द्वारा तालियाँ बजाई गईं और आठ बार उन्होंने खड़ा होकर उनका अभिवादन किया। यही नहीं अमेरिकी सांसदों में नरेन्द्र मोदी का ऑटोग्राफ लेने की होड़ दिखी। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उनकी करीब आधा दर्जन बार की मुलाकातों ने दोनों देशों के रिश्तों में जबरदस्त गर्माहट पैदा की। वैसे तो मोदी अमेरिकी संसद को संबोधित करने वाले पाँचवे भारतीय प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रभाव के लिहाज से सबसे ऊपर

माने जाएँगे। उल्लेख्य है कि अमेरिकी संसद में मोदी के संबोधन के अगले ही दिन अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवाद से बाज आने की चेतावनी दे डाली।

छह दिनों में पाँच देशों के दौरे में प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी में भारत के प्रवेश की मजबूत जमीन तैयार करना रही। एनएसजी में भारत के प्रवेश को जिस तरह स्वीट्जरलैंड और अमेरिका के बाद मैक्सिको ने भी समर्थन दिया। वह मोदी की उच्चस्तरीय कूटनीतिक दृष्टि का प्रमाण है। उन्होंने आतंकवाद से लेकर पर्यावरण तक की भी चर्चा की। यह भारतीय कूटनीति की कामयाबी ही है कि भारत अपने पुराने मित्र रूस के साथ संबंधों का सामान्य रखते हुए अमेरिका के साथ नजदीकी कायम रखने में सफल है।

(29)प्रश्न : आधुनिक युग में भी वैश्विक स्तर पर सामंती युग की गुलामी का मौजूद होना क्या निहायत शर्मनाक नहीं है? दुनिया के साथ-साथ भारत को भी ऐसी आधुनिक दासता पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या आप कड़े कानून बनाने की जरूरत महसूस करते हैं?

उत्तर : ऑस्ट्रेलिया की मानवाधिकार समूह वाक फ्री फाउन्डेशन द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक गुलामी सूचकांक-2016 की रिपोर्ट के अनुसार आधुनिक युग में भी सामंती युग की गुलामी मौजूद है। यह रिपोर्ट खुलासा करती है कि एक ओर जहाँ दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों समेत चार करोड़ 58 लाख लोग आधुनिक गुलामी की गिरफ्त में हैं, वहीं दूसरी ओर भारत में बंधुआ मजदूरी, वैश्यावृत्ति और भीख माँगने वालों की संख्या एक करोड़ 83 लाख 50 हजार बतायी गई है। यानी दुनिया में चार करोड़ से अधिक दासता का जीवन जीने वाले लोगों के तकरीबन आधे भारत में हैं। गौरतलब है कि वैश्विक दासता सूचकांक में 167 देशों की गणना में पाँच शीर्ष देश एशिया के हैं। इनमें उत्तर कोरिया गुलामी की व्यापकता में अव्वल है जहाँ आबादी का 4.37 फीसदी आधुनिक गुलामी की गिरफ्त में है।

चीन में 33 लाख 90 हजार, पाकिस्तान में 21 लाख तीस हजार, बांग्लादेश में 15 लाख तीस हजार और उज्बेकिस्तान में 12 लाख तीस हजार लोग गुलामी के शिकार हैं। थाइलैंड, म्यामार, लक्जमबर्ग, नार्वे, बेल्जियम, कनाडा, अमेरिका, स्वीडन व ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में गुलामी का कम आकलन किया गया है। इस गुलामी सूचकांक में कर्जग्रस्त बंधुआ मजदूर, जबरन विवाह, मानव तस्करी, खरीद फरोख्त के लिए अपहरण, वेश्यावृत्ति के

लिए कैद जीवन, बिना वेतन मजूदरी और घरेलू नौकरी में शोषण जैसी गतिविधियों को शामिल किया गया है।

गुलामी शब्द आजाद भारत में एक विदेशी उपनिवेश का संकेत देता है। इस लिहाज से देखा जाए तो उपर्युक्त रिपोर्ट में दासता शब्द का जो भाव लिया गया है वह भारत जैसे देश में बढ़ती बंधुआ, इंट भट्टों, राइस मिल्स, कृषि और जरी की फैक्ट्रियों में जो जबरन लोगों से काम कराया जाता है उसी वजह से इसे गुलामी की संज्ञा दी गई है। इसलिए यह निहायत शर्मनाक है।

देश की इस समस्या से जुड़े कानूनों की ही कमजोरी है कि देश में बड़ी संख्या में महिलाओं व बच्चों से बंधुआ मजदूरी कराने तथा उनपर होने वाली हिंसा की खबरें आए दिन सुनने व समाचार पत्रों में पढ़ने को मिल रही हैं। शर्म की बात है कि भारत के कुपोषित लोगों में औरतें और बच्चे ही अभी भी इसके अधिक शिकार हैं।

संयुक्त राष्ट्र की 2015 की मानव विकास रपट में भी भारत को दुनिया के 186 देशों में 130वें पैदान पर रखा गया है। यह हाल तब है जब भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से प्रगति की ओर अग्रसर है और आर्थिक विकास भी अपनी गति पकड़ रहा है। इसके बावजूद विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कुल गरीब लोगों में से एक तिहाई केवल भारत में ही रहते हैं। देश में लगातार बढ़ती सामाजिक-आर्थिक असमानता समाज के कमजोर वर्गों में अनेक प्रकार की वंचनाओं को जन्म दे रही है। देश की एक बड़ी आबादी आज भी न्यूनतम मजदूरी, बुनियादी जरूरतों तथा मालिकों से अच्छे बर्ताव से महरूम है। साथ ही वह असंगठित रूप से बेहद अमानवीय हालातों में काम करने को भी विवश हैं जिसका मुख्य कारण गरीबी तो है ही, देश की कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार भी जवाबदेह है। समाज का कमजोर व गरीब तबका अभी भी जीवन जीने की न्यूनतम से वंचित हो रहा है। इसलिए दुनिया के साथ-साथ भारत को भी ऐसी आधुनिक गुलामी पर प्रतिबंध लगाने के लिए कड़े कानून बनाने की जरूरत है।

(30) प्रश्न : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले जून, 2016 में पाँच देशों की अपनी छह दिनी यात्रा में से दो दिन मात्र 20 लाख की आबादी और राजशाहीवाले देश कतर की यात्रा को आखिर क्यों अहमियत दी?

उत्तर : पिछले जून, 2016 में सवा अरब की आबादीवाले देश के

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पाँच देशों की अपनी छह दिनी यात्रा में से दो दिन की यात्रा मात्र बीस लाख की आबादी और राजशाहीवाले कतर देश की यात्रा को अहमियत दिए जाने का कई मायने में महत्व रखता है। दरअसल, कतर प्राकृतिक गैस भंडार के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है और पिछले साल 2015 में भारत के कुल तरल प्राकृतिक गैस आयत का 65 प्रतिशत कतर से ही आया था, इसलिए मामला पारंपरिक निर्भरता का भी बनता है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा चाहिए और इसमें कतर से बना सौहार्दपूर्ण संबंध सहायक हो सकता है। अपने विशाल प्राकृतिक गैस तथा तेल भंडार की वजह से कतर दुनिया के सर्वाधिक धनी देशों में शुमार है और इसी कारण उसके पास दुनिया का 15वां सबसे बड़ा 256 अरब डॉलर 'सॉवरन फंड' है। व्यापार अधिशेष और प्रचुर विदेशी मुद्रा भंडार की बदौलत बना सरकारी नियंत्रणवाला यह 'सॉवरन फंड' 'मेक इन इंडिया' के नारे से झांकने वाले विजन की पूर्ति के लिहाज से महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री के कतर दौरे की सफलता भी इन्हीं दो तथ्यों से जुड़ी है।

एक तो इस दौर के बाद तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के आयात में कतर की तरफ ज्यादा विश्वास भरी नजरों से देख सकता है, दूसरे कतर से हुए द्विपक्षीय समझौते के मुताबिक अगले कुछ सालों में बुनियादी ढाँचे की बहुत सी परियोजनाओं में 'सॉवरन फंड' के जरिए निवेश की उम्मीद कर सकता है। भारत अरब मूल्कों को अपने नवनिर्माण में मुख्य भागीदार मान कर चल रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के पास कतर से भी ज्यादा 800 अरब डॉलर का 'सॉवरन फंड' है और उसने वादा किया है कि भारत के बुनियादी क्षेत्र में अगले कुछ सालों में 75 अरब डॉलर का निवेश करेगा। निवेश को सुगम बनाने के लिए कस्टम और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से भी समझौते हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कतर के राष्ट्राध्यक्ष तमिम बिन हमाद अल थानी और व्यापारियों को अपने इस संदेश पर सफलता हासिल की है कि 'भारत संभावनाओं का देश है' और दोनों देश व्यावसायिक जमीन पर इन संभावनाओं का अपने-अपने हक में लाभ उठा सकते हैं।

(31) प्रश्नः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मई, 2016 में हुई ईरान की दो दिवसीय यात्रा को आप किस रूप में आँकते हैं?

उत्तर : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मई, 2016 में हुई ईरान की दो दिवसीय यात्रा से ईरान और भारत के संबंध कई तरह के द्वार खुलता है।

ईरान का रवैया प्रचलित इस्लामी आतंकवाद से हमेशा विरोध कर रहा है। शिया बहुल होने के नाते ही नहीं, पुरानी सांस्कृतिक विरासत की भी वजह से ईरान का रवैया पाकिस्तान और अरब देशों से अलग रहा है। इस ख्याल से हमारे संबंधों के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत और हमारी व्यापक सामरिक भागीदारी में एक नए आयाम का पूरा भरोसा है।

प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान ईरान के साथ 12 समझौते हुए, जो भारत के लिए मील का पत्थर है। अमेरिका की टेढ़ी नजर के बावजूद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ईरान यात्रा ने भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। ईरान के साथ हुए विभिन्न समझौतों खासकर चाबहार पोर्ट समझौते से भारत को बहुत सारे फायदे होंगे। इसके जरिए ग्वादर पोर्ट के आसपास जारी चीन और पाकिस्तान की नयी कूटनीतिक इतिहास में जुड़े इस अध्याय से चीन और पाकिस्तान की कूटनीतिक चालों का जवाब दिया जा सकेगा। दरअसल, चीन द्वारा पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट को विकसित करने की वजह उसके दूरगामी हित हैं और वह अपने प्रभाव को खाड़ी क्षेत्रों में भी बढ़ाना चाहता है, लेकिन चाबहार समझौते से अब भारत और ईरान के बीच व्यापार में आसानी होगी तथा भारत की व्यापारिक पहुँच मध्य एशियाई देशों तक हो जाएगी जो भारत के लिए फायदेमंद साबित होंगे। इससे चीन के भारी समर्थन से तैयार हो रहे पाकिस्तान के ब्लूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह से ही गुजरने की न केवल मजबूरी खत्म होगी, बल्कि बरास्ते ईरान हमारे लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों से भी आवाजाही आसान हो जाएगी। इससे हमें पाकिस्तान के रास्ते जाने की जरूरतें खत्म हो जाएँगी। अगर समुद्री पाइपलाइन भी बिछा दी जाती है, तो हमें ईरान से गैस की आपूर्ति सीधे मिल जाएगी। चीन की इस महाद्वीप में बढ़ती आकांक्षाओं पर भी कुछ काबू पा सकेंगे। इससे भी बड़ा फायदा यह होगा कि विश्व बिरादरी में हमें पाकिस्तान के बरक्स ईरान का समर्थन हासिल होगा। अफगानिस्तान के मौजूदा शासक भी इसके लिए भारत और ईरान की ओर ज्यादा झुक रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से उन्हें तालिबानी खतरों की ज्यादा आशंका है। वैसे भी फारस से हमारे पुराने सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं और अब वे फिर मददगार साबित हो रहे हैं।

इसी संदर्भ में मैं आपको यह भी बता दूँ कि दशकों से ईरान अपने पूर्व में स्थित दक्षिण एशिया में ऊर्जा के बाजार में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश में रहा है, लेकिन राजनीतिक तनाव, अंतरराष्ट्रीय दबाव

और सुस्त नौकरशाह की वजह से अनेक बड़ी परियोजनाएँ अधर में लटकी रही हैं। इनमें पाकिस्तान होते हुए भी भारत तक 1700 मील लंबी गैस पाइपलाइन परियोजना भी है, जिसकी बनने की संभावना निरंतर क्षीण होती जा रही है।

बहरहाल, उपर्युक्त बातों के मद्देनजर भारत और ईरान दोनों देशों की जरूरतें इन समस्याओं पर भारी पड़ी हैं। ईरान का अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से मुक्त होने के बाद अपने गैस और तेल के लिए बाजार खोजना है और भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने तथा बढ़ते मध्य वर्ग के चैन के लिए तेल चाहिए। दोनों देशों ने पश्चिमी देशों द्वारा प्रतिबंध हटाए जाने से काफी पहले से अधिक सहयोग के लिए प्रयास शुरू कर दिया था। उस समय ईरान कच्चे तेल का भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था। प्रतिबंध के दौरान अमेरिकी विदेश विभाग की छूट के कारण भारत ईरान से तेल खरीद सकता था, किंतु वित्तीय लेन-देन की कठिनाइयों की वजह से आपूर्ति में कमी आई। अब प्रतिबंध हटने के बाद तेल की आपूर्ति में निरंतर वृद्धि होती जा रही है।

एक और बात काबिलेगौर है कि भारत के कांडला बंदरगाह चाबहार बंदरगाह की दूरी मुंबई और दिल्ली के इतना ही है। वस्तुतः चाबहार बंदरगाह के तैयार हो जाने के बाद भारत और ईरान के जहाजों को पाकिस्तान की ओर से नहीं जाना पड़ेगा। इससे भारत के जहाज सीधे अफगानिस्तान पहुँच सकेंगे। ईरान और अफगानिस्तान तक सीधी पहुँच से भारत आर्थिक एवं सामरिक दृष्टि से उस क्षेत्र में काफी मजबूत हो जाएगा। पाकिस्तान ने आज तक भारत के उत्पादों को सीधे अफगानिस्तान और उसके आगे जाने की इजाजत नहीं दी है। चाबहार बंदरगाह के बन जाने के बाद भारत को उसकी किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होगी। दरअसल, नरेन्द्र मोदी की विदेश नीति का एक पहलू है कि वह इसे संवेदना और भावना के स्तर पर ले जाते हैं अतीत से जोड़ते हैं तथा इसके सांस्कृतिक पहलू को पूरा महत्व देते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि मोदी की ईरान यात्रा से हमारे लिए कई तरह के द्वार खुलेंगे। मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों की दोस्ती मजबूत हुई।

(32) प्रश्न : पिछले जून, 2016 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पाँच देशों की छह दिवसीय विदेश यात्रा की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में कहा गया कि भारत की एनएसजी की सदस्यता की संभावना बढ़ गई है। एनएसजी क्या है

और इसकी सदस्यता का महत्व क्या है? यदि भारत को एनएसजी की सदस्यता मिल जाती है, तो इस देश को क्या लाभ मिल सकते हैं?

उत्तर: पिछले जून, 2016 में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका, मैक्सिको, अफगानिस्तान, स्वीट्जरलैंड तथा कतर – इन पाँच देशों की छह दिवसीय यात्रा की जिसकी उपलब्धि में कहा गया कि भारत को एनएसजी की सदस्यता मिल सकती है। दरअसल, एनएसजी या न्यूक्लियर सप्लायार्स ग्रुप परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का समूह है, जो परमाणु हथियार बनाने में सहायक हो सकने वाली वस्तुओं, यंत्रों और तकनीक के निर्यात को नियंत्रित कर परमाणु प्रसार को रोकने की कोशिश करता है। भारत को 1974 में किए गए पहले परमाणु परीक्षण की प्रतिक्रिया में इस समूह के गठन का विचार पैदा हुआ था और इसकी पहली बैठक नवंबर, 1975 में हुई थी। इस परीक्षण से संकेत गया था कि असैनिक परमाणु तकनीक का उपयोग हथियार बनाने में किया जा सकता है। ऐसे में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर चुके देशों को परमाणविक वस्तुओं, यंत्रों और तकनीक के निर्यात को सीमित करने की जरूरत महसूस हुई।

प्रारंभ में एनएसजी के सात संस्थापक सदस्य थे- कनाडा, वेस्ट जर्मनी, फ्रांस, जापान, सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका। वर्ष 1976-77 में यह संख्या 15 हो गई। फिर 1990 तक 12 और अन्य देशों ने इसकी सदस्यता ली। चीन को 2004 में इसका सदस्य बनाया गया। फिलहाल इस समूह में 48 देश शामिल हैं और 2015-16 के लिए समूह की अध्यक्षता अर्जेंटीना के पास है।

चूँकि एनएसजी का गठन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण की प्रतिक्रिया में हुआ था, इसलिए भारत का मानना है कि इसका लक्ष्य आधुनिक तकनीक तक भारत की पहुँच को रोकना है। मौजूदा 48 सदस्य देशों में से पाँच देश परमाणु हथियार संपन्न हैं, जबकि अन्य 43 देश परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इस संधि को भेदभावपूर्ण मानने के कारण भारत ने अबतक इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। वर्ष 2008 में हुए भारत-अमेरिका परमाणु करार के बाद एनएसजी में भारत को शामिल होने की प्रक्रिया शुरू हुई।

यदि भारत को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की सदस्यता मिल जाती है, तो इसे निम्नलिखित लाभ मिल, सकते हैं-

(1) दवा से लेकर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए जरूरी तकनीकों तक भारत की पहुँच सुगम हो जाएगी, क्योंकि एनएसजी आखिरकार परमाणु कारोबारियों का ही समूह है। भारत के पास देशी तकनीक तो हैं, पर अत्याधुनिक तकनीकों के लिए उसे समूह में शामिल होना पड़ेगा।

(2) भारत ने जैविक ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करते हुए अक्षय और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से अपनी ऊर्जा जरूरतों का 40 फीसदी पूरा करने का संकल्प लिया हुआ है। ऐसे में उस पर अपनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने का दबाव है और यह तभी संभव हो सकेगा, जब उसे एनएसजी की सदस्यता मिले।

(3) भारत के पास परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर हर तरह की तकनीक हासिल करने का विकल्प है, पर इसका मतलब यह होगा कि उसे अपने परमाणु हथियार छोड़ने होंगे। पड़ोस में पाकिस्तान और चीन - इन दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के होते हुए उसका ऐसा करना संभव नहीं है। एनएसजी में सदस्यता इस संशय से बचा सकता है।

(4) तकनीक तक पहुँच के बाद भारत परमाणु ऊर्जा यंत्रों का वाणिज्यिक उत्पादन भी कर सकता है। इससे देश में नमोन्मेष और उच्च तकनीक के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा, जिसके आर्थिक और राजनीतिक लाभ हो सकते हैं। परमाणु उद्योग का विस्तार 'मेक इन इंडिया' के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को नयी ऊँचाई दे सकता है।

(5) इस समूह में नए सदस्य मौजूदा सदस्यों की सर्वसम्मति से ही शामिल हो सकते हैं। यदि भारत को सदस्यता मिल जाती है तो वह भविष्य में पाकिस्तान को इसमें आने से रोक सकता है। इस स्थिति को रोकने के लिए ही चीन भारत के साथ पाकिस्तान को भी सदस्य बनाने पर जोर दे रहा है।

(6) अगर भारत एनएसजी का सदस्य बना, तो दक्षिण एशिया में भारत का प्रभुत्व बढ़ जाएगा। भारत को हमेशा अपने से कमतर समझने वाला चीन इसे अपने समकक्ष नहीं चाहता। भारत की सदस्यता से पड़ोस में अमेरिकी दखल भी बढ़ जाएगा। अमेरिका की कूटनीति और आर्थिक नीति है कि वह भारत को चीन के समकक्ष खड़ा करना चाहता है।

(7) अमेरिका भारत में तीन एटमी रिएक्टर भी लगाने जा रहा है जिसके लिए जरूरी परमाणु सामग्री भारत को आसानी से मिल सकेगी।

(8) भारत को परमाणु तकनीक और यूरेनियम बिना किसी विशेष

समझौते के हासिल होगी और परमाणु संयंत्रों से निकलने वाले कचरे का निस्तारण करने में भी सदस्य देशों से मदद मिलेगी।

बहरहाल सियोल में एनएसजी (न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रूप) का पूर्ण सम्मेलन भारत को सदस्यता देने के प्रश्न पर फैसला लेने में नाकाम रहा, क्योंकि एनएसजी के एक सदस्य देश चीन को भारत के प्रवेश पर कड़ी आपत्ति है। जबकि कुछ अन्य सैद्धांतिक स्तर पर भारतीय सदस्यता को समर्थन देने के बावजूद प्रवेश देने की प्रक्रिया में अधिक स्पष्टता चाहते हैं। यह मामला अब एनएसजी के निवृत्तमान प्रमुख अर्जेंटीना के दूत रफेल ग्रॉसी को सौंप दिया गया है और संकेत तो यही है कि वर्ष 2016 के अंत तक भारत को प्रवेश देने का तरीका खोज लिया जाएगा।

इसी संदर्भ में प्रसन्नता की बात यह है कि एनएसजी में भारत को सदस्यता मिले या न मिले, परंतु भारत को एमटीसीआर (मिसाइल ट्रेनिंग कंट्रोल रिजीम की सदस्यता मिल चुकी है, जबकि चीन को एमटीसीआर में जगह नहीं मिली है जिससे चीन भारत पर बौखलाया हुआ है।

भारत को एनएसजी की सदस्यता नहीं मिलने के बावजूद एनएसजी के 48 देशों के कुछ प्रमुख देशों ने भारत के साथ अलग से यूरेनियम निर्यात की संधि कर रखी है।

(33) प्रश्न : ब्रिटेन द्वारा भारत के विभाजन का क्या उद्येश्य था?

उत्तर : ब्रिटेन द्वारा भारत के विभाजन का उद्येश्य था कि हिंदू क्षेत्रों को छोटे-छोटे राजनीतिक भूभागों में विखंडित कर दिया जाए और उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी व सुसंगत राजनीतिक शक्ति के रूप में पाकिस्तान का उद्भव हो। इसलिए पाकिस्तान का आखिरी लक्ष्य भारत को विखंडित करना है। सन् 1948 में कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठ और क्रमिक युद्ध इसी प्रयास का हिस्सा है। कारगिल युद्ध और जम्मू-कश्मीर में छद्मयुद्ध इसी प्रयास के ताजा उदाहरण हैं।

(34) प्रश्न : क्या पाकिस्तानी गतिविधियों का विरोध करने में भारत निर्णायक और सख्त नहीं रहा है?

उत्तर : हाँ, पाकिस्तानी गतिविधियों का विरोध करने में भारत निर्णायक और सख्त नहीं रहा है। भारत सभी बड़े युद्धों में पाकिस्तान को हराने के बावजूद पाकिस्तान के प्रति स्वैच्छिक रूप से उदार रहा है। दूसरी ओर, पाकिस्तान का दीर्घकालीन रणनीतिक उद्येश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सबसे प्रभावी ताकत के रूप में न उभरे।

पाकिस्तानी सत्ता व्यवस्था भारत में हिंदू बहुल आम समाज के प्रति शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण रखती है।

पाकिस्तान ने बहुत से मुस्लिम देशों, एशियाई और पश्चिमी शक्तियों का समर्थन हासिल कर लिया था, लेकिन कश्मीर के बारामुला के उरी स्थित सेना मुख्यालय पर हमले के दौरान कुल 18 सेना के जाबांज जवानों को मौत के घाट उतार देने के बाद दक्षिण-पश्चिम के प्रायः सभी देशों ने उस हमले की कड़ी निंदा करते हुए भारत को समर्थन दिया है।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थानों पर पाकिस्तान का बार-बार सवाल उठाना भारत में मतभेद पैदा करने का समझा-बूझा प्रयास है। जम्मू-कश्मीर, पंजाब भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में अलगाववादी तथा विध्वंसक शक्तियों को पाकिस्तान का सहयोग भारत की इस धारणा की पुष्टि करता है।

(35) प्रश्न : पिछले दिनों कुछ नामी-गिरामी लेखकों एवं साहित्यकारों ने कश्मीरी भाई-बहनों के दुख से दुखी होकर और कश्मीर में हो रही वारदातों को दुर्भाग्यपूर्ण, अन्यायसंगत और अनावश्यक बताते हुए कश्मीर समस्या पर बातचीत कर संयम और शांति की माँग की। एक सुलझे साहित्यकार होने के नाते आपसे हम जानना चाहते हैं कि क्या कश्मीर में सेना जवानों की शहादत पर शांति की माँग उचित है?

उत्तर : कश्मीर समस्या का बातचीत से हल निकालने की नीति भारत सरकार ने हमेशा से अपनायी है। सरकार चाहे बदलती रही हो, लेकिन इस रास्ते से कोई भी सरकार नहीं हटी। चाहे काँग्रेस की सरकार रही हो या अटल जी के नेतृत्व में भाजपा की सभी ने बातचीत से कश्मीर समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया है। अभी कुछ दिनों पूर्व नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार की ओर से भी एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल कश्मीर समस्या के हल के लिए संबंधित नेताओं से बातचीत के लिए भेजी गई थी, पर नतीजा वही ढाक के तीन पात।

यहाँ सवाल यह भी खड़ा होता है कि बातचीत किससे? क्या देश के उन गद्दारों से जो भारतीय भूमि पर रहते हुए, भारतीय सुरक्षा व्यवस्था महफूज रहते हुए, भारतीय पासपोर्ट रखते हुए पाकिस्तान की पैरोकारी करते हैं? आपने देखा नहीं, ऐसे ही हुर्रियत के सैयद अली शाह गिलानी तथा उमर

फारूख जैसे अलगाववादियों को शह देने वाले नेताओं से मिलने प्रतिनिधिमंडल के सदस्य शरद यादव तथा सीताराम येचुरी जब उनके घर पर गए, तो मिलना तो दूर खिड़कियों से झांकते हुए घर का दरवाजा तक नहीं खोला। क्या हुर्रियत के अलगाववादियों समेत ऐसे नेता कश्मीर की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं? बातचीत तो पिछली सरकार के दौरान दिलीप पड़गांवकर और राधा कुमार के दल ने भी की थी, पर उसका क्या हुआ? सच तो यह है कि कश्मीर में आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ चल सकती है क्या? क्या भारतीय गणराज्य के खिलाफ विषवमन करने वालों से भी बातचीत की जानी चाहिए?

संयम बरतना तो ठीक है, लेकिन आपकी भूमि पर कोई राष्ट्र के खिलाफ जंग का ऐलान करेगा, तो क्या उस वक्त भी संयम से काम लेना चाहिए? क्या ऐसे लेखकों और साहित्यकारों को भारतीय संविधान की जानकारी नहीं है जहाँ राष्ट्र के खिलाफ साजिश और जंग को सबसे बड़ा अपराध माना गया है और सरकार को उन स्थितियों से निपटने के लिए असीम ताकत दी गयी है। सच तो यह है कि यह वक्त कश्मीर को लेकर राजनीति करने का नहीं, बल्कि पूरे देश से एक आवाज उठनी चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो 'साहित्य का इतिहास' में कहा भी है कि साहित्य को राजनीति से ऊपर रहना चाहिए और सदा उसके इशारे पर नहीं नाचना चाहिए। ऐसे लेखक भी साहित्यकार जिन्होंने संयम बरतने और बातचीत की अपील की उन्हें आचार्य शुक्ल जी की नसीयत याद रखनी चाहिए। असलियत यह है कि राजनीति के आँख मूँदकर चलने वाले ऐसे अनुगामी लेखक केवल सियासी मोहरे के तौर इस्तेमाल किए जाते हैं।

ऐसे लोग यदि मिल जाएँ तो पूछूँ उनसे,
पाक मुझे और परेशान करेगा कितना।
चाँद को छूने के प्रयास में लगा है बेशक!
मगर उस बच्चे का हाथ उठेगा कितना।

(36) प्रश्न : क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि पाकिस्तान तो खुद भी एक डरा हुआ राष्ट्र है?

उत्तर : हाँ, मैं भी यह मानता हूँ कि पाकिस्तान तो खुद भी एक डरा हुआ राष्ट्र है अन्यथा वह कश्मीर में चोर दरवाजे से युद्ध क्यों चलाता रहता? कश्मीर के उड़ी स्थित सेना के मुख्यालय जाकर आतंकियों ने हमारे सोए हुए जवानों पर हमले किए, यह तो कायरता की निशानी है, वीरता की नहीं। सीना तानकर उसे सामने आने की हिम्मत नहीं।

पाकिस्तान यदि परमाणु बम की धमकी देता है तो उसे यह भी पता है कि भारत के पास उससे कहीं ज्यादा परमाणु बम हैं। पाकिस्तान को भी यह डर है कि यदि परमाणु युद्ध हो गया तो पाक का नामो-निशान भी नहीं बचेगा। अब तक पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय इस्लामी संगठन के देशों पर भरोसा कर रहा था कि वे उसके मदद को आएँगे, लेकिन पाक के लिए इससे बढ़कर शर्म की बात और क्या हो सकती है कि सऊदी अरब जैसे उसके संरक्षक देश ने भी उड़ी हमले को कलंक बताया है और उस इस्लामी संगठन के प्रमुख देशों में - संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कतर ने भी सऊदी अरब के स्वर में स्वर मिलाया है। उड़ी की घटना ने पाकिस्तान की कितनी दुर्गति कर दी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दक्षिण एशिया (दक्षेस) के तीन मुस्लिम राष्ट्रों- बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मालदीव ने भी पाकिस्तान की निंदा की है। इससे पाकिस्तान को डर हो गया है, लेकिन शैतान तो इनसान को परेशान करता ही है।

(37) प्रश्नः क्या आपको लगता है कि भारत को बलूच रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष बरहम दाग बुगती को राजनीतिक शरण देनी चाहिए?आखिर क्यों?

उत्तर : हाँ, मुझे लगता है कि भारत को बलूच रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष बरहम दाग बुगती को राजनीतिक शरण देनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन के दंभ दमन के लिए साम-दाम-दंड भेद का इस्तेमाल करना उचित जान पड़ता है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमें हर विकल्प पर ध्यान देना होगा। इसमें कूटनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक और सैन्य हर उपाय शामिल है। पड़ोसी को अलग-थलग करने के लिए भारत ने पिछले दिनों में जो कदम उठाए हैं वो काबिले-ए-तारीफ है। जब वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करने बलुचिस्तान, गिलगिट-बलिस्तान में मानवाधिकार के हनन के मुद्दे को बुलंदी से उठा सकते हैं, तो बलूच रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष बरहम दाग बुगती को अपने देश में राजनीतिक शरण देने में क्या हर्ज है?

(38)प्रश्नः क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि मौजूदा दौर की वैश्विक परिस्थितियों में गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता और सार्थकता नहीं रह गई है? आखिर क्यों?

उत्तर : हाँ, मैं महसूस करता हूँ कि मौजूदा दौर की वैश्विक परिस्थितियों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता और सार्थकता नहीं रह गई है। दरअसल, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अवधारणा शीत युद्ध के उस दौर

में प्रकट हुई थी, जब दुनिया दो परस्पर विरोधी वैचारिक ध्रुवों में विभाजित थी। दो प्रतिद्वंद्वी महाशक्तियाँ अमेरिका और सोवियत संघ न केवल एक-दूसरे का विरोध सैद्धातिक रूप से कर रहे थे, वरन सैनिक संधियों के माध्यम से एक-दूसरे की घेराबंदी का प्रयास कर रहे थे।

सच तो यह है कि जब कोरिया से लेकर क्यूबा तक पूरा विश्व शीत युद्ध की चपेट में था, तब इस पृष्ठभूमि में भारत के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने शक्ति संघर्ष से बाहर रहकर अपने विकास को प्राथमिकता देते हुए गुटनिरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन किया था जिसका इंडोनेशिया, मिस्र, कंबोडिया और म्यांमार, युगोस्लाविया आदि देशों ने बड़े उत्साह से समर्थन किया था।

तकरीबन तीन दशकों तक अफ्रीकी एशियाई देशों के इस गुट निरपेक्ष आंदोलन ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर सार्थक भूमिका का निर्वह्ण किया। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात् क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपयोगिता आज बची है? यह प्रश्न भाई विजय जी, आप ही के सामने खड़ा नहीं है, बल्कि हमारे आपके जैसे सभी के दिमाग में कौंध रहा है। खासतौर पर तब जब चीन इसके हाशिए पर खड़ा पर्यवेक्षक है और पाकिस्तान इसका मानद सदस्य। युगोस्लाविया का विखंडन वर्षो पहले हो चुका है और मिस्र खस्ताहाल है। इंडोनेशिया 1960 के दशक के मध्य से ही अमेरीकी सलाहवाली आर्थिक नीतियों का अनुसरण करता रहा है।

आपने देखा नहीं इस वर्ष यानी 2016 में वेनजुएला में आयोजित गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन में न तो भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाग लिया और न ही भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने। हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इस सम्मेलन में जाकर औपचारिकता निभाई। मेरा भी मत है कि नेहरू जी की इस मृतप्राय विरासत को ढोते रहने की क्या आवश्यकता, खासकर तब जब भारत का अमेरिका के साथ सबसे नजदीकी संबंध हो गया है।

आपने देखा नहीं इस बार के गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में जिन राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया सभी छोटे-छोटे राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दरअसल, असलियत यह है कि आज गुटनिरपेक्ष देशों की बिरादरी में भयंकर फूट पड़ी है। अनेक सदस्यों के बीच ऐसे उभयपक्षीय विवाद हैं, जिनका निबटारा आसान नहीं। इसके अतिरिक्त 21वीं सदी के दूसरे दशक में अनेक ऐसे वैकल्पिक क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय राजनयिक मंच सुलभ हैं जिनकी कल्पना

1950 वाले दशक में नहीं की जा सकती थी। राजनय में हर मंच की अपनी उपयोगिता होती है। भारत एक शिखर सम्मेलन में अपने राष्ट्रहितों को परिभाषित कर दूसरे मंच पर उनकी व्याख्या करते हुए उनके लिए समर्थन जुटाने की जमीन तैयार कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता की दावेदारी करने वाला उदीयमान भारत किसी भी ऐसे मंच पर अनुपस्थित नहीं रह सकता जहाँ सौ से अधिक देश उपस्थित हों। इसके मद्देनजर भारत फिलहाल गुटनिरपेक्ष आंदोलन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की स्थिति में नहीं है।

(38) प्रश्न : क्या भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भविष्यवाणी की थी कि पाकिस्तान का निर्माण भारत के मुसलमानों को नुकसान पहुँचाएगा?

उत्तर : हाँ, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के अध्यक्ष और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद को पाकिस्तान की हरकतों का पूर्वाभास था और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि पाकिस्तान का निर्माण भारत के मुसलमानों को नुकसान पहुँचाएगा तथा सीमा के दोनों ओर उनकी इस्लामी पहचान के बारे में संकट उत्पन्न करेगा।

पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित कई देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले अनुभवी राजनयिक जे एन दीक्षित ने अपनी किताब 'भारत-पाक संबंध : युद्ध और शांति में' आजादी के बाद से कारगिल युद्ध तक के घटनाक्रमों और कूटनीतिक फैसलों का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि भविष्य का अनुमान लगाने वाले एकमात्र नेता थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। उन्हें पूर्वाभास हो गया था कि जातीय-भाषायी और कट्टरपंथी शक्तियाँ भारत और पाकिस्तान, खासकर पाकिस्तान को प्रभावित करेंगी। उनकी स्पष्टधारणा थी कि भारत एवं पाकिस्तान एक दीर्घकालीन शत्रुतापूर्ण संबंधों के रास्ते पर चलेंगे।

(39) प्रश्नः अगर भारत-पाक युद्ध होता है जिसकी संभावना कम है, तो इसमें चीन की क्या भूमिका होगी? क्या चीन भारत को अपना प्रतियोगी मानता है? आखिर क्यों?

उत्तर : मेरा मानना है कि अगर भारत-पाक युद्ध होता है जिसकी संभावना कम है, तो चीन फौरन ही पाकिस्तान को सहायता कर देगा, लेकिन यह भी सच है कि भारत-पाक के आपसी तनाव या युद्ध की स्थिति में चीन अपनी तरफ से प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं करना चाहेगा और न ही कुछ बोलेगा।

चीन इस मामले में बहुत चालाक है। तब अधिक से अधिक यही होगा कि वह भारत-पाक युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान को मानसिक और सामरिक रूप से मदद करे, उसे हथियारों की पूर्ति करे और भारत-पाक युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की वकालत करे। अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मदद करके चीन यही चाहेगा कि भारत-पाक के बीच युद्ध लंबे समाज तक चलता रहे।

जहाँ तक आपके दूसरे प्रश्न का संबंध है निश्चित रूप से आज की तिथि में चीन भारत को अपना प्रतियोगी मानता है। भारत-चीन के बीच के रिश्तों में काफी मतभेद है। भारत-चीन के बीच सीमा विवाद जैसे मुद्दे हैं जिसे लेकर दोनों में अक्सर खींचतान मची रहती है। दरअसल, चीन भारत को इसलिए भी खासकर दक्षिण एशिया में प्रतियोगी मानता है, क्योंकि भारत उसके मुकाबले खड़ा हो रहा है। चीन को इस बात की चिंता है कि दुनिया भर से निवेश भारत को आ रहा है जो पहले चीन में जाता था। किसी भी सूरत में चीन यह नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से या सामरिक रूप से आगे बढ़े। इस तरह के अनेक कारण हैं जिन्हें समझकर हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों अप्रत्यक्ष तौर पर चीन अपने पड़ोसी भारत को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता है।

दूसरी बात यह है कि दक्षिण एशिया में भारत एक प्रमुख शक्ति बनने की इच्छा रखता है और भारत इस तरफ तेजी से आगे बढ़ भी रहा है। इसलिए चीन का यह बराबर प्रयास रहता है कि वह भारत को शक्ति बनने से रोके और इसीलिए वह पाकिस्तान की मानसिक और सामरिक तौर पर मदद करता है, ताकि पाकिस्तान पड़ोस में अपनी खुराफात को अंजाम देकर भारत को उलझाए रखे और परेशान करता रहे। चीन हमेशा चाहता है कि भारत का विकास बाधित और वह महाशक्ति बनने की राह से भटक जाए। कुछ इसी ख्याल से भारत को ताकतवर बनने से रोकने के लिए ही चीन ने अप्रत्यक्ष तौर पर पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक धर रखी है।

(40) प्रश्न : क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब वह समय आ गया है जब पाक के नापाक इरादों पर पानी फेरने के लिए भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने कूटनीतिक प्रयासों को और तेजतर बनाए रखने सहित सीमा पर घुसपैठ रोकने और संघर्ष विराम उल्लंघन का मुँहतोड़ जवाब देने के लिए भी चौकस हो जाना चाहिए?

उत्तर : हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि अब वह समय आ गया है जब पाक के नापाक इरादों पर पानी फेरने के लिए भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने कूटनीतिक प्रयासों को और तेजतर बनाए रखने सहित सीमा पर घुसपैठ रोकने और संघर्ष विराम उल्लंघन का मुँहतोड़ जवाब देने के लिए भी चौकस हो जाना चाहिए। इतिहास गवाह है कि भारत ने जब भी आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर घेरने की कोशिश की है, पाकिस्तानी सेना बौखलाहट का परिचय देती रही है। खासकर पिछले दो-तीन वर्षों से तो वह आतंकियों की घुसपैठ कराने, कश्मीर में अशांति फैलाने और भारतीय सैनिकों को उकसाने के मकसद से संघर्ष विराम का लगातार न केवल उल्लंघन कर रही है, बल्कि इधर उड़ी और नौगाम सेक्टर में नियंत्रण रेखा से घुसपैठ की दो बड़ी कोशिशों को नाकाम करने के बाद और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेज किए गए कूटनीतिक प्रयासों की काफी हद तक सफलता के चलते पाकिस्तान बौखलाया हुआ है।

पाकिस्तान के छल-छद्म वाले रवैए के मद्देनजर भारत को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि पाकिस्तान पर कारगर अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़े। पाकिस्तान की कूटनीतिक तौर पर घेराबंदी के मामले में कुछ कदम भारत को खुद भी उठाने चाहिए। कूटनीतिक मोर्चे पर कामयाबी सतत सक्रियता से मिलती है, लेकिन अक्सर यह देखने को मिलता है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपनी कूटनीतिक आक्रामकता थाम लेता है या फिर उसे निरंतरता नहीं दे पाता है। मुंबई हमले के गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई या फिर दाउद को खुद के हवाले करने की माँग जिस तरह कभी-कभार ही होती है, उससे भला पाकिस्तान क्यों दबाव में आएगा? भारत को यह ध्यान होगा कि उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। जब वह अपने मकसद के प्रति गंभीर दिखेगा तभी विश्व समुदाय भी वास्तविक गंभीरता दिखाएगा।

यह कहने की जरूरत नहीं कि उड़ी में सेना के मुख्यालय पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमले के बाद पूरा देश आक्रोशित है। ऐसी स्थिति में भारत अपनी मजबूत इच्छाशक्ति का परिचय देकर पाकिस्तान की नींद हराम कर सकता है। पाकिस्तान अमेरिका और चीन के भय और उनसे मिलने वाली खेरात में बँध चुका है। वह चाहकर भी खुद को युद्ध में नहीं झोंक सकता। इसी वजह से वह परोक्ष लड़ाई से भारत को नुकसान पहुँचाता रहा है। पाकिस्तान की यह नीति चीन और अमेरिका दोनों के लिए मुफीद रही है। ये दोनों ही देश पाकिस्तान की शह पर दक्षिण एशिया में अपने हित

साधते रहे हैं। यही वजह थी कि पाक को परमाणु संपन्न बनाया गया। इन परिस्थितियों में भारत के पास सबसे बेहतर विकल्प पाकिस्तान को अलग-थलग करना ही है।

भारतीय सेना के जाबांज जवानों ने उरी में हमले के बाद पहले दिन 11 आतंकियों और दूसरे दिन 20 आतंकियों की मौत के घाट उतार कर पाक को जैसे तैयार सराहनीय उत्तर दिया है। सेना, सरकार और राजनयिकों के एकजुट प्रयास से ही हमें कामयाबी मिलेगी। इसलिए अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को मुँहतोड़ जवाब दिया जाय।

(41) प्रश्न : क्या युद्ध भारत-पाक के बीच बीते सात दशकों से जारी मनमुटाव, टकराव या युद्धोन्माद को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? अगर नहीं तो सीमा पर शांति के लिए आज क्या जरूरत है?

उत्तर : वैसे मेरे ख्याल से तो भारत-पाक के बीच युद्ध की कोई संभावना नहीं है, फिर भी खुदा-न-खास्ते यदि दोनों देशों के बीच युद्ध हो भी जाए, तो बीते सात दशकों से जारी मनमुटाव, टकराव या युद्धोन्माद को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर पाएगा। कारण कि भारत-पाक के बीच अब तक हुए घोषित-अघोषित चार युद्धों में दोनों देशों को भारी जान-माल की क्षति उठाना पड़ा है। कारगिल युद्ध को छोड़कर बाकी तीन युद्ध में दोनों देश परमाणु-क्षमता विहीन देश थे, लेकिन आज की तिथि में दोनों देश परमाणु हथियारें से लैस हैं। ऐसे में मेरा ख्याल है कि पिछले चार युद्धों के बाद भी दोनों के बीच की समस्या का समाधान नहीं निकल सका, तो इसकी क्या गारंटी है कि पाँचवा युद्ध भारत-पाक के तमाम मसलों को हल कर देगा?

जहाँ तक मेरी समझ है कि युद्ध एक बरबादी के सिवा कुछ नहीं लाएगा- जान-माल और अर्थव्यवस्था की भारी बरबादी। हाँ, पाक-भारत को हथियार बेचने वाले ताकतवर देश चीन, अमेरिका और रूस जैसे आबाद जरूर होंगे। ऐसे में भारत-पाक के लंबित विवादों, दशकों से जारी झगड़ों और बार-बार के हिंसक टकरावों का हल युद्ध कतई नहीं हो सकता, बल्कि मुझे तो लगता है कि यदि भारत-पाक के बीच युद्ध हुआ, तो ऐसी भीषण लड़ाई तीसरे महायुद्ध का कारण भी बन सकती है।

आतंकवादियों ने जबसे उड़ी में सैन्य मुख्यालय पर हमला कर भारत के अट्ठारह जवानों को शहीद बनाया उसके बाद से ही युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। हालांकि जब आसमान साफ रहता है तो भारत और पाक

दोनों को ही यह ध्यान आता है कि गरीबी के खिलाफ युद्ध लड़ना है, पर *हमेशा छद्म युद्ध में लगे रहने वाले* आतंकवादी सीमा कुछ ऐसा काम कर डालते हैं कि युद्ध के बादल मंडराने लगते हैं। *ऐसी स्थिति में मुझे तो लगता* है कि सीमा पर शांति के लिए एक तो दोनों देशों के बीच विवाद से जुड़े हर पक्ष से राजनीतिक संवाद करने की जरूरत है और दूसरे अपनी सुरक्षा व्यवस्था और रणनीति को पुख्ता और अभेद्य बनाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि इन दोनों मोर्चों की हाल के दिनों में काफी अनदेखी हुई है। आखिर तभी हमारे रक्षा मंत्री ने भी उड़ी के हमले में अपनी चूक को स्वीकार किया। इसलिए शब्दों के जरिए आग उगलने की बजाय हमें अपने पेंचीदा मसलों को हल करने की समझ और कौशल विकसित करने पर जोर देना होगा।

(42) प्रश्नः भारत सरकार द्वारा कश्मीर के हुर्रियत नेताओं पर करोड़ों रुपए की भारी-भरकम राशि क्यों खर्च की जाती है?

उत्तर: इस बात को लेकर मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि हुर्रियत नेता जब आतंकियों तथा अलगाववादियों को शह देते हैं तो भारत सरकार कश्मीर के हुर्रियत नेताओं पर भारी-भरकम राशि क्यों खर्च कर रही है। जेड प्लस सुरक्षा तथा मुफ्त इलाज के अलावा आवागमन की राशि भी दी जाती है। करोड़ों की राशि इन पर खर्च की जाती है, यह जानने का हक देश की समस्त जनता को है। इतना सब करने का क्या मकसद है? रक्षा तो वो खुद ही कर लेंगे, खर्च भी इन्हें पाकिस्तान से मिलता है, तो हमारे करदाताओं को पैसा इन पर लुटाना सरासर मेरे ख्याल से ज्यादती है। इसे तत्काल बंद किया जाना चाहिए।

भारत जितना सहनशील देश है और सहिष्णु भी, पाक उतना ही कट्टर और असहिष्णु है और कश्मीर के हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी तथा उमर फारूख जैसे अलगाववादियों को शह देने वाले लोग। दरअसल, जिस देश का जन्म ही भारत विरोध की मुहिम पर हुआ हो और उसको पाक को हुर्रियत नेता साथ दे रहे हैं उसके साथ मित्रता की आशा बाँधना मृगतृष्णा के अतिरिक्त और कुछ नहीं।

(43) प्रश्नः क्या आप इस विचार से सहमत है कि पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अलग-थलग पड़ने की शुरुआत हो गई हैं? आखिर कैसे?

उत्तर: हाँ, मैं इस विचार से सहमत हूँ कि पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अलग-थलग पड़ने की शुरुआत हो गई है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने न केवल संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान पर

करारा प्रहार किया, बल्कि इससे पहले उन्होंने छद्म युद्ध में लगे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलने से भी इन्कार कर दिया था। उधर दक्षिण एशियाई देशों में भी पाकिस्तान को खोजने से भी दोस्त मिलना मुश्किल हो रहा है। अफगानिस्तान और भारत सहित बांग्लादेश दक्षिण एशिया में जारी हिंसा के लिए पाकिस्तान को सीधे तौर पर दोषी ठहरा रहे हैं और सार्क शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किये हैं।

इसी प्रकार अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने जहाँ पाक को आतंकियों की जन्नत न बनाने की सलाह नवाज शरीफ को दी है, वहीं संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) कश्मीर के उड़ी सेक्टर में भारत के सैन्य ठिकाने पर आतंकी हमले की निंदा करते हुए भारत के साथ अपनी संवेदना जताई है और आतंकवाद को मिटाने में हर तरह की मदद देने को तैयार है। उधर सउदी अरब ने भी उड़ी में भारतीय सेना के प्रतिष्ठान पर हुए आतंकी हमले की निंदा की है। जापान आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है और फ्रांस ने कहा है कि भारत हमारा रणनीतिक साझीदार है और हम लश्कर--ए-तेयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की माँग करते हैं जो भारत पर हमला कर रहे हैं। बहरीन भी भारत को आतंकवाद मिटाने में हर मदद देने को तैयार है और आतंकवाद को जड़ से नष्ट करने का आह्वान किया है।

(44)प्रश्न:आतंकियों के हाथों अपने जांबाज सैनिकों की शहादत पर शोकजदा होने के लिए हमारा देश भारत और कब तक अभिशप्त रहेगा?

उत्तर : जम्मू-कश्मीर के उड़ी में भारतीय सैन्य कैंप पर सीमा पार से आए घुसपैठियों और आतंकियों के हमले में हमारे 18 जांबाज जवान शहीद हो गए। ऐसे हमलों के वक्त मुँहतोड़ जवाब देने और सुरक्षा चाक-चौबंद करने के दावे हर बार किए जाते हैं, लेकिन हमलों का सिलसिला थमता नहीं है। आखिर हमारी इंटेलिजेंस, विजिलेंस और सुरक्षा एजेंसियों को ऐसी किसी अनहोनी के घटने की जानकारी होते हुए भी हमारी कार्रवाई में कैसे कमी रह गई। अगर सीमा पर भारतीय जवान मुस्तैद हैं, तो वहाँ किसी के घुसने की भनक तुरंत लग जाती है, फिर भी घुसपैठिओं का हमारी सीमा में घुस कर हमारे जवानों पर हमला करने का मतलब है कि कहीं-न-कहीं हमारी सतर्कता में कमी रह गयी। हमारे लिए यह चिंता का विषय है कि आखिर हमारी व्यवस्था में क्या कमी रह गयी है।

उड़ी के हमले को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी घुसपैठियों ने जो *कुछ भी किया है, यह* उसकी बहादुरी इसलिए नहीं है कि सोते आदमियों को मारना कोई बहादुरी नहीं होती। दरअसल, ऐसा करके पाकिस्तान भारत में फसाद फैलाना चाहता है। पाकिस्तान की शह पर आतंकियों ने भारतीय जवानों को मार कर यह दिखलाना चाहते हैं कि वे सेना के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान में अब हद से बढ़ रहे इन आतंकियों के खिलाफ भारत को अब ठोस कदम उठाना ही होगा, बातचीत करने से अब बात नहीं बनेगी। हालांकि यह भी सच है कि ऐसी वारदात के बाद भावनाओं का ज्वार हिलोरें लेता है, पर राजनीति की अपनी हदें हैं। इस वक्त जल्दबाजी में कोई फैसला करने की बजाय ठोस रणनीति पर काम करना होगा, सैन्य साजो-समान और हथियार का आधुनिकीकरण करना होगा और साथ ही इंटेलिजेंस को मजबूत करना भी आवश्यक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को अलग-थलग करने का प्रयास जारी रखना होगा। दरअसल, जो काम राजनीति और कूटनीति का है, उसे फौज से करवाना भी उचित नहीं लगता। इसलिए कूटनीतिक और राजनीतिक तैयारी को बढ़-चढ़ कर करना होगा और फौज को जवाबी हमले की छूट दे देनी होगी, क्योंकि जब चोट खाने की बजाय चोट देंगे, तभी हमारी फौज के जवानों का मनोबल ऊँचा होगा। आप जरा सोचिए, उन 18 जवानों के माँ-बाप और उनके बाल-बच्चों के दुख को, कैसा बीत रहा होगा उनपर! आखिर कबतक हम जवानों की शहादत पर शोक मनाते रहेंगे और शोकजदा होने के लिए यह देश और कबतक अभिशप्त रहेगा। चीन की शह पर पाकिस्तान पोषित आतंकियों से निबटने के लिए और उनकी मंशा को नाकाम करने एवं ऐसे हमलों के प्रतिकार करने के लिए भारत के सामने अब एक ही रास्ता है कि भारत की सुरक्षा के लिए हमारे सैन्य सुरक्षा बलों के पास सैन्य साजो-सामान और हथियार का आधुनिकीकरण किया जाए और भारतीय सेना के पास स्तरीय सुरक्षा-व्यवस्था भारत जैसे देश को जैसी होनी चाहिए उस स्तर की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र की जाए। साहस और संयम के साथ हमले का जवाब देने में शीघ्रता करनी होगी, ताकि हमारा रणनीतिक प्रभाव और स्पष्ट दिखाई देने वाला नतीजा नजर आने लगे।

उड़ी में आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान को विश्व समुदाय ने घेरना शुरू कर दिया है। रूस ने जहाँ पाकिस्तान के साथ साझा सैन्य अभ्यास से इनकार कर दिया है, वहीं जर्मनी के विदेश मंत्री फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर

ने पाकिस्तान की सरजमीं से पैदा आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करना हर देश का दायित्व बताया है। इसके साथ ही भूटान, मॉरीशस, कतर, नेपाल, मंगोलिया, ब्रिटेन व दक्षिण कोरिया समेत कई देशों ने कहा है कि वे भारत के साथ हैं और पाक आतंकी को नष्ट करे। और तो और चीन ने भी पाकिस्तान को अब मदद करने से बचने का प्रयास किया है या वह हिचकिचा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी देशों ने कहा है कि वे आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा है कि यहाँ तक कि पाकिस्तान के करीबी मित्र चीन ने भी उड़ी हमले की निंदा की है।

(45)प्रश्नः क्या आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापते-अलापते कहीं अपने देश का ही छिन्न-भिन्न कर दे?

उत्तरः हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापते-अलापते कहीं अपने देश को ही छिन्न-भिन्न न कर दे। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीय करने का दांव भी अब पूरी तरह विफल हो गया है। कश्मीर स्थित उरी घटना के चलते विश्व बिरादरी ने जिस प्रकार आतंकवाद के खात्मे के लिए एकजुटता दिखाने की कोशिश की है उससे भी यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान इस मामले में सुधरेगा या दण्ड भोगेगा, क्योंकि पश्चिमी देशों से मिल रहे समर्थन से परिस्थितियाँ काफी बदलाव की ओर है। भारत सरकार की कूटनीति का जो नेटवर्क विश्वभर में फैल चुका है उस फसल को काटने का यह एक खूबसूरत मौका भी है।

देखा जाए तो फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, अफगानिस्तान और कनाडा के बाद अब सूची में जापान, जर्मनी, सऊदी अरब, सऊदी अरब अमीरात, बहरीन, कतर, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मंगोलिया सहित मालदेव और दक्षिण कोरिया ने भी उरी हमले की कड़ी आलोचना की है। आतंकी हमले की आलोचना करने वाले उक्त देशों में कई न केवल मुस्लिम देश हैं, बल्कि इस्लामिक समूह 56 के सदस्य भी हैं। राष्ट्रपति ओबामा ने तो नवाज शरीफ को दो-टूक कह दिया कि छद्म युद्ध बंद करो। दक्षिण एशियाई देश भी अब पाकिस्तान के साथ खड़े होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। काठमांडू में विगत 1985 में स्थापित सार्क दक्षिण एशियाई देशों के आठ देशों के समूह ने भी सार्क सम्मेलन का बहिष्कार कर आतंकवाद के खिलाफ अपनी

एकजुटता का परिचय दे दिया है। पाकिस्तान को ले देकर अब सिर्फ इस्लामिक देशों के संघटन ओआईसी से कुछ समर्थन मिल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कश्मीर का राग अलापते-अलापते अपने देश को ही छिन्न-भिन्न करने की ओर अग्रसर है।

कश्मीर समस्या के समाधान का सबसे बढ़िया तरीका पाकिस्तानी सेना के लिए वहाँ दुरूह हालात पैदा कर देना है, जिससे उसके मनोबल को चोट पहुँचे। जब पाकिस्तान फौज की पूछ में आग लगेगी, तभी पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ भारत के साथ शांति की कीमत समझेंगे। वरना तो हमारा घर जलते हुए देखकर ऐश हो रहा है।

यही नहीं, भारत सरकार को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर गिलगिट-बलतिस्तान, खैबर, पख्तूनवा और बलूचिस्तान के लोगों को हर तरह की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को सहायता देनी चाहिए और दुनिया को यह बताना चाहिए कि पाकिस्तान इन क्षेत्रों पर अनधिकृत रूप से कब्जा जमाए हुए है। ऐसे में बलूच नेता बरहमदाग बुगती भारत में राजनीतिक शरण लेने की जब इच्छा जाहिर की है, तो उनके विधिवत आवेदन पर भारत सरकार विचार करे। फिलहाल वे भारत के अधिकृत दस्तावेज के आधार पर अमेरिका और पश्चिमी देशों में बलूचिस्तान की आजादी की आवाज बुलन्द कर रहे हैं।

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर गिलगिट-बलतिस्तान, खैबर, पख्तूनवा और बलूचिस्तान में जब अशांति होगी, तो उसकी गूँज इस्लामाबाद से अधिक बीजिंग में सुनाई देगी, क्योंकि इसका प्रभाव पाकिस्तान व चीन के आर्थिक गलियारे पर इसलिए पड़ेगा, कारण कि उन प्रांतों में ही अधिकतम खनीज पदार्थो के खान हैं। तभी तो चीन पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर से बाहर हटने के लिए मजबूर कर सकता है।

पाकिस्तान की हालत आप इसी से समझिए कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून के भाषण में भी कश्मीर का जिक्र नहीं हुआ। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र में भाषण दे रहे थे, तो पूरे हॉल में महज 15 लोग ही थे और वह भी सिर्फ पाकिस्तान के पीएमओ व विदेश मंत्रालय के अधिकारी। यही नहीं कई देशों ने तो उल्टे शरीफ को ही आतंकी गतिविधियों पर काबू पाने की सलाह दे दी।

(46) प्रश्न : जम्मू-कश्मीर के उड़ी क्षेत्र में सैन्य ठिकाने पर हुए आतंकी हमले में हमारे 18 सैनिकों के शहीद होने के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि देश की सुरक्षा से संबंधित मसलों में कार्रवाई करने में देरी घातक है?

उत्तर : इस साल यानी 2016 में सीमा पार से घुसपैठ की घटनाएँ तेजी से बढ़ी हैं। इस वर्ष जून तक ऐसे 90 घटनाओं के मामले सामने आए हैं, जबकि इसी अवधि में पिछले साल 29 घटनाएँ ही हुई थीं। घुसपैठी आतंकियों द्वारा सेना पर हमले के मामले भी बढ़े हैं।

न्यूयॉर्क में 19 सितंबर, 2016 को आयोजित संयुक्त राष्ट्र की महासभा के एक दिन पहले पाकिस्तानी आतंकी संगठन जेश-ए-मुहम्मद के चार आत्मघाती आतंकियों द्वारा कश्मीर के उड़ी स्थित 12वीं ब्रिगेड के मुख्यालय पर किए गए हमले में 17 शहीद हुए जवानों पर हमले अबतक के सबसे बड़ा हमला था। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली है, लेकिन सैन्य अधिकारियों के मुताबिक हमले में शामिल आतंकियों से मिले दस्तावेज बताते हैं कि उनका संबंध जैश-ए-मुहम्मद से था। सैन्य ठिकाने पर हुए इस आतंकी हमले से पाकिस्तान के खतरनाक इरादे एक बार फिर जाहिर हुए हैं। पाकिस्तान तो यही चाहता है कि हिंसा का दौर जारी रहे, ताकि वह दुनिया के सामने अपनी हरकतों को जायज ठहरा सके। इसलिए कश्मीर में अमन-चैन की बहाली और सीमाओं की सुरक्षा चाक-चौबंद करना तथा पाकिस्तान को उसके आक्रामक रवैए के लिए जवाबदेह बनाते हुए समुचित कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा देश की सुरक्षा से संबंधित मसलों पर कार्रवाई करने में देरी घातक सिद्ध होगा।

इसमें कोई शक नहीं कि इस हमले की साजिश के पीछे पाकिस्तान का हाथ है जो कश्मीर में आतंकियों को भेज रहा है। उससे निबटने के लिए उन छिद्रों की पहचान के बाद उसे बन्द करना होगा जिनके जरिए आतंकी अपने लक्ष्य तक पहुँचते हैं। भारत को अब केवल कौटिल्यीय कूटनीति अपनाने की जरूरत है, क्योंकि कश्मीर में अब पानी सिर से ऊपर बह रहा है। समय रहते यदि सरकार वहाँ कोई कदम नहीं उठाती है तो आने वाले दिनों में यह कश्मीर और देश के लिए और भी खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है, **क्योंकि** पाकिस्तान की शह पर आतंकी का मकद केवल आतंक फैलाना है। इसलिए अब समय की माँग है कि जैसे को तैसा व्यवहार किया जाय और अब और चोट खाने की बजाय चोट देने की जरूरत है, तभी हमारी

फौजों का मनोबल ऊँचा होगा। पाकिस्तान को तमाचा मारिए और सबके सिखाइए। तभी वह वह रास्ते पर आएगा।

(47) प्रश्न:वेनेजुएला में हुए गुटनिरपेक्ष देशों के 17वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करने के प्रस्ताव का विरोध करने के कारण क्या पाकिस्तान का दोहरा चरित्र उजागर हो गया है और वह गुट निरपेक्ष आंदोलन में भी अलग-थलग पड़ गया है?

उत्तर : हाँ, पिछले सितंबर, 2016 में वेनेजुएला में आयोजित गुटनिरपेक्ष देशों के 17वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा आतंक के खिलाफ आतंक निरोधक कार्य समूह बनाने के प्रस्ताव पर विरोध करने के कारण न केवल आतंक के मसले पर पाकिस्तान का दोहरा चरित्र उजागर हो गया, बल्कि गुट निरपेक्ष 120 देशों के सामने वह अलग-थलग पड़ गया है। मेजबान वेनेजुएला समेत अधिकतर भारत के इस प्रस्ताव के पक्ष में खड़े नजर आए और पाकिस्तान का साथ किसी ने नहीं दिया।

भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय शांति और राज्यों की संप्रभुता के लिए सबसे बड़ा खतरा है और विकास के मार्ग में बड़ी बाधा है। इसलिए गुटनिरपेक्ष देशों को वर्किंग ग्रुप बनाना जरूरी है जो आतंक के मसले पर समन्वय करे, मगर पाकिस्तान ने इसका विरोध कर आतंक कर अपना दोहरा चरित्र उजागर कर दिया।

(48) प्रश्न: कश्मीर के उरी हमले के बाद रूस द्वारा सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तान के साथ 2016 के अंत में होने वाले साझा युद्ध अभ्यास को आप किस नजर से देखते हैं?

उत्तर: पाकिस्तान और रूस 2016 के आखिर में होने वाली अबतक के सबसे पहले संयुक्त सैन्य अभ्यासों-फ्रेंडशिप-2016 में हिस्सा लेने तथा एमआई-35 हेलीकॉप्टर देने की डील को भी रूस ने रद्द कर दिया है, क्योंकि कश्मीर के उरी में हमले के बाद पाकिस्तान पर चौतरफा हमला हो रहा है और चौतरफा दबाव बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। भारत के कड़े रूख के बाद रूस ने युद्ध अभ्यास को रद्द करने का फैसला लेकर भारत के साथ वर्षों से अपनी मैत्री और अच्छे संबंध का परिचय दिया है। यह पहली बार था जब भारत के बेहद करीबी दोस्त रूस के साथ पाकिस्तान अपने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश कर रहा था,

क्योंकि इन दोनों के संबंध दशकों तक चली शीत युद्ध की दुश्मनी की वजह से बिगड़ गए थे। युद्ध अभ्यास और एमआई-35 हेलीकॉप्टर डील के दम पर पाकिस्तान की कोशिश थी कि वह रूस के साथ एक भरोसेमंद रिश्ता कायम करे, लेकिन उरी में पाकिस्तान की शह पर आतंकियों के हमले में 18 जवानों के शहीद होने के बाद भारत ने जब सख्त रूख अपनाया, तो रूस को भारत के साथ अपने पुराने रिश्ते की याद आई और युद्ध अभ्यास और डील को रद्द करना ही मुनासिब समझा।

(49) प्रश्न:क्या आपको ऐसा लगता है कि बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारत की भूमिका बढ़ी है? आखिर क्यों?

उत्तर: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारत की भूमिका बढ़ी है, क्योंकि आज भारत दुनिया के सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और सभी क्षेत्रों में तेज गति से विकास कर रहा है। इससे प्रभावित होकर ही आसियान देशों ने जनवरी, 1992 में चार क्षेत्रों में 'क्षेत्रक वार्ताकार सहयोगी' और दिसंबर, 1995 में 'पूर्ण वार्ताकार सहयोगी' का दर्जा दिया। 23 जुलाई, 1996 को भारत सामरिक दृष्टिकोण से बनाए गए 'आसियान क्षेत्रीय मंच' का भी सदस्य बना। इसके अतिरिक्त आर्थिक सहयोग को क्रियान्वित करने के लिए संस्थागत कार्य प्रारूप उपलब्ध कराने के उद्येश्य से भारत एवं आसियान ने 8 अक्टूबर, 2003 को कार्यप्रारूप समझौता अथवा व्यापक आर्थिक समझौता पर हस्ताक्षर किए।

हालांकि भारत अभी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग आयोग' एवं 'प्रशांत आर्थिक सहयोग आयोग' का सदस्य नहीं है फिर भी आसियान का सहयोगी वार्ताकार एवं 'आसियान क्षेत्रीय मंच' का सदस्य होने से इस क्षेत्र के सभी देशों से उसके संबंध मधुर हैं। भारत आसियान संबंधों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दोनों पक्षों के बीच बैंकाक में 13 अगस्त, 2009 को हुआ भारत-आसियान मुक्त समझौता है जो एक जनवरी, 2010 से लागू है। इस समझौते में आपसी व्यापार की लगभग 80 फीसदी कुल 4000 वस्तुओं पर व्यापार शुल्क न्यूनतर स्तर पर करने पर सहमति हुई। समझौते के प्रथम चरण में वर्ष 2013 से 3200 वस्तुओं तथा वर्ष 2016 तक शेष कुल 800 वस्तुओं पर व्यापार शुल्क न्यूनतम किया जाएगा।

आज आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र अमेरिका, यूरोप और पश्चिम एशिया की बजाय दक्षिण पूर्व एशिया बन गया है। आने वाले वर्षो में पूँजी निवेश की उपलब्धता की वजह से यह क्षेत्र अति आधुनिकतम

तकनीक एवं विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी होगा। जहाँ तक भारत का सवाल है वह दक्षिण पूर्व एशिया की ओर व्यापार, पूँजी निवेश तकनीक, बाजार की उपलब्धता एवं आदान-प्रदान के रूप में देखता है जो आज की जरूरत है। वहीं बदलती हुई नई विश्वव्यवस्था में दक्षिण पूर्व एशिया के देश भी भारत की ओर आर्थिक आदान-प्रदान की दृष्टि से देख रहे हैं। इसलिए और भी कि आज भारत आसियान के लिए छठा सबसे बड़ा कारोबारी साझीदार बन चुका है।

आज की तिथि में भारत का आसियान के साथ व्यापार, भारत के विश्व व्यापार का लगभग 10 प्रतिशत है। इस अनुपात में आसियान भारत में अपने विश्व व्यापार का सिर्फ दो प्रतिशत ही व्यापार करता है। ऐसे में भारत को व्यापारिक संतुलन स्थापित करने के सेवा क्षेत्र में व्यापार के लिए ठोस पहल करनी चाहिए। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि आसियान देशों का झुकाव पश्चिमी देशों की ओर अधिक है। गौर करें तो इंडोनेशिया के अलावा आसियान के अन्य देश मसलन मलेशिया, सिंगापुर, फिलिपीन एवं थाईलैंड पश्चिमी देशों के साथ सुरक्षात्मक समझौते से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अनेक मुद्दों पर ही नहीं, बल्कि हिंद चीन मसले पर भी पश्चिमी शक्तियों का साथ दिया है हालांकि परिस्थितियाँ पहले जैसी नहीं रहीं। इसलिए बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारत की भूमिका बढ़ी है।

(50)प्रश्न:पाकिस्तान के कब्जेवाला कश्मीर (पीओके) आज हमारे शरीर में कांटे की तरह क्यों चुभ रहा है? कब और कहाँ-कहाँ हमारे राजनीतिज्ञों से चूकें हुईं? क्या अभी भी नेता उस चूक से सीख लेगें?

उत्तर: हाल ही में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरूप राहा द्वारा दिया गया बयान आपके इस प्रश्न का उत्तर देने में इसलिए मददगार साबित हो रहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में मेरा भी ख्याल रहा है कि इस समस्या को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने की बजाय हम सैन्य विकल्प को चुने होते। एयर चीफ मार्शल की इस स्पष्टवादिता के हम भी कायल हैं कि देश ने या यों कहिए कि जवाहर लाल नेहरू ने उच्च नैतिक आधार लेने और संयुक्त राष्ट्र में जाने की बजाय कश्मीर समस्या के समाधान के लिए यदि सैन्य विकल्प को चुना होता, तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर आज भारत के साथ होता। इसी से जुड़ा प्रश्न यह भी है कि जवाहर लाल नेहरू ने गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी तो लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई को सौंपी, पर कश्मीर समस्या को उन्होंने अपने पास रख लिया। यदि सरदार पटेल को यह

जिम्मेदारी दी गई होती, तो कश्मीर समस्या आज हमारे शरीर में कांटे की तरह नहीं चुभती, क्योंकि आपने देखा है उनके अदम्य साहस और उनकी सूझबूझ को कि किस तरह उन्होंने पाँच सौ से अधिक देशी रियासतों को नहीं चाहते हुए ही अपनी सैन्य बल के आधार पर विभाजन के वक्त भारत में मिलाकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता का दूर्लभ उदाहरण प्रस्तुत किया।

यह शत-प्रतिशत सच है कि भारत ने अपने हितों की रक्षा के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जिसका दुष्परिणाम आज हमें भुगतना पड़ रहा है। हमारी विदेश नीति पंचशील सिद्धांत के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, गुट निरपेक्ष आंदोलन के चार्टर से बंधी थी। हम उच्च आदर्शों से शासित होते रहे और अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए आवश्यक व्यावहारिक मानदंडों का ठीक उसी प्रकार पालन नहीं किया जैसे आजादी के सात दशक तक गुट निरपेक्ष का झंडा लेकर हम खड़े रहे और पाकिस्तान हम पर धौंस दिखाता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इधर हाल में विदेश नीति में बदलाव लाकर जो कदम बढ़ाया है वह आजादी के वक्त पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर जो नेहरू जी से भूल हुई थी उससे नरेन्द्र मोदी ने सीख लेकर उसे दोहराना नहीं चाहते हैं और कश्मीर समस्या का सही समाधान की ओर उनकी पहल है।

दूसरी गलती यह भी हुई कि विभाजन के पूर्व जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरि सिंह राज्य को स्वतंत्र रखने पर विचार कर ही रहे थे कि उनके इस हिचकिचाहट के बीच पाकिस्तानी हमलावरों ने जम्मू-कश्मीर को हड़पने के लिए धावा बोल दिया और अक्टूबर, 1947 में पाकिस्तान ने राज्य पर बलपूर्वक कब्जा जमाने के लिए हजारों हथियार बंद कबायलियों को सीमा पार भेज दिया और पाकिस्तानी सेना के नेतृत्व में ये कबायली जम्मू-कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर काबिज हो गए जो आज तक हमारे गले की हड्डी बन कांटे की तरह चुभ रहे हैं। आश्चर्य इस बात की है कि जब तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेल 27 अक्टूबर, 1947 की सुबह से ही वायुसेना की मदद से अपने जवानों को श्रीनगर में उतारकर दो हफ्ते के अंदर बारामुला और उरी की चोटियों को पाक हमलावरों से खाली करा लिया, मगर जब सरदार पटेल अपनी सेना के यह अभियान चला ही रहे थे तब नेहरू जी ने एक जनवरी, 1948 को सरदार पटेल की सलाह के विपरीत इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने का दुर्भाग्यपूर्ण फैसला किया जिसकी वजह से कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया गया और परिणामस्वरूप कश्मीर दो भागों में

बंटकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारे देश के लिए चुभता कांटा बन गया और आज तक बना हुआ है। इसलिए मेरा भी मानना है कि सुरक्षा और सेना से संबंधित मामलों में केवल सीधा सच ही देश के हितों की रक्षा कर सकेगा।

आज के दिन जब हम भारत के तत्कालीन गृहमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 141वीं जयंती 31 अक्टूबर, 2016 को मना रहे हैं, तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके आदर्शों और सिद्धांतों के अनुरूप कश्मीर समस्या से निपटने के लिए 'जैसे को तैसा' अपने राष्ट्र रिपु पाकिस्तान के साथ अपनाएँ।

हमारे आज के नेताओं को खासतौर पर जो सत्तारूढ़ हैं उन्हें अतीत में हुए नेताओं की चूक से सीख लेकर देशहित में शीघ्र ही अपना कदम उठाना समय का तकाजा है। पाक अधिकृत कश्मीर को फिर से भारत में शामिल करने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से भारत सरकार को काम करने की जरूरत है।

(51) प्रश्नः भारत यात्रा पर हाल ही में आए नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल 'प्रचंड' और भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से हुई द्विपक्षीय बैठक से क्या दोनों देशों के बीच आई खटास दूर होगी?

उत्तरः आपको मैं यह बता दूँ कि नेपाल के नए संविधान बनने के बाद मोटे तौर पर भारतीय मूल के मधेशी नए संविधान का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि नेपाल के सात प्रातों में बँटने से वे हाशिए पर चले जाएँगे, क्योंकि वहाँ के संसद में उनके प्रतिनिधियों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। मधेशियों द्वारा नए संविधान के खिलाफ किए जाने से उत्पन्न ताजे राजनीतिक उठा-पटक के चलते जुलाई 2016 में प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पुष्पकमल दहल 'प्रचंड' नेपाल के नए प्रधानमंत्री होने के बाद उन्होंने पहली बार पिछले सितंबर, 2016 में भारत यात्रा पर आए और भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई।

जहाँ तक नेपाल तथा भारत के दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद दोनों देशों में आई खटास दूर होने का सवाल है, युगों के मित्र देश नेपाल और भारत के बीच जो गलतफहमियाँ हैं उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल 'प्रचंड' के बीच खुल कर बातें हुई हैं। इसके साथ ही यह भी तय हो गया है कि नेपाल में चीन की दाल नहीं गलेगी। नेपाल भारत की बजाय चीन को अपनाने की

कूटनीतिक गलती नहीं करेगा। इसके साथ ही दोनों देशों के रिश्तों में पिछले एक वर्ष से जो तनाव का माहौल था वह बहुत हद तक खत्म हो गया है। भारत न सिर्फ रक्षा व सुरक्षा से जुड़ी नेपाल की चिंताओं को समझने व उन्हें दूर करने को तैयार हो गया है, बल्कि नेपाल की अर्थव्यवस्था को जल्द पटरी पर लाने में हर संभव मदद करने के लिए भी हामी भरी है। हालांकि संविधान संशोधन के जिस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच मतभेद थे, उसको लेकर भी नेपाल ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। प्रधानमंत्री प्रचंड ने शीघ्र ही मधेशियों और जातियों से जुड़ी समस्याओं के दौरान उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठकर सुलझाने का वायदा किया है। नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल 'प्रचंड' ने जिस तरह अपने विचारों में सकारात्मक परिवर्तन किया है उससे दोनों देशों के रिश्ते पटरी पर आ सकते हैं। प्रचंड को यह समझ आया कि भारत उनका सामान्य पड़ोसी देशमात्र ही नहीं है, बल्कि दोनों देशों की सामाजिक स्तर पर अटूट एवं प्रचीन साझा विरासत है। इसकी बराबरी कोई अन्य देश नहीं कर सकता। नेपाली पी.एम की यात्रा के दौरान मोदी और प्रचंड के सामने तीन अहम समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए हैं जिसमें एक समझौता नेपाल में तराई परियोजना के तहत सड़क मार्ग बनाने और अन्य दो नेपाल को एक अरब डॉलर की आर्थिक मदद भी शामिल है जो नेपाल को भूकंप बाद निर्माण में मदद करेगा। भारत नेपाल के भूकंप पीड़ित इलाकों में तीन लाख घर बनाएगा। इसके अतिरिक्त दोनों के बीच विद्युत वितरण के लिए पारेषण लाइनों को जल्द शुरू हो जाने के बारे में भी सहमति बनी है। इस हिमालयी राष्ट्र नेपाल में चीन द्वारा पैर जमाने की कोशिश के बीच नरेन्द्र मोदी ने नेपाल को सभी संभव सहायता का आश्वासन दिया है। वहीं पुष्पकमल दहल 'प्रचंड' ने भी कहा कि उनकी सरकार पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के प्रति वचनबद्ध है और प्रधानमंत्री का पद ग्रहण के बाद तुरंत उन्होंने इन उद्येश्यों की पूर्ति के लिए भारत में विशेष दूत भेजा था। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल की भागीदारी बहुत अहम है और इसे मजबूत करके दोनों देश एक–दूसरे का फायदा उठा सकते हैं। हमारे करीबी संबंधों के कारण यह मित्रता आगे भी बरकरार रहेगी। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई बातचीत से तो लगता है कि नेपाल और भारत के बीच आई खटास अब दूर होगी।

(52) प्रश्नः क्या इस बात का अफसोस आपको भी है कि जिस तरह रियो ओलंपिक में शटलर पी वी सिंधु के रजत जीतने और महिला पहलवान साक्षी मलिक के कांस्य पदक जीतने पर देश में खुशी का जो माहौल बना था, वैसा माहौल रियो पैरालम्पिक खेल में मरियप्पन थंगावेलू के स्वर्ण पदक और वरुण सिंह के कांस्य पदक जीतने पर नहीं बना? क्यों?

उत्तरः सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि आलंपिक और पैरालम्पिक खेल में अंतर यह है कि जहाँ ओलंपिक खेल में सुविधाओं में खेलने वाले खिलाड़ी का शरीर का अंग-प्रत्यंग ठीक होना आवश्यक है, वही पैरालम्पिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों में शारीरिक खामियाँ रहती हैं यानी पैरालम्पिक खेल में वहीं खिलाड़ी भाग ले सकते हैं जिनके शरीर में कुछ-न-कुछ खामियाँ हैं।

सलेम से 60 किलामीटर दूर स्थित पेरियावादामगट्टी गाँव में जन्मे मरियप्पन थंगावेलू पाँच साल की उम्र में ही घर के बाहर खेलने के दौरान उसके दाहिने पैर पर राज्य परिवहन की बस के चढ़ने से घुटने तक का पैर का हिस्सा कट गया था। तब भी उसने पुरुषों की टी-42 केटेगरी की ऊँची कूद में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। टी-42 केटेगरी का मतलब है कि शरीर के निचले हिस्से की खामियोंवाले खिलाड़ी। मरियप्पन इसी टी-42 केटेगरी के खिलाड़ी हैं।

वैसे तो इन खेलों में भाग लेने वाला हर खिलाड़ी सम्मान का हकदार होता है, क्योंकि शारीरिक खामियों के बावजूद इन खेलों में भाग लेने का जज्बा रखते हैं। मरियप्पन द्वारा जीता स्वर्ण पदक भारतीय खिलाड़ियों द्वारा पैरालम्पिक खेलों में अब तक जीता तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले मुरलीकांत पेटकर ने 1972 में तैराकी में और देवेन्द्र झुझारिया 2004 के एथेंस पैरालम्पिक में तथा 2016 में भी पुनः जेवेलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में वरुण सिंह भाटी के कांस्य पदक जीत पर सोने पे सुहागा का काम किया। मरियप्पन की इस जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सिर्फ सुविधाओं में खेलने वालों को ही सफलता नहीं मिलती है, बल्कि मरियप्पन जैसे खिलाड़ी टैलेंट के बूते अपनी दुनिया में धाक जमा रहे हैं। इससे तो लगता है कि आप में यदि टैलेंट हो, तो थोड़ी मदद मिलने पर भी आप ऊँची उड़ान भर सकते हैं, मगर इस देश के और लोगों के साथ मुझे

भी इस बात का बेहद अफसोस हो रहा है कि जिस तरह कुछ दिनों पहले रियो ओलंपिक में शटलर पी वी सिंधु के रजत जीतने और महिला पहलवान साक्षी मलिक के कांस्य पदक जीतने पर देश में खुशी का जो माहौल बना था, वैसा माहौल मरियप्पन के स्वर्ण पदक और वरुण सिंह भाटी के कांस्य पदक जीतने पर नहीं बना। वास्तव में यह अफसोसजनक है जबकि मरियप्पन, सिंधु, मलिक तथा झझारिया ने शायर के इस ख्वाब को सच में बदला है–

'खुद से लड़ने के लिए जिस दिन खड़ा हो जाऊँगा,
देख लेना उस दिन खुद से बड़ा हो जाऊँगा।'

(53) प्रश्न: भारत की अमेरिका से बढ़ती नजदीकी बुद्धिजीवियों के एक तबके को क्यों रास नहीं आ रही है?

उत्तर: आपको याद होगा दशकों पूर्व देश की स्थिति को देखकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया गया था जिसमें हमारा देश भारत भी साथ रहा है, लेकिन आज वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक परदृिश्य बदल रहे हैं, इसलिए आज देश को गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नहीं, बल्कि ताकतवर देशों के साथ बेहतर संबंधों की जरूरत है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब भी विदेश की यात्रा पर निकलते हैं, तब उसके पीछे उनका कुछ मकसद होता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि चीन और पाकिस्तान से मिल रही चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया में एक राय रखने वाले देशों को एक कड़ी में पिरोना समझदारी है? नरेन्द्र मोदी यही तो कर रहे हैं। साझा मूल्यों के आधार पर एक ऐसा मंच वह खड़ा करना चाहते हैं, जो किसी भी कार्रवाई का पूरे दमखम से जवाब दे सके। अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील अरब अमीरात, ब्रिटेन, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से अच्छे संबंध बनाकर मोदी जी इसमें काफी हदतक कामयाब होते दिख रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने पिछले दिनों आईआईटी, दिल्ली में दिए गए अपने संबोधन में बिल्कुल ठीक कहा कि भारत और अमेरिका ने इतिहास की हिचकिचाहट से पिंड छुड़ा लिए हैं। भारत ने चीन और पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध बनाने के हर संभव प्रयास किए, किंतु दोनों देशों के रूख में अबतक कोई बदलाव नहीं आया, तब हमने अमेरिका से अपनी नजदीकी बढ़ाकर देशहित में कदम बढ़ाया है तो तथाकथित बुद्धिजीवियों को रास नहीं आना स्वाभाविक है।

दरअसल, हमारे देश में बुद्धिजीवियाँ का एक तबका ऐसा है, जो न

तो शक्तिशाली देशों को देखना चाहते हैं और न नरेन्द्र मोदी की राष्ट्रीयता और देशहित से कोई लेना-देना है। आखिर तभी तो आतंकवादियों तथा देश के कुछ युवा लोगों द्वारा खुलेआम सड़कों पर एक अलगाववादी की बरखी पर उनका जिंदाबाद के नारे लगाने के साथ पाकिस्तान के झंडे फहराने और देशविरोधी नारे लगाने में वे प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों को भला नरेन्द्र मोदी के बढ़ते कदम कैसे पसंद आएँगे?

अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपनी पाकिस्तान नीति में मोहरे कुछ इस तरह चलने होंगे कि कश्मीर में दुस्साहस के लिए इस्लामाबाद का असहनीय मूल्य चुकाना पड़े। अब भारत की भी बर्दाश्त की सीमा हद हो चुकी है और इस मुद्दे पर अब अमेरिका का रवैया बदल चुका है तथा चीन भी सिर्फ पाकिस्तान को कामचलाऊ समर्थन दे रहा है। ऐसे बुद्धिजीवियों के उस तबके को जिन्हें अमेरिका के साथ हमारी बढ़ती नजदीकी रास नहीं आ रही है उन्हें दीवारों पर स्पष्ट लिखी इबारत को पढ़ लेना चाहिए। बुद्धिजीवी का एक तबका अगर दीवार पर लिखी इबारत नहीं पढ़ पाए, तो यह उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अमेरिका तथा अन्य शक्तिशाली देशों के साथ भारत की नजदीकी के चलते ही तो आतंक को पनाह देने पर एक के बाद एक देश न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे हैं, बल्कि उसे लगातार चेतावनी दे रहे हैं। भारत और अमेरिका की तरफ से आतंक से लड़ने की पाकिस्तान की नीयत पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच जो लगातार सहयोगात्मक बातचीत हो रही है, यह उसी का नतीजा है।

बुद्धिजीवियों के एक खास तबके को अमेरिका से भारत की बढ़ती नजदीकी रास नहीं आ रही है यह सवाल प्रगतिशील विचारधारा का झंडा आज भी उठाए घुम रहे लेखकों, चिंतकों और विचारकों को अपने बीच उठाना चाहिए कि उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता सर्व समावेशी दरकार पर क्यों खरी नहीं उतरती? यह कहना कदाचित अनुचित नहीं होगा कि वाम जमात ने इतिहास से लेकर साहित्य तक जिस तरह अपने वर्चस्व को भारत में लंबे समय तक बनाए रखा, वह दौर अब हांफने लगा है। असहिष्णुता पर बहस और विरोध के दौरान यह खुलकर सामने आया था कि सत्तासीन से उपकृत होने वाले कैसे अब तक अभिव्यक्ति और चेतना के जनवादी तकाजों को सिर पर लेकर घूम रहे थे। अब जबकि वाम शिविर की प्रगतिशीलता अपने अंतर्विरोधों की वजह से खुद-ब-खुद अंतिम ढलान पर है, तो हमें एक खुली और धुली दृष्टि से इतिहास के उन पन्नों पर नजर दौड़ानी चाहिए, जिस पर

अब तक वाम पूर्वाग्रह की धूल जमती रही है।

और तो और जे. पी. के संपूर्ण क्रांति अभियान के चौहत्तर आंदोलन के वक्त संघर्षशील युवाओं और रचनात्मक कार्यकर्ताओं की जमात के साथ कलम के उन सिपाहियों को भी जे.पी. नहीं भूल पाए थे, क्योंकि वे जन चेतना की अक्षर ज्योति जलाने में बड़ी भूमिका निभा सकते थे और कवि रामगोपाल दीक्षित ने तो लिखा भी कि–

'आओ कृषक श्रमिक नागरिकों इंकलाब का नारा दो,
गुरुजन शिक्षक बुद्धिजीवियों, अनुभव भरा सहारा दो।
फिर देखें हम सत्ता कितनी बर्बर है बौराई है
तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है।'

पर दुर्भाग्य से हिंदी आलोचना के लाल साफाधारियों और आज अहिष्णुता के सवाल पर बढ़कर बोलने वालों ने देश में दूसरी आजादी की लड़ाई की गोद में रची गई। उस काव्य रचनात्मक के मुद्दे पर जान–बूझकर उस वक्त चुप्पी अख्तियार कर ली, जिसमें कलम की भूमिका कागज से आगे सड़क और समाज के स्तर पर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की हो गई थी। कागज पर मूर्तन और अमूर्तन के खेल को अभिजात्य सौंदर्य बोध और नवपरिष्कृत चेतना का फलसफा गढ़ने वाले वाम आलोचक और प्रबुद्धजन अगर आज भी पाकिस्तान और चीन की चुनौती को स्वीकार करने के लिए अमेरिका एवं जापान, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देशों से बढ़ती नजदीकी को स्वीकार करने से बच रहे हैं, तो इसे हिंदी भाषा और साहित्य के साथ–साथ देशहित के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ही कहेंगे और इसके लिए आगे आने वाले दिनों में इस देश की जनता उन्हें माफ नहीं कर पाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने देखा नहीं, हाल ही में 'अपने दुश्मन को पहचाने' शीर्षक लेख में माकपा के पूर्व महासचिव प्रकाश करात ने लिखा है कि जो वामपंथी और उदारवादी बुद्धिजीवी केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार को फासीवादी सरकार बता रहे हैं, वे स्थितियों को अतिरंजित करके देख रहे हैं। इधर माले ने करात की बात से करीबी जताते हुए काँग्रेस के साथ मोर्चा बनाने को आत्मघाती कहा है।

(54) प्रश्न: उत्तर कोरिया द्वारा विगत 9 सितंबर, 2016 को अपने सबसे शक्तिशाली पाँचवें परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय उत्तर कोरिया के खिलाफ हो गया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर: उत्तर कोरिया ने विगत 9 सितंबर, 2016 को पाँचवां परमाणु परीक्षण किया जो सफल रहा है। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने कहा कि परीक्षण से रॉकेट पर लघु परमाणु आयुध लगाने में सक्षम होने का देश का लक्ष्य पूरा हो गया। इसके पहले उत्तर कोरिया ने जनवरी, 2016 में चौथा परमाणु परीक्षण किया था और उसके पहले 2006, 2009 और 2013 में भी परमाणु परीक्षण किया था जिन पर उनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घोर आलोचना हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने परीक्षण को उकसावे की कार्रवाई बताया और चीन से लेकर फ्रांस, जापान व अमेरिका ने इसकी कड़ी निंदा की है और इस प्रकार परीक्षण के बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय उत्तर कोरिया के खिलाफ एक हो गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उस पर प्रतिबंध भी लगाए, क्योंकि किम जोंग उनकी परमाणु हथियार बनाने के प्रति दीवानगी गंभीर चुनौती उत्पन्न कर रही है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने भी कहा- भारत उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु परीक्षण की निंदा करता है। यह गंभीर चुनौती का विषय है कि उत्तर कोरिया ने अंतरराष्ट्रीय बाध्यताओं का उल्लंघन करके और कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियारविहीन बनाने के उद्येश्य के विपरीत फिर से कदम उठाया है। जहाँ तक इस पर मेरी प्रतिक्रिया का सवाल है जब इस परीक्षण की ताकत 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए बम से डेढ़ गुना ज्यादा बताई गई है तो निश्चित रूप से अंतरराष्ट्रीय समुदायों के बीच तनाव बढ़ेगा और शांति छीन जाएगी।

(55) प्रश्न: क्या आपको ऐसा लगता है कि अमेरिका, चीन और रूस के परस्पर विरोधाभासी हितों और नए सामरिक संबंधों से दक्षिण एशिया की परिस्थितियों में तेज बदलाव के संकेत हैं? आखिर क्यों?

उत्तर: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका, चीन और रूस के परस्पर विरोधाभासी हितों और नए सामरिक संबंधों से दक्षिण एशिया की परिस्थितियों में तेज बदलाव के संकेत हैं, क्योंकि शीत युद्ध के दौर में एक-दूसरे को शक की नजर से देखने वाले भारत और अमेरिका अब इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव, खासतौर पर दक्षिण चीन सागर में, के बरक्स अपने रक्षा और व्यापारिक संबंध मजबूत कर रहे हैं। दूसरी ओर, पाकिस्तान और अमेरिका के पुराने रिश्तों में दरार पड़ने लगी है। ऐसे में पाकिस्तान अब रूस के साथ कई स्तरों पर साझेदारी की संभावना तलाश रही है। दोनों देश

पहली बार साझा सैन्य अभ्यास की तैयारी कर रहे हैं। यही नहीं कृषि उत्पादों के पाकिस्तान से निर्यात तथा रूस द्वारा अत्याधुनिक लड़ाकू विमान और रक्षा उपकरणों देने जैसे कारकों को भी जोड़ दिया जाए, तो संकेत साफ है कि दोनों देशों की निकटता बढ़ी है।

हालिया दिनों में एक ओर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है, तो दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय राजनीति की खींचतान में अमेरिका और रूस को आमने-सामने ला खड़ा किया है। ऐसे समय में दक्षिण एशिया में भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया में वियतनाम के अमेरिका की ओर बढ़ते झुकाव से रूस का चिंतित होना स्वाभाविक है। उधर दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों को रूसी समर्थन मिल रहा है, तो अमेरिका और भारत इस मामले में वह पाकिस्तान पर अधिक भरोसा नहीं कर सकता है।

(56) प्रश्न: क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पाकिस्तान को बेनकाब करने का कोई भी अवसर हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं? आखिर कैसे?

उत्तर: हाँ, विजय जी, आपकी इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पाकिस्तान को बेनकाब करने का कोई भी अवसर हाथ से जाने नहीं देना नहीं चाहते हैं। आपने अभी देखा नहीं पिछले दिनों चीन की धरती हांगझोऊ शहर में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के मंच से जी-20 के नेताओं से आतंकवाद का प्रायोजन करने वालों को प्रतिबंधित और अलग-थलग करने का जो बयान दिया उसके एक दिन पहले वियतनाम की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान भी एक तरफ जहाँ चीन-पाक गठजोड़ तोड़ने की बात की, तो वही दूसरी तरफ बलुचिस्तान-पीओके के जरिए पाकिस्तानी आतंकवादी की कमर तोड़ने की नरेन्द्र मोदी की रणनीति अपनाए जाने से तो ऐसा लगता है कि नरेन्द्र मोदी पाकिस्तान को बेनकाब करने का कोई अवसर हाथ से जाने नहीं देना चाहते।

अभी-अभी जी-20 शिखर सम्मेलन के कुछ दिनों बाद नरेन्द्र मोदी ने लाओस की राजधानी वियतियाने में आयोजित 11वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी आसियान के मंच से आतंकियों को पनाह देने के लिए इस्लामाबाद को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि दक्षिण एशिया के ज्यादातर देश शांतिपूर्ण रास्ते पर चलकर आर्थिक समृद्धि हासिल करना चाहते हैं, लेकिन भारत के पड़ोस में एक देश ऐसा है, जो प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने के लिए सिर्फ आतंकवाद का उत्पादन और निर्यात कर रहा है। अमेरिकी

राष्ट्रपति बराक ओबामा और चीनी प्रधानमंत्री लीकछ्यांग की उपस्थिति में नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद के वैश्विक कारोबार पर रोक लगाने का अब समय आ गया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के प्रायोजकों पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें अलग-थलग कर दिया जाना चाहिए, न कि पुरस्कार दिया जाना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए आसियान में शामिल दूसरे सदस्य देशों के साथ आने की अपील करते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंक के निर्यात क्षेत्र के लिए चिंता का कारण बन गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ आतंकियों को खत्म करना नहीं है; बल्कि उन्हें समर्थन देने वाले पूरे तंत्र पर नजर रखनी है। हमें उन देशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी, जो आतंकवाद का इस्तेमाल सरकारी मशीनरी के तौर पर करते हैं।

नरेन्द्र मोदी कंबोडिया के अलावा आसियान के दस देशों-म्यांमार, सिंगापुर, मलयेशिया, लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस और थाइलैंड की यात्रा का ध्यान केंद्रित करने की अपनी कूटनीतिक प्राथमिकता को स्पष्ट कर दिया है। यह इलाका बंगाल की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है और इस रास्ते से भारत का 50 फीसदी व्यापार संचालित होता है। इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे के कारण अनेक आसियान देश भारत को एक सहयोगी के रूप में देखने लगे हैं।

(57) प्रश्नः चीन के हांगझोऊ शहर में विगत सितंबर, 2016 में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेताओं को जिस लहजे में आतंक, भ्रष्टाचार और कालेधन पर खरी-खरी सुनाई उससे क्या ऐसा नहीं लगता कि अपने हितों की रक्षा के लिए ऐसी ही कूटनीति की दरकार है जो टकराव तो न बढ़ाए, मगर संबंधित देशों से दो टूक बात कहने से भी परहेज न किया जाए? जी-20 शिखर सम्मेलन के मंच से प्रधानमंत्री के संबोधन और आह्वान को आप किस रूप में आँकते हैं?

उत्तरः सितंबर, 2016 के प्रथम सप्ताह में चीन के हांगझोऊ शहर में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेताओं को जिस लहजे में आतंक, भ्रष्टाचार और कालेधन से निबटने के लिए खरी-खरी सुनाई उससे नरेन्द्र मोदी की नीयत साफ झलकती है कि अपने देश के हित में ऐसी ही कूटनीति की दरकार है जो टकराव तो न बढ़ाए, मगर

संबंधित देशों में टो-टूक बात कहने से भी परहेज न किया जाए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि एक देश अकेले ही दक्षिण एशिया में आतंकवादियों को एजेंट फैलाने में जुटा है। पाकिस्तान को शह देने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के समक्ष पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों को लेकर चीन के रवैए पर आश्चर्य प्रकट किया और उन्होंने सलाह दी कि आतंकवाद को राजनीतिक हितों की दृष्टि से नहीं देखे जाना चाहिए।

इसी प्रकार नरेन्द्र मोदी ने जी-20 शिखर सम्मेलन में कालेधन पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षित पनाहगाह दिया। कालेधन का मसला आतंकवाद से भी इसलिए जुड़ा है, क्योंकि उससे उसके वित्त पोषण की आशंकाएँ कई बार जाहिर की जा चुकी हैं। इसके लिए जी-20 सम्मेलन का मंच इसलिए सबसे उपयुक्त मंच है, क्योंकि इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका, और यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व होता है। दुनिया का 80 प्रतिशत जीडीपी इन्हीं से मिलकर बनता है। इसलिए कालेधन और आतंकवाद के साथ चीन की पाकिस्तान से बढ़ती दोस्ती पर दुनिया को आगाह करने का सही मंच यही था। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कालेधन, कर चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपियों को पकड़ने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पर बल देते हुए उन्होंने आतंक को शह देने की चीन की नीति की घोर आलोचना की और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कार्रवाई करने को कहा। प्रधानमंत्री के लिए हांगझोऊ में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन का मंच ऐसा ही था जिसका समुचित उपयोग करते हुए उन्होंने भारत की चिंताओं को सामने रखा तथा यह संदेश भी बखूबी दे दिया कि वैश्विक, आर्थिक और राजनीतिक तंत्र में भारत की एक महत्वपूर्ण उपस्थिति है, जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। इस दृष्टिकोण से दुनिया की ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं के मंच जी-20 के अंतिम सत्र में मोदी ने विश्व समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की और इस पर दोहरे मापदंड न अपनाने की सलाह दी। यही नहीं आतंकवाद को समर्थन दे रहे देशों को अलग-थलग करने की बात भी की न कि उनका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवाद पर भारत की नीति जीरो टोलरेंस की है, क्योंकि इससे कम कुछ नहीं चलेगा।

इसी प्रकार आर्थिक अपराधियों की पनाहगाह को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जी-20 की बैठक में भ्रष्टाचार और कालेधन पर रोक लगाने की बात करते हुए सदस्य देशों से मदद की अपील की, क्योंकि प्रभावी वित्तीय संचालन के लिए भ्रष्टाचार, कालाधन और कर चोरी से निपटना जरूरी है। इसके लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ आर्थिक अपराधियों की सुरक्षित पनाहगाह खत्म करनी होगी और साथ ही मनी लांड्रिंग करने वालों का बिना शर्त प्रत्यर्पण, जटिल अंतरराष्ट्रीय नियम सरल बनाना और बहुत ज्यादा गोपनीयता खत्म करने की दिशा में प्रयास जरूरी है। यही गतिविधियाँ भ्रष्टाचार पर पर्दा डालती हैं।

भ्रष्टाचार, कालेधन और आतंकवाद के मसले पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जी-20 शिखर सम्मेलन के नेताओं से बिना कोई लाग-लपेट के खरी-खोटी बात की है उससे उनकी साफ नीयत का पता चलता है और देश हित में एक प्रधानमंत्री को अंतरराष्ट्रीय मंच से जैसी स्पष्ट बात करनी चाहिए, मुझे लगता है कि आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉ. मनमोहन सिंह तक के किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी खुलकर बातें नहीं कीं, कारण चाहे जो हो, मगर इतना जरूर है कि किन्हीं को शांति का नोबल पुरस्कार लेने की इच्छा थी, तो किसी में इतना साहस नहीं था कि वे अपने देश हित में खरी-खोटी बात कर सकें। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जितनी सराहना की जाए कम होगी।

यह बात किसी से छिपी नहीं है कि दिन-प्रतिदिन मुखर हो रहे आतंकवाद से समूचा विश्व त्रस्त और हतोत्साहित है और जिन सरकारों का अपने-अपने देशों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगा होना चाहिए, उसमें भारत के प्रधानमंत्री द्वारा निश्चित रूप से अपने देश के नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री विश्व बन्धुत्व की भावना बनाए रखते हुए नापाक इरादा वाले देश को मुँहतोड़ जवाब देना जानते हैं। बार-बार समझाने और वार्ता के बाद भी यदि कोई देश नहीं समझता है तो उसे मुँहतोड़ जवाब देना देशहित में कहा जाएगा। आजादी के नाम पर कश्मीर को जहन्नुम बनाने वाले लोग क्या कभी कश्मीरियों के हितैषी हो सकते हैं? इसका उत्तर सीधे नकारात्मक होगा। जिस प्रकार इस्लाम के उजले दामन पर आतंकवाद के रूप में लगे काले दाग का दायरा दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए अब इसे साफ करने की प्रक्रिया वृहद स्तर पर प्रारंभ करने की महती आवश्यकता है। हमारे

प्रधानमंत्री के कदम उसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं यह हम देशवासियों के लिए प्रसन्नता की बात है। हांगझाऊ में आयोजित जी–20 शिखर सम्मेलन के मंच से उनका संबोधन और आह्वान इसी का प्रतीक कहा जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जी–20 शिखर सम्मेलन के दौरान हांगझाऊ में जो सराहना की गयी, वह उनकी पश्चिमी देशों की यात्राओं में मिली प्रशंसा की टक्कर की ही थी। ग्रुप फोटो के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अनदेखी करके नरेन्द्र मोदी को खोजते हुए उनके पास पहुँचे और उनसे गले मिले। ओबामा ने अपने भाषण में जीएसटी पारित कराने के लिए के लिए मोदी की तारीफ की। जापान की प्रधानमंत्री ने भी उनकी तारीफ की और तमाम बातों के बावजूद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी ऊर्जा नीति को लेकर मोदी की तारीफ की। बचे रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन? पुतिन ने इशारों–इशारों में भारत विरोध के खिलाफ चीन को जो चेतावनी दी, वह चीन के कानों में काफी समय तक गूँजती रहेगी। इसी तरह दो दिवसीय वियतनाम यात्रा के दौरान भी मोदी–मोदी के नारों से आसमान गूँज गया था। हालांकि वियतनाम दौरा प्रतीकात्मक नहीं था, लेकिन इसे प्रतीक समझने का मैसेज चीन तक बखूबी पहुँच गया। एक तरफ चीन–पाक गठजोड़ तोड़ने और दूसरे ब्लूचिस्तान–पीओके के जरिए पाकिस्तानी आतंकवाद की कमर तोड़ने की प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति अच्छे परिणाम देती नजर आ रही है। सम्मेलन के बाद चीनी विद्वानों के एक जत्थे ने प्रधानमंत्री को भारतीय दर्शन के चीनी अनुवाद की प्रतियाँ भेंट की। चीन अमूमन दार्शनिक स्तर पर समर्पण नहीं करता है। यही नहीं, मोदी ने वियतनाम से भारत के 2000 साल के पुराने संबंध की चर्चा करते हुए कहा कि कुछ लोग यहाँ युद्ध करने आए, हम यहाँ शांति का संदेश लेकर आए। युद्ध ने आपको दुनिया से दूर किया, बुद्ध ने आपको भारत से जोड़ दिया। मैं आपका यजमान हूँ, आपको निमंत्रण देता हूँ कि भगवान बुद्ध की धरती पर आइए। इन पंक्तियों में भावनात्मक पुट तो है ही, लेकिन गहरा अर्थ भी है। और वह है कि चीन ने आपको युद्ध दिया और हमने आपको बुद्ध। इसलिए आप अपने यजमान की धरती से रागात्मक संबंध रखिए।

(58) प्रश्नः क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत की विदेश नीति सही दिशा में कार्य कर रही है?

उत्तर : हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि भारत की विदेश नीति सही दिशा में कार्य कर रही है। खासतौर पर जबसे नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में

सरकार बनी है, तब से यदि उसके दो साल में सिलसिलेवार उठाए गए कदमों का हम विवेचन करें, तो योजनाबद्ध सुस्पष्ट तरीके और मजबूत इरादे के साथ भारतीय कूटनीति पृष्ठभूमि में काम कर रही है। कूटनीति की सफलता इसी बात में है कि दुश्मन को चाल के पीछे छिपे इरादों का पता नहीं लगना चाहिए। ऐसा लगता है कि कूटनीति में शतरंज की तरह ही राजा के सारे मार्ग बंद करके अचानक शह दी जाती है और उसे बचाने के लिए तबतक बहुत देर हो चुकी होती है। शह मिलने के बाद ही पुरानी चालों का रहस्य समझ में आता है। आपने देखा नहीं भारत की आजादी की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर लाल किले प्राचीर से 15 अगस्त, 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन में पाकिस्तान के प्रांत बलूचिस्तान और पाकिस्तानी कब्जेवाले गिलगिट क्षेत्र की जब बात की, तो कूटनीति का पूरा मंजर ही बदल गया। बलूचिस्तान में वर्षो से अत्याचार से पीड़ित राष्ट्रवादियों को नई ऊर्जा मिल गई। अब तो सिंध में बसे मुजाहिरों को नयी आवाज मिल गयी। पाकिस्तानी सेना घर में फैले इस विद्रोह को दबाने के लिए अब न तो उसके पास समय है और न हीं संसाधन। पाकिस्तान अपनी नीतियों से आत्मविनाशकारी ढलान पर तेजी से लुढ़क रहा है।

ठीक इसी प्रकार चीन के शहर हांगझोऊ में आयोजित जी-20 शिखर में शामिल होने के पूर्व वियतनाम की दो दिवसीय यात्रा और शिखर सम्मेलन में भ्रष्टाचार, कालेधन, कर की चोरी और आतंकवाद पर बीस देशों के नेताओं को चीन और पाकिस्तान को जो खरी-खरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सुनाई उससे तो विदेशनीति की सफलता कही जाएगी, क्योंकि उन्होंने शक्तिसंपन्न देशों का दिल जीता है और पाकिस्तान एवं चीन को सोचने के लिए विवश किया है।

गुलजार देहलवी साहब की ग़ज़ल की एक पंक्ति है-' 'नाम' गुम जाएगा, चेहरा जब बदल जाएगा', मुझे लगता है नरेन्द्र मोदी पर गुलजार की यह पंक्ति बिल्कुल सटीक इसलिए बैठती है, क्योंकि उनकी विदेश नीति मे भारी तब्दीली इससे बेहतर ढंग से नहीं बताई जा सकती है। पिछले दिनों अगस्त, 2016 के अंतिम सप्ताह में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अमेरिका के कैपिटल हिल में इस्तेमाल इस जुमले का उल्लेख किया। केरी ने उसे दोहराते हुए कहा कि भारत और अमेरिका ने न केवल इतिहास की हिचकिचाहट से पिंड छुड़ा लिया है, बल्कि इतिहास के पाखंडों से भी मुक्ति पा ली है।

आपको याद होगा बर्लिन की दीवार ढहने के बाद भारत ने तीन महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री पी वी नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉ. मनमोहन सिंह ने माना था कि पुरानी उदासीनता को झटक देने की जरूरत है। इनमें से प्रत्येक ने अपने-अपने तरीके से और अपनी-अपनी परिस्थितियों के अनुरूप ऐसा करने का प्रयत्न किया, लेकिन प्रत्येक मौके पर पाखंड की बजाय हिचकिचाहट ने उसे रोक दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उसे भूतकाल को फेंक दिया है और वह भी पूरे दुस्साहस के साथ। गुट निरपेक्ष आंदोलन के गठन के बाद से यह पहला वर्ष है, जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मौजूद नहीं रहे। तीस साल में पूर्ण बहुमत हासिल करने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब ऐसा करते हैं, तो वह एक वक्तव्य होता है, खासतौर पर तब जब वे विदेश यात्रा के इतने शौकीन हैं। इससे स्पष्ट होता है कि परंपरा से हटकर और लकीर का फकीर न होकर मोदी विदेश नीति को सही दिशा में ले जा रहे हैं।

इसी प्रकार सुन्नी व शिया सहित पूरे इस्लामी जगत से द्विपक्षीय संबंधों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व्यक्तिगत व राष्ट्रीय दोनों हैसियतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ऐसे वक्त जब अमेरिका से यूरोप व चीन तक और यहाँ तक कि सउदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात कट्टरपंथी इस्लाम से तंग आ चुके हैं और आईएसआईएस का विस्तार रोकने में ईरान की प्रमुख भूमिका देखते हुए मोदी जी के लिए पूरी गुंजाइश है। यह कम आश्चर्य की बात नहीं है कि संयुक्त अरब अमीरात जैसे इस्लामिक देश के सर्वश्रेष्ठ सम्मान से मोदी जी सम्मानित किए जाते हैं। आखिर यह विदेश नीति की सही दिशा में जाने का ही तो प्रतीक है।

यही रवैया पाकिस्तान के प्रति नई नीति और पाक अधिकृत कश्मीर गिलगिट और बलूचिसतान के जिक्र की वजह है। कश्मीर पर सावधानी बरतने की 25 साल पुरानी नीति को डम्प कर दिया गया है, खासतौर पर तब जब पाकिस्तान अलग-थलग पड़ चुका है। अपने ही नागरिकों के खिलाफ एफ-16 और तोपखाने के इस्तेमाल की वजह से कश्मीर में मानवाधिकार हनन को लेकर भारत से सवाल करने का पाक को नैतिक हक नहीं है। ये सब कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत की विदेश नीति में साफ बदलाव हो रहा है और वह बदलाव सही दिशा में है। कारण कि राष्ट्रीय संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने पर कोई समझौता नहीं करने का संकल्प लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जी-20 के नेताओं से

आतंकवाद का प्रायोजन करने वालों को प्रतिबंधित और अलग-थलग करने *का जो बयान दिया उसके ठीक बाद जी-20* के सदस्य देशों ने आतंकवाद की पूरजोर निंदा की और आतंकवाद के वित्तपोषण के सभी स्रोतों, तकनीकों और माध्यमों से निपटने का जो संकल्प लिया वह भारतीय विदेश नीति का सही दिशा में जाने का संकेत है।

(59)प्रश्नःक्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि 1947 के बाद से अबतक पाकिस्तान का खटराग एक ही रहा कि 'कश्मीर हमारा है और भारत हमारा एकमात्र दुश्मन राष्ट्र'? क्या इस खटराग को दोहराने का काम पाकिस्तानी जमीन पर कायम आतंकी जमाते करती हैं या पाकिस्तान के जनप्रतिनिधि अथवा वहाँ के सैन्य प्रमुख?

उत्तरः हाँ, मैं भी यह महसूस करता हूँ कि 1947 के बाद अबतक पाकिस्तान का खटराग एक ही रहा है कि 'कश्मीर हमारा है और भारत हमारा एकमात्र दुश्मन राष्ट्र।' अधिकतर राष्ट्र युद्ध लड़ते हैं और युद्ध की यादों को जीवित रखने के उपक्रम भी करते हैं और ऐसी कोशिश के जरिए अपने नागरिकों और विश्व बिरादरी को यह संदेश देना चाहते हैं कि युद्ध कोई भी हो, अपने आखिरी नतीजे में वह विध्वंश लाने वाला साबित होता है। इसलिए आपसी अमन ही मनुष्यता की रक्षा का एकमात्र रास्ता है। सभ्य राष्ट्र जानते हैं कि युद्ध की यादों को हर वक्त सीने से लगाए रखना मृत्यु पूजा सरीखी मनोविकृति है, लेकिन ढेर सारी विसंगतियोंवाला देश पाकिस्तान इस मामले में भी बाकी राष्ट्रों से अलग हटकर है। वह युग की अपनी यादों को जिलाए रखने की कोशिश करता है, ताकि दुनिया को बता सके कि वह जंग लड़ने को आमादा है।

युद्ध को लेकर पाकिस्तानी मानस में मौजूद इसी मनोविकृति का संकेत है वहाँ की सेना के प्रमुख राहील शरीफ का भारत को खबरदार करते हुए यह बयान कि 'दुश्मन छोटा हो या बड़ा, अगर उसने हमला किया, तो हम मुँहतोड़ जवाब देंगे।' राहील शरीफ के ये बोल 1965 में हुए भारत-पाक युद्ध की पचासवीं वर्षगांठ पर रावलपिंडी में आयोजित कार्यक्रम में गूंजे यानी युद्ध की एक याद का इस्तेमाल अनागत एक और युद्ध की दुदुंभि बजाने के रूप में किया गया। पाकिस्तान ने अपने जन्म के साथ दुनिया के सामने अपना युद्धप्रेम जाहिर किया और राहील शरीफ का बयान इस बात की मुनादी है कि उनका मुल्क आज के दिन तक अपनी इस मनोविकृति से उबर नहीं

पाया है। 1947 के बाद से अबतक पाकिस्तान का खटराग एक ही रहा कि 'कश्मीर हमारा है और भारत हमारा एकमात्र दुश्मन राष्ट्र।'

यूँ तो इस खटराग को दोहराने का काम पाकिस्तानी जमीन पर कायम आतंकी जमातें करती रहती हैं, परंतु मौका देखकर कभी पाकिस्तान के जनप्रतिनिधि दोहराते हैं और कभी सैन्य प्रमुख। पिछले 15 अगस्त, 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लालकिले के प्राचीर से किए गए संबोधन में बलूचिस्तान, गिलगिट-बाल्टिस्तान में होने वाले मानवाधिकार हनन की बात के बाद से पाकिस्तान का युद्ध राग कश्मीर प्रेम के बहाने कुछ ज्यादा ही बजने लगा है।

(59) प्रश्नः दक्षिण चीन सागर पर भारत के रूख को वियतनाम ने किस रूप में देखा है? प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वियतनाम का दो-दिवसीय दौरे के दौरान वहाँ के नेताओं के साथ मुख्य रूप से किस बात पर बल दिया गया? दोनों देशों के बीच व्यापार की क्या स्थिति है?

उत्तरः दक्षिण चीन सागर पर भारत के रूख को वियतनाम ने सराहणीय बताया है। इस सागर को लेकर वियतनाम और चीन के बीच विवाद है। विवादास्पद दक्षिण चीन सागर पर वियतनाम के वरिष्ठ नेताओं ने भारत की स्थिति का जोरदार समर्थन किया है। इसके साथ ही भारत ने वियतनाम को रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कर्ज दिया है। साथ ही दोनों देशों ने कुल 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें समुद्र में निगरानी करने वाली नौकाओं का निर्माण भी शामिल है। इसका मकसद विवादास्पद दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय चुनौतियों का मुकाबला करना है।

साम्यवादी देश वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव गुयेन फु ट्रांग ने विगत 3 सितंबर, 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बताया कि दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर भारत के रूख से वियतनाम पूरी तरह से सहमत है। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय और बहुआयामी मुद्दों पर हमें अपना तालमेल और बेहतर करना चाहिए। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत और वियतनाम को मिलकर क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना करना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक से मुलाकात कर सामरिक रिश्तों को और मजबूत करने पर बल दिया। इससे पहले वियतनाम की रणनीतिक साझेदारी केवल रूस और चीन से थी। वियतनाम की राजधानी हनोई में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भव्य स्वागत वहाँ

के प्रधानमंत्री ने भारत के तिरंगे झंडे फहराकर किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हनोई में ही 20वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में से एक रहे होचिमिन्ह की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

साल 2013 में दोनों देशों के बीच 5.23 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था और पिछले साल की तुलना में इसमें 32.8 डॉलर फीसदी की बढ़ोतरी हुई। 2014 में यह आँकड़ा बढ़कर 5.60 बिलियन डॉलर हो गया। दोनों देशों के बीच 2020 तक 15 बिलियन डॉलर के व्यापार का लक्ष्य है। भारत वियतनाम में 111 प्रोजेक्ट में निवेश किए हुए है और इसमें करीब 530 मिलियन डॉलर की पूँजी लगी हुई है। भारतीय कंपनियाँ तेल और गैस, खनिज उत्खनन, एग्रो केमिकल, आईटी सहित तमाम क्षेत्रों में निवेश किए हुए है। वियतनाम ने भी भारत की तीन कंपनियों में कुल 26 मिलियन डॉलर का निवेश किया है। इनमें ओएनजीसी, नगोन कॉफी, टेक महिंद्रा और सीसीएल शामिल है।

उल्लेखनीय है कि वियतनाम को साम्यवादी विचारधारा की वजह से अधिकतर चीन के करीब माना जाता रहा है। जी-20 के सिलसिले में चीन जाने के पहले नरेन्द्र मोदी ने वियतनाम के दौरे के दौरान सागर गर्भ में तेल-गैस के भंडार के शोध दोहन के लिए सरकार की परियोजनाओं को पुनः गतिशील बनाने का प्रयास करने में चीन के अड़ंगे डालने से आए गतिरोध को दूर किया है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए।

(60) प्रश्न:विगत 30 अगस्त, 2016 को भारत-अमेरिका के बीच हुए रक्षा समझौते को क्या आप एशिया में शक्ति संतुलन का नया कदम मानते हैं?

उत्तर: हाँ, विगत 30 अगस्त, 2016 को अमेरिका के वाशिंगठन में भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर और अमेरिकी समकक्ष एश्टन कार्टर के बीच हुए रक्षा समझौते को मैं एशिया में शक्ति संतुलन का नया कदम इसलिए मानता हूँ कि भारत और अमेरिका ने सैन्य सहयोग बढ़ने के लिए अहम समझौता किया है। इसके अंतर्गत दोनों देश सैन्य सुविधाओं को साझा कर सकेंगे। इसके साथ भारत को अमेरिका के महत्वपूर्ण साझेदार का दर्जा प्राप्त हो गया है। इस समझौते के तहत दोनों देशों की सेना एक-दूसरे के सैन्य ठिकानों का उपयोग कर सकेंगी। इतना ही नहीं, साज-समान का उपयोग एवं साज-समान का आदान-प्रदान भी करेंगी। इसके लिए दोनों देशों की रजामंदी आवश्यक होगी।

वाशिंगटन में हुए इस समझौते–'लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट' की अहमियत का अंदाजा इससे भी लग जाता है कि अमेरिका ने जहाँ इसे भारत–अमेरिका संबंध के इतिहास में पिछले 50 वर्षो की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है, वहीं चीन इससे घबराया हुआ है, क्योंकि इस समझौते के तहत दोनों देश अब एक–दूसरे के थल, वायु और नौसेना बेस, ईंधन आपूर्ति सुविधाओं और अन्य रक्षा साजो–समान का इस्तेमाल कर सकेंगे। मगर यह इस्तेमाल युद्ध के लिए न होकर रक्षा अभ्यास, प्रशिक्षण, आपदा के दौरान मानवीय सहायता एवं राहत आदि जैसे कार्यो तक सीमित होगा। साथ ही सुविधा लेने वाला देश इसके लिए न केवल पहले अनुमति लेगा, बल्कि भुगतान भी करेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में भारत के साथ हुए संभवत: आखिरी बड़े समझौते से उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच भरोसा भी बढ़ेगा। इस समझौते से चीन और पाकिस्तान इसलिए भी तिलमिलाए हुए है, क्योंकि दोनों देश मिलकर न केवल भारत को घेरने का प्रयास करते रहे हैं, बल्कि आतंकवाद के मसले पर भी चीन पाकिस्तान का साथ देकर भारत की राह में रोड़े अटकाता रहा है। इसलिए चीन को काबू में रखने के लिए ओबामा प्रशासन के कार्यकाल का यह बेहद अहम समझौता है। इससे भविष्य में भारत को चीन के सामने खड़ा होने के लिए मजबूत आधार मिलेगा। हालांकि, इस समझौते से जहाँ भारत और उसके भरोसेमंद सहयोगी रूस के रिश्तों में तनाव आने की संभावना है, वहीं भारत अब गुटनिरपेक्ष देशों की पंक्ति में खड़ा नहीं हो सकेगा। बराबरी के इस समझौते के बावजूद भारत को इसके प्रति सतर्क रहना पड़ेगा, ताकि विश्व समुदाय को सही संदेश देने के लिए यह जरूरी है कि अमेरिका के साथ अन्य अनेक क्षेत्रों में जो भी समझौते हों वे परस्पर लाभ के फार्मूले के तहत ही हों। भारत और अमेरिका के बीच आपसी संबंधों की प्रगाढ़ता के लिए यह आवश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य है कि दोनों देश एक–दूसरे की चिंताओं को समझें, बल्कि उसका समाधान भी करें। भारत और अमेरिका ने अपने रक्षा संबंधों को एक नई ऊँचाई पर ले जाने के लिए बड़ा कदम उठाया है जिससे भारत की सामरिक स्वयात्तता को बल मिला है।

(61)प्रश्न:पर्वतीय क्षेत्रों पर अरुणाचल प्रदेश में सुपरसेनिक 'ब्रह्मोस' क्रूज मिसाइल तैनात करने के भारत के फैसले से चीन क्यों बेचैन हो उठा है?

उत्तर: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षतावाली सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पर्वतीय क्षेत्रों पर अरुणाचल प्रदेश में युद्ध के लिए विकसित सुपरसेनिक 'ब्रह्मोस' क्रूज मिसाइल के आधुनिक संस्करण से लैस एक नई रेजिमेंट की स्थापना को मंजूरी दी है। इस रेजिमेंट में करीब 100 मिसाइल, 5 मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर्स और मोबाइल कमांड पोस्ट शामिल है। ब्रह्मोस मिसाइल देश की सबसे आधुनिक और दुनिया की सबसे तेज एंटीशिप क्रूज मिसाइल है। इसकी गति 3675 किलोमीटर प्रति घंटे है, जो किसी भी चीनी मिसाइल से करीब तीन गुना ज्यादा तेज है। पूरी फ्लाइट में इसकी सुपरसेनिक स्पीड बरकरार रहती है। इतना ही नहीं यह मिसाइल न्यूक्लियर वारहेड तकनीक से लैस है। यह 290 किलोमीटर दूरी तक के लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखती है और चीन के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। यह मिसाइल जमीन से, पनडुब्बी से, पानी के जहाज से और विमान से भी छोड़ा जा सकता है। इस मिसाइल के दागे जाने के बाद यदि लक्ष्य अपना रास्ता बदल देता है, तो मिसाइल भी अपना रास्ता बदल लेती है और लक्ष्य को निशाना बना लेती है।

दरअसल, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मोस रेजिमेंट की तैनाती के फैसले के पीछे भारत सरकार का उद्येश्य पूर्वोत्तर में सामरिक शक्ति संतुलन बनाए रखना है। चीन अरुणाचल की सीमा से सटे इलाके पर दावा ठोकता रहा है। इसी क्रम में हाल के वर्षो में अरुणाचल की भारत-चीन सीमा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर घुसपैठ की चीनी कोशिशों के चलते दोनों देश के जवानों के बीच झड़पें होती रहती हैं। चीन ने अपनी सीमा पर कई सारी मिसाइलें तैनात कर रखी हैं, जिनका मुँह भारत की तरफ ही है। लेकिन अब जब भारत ने अपनी सीमा पर ब्रह्मोस मिसाइल तैनात करने का फैसला किया है, तो चीन को तकलीफ हो रही है और वह बेचैन हो उठा है। इसलिए उसने इस पर आपत्ति जताई है कि इससे सीमा पर अशांति का माहौल बनेगा। सच्चाई यह है कि चीन की यह आपत्ति सिर्फ अरुणाचल प्रदेश को लेकर है, न कि भारत की सैन्य क्षमता को लेकर है। चीन हमसे बहुत ताकतवर है। उसकी सैन्य क्षमता हमसे बहुत ज्यादा है। दरअसल अपने इस एतराज के जरिए चीन सीधे-सीधे यह बताना चाहता है कि भारत विवादित अरुणाचल क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता है। इस एतराज के पीछे चीन का सिर्फ एक ही मकसद है कि वह अरुणाचल पर अपनी दावेदारी को मानता है। इसलिए वह चाहता है कि वहाँ भारत कोई सैन्य गतिविधि न करे। जबकि भारतीय

सेना ने कहा है कि भारत अपनी सीमा को किस तरह सुरक्षित करेगा, यह उसका निजी मामला है और किसी दूसरे को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। भारत की स्पष्ट नीति रही है कि वह परमाणु हमले की शुरुआत नहीं करेगा, न ही रिहायशी इलाके को निशाना बनाएगा। चीन के खिलाफ कोई युद्ध छेड़ने के लिए भारत ऐसा नहीं कर रहा है, अगर चीन ऐसा सोचता है, तो वह गलत सोचता है।

(62) प्रश्न : क्या आप ऐसा मानते हैं कि भारत-पाक संबंधों की बिसात पर 15 अगस्त, 2016 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बलूचिस्तान, गिलगिट और पाक अधिकृत कश्मीर से संबंधित किए गए संबोधन की चाल ने पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया है?

उत्तर: हाँ, मैं मानता हूँ कि भारत-पाक संबंधों की बिसात पर नरेन्द्र मोदी की एक चाल ने पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया है, क्योंकि विगत 15 अगस्त, 2016 को दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जैसे ही पाकिस्तान को बलूचिस्तान, गिलगिट और पाक-अधिकृत कश्मीर की जन-भावनाओं का आइना दिखाया, भारतीय कूटनीति का एक नया चेहरा विश्व के समक्ष आया। सच मानिए आजादी मिलने के बाद से ही 70 वर्षो से भारत ने पाकिस्तान पर ऐसा रूख अख्तियार कर रखा था कि उससे बेचारगी की बू आती थी और ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे विदेश नीति चलाने वालों ने न कौटिल्य पढ़ा और न ही मैकियावेली, जबकि इसके ठीक विपरीत चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों ने उनके अध्ययन में महारत हासिल कर ली हो।

दरअसल, भारत के पूर्ववर्ती शासन में भी अनेक सरकारें पाकिस्तान के प्रति सख्त रवैए से संभवत: इसलिए परहेज करती रहीं कि कहीं भारत का मुस्लिम समाज और विश्व के इस्लामिक देश नाराज न हो जाएँ? प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बार के लाल किले के संबोधन में इस दृष्टिकोण को त्याग दिया जिसका नतीजा सामने है कि न तो भारत का मुस्लिम समाज और न ही कोई मुस्लिम राष्ट्र मोदी जी के विचारों से नाराज हुआ। उल्टे अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ने भारत का समर्थन किया। यह संभवत: मोदी का भारतीय मुस्लिम समाज पर भरोसा है और विश्व भी यह मानता है कि पारस्परिकता के बावजूद सभी संप्रभु राष्ट्रों को अपने-अपने राष्ट्रीय हितों के संरक्षण का अधिकार है।

जब एक तरफ पाकिस्तान भारत में जघन्य आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने से बाज नहीं आता और दूसरी ओर कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकवादियों को उकसाता है, तो ऐसी स्थिति में पाक से कैसा व्यवहार करना चाहिए, नरेन्द्र मोदी समझ चुके हैं। कहना नहीं होगा कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक संस्कृति विकसित नहीं होने की वजह से वहाँ की जनता अपनी भावनाओं का खुलकर इजहार तो नहीं करती, लेकिन आम पाकिस्तानियों को भारत के लोगों से प्रेम है। वे भारत में बसे अपने बिछड़े परिजनों से मिलना चाहते हैं। वे हिंदी गानों और सिनेमा के दीवाने हैं।

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह समझ लिया है कि आखिर कब तक हम अपने शांतिप्रिय, न्यायप्रिय और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास होने का प्रमाण पत्र विश्व से लेते रहेंगे? कुछ इसी ख्याल से उन्होंने चाहे अमेरिका के दोनों सदनों के सांसदों के संबोधन करना रहा हो अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के समक्ष अपनी बात कहने का मौका मिला हो, नरेन्द्र मोदी ने खुलकर बात की है और दो-टूक बात की है। ठीक यही बानगी उन्होंने इस बार लाल किले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपने संबोधन में बलूचिस्तान, गिलगिट और पाक-अधिकृत कश्मीर के संबंध में दी है। प्रधानमंत्री को यह पता है कि पाकिस्तानी जनता का एक बड़ा भाग भारत का दीवाना है, जो भारतीय लोकतंत्र, उसके विकास की उपलब्धियों और उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि का कायल है। आखिर तभी तो लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद पाकिस्तान की आम जनता की ओर से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं सुनने को मिली कि वे उनके संबोधन से नाराज हैं। इसलिए हमें इस नतीजे पर पहुँचना पड़ा है कि भारत-पाक संबंधों की बिसात पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक चाल ने पाकिस्तान को बैक फुट पर ला दिया है। नरेन्द्र मोदी ने उपद्रवग्रस्त बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के हनन के प्रति संवेदनशीलता मुखर करके एक बड़ा दाव लगाया है। यह पहल बिल्कुल अप्रत्याशित थी।

पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर बार-बार न केवल दखल देने व अलगाववादियों को बढ़ावा देने का काम करता रहा है, बल्कि कश्मीर पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर वार्ता करने का बयान देकर भारत को उकसाने का काम करता रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने बलूचिस्तान, गिलगिट और पाक अधिकृत कश्मीर की भीतरी हालत की चर्चा कर पाकिस्तान को सोचने के लिए बाध्य किया है। अब पाकिस्तान इस मुगालते में न रहे कि हिंदुस्तान के

मुसलमान को ढाल बनाकर वह भारत को परेशान करता रहेगा। उसे यह पता होना चाहिए कि ऐसा करके वह सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों का ही कर रहा है। पाकिस्तान की कथनी-करनी में अंतर है। भारत के प्रधानमंत्री की मौजूदा कूटनीतिक चाल से पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह प्रोपेगंडा नहीं कर सकेगा कि हिंदुस्तान समस्याओं पर बात नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद का जवाब प्रतिक्रियात्मक नहीं करके सुविचारित तरीके से देकर पाकिस्तान को वस्तुतः बैकफुट पर ला दिया है। ऐसी कई चालें भारत को और चलने की जरूरत है तभी पाकिस्तान सीधे रास्ते पर आ सकेगा।

(63) प्रश्नः क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि वैश्वीकरण पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं? आखिर क्यों?

उत्तरः हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि वैश्वीकरण पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले सोवियत संघ एक झटके में बिखर गया और दुनिया के नक्शे में उसके स्थान पर 15 नए देश उभर आए। विखंडन की यह प्रक्रिया यहीं नहीं थमी, बल्कि कुछ ही सालों बाद सोवियत संघ के प्रभाव से मुक्त हुए लगभग डेढ़ करोड़ की आबादीवाले चेकोस्लोवाकिया जैसे छोटे राष्ट्र स्व्यं को और भी छोटा बनाने की ओर आगे बढ़े।

इसी प्रकार अभी-अभी कुछ माह पूर्व ब्रिटेन जो दुनिया का एक ऐसा देश रहा है जिसके साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था और ऐसा तकरीबन डेढ़ सौ सालों तक होता रहा, इस दौरान उसने मशीनों के दम पर खुद द्वारा शासित राष्ट्रों की न केवल अर्थव्यवस्था का जबर्दस्त शोषण करके उन्हें कंगाली के मुहाने पर खड़ा कर दिया, बल्कि उन देशों की संस्कृति पर भी अमरबेल की तरह छा गया। भारत भी उससे बच न सका और उसके साम्राज्य में रहकर हमारी संस्कृति भी प्रभावित हुई जिसका असर आजादी के सात दशक बीत जाने के बावजूद अँग्रेज़ियत के रूप में देखा जा रहा है।

जिस ब्रिटेन के पास अतीत के ऐसे अनुभव हैं उस ब्रिटेन ने इस आधार पर यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय ले लिया कि पोलैंड और लिथुयानिया से आए लोग उनके यहाँ आकर उनका रोजगार छीन रहे हैं और कई तरह की समस्याएँ भी बढ़ा रहे हैं। पोलैंड, लिथुयानिया और अन्य देशों से ब्रिटेन आए लोगों की संख्या लगभग तीस लाख थी और ब्रिटेन की आबादी तकरीबन साढ़े छह करोड़ है। इसके बावजूद बाहर से आए लोगों पर यह आरोप भी लगा कि वे ब्रिटेन की संस्कृति पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं।

ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने की घटना को भले ही महज आर्थिक नजरिए से देखा-समझा गया हो, लेकिन धीरे-धीरे उसके दूरगामी परिणाम उभरते दिख रहे हैं, न केवल यूरोप में, बल्कि शेष विश्व में भी। 1991 में यानी आज से 25 साल पहले उदारीकरण के तहत अपने बाजार की सीमाओं को शेष दुनिया के लिए हमारा देश भारत भी खोल दिया था यानी स्वयं को विश्व में तब्दील कर दिया था, मगर ब्रिटेन का जनमत के जरिए यूरोपीय आर्थिक संघ से अलग होने का लोकतांत्रिक फैसला और वह भी सत्ता की इच्छा के विरूद्ध की घटना हुई। ये दोनों घटनाएँ एक ही समय में एक साथ दो विपरीत दिशाओं में यात्रा करने वाली घटनाएँ थीं।

पश्चिम एशिया में पिछले कुछ सालों से चल रहे गृह युद्ध एवं आतंकी गतिविधियों ने यूरोपीय देशों को प्रवासियों की समस्या के रूप में एक गंभीर संकट के समक्ष खड़ा कर दिया है। इस्लामिक स्टेट नामक अत्यंत खूँखार आतंकी संगठन का तथाकथित राजनीतिक दर्शन ही पूरी तरह से इस्लाम के स्वार्थपूर्ण संकीर्ण विश्लेषण पर आधारित है जिसने फिलहाल यूरोप और एशिया की नाकों में दम कर रखा है जिसकी वजह से वहाँ उग्र राष्ट्रवादी भावनाएँ बहुत तेजी से उभरने लगी हैं। यूरोपीय समुदाय को एकजुट रखने की कोशिश के बावजूद इस समुदाय के कई देश अप्रवासियों का विरोध कर रहे हैं। और कुछ में उनके खिलाफ अभियान भी छिड़ गए हैं। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन का अलग होने का निर्णय भी कहीं न कहीं अधिकांश यूरोपीय राष्ट्रों में सुगबुगाती हुई उसी जन-आकांक्षा का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है जिसकी अनुगूँज कभी-कभार ही सुनाई पड़ती थी और जिसे अनसुना करना ही बेहतर समझा जाता था।

पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत के राष्ट्रवादियों का आंदोलन भी पाकिस्तान से अलग होने की सुगबुगाहट के रूप में देखा जा रहा है। किसी भी राष्ट्र का निर्माण उसकी भौगोलिक परिस्थितियों और हजारों वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा से होती है। संस्कृति, परंपरा, दर्शन आदि की यह लंबी यात्रा उस देश की लोक-चेतना में हमेशा मौजूद रहती है। सोवियत संघ के विघटन का मूल कारण इस चेतना को कुचलने की कोशिश करना ही था। यही कारण है कि आज तिब्बती और फलीस्तीनी समेत अन्य समूह अपने देश की माँग कर रहे हैं। एशिया और अफ्रीका के कई राष्ट्रों में अलग-अलग समूह सत्ता पर अधिकार करने के लिए खून-खराबे पर उतारू हैं। सीरिया और सूडान की सच्चाई अनजानी नहीं है। इस राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संकट का

आर्थिक असमानता ने और भी गहरा दिया है। यदि दुनिया के महज कुछ सौ लोगों के हाथों में दुनिया के तकरीबन आधी संपत्ति कैद हो जाए, तो इससे उत्पन्न विसंगतियों को समझा जा सकता है।

उपर्युक्त हालातों को देखते हुए मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि वैश्वीकरण पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं।

(64) प्रश्नः क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 9/11 के बाद महज अमेरिका ही नहीं ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय देशों में भी आतंकवाद का खौफ सर चढ़कर बोलता दिख रहा है?

उत्तरः हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि 9/11 के बाद महज अमेरिका ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में भी आतंकवाद का खौफ सर चढ़कर बोलता दिख रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर को विगत 9/11 को जिस दिन बम के हमले से उड़ा दिया गया और जिसमें कई लोगों की जानें गई अमेरिका में आतंकवाद का खौफ पैदा हो गया है। अभी-अभी पिछले दिनों अमेरिका की संघीय अदालत में 12 साल के पाकिस्तान मूल के छात्र नशवान उप्पल नामक छात्र के माता-पिता ने 50 मिलियन डॉलर के हर्जानें के लिए एक आवेदन दायर की है। खबरों के मुताबिक नशवान नामक वह छात्र, जो शैक्षिक अक्षमताओं का शिकार बताया जाता है उसे स्कूल के अधिकारियों ने यह कबूलनामा लिखने के लिए मजबूर किया कि वह आतंकवादी है। न्यूयॉर्क के ईस्ट ईलिप के मिडिल स्कूल में पढ़ रहे नशवान को स्कूल के दबंग छात्रों ने प्रताड़ित किया, उसे आतंकवादी कहा और पूछा कि अब वह अगला धमाका कहाँ करने वाला है? अपनी विशिष्ट स्थिति के चलते उनकी बातों को समझने में नाकाम नशवान ने कह दिया कि वह स्कूल के बाहर की दीवार उड़ा देगा। बस, इसी बात पर गोया कहर बरपा हो गया, पुलिस बुला ली गई, इतना ही नहीं पाकिस्तानी मूल के उस नशवान के घर तलाशी पुलिस ने ली।

पिछले साल अमेरिका के टेक्सास के एक स्कूल द्वारा वहाँ के छात्र अहमद मोहम्मद जब अपने घर में बनाई घड़ी को स्कूल ले आया था, तो अध्यापक ने उस घड़ी को बम समझ लिया था। अपने घर की छोटी सी प्रयोगशाला में तरह-तरह की चीजें बनाने का शौक रखने वाले उस अहमद को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि अध्यापक महोदय उसकी तारीफ करने की बजाय उसे पुलिस को सौंप देंगे। बहरहाल, मामला इस कदर

सुर्खियों में पहुँचा कि खुद राष्ट्रपति ओबामा ही नहीं अमेरिका के अग्रणी लोगों ने उसकी तारीफ की और उसे अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया।

उल्लेखनीय है कि अमेरिका के इस दमघोटू माहौल से तौबा करते हुए उसके माता-पिता अब पूरे परिवार के साथ कतर प्रस्थान कर गए हैं और उन्होंने भी अमेरिकी सरकार पर मुकदमा दायर कर दिया है। इसी प्रकार ब्रिटेन में आठ साल के एक स्कूली बच्चे को जो अल्पसंख्यक समुदाय से था, कई घंटों तक पुलिसिया पूछताछ का शिकार इसलिए होना पड़ा, क्योंकि उसके टी शर्ट पर अरबी भाषा में इस्लाम के इतिहास से संबंधित किसी मशहूर विद्वान के बोल लिखे थे। इन तीनों उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि 9/11 के बाद महज अमेरिका ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय देशों में भी आतंकवाद का खौफ सर चढ़कर बोलता दिख रहा है।

देश की दो बड़ी पार्टियाँ-काँग्रेस और भाजपा-इस नुक्ते से अबतक चंदे में प्राप्त रकम के स्रोत के बारे में बताने से बचती आयी हैं। राजनीतिक दलों के सभी स्रोतों से हासिल कुल रकम का करीब 80 प्रतिशत हिस्सा भाजपा और काँग्रेस के खाते में जाता है। 2014-15 में चंदे से भाजपा की कमाई 970 करोड़ रुपए थी, तो काँग्रेस की 765 करोड़। 2015-16 में राष्ट्रीय पार्टियों को कुल 1569 करोड़ रुपए की रकम हासिल हुई, जिसमें भाजपा के 674 करोड़ थे, तो काँग्रेस के 598 करोड़। इसमें से 70 प्रतिशत रकम का स्रोत दोनों पार्टियाँ नहीं बताना चाहतीं। ऐसे में आशंका लगी रहेगी कि किसी मंत्रालय का कोई निर्णय या संसद में उठा कोई प्रश्न कहीं किसी कंपनी या दानदाता व्यक्ति के हित साधन तो नहीं था। पार्टियाँ पार्टी फंड के मामले में जितनी पारदर्शिता बरतेंगी, लोगों के मन में जितनी पारदर्शिता बरतेंगी, लोगों के मन में उनके प्रति विश्वास उतना ही बढ़ेगा।

(65) प्रश्न: बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के एक सरकारी अस्पताल में हुए आत्मघाती विस्फोट क्या इस बात का साक्षी नहीं है कि पाकिस्तान का आतंकवाद से रिश्ता संकीर्ण स्वार्थों से तय होता है?

उत्तर: हाँ, मैं आपकी इस बात से पूर्णत: सहमत हूँ कि पाकिस्तान का आतंकवाद से रिश्ता संकीर्ण स्वार्थों से तय होता है और बलुचिस्तान की राजधानी क्वेटा के एक सरकारी अस्पताल में विगत 8 अगस्त 2016 को हुए आत्मघाती विस्फोट इसका ज्वलंत उदाहरण है, क्योंकि बलुचिस्तानी पाकिस्तानी राष्ट्रीयता की सबसे ज्यादा दुखती हुई नस है। प्राकृतिक गैस, कोयला, तांबा

और सोना जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों से भरा बलुचिस्तान अगर अलगाववादी रूझानों से ग्रस्त है, तो इसलिए कि सिंध और पंजाब के दबदबे वाली पाकिस्तानी हुकूमत ने कभी बलूची राष्ट्रीयता के दुःख-दर्द को न तो अपना समझा और न ही अपनेपन का बरताव किया। बलोच राष्ट्रवादी लगातार कहते रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार इस प्रांत को उसके जायज हक नहीं दे रही। बलोची राष्ट्रवादियों के एक धड़े के साथ पाकिस्तान सेना ने एक तरह से अघोषित युद्ध ही छेड़ रखा है और इनके आंदोलन पर काबू रखने के लिए पाकिस्तान अपनी शह में पलते तालिबानी आतंकी जमातों का भी इस्तेमाल करता रहा है। सच तो यह है कि नवाज शरीफ को बलूचिस्तान में सेना के कदमों तले रौंदी जाती बलोच राष्ट्रीयता और वहाँ के आम जन का मानवाधिकार याद नहीं आएगा, समाधान के तौर पर उन्हें फिर से याद आएगी सेना, सेना की शह में पलने वाली वे तालिबानी आतंकी ताकतें, जिसका इस्तेमाल सीमा-पार भारत के कश्मीर में अलगाववाद की आग भड़काने के लिए और सीमा के भीतर बलुचिस्तान जैसे प्राँतों में निर्दोष लोगों की जान लेने में किया जाता है।

दरअसल, सेना, आईएसआई और मजहबी कट्टरता के पैरोकार जमातो के साए तले चलने वाली पाकिस्तानी हुकूमत ने कभी आधिकारिक तौर पर आतंकवाद को लेकर स्पष्ट रूख अख्तियार नहीं किया। उसी का परिणाम हुआ कि बलुचिस्तान की राजधानी क्वेटा के एक सरकारी अस्पताल में पलक झपकते ही आत्मघाती विस्फोट के कारण 60 से ज्यादा मीडियाकर्मी और वकीलों की जान चली गयीं। पिछले मार्च, 2016 में भी लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क में हुए आत्मघाती विस्फोट में 75 लोग मारे गए थे और उसके पूर्व दिसंबर, 2014 के आतंकी हमले की भी याद दिलाती है। अस्पताल में मीडियाकर्मी और वकील बलुचिस्तान बार एसोसियेशन के अध्यक्ष बिलाल अनवर कासी पर हुए आतंकी हमले से उपजे आक्रोश और विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में जुटे थे। इसी प्रकार 11 अगस्त को अलखैर अस्पताल के पास हुए विस्फ़ोट में न्यायाधीश जहाशाहबानी बाल-बाल बचे। इन्हीं सब कारणों से कहा जाता है कि पाकिस्तान का आतंकवाद से रिश्ता संकीर्ण स्वार्थो से तय होता है और आतंकी ताकतों का इस्तेमाल पाकिस्तानी हुकूमत अपने घोषित-अघोषित दुश्मनों के खिलाफ कर पाता है।

(66)प्रश्नःआखिर कबतक पाकिस्तान को कोरी चेतावनी दी जाती रहेगी?

उत्तरःयह शुभ संकेत नहीं हैं कि कश्मीर के हालात लगातार चिंताजनक

बने हुए हैं। एक ओर कश्मीर घाटी में असंतोष और उपद्रव का सिलसिला जारी है, तो दूसरी ओर सीमा पार से होने वाली घुसपैठ की घटनाएँ थमने का नाम नहीं ले रही हैं। विगत 30 जुलाई, 2016 को सीमापार से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश हुई। यह कोशिश भले ही नाकाम रही और दो आतंकी मारे गए, लेकिन हमारे दो जवानों को भी तो शहादत का सामना करना पड़ा। अभी तक का अनुभव यही है कि पाकिस्तान हर तरह के सबूतों को नाकाफी बताकर पल्ला झाड़ लेता है और भारत उसके रवैए की निंदा-आलोचना करके रह जाता है। अब पाकिस्तान को ऐसी चेतावनी देते रहने का कोई फायदा नहीं कि वह अपनी भारत विरोधी हरकतों से बाज आए, क्योंकि यह और अधिक स्पष्ट है कि वह अपने रूख-रवैए को नहीं छोड़ने वाला।

आवश्यकता केवल अलगाववादियों और उनके समर्थकों की निंदा-आलोचना करने की नहीं है, बल्कि उन्हें हतोत्साहित और निष्प्रभावी करने की भी है। कश्मीर के मामले में केवल चिंता जताने अथवा सुरक्षा बलों को संयम की सीख देने या फिर पाकिस्तान को चेताते रहने से बात बनने वाली नहीं है। इसे जम्मू-कश्मीर सरकार को भी समझना होगा और केंद्र सरकार को भी। इसके साथ ही कश्मीर के मामले में कोई नई और ठोस पहल करने की जरूरत है। यह पहल ऐसी हो जिससे पाकिस्तान की सेहत पर भी असर पड़े।

(67) प्रश्न: दिल्ली हवाई अड्डे पर सीतामढ़ी की युवती यास्मीन काफी की गिरफ्तारी और आईएस आतंकी संगठन से जुड़े युवक अब्दुल रशीद से जुड़े रहने से क्या यह संकेत नहीं मिलते कि बिहार में भी प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएस की जड़ें कायम हो रही हैं?

उत्तर: दिल्ली हवाई अड्डे पर बिहार के सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी थाने के मुरौल गाँव की मूल निवासी यास्मीन को 31जुलाई, 2016 को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद खुफिया एवं सुरक्षा एजेंसियों के कान इसलिए खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि यास्मीन के तार प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएस से कहीं न कहीं जुड़े हैं। यास्मीन केरल की पीस इंटरनेशनल संगठन से जुड़ी थी। उसके पति से तलाक होने के बाद वह केरल के कासरागोड स्थित इसी संगठन में ही ज्यादातर रह रही थी जहाँ केरल में इस्लामिक स्टेट के मुख्य सूत्रधार अब्दुल रशीद से उसका संपर्क हुआ। कहा जाता है कि अब्दुल रशीद आईएस का सबसे प्रमुख मॉड्यूल है

जिसने दर्जनों पढ़े-लिखे युवाओं को केरल से बाहर आईएस से जुड़ने के लिए भेजा है। कुछ महीने पहले वह काबूल भाग गया। आरोप है कि युवती यासमीन अपने करीबी अब्दुल रशीद के इशारे पर आईएस एजेंट के रूप में काम कर रही थी। रशीद पर केरल के 21 युवकों को आईएस में भर्ती कराने का आरोप है। यास्मीन भी इस अभियान में उसकी सहयोगी रही है। यह उत्तर भारत में किसी महिला के आईएस से जुड़ने का पहला वाक्या सामने आया है। इसके पहले हैदराबाद में एक महिला पकड़ी गई थी, जो आईएस से जुड़ने के लिए बाहर जा रही थी। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि बिहार में भी आईएस की जड़ें कायम हो रही हैं।

(68) प्रश्न: सत्ता और संसाधनों की बंदरबांट में लिप्त नेताओं से नेपाल की गरीब जनता कब उबर पाएगी और वहाँ दशक से चले आ रहे अनवरत राजनीतिक अस्थिरता से मुक्ति कब मिल पाएगी?

उत्तर: पिछले एक दशक से अनवरत जारी राजनीतिक और प्राकृतिक भूचालों से नेपाल के नागरिकों की आँखों से आँसुओं की अविरल धारा थम नहीं पा रही है। अप्रैल 2015 में आए भीषण भूकम्प की त्रासदी से तो नेपाल देर-सबेर उबर भी सकता है, लेकिन सत्ता और संसाधनों की बंदरबांट में लिप्त नेताओं से वहाँ की गरीब जनता कब उबर पाएगी, कहना मुश्किल है।

पिछले आठ वर्षो में नौ प्रधानमंत्री नेपाल में बदल चुके हैं। इसी माह यानी जुलाई 2016 की शुरुआत में ही करीब नौ महीने तक सत्ता संभालने वाले प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली को कुर्सी छोड़नी पड़ी और नेपाल एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता के भंवर में फँसता दिखाई दे रहा है।

हालांकि प्रधानमंत्री के. पी. ओली की विदाई और उनकी जगह पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' की वापसी से नए समीकरण की संभावना तो दिख रही है, लेकिन कई तरह के सवाल भी हवा में तैर रहे हैं। ओली का झुकाव चीन की तरफ ज्यादा बताया जा रहा है। मधेशी आंदोलन और नाकेबंदी के दौरान वे चीन की तरफ ज्यादा झुक गए थे। उन्हें लगता था कि मधेसियों को आंदोलित करने के पीछे भारत का हाथ है, इसलिए वे अपनी रसद की भरपाई के लिए चीन की ओर उन्मुख हुए थे, मगर इस संदर्भ में हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रचंड ने नेपाली काँग्रेस की सरकार गिराने के लिए भारत विरोधी भावनाओं को भी हवा दी थी। असल में भारत और नेपाल दोनों के हित में है कि संबंध प्रगाढ़ हो, क्योंकि नेपाल और भारत के इतने

पुराने सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध हैं कि उनकी उपेक्षा करने से परेशानी ही बढ़ेगी। अब यह प्रचंड की जिम्मेवारी है कि भारतीय नागरिकों की इन भावनाओं को मजबूत करें।

प्रचंड और नेपाली काँग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा परस्पर विरोधी राजनीतिक विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेपाली काँग्रेस जहाँ भारत के प्रति नरम रूख रखने वाली मानी जाती है, वहीं माओवाद कठोर। फिर नेपाल में व्याप्त भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और राष्ट्र का पुनर्निर्माण तथा इन सबसे बड़ी मधेसियों की राजनीतिक चुनौतियों का सामना प्रचंड कैसे कर पाएँगे? सवाल यह है कि कम्युनिस्टों की पार्टी लाइन से हटकर क्यों वे भारत और चीन के साथ समान दूरी बनाकर चलने की समझदारी पूर्ण कूट-कौशल का परिचय दे पाएँगे? इसलिए कि चीन के साथ प्रचंड की निकटता जगजाहिर है। और बड़ा सवाल यह भी है कि नेपाल को दशक से चले आ रहे अनवरत राजनीतिक अस्थिरता से मुक्ति मिल पाएगी?

नेपाल की जो वर्तमान स्थिति है उसे देखते हुए मैं कह सकता हूँ नेपाल से जिस दोस्ती को भारत अपनी अटल थाती मान बैठा था वह नेपाल के घरेलू लफड़ों तथा भूकंप की मार से चौतरफा घिर गया है। पूर्व प्रधानमंत्री ओलो जबतक सत्ता पर विराजमान रहे भारत पर अपनी तराई में मधेशी विद्रोह को हवा देने का आरोप लगाते रहे और आज भी भारत को कोसना कम नहीं हुआ है। इस भय को चतुर चीन ने खूब दुहा है। इसी तरह पाकिस्तान से भी चीन ने गहरी दोस्ती कर ली है और काठमांडू से बाल्टिस्तान और ग्वादर बंदरगाह तक अपने माल तथा सेना की आवाजाही के लिए निरापद राहें बनवा रहा है।

हाँ, इतना जरूर है कि भारत की मोदी सरकार ने अत्यंत धीरज और कौशल के साथ नेपाल की इस रणनीति को अमली रूप दिया और भारतपरस्त कही जाने वाली नेपाली काँग्रेस के नेता शेरबहादुर देउबा को मोर्चे पर न लाकर पिछली कतार में रहने का सुझाव दिया। मोर्चा संभालने की जिम्मेवारी माओवादी नेता पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' को सौंप दी, जो न केवल अपनी महत्वाकांक्षा से संचालित हो रहे थे, बल्कि जनयुद्ध के दौरान घटित 'अपराधों' की परछाई भी उनके ऊपर मंडरा रही थी। फिलहाल के. पी. ओली के हाथ से सत्ता की बागडोर भले छूट गयी हो और भारत को इससे संतोष मिला हो, परा सत्ता के खेल में वे मजबूत होकर उभरे हैं और वापसी के लिए देशभक्ति का पत्ता खेल सकते हैं।

(69) प्रश्नः जब इसरो उपग्रह छोड़ने की बढ़ती क्षमताओं से पूरी दुनिया से व्यावसायिक फायदा उठाने की स्थिति में आ गया है, तो उसे डर के एवज में भारत पर एक अरब डॉलर का हर्जाना से जो चपत लगी है उससे क्या लोकतांत्रिक संस्थाओं, मीडिया और उसमें सक्रिय राजनीतिक दलों के लिए यह सबक नहीं है?

उत्तरः हाँ, हेग स्थित (इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल) अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने देवास-ऐंट्रिक्स सौदा रद्द करने के लिए भारत पर एक अरब डॉलर का हर्जाना लगाकर यह साबित कर दिया है कि लोकतांत्रिक सरकारों का हड़बड़ी में लिया गया फैसला उन पर कितना भारी पड़ता है। मनमोहन सरकार के कार्यकाल में लिए गए निर्णय पर आए पंचाट(अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण) के इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि भ्रष्टाचार के आरोपों से बेवजह सशंकित मनमोहन सरकार की गलती से मौजूदा स्थिति बनी है। इसरो के तत्कालीन प्रमुख माधवन नायर ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा भी है कि देवास-ऐंट्रिक्स सौदा रद्द करने का फैसला 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के माहौल में लिया गया था। दरअसल, उस समय मनमोहन सरकार को कुछ नहीं सूझ रहा था। डॉ. मनमोहन सिंह ने छवि बचाने के लिए सौदा भले रद्द कर दिया, लेकिन उससे देश को दीर्घकाल में भारी नुकसान हुआ।

निश्चित रूप से यह विडंबना है कि जब इसरो उपग्रह छोड़ने की बढ़ती क्षमताओं से पूरी दुनिया से व्यावसायिक फायदा उठाने की स्थिति में आ गया है तो आरोपों पर कार्रवाई करने से पहले उसकी पूरी सच्चाई जान लें, ताकि देश का नुकसान न हो। दरअसल, राजनीतिक दल और बड़े दलों की सरकार को देश के लाभ-हानि से उतना लेना-देना नहीं है जितना की उनकी अपनी राजनीति की छवि खराब होने का डर रहता है। यही तो हुआ इस सौदे का रद्द करने में। देवास-ऐंट्रिक्स सौदा करना मनमोहन सरकार का गलत फैसला था, क्योंकि उन्हें अपनी काँग्रेसी सरकार की छवि समाप्त होने का डर था, हालांकि जिस काँग्रेस की छवि समाप्त होने का उन्हें डर था वह तो अंततः हो ही गया, मगर भारत को पंचाट के इस फैसले से करीब 67 अरब रुपए के नुकसान का अनुमान है।

(70) प्रश्नः क्या विश्व को आतंकवाद के दंश से मुक्त किया जा सकता है? यदि हाँ, तो कैसे?

उत्तरः यह कटू सत्य है कि इस्लामी आतंकवाद की निंदा तो की

जाती रही है, लेकिन उसके पीछे की वजहों की विवेचना कभी नहीं की गयी और इस्लामी दर्शन को निष्पक्ष रूप से उधेड़ने का कभी प्रयास नहीं किया गया। इस्लाम के नाम पर सदियों से लाखों लोगों ने न केवल असंख्य निर्दोष और बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा गया और आज भी सीरिया, इराक, तुर्की, लीबिया, अफगानिस्तान आदि देशों में आए दिन बेगुनाहों की कत्ल हो रही है, बल्कि उनके मान-बिंदुओं को भी रौंदा जा रहा है और साथ ही इस रक्तरंजित प्रक्रिया में अपनी बलि देने से भी संकोच नहीं किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि आतंकवाद की समस्या के कारणों की विवेचना नहीं होने के चलते आतंकवाद का दानव आने वाले दिनों में सुरसा के मुख की तरह फैलता जाएगा।

इतिहास गवाह है कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने मजहबी उन्माद में भारत पर आक्रमण किया था। मध्यकाल में औरंगजेब और कई मुस्लिम बादशाहों ने तलवार के बल पर मजहब बदलने का अभियान चलाया। मोहम्मद अली जिन्ना ने मजहब के आधार पर भारत का रक्तरंजित विभाजन करवाया। ओसामा बिन लादेन ने इस्लाम के नाम पर न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर पर हमला किया। वर्ष 2008 के नवंबर में जमात-उद दावा सरगना हाफिज सईद ने मुंबई पर हमला करवाया। अभी-अभी 23 जुलाई, 2016 को अफगानिस्तान में एक प्रदर्शन के दौरान आत्मघाती बम बिस्फोट में 80 से ज्यादा हजारा मुसलमानों के चिथड़े उजड़ गए। जर्मनी में 24 जुलाई, 2016 को 27 वर्षीय सीरियाई मुसलमान की एक संगीत कार्यक्रम में बम बिस्फोट करने के प्रयास में मौत हो गई। फ्रांस की राजधानी पेरिस में, भारत में कश्मीर से लेकर केरल तक इस्लामी जिहाद का उन्माद समय-समय पर सभ्य समाज को दंश मार रहा है। आईएस के खूंखार आतंकवादी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 20 गैर-मुस्लिमों का गला रेतकर हत्या की गई। क्या इन सारे दुष्कर्मों को करने वालों ने यह दावा नहीं किया कि उनका प्रेरणास्रोत इस्लाम है? इतना कुछ होने के बावजूद क्या सभ्य समाज ने कभी इस्लाम का अध्ययन कर उसकी विवेचना करने का प्रयास किया है? आखिर क्या कारण है कि आज भी हिंसा से मरने वाले अधिकांश मुसलमान इस्लाम के नाम पर या शिया-सून्नी के नाम पर दूसरे मुसलमानों द्वारा कत्ल किए जाते हैं?

क्या यह सत्य नहीं कि सुन्नी बहुल पाकिस्तान में अक्सर शियाओं की हत्या होती है और उनकी मस्जिदों पर बम फेंके जाते हैं? अफगानिस्तान के काबूल में हुए बम विस्फोट में क्या केवल हजारा शिया मुसलमानों की

मौत नहीं हुई? क्या यह भी सत्य नहीं कि अधिकांश मुस्लिम बहुल देशों में गैर-मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं और उन्हें सामान्य नागरिक अधिकार से वंचित रखा जाता है? इराक और ईरान, दोनों मुस्लिम राष्ट्र होते हुए भी सदैव एक-दूसरे के खिलाफ युद्ध की मुद्रा में क्यों रहते हैं? क्या कभी इन सवालों के आलोक में सभ्य समाज ने आतंकवाद की समस्या के समाधान के लिए इस्लामी दर्शन, परंपरा और उसके नायकों के जीवन का ईमानदारी से अध्ययन किया है? इस सवाल का जवाब नकारात्मक होगा। यदि हम चाहते हैं कि विश्व को आतंकवाद के दंश से मुक्त किया जाए तो इस्लाम के दर्शन, परंपरा और उसके नायकों के जीवन का ईमानदारी से अध्ययन कर उसकी विवेचना करनी ही होगी।

इसी संदर्भ में मैं यह भी बता दूँ कि आतंकवाद पर काबू पाने के लिए सेना को इतनी आजादी दी जानी चाहिए कि जो लोग इसे हवा दे रहे हैं उन्हें यह बात समझ में आ जाए कि अब बातचीत किए बिना काम नहीं चलेगा। दूसरी बात यह कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा पिछले दिनों एक बंदूकधारी की ओर से पुलिस कर्मचारियों को निशाना बनाए जाने की घटना के बाद दिए गए बयान से मैं पूर्णतः सहमत हूँ जिसमें उन्होंने कहा था-"मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कानून के रक्षकों के खिलाफ हिंसा के लिए कोई सफाई नहीं दी जा सकती, कोई भी नहीं। वे कुछ भी गलत नही कर सकते और न ही नुकसान पहुँचा सकते हैं।" राष्ट्रपति ओबामा की उपर्युक्त बातें चाहे कश्मीर में तैनात सेना के दस्तों का हो या फिर चाहे दुनिया के किसी भी देश में आतंकवादियों अथवा अलगाववादियों द्वारा हिंसा की जा रही हो, पूरी तरह उचित बैठती है।

(71)प्रश्नः पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अलग-थलग करने की कोशिश क्यों आवश्यक है? क्या इससे पाकिस्तान भारत को अशांत-अस्थिर करने और आतंकवाद फैलाने से बाज आएगा?

उत्तरः पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अलग-थलग करने की कोशिश इसलिए आवश्यक है, क्योंकि उससे संबंध सुधारने के जो भी प्रयास किए गए उन पर उसने पानी फेर दिया। पिछले दिनों कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से बिगड़ते रिश्तों के बीच विदेश मंत्रालय का यह फैसला आया कि इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के अधिकारी कर्मचारी अपने बच्चों को वहाँ के स्कूलों में न पढ़ाएँ। विदेश मंत्रालय के इस फैसले से करीब

50–60 बच्चों को अपनी आगे की पढ़ाई के लिए स्वदेश लौटना होगा। इस फैसले के पीछे एक मात्र कारण कश्मीर को लेकर पाकिस्तान में बिगड़े हालात हैं, मगर यह कहना कठिन है कि इस फैसले से पाकिस्तान को कोई सही संदेश देने में सफलता मिलेगी, पर इतना जरूर है कि इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि अवश्य प्रभावित होगी और इसके साथ कुछ अन्य देश भी वैसा ही फैसला कर सकते हैं जैसा भारत के विदेश मंत्रालय ने किया है। कई देशों ने तो पहले से ही पाकिस्तान को 'नो स्कूल गोइंग मिशन' वाली सूची में पहले से डाल रखा है।

यह संभव है कि भारत के इस कदम के बाद पाकिस्तान भी ऐसा ही कोई जवाबी फैसला करे, लेकिन उसकी परवाह नहीं की जानी चाहिए। परवाह इसकी की जानी चाहिए कि भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बना पाकिस्तान विश्व बिरादरी में और अधिक अलग-थलग कैसे पड़े? इस संदर्भ में मेरा यह भी मत है कि पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हाशिए पर करने की कोशिश के तहत यह भी जरूरी है कि उसे सबसे पहले दक्षिण एशिया के स्तर पर अलग-थलग किया जाए। इस मामले में बांग्लादेश और अफगानिस्तान विशेष सहयोगी बन सकते हैं। इन देशों की मदद से अन्य दक्षिण एशियाई देशों को यह संदेश देने में कोई कसर नहीं उठा रखी जानी चाहिए कि पाकिस्तान के रहते दक्षिण एशिया एक समूह के रूप में आपसी सहयोग की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता। यदि एक लंबे अरसे से महसूस किया जा रहा है कि दक्षिण एशियाई देशों में सहयोग के सबसे बड़े मंच दक्षेस के स्तर पर कहीं कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो पा रही है, तो पाकिस्तान के कारण।

जहाँ तक आपके दूसरे प्रश्न का सवाल है हाल-फिलहाल इसकी कोई संभावना नहीं दिखती कि पाकिस्तान भारत को अशांत-अस्थिर करने और आतंकवाद फैलाने से बाज आएगा।

(72) प्रश्नः क्या आप ऐसा मानते है कि विगत 15 जुलाई, 2016 की रात तुर्की में तख्ता पलट की यह कोशिश कमाल अतातुर्क की सेकुलर धारा में यकीन करने वालों की थी, जो एर्दोगेन के इस्लामी रीति-रिवाजें के शह देने के खिलाफ रहे हैं?

उत्तर: विगत पाँच दशक में तुर्की तीन तख्ता पलट देख चुका है। पिछले 15 जुलाई, 2016 की रात कभी न भूलने वाली दहशत में तुर्की में

तीसरी तख्तापलट की कोशिश हुई, मगर वह नाकाम रही। तुर्की में इन दिनों राष्ट्रपति के पद पर रेचप तैयब एर्दोगन हैं जिनका झुकाव कट्टरवाद की तरफ है। 1999 में वे इसी चक्कर में जेल भी जा चुके हैं। सत्ता संभालने के बाद उन्होंने इस्लामिक नियमों को लागू करने के लिए कई कानून पास किए थे। इसके अलावा एर्दोगन पर आरोप लगते रहे हैं कि वे राष्ट्रपति के इर्द-गिर्द सारी शक्तियाँ केंद्रित करना चाहते हैं। उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ भी काम किया है।

तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और प्रधानमंत्री यिलदिरीम का कहना है कि तख्तापलट के लिए अमेरिका के पेन्सिलवानिया में रह रहे निर्वासित मौलवी फतेहुल्लाह गुलेन को जिम्मेदार ठहराया है। कहा जाता है कि फतेहुल्लाह गुलेन तुर्की का दूसरा सबसे ताकतवर शख्स है। इस्लामी धर्मगुरु गुलेन के तुर्की में लाखों अनुयायी हैं। डेढ़ सौ से ज्यादा देशों में उनके स्कूल हैं और उनका कारोबार अरबों डॉलर का है। नब्बे के दशक से पेन्सिलवानिया में रह रहे गुलेन तुर्की में देश के खिलाफ काम करने के आरोप लगने के बाद अमेरिका आ गए थे। अमेरिका ने तुर्की की चुनी गई सरकार को पूरा समर्थन दिया है। सीरिया की सीमा से सटा तुर्की नाटो का एक सदस्य देश है और नाटो में अमेरिका का खास सहयोगी है। तख्तापलट और तुर्की में उथल-पुथल मचाने वाले सैनिकों ने मार्शल लॉ और कर्फ्यू की घोषणा करने वाले खुद को 'कॉसिल फॉर पीस इन होम लैंड' कहने वाले समूह ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था, लोकतंत्र, मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए तख्तापलट की शुरुआत की गई है तथा तुर्की में कानून की सर्वोच्चता बरकरार रहने दें।

उल्लेखनीय है कि 1920 के दशक में कमाल अतातुर्क ने तुर्की में एक आधुनिक सेकुलर व्यवस्था की नींव रखी थी। तुर्की कम से कम पिछले आठ दशकों तक उसी व्यवस्था की कड़ाई से पालन करता रहा है और समय-समय पर कई बार फौज ने सत्ता अपने हाथ में लेकर खास सेकुलर व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश की है। ऐसा आखिरी तख्ता पलट 1997 में हुआ था। 2014 में एर्दोगन के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद बेपनाह भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलीं। उनके करीबी लोगों की संपत्तियों में बेपनाह इजाफा हुआ। इसके खिलाफ 2013 और 2015 में भारी प्रदर्शन हुए, मगर एर्दोगन पूरी कड़ाई से दबा दिया।

नाटो सदस्य होने के नाते तुर्की, अमेरिका और यूरोपीय देशों की

इराक-सीरिया में आईएस पर बमबारी का केंद्र बना हुआ है। तुर्की के तख्तापलट की कोशिश को लेकर अबतक 6000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है तथा संदिग्ध संलिप्तता को लेकर करीब 3000 सैनिकों को हिरासत में लिया जा चुका है। विद्रोह में मरने वालों की संख्या करीब 300 तथा घायलों की संख्या 1400 बताई गई है।

तुर्की के पूर्व राजनयिक तथा .फॉरेन पॉलिसी स्टडीज के चेयरमैन सिनान यूल्जन के अनुसार तुर्की का समाज ध्रुवीकरण का शिकार है। आधा देश राष्ट्रपति एर्दोगन का समर्थक है जबकि शेष विरोधी हैं।

कुल मिलाकर देखा जाए, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि स्वयंभू निर्वासन में रह रहे मौलाना फतेहुल्लाह गुलेन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के इस्लामी रूझान के विपरीत हैं और गुलेन उदार इस्लाम में यकीन करते हैं तथा सभी धर्मो के समान हिमायती हैं। कहा जाए, तो तख्तापलट की यह कोशिश फौज में कमाल अतातुर्क की सेकुलर धारा में यकीन करने वालों की थी, जो एर्दोगन के इस्लामी रीति-रिवाजों को शह देने के खिलाफ रहे हैं। सच तो यह है कि अगर कोई समाज मध्ययुगीन मान्यताओं को तरजीह दे, जिंदगी की जगह मौत का जश्न मनाए और शांतिपूर्ण बदलाव के किसी विकल्प को न सुझाए तो वह तो आतंकवाद, अराजकता और विनाशवाद के लिए सबसे मुफीद होगी ही।

(73) प्रश्नःआर्थिक एवं सामरिक महत्व के दक्षिणी चीन सागर से जुड़े विवाद हेग स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (पीसीए) के फैसले को चीन द्वारा मानने से इनकार करने पर दुनिया भर में समुद्री विवादों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दक्षिणी चीन सागर से गहरे रूप में जुड़े होने के कारण भारत का हित विवाद गहराने से देश की अर्थव्यवस्था कहाँ तक प्रभावित होगी?

उत्तर: सबसे पहले तो मैं यह बता दूँ कि 35 लाख वर्गमील जलक्षेत्र में बसा दक्षिणी चीन सागर (साउथ चाइन सी), प्रशांत महासागर का हिस्सा है, जिसके इर्द-गिर्द इंडोनेशिया का करिमाता, मलक्का, फारमोसा जलडमरूमध्य और मलय व सुमात्रा प्रायद्वीप आते हैं। दक्षिणी इलाका चीनी मुख्यभूमि को छूता है तो दक्षिण-पूर्वी हिस्से पर ताइवान की दावेदारी है। दक्षिण चीन सागर के पूर्वी तट वियतनाम और कंबोडिया को छूते हैं। पश्चिम में फिलीपींस है, तो दक्षिण चीन सागर के उत्तरी इलाके में इंडोनेशिया के बंका व बैतुंग द्वीप लगे हैं।

चीन, ताइवान और वियतनाम ने जहाँ स्पॉटलेस द्वीप समूह पर दावेदारी कर रखी है, वहीं स्पॉटलेस दक्षिण चीन सागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह है। यहाँ के 20 द्वीप वियतनाम के कब्जे में है। इसी प्रकार फिलीपींस के हिस्से में नौ, चीन ने आठ पर आधिपत्य जमा रखा है, मलयेशिया पाँच और ताइवान के कब्जे में एक द्वीप है। दक्षिण चीन सागर के इर्द-गिर्द जितने देश आते हैं विवाद भी उतने ही गहरे हैं। चीन को लगता है कि दक्षिणी चीन सागर के 90 प्रतिशत हिस्से पर उसका प्रभुत्व होना चाहिए।

नीदरलैंड के नगर हेग में कोई डेढ़ सौ अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं जिनमें से एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन(पीसीए) है। इसकी स्थापना समुद्री विवादों को सुलझाने के लिए 1899 में की गयी थी। पीसीए एक किस्म का पंचाट या न्यायाधिकरण है जिसके न्यायाधीशों द्वारा दुनिया के 119 देशों के आपसी विवादों का निपटारा किया जा सकता है।

विगत 17 साल से फिलीपींस कूटनीतिक प्रयासों के जरिए चीन से दक्षिण चीन सागर विवाद सुलझा लेना चाहता था, लेकिन बात बनी नहीं तो फिलिपींस ने 2013 में हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण-'पीसीए' का दरवाजा खटखटाया। न्यायाधिकरण के पाँच न्यायाधीशों ने दक्षिणी चीन सागर को विगत 12 जुलाई, 2016 को संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून के अनुच्छेद-258 को आधार बनाकर फिलिपींस के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि 'नाइन डैस लाइन' की परिधि में आने वाले जल क्षेत्र पर चीन कोई ऐतिहासिक दावेदारी नहीं कर सकता। इस फैसले से बाकी देशों को भी राहत मिली है, मगर समुद्री कानूनों को खुलेआम चुनौती देते रहने वाले चीन ने पीसीए के इस फैसले को मानने से साफ इनकार करते हुए यहाँ तक बयान दे डाला-'पीसीए किस खेत की मूली है, उसे हम उसे नहीं जानते और न दक्षिणी चीन सागर पर उसका फैसला मंजूर है। कर लो, जो करना है। ' चीनी विदेशमंत्री वांग यी ने तो यहाँ तक कह दिया कि 'यह न्यायाधिकरण नहीं, एक राजनीतिक मजाक है', जिसे कानून के बहाने स्वार्थ सिद्धि का हथियार बनाया गया है। दरअसल, चीन इन दिनों 'नंग बड़ा या परमेश्वर' की मुद्रा में खड़ा है कि जिसे आना है सामने आए, चाहे युद्ध कर ले, किंतु हम किसी अदालत, अंतरराष्ट्रीय कानून को नहीं मानते।

चीन के इस बयान ने सचमुच एक नया संकट खड़ा कर दिया। अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष यह एक बड़ा सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण का फैसला कौन लागू कराएगा? हेग स्थित स्थायी अंतरराष्ट्रीय

इस न्यायाधिकरण-पीसीए में वर्ष 2013 से ही सुनवाई चल रही है, मगर चीन इस दौरान एक बार भी उपस्थित नहीं हुआ। चीन एक ऐसे विष का बीजारोपन कर रहा है, जिसके बेल दुनिया भर में समुद्री विवादों को उलझाने वाले हैं। सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य चीन के पास 'वीटो' नामक एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, जिसके बूते वह समुद्री कानून की ऐसी-तैसी में लग गया है।

पाक को परमाणु हथियार की आपूर्ति, उत्तरी कोरिया के परमाणु कार्यक्रम में सहयोग, लखवी व मसूद अजहर जैसे कुख्यात आतंकियों का समर्थन, तिब्बत व जिजियांग प्रांत में मानवाधिकारों का उल्लंघन व साम्राज्यवादी नीति के दरम्यान चीन ने सदैव संयुक्त राष्ट्र वीटो का दुरुपयोग कर अंतरराष्ट्रीय कानूनों को चुनौती प्रस्तुत की है। यदि समय रहते इस दिशा में कड़े कदम नहीं उठाए गए, तो चीन का अनुसरण कर अन्य देश भी वैश्विक व्यवस्था को धता बताने से नहीं हिचकेंगे।

असल में चीन के लिए दक्षिणी चीन सागर की अहमियत अंतरराष्ट्रीय ताकत ही नहीं आर्थिक दृष्टि से भी अहम है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के दावे को धता बताते हुए सैन्य अभ्यासो की कवायद शुरू कर दी है, क्योंकि दक्षिणी चीन सागर को लेकर चीन का फिलीपींस विवाद चल रहा है, लेकिन दक्षिण चीन सागर व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है इसलिए चीन इसे लेकर कतई झूकने के मूड में नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून संबंधी संधि के अनुच्छेद-296 और आठवीं अनुसूची के अनुच्छेद 11 के तहत न्यायाधिकरण का यह फैसला अंतिम और बाध्यकारी है। न्यायाधिकरण ने चीन के विशेष आर्थिक क्षेत्र के दावों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि विवादवाले इलाके का कोई भी द्वीप चीन के विस्तारित समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में आपसी प्रतिद्वंद्विता और तनाव के माहौल में इसकी पूरी आशंका है कि अगर चीन ने संयम नहीं बरता, तो टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

जहाँ तक भारत के हित का सवाल है दक्षिणी चीन सागर से गहरा जुड़ा हुआ है, इसलिए विवाद गहराने से इस देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, क्योंकि इस सामुद्रिक क्षेत्र में भारत की रुचि का सबसे अहम कारण व्यावसायिक है। भारत के तकरीबन 750 अरब डॉलर के विदेशी कारोबार का आधा हिस्सा इस रास्ते से गुजरता है। इसके अलावा इस क्षेत्र के तमाम देशों के साथ भारत गहरे आर्थिक संबंध बनाने में जुटा है। वियतनाम,

फिलीपींस, कंबोडिया समेत अन्य देशों में भारतीय कंपनियाँ न सिर्फ बड़ा निवेश कर रही हैं, बल्कि भारतीय उत्पादों का एक अहम बाजार विकसित हो रहा है। चीन के विरोध के बावजूद भारत की राष्ट्रीय तेल कंपनी ओएनजीसी दक्षिणी चीन सागर में वियतनाम के अधिकारवाले दो तेल ब्लॉकों में हिस्सेदारी खरीद चुकी है। ऐसे में अगर चीन का वर्चस्व इस समुद्री मार्ग पर होता है, तो यह भारत के वैश्विक कारोबार पर काफी प्रतिकूल असर डालेगा। सिर्फ दक्षिणी चीन सागर में ही नहीं, बल्कि भारत के चारों तरफ समुद्री इलाकों में जिस तरह चीन अपनी गतिविधियाँ बढ़ा रहा है वह सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए दक्षिणी चीन सागर को लेकर अंतरराष्ट्रीय कानून को मानने के लिए चीन को बाध्य करना जरूरी है। ऐसा नहीं होता है, तो उसकी मनमानी और बढ़ सकती है जिसका सबसे बड़ा प्रभाव भारत पर पड़ सकता है।

अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले के बाद विवादित क्षेत्र में दावे पर जोर देने के प्रयास के क्रम में 18 जुलाई, 2016 को ही चीन ने सैन्य अभ्यास के लिए दक्षिणी चीन सागर के हिस्से को बंद करने की घोषणा कर दी।

भारत ने सभी देशों से आग्रह किया है कि न्यायाधिकरण के फैसले का सम्मान करें। भारत ने पहले भी न्यायाधिकरण द्वारा बांग्लादेश के साथ हुए विवाद पर दिए गए फैसले का सम्मान करते हुए कई हजार एकड़ भूखण्ड बांग्लादेश को वापस किया है। मुझे लगता है कि न्यायाधिकरण के इस फैसले को नहीं मानने से दक्षिणी चीन सागर के तनाव में इजाफा होगा। चीन ने संकेत दिया है कि वह दक्षिणी चीन सागर में एयर डिफेंस सिस्टम खड़ा करने जा रहा है। इसे आसियान, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका द्वारा चुनौती मिलने की संभावना है। भारत के लिए इसका प्रभाव सकारात्मक होगा, क्योंकि यह दक्षिणी चीन सागर में भारत को कानूनी रूप से मुक्त आवागमन का अधिकार देता है। नई दिल्ली अब वियतनाम से तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए किए गए वादे को पूरा कर सकती है। इससे भारत, अमेरिका, आसियान और जापान के बीच नौसैनिक सहयोग को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। फैसले को अस्वीकार करने से चीन विश्व समुदाय में अलग-थलग पड़ सकता है।

(74) प्रश्नः क्या भारत सरकार वास्तव में बलूचिस्तान में 1971 के इतिहास को दोहराना चाहती है? क्या ऐसा करने के लिए बलूचिस्तान की स्थितियों का आकलन सम्पूर्णता के साथ कर लिया गया है?

उत्तर: पिछले दिनों 15 अगस्त, 2016 को दिल्ली के लालकिला के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के 70वें समारोह के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिस लहजे में बलूचिस्तान आंदोलन पर अपने संबोधन में उद्गार व्यक्त किए और उसके बाद कई स्थानों पर उसे बार-बार लगातार वे दोहराते आ रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि वास्तव में भारत सरकार बलूचिस्तान में 1971 का इतिहास दोहराना चाहती है। आपको याद होगा कि 1971 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी के नेतृत्व में या उनके कार्यकाल में ही पूर्वी पाकिस्तान को बंग्लाभाषियों ने आंदोलन कर पाकिस्तान से अलग हो बांग्लादेश बना था।

यदि 1971 के इतिहास को दोहराने की बात की चर्चा हम कर रहे हैं तो हमें यह देखना होगा कि क्या बलूचिस्तान में इस समय का सक्षम नेतृत्व है जैसी 1971 में पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश में था। क्या बलूचिस्तान में मुक्ति वाहिनी जैसा लड़ाकू बल इस समय प्रभावशाली स्थिति में है? फिर एक सवाल यह भी है कि भारत यदि इस दिशा में कदम उठाता है तो अंतरराष्ट्रीय मंच और वैश्विक शक्तियाँ उसे किस तरह से लेंगी या इसके लिए भारत की कूटनीतिक तैयारी कितनी है? निश्चित रूप से इन सभी सवालों के जवाब सकारात्मक नहीं होंगे। हाँ, इतना जरूर है कि बलूचिस्तान में विद्रोह की चिंगारी है जिसका फायदा भारत उठा सकता है, लेकिन चीन-पाकिस्तान के संबंध की ताकत को परखना होगा। दूसरे कि पाकिस्तान आज जिस प्रकार पूरी दुनिया से अलग-थलग पड़ चुका है और तीसरी बात यह कि बलूचिस्तान समर्थकों ने न्यूयॉर्क में बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का उल्लंघन बंद करने, वहाँ बमबारी बंद करने, बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं भारत बलूचिस्तान को मदद करो। संयुक्त राष्ट्र कहाँ हो और तुम संयुक्त राष्ट्र के सदस्य पाकिस्तान को दान देना बंद करो और बलूचिस्तान दूसरा बांग्लादेश है जैसे बुलन्द नारे लगे, उससे यह पता चलता है कि भारत ने यदि इस स्तर की रणनीति का खुलासा नवाब अकबर खान बुगती, जिनकी 26 अगस्त, 2006 को बलूचिस्तान की भम्बोर पहाड़ियों में जनरल मुर्शरफ की फौज ने इस 80 वर्षीय नेता और बलूचिस्तान के पूर्व मंत्री की हत्या कर दी थी, के समय की स्थितियाँ बलूचिस्तान में आज भी मौजूद हैं और उनके पोते बरहन दाग बुगती, जो इन दिनों स्विट्जरलैंड में और उनके दूसरे पोते हरबयार मरी, जो ब्रिटेन में और तीसरे पोते करीमा बलोच जो कनाडा में हैं, अपनी-अपनी जगह से अलगाववादियों के सहारे आंदोलन कर

रहे हैं। इनमें बरहान दाग बुगती ने तो भारत सरकार से राजनीतिक शरण देने का विधिवत अनुरोध किया है। लेकिन वक्त की पुकार है कि ये विद्रोही नेता बलूचिस्तान में रहें या फिर भारत उन्हें राजनीतिक शरण दे, ताकि वे भारत से ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे सके। जब तक ऐसा नहीं होता, तबतक बलूचिस्तान में ऐसी कार्रवाई संभव नहीं है जो 1971 के इतिहास को दोहराने में सफल हो जाए। अन्यथा ऐसे में बलूचिस्तान में 1971 का इतिहास दोहराना जोखिम भरा और चुनौतीपूर्ण भी होगा।

इसमें कोई शक नहीं कि बांग्लादेश बन जाने के बाद भी पाक नेताओं की लार टपकना बंद नहीं हुई है। इसलिए भारत को एक बार फिर उसका दिमाग ठिकाने पर लाने के लिए अपनी ओर से कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र बलूचिस्तान है। इसलिए जबतक वहाँ शांति स्थापित नहीं होगी तबतक भारत भी सुख-चैन से नहीं रह पाएगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान के अत्याचारों से इस वक्त बुरी तरह त्रस्त है। वह चाहता है कि भारत उसे आजाद कराने में सहायता करे, ताकि भारत से टकराने का उसे मौका मिले, किंतु भारत प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने में कुछेक कारणों से हिचकिचा रहा है। हालांकि शैतान पाकिस्तान भारत को परेशान करने पर तुला है, तो भारत के लिए भी यह स्वर्णिम अवसर है कि पाकिस्तान से मुक्ति दिलाने के लिए बलूच जनता को मदद करे। भारत और बलूचिस्तान की जनता मिलकर पाकिस्तान को पाठ पढ़ाएँगी, तो इस क्षेत्र में शांति कायम हो सकेगी।

(75) प्रश्न: कश्मीर के उड़ी स्थित भारतीय सेना के कैंप पाकिस्तानी शह पर आतंकियों के हमले के बाद भारतीय सैनिकों द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर के सात कैंपों में छिपे 40 आतंकियों मार गिराने से क्या पाकिस्तान में ऐसे हालात बन रहे हैं कि सत्ता पलट हो सकता है?

उत्तर: हाँ, भारतीय सैनिकों द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर के सात कैंपों को नुकसान पहुँचाने और 40 आतंकियों को मौत के घाट उतारे जाने के बाद भारत सरकार की ठोस कूटनीतिक पहलों के परिणामस्वरूप जहाँ पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अलग-थलग पड़ रहा है, वहीं पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपने देश की आंतरिक राजनीति में भी बड़ा दबाव झेलना पड़ रहा है। खुद पाकिस्तान में विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि नवाज शरीफ की सरकार न केवल भ्रष्ट और नकारा है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर

असफल है। उड़ी हमले के बाद पूरी दुनिया ने भारत के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान का दोस्त माना जाने वाला चीन भी उसके साथ खड़ा दिखने में हिचकिचा रहा है।

पाकिस्तान के भीतर सेना की हलचल बता रही है कि भारत के खिलाफ कोई भी कार्रवाई को न केवल नवाज शरीफ की असफलता मानी जा रही है, बल्कि पाक सेना के प्रमुख राहील शरीफ भी शक के घेरे में आ रहे हैं। भारत के चार घंटे के ऑपरेशन ने पाकिस्तान के सियासी और सेना के इतिहास को ही उलट-पुलट दिया है। पहली बार दोनों शरीफ पाक के भीतर ही इस तरह कठघरे में आ खड़े हुए हैं कि अब दोनों को यह तय करना है कि साथ मिलकर चलें या फिर एक-दूसरे को शह-मात देने की बिसात बिछा लें। इसलिए पाकिस्तान के हालात शह-मात बिसात की दिशा में जाने लगे हैं। वैसे भी पाकिस्तान में सत्ता पलट का इतिहास रहा है। इसलिए यह कहना अनुचित नहीं होगा कि पाकिस्तान के हालात के मद्देनजर सत्ता पलट हो सकती है।

(76)प्रश्नः क्या आप मानते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर में भारतीय सेना की कार्रवाई से उड़ी हमले पर पाकिस्तान को मुँहतोड़ जवाब मिल गया है? क्या पाक को इससे सीख मिल जाएगी?

उत्तर: हाँ, मैं मानता हूँ कि जम्मू-कश्मीर के बारामुला के उड़ी स्थित सैन्य मुख्यालय पर हमले के बाद पाकिस्तान को जिस जवाब की प्रतीक्षा लंबे समय से की जा रही थी वह मुँहतोड़ जवाब आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में उसे मिल चुका है। इस तरह जोखिम भरी कार्रवाई को भारतीय सैनिकों ने बड़ी कुशलता से अंजाम दिया जिसमें पीओके में तीन किलोमीटर अंदर घुसकर 7 कैंपो को तबाह कर जहाँ कुल 40 आतंकियों को मार गिराया गया, वहीं भारतीय पक्ष को तनिक भी क्षति नहीं हुई। उड़ी में पाकिस्तान की धरती पर पल-पल पनप रहे आतंकियों के हमले ने यह साफ कर दिया था कि अब पानी सिर से ऊपर से बहने लगा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर स्थित आतंकियों और उसके ठिकानों को कितनी क्षति हुई यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि सांबा, कठुआ, गुरुदासपुर, पठानकोट और उड़ी दोहराने के पहले पाकिस्तान सौ बार सोचने को विवश होगा।

एक लंबे अरसे के बाद हमारे राजनीतिक नेतृत्व की ओर से सेना को इस तरह की साहसिक कार्रवाई की अनुमति दी गई और पूरा देश इस सफल अभियान के लिए सेना को बधाई देने के साथ ही गर्व और प्रसन्नता

का अनुभव कर रहा है। हालांकि भारत के महानिदेशक, सैन्य अभियान के अनुसार आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का तात्कालिक लक्ष्य हासिल कर लिया गया है और नई दिल्ली का सैन्य अभियान का दायरा बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, मगर भारत को सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि हताश-निराश पाकिस्तान न केवल सीमा पर तनाव बढ़ा सकता है, बल्कि भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने के साथ ही किसी बड़ी वारदात की साजिश भी रच सकता है।

पाकिस्तान इस स्थिति के खुद जिम्मेदार है, क्योंकि आतंकवाद के मामले में वह कभी भी अपनी जिम्मेदारी समझने के संकेत नहीं दिए। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया कुछ भी हो, भारत को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि अगर पाकिस्तान ने अपनी शत्रुतापूर्ण हरकतें आगे भी जारी रखेंगी, तो भारत उसका जवाब देने में सक्षम भी है और संकल्पबद्ध भी। वैसे भी पाकिस्तानी सेना की खोखली अँधराष्ट्रीयता का उसे उपयुक्त जवाब मिल चुका है। भारतीय सेना के जवानों ने यह सर्जिकल स्ट्रॉइक पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की इस धमकी के कुछ समय पहले ही अंजाम दिया जिसमें वह भारत को परमाणु हमले का सामना करने की चेतावनी दे रहे थे। सेना के जवाब निश्चित ही उड़ी हमले के बाद घायल घरेलू भावनाओं पर कुछ मरहम लगाएगा, लेकिन यह देखना अभी शेष है कि यह सैन्य कार्रवाई हमें किस राह पर ले जाएगी? यह ठीक है कि उड़ी हमले से आहत भारतीय जनमानस में संतोष की भावना पैदा हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से होने वाली कार्रवाईयों का पहले की सरकारों ने माकूल जवाब नहीं दिया था। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की भारतीय प्रतिबद्धता के लिहाज से भी, भारतीय सेना का मनोबल बनाए रखने के लिहाज से भी और एक जिम्मेदार राष्ट्र के अपने नागरिकों के प्रति कर्तव्य के लिहाज से भी उड़ी हमले के बाद पाकिस्तान को यह सबक देना निहायत जरूरी हो गया था। भारत ने पाकिस्तान की तरह छद्‌मयुद्ध या चोरी-छिपे हमला न करके खुद ही पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया को इस 'सर्जिकल स्ट्राइक' की जानकारी दे दी है, जिसका मकसद था घुसपैठ की तैयारी कर रहे आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करना। पाकिस्तान को इससे सीख मिल जानी चाहिए, मगर भारतीय मेना और सरकार को भी आसन्न खतरों और हर तरह के हालात से निपटने के लिए अधिक चौकस रहने की जरूरत है। मगर इतना जरूर है कि दिवास्वप्न देख पड़ोसी राष्ट्र की आँखें अब तो खुल जानी चाहिए और

उसे भारतीय सेना की ताकत, कौशल और दृढ़ता का अहसास हो जाना चाहिए और इससे उन्हें सीख भी ले लेनी चाहिए।

(77) प्रश्नः पाकिस्तान के बारे में गाँधी जी की चिंता क्या रही है?

उत्तरः आज जब हम शांति और अहिंसा के पुजारी गाँधी को उनकी 147वीं जयंती पर याद कर रहे हैं और युद्धोन्माद पर श्रद्धा निवेदित कर रहे हैं, तो उस पृष्ठभूमि में जब पाकिस्तान प्रेरित-प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा उड़ी में किए गए कायराना हमले में भारत के 20 जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी। और जब हमारे धैर्य की सीमा टूट गई और देश की समूची देश भक्ति आहत होने पर प्रतिशोध माँग रही थी, तो सत्ता और सैन्य प्रतिष्ठान ने लोगों की प्रतिशोधी प्यास बुझाने और जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए नियंत्रण रेखा से सटे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर स्थित आतंकशालाओं को अपनी सीधी कार्रवाई से ध्वस्त कर 40 आतंकियों को मौत के घाट उतार कर उड़ी का बदला लिया जिससे गाँधी जी की आत्मा को ठेस लगी होगी, क्योंकि हमनें अहिंसा के विरूद्ध काम किया, लेकिन गाँधी जी भी तो अन्याय और हिंसा के विरूद्ध वास्तविक शांति के लिए मनुष्य में आचरणगत बदलाव चाहते थे। गाँधी जी भी तो हिंसामुक्त शांतिप्रिय मानवीय समाज चाहते थे। समाज को हिंसामुक्त करने के लिए जरूरी है कि उन मानवीय प्रवृत्तियों से मुक्ति पाई जाए जो हिंसा को जन्म देती है और उन विचारों एवं व्यवहारों से मनुष्य को मुक्त किया जाए, जो हिंसक बनाते हैं। हमने तो वही किया जो गाँधी जी का सिद्धांत था।

जहाँ तक पाकिस्तान के बारे में गाँधी जी की चिंता का सवाल है आपको याद दिलाऊँ कि आजादी के आसपास के दिनों में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़की हिसा के दौरान गाँधी जी ने हिंदुओं से अनुरोध किया था कि पाकिस्तान की नीति चाहे कुछ भी हो, हिंदुस्तान में हर कीमत पर मुसलमानों के साथ उचित व्यवहार करें और उन्होंने यह भी कहा था कि यही उचित होगा कि हर बहुसंख्यक जाति नम्रता से अपना कर्तव्य निभाएँ और इस बात की परवाह न करें कि दूसरे राज्य की बहुसंख्यक जाति क्या करती है। आजादी के आसपास के दिनों में पाक को लेकर गाँधी जी की चिंताओं के बरक्स यदि हम आज के पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक को देखें, तो उनकी सात दशक बाद भी हालात बहुत बेहतर नहीं है, मगर भारत में जो अल्पसंख्यक हैं खासतौर पर मुसलमान समुदाय का तो आप उनके हालात पाकिस्तान के अल्पसंख्यक को छोड़िए वहाँ के मुसलमानों से

भी बेहतर हैं। 24 नवम्बर, 1947 को भारत की आजादी के बाद प्रार्थना सभा में गाँधी जी ने कहा था कि 15 अगस्त, 1947 से बहुत-बहुत पहले मुस्लिम लीग ने शरारत शुरू की थी। इसके पूर्व 27 सितंबर, 1947 को प्रार्थना सभा में ही गाँधी जी ने कहा था कि यदि पाकिस्तानवाले कहें कि नहीं हम तो 'लड़कर लेंगे हिंदुस्तान' तो मैने कल सुनाया था कि वे ऐसा गुमान रखेंगे तो यहाँ हिंदुस्तान की हुकूमत लड़ेगी नहीं तो क्या करेगी? इस लिहाज से देखा जाए तो भारत की सरकार और उसकी सेना ने अभी जो कुछ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में किया वह गाँधी जी के कथन के अनुरूप ही हुआ।

(78)प्रश्नः क्या आप इस बात से सहमत है कि भारत द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर स्थित आतंकियों पर किए गए लक्षित हमले (सर्जिकल स्ट्राइक) जैसे प्रत्येक हमले का रूस साथ देगा?

उत्तरः हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि भारत द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर स्थित आतंकियों पर किए गए हमले जैसे प्रत्येक लक्षित हमले (सर्जिकल स्ट्राइक) का रूस साथ देगा, क्योंकि रूस ही हमारा सबसे विश्वसनीय दोस्त रहा है। यह तो कहिए कि जबसे अमेरिका से भारत की नजदीकी बढ़ी है, रूस का हमसे थोड़ा खफा होना स्वाभाविक है।

आपको याद होगा कुछ ही दिनों पूर्व रूस ने पाकिस्तान से कहा था कि वह अपनी जमीन पर आतंकवादी समूहों की गतिविधियाँ रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए। फिर इधर हाल ही में भारत में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर एम कदाकिन ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद से मुकाबले में उनका देश हमेशा ही भारत के साथ रहा है। उन्होंने एक समाचार चैनल से कहा कि सबसे बड़ा मानवाधिकार उल्लंघन तब होता है जब आतंकवादी भारत में सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले करते हैं और शांतिपूर्ण नागरिकों पर हमले करते हैं। भारत द्वारा किए गए लक्षित हमले का भी उन्होंने स्वागत किया, क्योंकि प्रत्येक देश को अपनी हिफाजत करने का अधिकार है। उन्होंने यह भी भारत को भरोसा दिया कि उसे रूस-पाकिस्तान के संयुक्त सैन्य अभ्यास से चिंतित होने की जरूरत नहीं है और फिर भारत भी तो अमेरिका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहा है। वैसे भी लगभग आधी सदी से भारत यह मानकर चलता रहा है कि चीन के साथ ही पाकिस्तान से किसी भी मुठभेड़ में रूस हमारा मददगार होगा।

(79) प्रश्नः आतंकवादियों द्वारा बारामूला में 46 राइफल्स और सीमा सुरक्षा बल के कैंप पर किए गए हमले से आपको क्या आश्चर्य हुआ?

उत्तरः नहीं, उरी हमले के बाद भारतीय सैनिकों द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर में तीन कि.मी. भीतर जाकर पाक के सात कैंपों पर किए गए हमले में 40 आतंकियों को मौत के घाट उतारे जाने पर भी पाकिस्तान नहीं चेत सका और उसके शह पर आतंकवादियों द्वारा फिर बारामूला में 46 रायफल्स और सीमा सुरक्षा बल के कैंप पर किए गए आत्मघाती हमले में हमारे सीमा सुरक्षा बल के एक जवान का शहीद होना अत्यंत दुखद है, मगर उसकी इस हरकत से मुझे आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि वास्तव में हमारे सैनिकों द्वारा सर्जिकल ऑपरेशन के बाद से ही इस बात की संभावना बलवती थी कि आतंकवादी अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए सुरक्षा बलों पर बड़े हमले कर सकते हैं।

जिस ढंग से पाकिस्तानी रेंजरों की ओर से जगह-जगह फायरिंग की गई, वह सर्जिकल ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों की बौखलाहट की परिणति है। वे स्वयं या आतंकवादियों के सहयोग से एक बड़ी हिंसा को अंजाम देने के लिए छटपटा रहे हैं। इन सबका ध्यान रखते हुए हमें विशेषकर सुरक्षा बलों के शिविरों, पुलिस थानों आदि की सुरक्षा व्यवस्था को इतना कड़ा करना होगा कि न केवल हमलों से रक्षा हो सके, बल्कि हमलावरों को पकड़ा जाए या उनका काम तमाम हो जाए। यही एक तरीका है जिसके जरिए हम आतंकवादियों पर काबू पा सकते हैं। आतंकवाद से जूझ रहे भारत को आतंकवादी हिंसा से आत्मरक्षा करना इसका नैसर्गिक अधिकार है।

(80) प्रश्नः क्या पाकिस्तान का आकलन प्रारंभ से ही गलत था जो भारत की ओर से 29 सितंबर, 2016 को पीओके के सात कैंपों को ध्वस्त करने के बाद साबित हुआ? क्या भूतकाल का सिलसिला अब खत्म हो गया और नया इतिहास आकार ले रहा है?

उत्तरः हाँ, पाकिस्तान का आकलन तो आजादी के बाद से ही भारतीय प्रशासन के बारे में गलत था जो सप्रंग सरकार के स्वभाव पर आधारित था। उसे डॉ. मनमोहन सिंह और नरेन्द्र मोदी की सरकारों में फर्क नहीं दिख रहा था। उसके आकलन में ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक की उम्मीद नहीं थी। वह पाकिस्तान पर भारत की पुरानी नीति के ही भरोसे में था कि भारतीय सेना

पर आतंकी हमले की निंदा का कर्मकांड कुछ दिन चलेगा, संयम उपदेश चलेंगे, द्विपक्षीयवार्ता का दबाव होगा, पाकिस्तान कश्मीर राग अलापता ही रहेगा, भारत पाक प्रायोजित आतंकवाद के सबूत पाक को पेश करता ही रहेगा और धीरे-धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। दरअसल, पाक ने भारत की चुप्पी को कमजोरी समझ कर भूल की थी। लेकिन नए राजनीतिक नेतृत्व को ऐसा मंजूर नहीं हुआ, क्योंकि सहन की भी एक सीमा होती है जो टूट गई और भारत की जनता भी आक्रोश में थी तथा वह प्रतिकार चाहती थी जिसे भारत सरकार का वर्तमान नेतृत्व भांप गई, लेकिन पाकिस्तान नए नेतृत्व का मिजाज नहीं भांप सका। आखिर तभी तो भारत द्वारा की गई कार्रवाई की प्रशंसा और पाकिस्तानी नीति की निंदा हो रही है। अच्छा हुआ कि पाकिस्तान नए नेतृत्व की विचारधारा से परिचित हो गया है। भारत की यह कार्रवाई अंतिम नहीं है, पाक इसे भी समझ ले।

भारत की ओर से अब पुख्ता इशारा है कि भूतकाल का सिलसिला खत्म हो गया है। इतिहास अब शुरू होता है। जबसे कश्मीर घाटी में 1989 में आतंक लौटा और 1993 में मुंबई बम धमाकों से इसने भारत की मुख्यभूमि पर प्रवेश किया, भारत की प्रतिक्रिया को वर्णित करने के कुछ सिद्धांत रहे हैं। जैसे कश्मीर की दोपक्षीय समस्या का 'अंतरराष्ट्रीयकरण' करने के किसी भी पाकिस्तानी प्रयास पर तिखी प्रतिक्रिया पुरानी है व उनकी जड़ें शिमला समझौतो में हैं। पाकिस्तानी यदि यह सोच रहे हैं कि भारत सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, तो वे गलती कर रहे हैं, क्योंकि भारत अब पुराने रणनीतिक संयम से आगे बढ़ गया है। नई सरकार ने पुराना सुलह-सफाईवाला तरीका छोड़ दिया है। अब जो खो दिंया है वह कितना ही दुखद क्यों न हो, पर उसके लिए खेद जताने का कोई मतलब नहीं है, बल्कि अब आगे कुछ नहीं खोएँ यही सोचना है। हमारा सामना नए इतिहास से है जो अब आकार ले रहा है।

(81) प्रश्न: क्या भारत-पाक के सुरक्षा सलाहकारों के बीच होने वाली बातचीत में पाक प्रेरित आतंकवाद के मुद्दे को आगे रखने में भारत को सफलता मिलेगी?

उत्तर: उड़ी के सैन्य शिविर पर पाक प्रेरित आतंकियों के हमले और इसके प्रतिकार में आतंकी ठिकानों पर भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पहली बार दोनों पक्षों के बीच बढ़ रहे तनाव को कम करने के लिए भारत और पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकारों की आपस में बातचीत एक अच्छी

खबर इसलिए कही जाएगी, क्योंकि युद्ध की आशंका और सीमा के दोनों तरफ सैन्य तैयारियों का जायजा लेते सैन्य-प्रमुखों की खबरों के बीच अमन की आशा अवश्य जगाता है।

जहाँ दोनों के सुरक्षा सलाहकारों के बीच होने वाली बातचीत में पाक प्रेरित आतंकवाद के मुद्दे को आगे रखने में भारत को सफलता मिलने का सवाल है, अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से आई इस सलाह की रोशनी में इसलिए देखा जाना चाहिए, क्योंकि सलाह में कहा गया है कि दोनों देश बढ़ रहे तनाव को कम करने के कम-से-कम सैन्य-स्तर पर संवाद कायम रखें। वैसे भी पहले दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के सूरते हाल में अमेरिका इस तरह की सलाह देता रहा है। बेशक उसी की कूटनीतिक कोशिशों के बीच कारगिल युद्ध समाप्त हुआ था और दोनों देशों के बीच एक हद तक शांति की स्थिति बनी, जिसका एक बड़ा उदाहरण है सन् 2000 के दशक के कुछ वर्षो में नियंत्रण रेखा पर कायम युद्धविराम की स्थिति।

अजित डोभाल और निसार जंजुआ के बीच बातचीत बेशक अमेरिकी सलाह के साए के तले हुई हो, लेकिन अब के हालात पहले जैसे नहीं हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की बात स्वीकार करके भारत ने पाकिस्तान सहित विश्व-बिरादरी के अन्य देशों को संदेश दिया है कि पाक प्रेरित आतंकवाद के खात्मे की पुरानी रक्षात्मक नीति पर चलना उसे स्वीकार नहीं और अपने हितों की रक्षा के लिए भारत आक्रामक तेवर भी अपना सकता है। जाहिर है, भारत के ऐसे रूख के बाद दोनों देशों के बीच कोई संवाद होता है, तो उसका विषय पाक प्रेरित आतंकवाद ही होगा, ना कि कश्मीर को मसला, जिसका राग अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान अलापते रहता है। फिंलहाल नियंत्रण-रेखा पर मौजूद हालात के भी संकेत यही हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी भारत के विरूद्ध आतंकियों को शह देने से पाक बाज नहीं आ रहा है। बारामूला के सैन्य-शिविर पर हुआ आतंकी हमला इसी का नजीर है। बीते अप्रैल, 2016 से सितम्बर, 2016 के बीच कम-से-कम 81 आतंकियों ने पाकिस्तान की शह पर भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की, जबकि 2015 की इसी अवधि में 31 आतंकियों ने घुसपैठ के प्रयास किए थे। उम्मीद की जाती है कि घुसपैठ की बढ़ी कोशिशों और नियंत्रण-रेखा पर पाक सेना की तरफ से हो रहे युद्ध विराम के उल्लंघन के बीच सुरक्षा सलाहकारों के बीच होने वाली बातचीत में पाक प्रेरित आतंकवाद के मुद्दे को आगे रखने में भारत को सफलता मिलेगी।

(82)प्रश्न: क्या बिम्सटेक (द वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक को-ऑपरेशन) के जरिए भारत पाकिस्तान को एक बार फिर अलग-थलग कर घेरने की कोशिश कर रहा है?

उत्तर: हाँ, पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देना जारी रखने के चलते भारत ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने से इन्कार कर दिया था जिसके बाद बांग्लादेश, भुटान, अफगानिस्तान तथा श्रीलंका ने सार्क सम्मेलन नहीं जाने का मन बनाकर भारत का समर्थन किया जिसकी वजह से सार्क शिखर सम्मेलन रद्द हो गया और इसके कारण भी पाकिस्तान की किरकिरी हुई।

खबर है कि अक्टूबर, 2016 में ही 15 और 16 अक्टूबर, 2016 को गोवा में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बिम्सटेक(द वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीसेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक को-ऑपरेशन) के देशों के अलावा अफगानिस्तान और मालदीव को भी आमत्रित किया जा रहा है और बैठक में आतंकवाद का भी मसला उठाया जाएगा। भारत की इस रणनीति से अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरों में पाकिस्तान एक बार फिर अलग-थलग पड़ जाएगा। आशा है कि भारत इस अवसर पर एक नए संगठन की शुरुआत भी कर सकता है जिसमें पाकिस्तान को शामिल नहीं किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि सार्क की कामयाबियों की राह में पाकिस्तान बाधक बनता जा रहा है, ऐसे में बिम्सटेक पाकिस्तान को अलग-थलग करने का एक बेहतरीन जरिया बन सकता है, क्योंकि बिम्सटेक में पाकिस्तान नहीं है। सार्क तक तो भारत सिर्फ दक्षिण एशिया में ही क्षेत्रीय सहयोग, व्यापार, आयात-निर्यात आदि कर रहा था, लेकिन बिम्सटेक को बढ़ावा मिलने से हमारी पहुँच दक्षिण पूर्वी एशिया तक हो जाएगी। अब भारत ने विकल्प के रूप में बहुपक्षीय संगठनों को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया है, जिसमें सबसे ऊपर है बिम्सटेक और इसके विकास के लिए इस संगठन का विकास साथी (डेवलपमेंट पार्टनर) बना है एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)। बिम्सटेक देशों के बीच में भौतिक संपर्क, आर्थिक संपर्क और सांस्कृतिक संपर्क इन तीनों को बढ़ाने के लिए एडीबी प्रोत्साहित करता है और फंड भी देता है। इसके लिए त्रिपक्षीय संपर्क मार्ग की व्यवस्था बनाई गई है, जो भारत समेत थाइलैंड और म्यांमार के बीच है। यानी भारत ने 'चौतरफा सहयोग' को बढ़ावा देने की मुहिम छेड़ दी है, जिसमें पाकिस्तान नहीं है।

आपको मैं अवगत करा दूँ कि बिम्सटेक के सदस्य देश संसाधन संपन्न हैं और तकनीकी रूप से आगे बढ़ रहे हैं। बिम्सटेक को बढ़ावा मिलने से इसके सदस्य देशों के बीच बाजार तेजी से बढ़ेगा, जिसका आर्थिक लाभ सभी को होगा, लेकिन पाकिस्तान इससे वंचित रह जाएगा। बिम्सटेक के देश आपसी सहयोग के जरिए बड़ा बाजार फायदों को भुनाकर जहाँ अपना विकास करेंगे, वहीं पाकिस्तान और पिछड़ जाएगा और अलग-थलग पड़ जाएगा।

(83)प्रश्नः गुलाम कश्मीर में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक में सफलता के बाद पाकिस्तान में मचे कोहराम के बीच क्या आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और चीन की चुनौती से एक साथ निपटने की क्षमता हमारे तीनों सेनाओं में है?

उत्तरः भाई कपिलदेव जी, आप बिहार पुलिस के एक अनुभवी पदाधिकारी रहे हैं इस नाते आपने अनुभव किया होगा कि पाक के कब्जेवाले कश्मीर यानी गुलाम कश्मीर में भारतीय सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक कर जिस साहस के साथ वहाँ के न केवल सात कैंपों को नुकसान पहुँचाया, बल्कि पाकिस्तान की शह पर भारत के साथ रह-रहकर छेड़खानी करने वाले तकरीबन 40 आतंकवादियों को मार गिराने में सफलता पाई और उसके बाद पाकिस्तान में कोहराम मच रहा है तथा वहाँ तख्ता पलट की संभावना व्यक्त की जा रही है, वैसे वक्त में भारतीय वायु सेना प्रमुख और तीनों सेनाओं की स्टाफ कमिटी के चेयरमैन के नाते एयर चीफ मार्शल अरुप राहा ने नई दिल्ली में विगत 4 अक्टूबर, 2016 को सालाना प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि न केवल भारतीय वायु सेना, बल्कि तीनों सेना दुश्मन की किसी भी चुनौती को कभी भी सबक सिखा सकती है और उसकी चुनौती का जवाब देने को तैयार है। बेशक वायु सेना को अपने बेड़े में कई लड़ाकू विमानों की जरूरत है, लेकिन मौजूदा क्षमता भी दुश्मन की किसी भी चुनौती को जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है।

एयर चीफ मार्शल ने तो यहाँ तक कहा कि पूर्वी व पश्चिमी सीमा पर चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौतियों और दोनों मोर्चो पर एक साथ दुश्मन की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए न केवल तेयार है, बल्कि पूरी तरह सक्षम है। भारतीय वायु सेना की क्षमता इतनी बढ़ गई है कि दुश्मन को भयाक्रांत कर उसे रणनीतिक रूप से रोकने के साथ सबक सिखाने में पूरी तरह सक्षम है। भारतीय सेना की तीनों सेनाएँ हर चुनौती के लिए सदैव तैयार रहती हैं। मौजूदा बेड़े में राफेल जैसे लड़ाकू विमानों की कमी है, मगर

मिग, मिराज और सुखोई विमानों की उम्र और क्षमता बढ़ाने के लिए निरंतर रखरखाव और तकनीकी उन्नयन पर वायु सेना का फोकस है। सुखोई के इंजन में सुधार किया जा रहा है, ताकि अगले 20 साल तक यह वायुसेना के बेड़े में कारगर रूप से रहे।

इसमें कोई शक नहीं कि आईएसआई और पाकिस्तानी सेना मिलकर आतंकियों के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने की योजना बना रही है। पठानकोट के पास पाकिस्तानी नौका मिलना, टोही विमान की सीमा के 100 मीटर के दायरे में नजर आना और गुरुदासपुर में एक पाकिस्तानी संदिग्ध का नजर आना इसी योजना का हिस्सा हो सकता है। इसके मद्देनजर थलसेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ही किसी भी प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रही है और रहेगी।

(84) प्रश्नः क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि चीन और अमेरिका के बीच उलझे भारत की सबसे बड़ी चिंता चीन और उसकी रणनीति से निबटना है?

उत्तरः हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि चीन और अमेरिका के बीच उलझे भारत की सबसे बड़ी चिंता चीन और उसकी रणनीति से निबटना है। जब पूरी दुनिया आतंक से जूझ रही है, उस स्थिति में चीन पाक की पनाह में पल रहे आतंकी अजहर मसूद की पैरवी क्यों कर रहा है। मसूद पर वीटो का प्रयोग स्पष्ट करता है कि चीन आतंक और आतंकवाद का समर्थन करता है। वह सिर्फ भारत और अमेरिका को अपनी कूटनीतिक चुनौती पेश कर रहा है। उसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान के समर्थन में अपनी कूटनीति को सफल कर दोनों देशों की दोस्ती को आइना दिखाना चाहता है। वह भारत को यह संदेश देना चाहता है कि अमेरिका से दूरिया बना कर रखे। यदि चीन दोबारा वीटो का प्रयोग न किया होता, तो संयुक्त राष्ट्र में अजहर मसूद को आतंकी घोषित करने का रास्ता साफ हो जाता, क्योंकि चीन भी 1999 में गठित सुरक्षा परिषद की 1267 समिति की सूची का समर्थन कर चुका था और यह अवधि समाप्त हो रही थी। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बदलते हालात का कूटनीतिक लाभ उठाते हुए चीन ने दाव पलट दिया और भारत के हाथ लगती बाजी फिर फिसल गई। इस प्रतिबंध के बाद मसूद की संपत्ति फ्रीज हो जाती और बाहरी यात्रा पर प्रतिबंध लग जाता तथा आतंकी उपयोग के लिए खरीदे जाने वाले हथियारों और दूसरी सुविधाओं का लाभ भी नहीं उठा पाता।

चीन की दरियादिली जिस तरह आतंक और उसकी नीति को

खाद-पानी दे रही है वह भविष्य के लिए कतई ठीक नहीं है। पूरी दुनिया यह जान रही है कि आतंकी अजहर मसूद पाकिस्तान की गोद में पल रहा है, लेकिन कोई चुप्पी नहीं तोड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ अपना मससद कामयाब करने के लिए भारत के खिलाफ कूटनीतिक साजिशें रची जा रही हैं। सवाल उठता है कि इसी तरह का प्रतिबंध अमेरिका पर ओसामा बिन लादेन के लिए भी लाया गया था फिर उस स्थिति में वीटो का प्रयोग क्यों नहीं किया था। इसका मतलब साफ है कि बदली हुई परिस्थिति में वह भारत को नीचा दिखाने की कोशिश और साजिश रच रहा है जिसका भारत को मुँहतोड़ जवाब देना चाहिए और वैश्विक मंच पर भारत को ठोस कूटनीतिक कदम उठाने होंगे जिससे चीन को मात दी जाए। इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी चिंता मौजूदा दौर में चीन ही है।

(85)प्रश्न: क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भारत और पाकिस्तान के बीच यदि परमाणु युद्ध शुरू हुआ, तो इसकी भीषण तबाही से दोनों देशों के करोड़ों लोगों की जान चली जाएगी?

उत्तर: वैसे तो युद्ध की संभावना नहीं है, पर यदि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध शुरू हुआ तो भीषण तबाही से दोनों देशों के करोड़ों लोगों की जान चली जाएगी, क्योंकि दोनों देशों ने कुल 100 परमाणु हथियारों का यदि इस्तेमाल किया, तो इससे 2.1 करोड़ से ज्यादा आबादी काल के गाल में समा जाएगी। इसके अलावा करीब आधी दुनिया की सुरक्षात्मक ओजोन परत नष्ट हो जाएगी और समूचे विश्व में मॉनसून और कृषि पर 'न्यूक्लियेर विंटर' का असर पड़ेगा।

परमाणु युद्ध होने पर इस बात की संभावना है कि यदि एक देश ने टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार का उपयोग किया, तो दूसरा भी बदले में कार्रवाई करेगा। इस होड़ में तेजी आने की भी बहुत ज्यादा संभावना है। ऐसी स्थिति में यह युद्ध तभी खत्म होगा जब सारे हथियार समाप्त हो जाएँगे।

(86)प्रश्न:क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् हमारे समय की जरूरतों के प्रति अनुत्तरदायी और अपने समक्ष मौजूद चुनौतियों से निबटने में निष्प्रभावी हो चुकी है? कैसे?

उत्तर: हाँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् हमारे समय की जरूरतों के प्रति अनुत्तरदायी और अपने समक्ष मौजूद चुनौतियों से निबटने में निष्प्रभावी हो चुकी है। आपने देखा नहीं आंतकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर प्रतिबद्ध लगाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में

महीनों से लंबित है जिससे नाराज होकर भारत ने सुरक्षा परिषद् को खूब खरी-खोटी भी सुनाई है। आपको मैं जानकारी दे दूँ कि परिषद् की प्रतिबंध समिति में भारतीय प्रस्ताव को चीन ने 31 मार्च, 2016 को तकनीकी कारणों से रोक दिया था। उस वक्त सुरक्षा परिषद् के अन्य सभी 14 सदस्यों ने मसूद अजहर को प्रतिबंध सूची में रखने के भारतीय प्रस्ताव का समर्थन किया था। ज्ञात हो कि इस सूची में शामिल होने के बाद पाकिस्तान में ऐश फरमा रहे मसूद अजहर की संपत्ति और यात्राओं पर रोक लग जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरूद्दीन ने कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकी संगठन घोषित होने के बावजूद सुरक्षा परिषद ने बीते नौ महीनों में संगठन के नेताओं की पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया तक शुरू नहीं की है। सुरक्षा परिषद की यह देरी इस महत्वपूर्ण इकाई के कामकाज और रवैए पर गंभीर टिप्पणी है। आतंकवाद जैसे जरूरी मसले पर भी यदि यह विश्व संस्था फैसले पाने में लचर और लापरवाह है, तो आतंक से लड़ने के इसके आह्वानों और प्रतिबद्धताओं पर सवालिया निशान लगना स्वाभाविक है।

(87) प्रश्न: क्या आपको ऐसा लगता है कि उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिला स्थित हंदवाड़ा के भारतीय सेना के कैंप पर आतंकियों के हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने जैसी चौकसी बरती और जवाबी कार्रवाई की, शांति और सुरक्षा के लिए इसी की जरूरत है?

उत्तर: हाँ, विगत 6 सितंबर, 2016 को उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिला के हंदवाड़ा स्थित लंगेट में 30 राष्ट्रीय रायफल के कैंप पर आतंकियों द्वारा किए गए हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और आठ आतंकियों को मार गिराया, ऐसी ही चौकसी और दबाव की जरूरत है शांति और सुरक्षा के लिए। कहा जाता है कि सुबह करीब 5 बजे आतंकियों ने कुपवाड़ा के आर्मी कैंप पर फाइरिंग शुरू कर दी, जिसका भारतीय जवानों ने जवाब दिया, क्योंकि जवान मुस्तैद थे और आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया गया। जम्मू-कश्मीर के नौगाम, कुपवाड़ा और रामपुर सेक्टरों में 6 सितंबर, 2016 को आतंकियों की पाँच बार घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए आठ आतंकवादियों को मार गिराया गया। घुसपैठ की ये कोशिशें पाकिस्तानी सैनिकों की मदद से की गई थी। 30 रायफल के शिविर पर हमले को सेना ने जिस तरह से विफल किया वह उसकी चौकसी का प्रमाण

है। इसी तरह की चौकसी की अभी जरूरत है। ऐसी चौकसी कम-से-कम तबतक तो चाहिए ही जबतक सीमा पर बर्फ न पड़ जाए और दोनों देशों के बीच चढ़ा हुआ तापमान गिर न जाए।

सेना का दावा है कि मारे गए सभी आतंकी पाकिस्तानी फौज के थे, क्योंकि उनके पास से नक्शे, जीपीएस, मोबाइल और हथियार बरामद हुए हैं। भारत सरकार इन सबूतों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी ताकत के साथ प्रकट करे, क्योंकि यह सबूत पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर करेंगे। जबकि अमेरिका, रूस और जर्मनी समेत यूरोप और दुनिया के कई देश भारत के आत्मरक्षा के अधिकार के साथ खड़े हैं, तो भारत को पाकिस्तानी साजिशों को बेनकाब करने में कसर नहीं छोड़नी चाहिए। हो सकता है, भारत और दुनिया के इस दबाव में पाकिस्तान के भीतर फौज और नागरिक प्रशासन के बीच विभाजन पैदा हो, क्योंकि उनके रिश्ते भारत जैसे सहज और लोकतांत्रिक कभी नहीं रहे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के भीतर इस तरह की खींचतान के संकेत मिलने भी लगे हैं।

अब तो स्थिति यह है कि तीन दशक के आतंकवाद की आड़ में भारत के खिलाफ छद्मयुद्ध चला रहे पाकिस्तान की हवा डेढ़ महीने में ही निकल गई। चौतरफा घिर चुके पाकिस्तान के अंदर ही छटपटाहट दिखने लगी है। बेचैनी इतनी ज्यादा है कि सेना के सामने अक्सर बेबस रहने वाली नवाज शरीफ सरकार ने उसे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने या फिर दुनिया में अलग-थलग होने के लिए तैयार रहने का परोक्ष अल्टीमेटम प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की उपस्थिति में विदेश सचिव की ओर से दिया गया। खबर यह भी है आईएसआई के महानिदेशक जनरल रिजवान अख्तर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नासिर जंजुआ से चार प्रांतों में आतंकियों पर कार्रवाई का संदेश देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हकीकत जो भी हों, लेकिन भारत के दबाव की पाकिस्तान लंबे समय तक उपेक्षा नहीं कर सकता। अब तो चीन में भी जैश-ए-मोहम्मद को लेकर पाक की नीति पर सवाल उठ रहा है।

(88) प्रश्नः जब अँग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान की आजादी के समय बलूचस्तिान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया, तब फिर यह पाकिस्तान का एक प्रांत कैसे हो गया? उसके बाद बलूच की स्थिति कैसी है?

उत्तरः तिवारी जी, आपने सही कहा कि अँग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान को 15 अगस्त, 1947 के समय बलूचिस्तान को भी एक स्वतंत्र

राष्ट्र घोषित किया था, लेकिन साढ़े सात माह तक वह स्वतंत्र राष्ट्र रहने के बाद पाक के प्रधानमंत्री जिन्ना की फौज ने बलूच जनता की इच्छा के विरूद्ध जोर जबरदस्ती से बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया, पर बलूच शांत न रहे। सत्ता के विरूद्ध उस समय जो विद्रोह शुरू हुए वे अब तक जारी हैं। इन विद्रोहों को सख्ती से दबाया गया।

1970 में पाकिस्तान सरकार ने लगभग एक लाख सैनिकों को बलूचिस्तान में लगाया। इन फौजों ने चार हजार बलूच नागरिकों की सामूहिक हत्याएँ की जिनमें स्त्रियाँ और बच्चे भी शामिल थे। सन् 2005 में परवेज मुर्शरफ की सेनाओं ने अनेक बलूचे ग्रामों को जला दिया। पाकिस्तानी सरकार के अन्याय और उत्पीड़न के विरूद्ध आवाज उठाने वालों में जो बलूचों की आवाज बना उस नायक का नाम है अकबर खां बुगती। मुशर्रफ ने समझा था कि बुगती की मौत के बाद बलूच राष्ट्रवाद का आंदोलन समाप्त हो जाएगा, लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत आज बलूचिस्तान धधक रहा है।

तिवारी जी, आप स्वयं काँग्रेस के एक सधे नेता है और उसकी किसान सभा के संचालन की जिम्मेदारी लिए हुए हैं इसलिए आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि भारत-पाक विभाजन के वक्त बलूच विभाजन के खिलाफ थे। ऐसे वक्त पख्तुन नेता खान अब्दुल गफ्फार खान का जिक्र करना इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ, .क्योंकि उनका कद भी नेहरू, पटेल, सुभाष आदि के जैसा था। इसीलिए तो उन्हें सीमांत गाँधी कहा जाता था यानी गाँधी के बराबर भी वे समझे जाते थे। बादशाह खां और सीमांत गाँधी जैसी उपाधियों से नवाजे गए खान अब्दुल गफ्फार खां ने सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार की एक बड़ी अहिंसक फौज खड़ी कर रखी थी। बादशाह खां की तरह बलूच नेता अब्दुल समद खान अचकजाई को भी अहिंसा में विश्वास था।

सीमांत राज्य काँग्रेस के साथ इस वायदे पर थे कि हिंदुस्तान के आजाद होने के साथ-साथ उन्हें ही आजादी मिलेगी, पर समय आया तो उनकी इच्छा के विरूद्ध उन्हें आजाद तो कर दिया गया, किंतु साढ़े सात माह के बाद उन्हें जोर जबरदस्ती से पाकिस्तान में मिला लिया गया। बादशाह खां यानी सीमांत गाँधी ने तो काँग्रेस से कहा था कि तुमने हमें भेड़ियों के बीच छोड़ दिया। पठानों के सामने विकल्प हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का नहीं, बल्कि पाक और पख्तुनिस्तान के बीच रखा जाना चाहिए था मगर काँग्रेस का कहना था कि वे परिस्थितियों के अधीन थे। बादशाह खां का

सवाल था कि ये परिस्थितियाँ किसने पैदा कीं? और यही कारण है कि वही परिस्थितियाँ बलूचिस्तान में आज भी मौजूद हैं। बादशाह खां के तीनों पोते स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और कनाडा में रहकर आज भी बलूचिस्तान में पाकिस्तान के विरूद्ध आंदोलन चला रहे हैं और भारत से उन्होंने राजनीतिक शरण की माँग की है।

(89)प्रश्नः क्या सचमुच पाकिस्तान के अंदर आतंक के खिलाफ आवाज उठने लगी है? यदि हाँ, तो क्या यह भारत सरकार की कूटनीतिक कोशिशों के कारण वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की व्यापक फजीहत होने का ही परिणाम है?

उत्तरः पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी के सिनेटर और संसद के ऊपरी सदन में विपक्ष के नेता ऐतजाज अहसन के कथन पर विश्वास किया जाए, तो मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान सरकार नेशनल एक्शन प्लान के अनुसार नॉन स्टेट एक्टर्स पर अंकुश लगाने में असफल रही है। ये समूह इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद और कराची में प्रदर्शन करते हैं, रैलियाँ निकालते हैं और बयानबाजी करते रहते हैं। ऐतजाज अहसन का यह भी कहना है कि वह किसी देश में अस्थिरता नहीं चाहते हैं, क्योंकि तब इन नॉन-स्टेट एक्टर्स के कारण दोष उन पर ही आएगा। अहसन के मतानुसार इस समय पाकिस्तान का अलग-थलग पड़ना पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की व्यक्तिगत असफलता है। एक तो नवाज शरीफ को उड़ी हमले का पूर्वानुमान नहीं था और दूसरे रक्षामंत्री का यह कहना कि कश्मीर से ध्यान हटाने के लिए भारत ने ही यह हमला करवाया है, तो फिर पाकिस्तान अलग-थलग क्यों पड़ा है, यह आवाज पाकिस्तान के आम नागरिक भी उठा रहे हैं।

इसी प्रकार पाक नेशनल एसेम्बली के सदस्य राणा मुहम्मद अफजल ने कश्मीर के हित को आगे बढ़ाने में हाफिज सईद के योगदान पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि हाफिज सईद पाक के लिए कौन से अंडे दे रहा है? उन्होंने यह भी कहा है कि हमें उन स्रोतों को अलग करना ही होगा जिनकी वजह से भारत कश्मीर में हमारे रूख को कमजोर कर रहा है। उन्होंने नॉन-स्टेट एक्टर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत बताई है, क्योंकि इनकी मौजूदगी से कश्मीर मसले को नुकसान पहुँचा है और पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिन्दा भी होना पड़ता हैं। हाफिज सईद की मौजूदगी पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने का अवसर मुहैया कराती है भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। कुछ इसी तरह की आवाज पाक के स्तंभकार

अयाज मीर का भी है। उनका कहना है कि पाकिस्तान के साथ सही या गलत तौर पर संबद्ध जेहादी हमारी आवाज को बेअसर बना देते " एक हाफिज सईद और एक मौलाना मसूर अजहर ही हमारी परेशानी को दूसरा रूख देने के लिए काफी हैं। फिर पाक पूरी दुनिया की उपेक्षा कर रोष क्यों जताता है?

लाहौर से प्रकाशित डॉन पत्र में तसद्दुक हुसैन ने तो पाक में विदेश मंत्री नहीं होने और उस विभाग को प्रधानमंत्री द्वारा अपने पास रखने पर भी प्रश्न उठाया है। यही नहीं उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि चीन के अलावा कोई और पड़ोसी देश पाक के दोस्त नहीं हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकी शिविरों की वजह से ही पीओके में लोगों का जीना मुश्किल हुआ है। पाक के आसिम जावेद अख्तर का मानना है कि कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई ही हमारी सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। पाक से निर्वासित राजनीतिक कार्यकर्ता जुल्फिकार शाह पाक के अंदर से आतंक के हिमायती लोगों को खारिज करने की बात करते हैं। उनका भी मानना है कि नॉन-स्टेट एक्टर्स का नेतृत्व पाक सेना करती है। वे कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान में भूचाल आ गया है और वे पाक सेना को अपनी कार्य प्रणाली बदलने की सलाह देते हैं। यदि उपर्युक्त बौद्धिक लोगों की बातों पर विश्वास किया जाए, तो सचमुच पाकिस्तान के अंदर आतंक के खिलाफ आवाज उठने लगी है और ये भारत के कूटनीतिक कोशिशों के ही परिणाम हैं।

(९०) प्रश्न: पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की माँग पर अमेरिका क्यों कतरा रहा है?

उत्तर: यह बात सही है कि अमेरिका पाकिस्तान को जो वित्तीय मदद करता था और उसे हथियार देता रहा है उसे उसपर वहाँ की संसद ने प्रतिबंध लगा दिया है, मगर पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की माँग पर अभी भी कतरा रहा है। हालांकि उसने कहा है कि वह आतंकवाद के उन पनाहगारों को खत्म करने के लिए क्षेत्र के देशों के साथ काम करना जारी रखेगा। उसने कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बताते हुए भारत और पाकिस्तान से तमाम मतभेदों को आपसी बातचीत से सुलझाने का आह्वान किया है, मगर अमेरिकी सरकार कॉंग्रेस में पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने से जुड़े एक विधेयक और एक ऑनलाइन याचिका का समर्थन अभी तक नहीं किया है। इस सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने विगत 6 अक्टूबर, 2016 को कहा, 'मैंने खासतौर पर ऐसे किसी विधेयक के बारे में कुछ नहीं देखा है। इस संदर्भ में किसी भी लंबित विधेयक पर मैं टिप्पणी

नहीं करूँगा।' जॉन किर्बी की यह टिप्पणी स्पष्ट करती दिखती है कि अमेरिका, पाकिस्तान को आतंकी देश घोषत करने से कतरा रहा है। जॉन किर्बी ने यह भी कहा कि भारत-पाक के क्षेत्र में साझा चुनौतियाँ और साझा खतरे मौजूद हैं और वे भारतीयों के लिए भी खतरा है। इनसे निपटने के लिए हम क्षेत्र की सरकारों के साथ काम करना जारी रखेंगे। आतंकियों के पनाहगारों को लेकर और भी बहुत कुछ किया जा सकता है और हम यही करने वाले हैं। उसने यह भी कहा है कि कश्मीर मुद्दे पर हमारा रूख नहीं बदला है। इसका समाधान दोनों देश आपसी बातचीत से निकाले।

(91) प्रश्नः क्या आतंकी पाकिस्तान को विशुद्ध इस्लामी स्टेट बनाना चाहते हैं?

उत्तरः हाँ, पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वाले जितने भी आतंकी संगठन पल रहे हैं सबकी विचारधाराएँ एक ही हैं- पाकिस्तान को विशुद्ध इस्लामी स्टेट बनाना, जिसके अंदर न तो लोकतांत्रिक खुशी-आजादी हो, न कोई बृहत् सांस्कृतिक परंपरा, न कोई कला-संगीत-सिनेमा और ना ही कोई गैर-इस्लामी काम हो। वे सभी बहुत कट्टर और तथाकथित धार्मिक संगठन हैं। इन संगठनों में से कुछ देवबंद स्कूल ऑफ इस्लामिक थॉट से जुड़े हैं, तो कुछ जमात-ए-इस्लामी से जुड़े हैं। पाकिस्तान के पुराने आतंकी संगठन, जैसे मुजाहिदीन वगैरह वे सभी जमात-ए-इस्लाम से जुड़े थे, लेकिन बाद में जो संगठन पैदा हुए, जैसे तालिबान वगैरह, वे सभी जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम से जुड़े हुए थे और इन सबकी विचारधाराएँ एक हैं पाक को विशुद्ध इस्लामी स्टेट बनाना जहाँ बस केवल शरिया कानून हो और धार्मिक कट्टरता हो, जिसके अंदर औरत की कोई भूमिका न हो, कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था न हो। तालिबानी निजाम इसकी सबसे असली मिसाल है। इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है-कट्टरता के रास्ते पर चलकर जेहाद करना और विशुद्ध इस्लामी स्टेट के सपने को साकार करने के लिए मरना-मारना। इन संगठनों के लोग खुद को इस्लामी सेना के रूप में देखते हैं।

पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को बनाने-संवारने की खतरनाक मुहिम में पाकिस्तानी सेना की बहुत बड़ी भूमिका तो है ही, इस बड़ी दहशतगर्द मुहिम के पीछे पाकिस्तान की आइएसआई का दिमाग लगा हुआ है।

(92) प्रश्नः आतंक का गढ़ पाकिस्तान में सक्रिय बड़े आतंकी और अतिवादी संगठनों से संबंधित जानकारियों से क्या आप मुझे अवगत कराएँगे?

उत्तर: यह जगजाहिर तथ्य है कि पाकिस्तान उन गिने-चुने देशों में से है, जहाँ न सिर्फ बड़ी संख्या में आतंकी संगठन सक्रिय हैं, बल्कि उन्हें बकायदा सरकारी और सैनिक संरक्षण भी मिला हुआ है। ये संगठन पाकिस्तान के भीतर कट्टरपंथ और उग्रवाद बढ़ाने के साथ भारत, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों को अस्थिर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। खुद पाकिस्तान में बीते सालों में हजारों सुरक्षाकर्मी और नागरिक आतंक का शिकार बने हैं, लेकिन राजनीतिक और रणनीतिक लाभ के लिए सरकार और सेना ने कभी भी गंभीरता से इनसे निपटने की कोशिश नहीं की है।

जहाँ तक पाकिस्तान में सक्रिय बड़े आतंकी और अतिवादी संगठनों से संबंधित जानकारियों से अवगत कराने का सवाल है आप इन आतंकी संगठनों में से बहुतों के बारे में जानते भी होंगे, फिर भी उनकी जानकारी इस प्रकार है।

जैश-ए-मोहम्मद नामक आतंकी संगठन की स्थापना कराची में विगत जनवरी, 2001 में मौलाना मसूद अजहर द्वारा स्थापित किया गया जिसके प्रमुख आतंकियों में मसूद अजहर के अतिरिक्त मौलाना कारी मंसूर अहमद, अब्दुल जब्बार मौलाना सज्जाद उस्मान, शाह नवाज खान उर्फ साजिद जेहादी तथा मुफ्ती मोहम्मद असगर के नाम उल्लेखनीय हैं।

इसी प्रकार लश्कर-ए-तैयबा(जमात-उद-दावा) नामक आतंकी संगठन की स्थापना लाहौर के समीप मुरीदके में हाफिज मोहम्मद सईद के द्वारा सन् 1990 में हुई जिसके प्रमुख आतंकियों में हाफिज सईद के अलावा मौलाना अब्दुल वाहिद, जिया-उर-रहमान लखबी, अब्दुल्ला शहजाद तथा अब्दगुल हसन का नाम आता है। हाफिज मोहम्मद सईद इसके सुप्रीम कमांडर हैं। यह आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर के अलावा भारत के नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, वाराणसी, कोलकाता आदि कई शहरों में आतंकी वारदातों को अंजाम दे चुका है। तालिबान और अलकायदा जैसे खूंखार आतंकी संगठनों के साथ-साथ इसका सऊदी अरब, यूके, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व एशिया में सक्रिय कई आतंकी समूहों से है। इस समूह की फंडिंग में आइएसआइ अहम भूमिका निभाता है।

जमियत-उल-मुजाहिदीन का गठन शेख अब्दुल बासित ने 1990 में किया था जिसके बड़े आतंकी समूहों में हिज्बुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल बद्र मुजाहिदीन मिलकर कश्मीर जेहाद के लिए 'मुवाखात' नाम से सक्रिय है।

हिज्ब-उल मुजाहिदीन नामक आतंकी संगठन के संस्थापक एहसानदार ने सितंबर, 1989 में इसका गठन किया था जिसके प्रमुख आतंकी हैं सैयद सलाहुद्दीन, हिलाल अहमदमीर, गुलामनबी नौसरी और गाजी नसिरूद्दीन आदि। कश्मीर में सक्रिय यह संगठन भारत-पाक सीमा पर सक्रिय आतंकी संगठनों में बड़ा माना जाता है।

नवंबर, 1990 में सैयद सलाहुदीन द्वारा स्थापित मुताहिदा जेहाद काउंसिल नामक आतंकी संगठन में 13 जेहादी संगठन शामिल हैं। इसी प्रकार अल बद्र नामक संगठन का गठन जून, 1998 में लुकमान ने किया था जिसमें बख्त जमीं, आरफीन, जाहिदजस्म भट और अबू मवाई प्रमुख आतंकी हैं। इसका मुख्य ऑफिस पाक के मेहसरा में तथा कैंप ऑफिस पीओके के मुजफ्फराबाद में है।

(93)प्रश्नः आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं कि परमाणु युग में शक्ति के प्रयोग का परिणाम एकता न होकर आत्महनन होगा? क्या राजनैतिक शक्ति का प्रयोग करते समय अपनी अंतरात्मा की पुकार को कार्यरूप में परिणत नहीं किया जाना चाहिए?

उत्तरः आपके दोनों प्रश्न सामयिक हैं इसलिए कि मौजूदा दौर में पाकिस्तान और भारत दोनों परमाणु युद्ध के द्वार पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। आपके प्रश्न के उत्तर में मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि परमाणु युग में शक्ति के प्रयोग का परिणाम एकता न होकर आत्म-हनन होगा। आपको याद होगा सम्राट अशोक को इसलिए याद किया जाता है कि उसने अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते समय अपनी अंतरात्मा की पुकार को कार्यरूप में परिणत किया। तत्कालीन मनुष्य को उस समय सुलभ भयानक से भयानक अस्त्रों से युद्ध करते समय अशोक को समग्र मानव जाति के ध्वंस की बात तो क्या, अपनी प्रजा के भी समाप्त होने का भय रहता था। युद्ध का परित्याग करते हुए अशोक ने मानव-जाति को एक करने के ध्येय को नहीं छोड़ा, प्रत्युत तबसे उसने अपने इस ध्येय को सैनिक पद्धति द्वारा पूर्ण कराने का उद्योग किया।

परमाणु युग में हम दोनों देशों के राजनीतिक नेताओं में जो भावना देखना चाहते हैं, वह निश्चय ही अशोक की भावना है। अब एकता के बिना काम नहीं चल सकता, क्योंकि उस अपरिहार्य लक्ष्य की प्राप्ति बल-प्रयोग से संभव नहीं है जिसे दोनों देशों के बीच हुए तीन युद्धों में देख चुके हैं। इस

युग में बल प्रयोग के स्थान पर हृदय-परिवर्तन ही वह साधन है, जो मानव जाति की एकता के लिए काम में लाया जा सकता है। इसलिए परमाणु-युग में शक्ति के प्रयोग का परिणाम एकता न होकर आत्महनन में होगा। इस युग में हमारा भय और विवेक दोनों ही उस नीति के हामी हैं जिसे अशोक ने अपने समय में अपनाया था और जिसका अनुसरण करने के लिए उसने केवल अपने अंतःकरण से ही प्रेरणा ली थी। वैसे भी समस्त पूर्वी एशिया में व्याप्त बौद्ध धर्म की आध्यात्मिक भ्रातृत्व-भावना विश्व को एक करने वाली शक्तियों में से एक बड़ी शक्ति रही है और अब भी है। बौद्धों की भ्रातृत्व-भावना आज शक्तिशाली होती दिखाई दे रही है। इसी प्रकार विशाल हृदयता से पूर्ण उदारता की वजह से ही अकबर का 'दीनइलाही' तात्विक दृष्टि से भारतीय ही था। इसलिए मेरा ख्याल है कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते समय अपनी अंतरात्मा की पुकार को कार्यरूप में परिणत किया जाना चाहिए।

(94) प्रश्नः भारत द्वारा हर बार चीन के साथ संबंध सुधारने के प्रयास किए गए, किंतु चीन भारत विरोधी नीति नहीं छोड़ पा रहा है। ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया के माध्यम से क्या हमें चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की मुहिम नहीं चलानी चाहिए?

उत्तरः निःसंदेह भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हर बार चीन के साथ संबंध सुधारने के प्रयास किये, किंतु चीन भारत विरोधी नीति नहीं छोड़ता। आपने देखा नहीं खूँखार आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंधित आतंकी घोषित करवाने में अड़ंगा लगाने और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी का पानी रोकने की वजह से इन दिनों हमारे देशवासियों की भावनाओं के सैलाब ने अचानक चीन के खिलाफ रूख मोड़ लिया है। ऐसे में सोशल मीडिया के माध्यम से चीन में बनी वस्तुओं के बहिष्कार की मुहिम हमारे देश के द्वारा चलायी जानी चाहिए।

पिछले कुछ वर्षो में 'मेड इन चाइना' भारतीयों के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गया है। आज की तारीख में भारत चीन की वस्तुओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। चीन में निर्मित सामग्री के आधे से अधिक के निर्यात पर उसकी आर्थिक व्यवस्था खड़ी है, क्योंकि चीन में निर्मित वस्तुओं को खरीदने के हम आदी हो गए हैं और हमारे रसोईघर तक उसके सामान पहुँच गए हैं।

इधर लगातार भारत विरोधी नीति की वजह से चीनी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू हो गया है। दरअसल, पर्व-त्योहार के मौसम में जब दीपक, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग, पटाखे, सजावट की चीजों की मांग बढ़ जाती है तब उसकी सस्ती चीजों को खरीदने के वक्त देशभक्ति की भावना उसकी सस्ती और अच्छी दिखने वाली चीजों पर भारी पड़ेगी। जाहिर है लोग सस्ते का आकर्षण छोड़ने को तैयार नही हो पाते हैं।

अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत-चीन व्यापार मामले में हमेशा चीन का पलड़ा भारी रहा है, क्योंकि चीन की वस्तुएँ सस्ती होती हैं। सरकार की नीतियाँ भी ऐसी हैं कि उसकी माँग भी ज्यादा होती है, लेकिन हम सभी देशवासियों को यह सोचना होगा कि जब चीन का नजरिया हमारे देश के प्रति सख्त रहा है तो क्यों न हम सभी भारतीय चीन को यह दिखा दें कि लड़ाई सिर्फ जंग के मैदान पर ही नहीं लड़ी जाती, आर्थिक मोर्चे पर भी विरोध प्रदर्शित कर हम चीन को उसकी गलतियों की सजा दे सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ हम देशवासियों में सच्ची देश भावना की।

जो चीन कदम-कदम पर भारत का विरोध करता है, उसकी झोली हम क्यों भरें। चीन की आर्थिक तरक्की बहुत हद तक भारत देश के बाजार पर निर्भर करती है। बहरहाल चीन के खिलाफ पूरजोर अभियान छेड़ने का सही वक्त दीपावली ही है। दीपावली पर चाइनीज सामान खुद नहीं खरीदने का संकल्प लें और दूसरों को भी प्रेरित करें। इस प्रतिबद्धता के साथ हम ज्योति पर्व को सच्चे देशभक्त के रूप में मना सकते हैं।

यह बात ठीक है कि चीन हमारा पड़ोसी देश है लेकिन चीन ने हमेशा ही भारत के हितों की अनदेखी की और पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का साथ दिया है। बहरहाल लोगों को चीन का खेल अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तभी तो मध्यवर्गीय लोगों को स्वदेशी उत्पादों को तवज्जों देने की सलाह दी जा रही है। 2015-16 के दौरान भारत ने चीन को 9 अरब डॉलर का निर्यात किया और 72 अरब डॉलर का चीन से आयात हुआ। नतीजतन एक ओर जहाँ हमारा व्यापार घाटा भी लगातार बढ़ रहा है, वहीं चीन की कंपनियाँ अपने उत्पादों की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं कर रही है। इसलिए चीन की पटाखें, पिचकारी, खिलौनें, फाइबर की टेबल-कुर्सियाँ जैसे उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हमें अपने अंदर इतनी शक्ति, हिम्मत और काबिलियत पैदा करनी होगी कि जो उत्पाद मौजूदा समय में हम चीन से मंगा रहे हैं, वे हम अपने यहाँ खुद ही बनाने लगें। अगर कीमत,

गुणवत्ता और उपलब्धता के संतुलन का साथ लिया गया तो आयातीत उत्पादों की माँग अपने आप ही बंद हो जाएगी।

(95) प्रश्नः क्या आप भी मानते हैं कि एक पुराना दोस्त, दो नए दोस्तों से ज्यादा अच्छा होता है? इस कहावत को किसने और किस पृष्ठभूमि में उद्धृत किया था?

उत्तर: यह कहावत रूसी है। भारत के अमेरिका की ओर से अतिशय झुकाव के मद्देनजर भारतीय राजनायिकों से कुछ ही समय पहले रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ने मानो कूटनीतिक संदेश देने के लिए उद्धृत किया था कि 'एक पुराना दोस्त, दो नए दोस्तों से ज्यादा अच्छा होता है।' फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उसे ही रूसी भाषा में दोहरा कर राष्ट्रपति पुतिन को भरसक नया संदेश देना चाहा। जाहिर है, पुतिन इस कहावत को अमेरिका के संदर्भ में कह रहे थे, तो मोदी का सीधा-सा संकेत रूस से पाकिस्तान और चीन की बढ़ती पींगे की तरफ हो सकती है। शायद वे रूस को भारत के साथ दोस्ती के लंबे और भरोसेमंद दौर की याद दिलाना चाह रहे हों। पाकिस्तान से तनाव के नए दौर में इस दोस्ती की जरूरत भी है। खासतौर पर तब जब चीन अपने सामरिक और आर्थिक हितों के कारण पाकिस्तान की ओर ज्यादा ही झुका है और अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस 'आतंकवाद की जननी' को अलग-थलग करने की भारत की कोशिशों में आड़े आ रहा है। वैसे मेरा भी मानना है कि पुराना दोस्त, दो नए दोस्तों से ज्यादा अच्छा होता है।

(96) प्रश्नः पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग-थलग करने का श्रेय आप किसको देते हैं? और क्यों?

उत्तर: पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग-थलग का श्रेय भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जाता है, क्योंकि विगत दो सालों के दौरान उन्होंने जितनी विदेशों की यात्रा की है उसमें पाकिस्तान के छद्मयुद्ध को उन देशों के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्रियों के साथ वहाँ के सांसदों एवं नागरिकों के समक्ष इतने सलीके से प्रस्तुत किया है जिसका कोई जवाब नहीं। इसके साथ-साथ मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर चौतरफा दबाव बनाने के लिए कई कूटनीतिक कदम भी उठाने के संकेत दिए। पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद और छद्मयुद्ध के जरिए भारत के लिए चुनौती पेश करता रहा है और उसका फायदा उठाता रहा है। पहली बार नरेन्द्र मोदी और उसकी सरकार ने पाकिस्तान के इन हथकंडों का मुँहतोड़ जवाब दियां है और आगे

भी देने की कमर कसी है। इसी की कड़ी के तहत क्षेत्रीय स्तर पर मोदी सरकार ने नवम्बर, 2016 में इस्लामाबाद में आयोजित दक्षेस सम्मेलन को स्थगित करवाकर पहली सफलता हासिल की। इसके पूर्व भी गुटनिरपेक्ष देशों में खुद नहीं भाग लेकर एक संकेत दिया कि भारत को मौजूदा दौर में गुट निरपेक्ष रहने से काम नहीं चलेगा।

इसके साथ ही नरेन्द्र मोदी की सरकार ने सिंधु जल संधि और पाकिस्तान को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे की स्थिति पर भी पुनर्विचार किया है। हालांकि अभी इस विषय पर आगे बढ़ने का फैसला नहीं हुआ है। दरअसल, ऐसा भारत ने पाकिस्तान को यह जताने के लिए किया कि उसे दबाव में लाने के लिए उसके पास कई-कई विकल्प हैं और जरूरत पड़ने पर इनके प्रयोग से भारत हिचकिचाएगा नहीं।

इसी तरह कूटनीतिक दबावों से दो चार होने के साथ-साथ नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य ताकत का प्रयोग करने का फैसला किया जिससे भारत प्रयोग करने से हमेशा बचता रहा था। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत ने पाकिस्तान और दूसरे देशों को दिखा दिया है कि पाकिस्तान की परमाणु युद्ध की धमकी खोखली है और भारतीय सेना के पास सीमित हमला करने की भी क्षमता है।

नरेन्द्र मोदी की पहल की सफलता इस बात से आंकी जा सकती है कि भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक की किसी भी देश ने आलोचना नहीं की। और तो और पाकिस्तान के दोस्त चीन ने भी एक घिसा-पिटा मुहावरा दोहराया कि आशा है कि भारत और पाकिस्तान अपने दो-पक्षीय विवादों को सुलझाने के लिए वार्ता करेंगे और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बरकरार रखेंगे। इसी प्रकार गत सितंबर, 2016 में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान को मिलने वाली 300 करोड़ डॉलर की मदद रोक दी, क्योंकि वह अमेरिका के लिए परेशानी का सबब बने हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हक्कानी नेटवर्क अभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है।

मोदी सरकार अपनी पाकिस्तान नीति को इस तरह रूप दे रही है, ताकि इसका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल हो जाए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीति पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय मंच पर अलग-थलग करने की भी है। अब 'चलता है' का दौर खत्म हो गया है। अब मोदी ने बाजी पलट दी है। भारत उस आधार को ही समाप्त कर देगा जिस पर दक्षिणी एशिया की सामरिक

स्थिरता टिकी है।

(97)प्रश्नः क्या ब्रिक्स तथा ब्रिक्स-बिम्सटेक सम्मेलनों के निर्णयों एवं घोषणाओं से आर्थिक और राजनीतिक सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ आतंक पर अंकुश लगाने तथा पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की ठोस पहलें भी की जा सकेंगी?

उत्तर: इसके पूर्व कि मैं आपके मूल प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत करूँ ब्रिक्स और बिम्सटेक के विषय में बताना उचित समझूँगा। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इन पाँच का यह संघटन ब्रिक्स के हर सदस्य देश के नाम के पहले अक्षर से बना है ब्रिक्स (BRICS)। अँग्रेजी से ब्रिक्स का माने होता है ईंट। यानी पश्चिमी जगत की आक्रामक अर्थ नीतियों के विरूद्ध ईंटों की दीवार खड़ी करना ही ब्रिक्स का मुख्य लक्ष्य है।

पाँच देशों के इस ब्रिक्स संघठन का आठवाँ सम्मेलन 15 एवं 16 अक्टूबर, 2016 को भारत के गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित था जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन रूस में 2009 में हुआ था।

ब्रिक्स में पश्चिमी खेमे का एक भी देश नहीं होने के बावजूद यह संघठन इसलिए मजबूत है, क्योंकि इसमें दुनिया की तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ शामिल हैं। चीन, रूस और भारत। इन तीनों में से दो चीन और रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। ब्राजील लातीनी अमेरिका प्रमुख देश है और साउथ अफ्रीका, अफ्रीका महादेश का बड़ा देश है। ब्रिक्स की सीमाएँ दुनिया के इस पार से उस पार तक फैली हैं। इन देशों की अर्थव्यवस्थाएँ कुल मिलाकर 16 खरब डॉलर तक पहुँच गई हैं। दुनिया की 53 प्रतिशत यानी आधी से अधिक आबादी इन पाँच देशों में रहती है। विश्व व्यापार का 17 प्रतिशत इन देशों के पास है।

15 एवं 16 अक्टूबर, 2016 को गोवा में संपन्न ब्रिक्स के आठवें सम्मेलन से पाकिस्तान को ऐसा झटका लगा है जिससे उबरने का फिलहाल कोई रास्ता नहीं बचा है। बस एक ही उपाय है कि वह आतंकवाद की पैरोकारी करना बंद करे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि आतंकवाद दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, जिसका खात्मा विकास और शांति के लिए आवश्यक है। ब्रिक्स देशों के समक्ष उपस्थित अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय चुनौतियों पर विचार-विनियम किया गया। पाकिस्तान के वर्तमान तनाव, कतिपय मुद्दों पर चीन के साथ मतभेद और ब्राजील तथा

दक्षिण अफ्रीका की सुस्ती की ओर बढ़ी अर्थव्यवस्था से उपजी चिंताओं की *छाया के बीच ब्रिक्स* के नेताओं ने चुनौतियों से निबटने की और सार्थक पहल करने का निश्चय किया। वस्तुत: बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के सात देशों के नेताओं ने भी ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों तथा शासनाध्यक्षों से अपनी समस्याओं के संबंध में वार्तालाप किया जो इस सम्मेलन की खास विशेषता रही है। गोवा घोषणा के साथ विश्व की पाँच उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं- भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं का दो दिवसीय शिखर सम्मेलन इस अर्थ में सफल माना जाएगा, क्योंकि ब्रिक्स और ब्रिक्स-बिम्सटेक सम्मेलनों के अंतिम निर्णयों और घोषणाओं में आर्थिक और राजनीतिक सहयोग बढ़ाने के साथ आतंक पर अंकुश लगाने तथा पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की ठोस पहलें भी की जाएँगी। भारत ने ब्रिक्स के सदस्य देशों के सामने पाकिस्तान को आतंकवाद पर नंगा कर दिया। पाक ने अगर आतंकियों की पैरोकारी बंद नहीं की, तो आने वाला समय उसको और पड़ सकता है भारी।

ब्रिक्स देशों ने इस सम्मेलन में ब्रिक्स वाणिज्य परिषद का गठन किया है जिसकी बैठक भी हुई। ब्रिक्स बैंक बनाने से लेकर उसके लिए न्यूनतम राशि तक ये देश पहले ही एकत्र कर चुके हैं। आपसी व्यापार को अपनी मुद्रा में करने की दिशा में भी कदम बढ़ चुका है। इसे अमेरिकी डॉलर और यूरोप के यूरो के लिए चुनौती के रूप में देखा गया।

ब्रिक्स के चारों नेताओं से बातचीत करने के बाद नरेन्द्र मोदी ने अगर कहा कि ब्रिक्स देश करचोरी, कालाधन और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे, तो हमें कुशल, प्रतिभा, विचार, तकनीक और धन का प्रभाव बनाए रखना होगा और साथ ही सीमा पार आतंकवाद और उसके मददगारों से मुकाबला ब्रिक्स देशों की प्राथमिकता होगी।

कुल मिलाकर देखा जाए तो ब्रिक्स सम्मेलन का भारत उसके मूल लक्ष्यों पर कायम रहते हुए आतंकवाद विरोधी एवं पाकिस्तान को अलग-थलग करने की अपनी वर्तमान कूटनीति के अनुरूप सभ्य और शालीन तरीके से जितना बेहतर उपयोग कर सकता था, किया है। इसकी गूँज इन चारों देशों के साथ बिम्सटेक (बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल का समूह) एवं दुनिया के अन्य देशों में भी गई होगी।

(98) प्रश्न: क्या आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के मामले में भारत को चीन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए? क्यों?

उत्तर: हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के मामले में भारत को चीन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीते ढाई वर्षो में दोनों देशों के शासनाध्यक्षों की आठ बार मुलाकात होने के बाद अभी-अभी गोवा में संपन्न ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन के दौरान हुई नौवीं मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति शी-जिनफिंग आतंकी मसूद अजहर और ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन पर हालिया रूख, भारत की सूरक्षा परिषद में सदस्यता का निरंतर विरोध, पाकिस्तान का सदैव समर्थन और पाक अधिकृत कश्मीर में चीन द्वारा फ्रेंडशिप कार रैली का आयोजन स्पष्ट करता है कि भारत के प्रति चीन का शत्रुवत रवैया आज भी बरकरार है।

दरअसल, भारत के सीमा-विवाद के लिए चीन की साम्राज्यवादी, मानसिकता और उसकी विस्तारवादी नीति तो जिम्मेदार है ही पंडित जवाहर लाल नेहरू की अदूरदर्शी नीतियाँ भी इस समस्या की मुख्य वजह रही है। अक्टूबर, 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद नेहरू जी ने संयुक्त राष्ट्र में पश्चिमी देशों के विरोध के बावजूद चीन को शामिल किए जाने की वकालत की। 1950 में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तब नेहरू सरकार मौन रही। उस वक्त लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल, बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर सहित कई राष्ट्रवादी नेताओं ने चीन को लेकर पं. नेहरू को आगाह किया था, किंतु वह इस गलतफहमी में रहे कि चीन की दोस्ती से भारत का हिमालय क्षेत्र सुरक्षित हो जाएगा। 'हिंदी चीनी, भाई-भाई' के शोर में नेहरू जी चीनी सैनिकों की आहट को नहीं सुन सके। तिब्बत पर कब्जा करने के बाद से ही चीन की नजर लेह-लद्याख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम पर थी और आज भी है।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि चीन की वैश्विक प्रगति का एक बड़ा कारण वहाँ का प्रखर राष्ट्रवाद भी है। जब भी चीन का सामना कठिन परिस्थितियों से होता है, तो वहाँ सर्वोच्च नेतृत्व उग्र राष्ट्रवाद की मुहिम चलाता है। ठीक इसी के विपरीत स्थिति भारत की है। हम देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की भावना का लगातार ह्रास हो रहा है। यह तो कहिए कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के आने के बाद यहाँ के लोगों में हौसला बढ़ा है और मोदी के नेतृत्व पर हम-आप गर्व करने लगे हैं खासकर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद। ऐसी स्थिति में भारत-चीन के रिश्ते के सामान्य होने की उम्मीद कम ही नजर आती है, क्योंकि चीन ने हमेशा ही भारत के हितों की अनदेखी की है और पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का साथ दिया

है। हाल ही में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उसने पाकिस्तान के समर्थन में भारत विरोधी हरकत शुरू कर दी। इस दृष्टि से देखा जाए, तो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के मामले में भारत को चीन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए।

(99)प्रश्नः क्या पाकिस्तान इस समय उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है? आपको क्या लगता है कि ऊँट किस करवट बैठेगा?

उत्तरः हाँ, साधु बाबू, मुझे भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इस समय उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। दो-तिहाई बहुमत से विजयी नवाज शरीफ सरकार कब धराशायी हो जाए, यह कहा नहीं जा सकता। दरअसल, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के अलग-थलग पड़ जाने और उसे कुछ भी हासिल नहीं होने से वहाँ की सेना बौखला गई है। इसे वह नवाज शरीफ की विफलता मानती है। परवेज मुशर्रफ ने भी कहा है कि पाकिस्तान में सैनिक सत्ता की प्रबल संभावना है। पाक के प्रमुख शहर सेना प्रमुख राहिल शरीफ के समर्थन में पोस्टरों से पटे पड़े हैं। पिछले कुछ समय से सेना प्रमुख काफी सक्रिय दिख रहे हैं। उन्होंने कुछ समय पहले अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था। जो काम सरकार को करने चाहिए थे उन्हें सेना ने किया। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, जिनकी जाँच की माँग जोर पकड़ती जा रही है। उधर इमरान खान ने कौमी असेम्बली घेरने की धमकी दी है।

पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी के नेता बिलावल जरदारी भुट्टो भी सक्रिय हो गए हैं। जो कट्टरपंथी कल तक नवाज शरीफ के गीत गाते थे, आज वे उनके दुश्मन हो गए है। 'डॉन' अखबार के पत्रकार पर देश से बाहर जाने पर रोक इसलिए लगा दी गई है कि उसने सरकार को सच्चाई से रूबरू कराया था। हाफिज सईद, मसूद अजहर और हक्कानी गुट के खिलाफ कार्रवाई के लिए उस पत्रकार ने नसीहत दी थी।

इन सभी घटनाक्रमों से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इस समय उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। ऊँट किस करवट बैठेगा, अभी यह अनुमान लगाना मुश्किल होगा। वैसे तख्ता पलट की संभावना भी जताई जा रही है।

(100)प्रश्नः भारत पाकिस्तान को व्यापार के लिहाज से तरजीही राष्ट्र(मोस्ट फेवर्ड नेशन) का दर्जा क्या छीन लेगा?

उत्तरः भारत ने पाकिस्तान को 1996 में तरजीही राष्ट्र का दर्जा दिया था जिसकी वजह से पाकिस्तान को अधिक आयत कोटा और कम ट्रेड टैरिफ मिलता है। यह दर्जा विश्व व्यापार संगठन के शुल्क व्यापार सामान्य समझौते के तहत दिया गया है और यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों को लेकर तरजीही राष्ट्र(एमएफएन) का दर्जा दिया जाता है।

मगर, उड़ी आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान को लगातार कड़े संदेश देने की कोशिश में जुटा है, तरजीही राष्ट्र(एमएफएन) के दर्जे पर पुनर्विचार उसी का हिस्सा है। हालांकि इस संदर्भ में मैं आपको यह भी बता दूँ कि भारत ने तो पाकिस्तान को तरजीही राष्ट्र का दर्जा 1996 में ही दिया था, लेकिन बार-बार भरोसे के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से भारत को यह दर्जा अबतक नहीं दिया गया है। इसी वजह से यह माँग होती रही है कि पाकिस्तान से ये दर्जा छीन लिया जाए। मुझे लगता है कि आजादी के बाद से ही पाक जिस प्रकार आतंकियों को शह देकर भारत को परेशान करता आ रहा है और अब तो पाकिस्तान के इशारे पर हमारे जवानों पर आतंकी हमले होने लगे हैं उसे देखते हुए पाकिस्तान से तरजीही राष्ट्र के दर्जे को छीन लेना ही मुझे उचित जान पड़ता है।

(101)प्रश्नः क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत की चिंता का कारण आतंकवाद को शह देने की पाकिस्तानी नीति है?क्या राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर चीन को इस चिंता की गंभीरता का एहसास नहीं कराया जाना चाहिए?

उत्तरः हाँ, हम आपकी इस बात से सहमत हैं कि भारत की चिंता का कारण आतंकवाद को शह देने की पाकिस्तानी नीति है और इसके मद्देनजर राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर चीन को इस चिंता की गंभीरता का एहसास कराया जाना चाहिए। आखिर तभी तो पिछले दिनों एक अक्टूबर, 2016 को चीन के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संदेश में चीन और भारत के सदियों पुराने संबंधों का हवाला देते हुए परस्पर सहयोग को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि द्विपक्षियों संबंधों के सभी आयामों पर हाल के दिनों में ध्यान दिया गया है और आपसी भरोसे को बेहतर करने की पूरी कोशिश की जा रही है।

लेकिन बीते दो दिनों में चीन की ओर से दो ऐसे कदम उठाए गए हैं जो भारत के राष्ट्रीय हितों के विरूद्ध हैं। संयुक्त राष्ट्र में आतंकी गिरोह जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव को चीन ने तकनीकी कारणों के बहाने फिर से रोक दिया है और दूसरे उसने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी पर बाँध बनाने के लिए उसका बहाव रोकने की घोषणा भी की है। मगर नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने और दक्षिण एशिया में स्थिरता बहाल करने के लिए चीन का साथ जरूरी है, इस बात को उन्होंन अपने संदेश में रेखांकित किया है। चीन को यह ध्यान दिलाना होगा कि परस्पर चिंताओं को प्राथमिकता दिए बिना आपसी रिश्ते स्थायी नहीं हो सकते हैं। इसलिए दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग जरूरी है।

(102)प्रश्न: पाकिस्तान जब लगातार हमें उकसा रहा है, तो हम उसके साथ क्या करें? बिना गोली चलाए पाकिस्तान से कैसे निपटें?

उत्तर: पाकिस्तान हमें लगातार हमारी सीमा में घुसकर हमले कर रहा है और यहाँ तक कि अब तो उसकी शह पर हमारी सेना के जवानों पर भी प्रहार करना शुरू कर दिया है। ऐसी विकट स्थिति में उसके साथ हम क्या करें और बिना गोली चलाए उससे कैसे निपटें, आपका यह सवाल विकट है। इसके उत्तर के लिए अँग्रेजी के युवा उपन्यासकार चेतन भगत के विचार की प्रासंगिकता और सार्थकता सबसे अधिक मौजू लगती है।

आजादी के बाद विगत सात दशकों से पाकिस्तान की हरकतों से अब तो स्पष्ट हो गया है कि आतंक उसकी विदेश नीति है। वे निर्दोष लोगों को मारते हैं-मुंबई के निर्दोष नागरिकों से लेकर उड़ी में सैनिकों तक। हम चाहते तो बहुत हैं, लेकिन पलटकर वॉर नहीं कर सकते। आतंकी हमले चाहे जितने पीड़ादाई हों, हम दुनिया को उड़ा देने का जोखिम नहीं ले सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम अपने परमाणु का इस्तेमाल करेंगे, तो पाक बिना नतीजे की परवाह किए परमाणु डाल सकता है, जो शायद दिल्ली का सफाया कर दे और अगले दिन हम शायद पूरे पाकिस्तान का ही सफाया कर दें। तब वैसी हालत में दुनिया में अफरा-तफरी मच जाएगी। हवा में परमाणु धुआँ भर जाएगा, जिससे दुनिया भर में लोग मारे जाएँगे और पीढ़ियों तक पैदाइशी बीमारियाँ परेशान करेंगी। किंतु हमारे साथ यह भी लाचारी है कि भारत पड़ोसी पाकिस्तान को अकेला छोड़ देने की अय्याशी भी नहीं कर

सकता। हमारा सामना किसी असली राष्ट्र से नहीं, बल्कि आतंकी देश से है।

ऐसी स्थिति में हमारा ख्याल है कि हमें कुछ ऐसी योजना को लागू करने पर विचार करना है जो बिना गोली चलाए असर दिखा सकती है। इस योजना में एक है कि हम एक राष्ट्र के रूप में आधिकारिक रूप से तय कर लें कि पाकिस्तान नाकाम राष्ट्र है। बल्कि सच कहा जाए, तो यह राष्ट्र भी न होकर एक आतंकी क्षेत्र है जो परमाणु बम से लैस है। दुनिया की शांति के लिए खतरनाक मिश्रण। यही बात हम दुनिया को बताएँ जिसे भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रारंभ कर दिए हैं। हम दुनिया को यह भी बताएँ कि पाकिस्तान आईएसआईएस नंबर-2 है जहाँ सरकार राष्ट्र को नियंत्रित नहीं करती।

दूसरा उपाय यह है कि हम पाकिस्तान के साथ सारे राजनयिक रिश्ते तोड़ दें और पाक जैसे आतंकी क्षेत्र को हम अपनी राजधानी के चाणक्यपुरी में जगह क्यों दे रहे हैं? पाकिस्तानी लोग अच्छे हैं मौजूदा दौर में यह भी अप्रासंगिक है। इसलिए दुनिया तक यह संदेश पहुँच जाए कि हमारी पाकिस्तान के साथ भाईचारा और दोस्ती समाप्त हो चुकी है, क्योंकि पाक संघर्ष के साथ भाईचारा और अमन देखते हैं तो पूरी दुनिया के लोग भ्रमित हो जाते हैं।

इसके अलावे दुनिया को हम यह भी बताएँ कि भारत किस तकलीफ से गुजर रहा है और उन्हें समझाएँ कि भारत सिर्फ खुद को महफूज रखने के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया को परमाणु खतरे से बचाने के लिए भी आतंकवाद बर्दाश्त कर रहा है।

यही नहीं हमें पाकिस्तान के कलाकारों पर भी प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कला तो राष्ट्रीयता से परे होता है और प्रतिभाओं का स्वागत होना चाहिए। इसलिए हम उन पाकिस्तानी कलाकारों व उनके परिवारों को खासतौर पर वे जो आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं और उन्हें बदला लिए जाने का खतरा है, शरण देने की पेशकश करनी चाहिए। यदि आधा दर्जन कलाकार भी हमारी पेशकश स्वीकार करते हैं, तो दुनिया को बता सकते हैं कि कैसे पाकिस्तानी कलाकार वहाँ से भागकर भारत आ रहे हैं। हम किसी कलाकार को किसी तरह के बयान देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं, मगर उन्हें हमारे दूतों की तरह तो इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है कि वे दुनिया को बताएँ कि भारत किस स्थिति से गुजर रहा है।

हमारी समझ है कि यदि इन सभी योजनाओं को कार्यान्वित करने

पर विचार करें, तो जाहिर है कि इस स्पष्ट संदेश और कदमों से दुनिया को *अपने पक्ष में करना महत्वपूर्ण होगा। समानता व भाईचारा वह अयूयाशी है,* जिसका लाभ शांतिकाल में उठाया जा सकता है। तब नहीं जब हमारे लोगों को कत्ल किया जा रहा हो।

(103)प्रश्नः क्या आपको ऐसा लगता है कि नवंबर, 2016 में इस्लामाबाद में होने वाले सार्क देशों के शिखर सम्मेलन के रद्द होने से पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी है?

उत्तरः निःसंदेह नवंबर 2016 में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित सार्क शिखर सम्मेलन के रद्द हो जाने की वजह से पाकिस्तान को न केवल मुँह की खानी पड़ी है, बल्कि सार्क देशों से भी वह अलग-थलग पड़ गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नहीं जाने से लगभग यह तय हो गया था कि यह सम्मेलन अब इस्लामाबाद में नहीं होगा, क्योंकि सार्क के चार्टर में इस तरह का प्रावधान है कि सार्क के किसी भी सदस्य देश के इनकार करने पर सार्क शिखर सम्मेलन नहीं हो सकता है। दरअसल, भारत के इनकार करने के बाद अफगानिस्तान, भूटान और बांग्लादेश ने भी सार्क सम्मेलन से दूर रहने का फैसला किया।

सार्क के 31 साल के इतिहास में यह पहला मौका है जब एक साथ चार देशों ने आतंक के मुद्दे पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (दक्षेस या सार्क) समिट का बहिष्कार किया है। सार्क में कुल 8 देश हैं। जीडीपी के लिहाज से सार्क देशों की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसकी कुल आबादी 162 करोड़ है। भारत, अफगानिस्तान, भूटान और बांग्लादेश के विरोध का मतलब है 86 प्रतिशत आबादी का नेतृत्व पाक के खिलाफ है। पहली बार दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पाक का खुला विरोध होने से भारत द्वारा पाक को अलग-थलग करने की नीति कारगर रही। सार्क सम्मेलन के जरिए विश्व बिरादरी में अपनी छवि सुधारने की कोशिश में जुटे पाकिस्तान को इससे करारा झटका लगा है। चार पड़ोसी देशों द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाने से पाकिस्तान को अब सफाई देने में काफी दिक्कत होगी।

(104)प्रश्नः क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि पठानकोट हमले के मामले में खुद को फँसता देखकर पाकिस्तान भारत के साथ वार्ता से पीछे हटा?

उत्तरः पाकिस्तान हमेशा से भारत के लिए एक मुसीबत की तरह पेश आता रहा है। छल व कपट के सहारे उसने भारत को हमेशा बरबाद

करने की हर मुमकिन कोशिश की, परंतु उसकी एक न चली। 1965, 1971 और 1999 के युद्धों में उसे पराजय का जब मुँह देखना पड़ा तो उसने अपनी रणनीति में फिर से आतंकवाद को शामिल कर लिया। आज पाकिस्तान में लश्कर-ए-तोएबा, जैश-ए-मुहम्मद, जमात-उद-दावा जैसे आतंकी संगठन सक्रिय हैं। पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आइएसआइ और पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों की मदद कर रही है। फिर भी हमारे देश के नेता पाकिस्तान से अच्छा रिश्ता चाहते हैं। रिश्ते अच्छे हों इसकी कोशिश होनी चाहिए, लेकिन देश के स्वाभिमान के साथ समझौता कर नहीं।

जहाँ तक पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले में पाकिस्तान के फँसने के बाद भारत के साथ वार्ता से पाकिस्तान का पीछे हटने का सवाल है, निष्पक्ष जाँच का मौका मिलने के बाद भी पाकिस्तान जिस तरह एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता दिख रहा है उससे दोनों देशों के रिश्ते में नए सिरे से खटास आना तय है, क्योंकि इस्लामाबाद भारतीय जाँच दल को पाकिस्तान जाने और इस हमले की साजिश रचने वाले जैश-ए-मुहम्मद के आतंकियों से पूछताछ करने की इजाजत नहीं देगा। पाकिस्तान का यह रूख भारत के भरोसे को तोड़ने वाला और दुनिया के समक्ष यह नए सिरे से स्पष्ट करने वाला है कि आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान ने एक बार फिर यही साबित किया है कि वह भारत में हो रहे आतंकी हमलों के प्रति बिल्कुल ही गंभीर नहीं है और उसकी नीयत उन तत्वों पर लगाम लगाने की है ही नहीं जो भारत को नुकसान पहुँचाने पर आमादा हैं। इसीलिए पठानकोट हमले के मामले में खुद को फँसता देखकर पाकिस्तान भारत के साथ वार्ता करने से पीछे हटा, इस विचार से हम पूरी तरह सहमत हैं। कारण कि पाकिस्तान में ऐसी ताकतें हैं जो किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहतीं कि भारत के साथ संबंध सामान्य बने। भारत के साथ बातचीत की हमेशा रट लगाए रहने वाला पाकिस्तान खुद इस बार बातचीत से पीछे हटता दिखा। संभवत: यह मोदी सरकार के कूटनीतिक दबाव का ही नतीजा है कि पाकिस्तान पठानकोट हमले में अपने यहाँ के आतंकी संगठनों की भूमिका की वजह से वार्ता की मेज पर भारत का सामना करने से बच रहा है। पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी को यह रास नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भारत के प्रति मैत्री भाव प्रदर्शित करें और उसकी चिंताओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ।

हालांकि पिछले दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने केरल के एक मंदिर में हादसे पर अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को ऐसे वक्त फोन किया जब दोनों देशों के संबंध मधुर नहीं दिख रहे। मेरे ख्याल से यह सिलसिला कायम रहना चाहिए, क्योंकि अंततः संवाद से ही किसी समाधान तक पहुँचा जा सकता है।

(105) प्रश्नः अमेरिका के साथ भारत का सामरिक सहकार आखिर किस सोच को दर्शाता है?

उत्तरः अमेरिका के साथ भारत ने हाल ही में रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। आजादी के बाद 25-30 वर्षो तक भारत में अमेरिका की पहचान हमारे शत्रु के मित्र और हम पर दबाव डालने वाली ही रही। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष के दौरान तनाव घातक विस्फोटक की कगार पर पहुँच गए थे। इसके ही कारण आज बदले सामरिक परिप्रेक्ष्य में भी हम उभयपक्षीय सामरिक रिश्ते के बारे में तटस्थता से सोचने में असमर्थ हैं।

वैसे पाकिस्तान और चीन जिस प्रकार भारत को हमेशा कमजोर बनाने के लिए प्रयासरत है, जापान के करीब आने से भारतीय प्रयास भी चीन एवं पाक को आशंकित करते हैं। ऐसे में अमेरिका के साथ भारत का सामरिक सहकार समझदार सोच ही दर्शाता है। भारत को अहसास है कि चीन की आर्थिक और सैनिक ताकत का मुकाबला हम अकेले नहीं कर सकते। दक्षिण-पूर्व एशिया में तथा हिंद महासागर में भी हमारी नौसैनिक क्षमता सीमित है। अमेरिका को वाहनों-उपकरणों के रख-रखाव की सुविधाएँ सुलभ कराना या युद्धाभ्याय में साझेदारी के कार्यक्रम संप्रभुता का हनन नहीं, बल्कि भविष्य में अपनी सामरिक क्षमता के निर्माण तक ऐसा सहकार आवश्यक है। इसके अभाव में एशियाई शक्ति-संतुलन हमारे राष्ट्रहित के प्रतिकूल होता जाएगा। चीनी-पाकिस्तानी गठजोड़ से उत्पन्न दीर्घकालीन सामरिक चुनौती का सामना करने के लिए अन्य विकल्प हमारे पास सुलभ नहीं हैं। वैसे भी केंद्र की पूर्व सरकार ने चीन के साथ व्यापार के दैत्याकार विस्तार ने इस सामरिक गुत्थी को जिस प्रकार बुरी तरह उलझा कर रख दिया है उसे देखते हुए भी फिलहाल भारत और अमेरिका के हितों में दोनों देशों के साथ सामरिक सहकार स्वागतयोग्य है।

(106)प्रश्नःपाकिस्तान में चीन के बढ़ते दखल से क्या आप भारतीय हितों के लिए खतरा महसूस करते हैं? यदि हाँ तो क्यों?

उत्तरः चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ कोई नई बात नहीं है और

भारत दशकों से इस गठजोड़ से दो-चार होता रहा है। हाँ, पर चीन से पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत द्वारा जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ पेश प्रस्ताव के पारित होने में अडंगा डालकर एक बार फिर चौका दिया। एक अरसे पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सफल भारत यात्रा और फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गर्मजोशी भरी चीन यात्रा और बड़े निवेश समझौतों के मद्देनजर इसकी उम्मीद कम थी कि चीन पठानकोट हमले के लिए जिम्मेदार एक आतंकी के विरूद्ध कार्रवाई जैसे मुद्दे पर भारत के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है। वर्ष 2008 में 26/11 को मुंबई के आतंकी हमले के बाद सैन्य और जमात-उद-दावा पर सयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा इसी प्रकार की कार्रवाई का विरोध नहीं किया था, लेकिन उसके बाद से वह लगातार लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकियों को संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित सूची में डालने के हर भारतीय प्रयास में रोड़े अटकाता रहा है।

दरअसल, पाकिस्तान लंबे अरसे से भारत को उलझाए रखने की चीनी नीति का मुख्य हथियार रहा है, लेकिन पिछले दशक में पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता ने बीजिंग को भी चिंता में डाला है। चीन किसी भी हाल में पाकिस्तान को पूर्णत: असफल देश में नहीं बदलने देना चाहता, क्योंकि ऐसा होने पर उसकी भारत को उलझाएँ रखने की क्षमता में गिरावट आएगी। यही कारण है कि पीओके में दखल बढ़ाकर चीन भारत पर सीमा विवाद के मामले में दबाव बना रहा है और साथ ही भारत को पीओके के दावा करते रहने और वहाँ की असंतुष्ट जनता की मदद करने से हतोत्साहित करना चाहता है। चीन-पाक आर्थिक कॉरिडोर उसको दक्षिण चीन सागर में भी अधिक आक्रामक रूख अख्तियार करने की इजाजत देता है। चीन पाकिस्तान के जरिए इस्लामी जगत में चल रही उथल-पुथल का जहाँ तक संभव हो प्रबंधन करना चाहता है और इसलिए वह आजकल आईएसआई समर्थित अफगान तालिबान को अफगानिस्तान में सत्ता में भागीदारी दिलाने के लिए प्रयासरत है। चीन आतंकवाद की आग को हमेशा भारत की ओर मोड़ना चाहता है। इस रणनीति में चीन का परोक्ष हथियार है पाकिस्तान और पाकिस्तान के परोक्ष हथियार हैं लश्कर, जैश और अफगान तालिबान जैसे आतंकी संगठन। भारत को इसके गहरे निहितार्थे समझने होंगे। इन्हीं सब वजहों से पाकिस्तान में चीन के बढ़ते दखल से मैं भारतीय हितों के लिए खतरा महसूस करता हूँ। वैसे भी पाकिस्तान और चीन की धुरी भारत को

निर्बल बना खूँट से बाँधे रखने के लिए आमादा है। श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव एवं पाकिस्तान में अपनी नौसेना के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण कर वह हमारे गले में जहरीली मोतियों की माला पहनाने पर आमादा है। दक्षिणी चीन सागर में वियतनाम के साथ भारत का सहयोग उसे रास नहीं आता। ऐसे में पाकिस्तान में चीन के बढ़ते दखल से भारतीय हितों पर खतरा महसूस करना स्वाभाविक है।

(107)प्रश्नः म्यांमार में आधी सदी बाद हेतिन काव के पहले असैन्य राष्ट्रपति चुने जाने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? म्यांमार में नेशनल लीग फौर डेमोक्रेसी की नेता नोबल पुरस्कार विजेता आंग सान सू को संसद ने राष्ट्रपति क्यों नहीं बनाया और परदे के पीछे शासन चलाना स्वीकार किया? म्यांमार में बनी नई संसद और नए राष्ट्रपति चुने जाने के बाद भारत का संबंध कैसा रहेगा?

उत्तर: म्यांमार में संसद ने विगत 15 मार्च, 2016 को नोबल पुरस्कार विजेता आंग सान सू के करीबी और लंबे समय से सहयोगी रहे 70 वर्षीय हेतिन काव को करीब आधी सदी बाद देश का पहला असैनिक राष्ट्रपति चुना जो उस देश के राजनीतिक इतिहास में एक नया मोड़ है। पिछले वर्ष 2015 के 8 नवंबर को संपन्न चुनाव में म्यांमार की राजनीतिक पार्टी–नेशनल लीग फौर डेमोक्रेसी को संसद के दोनों विधायी सदनों में 652 में से 360 मत पाकर शानदार जीत मिली थी जिससे दो सदनीय संसद में सू की पार्टी का वर्चस्व कायम हो गया था, लेकिन दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र म्यांमार में सेना की अभी भी शक्तिशाली ताकत बने रहने की वजह से उसने संविधान के उस उपबंध में बदलाव से इनकार कर दिया जो सू की को शीर्ष राजनीतिक पद पर आसीन होने से रोक रहा था। इसलिए म्यांमार की राजधानी नेपीताव में मतगणना की लंबी प्रक्रिया के बाद हेतिन काव को राष्ट्रपति के लिए चुना गया।

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हेतिन काव एक सम्मानित कवि के पुत्र हैं और हालिया वर्षो में सू के धर्मार्थ संगठन को चलाने में सहायता की थी। वह लंबे अरसे से सू की के वफादार व्यक्ति माने जाते रहे हैं और जिन्होंने निवर्तमान राष्ट्रपति थेन सेन के पाँच साल के सेना समर्थित कार्यकाल में देश को सैन्य शासन की छाया से निकालने का सराहनीय कार्य किया था। कहा तो यहाँ तक जाता है कि हेतिन काव सू की के गाड़ी चालक का काम भी करते थे। यानी वे सू की के बहुत विश्वसनीय रहे हैं।

म्यांमार के नेशनल लीग फौर डेमाक्रेसी पार्टी की सर्वमान्य नेता सू की को संवैधानिक प्रावधानों के चलते उन्हें राष्ट्रपति बनने से रोक दिया गया और परदे के पीछे से इस पद की जिम्मेदारी संभालने का मौका हेतिन काव को मिल गया। सच तो यह है कि संसद में शानदार जीत का सारा श्रेय सू की को ही जाता है, मगर म्यांमार के सैन्य शासन के संविधान के प्रावधान के अनुसार सू की को इस आधार पर देश के शीर्ष पद का चुनाव लड़ने से ही रोक दिया गया था, क्योंकि उन्होंने एक विदेशी से शादी की थी और उस विदेशी से उनके बच्चे हैं। 1962 में देश की सत्ता को अपने हाथ में लेने वाली सेना ने संविधान में ऐसा प्रावधान कर रखा है जिससे सू की सर्वोच्च पद पर काबिज नहीं हो सकती हैं। प्रावधान के अनुसार, जिसके करीबी परिजन विदेशी नागरिक हों, वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। सेना के पूर्व जनरल राष्ट्रपति थीन सेन की सैन्य समर्थित यूनियन सोलिडरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी को संसद में 25 प्रतिशत सीटों पर गैर निर्वाचित सीटों पर कब्जा है और संविधान के संशोधन में उनके पास ही वीटो की शक्ति है जिसे सैन्य शासन ने 'अनुशासित लोकतंत्र' का नाम दिया। सू की को राष्ट्रपति बनाए जाने के संबंध में सैन्य प्रतिनिधियों के साथ बातचीत विफल होने के बाद ही हेतिन काव को राष्ट्रपति पद के लिए आगे बढ़ाया गया।

म्यांमार की संसद निचले तथा उच्च सदनों के निर्वासित सदस्यों के साथ-साथ गैर निर्वाचित सैन्य प्रतिनिधियों के मिलने से बनती है। संयुक्त सदन में ये तीनों समूह राष्ट्रपति पद के लिए अपने दावेदार खड़े करते हैं। उसके बाद जीतने वाला राष्ट्रपति और हारे हुए दोनों प्रत्याशी उपराष्ट्रपति बनते हैं। वैसे तो भारत के सैन्य जुंटा सेन से संबंध मधुर रहे हैं, लेकिन म्यांमार में लोकतंत्र की मजबूती से भारत के साथ सहज संबंधों की शुरुआत होगी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हेतिन काव शांत, मितभाषी हैं। उन्होंने ब्रिटेन से उच्च शिक्षा ग्रहण की है और इनके पिता सांसद रहे हैं और इनकी पत्नी सू सू विन भी सांसद तथा नेशनल लीग फौर डेमोक्रेसी पार्टी की प्रमुख सदस्य है। इसलिए कुल मिलकार कहा जाए तो तकरीबन पाँच दशकों के सैन्य शासन के बाद म्यांमार में पहली बार इतिहास़ की नई इबारत लिखी गई और लोकतांत्रिक तरीके से असैन्य राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया राष्ट्रपति भारत के लिए एक अहमियत रखता है, क्योंकि भारत की लुक इस्ट पॉलिसी के क्रियान्वयन के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में भारत का प्रवेश द्वार म्यांमार से बेहतर संबंध मददगार हो सकते हैं।

नि:संदेह म्यांमार में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की भारी जीत और पहली बार असैनिक राष्ट्रपति चुने जाने का पूरा श्रेय उसकी नेता सू की को जाता है जिसने म्यांमार में सैनिक तानाशाही से कड़ी लड़ाई लड़ने की बड़ी कीमत चुकायी है। न केवल वह दशकों नजरबंद रही हैं, बल्कि अपने लाइलाज रोगग्रस्त विदेशी पति के साथ उनके अंतिम क्षणों में भी सू की नहीं रह सकी। उनके पुत्र बचपन से ही अपनी मां के स्नेह से वंचित रहे हैं। इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि सू की की असाधारण लोकप्रियता की वजह से ही बर्बर दमन के बावजूद सेना का प्रतिरोध करने का मनोबल जनसाधारण बनाए रख सका है। इस बात का श्रेय भी सू की को देना पड़ेगा कि वह हमेशा एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रही है और अपने समर्थकों को समझाती रही है कि मीलों लंबे सफर का पहला कदम ही अभी उठाया जा सका है। शायद इसी कारण सेना के साथ किसी निर्णायक मुठभेड़ की बजाय सू की ने परदे के पीछे से ही कठपुतलियों के धागे अपने हाथ में समेट उनके संचालन की रणनीति बेहतर समझी है। म्यांमार में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में 50 साल के लंबे सैन्य शासन के बाद लोकतंत्रवादी आंग सान सू की एनएलडी पार्टी ने सत्ता ग्रहण की और सू की के स्कूली मित्र और करीबी सहयोगी हतिन काव ने पूर्व जनरल थीन सीन की जगह ली और राष्ट्रपति बने। सू की भी इस मंत्रिमंडल में शामिल हुई हैं और विदेश मंत्रालय के साथ ही अनेक मंत्रालय की जिम्मेदारियाँ संभालेंगी।

(108)प्रश्न: क्या अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा घोटाला दूसरा बोफोर्स साबित होने जा रहा है? क्या आप मानते हैं कि अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में दलाली का मामला काँग्रेस के लिए बोफोर्स से भी बड़ा संकट है?

उत्तर: विवादित 3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में दलाली के लेन-देन ने फिर साबित किया है कि हमारे देश में राजनेताओं, नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों की हथेली गर्म किए बिना ऐसे सौदे हो पाना टेढ़ी खीर है। भारत में करीब-करीब हर दूसरा-तीसरा सौदा दलाली के आरोपों से घिरता रहा है। विडंबना यह है कि ऐसा होने के बावजूद सबक सीखने से इंकार किया जा रहा है, क्योंकि बोफोर्स तोप सौदे में दलाली के लेन-देन के पुख्ता सबूतों के बाद भी अंतत: सच्चाई की तह तक नहीं पहुँचा जा सका था, लेकिन यह एक तथ्य है कि इस मसले की भी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। राजीव गाँधी की सत्ता से बेदखली का मूल

कारण आम लोगों के मन में व्याप्त यह संदेह ही था कि उनके करीबियों ने दलाली का पैसा खाया। काँग्रेस अभी भी बोफोर्स मामले का जिक्र होने पर सहज नहीं रह पाती। इसके पूरे आसार हैं कि रक्षा सौदे में दलाली के नए मामले के राजनीतिक असर से बचना सोनिया गाँधी के लिए उतना ही मुश्किल साबित हो सकता है जितना बोफोर्स मामले में राजीव गाँधी के लिए साबित हुआ था।

इटली के मिलान शहर की अदालत ने अगस्ता-वेस्टलैंड और उसकी मातृ कंपनी फिनमेकानिया के तीन बड़े अधिकारियों को इस सौदे में भ्रष्टाचार और लेखा-जोखा में हेराफेरी का दोषी पाते हुए जेल भेज दिया है, लेकिन अपने देश में रिश्वत लेने वालों के नाम तक पता नहीं चले हैं। मामले की सुनवाई के दौरान मिलान शहर की अदालत में पेश दो दस्तावेजों में काँग्रेस पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं का उल्लेख है जिसमें उन भारतीय नेताओं को 120 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की बात कही गई है। इस सौदे के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की डायरी में संक्षिप्त रूप में जो नाम लिखे मिले हैं उनमें एक ए.पी. भी हैं। संदेह है कि यह सोनिया गाँधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल (ए.पी) का नाम है। ऐसे ही अन्य संक्षिप्त नामों से कई बड़े लोग संदेह के घेरे में हैं। इटली कोर्ट ने वायुसेना के डिप्टी प्रमुख एसपी त्यागी का भ्रष्टाचार को दोषी बताया है। इटली की अदालत का फैसला वहाँ की जाँच एजेंसियों की लंबी छानबीन पर आधारित है इसलिए उसे खारिज नहीं किया जा सकता। तो क्या यही काम भारत में क्यों नहीं हो सकता? मोदी सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि हेलिकॉप्टर सौदे में रिश्वत के लेन-देन के मामले में हश्र बोफोर्स सौदे जैसा न हो। सी.बी.आई. और प्रवर्तन निदेशालय की धीमी गति से चल रही जाँच का कोई नतीजा अभी देश के सामने नहीं आया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या यह मामला भी बोफोर्स सौदा सहित पूर्व के कुछ अन्य हंगामाखेज घपलों-घोटालों की तरह ही राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के शोर में डूब जाएगा या निकट भविष्य में इसका पूरा सच देश के सामने आएगा?

देश ने बोफोर्स घोटाले का हश्र देखा है। जाँच एजेंसियों और न्याय तंत्र की शिथिलता की वजह से बोफोर्स मामला अपने अंजाम तक नहीं पहुँच पाया। ओट्टावियों क्वात्रोची जहाँ दुनिया में आजाद घूमता रहा, वहीं देश में भी किसी को सजा नहीं मिली। इसको देखते हुए अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर सौदे में दलाली को लेकर मचे हंगामे का परिणाम क्या होगा कोई

नहीं कह सकता। लेकिन इतना जरूर है कि इटली की मिलान कोर्ट ऑफ अपील्स के फैसले के बाद अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे में दलाली को लेकर रत्ती भर भी संदेह की गुंजाइश नहीं रह जाती। मिलान कोर्ट ऑफ अपील्स ने अपने फैसले में माना है कि इस सौदे के दौरान हुए भ्रष्टाचार में पूर्व नौसेना प्रमुख एस.पी. त्यागी शामिल थे। 225 पृष्ठों के अपने फैसले में न्यायालय ने कहा कि जाँच में यह बात सिद्ध हो चुकी है कि सौदे में 10-15 मिलियन डॉलर भारतीय अधिकारियों को दिए गए। अदालत के अनुसार दलाली सामने आने के बावजूद तत्कालीन सप्रंग सरकार ने इस हेलिकॉप्टर दलाली के पीछे की सच्चाई का पता लगाने की न कोशिश की और न ही जाँचकर्ताओं को संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराए। भारत के रक्षा मंत्रालय ने तथ्यों को सामने लाने में लापरवाही की। अब तो राहुल गाँधी के राजनीतिक सहायक कनिष्क सिंह का संबंध भी अगस्ता वेस्टलैंड सौदे के बिचौलिए से बताया जा रहा है।

हालांकि भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद, सरकार ने 1 जनवरी, 2014 को सौदा रद्द कर दिया था। सी.बी.आई. की जाँच भी सौंपी गयी थी, लेकिन सप्रंग सरकार के कार्यकाल में जाँच में कोई प्रगति हुई ऐसा सामने नहीं आई जबकि इटली की अदालत इसके उलट बात कर रही है जिसके आधार पर सरकार पहले से जाँच आरंभ कर सकती थी, मगर इसने वैसा नहीं किया, तो फिर दाल में काला दिखेगा ही। अब तो मोदी की वर्तमान सरकार के कार्यकाल भी तो दो साल से अधिक बीत चुके हैं। इसमें तो तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए थी, खास तौर पर इटली के मिलान कोर्ट का फैसला आने के बाद तो तेजी आ जानी चाहिए थी। अगर केंद्र की वर्तमान सरकार अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर के सौदे की दलाली के मामले की जाँच ठीक से कराती है तो काँग्रेस के लिए बोफोर्स से भी यह बड़ा संकट साबित हो सकता है। बोफोर्स घोटाले के मामले में हुई चूक से सबक लेते हुए अगस्ता मामले में आगे बढ़ने की ठोस पहल की जाए, तो न्याय तंत्र को सभी दोषियों को उनके किए की सजा देने में आसानी होगी। कारण कि इटली के मिलान अदालत के फैसले के अनुसार भी पूर्व एयर मार्शल एस.पी. त्यागी ने अगस्ता वेस्टलैंड को हेलिकॉप्टर कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में मदद की और त्यागी के परिवार को घूस के पैसे नकद और वायर के जरिए दिए गए। एस. पी. त्यागी साल 2005 से 2007 के बीच नौसेना प्रमुख थे जिस दौरान वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदा किया गया था।

(109)प्रश्नः क्या आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में फिर से एक बार बहुध्रुवीय दुनिया के नाम पर सैन्य शक्ति के संचय तथा युद्ध के नासूरों को पनपाया जा रहा है?

उत्तरः हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में फिर से एक बार बहुध्रुवीय दुनिया के नाम पर सैन्य शक्ति के संचय तथा युद्ध के नासूरों को पनपाया जा रहा है। आखिर तभी तो 1986-87 में सोवियत रूस के बिखराव के लगभग तीन दशक के बाद पूरी दुनिया एक ध्रुवीय दुनिया में बदली और अब रूस फिर अपनी सैन्यशक्ति को स्थापित करना चाह रहा है तथा साम्यवादी सपनों को देखने वाले लोगों को अपनी सैन्य शक्ति से गर्वित कर रहा है। इसी प्रकार यूरोप भी सैन्य उपकरणों की खोज और बिक्री पर अपनी संपन्नता का सपना संजोया है और अमेरिका तो पहले से ही बड़ा खिलाड़ी रहा है।

और तो और राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के भारत जहाँ से अहिंसक आंदोलन की नींव पड़ी और जहाँ गाँधी का अहिंसक प्रतिरोध का अस्त्र भी जहाँ-तहाँ प्रयोग में लाया जा रहा था, पिछले एक दशक में भारत के सैन्य बजट में लगभग दस गुने की वृद्धि हुई है और यह 16 हजार करोड़ रुपए वार्षिक से बढ़कर दो लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है यानी भारत के कुल बजट का तकरीबन 20 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार पाकिस्तान जो अमेरिकी मदद पर जिंदा है इसके बावजूद पाकिस्तान ने इस वर्ष 2016 में अपने सैन्य बजट में एक मुश्त 28 प्रतिशत की वृद्धि की है और जिसका अधिकांश हिस्सा परमाणु शक्ति पर खर्च होना है। दरअसल, आज दुनियावालों की संपत्ति का बड़ा स्रोत हथियारों की बिक्री है और उनकी संपन्नता को टिकाए रखने के लिए तथा बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम शस्त्र व्यापार है। एक सुखोई विमान की कीमत से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 700 अस्पताल और विद्यालय की स्थापना हो सकती है।

वैसे स्वहित के लिए युद्ध करना, अपने खेमे या समर्थक के लिए युद्ध की बजाय युद्ध का सैन्य सहयोगी बनना यह भी उतना ही हिंसा समर्थक विचारधारा है, जितनी की युद्ध करना। आज दुनिया की विषमता या दुनिया की संपन्नता का बड़े पैमाने पर संबंध हिंसा हथियार और युद्ध के साथ है। आज दुनिया के जो संपन्न और शक्तिशाली देश हैं, उनकी संपन्नता का बड़ा कारण युद्ध और हथियार का व्यापार है। युद्ध भी इस प्रकार आज एक व्यापार हो गया है जिसकी तैयारी के लिए मानसिक तौर पर दुनिया को तैयार करने

के लिए मीडिया और प्रचार का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। युद्ध के *लिए वातावरण तैयार करने* को वैश्विक झूठ का सहारा लिया जाता है, ताकि युद्ध के तर्क गढ़े जा सकें।

हिंसा और युद्ध के लिए शस्त्र की बिक्री, यह एक ऐसा मुनाफा शास्त्र है, जिसका प्रयोग अमेरिका, ईराक से अफगानिस्तान और दुनिया के अन्य देशों में सफलतापूर्वक कर रहा है। अफगानिस्तान में पहाड़ों की गुफाओं में छिपे तालिबानों को मारने के लिए द्रोण विमान और बमों का प्रयोग न केवल दुनिया के लिए आश्चर्य था, बल्कि युद्ध और हिंसा के प्रयोगकर्ताओं की एक आकर्षक खोज थी। ईराक और अफगानिस्तान की घटनाओं के बाद अमेरिका के हथियारों की बिक्री तेजी से बढ़ी और खरबों डॉलर का हथियार का धंधा बढ़ गया। यह सुविदित तथ्य है कि आगामी दशकों अमेरिकी या यूरोप की संपन्नता के लिए हथियार, तेल, खाद्यान्न और व्यापार पर एकाधिकार जरूरी है। हथियार और तेल के लिए वे युद्ध का इस्तेमाल करते हैं और खाद्यान्न एवं व्यापार के लिए विश्व व्यापार संगठन का।

दुनिया में एक ओर जहाँ भूख और बेरोजगारी बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर संपन्नता के बड़े-बड़े पहाड़ खड़े हो रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका और यूरोप में भी भीख माँगने वालों की संख्या बढ़ रही है। इस प्रकार इस विषम दुनिया में निःसंदेह हथियार, हिंसा और युद्ध के नासूरों को पनपाया जा रहा है।

(110) प्रश्नः रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किस तरह रूस को अपनी मुट्ठी में कर रखा है?

उत्तरः फ्योदोर दोस्तोवस्की के उपन्यास 'ब्रदर्स कारामाजोव' में जाँचकर्ता के अनुसार रहस्य, चमत्कार और सत्ता ही वे तीन शक्तियाँ हैं जो लोगों की चेतना काबू में रखती हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इन तीनों शक्तियों में महारत हासिल कर रखी है। लेकिन इनमें से कोई भी गोपनीयता जितना महत्वपूर्ण नहीं है अच्छे गुप्तचर का मुख्य औजार। कोई नहीं जानता कि क्रेमलिन की मोटी दीवारों के पीछे या पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है।

पुतिन का शासक उत्तरोत्तर व्यक्तिगत रूप लेता जा रहा है। उनके दल में पीढ़ीगत बदलाव हो रहा है और केजीबी की उत्तराधिकारी संस्था फेडरल सिक्योरिटी सर्विस (एफएसबी) सत्ता चलाने का मुख्य जरिया बन रही है। पुतिन हमेशा केजीबी के पूर्व साथियों पर अत्यधिक निर्भर रहे हैं, लेकिन क्रीमिया के बाद से एपुएसबी के विस्तार ने रफ्तार पकड़ी है। अब वह खुलेआम राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का इस्तेमाल करती है। हाल

ही में पुतिन ने अपने सुरक्षा दल के तीन सदस्यों और केजीबी के एक पूर्व अधिकारी को क्षेत्रीय गवर्नर बनाया है। एफएसबी ही ज्यादातर दमनकारी कानूनों को मसौदा बनाती है जिस पर संसद सिर्फ मुहर लगाती है। संसद तो एफएसबी की पिछलग्गू बन गई है।

व्यक्तिगत रुतबा बढ़ने के साथ पुतिन पुराने कामरेडों से पींड छुड़ा रहे हैं और उनकी जगह वे ले रहे हैं, जिन्होंने पुतिन को सिर्फ राष्ट्रपति के रूप में देखा है पूर्व बॉडीगार्ड के रूप में जोलोतोव पुतिन की व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ-साथ एफएसबी की ताकत भी संतुलित करते हैं।

(111)प्रश्न: क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि पाकिस्तानी खुराफातों की वजह से उससे जासूस व उसके मददगारों की चौकसी के साथ ही सीमा पर सतर्कता जरूरी है?

उत्तर: हाँ, मैं भी ऐसा महसूस करता हूँ कि भारत-पाक के बीच तनाव के इस दौर में पाकिस्तान की गतिविधियाँ बहुत घातक हो सकती हैं। इसलिए पाक उच्चायुक्त के अधिकारी महमूद अख्तर के दिल्ली के चिड़ियाघर के पास गोपनीय दस्तावेज लेते समय पकड़े जाने पर देश निकाला देकर भारत सरकार ने ठीक ही किया है। तीन साल से भारत में तैनात इस अधिकारी पर दिल्ली पुलिस तकरीबन सालभर से निगाह रखे हुए थी।

हिंदी फिल्म सरफरोश की तरह जासूसी के इस काम में राजस्थान के नागौर जिले के दो भारतीय भी पकड़े गए हैं, जो महमूद अख्तर को रक्षा संबंधी नक्शे, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों की सूची और कई वीजा देने गए थे। जाहिर है कि सीमा पर घुसपैठ की गतिविधियाँ स्थानीय लोगों की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकती और एक फौज एवं आईएसआई इस काम को बखूबी अंजाम देती है। आईएसआई का जाल भारत से लेकर बांग्लादेश तक फैला हुआ है और वह संस्था जासूसी से लेकर आतंकी गतिविधियों तक को अंजाम देती रहती है। उसे रोकना तो जरूरी है ही, पर उससे ज्यादा जरूरी है देश के भीतर के दगाबाजों पर निगाह रखने की। इन गद्दारों का न तो कोई धर्म होता है और न कोई जाति। उनका ईमान केवल पैसा कमाना होता है। भारत की सीमा से घुसपैठ और तमाम आतंकी गतिविधियों में उनकी भूमिका संदिग्ध होती है। इसलिए सीमा पर चौकसी और सतर्कता के साथ देश के भीतर पनप रही गद्दारी को भी उखाड़ फेंकना जरूरी है।

(112) प्रश्न: पाकिस्तान के क्वेटा शहर के करीब बलूचिस्तान पुलिस कॉलेज में इस्लामिक स्टेट के खुँखार आतंकियों द्वारा मारे गए लोगों के परिजनों की चीख-पुकार क्या उन प्रभावशाली देशों की अंतरात्मा को झकझोर सकेगी, जो पाकिस्तानी शासन के भयानक इरादों को लेकर लापरवाह हैं?

उत्तर: पिछले दिनों पाकिस्तान के क्वेटा शहर के करीब बलूचिस्तान पुलिस कॉलेज में इस्लामिक स्टेट के खूँखार आतंकियों द्वारा किए गए हमले में कम-से-कम 60 लोग मारे गए और सौ से अधिक घायल हुए। पाकिस्तान में इस साल 2016 में हुआ यह चौथा बड़ा आतंकी हमला है। इससे पहले मार्च, 2016 में लाहौर में, अगस्त, 2016 में क्वेटा में और सितंबर, 2016 में उत्तर-पश्चिम कबायली इलाके में बड़े फियादीन हमले हो चुकी हैं।

कपिलदेव जी, अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी धरती पर सक्रिय दर्जनों चरमपंथी हिंसक गुटों पर कोई गंभीर कार्रवाई करेगा या फिर अंदरूनी और विदेशी नीति के एक हथियार के रूप में इनका इस्तेमाल जारी रखेगा। लगातार हमलों से त्रस्त पाकिस्तानी जनता को भी अपने हुक्मरानों पर दबाव बनाना होगा। पाकिस्तान के खतरनाक रवैए की वजह से आतंकियों को न सिर्फ एक सुरक्षित पनाह मिल रही है, बल्कि उन्हें राजकीय संरक्षण भी प्राप्त है।

वैसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय तो लंबे समय से पाकिस्तान को चेतावनी देता रहा है, पर वैश्विक कूटनीतिक परिदृश्य के अंतर्विरोधों के कारण उसके विरूद्ध ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है। विश्वास ही नहीं उम्मीद भी की जाती है कि इस बार क्वेटा के बलूचिस्तान पुलिस कॉलेज में मारे गए कैडेट के परिजनों की चीख-पुकार शायद उन प्रभावशाली देशों की अंतरात्मा को झकझोर सके, जो पाकिस्तानी शासन के भयानक इरादों को लेकर लापरवाह हैं।

क्वेटा अशांत बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी है। यह पाकिस्तान में सबसे भीषण आतंकी हमलों में से एक है जिसमें बैरक में सो रहे रंगरूटों को निशाना बनाया गया। कई कैडेटों को आतंकियों ने बंधक बना लिया। आतंकियों ने पाँच अलग-अलग जगहों से गोलीबारी की। ज्यादातर मौतें तब हुई जब दो हमलावरों ने खुद को उड़ा लिया।

उल्लेख्य है कि आतंकवाद पर एक ठोस समझ बनाने के लिए भारतीय प्रस्ताव बरसों से संयुक्त राष्ट्र में लंबित है। पाकिस्तान में खुलेआम आतंक की पैरोकारी कर रहे सरगनाओं पर पाबंदी की माँग पर भी फैसला

बाकी है। दहशतगर्दी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में अब विलंब उचित नहीं है। क्वेटा की घटना का यही सबक है।

मुझे लगता है कि प्रभावशाली देशों में सबसे पहले चीन की अंतरात्मा क्वेटा की यह घटना अवश्य झकझोरेगी, क्योंकि पीओके और बलूचिस्तान से गुजरने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर में 46 अरब डॉलर का निवेश चीन की एक और दुखती राग है। भारत ने सिर्फ इसका विरोध कर रहा है, बल्कि जबसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र किया है, बलूच आंदोलन तेज हुआ है और कॉरिडोर पर काम कर रहे चीनियों पर हमले भी हुए हैं। भारतीय सीमा में अपने सैनिक भेजकर और गाहे-बगाहे अरुणाचल का मसला उठाकर भारत पर दबाव बनाए रखने वाले चीन को पहली बार पता चल रहा है कि भारत भी उस पर दबाव बना सकता है और वह उसपर ज्यादा भारी पड़ेगा।

(113)प्रश्न: अमेरिका के आतंकवाद और वित्तीय खुफिया विभाग के उपमंत्री ऐडम जुबिन ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में कहा कि यदि उसने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो वह खुद उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। जुबिन की इस चेतावनी को आप किस रूप में आँकते हैं?

उत्तर: बेशक पाकिस्तान में आतंकवाद के विरूद्ध यह अमेरिका का सबसे बड़ा वक्तव्य है, क्योंकि हमारे लिए इसमें सीमा पार आतंकवाद के संदर्भ में भारत का समर्थन है। पाकिस्तान इसे चेतावनी समझे या और कुछ, मगर पहली नजर में अमेरिका के आतंकवाद और वित्तीय खुफिया विभाग के उपमंत्री ऐडम जुबिन का यह वक्तव्य कि 'यदि पाकिस्तान ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो वह खुद उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा', सामान्य नहीं लगता। उन्होंने पाकिस्तान पर आतंकवाद को संरक्षण देने और उसे खत्म न करने का भी आरोप लगाया। पाकिस्तान सरकार के अंदर मौजूद कुछ ताकतें, खासतौर पर आईएसआई पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं करना चाहते।

अब प्रश्न यह उठता है कि सेना और आईएसआई या पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान के दूसरे ऐसे तत्व क्या अमेरिका की इस चेतावनी से अपने को बदल देंगे? मैं समझता हूँ कि ऐसा मानना बेमानी होगा और जल्दबाजी भी। वैसे अमेरिका ड्रोन हर कुछ अंतराल पर आतंकवादियों पर हमला कर

रहे हैं। इनका पाकिस्तान में विरोध भी होता है और कट्टरपंथी तत्व इसे संप्रभुता पर हमला तक करार देते हैं। फिर भी अभी तक अमेरिका ने कभी पाकिस्तान में आतंकवाद को समूल नाश करने की योजना नहीं बनाई है।

(114)प्रश्नः क्या आपको ऐसा लगता है कि रूस के सीमावर्ती देशों पर फौज के जमावड़ा रूस द्वारा परमाणु ताकत के प्रदर्शन और एस्तोनिया में ब्रिटेन द्वारा तैनात किए गए टैंक के साथ 800 सैन्य टुकड़ियाँ तैनात किए जाने की वजह से यूरोप में युद्ध के बादल मंडराते नजर आने लगे हैं?

उत्तरः हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि जब रूस ने अमेरिका से समझौता तोड़ते हुए परमाणु मिसाइलों का परीक्षण किया है और इसके बाद रूस से लगे सीमावर्ती देशों में नाटों के सदस्य देशों ने सेना तैनात कर दी है तथा इसी प्रकार ब्रिटेन ने सबसे बड़ी फौज के रूप में 800 सैन्य टूकड़ियाँ, कई सारे टैंक और ड्रोन एस्तोनिया में तैनात किए हैं, तो ये सारे तथ्य इस बात की ओर संकेत हैं कि यूरोप में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं।

अमेरिका को लगता है कि जिस तरह रूस ने 2014 में अचानक यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा किया था वैसे ही वह सोवियत संघ से अलग हुए अन्य देशों पर कर सकता है। उसे उम्मीद है कि नाटो के सदस्य देश अपनी प्रतिबद्धता के कारण चार युद्ध क्षेत्रों में करीब 4000 सैनिक भेज देंगे। अत्याधुनिक हथियारों से लैस सैनिक बख्तरबंद गाड़ियाँ, टोहीड्रोन चैलेंजर-2 टैंक सहित 40 हजार नाटों के सैनिक तैयार हैं। ब्रिटेन 28 मजबूत टीमें कोसोबों भेज रहा है। अमेरिकी सेना की मदद के लिए ब्रिटिश और रोमानियाई सेना पोलैंड पहुँच रही है। रूस ने आरएस-28 सरमत परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है जो फ्रांस के बराबर के इलाके को तबाह कर सकती है। ब्रिटेन तो पूरी तरह खत्म हो सकता है। अमेरिका ने इसे शैतान-2 का नाम दिया है। इसकी गति 7 कि.मी. प्रति सेकेंड है। एंटी मिसाइल शील्ड प्रणाली को भी धोखा दे सकती है। यह 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए बम से 2000 गुना ज्यादा ताकतवर है। इन सभी गतिविधियों से ऐसा लगता है कि यूरोप युद्ध के कगार पर है।

(115)प्रश्नः क्या औपनिवेशिक मानसिकता आज भी संयुक्त राष्ट्र पर हावी है? आखिर क्यों?

उत्तरः हाँ, संयुक्त राष्ट्र पर औपनिवेशिक मानसिकता आज भी हावी है, क्योंकि पी-5 यानी परमानेंट-5 के पाँच देशों अमेरिका, इंग्लैंड, रूस,

फ्रांस और चीन जिनके पास 'वीटो पावर' है संयुक्त राष्ट्र की 1945 में हुई स्थापना के ही समय से उसकी सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य बने हुए हैं और उनका 'वीटो पावर' इनकी दबंगई का ब्रह्मास्त्र है। इसके आगे बाकी 188 संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के सारे हथियार बेकार हो जाते हैं।

21वीं सदी में बदलते विश्व परिदृश्य के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बात भारत ने उठाई थी, लेकिन ये पी-5 के पाँच दबंग देश अन्य 188 देशों को आज भी इस लायक नहीं समझते कि सभी सदस्यों को समान अधिकार हो। यह उनकी औपनिवेशिक मानसिकता नहीं तो और क्या है? दादागिरी से हथियाए इसी वीटो पावर के चंगुल में 71वें वर्ष में संयुक्त राष्ट्र है और सिर्फ कमजोर होने की वजह से अन्य सदस्यों की आवाज फड़फड़ा कर रह जाती है। यह इस बात का सूचक है कि आज भी संयुक्त राष्ट्र पर औपनिवेशिक मानसिकता हावी है।

(116)प्रश्न: क्या आपको ऐसा लगता है कि पश्चिम एशिया में वर्षों से चल रहे युद्ध का अंत होगा?

उत्तर: जिस प्रकार ईरान और सीरिया में वर्षों से युद्ध चल रहा है और इसमें विदेशी ताकतें शामिल हो गयी हैं उससे तो अभी ऐसा आसार नहीं लग रहा है कि युद्ध समाप्त होने वाला है। इस युद्ध में हजारों निरापराध लोग जहाँ मारे गए हैं, वहीं लाखों लोग अपने घरबार छोड़कर विदेशों में शरण लेने के लिए विवश हुए हैं। युद्ध जर्जर पश्चिम एशिया में संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना के सभी प्रयास भी विफल हो चुके हैं।

ईराक में जहाँ इस्लामिक स्टेट जैसे खूँखार आतंकी संगठन के खिलाफ सरकारी सेना लड़ रही है, वहीं सीरिया में सरकार और विद्राहियों के बीच घमासान मचा है। सीरिया में रूस जहाँ सरकारी सेना का साथ दे रहा है, वहीं अमेरिका विद्राहियों को मदद कर रहा है। इसलिए यह लड़ाई विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप से और भी भयानक हो गई है। एक तरफ ईराक में सरकारी सेना ने देश के सबसे बड़े शहर मसूल को इस्लामिक स्टेट के कब्जे से मुक्त कराने के लिए अपना अभियान तेज कर दिया है, तो दूसरी तरफ सीरिया की स्थिति भी खराब होती जा रही है। यहाँ तक कि खाने-पीने वाली जरूरत की चीजों का भी अब अभाव होता दिख रहा है और दवा के बिना इलाज कराना मुश्किल हो रहा है।

इस प्रकार प. एशिया में युद्ध कब अंत होगा फिलहाल निकट भविष्य में तो इसके आसार नहीं नजर आ रहे हैं।

(117)प्रश्नः क्या आपको ऐसा लगता है कि दक्षेस की जगह बिम्सटेक भारत के लिए सही सहयोग संगठन साबित होगा? इसकी क्या वजह है?

उत्तरः हाँ, भाई शर्मा जी, मुझे ऐसा लगता है कि ब्रिक्स यानी दक्षेस (बांग्लादेश, इंडिया, चीन, रूस और साउथ अफ्रीका) की बजाय बिम्सटेक(वे ऑफ बंगाल इनीशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनोमिक कोओपरेशन) भारत के लिए सही संगठन साबित होगा, क्योंकि इसमें दो बड़े शत्रु देशों की मौजूदगी एक साथ नहीं है। जाहिर है इससे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के रास्ते में कोई गतिरोध नहीं है। बिम्सटेक में बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाइलैंड, नेपाल और मालदीव शामिल चीन और अमेरिका दोनों एक-दूसरे के दुश्मन देशों के नहीं रहने से गतिरोध नहीं हो पाएगा। जैसे अभी पिछले 15 एवं 16 अक्टूबर, 2016 को गोवा में संपन्न ब्रिक्स-बिम्सटेक के आठवें शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में पाकिस्तान को जब आतंकवाद की जननी कहा, तब पाकिस्तान का बड़ा भाई चीन नहीं चाह रहा था कि पाकिस्तान आधारित जिहादी संगठनों का नाम लिया जाए और उनकी निंदा की जाए, जिसकी वजह से गोवा घोषणापत्र में उनके नामों का उल्लेख नहीं हो पाया। वहीं बिम्सटेक, देशों ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए आतंकवाद के प्रायोजक देशों की निंदा की। इस प्रकार गोवा सम्मेलन के उपरांत पाकिस्तान 1947 में अपने निर्माण के बाद पहली बार कूटनीतिक स्तर पर इतना अलग-थलग हुआ है। गोवा सम्मेलन का सबसे सकारात्मक पहलू बिम्सटेक की ताजा शुरुआत होना है, जो कि क्षेत्र में आर्थिक राजनीतिक और सामरिक सहयोग के नए दौर का अग्रदूत बना है।

दक्षेस का मुख्य उद्येश्य हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अवसर मुहैया कराकर दक्षिण एशिया के लोगों का कल्याण करना और जीवन की गुणवत्ता को ऊपर उठाना तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को तीव्र करना था। इसके साथ ही एक-दूसरे की समस्याओं को समझकर उनको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग करना था, लेकिन दक्षेस ने अपने 31 साल के इतिहास में इनमें से एक भी उद्येश्य पूरा नहीं कर पाया है। सच कहा जाए तो वह दो सबसे बड़े देश भारत और पाकिस्तान के विवादों का मंच बनकर रह गया है। इसलिए समय का तकाजा है कि दक्षेस को विघटित कर दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के बिना एक नया क्षेत्रीय मंच स्थापित किया जाए। दूसरा विकल्प यह हो

सकता है कि भारत दक्षेस से खुद बाहर आ जाए और एक साझा आर्थिक बाजार कायम करने का लक्ष्य लेकर अपने मित्र पड़ोसी देशों के साथ मिलकर एक नया संगठन बनाए। तीसरा विकल्प यह हो सकता है कि बिम्सटेक को ही मजबूत किया जाए और कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, मलेशिया और सिंगापुर को इसमें शामिल कर और साथ ही अफगानिस्तान को एक विशेष पर्यवेक्षक का दर्जा देकर इसका विस्तार कर दिया जाए। इस प्रकार बिम्सटेक दक्षेस की तुलना में शक्ति संतुलन के ख्याल से बेहतर सहयोगी संगठन साबित हो सकता है।

(118)प्रश्न:भूमिबोल अदुल्यदेज के देहावसान से थाईलैंड की राजनीति में अत्यंत सूनापन आखिर क्यों आ गया है? क्या नया राजा भूमिबोल की नीतियों का समर्थन करेंगे या सेना के हाथों कठपुतली बनकर रह जाएँगे?

उत्तर: डॉ. मधु जी, पिछले दिनों थाइलैंड के 88 वर्षीय राजा भूमिबोल अदुल्यदेज का निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार थे। उनके निधन ने थाइलैंड की राजनीति में एक भयानक सूनापन ला दिया है। राजा भूमिबोल ने 70 वर्षो तक थाइलैंड पर राज किया। संसार में किसी दूसरे राजा ने इतनी अवधि तक राज नहीं किया। भूमिबोल को लोग देवता की तरह पूजते थे। अपने पूजा घर में भगवान बुद्ध की मूर्ति के साथ भूमिबोल की तस्वीर रखते थे और नियमपूर्वक सुबह-शाम अगरबत्ती जलाकर उस तस्वीर की आरती उतारते थे। भूमिबोल का सम्मान थाइलैंड में इतना अधिक था कि किसी देशी या परदेशी व्यक्ति को उनकी समालोचना करने का हक नहीं था और यदि कोई व्यक्ति भूमिबोल के खिलाफ कुछ बोलता था, तो उसे वर्षो की कड़ी सजा होती थी। थाईलैंड में पिछले अनेक वर्षो में कई सैनिक क्रांतियाँ हुई, परंतु किसी सेनाध्यक्ष को यह हिम्मत नहीं हुई कि वह राजा की बातों का उल्लंघन कर सके। भूमिबोल बोलते कम थे, परंतु कुछ शब्दों में ही अपनी भावना को व्यक्त कर देते थे जिससे दरबारी यह समझ जाते थे कि सैनिक क्रांति को राजा का आशीर्वाद प्राप्त है अथवा नहीं।

भूमिबोल एक अत्यंत ही पारदर्शी राजा थे। वह केवल एक संवैधानिक राजा नहीं थे, बल्कि उन्होंने सही अर्थ में देश पर राज किया था। वह बिना किसी को बताए दूर-दराज जाते और गरीब प्रजा की कठिनाइयों को सुनते-समझते थे। कई बार तो उन्होंने गरीबों के साथ खड़े होकर गाँव के उत्थान के लिए श्रमदान किया था।

थाइलैंड का कोई भी प्रधानमंत्री हो, लेकिन हुक्म भूमिबोल का ही चलता था। जो कोई विशिष्ट व्यक्ति चाहे वह प्रधानमंत्री हो या मंत्री या सेनाध्यक्ष जब भूमिबोल से मिलने आते थे, तो उन्हें मुख्य द्वार से राजा से सिंहासन तक घुटनों के बल चलकर आना होता था। वह राजा के प्रति सम्मान का सूचक था।

थाइलैंड की 80 प्रतिशत जनता बौद्ध है। सम्राट अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म भारत से थाइलैंड गया। उन दिनों थाइलैंड का नाम 'सियाम' था। आज तक थाइलैंड में बौद्ध धर्म जीवित है। राजा यद्यपि बौद्ध थे, परंतु हिंदू धर्म का भी समान रूप से सम्मान करते थे। यही कारण है कि थाइलैंड में एक प्राचीन परंपरा चली आ रही है कि जब कोई व्यक्ति राजा बनता है, तो उसे 'राम' की उपाधि दी जाती है।

भारत के बहुत बड़े समर्थक भूमिबोल भारत की गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करते थे तथा किसी सामरिक गुट में शामिल नहीं होने की बात करते थे। उन्हें भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं था। भूमिबोल ने अपने जीवनकाल में ही कहा था कि उनके युवराज 'महावजीरा लोंगकोर्न' देश के अगले राजा होंगे। वैसे राजकुमारी वहाँ के लोगों में अधिक लोकप्रिय हैं, जिनकी शिक्षा-दिक्षा भारत में ही हुई है। बौद्ध धर्म की परंपरा के अनुसार राजकुमार ने सौ दिनों के बाद राजा का पदभार ग्रहण कर लिया। एक बात तो तय है कि राजकुमार अपने देश में अधिक लोकप्रिय नहीं होने के कारण वहाँ के लोगों में यह डर है कि भूमिबोल ने थाइलैंड में जो स्थायित्व लाने का प्रयास किया था वह शायद अब संभव नहीं होगा। वैसे भी राजकुमार को भूमिबोल की तरह देवता जैसा नहीं पूजा जा सकेगा, क्योंकि जनता के कल्याण से उन्हें कोई मतलब नहीं रहा है। यही कारण है कि भूमिबोल के निधन के बाद थाइलैंड की राजनीति में एक बड़ा सूनापन आ गया है। देखना यह है कि क्या नए राजा महावजीरा लोंगकोर्न भूमिबोल की नीतियों का समर्थन करेंगे या सेना के हाथों कठपुतली बनकर रह जाएँगे?

(119)प्रश्नः विकास को लाने और दलाली पर टिके इस 'क्रोनी पूँजीवादी' तंत्र को खत्म करने का क्या उपाय हो सकता है?

उत्तरः भारतीय समाज हो या वैश्विक समाज हर तरफ दलाली का बोलबाला हो गया है। रक्षा सौदों की दलाली एक ऐसा मुद्दा है, जिसमें यदि जन-चौकसी न बरती गयी, तो जिस देश के चलते हम सभी का वजूद है, वही खोखला हो जाएगा। आपको याद होगा, बोफोर्स कांड तब सामने आया,

जब मिस्टर क्लीन देश के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद जॉर्ज फर्नाडीज से लेकर ए. के. एंटनी और मौजूदा रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर तक की छवि बड़ी साफ शफ्फाक रही है।

इधर, पाकिस्तान से बढ़ते तनाव और युद्धक विमानों से लेकर मिसाइलों व पनडुब्बियों की खरीद के बीच एक बार फिर रक्षा सौदों में दलाली के मुद्दे ने सिर उठाना शुरू किया है। आपने सुना होगा न्यायिक हिरासत में चल रहे हथियारों के सौदागर अभिषेक वर्मा के पूर्व पार्टनर अमेरिकी वकील एडमंड्स एलेन ने सीधे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि भाजपा सांसद वरुण गाँधी ने रक्षा संबंधी संवेदनशील जानकारियाँ लीक की हैं। वरुण गाँधी ने इन आरोपों का खंडन किया है। दरअसल, हथियारों के धँधें में किसके तार कहाँ-कहाँ से जुड़े हैं, पता लगाना बेहद मुश्किल है। दुनिया में हथियारों की बहुत लंबी लॉबी है। उसका बड़ा शातिर और आपराधिक किस्म का तंत्र है, जो सरकारों से लेकर विपक्षी दलों तक को हमेशा साध कर रखता है। यहाँ तक कि तमाम राष्ट्र-प्रमुख भी इसके एजेंट की तरह काम करते हैं। भारत पर इस लॉबी की गिद्ध-दृष्टि हमेशा लगी रहती है। कारण कि एक तो यह कि भारत अब भी दुनिया का सबसें बड़ा हथियार आयातक देश बना हुआ है। दूसरे, हमारे केंद्रीय बजट का सबसे बड़ा हिस्सा रक्षा पर खर्च किया जाता है। इसके अतिरिक्त कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सरकारी ठेकों के लिए भयंकर मार होती है। जाहिर है कि जहाँ चीनी ज्यादा होगी, वहाँ चीटियाँ ज्यादा आएँगी ही। इसलिए रक्षा सौदे के मामले में दलालों की भरमार है।

जहाँ तक विकास लाने और दलाली पर टिके इस 'क्रोनी पूँजीवादी' तंत्र को खत्म करने के उपाय का सवाल है इसे पारदर्शिता लाकर खत्म किया जा सकता है। अब लगभग हरेक देशवासी के पास मोबाइल है और कनेक्टिविटी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसमें उनकी नजरों का पहरा बहुत सुधार ला सकता है। रक्षा सौदों का विवरण संसदीय समिति के सामने रखकर पहल की जानी चाहिए। अन्यथा, रक्षा क्षेत्र को गाय बनाकर रखा गया, तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शब्दों में ऐसे फर्जी गोरक्षक पनपते रहेंगे, जो 'पूरी रात असामाजिक कार्यो में लिप्त रहते हैं और दिन में गोरक्षक का चोला पहन लेते हैं।'

(120)प्रश्नः क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत को सुस्पष्ट रणनीतिक उद्येश्यों के साथ इजरायल से दोस्ती बढ़ानी चाहिए?

उत्तरः हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि भारत को सुस्पष्ट रणनीतिक उद्येश्यों के साथ इजरायल से दोस्ती बढ़ानी चाहिए, क्योंकि भारत की बदलती जरूरतों को देखते हुए उसकी भू-सामरिक आवश्यकताएँ अब पहले जैसी नहीं रहीं, बल्कि उनमें भी बदलाव आए हैं। सुरक्षा और आर्थिक विकास, भारत की दो सबसे बड़ी और आधारभूत जरूरतें हैं। इन दोनों जरूरतों को देखते हुए यदि कोई देश भारत के साथ साझेदारी करना चाहता है, तो भारत के लिए बेहतर यही होगा कि वह उसे स्वीकार करे। इजरायल कुछ ऐसी ही मंशा प्रकट करता है, क्योंकि इजरायली राष्ट्रपति रियवेन रिवलिन की हाल की भारत यात्रा पर पहुँचने के पश्चात् उन्होंने आतंक को सिर्फ आतंक के रूप में मान्यता देकर भारत के दृष्टिकोण को स्वीकार कर यह संकेत दिया कि इजरायल भारत के कदमों को उचित मानता है और भारत के साथ है।

भारत की प्रमुख दो जरूरतों की बात करें, तो इनमें पहली चीन के साथ सीमा विवाद तथा चीन की आक्रामकता है। चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' नीति के जरिए भारत को घेरने की कोशिश पाकिस्तान के साथ काश्गर से ग्वादर तक सामरिक महत्व के कॉरिडोर का निर्माण एवं 'वन वेल्ट, वन रोड' योजना पर चीनी सक्रियता, भारत के लिए गंभीर चुनौती की तरह है। इसलिए जरूरतों के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि भारत को सुस्पष्ट रणनीतिक उद्येश्यों के साथ इजरायल से दोस्ती बढ़ानी चाहिए। वैसे भी भारत इजरायल का 10वाँ सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच लगभग 670 अरब रुपए का कारोबार हुआ और भारत प्रतिवर्ष 67 से 100 अरब रुपए का सैन्य साजो-सामान इजरायल से आयात करता है।

(121)प्रश्नः क्या आपको ऐसा लगता है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद पूरे विश्व की राजनीति में एक अजीब परिवर्तन दिखाई दे रहा है?

उत्तरः हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति के पद पर डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद पूरे विश्व की राजनीति में एक अजीब परिवर्तन दिखाई दे रहा है, क्योंकि कभी जिन मुद्दों पर सरकारें बदनाम होती थीं या गिर जाती थीं, आज उन्हीं मुद्दों पर पूर्ण बहुमत से सरकारें बन रही हैं। यानी कि छद्म धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के गीत गाने वाले तथा खुद

को उदारवादी और परम सहिष्णु कहने वाले नेताओं को लोग नकारते नजर आ रहे हैं। चाहे वह भारत का 2014 का लोकसभा चुनाव हो या ब्रिटेन का यूरोपीय संघ छोड़ने का मामला या फिर अमेरिका जैसे समृद्ध एवं सर्वशक्तिशाली देश में राष्ट्रपति का चुनाव हो।

दरअसल, चुनावों में पारंपरिक मुद्दों का गौण हो जाना सिर्फ अमेरिका में ही नहीं दिख रहा है, बल्कि दुनिया के कई देशों में पिछले कुछ सालों में ढेरों ऐसे मौके आए हैं जिनसे ऐसे संकेत मिले हैं कि आम लोगों के लिए सियासत के मुद्दे बदल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वही बात की जो अमेरिकी जनता सुनना चाह रही थी। ट्रंप द्वारा चुनाव प्रचार में आतंकवाद के खिलाफ खरी-खरी बात करना तथा अमेरीकियों के अंदर राष्ट्रवाद का भाव पैदा करना तथा कट्टर इस्लामवादियों पर प्रतिबंध लगाने की बात करना ट्रंप के पक्ष में गया। इस भावना ने अमेरीकियों के एक बड़े वर्ग को प्रभावित किया, क्योंकि अमेरिका अपनी भौगोलिक सीमाओं में संरक्षित होते हुए भी हर क्षण हमले के भय में जीता है? इस समय जेहादी आतंकवाद ने जिस तरह दुनिया भर में भय पैदा किया है उससे अमेरिका अछूता नहीं है। यह सामान्य बात नहीं है कि इसको लेकर अमेरिकी भारतीयों के बड़े समूह ने ट्रंप के पक्ष में मतदान किया। इसी प्रकार बहुत कम लोगों को उम्मीद थी कि ब्रिटेन के लोग यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के पक्ष में मत देंगे, लेकिन नतीजों ने सारे अनुमानों को झूठा साबित कर दिया।

(122)प्रश्नः क्या आप मानते हैं कि जापान सिर्फ भारत का आर्थिक साझीदार ही नहीं, बल्कि एक विश्वसनीय मित्र भी है? आखिर कैसे?

उत्तर: हाँ, मैं मानता हूँ कि जापान सिर्फ भारत का आर्थिक साझीदार ही नहीं, बल्कि एक विश्वसनीय मित्र भी है, क्योंकि 1980 के पूर्वार्द्ध में सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन का भारत में निवेश न सिर्फ भारत के आर्थिक विकास को बदलने वाला साबित हुआ, बल्कि इसने यहाँ के ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी क्रांति का सूत्रपात कर दिया।

1991 में जब भारत में मुद्रा संकट पैदा हुआ तब जापान ने बिना किसी शर्त के इस संकट से उबरने में भारत का साथ दिया। 21वीं सदी की शुरुआत में इन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में गर्माहट आयी, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2000 में जापान-भारत वैश्विक साझेदारी की शुरुआत हुई। 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और शिंजो आबे ने संयुक्त

वक्तव्य पर हस्ताक्षर किया। 2011 में जापान और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को अंतिम रूप दिया। वर्ष 2013 में जापान के राजा अकिहितो भारत यात्रा पर आए।

करीब 1400 वर्ष पूर्व स्थापित संपर्क के बाद तबसे भारत और जापान के संबंध मधुर रहे हैं। द्विपक्षीय संबंधों की गर्माहट इस बात से समझी जा सकती है कि द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद भारत ने सैन फ्रांसिस्कों कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की बजाय जापान की पूर्ण संप्रभुता बहाल होने के बाद 1952 में उसके साथ पृथक संधि को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया। भारत और जापान के आर्थिक संबंधों में विकास की काफी गुंजाइश अब भी है। जापान भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता यानी डोनर है। जापानी आधिकारिक विकास सहायता भारत के आर्थिक विकास की गति देने के प्रयासों में काफी सहायक सिद्ध हो रहा है जिसका जीता-जागता उदाहरण दिल्ली मेट्रो परियोजना है जिसमें जापान ने सहयोग किया है। इस प्रकार जापान भारत का एक विश्वसनीय मित्र होना सिद्ध करता है।

(123)प्रश्नः क्या आप इस बात से सहमत हैं कि विकास का रास्ता शांति के पक्ष से गुजरता है? क्या इस कथ्य के मद्देनजर अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी मानसिकता में बदलाव लाएँगे?

उत्तरः हाँ, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि विकास का रास्ता शांति पथ से गुजरता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब देश को विकास के पथ पर ले जाने की बात आई तब उग्रता का रास्ता छोड़ नम्रता का रास्ता चुनना पड़ा। इस तरह का एक उदाहरण ग्रेट ब्रिटेन के इतिहास में भी मिलता है। द्वितीय विश्व महायुद्ध के बाद ब्रिटेन के नेताओं के बीच यह वैचारिक मंथन होने लगा कि ब्रिटेन अब भारत और उसके जैसे अन्य देशों पर शासन नहीं कर सकता और उसे अब इन देशों को स्वतंत्र कर देना चाहिए। यह सब जानते हैं कि विंस्टन चर्चिल द्वितीय महायुद्ध के हीरो के रूप में उभरकर सामने आए थे, पर वह 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हार गए थे जिसकी वजह थी ब्रिटेन की जनता में यह आम सोच पैदा हो गई थी कि अब उन्हें युद्ध के बाद सुधार की जरूरत है और जिस व्यक्ति ने ब्रिटेन का युद्ध में नेतृत्व किया हो वह उनके देश का नेतृत्व शांति के पथ पर नहीं कर सकता।

अब सवाल उठता है कि क्या इस कथ्य के मद्देनजर अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी मानसिकता में बदलाव ला पाएँगे, क्योंकि

उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान यह कहकर पूरे विश्व में एक हलचल पैदा कर दी थी कि अगर वह अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो वह सभी मुसलमानों के अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगा देंगे। इस बात का विश्व भर के मुस्लिम संगठनों और मानवाधिकार के लिए लड़ने वाली संस्थाओं ने कड़ा विरोध किया था, लेकिन ट्रंप अपनी बात से पीछे हटते न दिखे। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान ही यह बात स्पष्ट कर दी थी कि अमेरिका की सुरक्षा को लेकर वह किसी तरह का भी समझौता नहीं करने वाले हैं फिर चाहे उनके फैसले से खुश हो या नाराज।

आठ नवंबर, 2016 को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव होने के बाद 9 नवंबर, 2016 को जब चुनाव के नतीजे आए, तो उसने कई लोगों को चौंका दिया, क्योंकि अमेरिका ने ट्रंप को अगले राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया, लेकिन जीत के बाद नए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मैं अमेरिकी धरती के प्रत्येक नागरिक को भरोसा दिलाता हूँ कि मैं सब अमेरीकियों का राष्ट्रपति हूँ। वास्तव में किसी भी देश के विकास के लिए जरूरी है कि सबको साथ लेकर चला जाए, तभी उस देश का विकास संभव है।

सच कहा जाए, तो आज मुस्लिम समाज का एक बड़ा हिस्सा दुनिया भर में कट्टर मानसिकता का शिकार हो चुका है जिसकी वजह से ही डोनाल्ड ट्रंप को मुस्लिमों को अमेरिका में आने पर प्रतिबंधित करने जैसी बात कहने पर मजबूर किया। दुनिया में लगभग 50 मुस्लिम देश हैं, जिनमें से गिनती के कुछ देशों में प्रजातंत्र है। यही कारण है कि 19वीं और 20वीं सदी के अधिकांश मुस्लिम देश राजतंत्र केंद्रित रहा। वर्तमान दौर के लोकतंत्र में चुनाव जीतने का मतलब है देश के विकास के लिए काम करना, न कि किसी विशेष समुदाय का। समाज को अपना विकास स्वयं करना पड़ता है और उसकी जिम्मेदारी समाज के बुद्धिजीवियों के ऊपर होती है। इस दृष्टि से आज अगर राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को साथ लेकर चलने की बात की है, तो हम समझते हैं कि मुस्लिम समाज को भी अब एक वैचारिक पहल करनी चाहिए, ताकि निरंतर विरोध की नीति त्याग कर शांति और विकास के आसान रास्ते को अपनाएँ और विश्व विकास में अपना योगदान दें। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने पर डोनाल्ड ट्रंप को भी अपनी मानसिकता में बदलाव लाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर मुस्लिम समाज खुद को आगे लाने में अग्रसर नहीं होता है, तो संभव है कि नए राष्ट्रपति ट्रंप भी अपनी मानसिकता में बदलाव नहीं ला पाएँगे।

(124)प्रश्न: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत में किन-किन क्षेत्रों में आपको समानता नजर आती है?

उत्तर: हाँ, मुझे भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में कई क्षेत्रों में समानता नजर आती है। पहली बात तो यह कि दोनों की शख्सियत एक है और दोनों राष्ट्रवाद के सिद्धांत के नायक हैं, क्योंकि दोनों राष्ट्र की सुरक्षा पर कोई समझौता पसंद नहीं करते। आपने देखा कि चुनाव प्रचार के दौरान जिस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकियों, आतंकवादियों, अपराधियों या आपराधिक रिकार्ड वाले लोगों, गिरोहों के सदस्यों पर शिकंजा कसने की बात कही थी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही आतंकियों, अलगाववादियों और आपराधिक रिकार्डवाले लोगों को लगाम लगाने पर आमादा हैं जिसका नमूना सेना द्वारा आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक और कालेधन के खिलाफ पाँच सौ और एक हजार रुपए के नोटों का प्रचलन विगत आठ नवंबर, 2016 से बंद करने के उनके फैसले से मिलता है।

नरेन्द्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का मिजाज और अंदाज एक है। दोनों नेताओं का कहना है कि वर्तमान की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में वही सफलता दिलाएगी। दोनों का कहना है कि बीते हुए कल पर ध्यान देने से कुछ नहीं होगा और भविष्य तो आने वाला है। इसलिए सफलता के लिए वर्तमान समय को ही हमेशा तवज्जों देना चाहिए।

जिस प्रकार नरेन्द्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान वर्तमान के जरूरी मुद्‌दों को ही प्राथमिकता दी उसी प्रकार डोनाल्ड ट्रंप ने भी 8 नवंबर, 2016 को अमेरिका में हुए राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार के दौरान भी वर्तमान के जरूरी मुद्‌दों को ही प्राथमिकता दी। चुनावी सर्वेक्षण ट्रंप की हार की भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन फिर भी ट्रंप अपनी जीत के प्रति आश्वस्त थे। इसलिए उन्होंने इस तरह के सर्वेक्षणों तथा मीडिया की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

नरेन्द्र मोदी तथा डोनाल्ड ट्रंप दोनों नेताओं को हमेशा जुनूनी होने पर विश्वास है। जिस प्रकार नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय राजनीति में आने के पूर्व हमेशा गुजरात राज्य की राजनीति की और चौदह वर्षो तक वहाँ के मुख्यमंत्री रहे, मगर जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो वे वाराणसी से चुनाव लड़कर जीत गए और प्रधानमंत्री के पद को भी हासिल किया, क्योंकि उनमें जुनून था और

आज भी वह जुनून उनमें मौजूद है। इसी प्रकार डोनाल्ड ट्रंप भी राष्ट्रपति से पहले उन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन जब उनके मन में राष्ट्रपति बनने का ख्याल आया और जब रिपब्लिकन पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया, तबसे वह अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव को जीतने के लिए जुट गए। कुछ विवादित खुलासों की वजह से उनके पार्टी के भी लोग उनके विरोधी हो जाने के बाद भी ट्रंप पर कोई प्रभाव न पड़ा, क्योंकि उनका ध्यान अपने मिशन में सफल होने पर था। इसी प्रकार नरेन्द्र मोदी के भी विरोध में उनके अपने पार्टी के लोग भी कई थे, किंतु मोदी ने किसी की बात पर ध्यान न देकर अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं।

जिस प्रकार मोदी प्रधानमंत्री के पद पर रहकर अबतक कोई छुट्टी उन्होंने नहीं ली है, ट्रंप ने भी घोषणा की है कि राष्ट्रपति पद पर रहकर वह भी कभी छुट्टी नहीं लेंगे और कानून का पालन करने के ख्याल से वेतन के रूप में 4 लाख डॉलर न लेकर साल में मात्र एक डॉलर यानी 67 रुपए ही लेंगे। इस प्रकार इन दोनों नेताओं से कुछ सीखा जा सकता है।

नरेन्द्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के जुनून की वजह से ही एक ओर जहाँ अमेरिका के चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप के विरूद्ध हवा रहने के बावजूद राष्ट्रपति के लिए वे चुन लिए गए, वहीं दूसरी ओर 8 नवंबर, 2016 की आधी रात से पाँच सौ एवं एक हजार रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाने के कड़क फैसले के बाद राहुल गाँधी जैसे नेता को चार हजार रुपए की निकासी के लिए बैंक में चार करोड़ की गाड़ी से जाकर लाइन की कतार में लगना पड़ा। कहा जाता है कि जिस प्रकार कभी चाय बेचने वाला ग्राहकों द्वारा विशेष तौर पर माँगे जाने पर कड़क चाय बनानी पड़ती थी उसी प्रकार 2014 के लोक सभा चुनाव के दौरान देशवासियों के समक्ष भ्रष्टाचार मिटाने के दावे को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री के गद्दी पर बैठे नरेन्द्र मोदी को कड़क चाय की तरह पाँच सौ और एक हजार रुपए के नोटों को अचानक प्रचलन से बाहर करने का कड़क फैसला लेना पड़ा। इसी को जुनून कहा जाता है जो अपने-अपने देश के दो बड़े-बड़े नेताओं की शख्सियत के पोर-पोर में समान रूप से मुझे नजर आते हैं। पाँच सौ और हजार रुपए के पुराने नोटों को हटाकर पाँच सौ और दो हजार रुपए के नए नोटों का जारी होना भारत में कागजी मुद्रा के ढाई सदियों के इतिहास का नवीनतम इतिहास है।

आखिर तभी तो नवंबर, 2016 के दूसरे सप्ताह की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में रेलपुल के शिलान्यास के वक्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र

मोदी के मुँह से ऐसा चमकदार वाक्य निकला कि 'गरीब चैन की नींद सो रहा है, कालेधन वाले नींद की गोलियाँ खरीद रहे हैं।' किसी शासन में गरीब चैन की नींद सोए और भ्रष्ट कमाई के बूते अमीर बने लोग नींद की गोलियाँ खरीदने को मजबूर हो जाएँ, तो माना जाएगा कि शीर्ष के पद पर बैठे हुए आदमी में एक ऐसा जुनून है जिसके राजकाज के कड़क फैसलों में आर्थिक न्याय का सवाल प्रधान रहा है। इस कठोर निर्णय के कुछ दिनों तक तो आमजन को परेशानी होगी, पर लंबी अवधि के हिसाब से यह गेम चेंजर फैसला साबित होगा, जो देश को एशिया ही नहीं विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था में शुमार कर सकता है। ठीक वैसे ही हमारी नजरों में अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल में पहले जैसा नहीं रहेगा अमेरिका। इस मामले में अमेरिका हमेशा से बेहतर कहानियोंवाला देश रहा है जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे पुराना लोकतंत्र है। साथ ही जो आप्रवासियों के लिए स्वर्ग और अमेरिकी सपने की भूमि रहा है।

ऐसी स्थिति में अब जब अमेरिका की अगुआई भी एक स्पष्ट वक्ता नेतृत्व के हाथों आई है और भारत की अगुआई भी विगत ढाई साल से एक सफल नेतृत्व के हाथ में है, तो यह आस बाँधना लाजिमी है कि विश्व में जिहादी आतंकवाद और उसके समर्थकों से लड़ने के लिए दो बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियाँ अवश्य एकजुट होंगी। वैसे भी ट्रंप पाकिस्तान के घोर विरोधी हैं। इस्लामिक स्टेट, तालिबान, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को जड़ से समाप्त करना ट्रंप चाहते हैं।

(125)प्रश्नः ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनने के बाद थेरेसा मे पहली बार ब्रिटेन से बाहर भारत की तीन दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से हुई बातचीत में क्या दोनों देशों के रिश्तों को नया आयाम देने पर चर्चा हुई?

उत्तरः ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार ब्रिटेन से बाहर भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर निकली थेरेसा मे से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से हुई बातचीत में दोनों देशों के रिश्तों को नया आयाम मिलने की आशा जगी है। सबसे बड़ी बात तो यह कि दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत के बाद ब्रिटेन और भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग का स्थाई ढाँचा तैयार करने पर सहमत हो गए हैं। इस बातचीत में इस बात की भी सहमति बनी कि वांछित अपराधियों का प्रत्यर्पण जल्द से जल्द होना चाहिए। इस दौरान दोनों देशों के बीच करीब 83 सौ करोड़ रुपए के सौदे होंगे। प्रधानमंत्री

थेरेसा मे ने कहा कि वे दोनों अपने नागरिकों की आजीविका में सुधार, रोजगार सृजन, कौशल विकास, बुनियादी ढाँचे में निवेश तथा भावी की प्रौद्योगीकियों के समर्थन की दिशा में काम करेंगे।

इस समय भारत दुनिया के उन चंद देशों में है, जहाँ आर्थिक विकास दर काफी अच्छी चल रही है और यह रूझान अगले काफी समय तक बने रहने की संभावना है। ऐसे में, ब्रिटेन के लिए जरूरी है कि वह भारत के साथ आर्थिक साझेदारी करे और उसकी विकास दर में योगदान करते हुए अपने आर्थिक सुधार को पुख्ता करे, खासकर तब जब ब्रिटेन को दो साल में यह साबित करना है कि यूरोपीय संघ से अलग होने का फैसला महज क्षणिक और भावुकता भरा नहीं था। ऐसे में, भारत के लिए ब्रिटेन के साथ अपने रिश्तों को नए समीकरण में ढालना जरूरी हो गया है। प्रधानमंत्री थेरेसा मे का यह दौरा उसे इसका अवसर दे रहा है।

(126)प्रश्न: रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वैश्विक घटनाक्रम पर खासतौर पर भारत के साथ और मुस्लिमों को लेकर क्या अमेरिका का नजरिया बदल सकता है?

उत्तर: राजनीति में कब क्या हो जाए इसका अंदाजा लगाना वाकई में काफी मुश्किल होता है। आप अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव को ही ले लीजिए, आज से साल भर पहले शायद किसी ने कहीं सोचा होगा कि एक रियल स्टेट व्यवसायी महज कुछ महीनों की ताबड़तोड़ प्रचार-प्रसार के जरिए अमेरिकी सत्ता के शिखर को हासिल कर लेगा? और तो और उसकी टक्कर भी एक ऐसी नेता से थी जो 48 साल से सक्रिय राजनीति का हिस्सा थी और अमेरिका की प्रथम महिला, पूर्व विदेश मंत्री और वर्तमान चुनाव में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन। मगर इन सब के इतर डोनाल्ड ट्रंप ने वो करिश्मा कर दिखाया जो राजनीतिक गलियारों में लगभग असंभव था।

अंतत: अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंद्वी डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को कड़े मुकाबले में 58 मतों के अंतर से शिकस्त देकर जीत दर्ज की। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बन गए हैं। ट्रंप को 276 मत मिले जबकि हिलेरी को 218 मतों से ही संतोष करना पड़ा। 2001 में 9/11 के विश्व व्यापार केंद्र के हमले ने अमेरिका को चौकाया था। अब 15 साल बाद 11 नवंबर, 2016 को अमेरिका ने पूरी दुनिया को चौका दिया, क्योंकि सारे सर्वे-अनुमान

धरे-के-धरे रह गए। 6 जनवरी, 2017 को अमेरिकी काँग्रेस का संयुक्त सत्र में इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की गिनती के बाद जीत की औपचारिक घोषणा हुई और 20 जनवरी, 2017 को शपथ ग्रहण समारोह में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के पद की गोपनीयता की शपथ ली।

जहाँ तक नए राष्ट्रपति के चुने जाने के बाद वैश्विक घटनाक्रम पर अमेरिका के नजरिए में बदलाव का सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद जनता को संबोधित करते हुए वचन दिया है कि वे अमेरिका की अर्थव्यवस्था दोगुना करने के लिए सभी देशों से दोस्ती रखेंगे, सभी देशों से अच्छे संबंध होंगे और अमेरिका का पुनिर्माण ही उनका लक्ष्य होगा। इसके मद्देनजर आर्थिक-सामाजिक स्तर पर तो बदलाव होगा ही, मस्जिदों पर निगरानी, आईएस जैसे आतंकी संगठनों पर बमबारी, अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए अमेरिका-मैक्सिको के बीच दीवार खड़ी करना भी ट्रंप का कार्यक्रम रहा है। वे मुस्लिम देशों और चीन के प्रति सख्त रूख अपना सकते हैं और अपने उन्मादी रवैए से ट्रंप दुनिया को एक बार फिर शीत युद्ध काल में ले जा सकते हैं। सामरिक रूप से भारत को फायदा होगा, क्योंकि वे आतंकवाद, पाक व चीन के खिलाफ काफी बोल चुके हैं। पाक प्रायोजित आतंक के खिलाफ भारत-अमेरिका संयुक्त योजना बना सकते हैं, क्योंकि ट्रंप को विजयश्री दिलाने में अमेरिका में बसे भारतीय मूल के लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चुनाव में भारतीय मूल की प्रमिला जायसवाल, कमला हैरिस, राजाकृष्ण मूर्ति तथा ए. खन्ना भी अमेरिकी संसद के लिए चुने गए हैं। इसे देखते हुए अमेरिका कभी भी भारत को अनदेखा नहीं कर सकता। वैसे भी भारत एक बड़ा मार्केट है। भारत में काफी संख्या में अँग्रेजी बोलने वाले, तकनीकी रूप से सक्षम, सस्ता श्रम-इन सबका लाभ अमेरिका को मिलेगा। दोनों के बीच सौ बिलियन डॉलर का व्यापार है। अमेरिका के आईटी क्षेत्र में भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। चीन को लेकर अमेरिका के मतभेद के चलते भी अमेरिका को भारत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के साथ है।

मुस्लिमों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के नजरिए का जहाँ तक सवाल है चुनाव प्रचार के दौरान 'कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादी' पर उनके कड़े रूख तथा मुसलमानों का आव्रजन रोकने के उनके आह्वान ने मुस्लिम जगत में चिंता पैदा कर दी थी। चुनाव के दौरान ट्रंप ने अमेरिका में रहने वाले लाखों अपराधियों को निकालने और अमेरिका में मुसलमानों के आने पर प्रतिबंध

लगाने की बात की थी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ अमेरिका के बेहतर रिश्ते ट्रंप चाहेंगे। ट्रंप ने तो बमबारी कर इस्लामिक स्टेट को नरक बना देने और उसके चरमपंथियों की तेल के कुँओं के पहुँच नहीं रहने देने की बात प्रचार के दौरान की थी।

(127)प्रश्नः क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप की जीत राष्ट्रवाद की जीत है?

उत्तरः हाँ, मैं भी ऐसा मानता हूँ कि अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप की जीत राष्ट्रवाद की जीत है, क्योंकि हर देश के नागरिकों को अपने देश की सुरक्षा और भविष्य की चिंता होती है। इस्लामिक स्टेट ने तो ट्रंप को वोट देने वालों को मौत की नींद सुला देने की धमकी दे रखी थी। कुछ भारतीय बुद्धिजीवी भी ट्रंप के संबंध में अपमान करने वाले लेख लिखते थे और चैनलों पर बैठकर रिपब्लिकन पार्टी की हिलेरी क्लिंटन की जीत की घोषणा कर रखी थी। इस मायने में देखा जाए, तो डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा इस बात के लिए होनी चाहिए कि उन्होंने मुस्लिम वोट की परवाह नहीं की। उन्होंने उन सभी लोगों को खारिज किया जो उनकी राजनीतिक संस्कृति के विरोधी थे और उनपर हँसा करते थे।

दरअसल, मुस्लिम वोटरों को जीत की गारंटी मान ली जाती है। यह माना गया था कि बिना मुस्लिम समर्थन का कोई चुनाव जीत ही नहीं सकता है। इस खुशफहमी और तथ्यहीन हथकंडे को भारत में 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेन्द्र मोदी ने तोड़ा था। आज भी राज्यों में विधानसभा के आसन्न चुनाव के लिए तथाकथित समाजवादी कहे जाने वाले राजनेता मुस्लिम वोटों को हथकंडा बनाकर चुनाव जीतना चाह रहे हैं। इन्हें तो डोनाल्ड ट्रंप और नरेन्द्र मोदी से सीख लेनी चाहिए कि अमेरिका और भारत में राष्ट्रवाद के प्रवाह के चलते क्रमशः डोनाल्ड ट्रंप और नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने।

(128)प्रश्नः क्या पिछले दिनों भारत-जापान के बीच हुआ ऐतिहासिक नागरिक परमाणु समझौता पर हस्ताक्षर मील का पत्थर साबित होगा?

उत्तरः हाँ, पिछले दिनों 10 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तीन दिवसीय जापान यात्रा के दौरान भारत-जापान के बीच हुआ ऐतिहासिक नागरिक परमाणु समझौता पर हस्ताक्षर दोनों देशों की गहरी दोस्ती

में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि दोनों देशों की इस साझेदारी से पूरे महाद्वीप में शांति और स्थिरता आएगी। आतंकवाद से निबटने के लिए दोनों देश एकजुट प्रयास करेंगे और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने को लेकर भी एक साथ हैं। इस समझौते से विश्व पटल पर एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति संपन्न देश होने का भारत का दावा मजबूत हुआ है। वैसे भी जापान परमाणु हमले का शिकार होने वाला दुनिया का अकेला देश है, जिसकी परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उद्येश्यों को लेकर प्रतिबद्धता जगजाहिर है।

इस समझौते से जापान और भारत की इंडस्ट्रीज के बीच परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग का रास्ता खुल गया है। साथ ही यह समझौता क्लीन एनर्जी की दिशा में उपयोगी होगा। अपनी तेजी से बढ़ रही उर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत पर दबाव है, जिसके लिए उसे विभिन्न विकल्प अपनाने होंगे। इस दृष्टि से जापान के साथ यह नागरिक परमाणु समझौता उस दिशा में आगे बढ़ने में मददगार साबित होगा। इसके अलावा हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है। जापानी निवेशकों के लिए भी दुनिया की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के विकास में भागीदारी का अवसर है।

(129)प्रश्नः क्या आपको ऐसा लगता है कि चीन के बढ़ते असर को रोकने के लिए चीनी सामानों के बहिष्कार के बाद 'मेड इन जापान' से जवाब देने की तैयारी कारगर सिद्ध होगी?

उत्तरः हाँ, नरेन्द्र जी, जब चीन में निर्मित सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है, फिर भी चीन का बढ़ता असर कम नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में चीन में बढ़ते असर को रोकने का हमारे पास 'मेड इन जापान' से जवाब देने की तैयारी तो करनी ही होगी। दरअसल, करीब 5 दशक तक जापान ने मिलिट्री साजो-सामान के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन चीनी सामानों के बहिष्कार के बाद अब चीन को 'मेड इन जापान' से घेरने की रणनीति पर केंद्र की मोदी सरकार काम कर रही है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जापान के दौरे पर जा रहे हैं जिसमें भारत सरकार जापान से 10 हजार करोड़ के 12 एम्फीबियन प्लेन यूएस-2आई खरीद पर हस्ताक्षर होने की संभावनाएँ जताई जा रही हैं। ये ऐसे विमान हैं जो हवा के साथ-साथ पानी पर भी चल सकते हैं। एयरक्राफ्ट की ये डील ज्यादा पैसों के चलते 2013

से अटकी हुई है जिसे देखते हुए जापान ने 720 करोड़ रुपए कम कर दिए हैं। नरेन्द्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिंजों आबे के बीच सिविल न्यूक्लियर को-ऑपरेशन एग्रीमेंट पर चर्चा अहम रहेगी। चार टर्बो-इंजनवाला यूएस-2आई का इस्तेमाल रेस्क्यू ऑपरेशन में भी किया जाएगा। साथ ही इस विमान से किसी इमरजेंसी के दौरान 30 जवानों को घटनास्थल पर ले जाया जा सकेगा। जापान और भारत दोनों ही देश चीन के बढ़ते असर से चिंतित हैं। ऐसे में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक नई ताकत बनाना है। जापान और भारत नवम्बर, 2016 के दूसरे सप्ताह में एक विवादास्पद नागरिक परमाणु करार पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। इसके पीछे आर्थिक व सुरक्षा संबंधी आपसी सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ दोनों देशों का मकसद क्षत्रीय व वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन के बढ़ते प्रभाव का जवाब तलाशना है। यह करार परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी की सदस्यता पाने की भारतीय दावे को भी मजबूती देगा।

(130)प्रश्नःदुबई में पहली बार 18 महिलाओं को स्पेशल गार्ड यूनिट में शामिल किया गया है। क्या आप इसे स्त्री सशक्तीकरण की दिशा में बढ़ता कदम मानेंगे?

उत्तर: निश्चित रूप से दुबई में पहली बार 18 महिलाओं को स्पेशल गार्ड यूनिट में शामिल किए जाने को स्त्री सशक्तीकरण की दिशा में बढ़ता कदम मैं मानता हूँ, क्योंकि जिन खाड़ी के देशों में महिलाओं को गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं दी जाती रही है, उन्हें अकेले बाजार में नहीं जाने दिया जाता था और न ही वे पुलिस में भर्ती हो सकती थीं, यहाँ तक कि महिलाएँ हिजाब या बुर्के में ही घर से बाहर निकलती हैं ऐसी विपरीत स्थिति में भी दुबई में 18 महिलाओं का स्पेशल गार्ड यूनिट में शामिल किया गया है, तो स्त्री सशक्तीकरण की ओर एक कदम बढ़ना माना जाएगा। दुबई पुलिस में इसी साल महिलाओं के लिए स्पेशल यूनिट बनाई गई है। इनका काम महिला बिजनेसमैन, रॉयल फेमिली की महिला सदस्यों और विदेश से आने वाली महिला नेताओं को सुरक्षा मुहैया कराना है। दुबई में अबतक स्पेशल यूनिटों में भी सिर्फ पुरुष ही होते थे। मगर ये महिला पुलिसकर्मी जब लेम्बोरगिनी, फरारी और रेसिंग बाइक्स पर दुबई की सड़कों पर निकलती हैं तो लोग इन्हें देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। कई बार तो सड़कों पर जाम लग जाता है।

स्पेशल यूनिट में शामिल आयशा उबैद के मुताबिक कठिन ट्रेनिंग और काम ने उन्हें अपने डर पर जीत पाने में मदद की है। उन्होंने मुश्किलों

का मुकाबला करने की कला सीख ली है। लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उनकी ट्रेनिंग किस लेवल की होती है। अपने परिवार के साथ कई बार अहम मौकों पर वह मौजूद नहीं रह पाती हैं। इसके बावजूद वह परिवारवालों की आँखों में अपने लिए फख्र देखती हैं जो उन्हें प्रोत्साहित करता है।

(131)प्रश्नः सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना की ओर से रह-रहकर की जा रही गोलीबारी से क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि भारत को पाकिस्तान से निपटने के मामले में किसी नई रणनीति पर विचार करने की जरूरत है?

उत्तरः हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तानी सेना की ओर से रह-रहकर की जा रही गोलीबारी में जवानों के साथ आम नागरिकों के मारे जाने पर मैं भी यह महसूस करता हूँ कि भारत को पाकिस्तान से निपटने के मामले में किसी नई रणनीति पर विचार करने की जरूरत है। यह ठीक है कि पाकिस्तान को मुँहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और जवाबी कार्रवाई में उसे क्षति भी उठानी पड़ रही है, लेकिन जरूरत तो ऐसे कदम उठाने की है जो उसके लिए सबक बन सके और वह पागलपन से बाज आए। सीमा पर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना होगा जिससे पाकिस्तानी सेना संघर्ष विराम का उल्लंघन करने के बावजूद भारत को किसी तरह की क्षति न पहुँचा सके और आतंकी भी भारतीय सीमा में घूसपैठ न कर सकें।

इस भरोसे बिल्कुल ही नहीं रहा जा सकता है कि एक न एक दिन पाकिस्तान को समझ आएगी और वह अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा। आपको याद होगा कि तीन दशक से अधिक का वक्त बीत गया और हालात जस के तस हैं। कायदे से इतने लंबे दौर में ऐसे ठोस उपाय कर लिए जाने चाहिए थे जिससे पाकिस्तान जब-तब गोलीबारी करके सिरदर्द नहीं साबित होता। कम से कम अब तो ऐसे उपायों पर प्राथमिकता के आधार पर अमल होना ही चाहिए, इसलिए और भी, क्योंकि लक्षित हमले (सर्जिकल स्ट्राइक) के मनमाफिक नतीजे सामने आते नहीं दिख रहे। इसके अतिरिक्त तथ्य यह भी है कि जम्मू-कश्मीर के अंदरूनी हालात भी सुधरने का नाम नहीं ले पा रहे हैं। हड़ताल और पत्थरबाजी से हलकान घाटी में अब स्कूलों को जलाने का सिलसिला तेज हो रहा है। स्पष्ट है कि जम्मू-कश्मीर में सीमा पर और उस सीमा के अंदर दोनों स्थानों पर सख्ती एवं सतकर्ता बरती जानी चाहिए।

हमारे नीति-नियंताओं को समझना होगा कि जितनी जरूरत इसकी

है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग-थलग किया जाए उतनी ही इसकी भी कि उसे सीमा पर उत्पात मचाने और साथ ही कश्मीर में हस्तक्षेप करने से रोका जाए। पाकिस्तान की हरकतें बता रही हैं कि उसे मुगालता है कि वह आतंक, उपद्रव के जरिए भारत को झुकने के लिए विवश कर सकता है। उसके इस मुगालते को दूर करने के लिए कुछ नए कदम उठाने ही होंगे और कुछ नई रणनीति बनाने पर विचार करना ही होगा।

भारत को अब पुरानी कूटनीति का परित्याग कर नई आक्रामक कूटनीति का अनुसरण करना होगा।

(132) प्रश्न: पाकिस्तान ने 26 दिसंबर, 2016 को दो सौ बीस भारतीय मछुआरों को रिहा करने की घोषणा की, जो उसके यहाँ समुद्री सीमा के उल्लंघन के आरोप में बंद थे। पाकिस्तान के इस अप्रत्याशित कदम से क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब कूटनीतिक जरूरत महसूस होती है, तब बंदी मछुआरों में से कुछ को रिहा कर दिया जाता है और बदले में दूसरी तरफ से भी आंशिक कदम उठाया जाता है?

उत्तर: हाँ, समुद्री सीमा के उल्लंघन के आरोप में पाक के जेलों में बंद 220 भारतीय मछुआरों को दिसंबर, 2016 के आखिरी सप्ताह में रिहा करने की अप्रत्याशित घोषणा से मुझे भी लगता है कि जब कूटनीतिक जरूरत महसूस होती है तब बंदी मछुआरों में से कुछ को रिहा कर दिया जाता है और बदले में दूसरी तरफ से भी आंशिक कदम उठाया जाता है। पाक का यह कदम निश्चित रूप से अप्रत्याशित है, लेकिन मेरे ख्याल से स्वागत योग्य भी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में उतार-चढ़ाव हमेशा चलता रहा है और कई बार खटास काफी बढ़ जाती है। मसलन पठानकोट और फिर उड़ी में हुए आतंकी हमलों के बाद से दोनों देशों के बीच लगातार तीखी तकरार बनी रहती है। इसलिए भारतीय मछुआरों की रिहाई बहुतों को थोड़ी चौकाने वाली घटना लगेगी।

तो क्या भारतीय मछुआरों को जेल से रिहा करके पाकिस्तान ने इसके जरिए भारत से बातचीत के बंद दरवाजे खोलने की इच्छा जताई है? यह सवाल स्वाभाविक रूप से हमारे आपके दिमाग में आया है। इसमें दो राय नहीं कि यह सद्भावना कूटनीतिक है।

अगर भारत भी जवाब में वैसा ही कदम उठाता है, तो इस तरफ से भी वैसा ही संदेश जाएगा अगर सौहार्द भरा प्रत्युत्तर मिला, तो और कैदियों

की भी रिहाई हो सकती है, लेकिन सवाल है कि दोनों तरफ से मछुआरों को अपनी रिहाई के लिए कूटनीतिक पहल का इंतजार क्यों करना पड़े? क्या वे कूटनीति के मोहरे भर हैं? हर साल दोनों तरफ के सैकड़ों मछुआरे अपनी आजीविका के क्रम में मछली पकड़ने के दौरान जाने-अनजाने समुद्री सीमा पार कर जाते हैं। फिर वे जेल में सड़ते रहते हैं। यह दोनों तरफ होता है। अक्सर दूतावास भी उनकी सुध नहीं लेते, न उन्हें कोई कानूनी मदद मिल पाती है।

विडंबना यह है कि दोनों देशों के बीच समय-समय पर हुई वार्ताओं के कार्यक्रम में कैदियों के मसले को कभी प्रमुखता नहीं मिली। जबकि इसे सबसे पहले सुलझाने की पहल होनी चाहिए, क्योंकि यह एक मानवीय मसला है और दूसरे देश के कैदियों से कैसा बर्ताव किया जाए इस बारे में अंतरराष्ट्रीय कायदे भी हैं। आपको याद होगा 1997 में दोनों तरफ के प्रधानमंत्रियों ने सार्क शिखर सम्मेलन के मौके पर आश्वस्त किया था कि जाने-अनजाने समुद्री सीमा लांघ जाने वाले मछुआरों को शीघ्र स्वदेश भेजने का प्रबंध और तौर-तरीका तय किया जाएगा, लेकिन वह आश्वासन कभी मूर्त रूप नहीं ले पाया। हाँ, जब कूटनीतिक जरूरत महसूस होती है तो बंदी मछुआरों में से कुछ को रिहा कर दिया जाता है और बदले में दूसरी तरफ से भी वैसा ही आंशिक कदम उठाया जाता है। जबकि आपसी रिश्तों के उतार-चढ़ाव से परे जाकर, इस मसले का स्थायी समाधान निकालना आवश्यक है।

(133)प्रश्नः क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यदि अमेरिका और रूस परमाणु शक्ति के मामले में संतुलन और संयम बरकरार नहीं रख पाए, तो यह दुनिया की सेहत के लिए बेहद खतरनाक बात होगी? आखिर कैसे?

उत्तरः हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि यदि अमेरिका और रूस परमाणु शक्ति के मामले में संतुलन और संयम बरकरार नहीं रख पाए, तो यह दुनिया की सेहत के लिए बेहद खतरनाक बात होगी, क्योंकि पूरी दुनिया में इन्हीं दो देशों के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। जब भी परमाणु हथियारों की होड़ में कमी लाए जाने की बात होती है, तो दुनिया की निगाहें सबसे पहले इन्हीं दो महाशक्तियों-अमेरिका और रूस पर जा टिकती हैं। दोनों देश अपने देश की सैन्य गतिविधियों का जायजा लेने के बाद अपनी रणनीतिक क्षमता बढ़ाने पर जोर दिए हैं। रक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि दोनों देशों की नीति में अहम बदलाव के संकेत हैं और इससे परमाणु हथियारों की होड़

रोकने की वैश्विक कोशिशों को धक्का लग सकता है। यही नहीं, अमेरिका और रूस के बीच पहले जो प्रमुख हथियार नियंत्रण संधि कायम है, उसे टूटने का खतरा भी पैदा हो सकता है। ऐसा हुआ हो तो खतरे की जद में पूरी दुनिया होगी।

वैसे भी उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, भारत, पाक, चीन, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के देशों के बीच परमाणु शक्ति के विस्तार को लेकर जिस प्रकार तनावपूर्ण स्थितियाँ हैं, उसपर दुनिया भर में चिंताएँ जाहिर की जाती रही हैं। ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका और रूस परमाणु शक्ति पर संतुलन और संयम नहीं बरत पाएँ, तो यह दुनिया की सेहत के लिए बेहद खतरनाक बात होगी।

(134)प्रश्नः 20 जनवरी, 2017 से व्हाइट हाउस से विदा होने वाले अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने विगत 23 दिसंबर, 2016 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकरण कानून पर हस्ताक्षर कर क्या एक ओर जहाँ भारत का रूतबा बढ़ाया है, वहीं दूसरी ओर पाक के पर क़तरे? आखिर कैसे?

उत्तरः हाँ, 20 जनवरी, 2017 से व्हाइट हाउस से विदा हो रहे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने विगत 23 दिसंबर 2016 को राष्ट्रीय रक्षा अधिकरण कानून पर अपने हस्ताक्षर कर एक ओर जहाँ भारत का रूतबा बढ़ाया है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के पर भी कतरे, क्योंकि इससे अमेरिका और भारत के बीच रक्षा सहयोग बढ़ेगा और दोनों देशों की एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय रक्षा क्षेत्र से जुड़े अधिग्रहण, तकनीक को मजबूत और सुनिश्चित करने के लिए अलग से शीर्ष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इससे दोनों देशों के बीच लंबित मसलों को हल करने, सुरक्षा सहयोग बढ़ाने और साझा उत्पादन के मौके बढ़ाने में मदद मिलेगी। दूसरी ओर पाकिस्तान को तभी वित्तीय मदद मिलेगी जब वह हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई का सुबूत देगा। पाक को अमेरीका से मदद मिलने वाली 90 करोड़ डॉलर में से 40 करोड़ डॉलर पाने के लिए उसे चार शर्तें पूरी करनी होगी, जो आसान नहीं है। अमरीकी रक्षा मंत्री को काँग्रेस में यह प्रमाणित करना होगा कि पाक हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। उल्लेख्य है कि वर्ष 2016 में अमरीकी रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर ने पाकिस्तान को यह प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया था कि वह हक्कानी नेटवर्क के

खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान गठबंधन मदद कोष (सीएसएफ) से 30 करोड़ डॉलर की मदद मिल पाई थी।

इन तथ्यों के आलोक में कहा जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने पद छोड़ने के पूर्व राष्ट्रीय रक्षा अधिनियम कानून पर हस्ताक्षर कर भारत के रूतबे को जहाँ बढ़ाया है, वहीं पाकिस्तान को मदद करने के मामले में कई तरह की शर्तें लगाकर उसके पर कतरे हैं।

(135)प्रश्नःतमाम टकराव और भटकाव के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि नेपाल की राजनीति में पहली बार मधेशियों को उनका वाजिब हक देने पर सहमति बनती दिख रही है? आखिर कैसे?

उत्तर: भाई रामविलास जी, पहली बात तो यह कि आप नेपाली भाषा जानते हैं और नेपाल से सटे इलाके में आप रहते भी है इसलिए मधेशियों की स्थिति से आप निश्चित रूप से परिचत होंगे। फिर भी तमाम टकराव और भटकाव के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि नेपाल की राजनीति में पहली बार मधेशियों को उनका वाजिब हक देने पर सहमति बनती दिख रही है, क्योंकि नेपाल में सत्ता के गलियारे का मन-मिजाज बदला है। मूल के आधार पर भेदभाव और टकराव की राजनीति से बाहर आकर आपसी सहमति और विश्वास के पथ पर कदम बढ़े हैं। नागरिकता, समान अधिकार, संसद में प्रतिनिधित्व और राज्यों के गठन जैसे विवादित मुद्दे को सुलझाने और भारत से संबंध मजबूत करने की इच्छाशक्ति अरसे बाद नजर आ रही है। दूसरी पारी में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल 'प्रचंड' के नए अवतार और उन्हें नेपाली काँग्रेस का साथ मिलने की वजह से ही ऐसा संभव हुआ है। हालांकि राह अब भी आसान नहीं है।

मधेशियों, थारूओं, दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं का दिल जीतने के लिए प्रचंड सरकार द्वारा लाए गए संविधान संशोधन प्रस्तावों को कड़े विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। भारत विरोध की धुरी पर खड़ी एकीकृत माओवादी-लेनिनवादी (एमाले) ने आठ छोटे दलों का मोर्चा बनाकर संशोधन प्रस्तावों को चुनौती दी है। प्रचंड सरकार को बहुमत तो है, लेकिन संशोधन प्रस्तावों को पारित कराने के लिए अपेक्षित दो-तिहाई बहुमत नहीं है।

नेपाल के नए संविधान के अनेक प्रावधानों पर वहाँ के मधेशी और जनजातीय समुदाय को सख्त एतराज था। संविधान में देश को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया, लेकिन राज्यों को अधिकार नहीं दिए

गए। जो सात प्रदेश बनाए गए उनके सीमांकन से भी इन दोनों समुदाय में बेहद नाराजगी रही है।

मधेश में दो राज्य बनाने की बात थी, पर भारत की सीमा से एक कड़ी में लगे आठ जिलों का एक प्रदेश बनाया गया। बाकी जिलों को छह भाग में बाँटकर पहाड़ी राज्यों में शामिल कर दिया गया जिसके परणिामस्वरूप मधेशी अल्पसंख्यक बने रहेंगे। जनजाति बहुल थरूहट को अलग राज्य नहीं बनाया गया। नेपाल के 17 प्रतिशत क्षेत्रफल में करीब 50 प्रतिशत मधेसी आबादी बसती है। बाकी पहाड़ी इलाके हैं। जाहिर है क्षेत्रफल के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र बनते तो संसद में मधेसियों का प्रतिनिधित्व सिमट जाता।

बीते दो दशक में नेपाल की राजनीति में भारत विरोध और मधेस के हितों को भारत से जोड़कर नकराने की प्रवृत्ति एक फैशन की तरह बन गई है। अनेक नेताओं और दलों की राजनीति इसी वैशाखी पर टिकी है, इसलिए वह सत्ता के इस नए मिजाज को सहज स्वीकार नहीं करेंगे। नेपाल सरकार के पास बहुत समय भी नहीं है।

(136)प्रश्न: आतंकी हमलों के सिलसिले को बंद करने के लिए क्या पाकिस्तान को नया सबक सिखाने की जरूरत आप महसूस करते हैं?

उत्तर: हाँ, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि आतंकी हमलों के सिलसिले को बंद करने के लिए पाकिस्तान को नया सबक सिखाने की जरूरत है, क्योंकि जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमलों का क्रम जारी है। पांपोर तथा जम्मू-कश्मीर की सीमा पर अथवा सीमा के अंदर हमारे सैनिकों को लगातार शहादत का सामना करना पड़ रहा है। नोटबंदी के बाद जम्मू-कश्मीर में युवा आतंकियों द्वारा की जा रही पत्थरबाजी तो बंद हो गई, मगर सीमा पार के घुसपैठियों का सिलसिला अभी जारी है। शांतिकाल में सैनिकों की शहादत के ऐसे सिलसिले को सहन नहीं किया जा सकता।

माना गया था कि उड़ी में आतंकी हमले के बाद पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा, पर ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। पांपोर के पहले नगरोटा में सेना के शिविर पर हुआ हमला तो यही बात रहा था कि हालात करीब-करीब पहले की तरह है। दरअसल, पाकिस्तान वह बर्बर शत्रु है जिसने पाशविकता की कोई भी हद लांघने में न तो पहले कोई हिचक दिखाई है और न ही भविष्य में दिखाने की उम्मीद है। हमें

अपनी रक्षा नीतियाँ इस कड़वे सच को ध्यान में रखकर ही बनानी होगी।

सच तो यह है कि पाकिस्तान में कट्टरपंथी मदरसों और आतंकी संगठनों का मकड़जाल वहाँ तिलचट्टों की तरह आतंकी पैदा कर रहा है। चूँकि उसने छद्मयुद्ध हम पर थोपा है, इसलिए हम उसे उस ओर घसीटें जहाँ वह संघर्ष की कीमत बर्दाश्त नहीं कर पाए। ऐसे विकल्पों पर अमल करके ही पाकिस्तान को यह जरूरी सबके सिखाने की जरूरत है, ताकि भारत अपने सैनिकों की शहादत के सिलसिले को बर्दाश्त न कर सके।

(137)प्रश्न:पश्चिमी पाकिस्तान में शरणार्थियों के मामले में केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने उनकी सुधि क्यों नहीं ली?

उत्तर:पश्चिमी पाकिस्तान से आए 70-80 लाख आबादीवाले शरणार्थियों की केंद्र या राज्य सरकारों ने इसलिए सुधि नहीं ली, क्योंकि ये शरणार्थी वोट बैंक नहीं बन सके। यह शर्मनाक है कि जिन शरणार्थियों की सुधि बहुत पहले ली जानी चाहिए थी उनकी हर स्तर पर उपेक्षा की गई। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पश्चिमी पाकिस्तान से आए लोग बीते सात दशक से शरणार्थी रूप में तमाम तरह की कठिनाइयों से दो-चार होते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनकी समस्याएँ इसलिए बढ़ गई हैं, क्योंकि उनके पास अपनी नागरिकता को साबित करने वाला कोई पहचान या प्रमाण पत्र नहीं। इसके अभाव में उनके बच्चों को न तो सरकारी नौकरियाँ मिल सकीं और न ही वे वोटर बन सके। क्या यह मान लिया जाए कि इस रवैए का कारण यह है कि पश्चिमी पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को पहचान पत्र देने का फैसला भाजपा के नेतृत्ववाली केंद्र सरकार ने किया है? मुझे आश्चर्य तो तब होता है कि जम्मू में म्यांमार से आए रोहिंड्या मुसलमानों को जम्मू और आसपास के इलाकों में बसाया गया और कश्मीर के नेताओं को उनकी बसावट से कोई एतराज नहीं हुआ तो फिर वे शरणार्थी जो पश्चिमी पाकिस्तान से आए तो उनका विरोध कैसे कर सकते हैं जो पिछले सत्तर सालों से यहीं रह रहे हैं। इसका मतलब है कि कश्मीरियत की बात करने वाले घोर साम्प्रदायिता से ग्रस्त हो चुके हैं। ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। यदि कश्मीरियत इंसानियम का परिचय देने से इनकार करती है, तब फिर उसका गुणगान करने का कोई मतलब नहीं।

(138)प्रश्न: क्या आपको ऐसा लगता है कि संयुक्त राष्ट्र के नए महासचिव एंटोनिया गुटेरस के आने से संयुक्त राष्ट्र चुस्त, दक्ष और प्रभावी बन सकेगा?

उत्तर: विगत 12 दिसंबर, 2016 को 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र के विशेष सत्र में इस विश्व निकाय की महासभा के अध्यक्ष पीटर थॉमसन ने वर्ष 2005 से 2015 तक संयुक्त राष्ट्र में शरणार्थी मामलों के उच्चायुक्त रहे एंटोनिया गुटरेस को संयुक्त राष्ट्र के नौवें महासचिव के रूप में पद की शपथ दिलाई। वर्ष 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे एंटोनिया गुटरेस ने महासचिव बान की मून की जगह ली है। मून बीते दस वर्षो से इस विश्व निकाय संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की कमान संभाले हुए थे, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर, 2016 को समाप्त हुआ और एक जनवरी, 2017 से गुटरेस ने महासचिव की जिम्मेदारी संभाल ली।

अब सवाल यह उठता है कि क्या एंटोनिया गुटरेस के आने के बाद संयुक्त राष्ट्र चुस्त, दक्ष और प्रभावी बन सकेगा? आपके इस सवाल के जवाब में मैं कहना चाहूँगा कि वैसे तो गुटरेस ने संयुक्त राष्ट्र के कामकाज में बदलाव लाने का आह्वान किया है और विकास को केंद्र में रखने का संकल्प भी लिया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के समक्ष आई अनेक चुनौतियों से भी निबटना होगा। संयुक्त राष्ट्र को प्रक्रिया से ज्यादा ध्यान परिणाम पर देना होगा और नौकरशाही से ज्यादा लोगों पर ध्यान देना होगा साथ ही बड़े पैमाने पर जो चुनौतियाँ मुँह बाए खड़ी हैं, उनसे निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र में सुधार की निरंतर और गहन प्रक्रिया पर मिलकर काम करना होगा जिसे उन्होंन भी महसूस किया है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति की वजह से असमानता बढ़ी है, कई देश बेरोजगार युवाओं की समस्या से जूझ रहे हैं और वैश्वीकरण के कारण संगठित अपराध तथा तस्करी बढ़े हैं जबकि जनता और सियासी प्रतिष्ठानों के बीच की खाई चौड़ी और गहरी हुई है। ऐसी स्थिति में एंटोनिया गुटरेस को अनेक समस्याओं सहित शरणार्थियों की बढ़ती संख्या, आतंक और गृह युद्ध, उभरते संकीर्ण राष्ट्रवाद, आर्थिक संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं का सामना करना है। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के जटिल जंजाल ने आतंक पर कठोर रूख अपनाने की उनके पूर्ववर्ती बान की मून की कोशिशों को फलीभूत नहीं होने दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की चिंताएँ सुरक्षा परिषद में विशिष्ट सदस्य के रूप में बैठी महाशक्तियों की आपसी राजनीति में उलझी रह जाती है। भारत समेत अनेक देश संयुक्त राष्ट्र को उत्तरोत्तर लोकतांत्रिक बनाने की माँग बरसों से करते रहे हैं जिनमें सबसे प्रमुख सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाना है। पाकिस्तान की

शह पर भारत-विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले आतंकी सरगना मसूद अजहर पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव चीन के अड़ियल रवैए की वजह से कई महीनों से लंबित है। नए महासचिव गुटेरस का ध्यान इस ओर जाएगा, ऐसी उम्मीद की जाती है, क्योंकि कामकाज में अनावश्यक विलंब से मुश्किलें हल नहीं हो पातीं। इसके मद्देनजर सुलझे व्यक्तित्व के धनी गुटरेस विवादों के समाधान में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेने का उनका वादा भरोसा जगाता है। ऐसा करने पर ही संयुक्त राष्ट्र चुस्त, दक्ष और प्रभावी बन सकेगा।

(139)प्रश्नः क्या इंडोनेशिया भारत का अहम साझेदार बन सकेगा? आखिर क्यों?

उत्तरः हाँ, इंडोनेशिया भारत का अहम साझेदार बन सकेगा, क्योंकि एक तो इंडोनेशिया 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का एक हिस्सा है और दूसरे कि आर्थिक एवं राजनीतिक मोर्चे पर भारत और इंडोनेशिया के हित एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे मूल्य समान हैं, हमारा समाज एक जैसा है और हमारी चुनौतियाँ भी एक जैसी हैं। हम व्यापार और संस्कृति के मजबूत बंधन से जुड़े हैं। वैसे भी सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादीवाले देश इंडोनेशिया में लोकतंत्र, बहुलतावाद और समाजिक सद्भाव दुनिया के लिए मिसाल है।

अभी-अभी पिछले दिनों 12 एवं 13 दिसंबर, 2016 को भारत दौरे पर आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ हुए संयुक्त घोषणापत्र में रक्षा के क्षेत्र में सुरक्षा और सहयोग, आतंकवाद से जंग, संगठित अपराध और मानव तस्करी पर नकेल के कार्यक्रम पर जोर दिया गया है। समुद्री क्षेत्र से जुड़े देश होने के नाते दोनों पड़ोसी देशों के बीच समुद्री मार्गों की सुरक्षा के साथ ही आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के मसले पर भी व्यापक सहयोग करने पर सहमति जताई गयी। दोनों देश मिलकर द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे। सामरिक हित एक जैसे हैं। दोनों देश ही कट्टरता का सामना कर रहे हैं। आतंकवाद से मुकाबला के लिए आवश्यक है परस्पर सहयोग। इन सभी तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इंडोनेशिया भारत का अहम साझेदार बखूबी बन सकता है।

(140)प्रश्नःक्या आपको ऐसा लगता है कि घुसपैठ के लिए पाकिस्तान हर आतंकी को एक करोड़ रुपए देता है?

उत्तरः हाँ, पाकिस्तान के कब्जेवाले संगठन जम्मू एंड कश्मीर अमन फोरम के नेता सरदार रईस इंकलाबी द्वारा लगाए गए आरोप पर यदि विश्वास

किया जाए तो पाकिस्तान एलओसी पार करने वाले आतंकवादी को एक करोड़ रुपए देता है। सरदार रईस इंकलाबी ने यह भी आरोप लगाया है कि जिन आतंकी संगठनों को पाकिस्तान द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है उन्हें पीओके में फ्री हैंड मिलता है। पिछले कुछ महीनों से यहाँ के नागरिकों में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है और वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही सरदार रईस ने यह भी आरोप लगाया है कि पाकिस्तान एक करोड़ रुपए देकर लोगों की हत्या करवा रहा है।

पीओके में रहने वाले लोगों का भी आरोप है कि पाकिस्तान मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान की सेना और पैरा मिलिट्री पुलिस पीओके के नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुरी तरह परेशान कर रही है। प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने के लिए पाक सुरक्षा बलों ने सख्ती दिखाई जिसमें कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। पीओके के नेता का दावा है कि पाकिस्तान भारत में घुसपैठ के जरिए आतंकवाद को प्रोत्साहित कर रहा है और पाक स्थित आतंकी संगठन की मिलीभगत से नवाज शरीफ सरकार पूरा खेल खेल रही है। इन तथ्यों के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि घुसपैठ के लिए पाकिस्तान हर आतंकी को एक करोड़ रुपए अवश्य दे रहा है।

(141)प्रश्नः रक्षा सौदों की खरीद में बढ़ती दलाली और बिचौलियों की भूमिका के कारण क्या रक्षा हितों से खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है?

उत्तरः हाँ, रक्षा सौदों की खरीद में बढ़ती दलाली और बिचौलियों की भूमिका के कारण रक्षा हितों से निश्चित रूप से खिलवाड़ किया जा रहा है। इन सौदों में हमारी राजनीति और नौकरशाहों की सक्रिय भूमिका होती है। नौकरशाह और राजनीतिक दखल के चलते ही सेना को भी बदनामी झेलनी पड़ रही है, मगर अगस्ता-वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर खरीद मामले में पहली बार वायुसेना के किसी पूर्व वायु सेनाध्यक्ष एस. पी. त्यागी की गिरफ्तारी ने रक्षा सौदों में बिचौलियों की भूमिका और रिश्वत की लेन-देन की समस्या की ओर फिर से ध्यान खींचा है। आजादी के बाद से अब तक हुई बड़ी रक्षा सौदों की खरीदों पर सवाल उठते रहें हैं, कुछ मामलों में जाँच भी हुई और मुकदमें भी चले, पर सजा के नाम पर कुछ उल्लेखनीय नहीं हो सका है।

दरअसल, रक्षा सौदों की खरीद में दलाली को रोकने के लिए जो प्रक्रिया बनाई गई है, वह बहुत उलझाउ है। दलाली पर नियंत्रण की प्रक्रिया

एक भूलभुलैया की तरह है। सामरिक खरीद में जो हथियार लेने होते हैं, उसके लिए रिश्वत दिया जाता है। या फिर उस चीज के वाजिब दाम के मुकाबले घूस-ले-देकर ज्यादा दाम में सौदा हो जाता है। यह तो हुई एक तरह की दलाली। दूसरी तरह की दलाली यह है कि एक सौदे पर बात चल रही है और इस सौदे के बारे में एक व्यक्ति अंदर खाने यह पता करता है कि क्या हो रहा है, यह कितना सही हो रहा है। तकनीकी रूप से यह बिचौलिये के गैरकानूनी काम नहीं हैं। इनको इस काम के लिए कमीशन मिलता है।

देशभर में सेना को बहुत ही सम्मान की नजर से देखा जाता है। एक रक्षा विशेषज्ञ का मानना है कि आज तक जितने भी रक्षा सौदे हुए हैं, किसी भी एक सौदे में ऐसा नहीं रहा कि किसी ने दलाली न खाई हो। आपको याद होगा 1987 में 155 एम एम हावित्जर के लिए 1.3 बिलियन डॉलर का स्वीडिश कंपनी बोफोर्स के साथ हुए समझौते को पूरा करने के लिए बिचौलिए को दिए 64 करोड़ रुपए के घूस मामले में राजीव गाँधी सरकार निशाने पर थी जिसमें बिचौलिए के रूप में गाँधी परिवार के करीबी ओट्टिवो क्वोत्रोची का नाम आया था। इसी प्रकार भारत ने 1150 करोड़ रुपए की लागत से इजराइल से बराक मिसाइल की खरीद में समता पार्टी के आर. के. जैन को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि निश्चित मूल्य से अधिक राशि का भुगतान किए जाने का मामला था। फिर 1999 में कारगिल युद्ध के समय शहीदों के शवों को उनके परिजनों तक पहुँचाने के लिए ताबूत की खरीद में घोटाला हुआ था। 1999 में ही समाचार पोर्टलेन तहलका डॉट कॉम ने रक्षा सौदों में सैन्य अधिकारियों और नेताओं द्वारा लिए जाने वाले घूस के मामलों को उजागर किया गया था। स्टिंग ऑपरेशन में तत्काल भाजपा अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को घूस लेते हुए दिखाया गया था। इस प्रकार रक्षा सौदों की खरीद में दलाली या रिश्वतखोरी कर अधिकारी या राजनेताओं ने रक्षा हितों से खेलवाड़ किया है।

(142)प्रश्नः अमृतसर में संपन्न हर्ट ऑफ एशिया के छठे सम्मेलन में क्या पाकिस्तान नजरअंदाज हुआ?

उत्तर: हाँ, दिसंबर, 2016 के प्रथम सप्ताह में अमृतसर में आयोजित हर्ट ऑफ एशिया के छठे दो-दिवसीय सम्मेलन में पाकिस्तान नजरअंदाज हुआ। आखिर तभी तो नरेन्द्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफगनी के अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद पर साधे बयानों पर पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज को अलग से बयान जारी करना पड़ा

कि एक देश को आतंकवाद के लिए जिम्मेदार न ठहराया जाए। हर्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के दौरान जिन शब्दों में पाकिस्तान को हिदायत दी गई उसे पूरी तरह अनसुना करना उसके लिए बहुत आसान नहीं होगा। पाकिस्तान के दो सबसे अहम पड़ोसी न सिर्फ उसके खिलाफ पूरी तरह लामबंद हैं, बल्कि उसके आतंकी चेहरे का बेनकाब करने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार हैं। ये दोनों पड़ोसी हैं अफगानिस्तान और भारत। पाकिस्तान की जोर-आजमाईश के बावजूद अमृतसर घोषणापत्र में वहाँ फल-फूल रहे जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के नाम शामिल किए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि इस्लामाबाद किस तरह से क्षेत्र में अलग-थलग पड़ रहा है। हाल के दिनों में पाकिस्तान को इस तरह की कूटनीतिक शर्मिंदगी का सामना बहुत करना पड़ा है। इस सम्मेलन में चीन भी शामिल था, लेकिन अधिकतर देशों के मूड को देखते हुए उसने चुप रहना ही मुनासिब समझा।

(143)प्रश्नः न्यूजीलैंड के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जॉन की का आठ वर्षों के कार्यकाल के बाद अपने से त्याग देने का चिंतन क्या यह विलक्षण घटना नहीं है? आखिर कैसे?

उत्तरः हाँ, न्यूजीलैंड के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जॉन की का आठ वर्षो के कार्यकाल के बाद अपने पद से त्याग पत्र देने का चिंतन वास्तव में यह विलक्षण घटना है, खासकर तब जबकि समूची दुनिया के राजनीतिक परिदृश्य में सत्तालोलुपता एवं पदलिप्सा व्याप्त है। प्रधानमंत्री तो क्या सांसद, विधायक एवं पार्षद भी स्वेच्छा से अपना पदत्याग नहीं करता है। ऐसे समय में एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री का अपने पद से स्वेच्छा से त्याग देना सचमुच एक विरल घटना है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जॉन की ने अपनी पत्नी के कहने पर प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र इसलिए दिया है, क्योंकि राजनीति में रहने की वजह से घर-परिवार के लिए वह ज्यादा वक्त निकाल नहीं पाते थे। उनकी उम्र भी तो अभी मात्र 55 साल की है। वस्तुतः राजनीति के लिए यह न केवल एक सीख बनी है, बल्कि इसने विश्व राजनीति का एक नया इतिहास गढ़ा है।

आज राजनीतिज्ञों की सोच, जीवन शैली, विचार और नीति इतनी पतनोन्मुखी बन गयी है कि सत्ता हथियाने के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं। कुर्सी के लिए आज कहाँ कयामत नहीं टूटती? सत्ता का व्यामोह कौन से गलत रास्ते नहीं चुनता? कौन-सा इंसान नहीं बिकता, आदर्श नहीं चरमराती, सिद्धांत सूली पर नहीं चढ़ते, जीवन मूल्य अपाहिज नहीं होते और रिश्तों के

नाम नहीं बदलते? सत्ता के लिए जब इतना सबकुछ होता है तो प्राप्त सत्ता और पद को कौन स्वेच्छा से त्यागेगा? लेकिज जॉन की ने सफल एवं यशस्वी आठ साल के कार्यकाल के चलयमान दौर में पद पर रहते हुए उसे त्याग देने का निर्णय लेना न केवल साहसिक, बल्कि एक नए अध्याय का श्रीगणेश है। जॉन की का कहना है कि उसने आज तक जितने भी फैसले लिए हैं, यह उन सभी में से सबसे ज्यादा कठिन फैसला है। यह अकेली घटना है जो न्यूजीलैंड को चर्चित करने के लिए पर्याप्त है। जॉन की का कहना है कि वह हमेशा नई प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के पक्ष में रहते हैं।

(144)प्रश्नः क्या आप बता सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उस वैश्विक व्यवस्था और नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय तंत्र का क्या होगा, जिसे अमेरिका ने निर्मित किया है और जिसकी वह 70 वर्षो से अगुआई करता आ रहा है?

उत्तरः फिलहाल तो अमेरिका अपने साझेदार देशों के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और पदभार संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी इनसे पीछे हटना मुश्किल होगा। मुझे ऐसा लगता है कि चीजें ज्यादा नहीं बदल सकतीं, क्योंकि अमेरिका के अपने हित हैं, जो कि नहीं बदलेंगे। यदि ट्रंप इन हितों को पोषित करने की राह से भटकते हैं, तो अमेरिकी काँग्रेस और वहाँ की जनता जल्द ही उन्हें सीधे रास्ते पर ले आएगी। पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों ने भी पदभार संभालने से पहले कट्टरपंथी मुद्रा अपनाई थी, किंतु बाद में उनका रूख नरम हो गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के विचार पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों से इन मायने में भिन्न हो सकते हैं कि ट्रंप वही करना चाहते है, जो वे कहते रहे हैं। अमेरिका बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी नियमों को और सख्त कर सकता है जिससे ना सिर्फ कनाडा, बल्कि भारत जैसे देश भी काफी प्रभावित हो सकते हैं। सुरक्षा के मामले में अमेरिका सबसे पहले अपने इलाके की ही फिक्र करेगा। उत्तर कोरियाई परमाणु हथियारों से निपटने हेतु दक्षिण कोरिया की आगे भी अमेरिका सहायता करता रहेगा और भारत के साथ भी उसके संबंध अच्छे रहेंगे। अमेरिकी नीतियों में किसी भी तरह का व्यापक फेरबदल वैश्विक व्यवस्था में उथल-पुथल मचा सकता है।

(145)प्रश्नःक्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि महान क्रांतिकारी और क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रों के निधन से भारत और दुनिया के विकासशील और अविकसित देशों

ने अपना एक हमदर्द साथी खो दिया है और वैश्विक शांति और न्याय के पक्षधरों ने अपना सरपरस्त खो दिया है?

उत्तर: हाँ, मैं भी यह महसूस करता हूँ कि करीब 50 साल तक अमेरिका की आँखों की किरकिरी बने रहे और करीब 50 साल तक क्यूबा के राष्ट्रपति पद पर रहकर सत्ता संभाल रहे साम्यवादी व्यवस्था के स्तंभ फिदेल कास्त्रों के विगत 25 नवंबर, 2016 को निधन हो जाने के बाद भारत और दुनिया के विकासशील एवं अविकसित देशों ने न केवल अपना एक हमदर्द दोस्त खो दिया है, बल्कि वैश्विक शांति और न्याय के पक्षधरों ने अपना एक सरपरस्त खो दिया है। आखिर तभी तो 90 वर्ष की उम्र में उनके देहावसान के बाद कास्त्रों की महानता और उनके योगदानों की चर्चा आज उनके विरोधी भी कर रहे हैं।

पिछले छह दशकों से अधिक समय से क्यूबा और भारत के बीच गहरी मित्रता रही है। क्यूबा के आड़े वक्तों में भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है, तो क्यूबा ने भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हमेशा भारत को साथ दिया है। फैंज फेनन ने अपनी चर्चित पुस्तक 'द रेच्ड ऑफ द अर्थ' में फिदेल कास्त्रों का जिक्र करते हुए लिखा है– 'संयुक्त राष्ट्र में सैन्य गणवेश में बैठे फिदेल अल्प विकसित देशों का वितंडा नहीं बनाते, कास्त्रों असल में हिंसा के राज की सतत उपस्थिति की चेतना प्रदर्शित करते हैं।'

अमेरिका के ठीक पिछवाड़े संसाधनहीन क्यूबा को समाजवादी देश बनाने का संघर्ष आसान नहीं था। नब्बे के दशक में सोवियत संघ के विघटन के बाद तो आर्थिक तकनीकी सहायता का कोई स्रोत भी नहीं रह गया था उनके पास, लेकिन इन सबके बीच फिदेल कास्त्रों ने उन सपनों को धुंधला नहीं पड़ने दिया, जिनकी ऊर्जा के सहारे 1956 में भाई राउल कास्त्रों और येग्वेरा सहित अपने 80 साथियों के साथ ग्रैन्मा नामक नौका में सवार होकर वह अपने देश में क्रांति करने निकले थे। वे दुनिया भर की जनपक्षीय ताकतों के लिए एक प्रेरणा हैं और आदर्श भी। उनका जाना निश्चित रूप से एक युग का विराम है।

(146)प्रश्न:विश्व में सबसे अगुआ राष्ट्र अमेरिका की पहली राष्ट्रपति के रूप में हिलेरी क्लिंटन को चुनकर स्त्री-सशक्तीकरण में भी अगुआ होने का सारा विश्व इंतजार कर रहा था, तब फिर अचानक नाउम्मीद क्यों हो गए?

उत्तर: लगभग ढाई सौ वर्ष की आजादी में अमेरिका में अबतक

पैंतालिस राष्ट्रपति चुने गए, मगर एक भी स्त्री उस सर्वोच्च पद तक नहीं पहुँच सकी जबकि अक्सर अमेरिका को एक आदर्श राष्ट्र के रूप में जाना जाता है जिसकी मुख्य धारा में पहुँच जाने का ख्वाब न केवल भारतीय का है, बल्कि एथनिक अस्मिताओं का भी स्वप्न रहा है। अभी-अभी अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के चुनाव में जब सारा विश्व हिलेरी क्लिंटन को अमेरिका की पहली राष्ट्रपति चुनने का इंतजार कर रहा था और स्त्री-सशक्तीकरण में भी सच में अमेरिका को अगुआ कहने की उम्मीद की जा रही थी, तब लोग अचानक नाउम्मीद हो गए और महिलाओं के लिए भद्दी-वाहियात बातें कहने वाले अमेरिका के लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद पर बैठा दिया। एक स्त्री-विरोधी व्यक्ति को चुन लेना क्या उन स्त्रियों का आत्मघृणा की गुलाम मानसिकता पर ठप्पा लगाने जैसा नहीं था? अपने शोषक की शक्ति से प्रभावित हो स्त्रियाँ आत्मविस्मृति की, अस्मिताहीन स्थिति की ओर क्या जाती नहीं दिखती हैं?

उपर्युक्त दोनों सवालों के जवाब में मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रपति का चुनाव हो या प्रधानमंत्री का उसका आधार लिंग न होकर योग्यता है। तो क्या यह मानकर चला जाए कि विगत ढाई सौ वर्षो की राजनीति में अमेरिका में एक भी राष्ट्रपति की योग्य स्त्री उम्मीदवार नहीं बन सकी। सवाल स्त्री के योग्य या अयोग्य होने का नहीं, बल्कि राजनीति में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम होने का है। यह सोच या शोध का विषय है कि राजनीति में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व कम क्यों है।

जहाँ तक अमेरिका की राजनीति में स्त्रियों के प्रतिनिधित्व का सवाल है, वहाँ स्त्रियों के लिए मताधिकार का सवाल 1840 में उठा था और एक लंबे संघर्ष के बाद 1920 में अंततः यह अधिकार स्त्रियों को मिला और एक नागरिक के तौर पर लिंग समानता की जंग जीती गयी। दरअसल, अबतक एक आमधारणा रही है कि राजनीति एक गंदी जगह है जहाँ महिलाएँ ऐसी गंदी जगह नहीं जातीं। दूसरी विचारधारा यह रही है कि स्त्रियों का काम घर-बार तक सीमित है। मगर मताधिकार मिलने से वे अपनी पवित्रता खो देंगी और इससे घर टूटने लगेंगे ऐसी 'कॉमन सेंस' मासूम और अराजनीतिक नहीं मानी जा सकती।

सच तो यह है कि विश्व समुदाय के पूरे समाज में स्त्रियों के लिए स्वाभाविक तौर पर नेता बनने के गुणों के विकसित होने के लिए कभी माहौल नहीं बनाया गया। अपने समुदाय के लिए, अपने परिवेश, अपने

अधिकारों के प्रति जागरूक और सभाओं में बोलने वाली स्त्रियों को न सिर्फ पुरुषों ने बल्कि पितृसत्ता समर्थक स्त्रियों ने भी घर तोड़ने वाली और अनैतिक स्त्रियाँ ही माना। इस तरह नेता के तौर पर स्त्रियों को तैयार करने के मौके आज तक अख्तियार नहीं किए जा रहे हैं। होना तो यह चाहिए कि लड़कियों में बचपन से ही नेतृत्व गुणों को विकसित होने देने के लिए माहौल बने, ताकि वे अपने लिए अपने समुदाय और स्त्रियों, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीख सकें, सभाओं में अपनी आवाज बुलंद कर सके।

(147)प्रश्नः क्या आपको ऐसा लगता है कि रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमुर पुतिन स्टालिन की तरह ताकतवर हो रहे हैं?आखिर कैसे?

उत्तरः हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमुर पुतिन स्टालिन की तरह ताकतवर हो रहे हैं। आखिर तभी तो स्टालिन के बाद अगर किसी रूसी से अमेरिका भयभीत है तो वो है पुतिन। अमेरिकी चुनावों में पुतिन का हौव्वा ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी थी जो डेमोक्रेट हिलेरी क्लिंटन राष्ट्रपति के चुनाव में अखबारों में मतदान के पूर्व किए गए सर्वे में काफी आगे थीं वो चुनावों में धूल चाटती नजर आईं। इस हार के बाद हिलेरी क्लिंटन सदमें में हैं, क्योंकि उन्हें यह हार बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जाते-जाते भी पुतिन से व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहे हैं। विभिन्न फ्रंटों पर पुतिन से पराजित होने के बाद ओबामा ने झल्लाकर रूसी राजनयिकों को अमेरिका से निकालने का फैसला लिया। रूसी इंटेलिजेंस एजेंसियों का एजेंट बताकर 35 राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश ओबामा ने जारी कर दिया।

रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिम से खुलकर लड़ाई तब ली जब अमेरिका और उनके यूरोपीय देशों ने यूक्रेन में रूस के खिलाफ मोर्चा खोला। यूक्रेन के अंदर अमेरिका प्रायोजित स्वयंसेवी संगठनों ने रूस समर्थित राष्ट्रपति के खिलाफ आंदोलन शुरू करवाया। रूस समर्थित राष्ट्रपति को यूक्रेन से भागना तक पड़ा। इसके बावजूद पुतिन दबाव में नहीं आए। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को लेकर रूस पर दबाव बनाने के तमाम तरीके अपनाए। यहाँ तक कि यूरोपीय संघ ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन पुतिन ने इन आर्थिक प्रतिबंधों का जोरदार जवाब दिया। रूस की जवाबी कार्रवाई में जर्मनी और फ्रांस की अर्थव्यवस्था हिलने लगी, क्योंकि रूस, जर्मनी और फ्रांस से खाद्य पदार्थो व ओटोमोबाइल समेत कई और सेक्टर में भारी आयातक है। रूस ने यूरोप से होने वाले इन आयातों पर प्रतिबंध लगा दिया। परिणामस्वरूप

जर्मनी और फ्रांस के फल उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ। जर्मन ऑटोमोबाइल और फार्मा सेक्टरों को भी भारी क्षति हुई। यहाँ पर लाखों लोग रूसी आयात बंद होने से बेरोजगार हो गए। मजबूरी में फ्रांस और जर्मनी को पुतिन से बातचीत का रास्ता खोजना पड़ा। ये दोनों देश अमेरिकी नीति से दूरी बनाने लगे।

पुतिन ने पश्चिम एशिया में भी अमेरिकी प्रभुत्व की कमर तोड़ दी। सीरिया में अमेरिकी प्लान पूरी तरह से विफल कर दिया। रूस ने बशर अल असद के बचाव में एक साथ इस्लामिक स्टेट और अमेरिका समर्थित आतंकी संगठनों पर कार्रवाई शुरू कर दी। अमेरिका यहाँ डिफेंसिव हो गया। हालात यह हो गए कि अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी को कहना पड़ा कि वो रूस युद्ध नहीं चाहते। आज सीरिया में असद सरकार मजबूत हो गई और अमेरिका की सारी रणनीति विफल हो गई। अमेरिका सीरिया के रास्ते भूमध्य सागर तक जाने वाले रास्ते पर कब्जा करने में विफल हो गया है।

बराक ओबामा के कार्यकाल में भारत अमेरिकी संबंधों की मजबूती की वजह से पुतिन भारत को सबक सिखाने के मूड में भी है, हालांकि भारत के साथ दोस्ती खत्म करने के संकेत पुतिन ने नहीं दिए हैं, मगर रूस के प्रभाव में ईरान इतना ज्यादा है कि रूस के इशारे पर ईरान भी भारत विरोधी फैसले ले सकता है। यह भारत के लिए बड़ा झटका होगा। हालांकि पुतिन भारत के साथ सिविल न्यूक्लीयर एरिया में सहयोग दे रहे हैं, वहीं भारत रूस को भारी रक्षा सामान खरीद कर आड़े भी दे रहा है। पर इतना जरूर है कि पुतिन कड़े और व्यावहारिक फैसले ले रहे हैं। इसलिए उनकी ताकत भी बढ़ रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पुतिन स्टालिन की तरह ताकतवर हो रहे हैं।

(148) प्रश्न: क्या आपको ऐसा लगता है कि नोटबंदी ने आतंक के पनाहगारों की कमर तोड़ दी है? कैसे?

उत्तर: हाँ, कृष्णनन्दन जी, मुझे भी ऐसा लगता है कि नोटबंदी ने आतंक के पनाहगारों की कमर तोड़ दी है, क्योंकि इसी वजह से ही दिसंबर, 2016 में घाटी में आतंकवाद से जुड़ी हिंसा की घटनाओं में 60 प्रतिशत की कमी आई है और इसके अलावा नोटबंदी की वजह से ही नक्सली गतिविधियों पर भी चोट पहुँची है। भारत में हुई नोटबंदी ने पाकिस्तान में जाली नोटों के धंधेबाजों को बेरोजगार कर दिया है, क्योंकि जाली नोट छापने वाली दो अहम पाकिस्तानी प्रेस को मजबूरन बंद किया गया है। सरकार के इस फैसले से आतंकियों की फंडिंग पर शिकंजा कसा है। हमारे जवानों पर

पत्थर फेंकने वाले कश्मीरी नौजवानों को नोट मिलना बंद हो जाने के बाद से वे भी हताश हो गए हैं। पाकिस्तान से आने वाली जाली नोटों से हथियार खरीद कर मुल्क में हिंसा फैलाने वाले आँन्ध्रप्रदेश, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के नक्सली भी टूट गए हैं।

देश की सुरक्षा एजेंसियों का यह कहना कि भारत सरकार का यह फैसला मजबूत है, क्योंकि इस एक फैसले से आतंकवाद की चूलें हिल गई हैं। अमन कायम होना इस बात की जमानत है कि नकली करेंसी भारत में हिंसा का जनक था। इसके अतिरिक्त भारत में हवाला एजेंटस के कॉल ट्रैफिक में भी 50 प्रतिशत की कमी आई है। नोटबंदी के बाद पाकिस्तान के पास जाली नोटों की दुकान बंद करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा। यही नहीं, नोटबंदी के कारण भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों की गतिविधि कम हुई है। ये सभी उदाहरण ऐसे हैं जिससे लगता है कि नोटबंदी ने आतंक के पनाहगारों की कमर तोड़ दी है।

(149)प्रश्न:भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रवासी भारतीयों का क्या योगदान है? बैंगलुरु में पिछले दिनों आयोजित तीन दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन को ज्यादा परिणामकारी बनाने के लिए क्या किया गया?

उत्तर: भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रवासी भारतीयों का योगदान जगजाहिर है। प्रवासी भारतीयों की तरफ से प्रत्येक वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था में होने वाला निवेश करीब 69 अरब डॉलर तक पहुँच गया है जो सामान्य राशि नहीं है। वैसे सरकार कई प्रकार के कार्यक्रम चला रही है जिनसे उन्हें न केवल भारत में वित्तीय, तकनीकी, मानवीय आदि संसाधनों के निवेश के लिए प्रेरित किया जाए, बल्कि सरकार शीघ्र ही प्रवासी कौशल विकास योजना आरंभ करेगी जिसमें ऐसे भारतीयों को रोज़गार के योग्य बनाया जाएगा जो विदेशों में रोजगार के मौके तलाशते हैं। एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत विदेशों में रहने वाले युवा भारतीयों के समूह भारत आएँगे और उनके साथ अलग-अलग विषयों पर विचार-विनिमय होगा जिससे भारत के साथ उनका भावनात्मक, व्यावसायिक या अन्य कार्यगत जुड़ाव हो सके।

जहाँ तक बैंगलुरु में जनवरी, 2017 में आयोजित तीन दिवसीय 14वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में इसे ज्यादा परिणामकारी बनाने का सवाल है, दुनिया भर में फैले भारतवंशी भारत के लिए एक बड़ी ताकत हैं, जिनका उनकी संभावी क्षमता के अनुरूप उपयोग नहीं हुआ है। वे जिस देश में रहते

हैं, वहाँ से ईमानदार जुड़ाव रखते हुए भी भारत के लिए कई रूपों में काम कर सकते हैं। यह माना जाना चाहिए कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन के जरिए सरकार युवाओं के समागम सहित जो अन्य कार्यक्रम चला रही है, उसका अपेक्षित प्रभाव होगा और भारतवंशी भारत के लिए भारत में और दुनिया के स्तर पर भारत के लिए खड़ा होने वाले शक्तिपुँज बनेंगे। प्रवासी दिवस कार्यक्रम ने अब सांस्थानिक रूप ले लिया है। बैंगलुरु में आयोजित यह सम्मेलन आज तक का सबसे विशाल आयोजन हो चुका है जिसमें सात हजार से ज्यादा प्रवासी भारतीयों ने शिरकत किया जिसका परिणाम यह रहा कि भारत के विकास कार्यक्रमों से अधिक निकटता से जोड़ने का रास्ता मिला।

(150)प्रश्नः क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि विश्व राजनीतिक समीकरण से बराक ओबामा ने जिस तरह से अपना तालमेल बैठाया वह करिश्माई से कम नहीं था? कैसे?

उत्तर: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने कार्यकाल में विश्व राजनीतिक समीकरण से जिस तरह तालमेल बैठाया वह करिश्माई से कम नहीं था, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने जिस अंदाज में अमेरिकी लोकतंत्र की रक्षा की उससे तमाम उभरते हुए देशों के बीच उनका मूल्क आज दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनकर खड़ा है। सबसे शक्तिशाली के तौर पर बीते आठ सालों में दुनिया पर राज करने वाले बराक ओबामा ने अपने विदाई समारोह को जब संबोधित किया तो अपनी पत्नी और बच्चों का जिक्र करते हुए उनकी आँखों के कोर गीले हो गए। नि:संदेह अपने कार्यकाल में उन्होंने अपने परिवार को राजनीति से दूर रखा और पूरी कोशिश की कि कोई विवाद न खड़ा हो।

वस्तुत: मुझे भी ऐसा लगता है कि अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसका लोकतंत्र है, क्योंकि रूस और चीन जैसे देश सब कुछ होते हुए भी ताकत बनकर जब नहीं उभर सके, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके यहाँ लोकतंत्र की जड़ें काफी कमजोर हैं। उन्होंने बड़ी संवेदनशीलता के साथ नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नसीहत देते हुए बड़े भावुक होकर कहा–'प्लिज, हर हाल में नस्लवाद को रोकिएगा। खुद तो सहिष्णु बनिए ही दूसरों को भी इस बात के लिए प्रेरित करिए कि वो जातिवाद के खाँचे से निकल आए।'

बराक ओबामा ने अपने कार्यकलापों से पूरी दुनिया में एक अलग छाप छोड़ी और विश्व के राजनीतिक समीकरण से उन्होंने जिस तरह से

अपना तालमेल बैठाया वह करिश्माई था। अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए हर वो कदम उठाए जो उस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत थी। इस्लामी आतंकवाद को कुचलने के लिए हर संभव कदम उन्होंने उठाए, लेकिन इस बात का ख्याल भी रखा कि महज मुसलमान होने की वजह से किसी को परेशान न किया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति के पद से वह रूखसद हो गए हों, लेकिन लोकतंत्र के पैरोकारों के जेहन में उनकी याद हमेशा आती रहेगी।

(151)प्रश्नः दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में विगत 20 जनवरी, 2017 को विधिवत कमान संभालने वाले डोनाल्ड ट्रंप के आगामी रूख-रवैए पर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे?

उत्तरः देखिए विजय जी, चुनाव जीतने के बाद तो नए राष्ट्रपति एक सुलझे हुए नेता की तरह संबोधित किया डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में वह पुराने अक्खड़ रूप में नजर आए। सच तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप देश-दुनिया के मसलों पर बिल्कुल भिन्न राय रखते हैं। इस क्रम में न जाने कितने बयान-विवाद का विषय बने। उन्होंने पड़ोसी देश मैक्सिको के लोगों को अमेरिका आने से रोकने के लिए जहाँ सीमा पर दीवार खड़ी करने की बात कही, वहीं मुसलमानों के प्रवेश पर भी पाबंदी लगाने का ऐलान किया।

जहाँ तक मैं समझता हूँ राष्ट्रपति की कुर्सी डोनाल्ड ट्रंप को उनकी जिम्मेदारियों को अहसास कराने के साथ ही देश-दुनिया की जमीनी हकीकत से परिचित कराएगी, लेकिन यह संभव नहीं कि उनके नेतृत्व में अमेरिकी नीतियों में कहीं कोई तब्दीली नहीं आए। ऐसा होने के आसार इसलिए है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य बदलता दिख रहा है। अब यही देखिए न डोनाल्ड ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन से दोस्ती है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि दोनों देशों के संबंधों में खटास दूर होगी, क्योंकि रूस अंतरराष्ट्रीय मामलों में अपना प्रभुत्व कायम रखने के लिए तत्पर दिख रहा है। जहाँ तक अमेरिका और भारत के रिश्तों का सवाल है तो इस बारे में तत्काल किसी नतीजे पर नहीं पहुँचा जा सकता।

मुझे लगता है कि अमेरिका में ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद चीन-भारत के बढ़ते तनाव और चीन-रूस की मित्रता से उत्पन्न परिस्थितियाँ और जटिल हो सकती हैं। ट्रंप का रूस के प्रति दोस्ताना और चीन के प्रति

विरोधी रूख आने वाले दिनों में एशिया में भूराजनीतिक समीकरणों को और उलझाएगा। जाहिर है, आने वाला समय काफी दिलचस्प रहने की संभावना है। जहाँ तक सूचना तकनीकी से जुड़े पेशेवरों का सवाल है वैसे तो यह संरक्षणवादी नीति से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ट्रंप अगर एच-1 वीजा के मसले पर कड़ा रवैया अपनाते हैं, तो इसका भारतीय हितों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका जितने विदेशी पेशेवरों को एच-1 वीजा देता है उनमें 90 प्रतिशत भारतीय होते हैं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों की कमाई का यह बहुत बड़ा स्रोत है। साथ ही भारत को आईटी निर्यात से ही कमाई होती है।

(152)प्रश्न:पाकिस्तान ने आर्थिक गलियारे के लिए धन जुटाने को लेकर चीन कंपनियों के समूह को पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज की 40 प्रतिशत इक्विटी बेचकर क्या अप्रत्याशित कदम नहीं उठाया है? ऐसा करके चीन ने प्रत्यक्ष रूप से क्या यह सबूत नहीं दे दिया है कि वो पाक को अपनी कॉलोनी की तरह ट्रीट करना चाहता है?

उत्तर: निश्चित रूप से पाकिस्तान ने अपने आर्थिक गलियारे के लिए धन जुटाने को लेकर चीनी कंपनियों के समूह को 85 मिलियन डॉलर(8.96 अरब रुपए) में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की 40 प्रतिशत इक्विटी बेचकर अप्रत्याशित कदम उठाया है। मैं समझता हूँ कि पाक के इस कदम से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में चीन का हस्तक्षेप बहुत बढ़ जाएगा। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में पाकिस्तान के कब्जेवाले कश्मीर (पीओके) का हिस्सा भी शामिल है। इसलिए भारत शुरुआत से ही इसका विरोध करता रहा है।

पाकिस्तानी वित्त मंत्री इशाक डार की उपस्थिति में विगत 20 जनवरी, 2017 को बिक्री व खरीद समझौता पर हस्ताक्षर किया गया, हालांकि पाकिस्तान में इसका विरोध भी हुआ है, क्योंकि वहाँ के लोगों को यह चिंता है कि ऐसा करके चीन ने प्रत्यक्ष रूप से सबूत दे दिए हैं कि पाक को अपनी कॉलोनी की तरह ट्रीट करना चाहता है।

(153)प्रश्न:भारत और यूएई के प्रगाढ़ होते रिश्ते को लेकर पाकिस्तान क्यों परेशान है?

उत्तर:भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के प्रगाढ़ होते रिश्ते को लेकर अभी तक यूएई को अपना बिरादरी देश मानने वाला पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि भारत की सोच से सहमत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त

घोषणाओं के दौरान अब उन देशों को आड़े हाथ लिया जो आतंकवाद का पोषण करते हैं। जाहिर है आतंकवाद का पोषण करने वाला पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया गया। यह शुभ संकेत है कि 26 जनवरी, 2017 को नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में भारत के मुख्य अतिथि संयुक्त अरब अमीरात के युवराज शेख मोहम्मद बिन जाएद नहयां रहे।

आपको याद होगा कि यह वही युवराज हैं जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की अगस्त, 2015 की यात्रा के समय सारी राजनीतिक मर्यादाओं को ताक पर रखते हुए अपने पाँच भाइयों के साथ मोदी के आगमन पर उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुँच गए थे। मोदी के आमंत्रण पर फरवरी, 2016 में शेख मोहम्मद तीन दिवसीय दौरे पर भारत पहुँचे थे और कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। यूएई को एक अत्याधुनिक राष्ट्र बनाने में भारतीय मजदूर, व्यापारी, लेखाकर्मी तथा तकनीकी विशेषज्ञों का बड़ा हाथ रहा है। इसलिए अन्य दक्षिण एशियाई देशों के लोगों की अपेक्षा भारतीय समुदाय को यहाँ काफी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। भारत एवं यूएई प्रतिरक्षा, गृहसुरक्षा, आतंकवादी और धार्मिक कट्टरता से लड़ने में आपसी सहयोग करने की बात कर रहे हैं। यही कारण है कि भारत और यूएई के प्रगाढ़ होते रिश्ते को लेकर पाक परेशान है।

(154)प्रश्नः क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि दुनिया में लगातार बढ़ती आर्थिक विषमता हर किसी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए? क्या अमीर लगातार और ज्यादा अमीर और गरीब और ज्यादा गरीब नहीं होते जा रहे हैं?

उत्तरः हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि दुनिया में लगातार बढ़ती आर्थिक विषमता हर किसी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि अमीर लगातार और ज्यादा अमीर और गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। जहाँ तक भारत का सवाल है यहाँ का हाल बाकी दुनिया से भी बुरा है, क्योंकि अमीरी-गरीबी की खाई हमारे देश में कुछ ज्यादा ही चौड़ी है।

गरीबी उन्मूलन पर काम करने वाली संस्था ऑक्सफैम की ताजा रिपोर्ट ऐन इकोनॉमी फॉर द 99 परसेंट के मुताबिक दुनिया की एक प्रतिशत सबसे अमीरी आबादी की संपत्ति का आँकड़ा बाकी 99 प्रतिशत आबादी की कुल संपत्ति से भी ज्यादा है। गिनती के आठ सुपर अमीरों के पास दुनिया की आधी आबादी के बराबर की संपत्ति है। जहाँ तक भारत का सवाल है तो यहाँ देश की कुल संपत्ति का 58 प्रतिशत हिस्सा एक प्रतिशत सबसे

अमीर आबादी की झोली में है। आर्थिक विषमता की यह खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। अध्ययन के अनुसार दुनिया की आधी गरीब आबादी की संपत्ति पहले के अनुमानों से भी कम दर्ज की गई है। चीन, इंडोनेशिया, लाओस, भारत में 15 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है जबकि सबसे गरीब 10 प्रतिशत आबादी की आय में 15 प्रतिशत से अधिक की गिरावट हुई है।

इस देश की संपत्ति पर कब्जा मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है। आर्थिक उदारीकरण के बाद देश में संपत्ति और आय का बँटवारा बेहद असंतुलित हुआ है। हमारे देश की 98 प्रतिशत संपत्ति पर महज 1 प्रतिशत लोगों का कब्जा है। पिछले एक दशक में नीचे के लोगों में अनिश्चितताओं का दायरा लगातार बढ़ता गया है। इसका असर किसानों की आत्महत्या के रूप में भी दिखा है।

दावोस में प्रतिवर्ष विश्व आर्थिक फोरम के सम्मेलन के अवसर पर अमीरी और गरीबी के बीच बढ़ते आर्थिक अन्तर पर चिंता व्यक्त की जाती है, पर ऐसी कोई कार्ययोजना पेश नहीं की जाती जिससे असमानता को कम किया जा सके। भले ही डॉलरवाले अरबपतियों की बढ़ती संख्या को अर्थव्यवस्था का खुशनुमा विस्तार माना जाए, पर उनकी अपेक्षा गरीबों की संख्या कहीं तेजी से बढ़ रही है जो सरकार की नीतियों को बदलने की आवश्यकता की ओर इशारा करती है। दरअसल, वित्तीय पूँजी आधारित वर्तमान व्यवस्था का फायदा पहले से मजबूत तत्वों को ही हुआ। आखिर तभी तो विगत तीस साल में निचले तबकों में से 50 प्रतिशत लोगों की कमाई नहीं बढ़ी, जबकि 1 प्रतिशत अमीर लोगों की कमाई 300 प्रतिशत तक बढ़ गई।

लगभग एक सौ तीस करोड़ आबादीवाले इस देश में अधिकांश लोगों के घर का सपना आजादी के सत्तर साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। जीवन काल में ऐसे लोगों का आशियाना सड़क, फुटपाथ, पार्क, गाँव, निर्जन इलाके, पेड़ आदि होते हैं। जबतक मौजूदा स्थिति में सुधार नहीं होता है, तबतक कुछ धनवानों के हाथों में संकेंद्रीत संपत्ति का वितरण आम लोगों के बीच संभव नहीं है।

(155)प्रश्न: रूसी समाज के निम्नतम स्तर से आए मैक्सिम गोर्की रूसी साहित्य क्षेत्र में एकाएक इतने प्रसिद्ध कैसे हो गए?

उत्तर: यदि हम लेखक मैक्सिम गोर्की के काल के रूसी समाज तथा साहित्य पर दृष्टि डालने का प्रयत्न करते हैं, तो पाते हैं कि उन दिनों रूस

के महानतम लेखक चेखव 1880 के काल की भयानक निराशा में से उभरे थे। यह वह समय था जब बुद्धिजीवियों को अपना कोई भविष्य नहीं दिखाई देता था, क्योंकि रूसी समाज की श्रेष्ठतम शक्तियाँ जारशाही के विरूद्ध व्यर्थ संघर्ष की बलिवेदी पर चढ़ा दी गयी थी और चेखब का साहित्य इसी भावना से सराबोर रहा है। निराशा के इसी वातावरण में गोर्की ने एक नयी ताजगी का संचार किया, समूची रूसी जनता के लिए वह आशा का एक नया संदेश लाए और इसी वजह से रूसी राष्ट्र जीवन में एक नयी शक्ति के रूप में प्रकट होने के कारण गोर्की रूस के एक कोने से दूसरे कोने तक एकाएक प्रसिद्ध हो गए।

रूसी लेखक के रूप में गोर्की शक्ति के पुँज नजर आने लगे और यह शक्ति उन लोगों की थी जिनके बीच वह रहते थे। वह हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि आम लोगों की बोलचाल, लोक-साहित्य और जनता में प्रचलित कहानियों में भाषा का सबसे समृद्धतम खजाना मौजूद है, उसमें भाषा और साहित्य की महानतम निधियाँ निहित है। उनका समूचा साहित्य इस बात का प्रमाण है। गोर्की रूसी साम्राज्य की साहित्य अकादमी के सदस्य चुने गए, लेकिन उतनी ही तेजी से, जार के सीधे फरमान पर, वह अकादमी की सदस्यता से हटा भी दिए गए। एक लेखक गोर्की के इस दमन के लज्जास्पद कृत्य के विरोध में चेखव और कोरोलैन्कों- ये दो ख्यातिप्राप्त लेखकों ने भी अपने आपको सदा के लिए गौरवान्वित करते हुए अकादमी की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया, किन्तु पुरातनपंथी गिरजे का कोप-भाजन बनना पड़ा, उन्हें धर्मच्यूत किया गया और रूसी साम्राज्य के हर प्रार्थना घर में उनके खिलाफ घिनौने फतवे पढ़े जाने लगे।

इसी पृष्ठभूमि में गोर्की ने रूसी लेखकों को दिखाया कि निरंकुशता कितनी ही क्रूर और हिंसक क्यों न हो, उससे लड़ने के उपायों और साधनों का अभाव नहीं है कि 1905 की भयानक पराजय के बाद भी निराशा की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद, कई वर्षो तक, गोर्की ने प्रवासी जीवन बिताया, किन्तु इस काल में भी, जबकि वह अमेरिका तथा अन्य देशों में थे, वह सोशल-डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए ही काम करते रहे। जब वह इटली के क्रैपी में रहने गए तब भी वह निरंकुशता को उखाड़ फेंकने तथा रूसी क्रांति का मार्ग प्रशस्त करने में लगे रहे। जैसे क्रेपी में उन्होंने क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक स्कूल चलाया और क्रांतिकारी काम भी करते थे। इन्हीं सब् कारणों से गोर्की रूसी साहित्य क्षेत्र में एकाएक इतने प्रसिद्ध हो गये।

(156)प्रश्न: अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के पद पर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या चीन को युद्ध का डर सता रहा है? आखिर कैसे?

उत्तर: हाँ, कर्ण जी, अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के पद पर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद चीन को युद्ध का डर सता रहा है। ट्रंप युग शुरू होने के साथ ही चीन खौफजदा है। उसे भविष्य में अमेरिका के साथ युद्ध का डर सताने लगा है। दक्षिण चीन सागर और अन्य मुद्दों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त रूख से बीजिंग बेहद सशंकित है। इसी के मद्देनजर उसने अपनी सैन्य तैयारियाँ तेज कर दी है। पिपुल्स लिब्रेशन आर्मी ने अपनी आधिकारिक बेबसाइट के जरिए अमेरिका से संभावित युद्ध के खतरे के बारे में साफ संकेत दिए हैं। हांगकांग से प्रकाशित अखबार 'साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट' ने पिपुल्स लिब्रेशन आर्मी (पीएलए) की इस आशंका को विस्तार से छापा।

उल्लेख्य है कि वाशिंगटन में 20 जनवरी, 2017 को जब ट्रंप ने शपथ ग्रहण कर अमेरिका की कमान संभाली, पीएलए ने उसी दिन अपनी बेबसाइट पर लेख लिख युद्ध की आशंका जता दी। चीनी सेना की ओर से कहा गया कि लड़ाई की संभावना अब ज्यादा सटीक हो गई है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति बेहद जटिल होने जा रही है। पीएलए के अनुसार, पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर में सेना की तैनाती और दक्षिण कोरिया को मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस करने की अमेरिकी घोषणा से हालात विस्फोटक हो सकते हैं। युद्ध की आशंका अब वास्तविक सच्चाई में तब्दील होने जा रही है।

(157)प्रश्न: अपने वादे को पूरा करने की दिशा में अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कमान संभालने के बाद क्या अपना कदम बढ़ाया है? यदि हाँ, तो कैसे?

उत्तर: हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के पहले देश की जनता से जो वादा किया था उस वादे को पूरा करने के लिए ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के नागरिकों के वीजा पर चार माह के लिए रोक लगा दी है जिसका मतलब है कि एक बड़ी मुस्लिम आबादी के अमेरिका प्रवेश पर पाबंदी। पाक, अफगानिस्तान और सऊदी अरब निगरानी सूची में है। हो सकता है ट्रंप के आलोचक सात मुस्लिम देशों के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंध के उनके इस फैसले को

राजनीति के चश्मे से देखें, लेकिन सच्चाई ये है कि वैश्विक कूटनीति पर इसका गहरा असर पड़ेगा।

प्रतिबंध को लगाते समय ट्रंप ने कहा कि अब उन्हीं पर एतवार करना होगा जो हकीकत में अमेरिका से प्यार करते हैं। सब जानते हैं कि इस्लामी आतंकी संगठन अमेरिका और उसके नेतृत्व से बेहद नफरत करते हैं। जाहिर है कि उनके निशाने पर वाशिंगटन है। ये भी सबकी नजर में है कि दीनी तालीम के बहाने ये संगठन अमेरिका में लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। सीरिया और यमन से आ रहे शरणार्थियों की आड़ में तमाम आतंकी संगठनों ने घुसपैठ बना ली हैं।

ऐसा नहीं है कि ट्रंप के पहले का शासन इन सब बातों से वाकिफ नहीं था, पता तो तब भी था, लेकिन इस तरह का फैसला लेने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखायी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अमेरिका में रह रहे तमाम मुसलमान के अलावा दुनिया भर में इस पर प्रतिक्रिया होगी। ट्रंप ने इस सब अंदेशों को धता बताते हुए जो कदम उठाया है उससे एक खास तबके के लोग दुखी हैं। दरअसल, कबिलाई मानसिकता से लोग अब उब चुके हैं और चाहते हैं कि दुनिया में सुकून हो और इसके लिए जितने भी कड़े फैसले लेने हों, लिए जाने की जरूरत है। उल्लेख्य है कि जिन विदेशी लोगों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर और उसके बाद के हमलों को अंजाम दिया, वे कट्टरपंथी अमेरिका में पर्यटन, पढ़ाई, नौकरी आदि के लिए वीजा लेकर आए थे। कुछ ऐसे भी थे जो अमेरिका के शरणार्थी सहायता कार्यक्रम का फायदा लेकर आए थे। क्या ऐसे लोगों से सरकारों को सतर्क नहीं होना चाहिए?

(158)प्रश्नः रूस में पत्नियों के पीटने को अपराध नहीं मानना क्या परंपरावाद की ओर लौटने की सरकारी पहल का हिस्सा नहीं माना जाएगा? इससे रूसी को क्या संदेश जाएगा?

उत्तरः उपेन्द्र जी, हमारे देश भारत में तो पति द्वारा अपनी पत्नी को पीटना अपराध माना जाता है, लेकिन रूस में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ की संसद (डयूमा) ने जनवरी, 2017 के अंतिम सप्ताह में परिवार के सदस्यों के खिलाफ घरेलू हिंसा को अपराध न मानने बशर्ते वह दोबारा ना हो या गंभीर शारिरिक क्षति ना पहुँचाए, को मंजूरी दे दी है। इससे पति के द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार को वैधता मिल जाएगी। रूसी नागरिक को संदेश जाएगा कि घरेलू हिंसा अपराध नहीं है। मुझे लगता है कि रूसी संसद द्वारा घरेलू हिंसा

में किया गया यह परिवर्तन राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के तीसरे कार्यकाल में परंपरावाद *की ओर लौटने की सरकारी* पहल का हिस्सा है।

यूरोप और मध्य एशिया के तीन देशों में रूस शामिल है जिनमें घरेलू हिंसा के खिलाफ विशिष्ट कानून नहीं है। रूस के धर्मग्रंथों और रूसी परंपरा में शारीरिक दंड का उचित और स्नेहिल उपयोग अभिभावकों को ईश्वर प्रदत्त अधिकारों का आवश्यक अंग है।

पिछले वर्ष 2016 में रूसी संसद ने ऐसी घटना को अपराध ना मानते हुए घरेलू हिंसा पर अधिकतम दो वर्ष की सजा कायम रखी थी जिससे सिविल सोसाइटी समूह खुश हुए थे, लेकिन रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च ने प्रखर विरोध किया। अनुदारवादी समूहों का तर्क था कि अपने बच्चों को पीटने के लिए माता-पिता पर कठोर दंड गलत होगा। ऐसे समूहों के दबाव में सांसदों ने एक विधेयक पेश किया जिसमें अधिक नुकसान ना पहुँचाने वाली पहली घटना पर 30000 रूबल जुर्माना, सामुदायिक सेवा या 15 दिन की कैद का प्रावधान किया गया। इस अपराध को निजी अभियोजन के दायरे में लाया गया जिसमें पीड़ित पर सबूत जुटाने और मामला सामने लाने की जिम्मेदारी है। पहले अपराध के एक वर्ष के अंदर दोबारा ऐसी घटना न होने पर आपराधिक मामला चलेगा।

(159)प्रश्नः क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के नाम बदलकर नए सिरे से सक्रिय होने की सुविधा नयी नहीं है?

उत्तरः हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के नाम बदलकर नए सिरे से सक्रिय होने की सुविधा नयी नहीं है, क्योंकि वहाँ ऐसे कई संगठन हैं जो यह काम बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं। खुद जमात उत दावा पहले वह लश्कर-ए-तैयबा नाम से सक्रिय था जब उस पर पाबंदी लगी, तो नया नाम जमात उत दावा कर लिया गया। जमात उत दावा के नाम से यह स्पष्ट है कि हाफिज सईद की निगाह केवल कश्मीर पर ही नहीं, बल्कि जम्मू पर भी है, क्योंकि हाफिज सईद ने जमात उत दावा का नया नाम बदलकर तहरीक आजादी जम्मू-कश्मीर कर लिया। यह नया नाम यह भी बता रहा है कि पाकिस्तान ने अपने यहाँ पल रहे आतंकियों को किस तरह भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की खुली छूट दे रखी है। भले ही हाफिज सईद के कथित तौर पर नामजद किए जाने के बाद जमात उत दावा ने अपना नाम बदला हो, लेकिन इसके संकेत पहले ही मिल

गए थे। आश्चर्य नहीं कि इस आतंकी सरगना को दिखावे की कार्रवाई की भनक पहले ही दे दी गयी हो। यह किसी से छिपा नहीं कि उसे एक तरह की शाही नजरबंदी मिली हुई है। उसे मीडिया से बात करने के साथ ही अपने वीडियो संदेश जारी करने की भी सुविधा हासिल है। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है।

हास्यास्पद यह है कि हाफिज सईद के खिलाफ दुनिया की आँखों में धूल झोंकने वाली कार्रवाई करने के बाद भी पाकिस्तान यह उम्मीद कर रहा है कि भारत समेत विश्व समुदाय यह मान ले कि वह आतंकवाद से लड़ने के मामले में गंभीर है। हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई का भद्दा दिखावा करने वाले पर पाकिस्तान के मामले में विश्व समुदाय की सोच कुछ भी हो, किंतु भारत के लिए यह उचित यही है कि वह उसकी पैतरेबाजी की एक तमाशे के अतिरिक्त और कुछ न माने।

(160)प्रश्न: क्या अमेरिका में नौकरी पाना भारत के नागरिकों का जन्मसिद्ध अधिकार है? यदि अमेरिका अपने नौजवानों को अमेरिका में नौकरी दे रहा है, तो क्या यह भारत के प्रति अन्याय होगा?

उत्तर: नहीं, अमेरिका में नौकरी पाना भारत के नागरिकों का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। यह बात ठीक है कि अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति ने एच-1 बी वीजा की शर्ते इतनी कठिन कर दी कि भारत सहित अन्य देशों से अमेरिका जाने वाले प्रतिभाशाली लोगों को नौकरी मिलने में कठिनाई होगी, मगर यह भी तो सही है कि हर देश को अपने तरीके से, अपनी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों और सरकार के माध्यम से अपने हित में हर प्रकार का निर्णय करने का पूरा अधिकार होता है। ट्रंप अच्छे हैं या बूरे, इसका फैसला तो अमेरिकी जनता करे और इसकी कसौटी एक ही होगी-ट्रंप जो भी कर रहे हैं, वे अमेरिका के हित में है या नहीं। ट्रंप से यह अपेक्षा नहीं हो सकती कि जिन फैसलों को वे अमेरिका के हित में समझते हैं, उन्हें इसलिए रोक दें, क्योंकि उससे कुछ देशों के साथ उनके दोस्ताना संबंध बिगड़ सकते हैं।

इस दृष्टि से देखा जाए, तो यदि अमेरिका अपने नौजवानों को अमेरिका में नौकरी दे रहा है, तो यह भारत के प्रति अन्याय कतई नहीं कहा जाएगा, क्योंकि राजनीति और कूटनीति का सर्वोच्च एवं सर्वमान्य सिद्धांत एक ही होता है-मेरे अपने राष्ट्र का हित भारत भी तो सबसे पहले अपने हितों की रक्षा करता है और उसके बाद अन्य देशों के साथ संबंध बढ़ाता है। दो देशों

में अच्छे मैत्री संबंध तब होते हैं, जब उनके राष्ट्रहित तथा आपसी हित मिल जाएँ। ऐसे उदाहरणों में भारत-नेपाल, भारत-इजराइल तथा भारत-जापान संबंध गिनाए जा सकते हैं। इसलिए ट्रंप द्वारा अमेरिका के हित में किए जा रहे कदमों से परेशान न होकर भारत के तेजस्वी नौजवान नौकरी के लिए अमेरिका की ओर न देखकर अपने ही देश में ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए।

(161)प्रश्नःआतंकी सरगना हाफिज सईद की नजरबंदी के बाद उसका नाम प्रतिबंधित लोगों की सूची में शामिल करने और उसके हथियारों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई के आधार पर क्या ऐसे किसी नतीजे पर पहुँचा जा सकता है कि पाकिस्तान की आँखें खुल गई हैं और उसने आतंकियों को पालने-पोसने के काम से तौबा कर ली है?

उत्तरः पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा हाफिज सईद को देश के सुरक्षा के लिए संभावित खतरा बताने पर उनके खिलाफ पाकिस्तान में आंदोलन छेड़ दिया गया और पाकिस्तान की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और धर्मगुरुओं ने हाफिज सईद को देशभक्त करार देते हुए अपने रक्षामंत्री को भारत का भोंपू करार दिया है।

हाफिज सईद पर शिकंजा कसने के साथ ही उसकी सरपरस्तीवाले आतंकी संगठनों जयात-उद-दावा और फलाद-ए-इंसानियत पर पाबंदी लगा दी गयी है, क्योंकि ऐसे संगठन नाम बदलकर नए सिरे से सक्रिय होने के लिए कुख्यात हैं। उल्लेख्य है कि हाफिज सईद पहले भी कई बार नजरबंद हो चुका है। आतंक के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई को केवल हाफिज सईद तक सीमित करने का कोई मतलब इसलिए नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में हाफिज सईद सरीखे तत्वों की तो पूरी फौज है। कायदे से तो यह होना चाहिए था कि मुंबई के हाफिज सईद जैसे गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई हुए बगैर उस पर भरोसा नहीं किया जाता, लेकिन ऐसा किया गया जिसका यही परिणाम हुआ कि गुरदासपुर, पठानकोट और उड़ी में भीषण आतंकी हमले देखने को मिले।

इसके मद्देनजर आतंकी सरगना हाफिज सईद की नजरबंदी के बाद उसका नाम प्रतिबंधित लोगों की सूची में शामिल करने और उसके हथियारों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई के आधार पर ऐसे किसी नतीजे पर नहीं पहुँचा जा सकता कि पाकिस्तान की आँखें खुल गई हैं और उसने

आतंकियों को पालने-पोसने के काम से तौबा कर ली है। पाकिस्तान की हालिया कार्रवाई दुनिया की आँखों में धूल झोंकने की एक और कोशिश भर है। यह कोशिश नई नहीं है।

उल्लेख्य है कि कूटनीतिक मामलों में जल्दबाजी के लिए कोई स्थान नहीं होता और पाकिस्तान के संदर्भ में तो और भी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान से रिश्तों के मामले में भारत को अपनी उन भूलों से सबक लेना चाहिए जो उसने अतीत में की। कई धोखे खाने के बाद सतर्कता को अति सतर्कता में तब्दील करने की जरूरत है। जबतक पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत को नुकसान पहुँचाने पर आमादा आतंकी संगठनों को सहयोग-समर्थन देना बंद नहीं करती, तबतक यह नहीं माना जा सकता कि पाकिस्तान सही राह पर आ गया है।

वैसे भी अबतक हाफिज सईद पर किसी प्रकार की प्राथमिकी दर्ज होने की सूचना नहीं है। इस तरह उसके खिलाफ सख्ती तो नजर आती है, मगर जबतक मुकदमा न दर्ज हो, आरोप पत्र न दायर हो, तबतक कुछ भी कहना मुश्किल है।

(162)प्रश्नः क्या पाकिस्तान ने अपनी मुश्किलें खुद नहीं बढ़ाई हैं?

उत्तरः हाँ, मनोज जी, पाकिस्तान ने अपनी मुश्किलें खुद ही बढ़ाई हैं। यदि पाक के इतिहास के पन्नों पर जब हम नजर डालते हैं तो पाते हैं कि लीगी अपसंस्कृति से उपजे एक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान कभी भी उन प्रतिमानों से खुद को दूर नहीं कर पाया जिनके जरिया मोहम्मद जिन्ना एक बड़ी आबादी के साथ षड्यंत्र रचकर भारत का विभाजन कराने में सफल हो गए थे। पाकिस्तान बनने के बाद उन तत्वों का प्रकटीकरण कभी रावलपिंडी के मार्शलों द्वारा हुआ, कभी लोकतंत्र के नुमाईदों द्वारा, तो कभी या प्रायः जिहादियों द्वारा जिसका नतीजा यह हुआ कि कभी भारत का एक अहम हिस्सा रहा पाकिस्तान आज एक अनिश्चित और आतंकवादी राष्ट्र के रूप में नजर आ रहा है।

दरअसल, प्रारंभ से ही पाकिस्तानी सेना और चरमपंथी गठजोड़ भारत के खिलाफ गतिविधियों में सक्रिय रहा। जिनमें से एक पाक सेना भारत को दुश्मन नंबर एक मानती है, जबकि वहाँ के चरमपंथी भारत को सनातन शत्रु के रूप में पेश करते हैं, किंतु अब इसका परिणाम उसे भुगतना पड़ रहा है और वह पाक के लिए घातक सिद्ध हो रहा है।

पिछले दिनों 21 फरवरी, 2017 को ही पाकिस्तान के चारसद्दा

जिले में तीन बम धमाके हुए जिसमें सात लोगों की मौत हो गई। इसके पूर्व सिंध प्रांत के सेहवान कस्बे में स्थित सूफी संत लाल शाहबाज कलंदर की दरगाह पर हुए भीषण आतंकी हमले में तकरीबन 100 लोग मारे गए थे।

पिछले कुछ दिनों की घटनाओं पर नजर डालें, तो पाकिस्तान के सिंध, लाहौर, पेशावर, फाटा और क्वेटा से लेकर सिंध प्रांत के सेहवान तक आतंकी हमलों का एक ऐसा सिलसिला दिखेगा जो किसी भी देश की अंतरात्मा को झकझोर सकता है। दरगाह पर हमले के बाद पाकिस्तानी सेना की तरफ से कुछ आतंकी कैंपों पर कार्रवाई की गई, जिसमें मुख्य रूप से अफगानिस्तान में सक्रिय चरमपंथी संगठन जमात-उल-अहरार के प्रशिक्षण शिविर और चार कैंपों को तबाह किया गया है। सच तो यह है कि पाक सेना के पूर्व जनरल राहील शरीफ हों या वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल कमर बाजबा सभी ने कहा है कि चरमपंथ देसी खतरा है, ना कि विदेशी, जबकि पाक सरकार अपने मूल्क में हो रही आतंकी वारदातों के लिए चरमपंथी संगठनों की बजाय भारत या फिर अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करती रही है। यही वजह है कि दिसंबर, 2014 में पेशावर के सैनिक स्कूल में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी सेना द्वारा शुरू किए गए सैन्य आपरेशन 'जर्ब-ए-अज्ब' ने आरंभ में चरमपंथियों की कमर तोड़ने में कुछ हद तक कामयाबी पाई थी, लेकिन कुछ ही दिन बाद परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने अपनी मुश्किलें खुद बढ़ाने का काम किया है जिसका खामियाजा उसे आज भुगतना पड़ रहा है।

अब तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने की माँग उठ रही है। इससे पाकिस्तानी सेना और सरकार में भय है, क्योंकि आर्थिक प्रतिबंध के बाद सेना के लिए जरूरी 10 अरब डॉलर के बजट का इंतजाम भी मुश्किल होगा। यही नहीं आर्थिक प्रतिबंध के बाद पाकिस्तान को वार अंगेस्ट टेरर के नाम पर मिलने वाली जरूरी सैन्य सहायता भी बंद हो जाएगी। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों को संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 1267 के तहत प्रतिबंधित किया जा रहा है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा हाल में भारत के साथ दोस्ताना संबंध बनाने को जो ताजा बयाना दिया गया उसकी केवल अनदेखी ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके बहाने पाकिस्तान को नए सिरे से आईना भी दिखाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान नए-नए बहाने बनाने में माहिर है और

नवाज शरीफ तो इसमें पारंगत हो चुके हैं। कारण कि अब वह कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रची जा रही है। पाकिस्तान की ओर से जब भी ऐसा कहा जाता है तो इसका मतलब होता है कि भारत अफगानिस्तान का उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। आखिर पाकिस्तान को ऐसा क्यों लगता है कि अफगानिस्तान को अपने भले-बुरे की कोई समझ नहीं है?

(163) प्रश्नः पूँजीवाद के आराधकों का दावा है कि पूँजीवादी राष्ट्रों की दीवारों को गिराने के साथ ही लोगों के जेहन में बनी धर्म, जाति, नस्ल, सम्प्रदाय और रंगभेद की गाँठों को भी खत्म कर देती है, लेकिन अमेरिका के मामले में क्या यह दावा बार-बार गलत नहीं साबित हो रहा है? इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार हैं और क्यों?

उत्तरः हाँ, पूँजीवाद के आराधकों का दावा है कि पूँजीवादी राष्ट्रों की दीवारों को गिराने के साथ ही लोगों के जेहन में बनी धर्म, जाति, सम्प्रदाय, नस्ल और रंगभेद की गाँठों को भी खत्म कर देती है, लेकिन अमेरिका के मामले यह दावा बार-बार गलत साबित होता जा रहा है। इस स्थिति के लिए वहाँ का राजनीतिक तबका जिम्मेदार है, जो अपने देश के बाहर तो अपने को खूब उदार बताता है और दूसरों की भी उदार बनने का उपदेश देता है, लेकिन अपने ही देश के भीतर व्यवहार के स्तर पर वह कठमुल्लेपन को पालने-पोसने का काम करता है।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि न्यूयॉर्क के विश्व व्यापार केंद्र (World Trade Centre) पर 9/11 को किए गए हमले के बाद अमेरिका ने अपनी सरजमीं पर दूसरा कोई बड़ा आतंकवादी हमला नहीं होने दिया और उस हमले का सबसे बड़े सूत्रधार ओसामा बिन लादेन को मौत की नींद सुला दिया, जो कि उसकी एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन बाहरी खतरों से अपने को महफूज रखने की कोशिशों के चलते उसने अपने यहाँ के नस्लवादियों और उनकी गतिविधियों को जिस तरह नजरअंदाज किया है वह न सिर्फ उसके लिए, बल्कि दुनिया के उन मुल्कों के लिए भी बेहद खतरनाक है जिनके नागरिक बड़ी संख्या में अमेरिका में बसे हैं।

अमेरिका में हो रहे रंगभेद का तो मैं स्वयं चश्मदीद गवाह हूँ, क्योंकि विगत 2007 में अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के सभागार में आयोजित आठवें विश्व हिंदी सम्मेलन में बिहार सरकार की ओर

से भारतीय प्रतिनिधिमंडल में मैं शामिल हुआ था, तो मुझे वहाँ यह देखने को मिला कि कुछ अश्वेत नागरिक फटे-चिटे कपड़े में कूड़ेदान में पड़े पावरोटी तथा खाने की कुछ अन्य चीजों को निकालकर खाए जा रहे थे। उनकी माली हालत देखकर सहज रूप से यह अंदाजा लगाया जा सकता है और यह विरोधाभास देखकर किसी को भी हैरानी होगी कि एक तरफ तो अमेरिकी नागरिक समाज इतना जागरूक, उदार और न्यायप्रिय है कि बराक ओबामा जैसे एक अश्वेत को दो-दो बार राष्ट्रपति चुनता है, वहीं दूसरी ओर उसके भीतर नस्ली और रंगभेद दुराग्रह की हिंसक मानसिकता और नफरत आज भी जड़ें जमाए बैठी हैं।

दुनिया भर में नस्लवाद की शह पर चलने वाला साम्राज्यवाद भले ही अतीत के पन्नों में सिमटकर रह गया हो, पर मानसिकता के स्तर पर यह अमानवीय दुराग्रह आज भी जारी है, क्योंकि मैंने स्वयं अपनी खुली आँखों देखा है वहाँ के अश्वेत नागरिकों की माली हालत को जिससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ आज भी नस्लभेद और रंगभेद की मानसिकता बरकरार है।

अमेरिका अपने को लोकतंत्र, सामाज़िक न्याय, मानवाधिकार और धार्मिक आजादी का सबसे बड़ा हिमायती मानता है और दुनिया के दूसरे मुल्कों को भी इस बारे में सीख देता रहता है, लेकिन उसके यहाँ जारी नस्लीय नफरत, रंगभेद और हिंसा की घटनाएँ उससे अपने गिरेबां में झांकने की माँग करती हैं जिसके बारे में वहाँ के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सोचना-विचारना चाहिए।

जब बराक ओबामा पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे, तो दुनिया भर में यह माना गया था कि यह मुल्क अपने इतिहास के नस्लभेद और रंगभेद की खाई को पाट चुका है। दरअसल, ओबामा के रूप में एक अश्वेत व्यक्ति को दुनिया के इस सबसे ताकतवर मुल्क का बनना ऐसी युगांतरकारी घटना थी, जिसका सपना मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 20वीं शताब्दी में देखा था और जिसको हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने जीवन भर अहिंसक संघर्ष किया था। बराक ओबामा का राष्ट्रपति बनना एक तरह से मार्टिन लूथर किंग के अहिंसक संघर्ष की परिणति थी, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि ओबामा के कार्यकाल में भी नस्लवादी और रंगभेदी नफरत में कोई कमी नहीं आई, बल्कि सच तो यह है कि अमेरिका में नस्लीम अपराध उफान पर है। अभी हाल में एक भारतीय इंजीनियर की

हत्या उसी का परिणाम है। यही नहीं कभी वहाँ के किसी गुरुद्वारे पर हमला किया जाता है तो कभी किसी सिख अथवा दक्षिण-पश्चिम एशियाई मूल के किसी दाढ़ीधारी मुसलमान को आतंकवादी मानकर हमला कर दिया जाता है। कभी किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को ट्रेन के आगे धक्का देकर मार दिया जाता है। आखिर तभी तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी कहना पड़ा कि नस्लीय भेदभाव अमेरिका के डीएनए में है। एक नस्लीय घटना के बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी नस्लीय मानसिकता से अभी तक नहीं उभरा है और आज भी यहाँ नस्लवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं।

दुनिया को बड़ी शान से ग्लोबल विलेज बताने वालों से पूछा जाना चाहिए कि इतनी अजनबियत और नफरत से भरा यह कैसा विश्व गाँव है? राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र काँग्रेस के समक्ष राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की साफगोई, ईमानदारी और दृढ़ता इस बात का प्रमाण है कि अमेरिका को फिर से महान बनाने की जिस नारे से वह चुनकर आए थे, उस तक पहुँचने के लिए यह जाहिर था कि पहले वह उन कमियों को गिनाएँ जिन्हें खुद अमेरिकी ही भूल चुके थे। ट्रंप तो वही कर रहे हैं। वह अमेरिका को नुकसान पहुँचाने वाले हर एक मसले पर बोले और फिर से यह साफ कर दिया कि वह केवल अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, पूरी दुनिया के नहीं, इसलिए दुनिया भर को सुधारने की ठेकेदारी उनकी नहीं है। कहना नहीं होगा कि ट्रंप की यह नीति अब तक के राष्ट्रपतियों से अलग है।

ट्रंप के भाषण से यह स्पष्ट है कि अमेरिका में भी वे सारी कमियाँ जस की तस हैं, जिनके लिए कभी विकासशील देशों को पिछड़ा और गंवार बताया जाता था। अगर यही सच है, तो अब तक अमेरिका डॉलर के चक्कर में देश छोड़ने वालों के लिए संदेश यह है कि क्यों न वे अमेरिका जाने का लालच छोड़ अपने ही देश में रुकें, अपना हुनर दिखाएँ और राष्ट्र निर्माण में सहायक हों।

(164) प्रश्न: क्या आपको ऐसा लगता है कि चीन भले ही पाक समर्थित आतंकियों को वैश्विक परिदृश्य में नजरअंदाज करता रहा हो, लेकिन अब वह खुद भी इस्लामिक आतंकवाद के खतरे से जूझ रहा है? आखिर कैसे?

उत्तर: हाँ, हमें भी ऐसा लगता हैं कि चीन भले ही पाक समर्थित आतंकियों को वैश्विक परिदृश्य में नजरअंदाज करता रहा हो, लेकिन अब वह खुद भी इस्लामिक आतंकवाद के खतरे से जूझ रहा है, क्योंकि भारत

में बड़े-बड़े आतंकी घटनाओं में शामिल जैश-ए-मोहम्मद के खूँखार सरगना मसूद अजहर पर प्रतिबंध के मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रोड़े अटकाने वाले चीन को भी आतंकियों से आर-पार की जंग की धमकी मिल रही है। दुनिया के सबसे दुर्दांत आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने चीन को आर-पार की जंग की धमकी दे दी है।

दरअसल, आईएस यह चीन में शोषित उइगुर टेर्रिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के आतंकियों के हाथ मिलाने के बाद किया है। इस्लामिक स्टेट के बनाए नवीनतम प्रोपगंडा वीडियों में आतंकियों ने कहा है कि जल्द ही चीन की नदियों में खून बहेगा। गौरतलब है कि चीन के जिनजियोंग प्रांत में उइगर मुसलमानों की आबादी लंबे समय से सामान्य अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। उन्हें अपनी धार्मिक चिह्नों को सार्वजनिक करने, बुर्का पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने जैसी छूट नहीं है। धार्मिक मामलों में सरकारी प्रतिबंधों का विरोध धीरे-धीरे विद्रोह का रूप ले लिया। आईएस ने इस विद्रोह का फायदा उठाते हुए उइगर मुसलमानों के युवा वर्ग को भड़काकर अपने साथ ले लिया। अब तो स्थिति यह आ गई है कि वीडियो में जिनजियांग प्रांत की जमीन को उइगरों के खून से लाल करने की बात भी कही जा रही है। वीडियो में चीन की काम्युनिस्ट पार्टी और सरकार के बारे में जहर उगला गया है। वीडियों में पुनः कहा गया है कि लंबी प्रताड़ना के चलते आँखों से जो आँसू बहे हैं, हम उनके बदले ऊपरवाले की मर्जी से चीन की नदियों में खून बहाएँगे।

(165)प्रश्नः जैसा कि चीन का संकेत है कि अगर भारत उसे अरुणाचल का त्वांग वाला हिस्सा लौटा दे, तो वह अक्साई चिन पर कब्जा छोड़ सकता है। क्या सामरिक नजरिए से त्वांग को चीन को देना भी भारत के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं होगा?

उत्तरः हाँ, राज चतुर्वेदी जी, जैसा कि चीन ने कई बार ऐसा संकेत दिया है कि अगर भारत उसे अरुणाचल का त्वांग वाला हिस्सा लौटा दे, तो वह अक्साई चिन पर कब्जा छोड़ सकता है, मगर सामरिक नजरिए से त्वांग को चीन को देना भारत के लिए अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, क्योंकि असल में चीन अरुणाचल को तिब्बत से अलग करने वाली मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है और त्वांग को अपना हिस्सा बताता रहा है। त्वांग भारत चीन सीमा के पूर्वी सेक्टर का सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण इलाका है।

त्वांग के पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत है। सन् 1962 में चीनी सेना ने त्वांग कब्जा करने के बाद उसे खाली कर दिया था, क्योंकि वह मैकमोहन रेखा के अंदर पड़ता था। लेकिन इसके बाद से चीन त्वांग पर यह कहते हुए अपना हक जताता रहा है कि वह मैकमोहन रेखा को नहीं मानता।

दूसरी तरफ पश्चिमी सेक्टर में लद्दाख और अक्साईचिन का इलाका है। अक्साईचिन कश्मीर का हिस्सा रहा है, इसलिए कश्मीर का भारत में विलय के बाद यह इलाका भारत का है, लेकिन चीन अक्साईचिन को अपने शिनत्यांग प्रदेश का इलाका बताता है। भारत का कहना है कि चीन ने 1962 की लड़ाई में अक्साईचिन के 38 हजार वर्गमील इलाके पर कब्जा कर लिया था। इस दृष्टि से देखा जाए तो यह सौदेबाजी की भी लिहाज से भारत के पक्ष में नहीं है। त्वांग का भारत के लिए सामरिक महत्व है। दूसरा कि एक मानव बहुल इलाका के बदले बर्फीले स्थान का भारत समझौता क्यों करेगा?

(166)प्रश्नः कश्मीर के त्राल में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान जम्मू-कश्मीर के पुलिस के सिपाही मंजूर अहमद ने अपने प्राणों की आहूति देकर जिस बहादुरी के साथ आतंकियों का मुकाबला किया उससे क्या उन लोगों की आँखें नहीं खुल जानी चाहिए, जो इस मुठभेड़ के दौरान पत्थरबाजी कर रहे थे?

उत्तरः हाँ, कश्मीर के त्राल में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान जम्मू-कश्मीर पुलिस के सिपाही मंजूर अहमद ने अपने प्राणों की आहूति देकर जिस बहादुरी और दिलेरी के साथ आतंकियों का मुकाबला किया उससे निश्चित रूप से उन लोगों की आँखें खुल जानी चाहिए, जो इस मुठभेड़ के दौरान पत्थरबाजी कर रहे थे। मंजूर अहमद की शहादत यही बताती है कि आतंकियों के समर्थक, पत्थरबाज एवं अन्य ऐसे ही तत्व किस हद तक गुमराह हो चुके हैं। सचमुच यह चिंता की बात है कि कश्मीर घाटी में ऐसे गुमराह तत्वों की संख्या भी बढ़ रही है और उनका दुस्साहस भी।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग कश्मीर घाटी का सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से नेतृत्व कर रहे हैं वे गुमराह हो चुके कश्मीरी युवाओं को समझाने की बजाय आग से खेलने में लगे हुए हैं। कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला जैसे मौकापरस्त नेताओं की कमी नहीं। आपको याद होगा फारूक अब्दुल्ला ने अपने एक बयान में एक तरह से आतंकियों के समर्थकों और पत्थरबाजों को प्रोत्साहित करते हुए यह कहा था कि कश्मीरी नौजवान कुर्सी

के लिए नहीं अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। दरअसल, कश्मीर के राजनीतिक दल जब सत्ता में होते हैं तो अलग सुर में बात करते हैं और जब विपक्ष में होते हैं तो अलग सुर में। यदि कश्मीर के नेता अपने लोगों के भविष्य के प्रति तनीक भी फिक्रमंद हैं तो उन्हें कश्मीर को अशांति उपद्रव और हिंसा के दुष्चक्र से निकालने के लिए आगे आना होगा और कश्मीर के लोगों को यह समझाना होगा कि हुर्रियत कॉंफ्रेंस के नेता गिलानी जैसे लोग किस तरह उन्हें अँधेरी सुरंग में धकेलकर अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। आपने देखा नहीं था कि गिलानी के पौत्र को नियमों में ढील देकर नौकरी दी गई थी।

(167)प्रश्नः क्या भारतीयों की सुरक्षा अमेरिका में अब पर्याप्त है?

उत्तर: दो देशों के बीच संबंध और एक दूसरे के नागरिकों की सुरक्षा का जिम्मा दोनों देशों की सरकारों का होता है। ऐसे में अमेरिका की ट्रंप सरकार और उसके प्रशासन को खास ध्यान देना होगा कि वह अपने खास कूटनीतिक मित्र भारत के नागरिकों की रक्षा कैसे सुनिश्चित करेगा। पहले अमेरिका के कंसास राज्य में दो भारतीयों पर नस्लभेदी हमला हुआ जिसमें एक इंजीनियर की मौत हो गई। इसके बाद दो और भारतीय मूल के व्यक्ति पर हमला किया गया। इसी प्रकार वाशिंगटन में सिख समुदाय के एक युवक को गोली मारी गई। निश्चित तौर पर इससे अमेरिकी समाज को ही नुकसान नहीं पहुँचेगा, बल्कि सच तो यह है कि इन हमलों से अमेरिका के दूसरे देशों से संबंध भी खराब हो सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि अमेरिका की 99 प्रतिशत आबादी माइग्रेंट हैं। खुद ट्रंप के पूर्वज भी जर्मनी से आए थे और उनकी तीसरी पत्नी यूरोप से है। एशियन मूल के लोग तो पूरी अमेरिकी आबादी के 5 प्रतिशत ही हैं जिनमें से भी 35 प्रतिशत एशियन मूल के लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया। इसमें तनीक संदेह नहीं कि ट्रंप की राजनीति अमेरिका में एक तरह के राष्ट्रवाद को बढ़ा रही है, जिसमें नफरत की जगह है। यह राष्ट्रवाद अमेरिका को यूरोप की तरफ ले जा रहा है और यूरोप में भी ट्रंप के विचारों वाली राष्ट्रवादी ताकतें उभर रही हैं जिस तरह से नस्लभेदी हिंसा ट्रंप के अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने पर बढ़ी है वह अमेरिकी समाज के लिए भी खतरा है, क्योंकि अमेरिकी समाज उदार रहा है। मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में भारत अमेरिका का नजदीकी सहयोगी बना है जिसकी वजह से रूस से दूरी भी बढ़ी है, लेकिन जिस तरह से भारतीय मूल के खिलाफ

अमेरिका में हमले हो रहे हैं वो हमारे लिए तो चिंताजनक है ही, इससे भारत के संबंधों पर भी असर पड़ेगा। भारत के विदेश सचिव की हाल में हुई अमेरिकी यात्रा और फिर आगे आने वाले दिनों में भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा के दौरान इस मसले पर गंभीरतापूर्वक विचार-विमर्श दोनों देशों के बीच होगा और मुझे पूरी उम्मीद है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत से बिगड़ते संबंध पर गौर करेंगे और शीघ्र ही भारतीयों की सुरक्षा के उपाय निकालेंगे।

(168)प्रश्नः क्या आपको ऐसा लगता है कि फरवरी-मार्च, 2017 के पाँच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद पड़ोसी देश चीन को डर सता रहा है? क्यों?

उत्तरः हाँ, पाँच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद चीन को डर सता रहा है। खास तौर पर उत्तरप्रदेश और उत्तराखण्ड में भाजपा की बड़ी जीत से चीन को डर है कि यह जीत चीन के साथ भारत के संबंधों के लिए अनुकूल नहीं है। इस जीत से मजबूत हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अब कड़े कदम के कार्यक्रमों पर आगे बढ़ेंगे जो चीन-भारत के संबंधों के लिए अच्छा नहीं होगा।

सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी लिखा है कि सबसे बड़े राज्य उत्तरप्रदेश में हुई भाजपा की बड़ी जीत का असर भारतीय राजनीति पर भी पड़ेगा। इससे नरेन्द्र मोदी को 2019 में एक और कार्यकाल मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। इन दिनों जबकि भारत और चीन संबंध जटिल और संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं, तब मोदी की सत्ता पर पकड़ का मजबूत होना स्थिति को और ज्यादा मुश्किल बना सकता है। रिपोर्ट में भी कहा गया है कि मोदी ने विवादित मामलों को लेकर राय कायम करने की परंपरा शुरू की है और इसके बीच अपने देश का फायदा देखा है।

(169)प्रश्नः क्या आप मानते हैं कि आतंकी डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल में सुरक्षा एजेंसियों से आगे निकल चुके हैं? आखिर कैसे?

उत्तरः हाँ, मैं मानता हूँ कि आतंकी डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल में सुरक्षा एजेंसियों से आगे निकल चुके हैं, क्योंकि एक तरफ सीआईए, एम-15,एम-16 जैसी खुफिया एजेंसियों ने अरबों टेलीफोन और अन्य डिजिटल तकनीक को एक साथ सर्विलांस पर ले रखा है, तो दूसरी तरफ

आतंकी टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक जैसे डिजिटल एप्लिकेशन का बेहतर इस्तेमाल कर सुरक्षा एजेंसियों की आँखों में धूल झोंक रहे हैं। इसी डिजिटल तकनीक से आतंकियों ने यूरोप और अमेरिका में अपने कैडर तैयार कर लिए हैं। इससे तो स्पष्ट जाहिर होता है कि आतंकी डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल में सुरक्षा एजेंसियों से आगे निकल चुके हैं।

(170)प्रश्न: क्या आपको ऐसा लगता है कि दैनिक जीवन में इस्तेमाल किए जाने वाले चीजों से लोगों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर प्रोपगंडा हासिल करना आतंकी संगठनों की नई रणनीति है? आखिर कैसे?

उत्तर: हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि दैनिक जीवन में इस्तेमाल किए जाने वाले चीजों से लोगों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर प्रोपगंडा हासिल करना आतंकी संगठनों की नई रणनीति है। लंदन हमले ने आतंकी की रणनीति को लेकर कुछ नए खुलासे किए हैं। यूरोप में हमले के लिए अब एशिया और अफ्रीका से आतंकी भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आतंकी संगठनों के पास यूरोप में ही कैडर उपलब्ध है।

लंदन में हुए हाल के हमले में आतंकी हमलों के नए तरीकों को अपनाया गया था। पिछले साल 2016 में ही इस्लामिक स्टेट के मैगजिन रूमियाह में आईएस ने अपने कैडरों से अपील की थी कि यूरोप में आईएस के कैडर हमलों में चाकू और गाड़ियों का इस्तेमाल करें। यह काफिरों को मारने में ज्यादा से ज्यादा मदद करेगा। अब हाल ही में शोध से पता चला है कि यूरोप के अंदर हुए खतरनाक हमलों में 44 प्रतिशत मामलों में चाकू का इस्तेमाल किया गया है। वहीं पिछले एक साल में तीन बड़े आतंकी हमले यूरोप में हुए और तीनों में गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। पिछले साल 2016 में फ्रांस में एक बड़ी लॉरी का इस्तेमाल आतंकियों ने लोगों को मारने के लिए किया। फ्रांस के नीस में जुलाई महीने में एक लॉरी से 86 लोगों को इस्लामिक स्टेट के आतंकी ने मारा था। इसके बाद दिसंबर महीने में बर्लिन में आतंकियों ने गाड़ी से 12 लोगों को मारा। अब यही तरीका लंदन में हाल में अपनाया गया। पहले गाड़ी को भीड़ पर चढ़ाया और उसके बाद एक पुलिस अधिकारी पर हमला किया। आतंकियों का यह नया तरीका है जिसमें भीड़भाड़वाले इलाकों में विस्फोट करने की बजाय गाड़ियों को घुसा कर लोगों को मारा जा रहा है।

इस प्रकार देखा जा रहा है कि इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसियों ने जैसे-जैसे आतंक फैलाने के तरीकों को रोकने के लिए उपाय किए हैं, आतंकी नए तरीकों को ढूँढ़ने में सफल रहे हैं। हाल ही में अमेरिका ने दुनिया के कुछ देशों से आने वाले फ्लाइटों पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर सवार करने पर रोक लगा दी है, क्योंकि आतंकी इन गैजटों को इस्तेमाल धमाकों में कर सकते हैं, लेकिन आतंकी इतने खतरनाक हो चुके हैं कि वे यूरोप की धरती पर बिना किसी बारूद और गोले के नए तरीकों से हमले कर रहे हैं।

(171)प्रश्नः दक्षिण चीन सागर पर बढ़ता तनाव क्या खतरनाक हो सकता है? आखिर क्यों?

उत्तरः हाँ, पल्लवी, दक्षिण चीन सागर पर बढ़ता तनाव खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से दक्षिणी चीन सागर का विवाद काफी तनावपूर्ण रूप ले चुका है। चीन इसे लेकर काफी आक्रामक रूख अख्तियार कर चुका है। एक ओर जहाँ बाकी देश इस मुद्दे पर चीन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चीन दक्षिण चीन सागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने और यहाँ अपना सैन्य ढाँचा मजबूत करने में काफी तेजी दिखा रहा है। चीन ने पिछले तीन साल के दौरान दक्षिण चीन सागर में 3200 एकड़ की अतिरिक्त जमीन जोड़ी है।

विदित हो कि दक्षिण चीन सागर पर कई देश अपना अधिकार जताते हैं। इस मसले की वजह से अमेरिका और चीन के आपसी संबंधों में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल, प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से दक्षिण चीन सागर काफी संपन्न इलाका है। समुद्री मार्ग से होने वाले अंतरराष्ट्रीय कारोबार के लिए भी यह बेहद अहम मार्ग है। चीन इसके ज्यादातर हिस्से को अपना बताता है। ब्रुनेई, मलएशिया, फिलीपीन्स, ताइवान और वियतनाम भी इसके कई हिस्सों पर अपना दावा जताते हैं। चीन किसी भी परिस्थिति के मद्देनजर खुद को तैयार करने के लिए लगातार अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने में लगा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय आलोचना के बावजूद चीन ने यहाँ अपना निर्माण बंद नहीं किया है।

अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों का हवाला देते हुए अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में अपने कई जहाज और विमान भेजे हैं। इसके कारण अमेरिका और चीन के संबंधों में और तनाव पैदा हो गया है। अगर शीघ्र ही चीन इस मसले में सही रूख नहीं अपनाता है, तो यह तनाव इस पूरे क्षेत्र के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।

(172) प्रश्न: क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत ने मानक और *भरोसे के मामलों में चाइनीज उत्पादों को काफी पीछे* छोड़ दिया है? इसके क्या कारण हैं?

उत्तर: हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि भारत ने मानक और भरोसे के मामलों में चाइनीज उत्पादों को काफी पीछे छोड़ दिया है जिसकी कई वजहें हैं। एक तो चीन में लेबर कॉस्ट सस्ता है। इसके अलावा वो अपने उत्पाद में हमेशा घटिया कच्चे माल का इस्तेमाल करता रहा है। इसके ठीक विपरीत मेड इन इंडिया में गुणवत्ता, डिजायन, टेक्नोलॉजी, टिकाऊपन या कीमत के स्तर पर कोई समझौता नहीं किया गया। इन सबसे ऊपर नरेन्द्र मोदी को मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया को लेकर दुनिया भर में किया गया प्रचार अब रंग दिखाने लगा है। बाजारवाद का दौर है। जो बिकता है उसकी तूती बोलती है। उपभोक्ता को अब समझ में आ गया है कि मेड इन चाईना बेशक सस्ता जरूर है, लेकिन गुणवत्ता के स्तर पर मेड इन इंडिया से उसका कोई मुकाबला नहीं है। यह बात तो 47 देशों के संगठन मेड इन कन्ट्रीज इंडेक्स और यूरोपीय यूनियन की एक रिसर्च रिपोर्ट में कही गयी है। इस रिपोर्ट में भारत को 36 पॉइंट्स मिले हैं जबकि चीन को 28 अंक दिए गए हैं।

चीनी उत्पादों के साथ यही एक समस्या है कि वे सस्ते जरूर हैं, मगर भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता के सामने टिक नहीं पाते। कुछ साल पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब चीन में निर्मित चीजों को उतारा गया तो ग्राहक को चीजें समझ में नहीं आईं। उसने सस्ता देख हर चीन की बनी चीजों को हाथों हाथ लिया, लेकिन कुछ ही दिन बाद वो मानक की कसौटी पर खारिज होने लगीं। ग्राहक समझ गया कि सूरत से अच्छी दिखने वाली चीनी चीजें वैसी हैं नहीं।

यह भारत के लिए एक सुखद अहसास है। यह देश भारत है और इसकी अपनी एक मजबूत साख है, क्योंकि भारत के उत्पादों ने मानक और भरोसे के मामलों में चीन में निर्मित उत्पादों को बहुत पीछे छोड़ दिए हैं।

(173) प्रश्न: कट्टरपंथ और आतंकवाद के विरूद्ध लड़ने के लिए भारत का उदारवादी मुसलमान चुप क्यों है?

उत्तर: भाई मदन जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत का मुसलमान तमाम इस्लामी मुल्कों की तुलना में काफी उदार है और यही कारण है कि भारत का माहौल अलग है। इसके विपरीत पड़ोसी देश पाकिस्तान के

बलूचिस्तान प्रांत में हजारों शिया मुसलमान मारे जा रहे हैं। इस्लाम के नाम पर उग्रवादियों एवं आतंकवादियों ने गैर-मुस्लिमों को ही नहीं तमाम मुस्लिम समुदायों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है।

मगर, भारत की मिट्टी में ही कुछ ऐसा है कि जमालुद्दीन अफगानी जैसे मुस्लिम विचारक ने, जो साम्राज्यवाद के विरूद्ध संघर्ष करने के लिए सर्व इस्लामावाद का नारा देकर दुनिया के मुसलमानों को एक करना चाहता था, भारत के मामले में अपना विचार बदला। भारत के मुसलमानों के लिए उसका संदेश था कि वे हिंदुओं के साथ मिलकर राष्ट्रीय एकता स्थापित करें। इसी प्रकार अमीर खुसरो भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति से भलि-भाँति परिचित था। खुसरो वह पहला व्यक्ति था जिसने प्रचलित जनभाषा में रचना करके हिंदी और उर्दू के भविष्य की राह खोल दी। उसे खड़ी बोली हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं का पिता माना जा सकता है। मगर दुख की बात है कि अमीर खुसरो की परंपरा आज विलुप्त सी दिखती है। इस्लामी संसार में निरंतर चल रही हिंसा का प्रभाव भारत पर भी पड़ना स्वाभाविक है।

दुनिया में जेहादी कट्टरता और हिंसा को समाप्त करने के लिए आज जरूरत है उदारवादी मुस्लिम नेतृत्व की। अमीर खुसरो रहीम और दाराशिकोह के मुल्क में उदारवादी परंपरा अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन आखिर कट्टरपंथ और आतंकवाद के विरूद्ध लड़ने के लिए भारत का उदारवादी मुसलमान चुप क्यों है? यह सवाल उठना स्वाभाविक है। इस्लाम को आतंकी हिंसा से जोड़कर उसे बदनाम करने वालों के विरूद्ध आम मुसलमान क्यों नहीं बोलता? भारतीय मुसलमान से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अमीर खुसरो, रहीम और दाराशिकोह की परंपरा का निर्वाह करते हुए इस्लाम को बदनाम करने वाले कट्टरपंथियों के विरूद्ध संघर्ष करने के लिए उदारवादी सोच के साथ आगे आएँ। इस्लाम को बदनाम करने वालों से इस्लाम की रक्षा उदारवादी आम मुसलमान ही कर सकता है।

(174)प्रश्नः उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के आखिरी दिन लखनऊ में एटीएस से मुठभेड़ में आईएस से जुड़े आतंकी मोहम्मद सैफुल्ला के मारे जाने पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि देश में वैश्विक आतंकवाद की सक्रियता का संदेह बढ़ा है? ऐसा क्यों?

उत्तरः हाँ, 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी दिन 8 मार्च को लखनऊ में एटीएस से मुठभेड़ में आईएस से जुड़े आतंकी

मोहम्मद सैफुल्ला के मारे जाने पर मुझे भी ऐसा लगता है कि इस देश में खासतौर पर हिंदी भाषी राज्यों में वैश्विक आतंकवाद की सक्रियता का संदेह बढ़ा है, क्योंकि सैफुल्ला के मारे जाने के बाद उस खतरे की ओर भी निगाहें उठने लगी हैं, जो सीरिया में इस्लामिक स्टेट (आईएस) के कमजोर होने के साथ भारत में भी खतरा मंडराने लगा है।

पिछले दिनों भोपाल-उज्जैन पैसेंजर गाड़ी में विस्फोट करने वालों की पिपरिया, कानपुर में गिरफ्तारी और फिर लखनऊ में एटीएस से मुठभेड़ यह साबित करती है कि अब हिंदी भाषी प्रदेश अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से महफूज नहीं है। भले कभी गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया था कि भारतीय मुस्लिम इतने परिपक्व और देशभक्त हैं कि उन्हें आईएस की ओर प्रेरित करना असंभव है, लेकिन अब यह संदेह बढ़ गया है कि भारत में भी वैश्विक आतंकी सक्रिय है।

रूसी इंजीनियर द्वारा बनाए गए 'टेलीग्राम' नाम का मैसेजिंग एप का जिसका इस्तेमाल करने वालों की पहचान पता लगाना कठिन है, आतंकी धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत संभव है कि सीरिया में कमजोर पड़ने या सफाया होने के बाद आईएस 'खोरासन मॉड्यूल' नाम से दूसरे देशों में अपना तंत्र फैला रहे हैं। हमारे खुफिया तंत्र को पूरी तरह चौकस रहना होगा और राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर पर राजनीति से परे सूचनाओं का आदान-प्रदान करना होगा।

सच तो यह है कि आतंकवाद विकृत राजनीति की एक शाखा है और इसे स्वस्थ राजनीति की बयानबाजी और संरक्षण का मुद्दा किसी भी कीमत पर नहीं बनने देना है। साथ ही इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे नौजवान किसी भी तरह से खूंखार आतंकी संगठन आईएस की ओर भटकने न पाएँ। भारतीय नौजवानों को भटकने की आशंका इसलिए भी व्यक्त की जा रही है, क्योंकि आतंकी संगठन आईएस ने दावा किया है कि वह भारत में आ चुका है। इस आशय का एक संदेश आतंकियों ने पिछले दिनों 7 मार्च, 2017 को भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में रखे बम में लगा रखा था। जिस बम से विस्फोट किया गया था वह भी उत्तर प्रदेश से ही बनाकर लाया गया था। खुफिया जाँच एजेंसियों की अबतक की जाँच में केरल, तेलंगाना और मध्यप्रदेश से लेकर उत्तरप्रदेश तक आईएस के खुरासान ग्रुप के सक्रिय होने के पुख्ता सबूत मिले हैं।

(175)प्रश्नः दलाईलामा की त्वांग यात्रा से चीन परेशान क्यों है?

उत्तरः भाई लखन जी, चीन दलाईलामा की त्वांग यात्रा से क्यों घबराता है यह समझना कठिन नहीं है, क्योंकि वह त्वांग को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है जबकि वह भारत का अभिन्न अंग है। चीन त्वांग का रूख बदलता रहा है। इससे उसकी विश्वसनीयता सन्देहास्पद हो गयी है। ल्हासा के बाद त्वांगमठ भारत के लिए काफी अहम है। चीन की बढ़ती परेशानी का कारण त्वांग में दलाईलामा द्वारा नए बौद्ध मंदिरों की स्थापना और दीक्षा समारोहों को लेकर है, क्योंकि ऐसे में यहाँ उनका प्रभाव बढ़ने से भारत का पक्ष और दृढ़ होगा। यही कारण है कि चीन को दलाईलामा की त्वांग यात्रा से तिब्बत में अलगाव की प्रवृत्ति बढ़ने का भय सता रहा है।

दूसरी बात यह है कि भारत अरुणाचल प्रदेश के सामरिक महत्व की वजह से वहाँ अपनी स्थिति सतत सुदृढ़ कर रहा है। यह भी चीन की बेचैनी का कारण है। भारत त्वांग को रेल लाइन से जोड़ रहा है जिसका चीन विरोध कर रहा है और संयम बरतने की सलाह दे रहा है, जबकि भारत की आपत्ति के बावजूद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, जो भारत का हिस्सा है, अवैध रूप से सड़क और रेल लाइन का निर्माण कर रहा है।

जबसे दलाईलामा का अरुणाचल जाने का कार्यक्रम बना तभी से चीन ने इस पर कड़ा एतराज जताना आरंभ कर दिया। चीन ने यहाँ तक कह दिया कि दलाई लामा को अरुणाचल जाने की अनुमति देने से द्विपक्षीय संबंधों पर विपरीत असर पड़ेगा। यह एक प्रकार की धमकी थी जिसे भारत ने बिल्कुल नजरअंदाज किया है। दलाई लामा की यात्रा आध्यात्मिक है और इसे कोई अन्य रूप दिया जाना ठीक नहीं है। दलाई लामा के साथ वैसे भी चीन का रिश्ता कलेजे पर सांप लोटने वाला है। दलाई लामा को पूरी दुनिया बौद्ध धर्मगुरु तथा शांति व अहिंसा का उपदेशक मानती है। चीन इसके विपरीत कहता है कि वह धर्मगुरु नहीं अलगाववादी नेता है। चीन के कहने या विरोध करने से रूख नहीं बदल सकता। दरअसल, चीन को हमेशा यह भय सताता रहता है कि कहीं दलाई लामा उसके खिलाफ किसी तरह का विद्रोह न भड़का दे।

यह चीन की शरारत के अलावा कुछ नहीं कि दलाई लामा अब तक छह बार अरुणाचल की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन वह ऐसे दिखा रहा है जैसे इस बार कुछ नया हो रहा हो। यदि चीन अरुणाचल पर अपने रवैए में तब्दीली नहीं लाता, तो फिर भारत को यह संकेत देने में हिचकना नहीं चाहिए कि वह तिब्बत के मामले में अपना नजरिया बदलने को बाध्य हो सकता है।

(176)प्रश्नः क्या आप ऐसा मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जब *विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मामलों और देशों के बीच तनाव कम करने में असफल रहा है, तो ऐसी संस्था को बनाए रखने का क्या औचित्य है?*

उत्तरः द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् भावी पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। इस संस्था का मूल उद्येश्य अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए देशों की गतिविधियों में समरसता लाना और सभी समस्याओं व विवादों को शांतिपूर्ण उपायों से सुलझाने, संकट को टालने, शक्ति के प्रयोग को रोकने तथा हस्तक्षेप पर अंकुश लगाने के लिए सार्वभौमिक राष्ट्रों की समानता के आधार पर दायित्व निभाना था, किंतु ऐसा देखा गया है कि विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मामलों और देशों के बीच के तनाव को कम करने में संयुक्त राष्ट्र संघ असफल रहा है। ऐसे में जब संयुक्त राष्ट्र को जिस विश्व शांति को बनाए रखने के लिए अस्तित्व में लाया गया था, उसमें ही असफल रहा तो ऐसी संस्था को बनाए रखने का मेरे ख्याल से कोई औचित्य नहीं है। उदाहरण के लिए अभी हाल ही में सीरिया के इदलिब प्रांत में हुए रासायनिक हमले जिसमें 100 लोग मारे गए तथा करीब 400 लोग घायल हुए को लिया जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की जब आपातकालीन बैठक बुलाई गई तब संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत निकीहेली ने कहा कि अगर इदलिब प्रांत में हुए रासायनिक हमले पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से कार्रवाई नहीं की जाती है, तो अमेरिका को अपने स्तर पर कदम उठाना होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता को लेकर निकी हेली द्वारा उसकी प्रासंगिकता पर उठाया गया सवाल सही है, लेकिन कहीं न कहीं संयुक्त राष्ट्र को कमजोर करने में अमेरिका और सुरक्षा परिषद के बाकी स्थायी सदस्यों का भी हाथ है जिनके पास वीटो का अधिकार है, क्योंकि कई बड़े अंतरराष्ट्रीय मामलों में जब संयुक्त राष्ट्र ने कार्रवाई करने की कोशिश की तो वीटो की शक्ति का प्रयोग कर किसी न किसी स्थायी सदस्य ने इसे रोक दिया। अगर संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता को बनाए रखना है, तो इसमें न केवल नए सिरे से बदलाव करना होगा, बल्कि भारत जैसे देशों को सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल कर इसे और भी लोकतांत्रिक बनाना होगा, ताकि अंतरराष्ट्रीय मामलों में संयुक्त राष्ट्र मुखर होकर अपनी भूमिका निभा सके।

(177) प्रश्नः क्या आपको ऐसा लगता है कि सीरिया में राष्ट्रपति बशर-अल-असद सरकार द्वारा विद्रोहियों पर किए गए केमिकल अटैक के जवाब में अमेरिका द्वारा उसके बेस पर किए गए मिसाइल अटैक ने थर्ड वर्ल्ड वार जैसी स्थिति खड़ी कर दी है?

उत्तरः वैसे सच कहा जाए तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमुर पुतिन की गाढ़ी दोस्ती और खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद पर बैठाने में पुतिन का जिस प्रकार सहयोग मिला है उसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कभी आने वाले दिनों में तीसरे विश्वयुद्ध की संभावना है, मगर पिछले दिनों सीरिया में, राष्ट्रपति बशर-अल-असद सरकार द्वारा विद्रोहियों पर किए गए रासायनिक बम के हमले के जवाब में अमेरिका द्वारा उसके बेस पर मिसाइल के हमले किए गए, उसने तो तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति खड़ी कर दी है। विगत 9 अप्रैल, 2017 को जहाँ अमेरिका और रूस ने एक दूसरे को इस बाबत खरी-खरी सुनाई थी और साफ कह दिया था कि अगर उनकी ओर से सीरिया में एक और कार्रवाई हुई तो फिर दोनों पक्षों में आमने-सामने की जमीनी जंग छिड़ जाएगी। इस बीच रूस ने अपना एक जंगी पोत भी सीरिया भेज दिया है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने सीरिया में विद्रोही ठिकानों पर हुए रासायनिक हमले के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि रूस इस बात पर सहमत हुआ था कि वह आश्वस्त करेगा कि सीरिया के रासायनिक हथियारों का जखीरा खत्म हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

इस पूरे मामले पर अमेरिका और उसके सहयोगी इजरायल सउदी अरब, कुवैत, तुर्की, जार्डन, यूएई, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और सभी नाटों देशों ने फिलहाल कुछ नहीं कहा है, मगर वह रूस के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय रोक को और कड़ा करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, वहीं रूस और ईरान ने सीरिया में जंगी तैयारियों को अमलीजामा पहनाने का काम शुरू कर दिया है जिससे इन देशों सहित पूरी दुनिया में चिंता जताई जा रही है। अमेरिका और ब्रिटेन को रूस और ईरान ने साफ-साफ कह दिया है कि कि सीरिया में उन्होंने जो कुछ किया है उससे उन्होंने सहनशीलता की लक्ष्मण रेखा लाँघ दी है और यदि फिर से ऐसा हुआ, तो नौबत सीधी जमीनी जंग की आ जाएगी।

(178)प्रश्नः आधुनिक, सभ्य और प्रगतिशील होने का दावा करने वाली दुनिया के निवासी क्या आतंकवाद, गृहयुद्ध अथवा आंतरिक संघर्षों का शिकार नहीं हो रहे हैं? आखिर क्यों?

उत्तरः हाँ, आधुनिक, सभ्य और प्रगतिशील होने का दावा करने वाली दुनिया के निवासी आज आतंकवाद, गृहयुद्ध अथवा आंतरिक संघर्षों का शिकार हो रहे हैं और करोड़ों की संख्या में लोग अपने घर और अपने वतन को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार सीरिया में चल रहे गृहयुद्ध के चलते विगत तीन वर्षो में करीब 50 लाख लोग देश छोड़कर जा चुके हैं और अपने देश में ही बेघर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यह एक ओर जहाँ साम्राज्यवादी हस्तक्षेपों का परिणाम है, वहीं दूसरी ओर मध्य-पूर्व जैसे क्षेत्र में कुछ संगठित गिरोहों और कुछ शासकों की महत्वकांक्षाओं का भी परिणाम है।

पिछले दिनों पश्चिमोत्तर सीरिया के इदलिब प्रांत में हुए भीषण रासायनिक हमले में कम से कम 100 लोगों की मौत हो गई और 400 से अधिक लोग घायल भी हुए। दरअसल, सीरिया की जंग के साए में सऊदी अरब और ईरान एशियाई तेल बाजारों पर कब्जे की कोशिश में हैं और एक-दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। यह सारा खेल तेल बाजार को लकर रही है।

सच तो यह है कि रूस के सीरिया में 'भू-राजनीतिक हित' (जियो पालिटकल इंटरेस्ट) निहित है और रूस जिस तरह से सीरिया में कार्रवाई कर रहा है, वह वहाँ पर अमेरिकी हितों के लिए बड़ी चुनौती है जिसकी वजह से ओबामा प्रशासन तो सीरिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध रहा ही, अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बराक ओबामा की राह पर ही चल पड़े हैं। आखिर तभी तो सीरिया सरकार के बशर-अद-असद द्वारा रासायनिक हमले का करारी जवाब ट्रंप प्रशासन ने भी दे दिया। ट्रंप और पुतिन की दोस्ती के बावजूद ऐसा लगता है कि पुतिन अपने विशेषाधिकार क्षेत्र में किसी भी शक्ति के प्रवेश पर एतराज करेंगे। तात्पर्य यह कि मध्य-पूर्व नई करवट लेते दिख रहा है, जिसमें गंभीर परिणामों की रूपरेखा निहित है। यदि संयुक्त राष्ट्र कमजोर पड़ता है, तो स्वाभाविक रूप से परिणाम अनुभवों से परे आ सकते हैं।

(179)प्रश्नः क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि कुलभूषण जाधव को फाँसी देने के बहाने पाकिस्तान और चीन भारत को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं? आखिर

कैसे? क्या नवाज शरीफ सरकार का नियंत्रण सेना पर नहीं रह गया है?

उत्तर: हाँ, मैं भी यह महसूस करता हूँ कि कुलभूषण जाधव को फाँसी देने के बहाने पाकिस्तान और चीन भारत को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, क्योंकि कुलभूषण जाधव को फँसानेवाला आईएसआई एजेंट लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हबीब जहीर भारतीय एजेंसियों के कब्जे में है। भारतीय एजेंसियों ने उसे नेपाल सीमा के पास लुबिंनी में पकड़ा। दरअसल, आईएसआई एजेंट जहीर किसी बड़े साजिश के चक्कर में नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा के नजदीक पहुँचा था। आईएसआई को इससे बेहतर कोई जवाब नहीं मिल सकता है। भारत की जनता की इच्छा भी यही है। पाकिस्तान को बेनकाब करने का यह सही समय है। कुलभूषण जाधव को धोखे से ईरान सीमा पर लाकर गिरफ्तार करने के लिए जिम्मेदार जो पाकिस्तानी खुफिया टीम थी उसमें जहीर भी शामिल था। कहा जा रहा है कि जहीर की गिरफ्तारी के बाद ही भारत का दबाव बनाने के लिए पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट ने कुलभूषण जाधव को फाँसी की सजा सुना दी। वो भी बिना किसी साफ जाँच के। जाधव को पक्ष रखने के लिए भी वकील नहीं दिया गया।

यही नहीं पाकिस्तान ने तो जासूसी के आरोप में पकड़े गए एजेंटों के लिए बनाए गए अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का पालन किया। भारतीय दूतावास के अधिकारियों को जाधव से मिलने का भी मौका नहीं दिया गया। भारतीय दूतावास ने कई बार जाधव से मिलने के लिए भी पाकिस्तानी अधिकारियों से अपील की लेकिन भारतीय दूतावास के अधिकारियों के आग्रह को नामंजूर किया। आखिर पाकिस्तान ने पूरे मामले में पारदर्शिता क्यों नहीं रखी, यही अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है।

सच तो यह है कि कुलभूषण जाधव को फाँसी की सजा में अकेले पाकिस्तान की भूमिका नहीं है, बल्कि पीछे से चीन भी अब खेल खेल कर रहा है। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव पर चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर को डिस्टर्व करने का आरोप लगाया था। पाकिस्तान का आरोप था कि जाधव रॉ के एजेंट थे। वह रॉ के इशारे पर बलूचिस्तान में चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर पर हमलार करवा रहे थे। इन्हीं सब कारणों से मैं यह महसूस करता हूँ कि चीन और पाकिस्तान जाधव के बहाने भारत को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं।

पाकिस्तान सरकार को जिस तरह कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी के

वक्त अँधेरे में रखा गया। उसी तरह उन्हें फाँसी की सजा सुनाने के समय थी। इससे स्पष्ट जाहिर होता है नवाज शरीफ की सरकार बेहद कमजोर और दिखावटी सरकार है। उसके हाथ में केवल नाम की सत्ता है। सच तो यह है कि पाकिस्तान को पिछले दरवाजे से उसकी सेना ही संचालित कर रही है। पनामा कांड में नाम आने के बाद नवाज शरीफ राजनीतिक रूप से और अधिक कमजोर पड़ गए हैं। उन्हें उसकी कोई परवाह नहीं कि तानाशाही प्रवृत्तिवाली उनकी सेना लोकतंत्र को दीमक की तरह चाट रही है।

मुश्किल केवल यह नहीं कि पाकिस्तानी सेना नागरिक सरकार को अपनी उँगली पर नचा रही, बल्कि यह भी है कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता दिख रहा है। अब तो जाधव के मामले में हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत (International Court of Justice) से करारी पराजय के बाद पाकिस्तान की चारों तरफ थू-थू हो रही है। देश के अन्दर और बाहर उसकी छवि और साख पर आघात पहुँचा है। पाकिस्तान में जनाक्रोश बढ़ा है। नवाज शरीफ और उनकी सरकार जनता के निशाने पर हैं। पाकिस्तान तो पूरी तरह बेनकाब हो चुका है।

(180)प्रश्नः क्या आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान चीन के चंगुल में फँसता जा रहा है? क्यों?

उत्तरः हाँ, शिवबालक जी, मुझे भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान चीन के चंगुल में फँसता जा रहा है, क्योंकि इस्लाम के नाम पर बना मुल्क पाकिस्तान उस देश का आर्थिक उपनिवेश बनने पर आमादा है, जो अपने मुस्लिम बनने पर आमादा है और जो अपने मुस्लिम नागरिकों से अच्छा सुलूक नहीं करता। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी विदेश नीति पहल के तहत चीन की वन-वेल्ट-वन रोड (ओबीओआर) की आड़ में चीन अपने आर्थिक एवं सामरिक हित साध रहा है। चीन के कब्जेवाले शिनझियांग प्रांत से लेकर पाकिस्तान के कब्जेवाले कश्मीर में गिलगिट-बाल्टिस्तान से होते हुए पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक फैली इस परियोजना को देखा जाए तो यह एक विवादित और जबरन कब्जा करने वालों का गलियारा है। यह शिनझियांग स्थित कशगर और पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित ग्वादर बंदरगाह के बीच एक व्यापारिक मार्ग होगा जिसे चीन ही संचालित कर रहा है और यह औद्योगिक, ऊर्जा, कृषि और सुरक्षा परियोजनाओं तक फैलकर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और समाज के बड़े हिस्से में पैठ बनाएगी। चीन जिस समुद्री और स्थानीय रेशम मार्ग निर्माण की बात कर रहा है, उससे भारत

के सुरक्षा हितों को गहरा आघात पहुँचेगा। वास्तव में सीपीईसी चीन के लिए एक सहज माध्यम बन गया है जिसकी आड़ में वह पाकिस्तान में अपनी सामरिक योजनाएँ सिरे चढ़ा सकता है। इस इलाके को चीन का गुलाम बनाने की चाल है। यहाँ कई जगहों पर चीन ही काबिज है जिन्हें 1963 में पाकिस्तान ने चीन के साथ रिश्ते मजबूत बनाने के लिए उसे भेंट किए थे।

सच कहा जाए तो पाकिस्तान नाकाम देश बनने के कगार पर है और अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए चीन के सामने समर्पण ही उसके सामने इकलौता विकल्प है। शायद यही वजह है कि इस्लाम के नाम पर बना मुल्क पाकिस्तान उस देश का आर्थिक उपनिवेश बनने पर आमादा है जो अपने मुस्लिम नागरिकों पर तरह-तरह के अत्याचार करने के साथ ही दाढ़ी बढ़ाने और 'मोहम्मद' जैसे नाम रखने पर भी रोक लगा देता है। इन सभी वजहों से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान चीन के चंगुल में फँसता जा रहा है।

(181) प्रश्न: कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों में एक के बाद एक आतंकियों को मार गिराए जाने को क्या आप एक बड़ी कामयाबी मानते हैं?

उत्तर: हाँ, कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों में एक के बाद एक आतंकियों को मार गिराए जाने को हम एक बड़ी कामयाबी मानते हैं, क्योंकि सेना व सुरक्षाबल हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी सब्जार अहमद को भी ठिकाने लगाने में सफल रहे। उल्लेखनीय है कि सब्जार अहमद को बुरहान वानी के मारे जाने के बाद उसका उत्तराधिकारी बताया जा रहा था।

विगत 27 मई, 2017 को सेना ने जिस तरह से 24 घंटे के भीतर 10 बड़े आतंकियों को मार गिराया, वह न केवल सैनिकों का मनोबल बढ़ाने वाला था, बल्कि आतंकियों और उनके समर्थकों के लिए भी एक कड़ा संदेश था। भारतीय सैन्य बलों ने बहादुरी के साथ लंबी चली मुठभेड़ में सब्जार अहमद सहित कई दुर्दांत आतंकियों को मौत के घाट उतारकर यह भी साबित किया कि सेना उचित कार्रवाई करने में पूरी तरह सक्षम है।

(182) प्रश्न: नफरत की बुनियाद पर बना और आज अपनी ही आग में झुलसता पाकिस्तान की क्या अंतहीन घृणा ही इसके अंत का कारण बनेगी? यदि हाँ, तो क्यों और कैसे?

उत्तर: हाँ, नफरत की बुनियाद पर बना और आज अपनी ही आग में झुलसता पाकिस्तान की अंतहीन घृणा ही इसके अंत का कारण बनेगी, क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण किसी आर्थिक, जातीय, सांस्कृतिक आधार पर

नहीं हुआ था, बल्कि इसके निर्माण की सिर्फ यही मजहबी तर्क था कि हिंदू-मुसलमान साथ-साथ नहीं रह सकते।

दरअसल, हिंसा और बर्बादी पाकिस्तान की बुनियाद में है। आखिर तभी तो जो अल्लामा इकबाल ने कभी 'सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा' जैसा गीत लिखा था और जिनकी दो पीढ़ियाँ कश्मीरी पंडित हुआ करती थीं, बाद में वे ऐसे कट्टरमजहवी शख्स बन गए जो यूरोप दोरे के बाद समुद्री रास्ते से वापस आते हुए सिली के तटों को देखकर भावूक हो जाता है कि यह कभी मुसलमानों का जीता हुआ इलाका था।

मजहबी मुल्क बन जाने के बाद पाकिस्तान को कश्मीर की शक्ल में पूर्णकालिक काम मिल गया। कश्मीर हिंदुओं के कब्जे से मुक्त कराना था। इसलिए धार्मिक जेहादी सोच मजबूत होती गई। हसन निसार के शब्दों में पाकिस्तान प्रारंभ से ही 'पहचान का संकट' का शिकार रहा है। सूफी बोलवी सोच तो उसे वापस हिंदुस्तानी इस्लाम में गुम कर देती। इसलिए अरब के इस्लाम की ओर रूख उसकी मजबूरी बन गई। आज हाफिज सईद और उसका लश्कर पाक की जरूरत बन गया है।

दूसरी बात यह है कि नेहरू जी का यह सोचना गलत साबित हुआ कि शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान के आधार सिद्धांत द्विराष्ट्रवाद की हवा निकाल देंगे। जिस शेख अब्दुल्ला के दम पर नेहरू जी ने जनमत संग्रह के राजनैतिक समाधान का वायदा कर डाला था, वही जब कश्मीर की आजादी के पक्षधर हो गए, तो नेहरू जी की स्थिति बड़ी विषम हो गई। अगर उन्होंने संयुक्त राष्ट्रसंघ में जाने की गलती न कर 1947-48 में ही कश्मीर के सैन्य समाधान जैसा सरदार वल्लभभाई पटेल चाहते थे, का लक्ष्य रखा होता, तो आज पाकिस्तान से रिश्ते अलग होते। सच तो यह है कि कश्मीर को नेहरू जी ने युद्ध विराम के स्थाई हालात में रखकर एक खुला खेल बना दिया। कश्मीर द्विराष्ट्रवाद की अंतिम परीक्षा है। आधे-अधूरे युद्धों के तुरंत बाद राजनीतिक तौर पर नासमझ नेताओं की राजनीतिक समाधान की बेचैन उत्सुकता ने कश्मीर को बुरी तरह उलझा दिया है। गोवा, निजाम, हैदराबाद, बाँग्लादेश राजनीतिक समाधान नहीं है। इसलिए जिन परिस्थितियों में पाकिस्तान आज कैद हो गया है, अब जेहाद ही उसका एकमात्र रास्ता रह गया है जिस पर चलकर वह बिखराव की ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वह अपनी ही आग में झुलसता जा रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान की अंतहीन घृणा ही इसके अंत का कारण बनेगी।

(183)प्रश्न: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह पेरिस के जलवायु परिवर्तन समझौते से अपने देश को अलग किया है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वह दुनिया में बढ़ते संकीर्ण राष्ट्रवाद के खतरे की एक बानगी है? आखिर कैसे?

उत्तर: हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह भारत-चीन पर तोहमत लगाकर पेरिस के जलवायु परिवर्तन समझौते से अपने देश को अलग किया है वह दुनिया में बढ़ते संकीर्ण राष्ट्रवाद के खतरे की एक बानगी है, क्योंकि जिस पेरिस के जलवायु परिवर्तन समझौते को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस आधार पर अमेरिकी राजनय की बड़ी सफलता बताया था कि उन्होंने इससे भारत-चीन को जोड़ लिया है, उसी आधार पर ट्रंप ने इसे खारिज कर दिया है। ट्रंप ने यह कहकर घोर अमेरिकावाद का परिचय दिया है कि इस समझौते के तहत भारत न सिर्फ अमेरिका से लाखों डॉलर की मदद लेगा, बल्कि नए-नए कोयला संयंत्र लगाएगा और कोयले का उत्पादन दोगुना होगा।

ओबामा ने अमेरिका का बड़प्पन दिखाते हुए उसके खाते में दुनिया और उसकी भावी पीढ़ियों के लिए जो जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार की थी उसे 'पहले अमेरिका' के सिद्धांत के तहत खारिज करके ट्रंप ने यह जता दिया है कि वे अमेरिका को बेहद स्वार्थी देश बनाना चाहते हैं और ऐसी विश्वव्यवस्था कायम करना चाहते हैं, जो सिर्फ अमीरों के हित में हो। ओबामा ने इस समझौते के तहत अमेरिका की तरफ से तीन अरब डॉलर देने और एक दशक के भीतर 26 से 28 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम करने का वादा किया था, जिसमें से एक अरब डॉलर दिया भी जा चुका है, लेकिन अब ट्रंप के नए रूख के चलते बाकी राशि नहीं मिलेगी और इस समझौते को मूर्त रूप देने की कमान चीन-भारत के हाथ में जाएगी।

यदि समूची दुनिया को प्रभावित करने वाले मसलों पर सभी देश अमेरिका की तरह अपने-अपने हितों को जरूरत से ज्यादा महत्व देने लग जाएँगे, तो फिर किसी मसले पर सहमति बनना कठिन ही होगा। आखिर कोई देश एक तरह से अपनी ही पहलवाले अंतरराष्ट्रीय समझौते से अलग कैसे हो सकता है? एक सवाल यह भी है कि कोई जिम्मेदार देश वैश्विक संधि पर ऐसी मनमानी कैसे कर सकता है?

हालांकि अमेरिका के पेरिस समझौते से अलग होने के बाद भी

भारत समेत अन्य प्रमुख देशों ने उसके प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है, लेकिन *इसमें दो राय नहीं कि इससे जलवायु* परिवर्तन के दुष्प्रभाव से बचने में *मुश्किल आ सकती है। इसलिए और भी, क्योंकि एक तो अमेरिका* पर्यावरण के लिए हानिकारक *गैसों के उत्सर्जन के मामले में अग्रणी है* और दूसरे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने में पहले ही देर हो चुकी है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते से अमेरिका के पीछे हटने की वजह से इस समझौते के लक्ष्यों को पाना बाकी दुनिया के लिए मुश्किल हो गया है।

(184)प्रश्नः क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि टेरर फंडिंग के खिलाफ पूरी दुनिया को एक होने की जरूरत है? यदि हाँ, तो क्यों?

उत्तरः हाँ, पंचशील जी, मैं भी यह महसूस करता हूँ कि टेरर फंडिंग के खिलाफ पूरी दुनिया को एक होने की जरूरत है, क्योंकि आतंकवाद जिस तेजी से पांव पसार रहा है, उससे पूरी दुनिया चिंतित है। खासतौर पर पिछले एक दशक में उनकी पहुँच अविश्सनीय तरीके से बढ़ी है। ऐसे में दुनिया का चिंतित होना स्वाभाविक है।

कहा जाता है कि आतंकवाद की सबसे ज्यादा फंडिंग कतर कर रहा है जिससे क्षेत्र में अमेरिकी सेना की गतिविधियाँ तथा इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। आखिर तभी तो बहरीन, मिस्र, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने कतर से संबंध खत्म कर लिए हैं और उस पर कट्टरपंथी समूहों का साथ देने का आरोप लगाया है। आतंकवाद के खिलाफ ऐसे बड़े कदम उठाने की ही जरूरत है। आतंक पोषित देशों का दुनिया भर में बहिष्कार होना चाहिए। दुनिया को यह समझना होगा कि आतंकवाद के प्रसार का सबसे बड़ा कारण इसको मिलने वाली फंडिंग है, अगर इस पर रोक लगाई जाती है, तो दुनिया भर से आतंकवाद की कमर तोड़ी जा सकती है। इस संदर्भ में अच्छी खबर यह है कि टेरर फंडिंग को लेकर पूरी दुनिया में सरकारें सतर्क हैं और इसे खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस ओर किए जा रहे प्रयास में पूरी दुनिया को उनका साथ देना मेरे ख्याल से समय का तकाजा है।

(185)प्रश्नः क्या आपको ऐसा लगता है कि विगत 26 एवं 27 जून, 2017 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मुलाकात ने यह साफ किया

कि भारत-अमेरिका के रिश्ते अपेक्षित दिशा में ही आगे बढ़ने वाले हैं? आखिर ऐसा क्यों?

उत्तर: हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि पिछले दिनों अमेरिका की राजधानी वाशिंग्टन में 26 एवं 27 जून, 2017 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एवं भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात ने यह साफ किया कि भारत-अमेरिका के रिश्ते अपेक्षित दिशा में ही आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच जैसी समझबूझ कायम हुई उससे वे तमाम आशंकाएँ इसलिए उभर आई थीं, क्योंकि राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक कई ऐसे बयान दिए थे जो भारतीय हितों के अनुकूल नहीं नजर आ रहे थे। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने जहाँ एक ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ने मोदी के नेतृत्व में भारत की महत्ता को रेखांकित किया, वहीं दूसरी ओर भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर यह साबित किया कि वह विश्व के प्रमुख नेताओं के साथ तालमेल बैठाने में माहिर हैं। यह शायद इसी तालमेल का असर रहा कि दोनों नेताओं ने अपनी पहली मुलाकात में असहमति का विषय बन सकने वाले मसलों को टालना और रिश्तों को मजबूत करने वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर समझा। भारत के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं कि ट्रंप ने अपने कहे के अनुरूप मोदी की आवभगत सच्चे दोस्त के तौर पर की। दोस्ती के इस भाव की झलक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के साथ-साथ दोनों नेताओं की ओर से जारी साझा बयान में भी दिखाई दी।

आज जहाँ भारत को अपने उत्थान के लिए अमेरिकी मदद की दरकार है, वहीं अमेरिका को भी आगे बढ़ने के लिए भारत की जरूरत है। दरअसल, इसीलिए बार-बार यह रेखांकित होता है कि भारत और अमेरिका एक-दूसरे के स्वाभाविक सहयोगी हैं। यह कहना कदाचित अनुचित नहीं होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी पहली ही मुलाकात में अमेरिकी राष्ट्रपति पर जिस तरह अपनी छाप छोड़ते दिखे उससे वह वैश्विक नेता के तौर पर अपना कद और ऊँचा करने में तो कामयाब रहो ही दुनिया को भारत की बढ़ती अहमियत का संदेश देने में भी सफल रहे।

इस संदर्भ में यह भी काबिलेगौर है कि अमेरिकी प्रशासन ने जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप और नरेन्द्र मोदी की मुलाकात के ठीक पहले कश्मीर में आतंक फैला रहे आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित किया उससे यही स्पष्ट हुआ कि

भारतीय हित उसकी प्राथमिकता में शामिल है। सलाहुद्दीन को आतंकी घोषित किए जाने के बाद पाकिस्तान की ओर से भले ही गर्जन-तर्जन किया जा रहा हो, लेकिन यह तय है कि उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अमेरिका के कदम से वह एक बार फिर आतंकियों की शरणस्थली के रूप में सामने आया। इस पर हैरत नहीं कि भारत और अमेरिका की ओर से जारी संयुक्त बयान से चीन भी परेशान नजर आ रहा है। चीन को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि वह अपनी शर्तों से भारत से संबंध बनाए रख सकता है। यह संभव नहीं कि वह भारतीय हितों की अनदेखी भी करे और फिर यह भी अपेक्षा करे कि भारत उसके प्रति मित्रवत् रवैया बनाए रहे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिकी यात्रा को लेकर चीन इतना असहज इसलिए भी है, क्योंकि ट्रंप और मोदी के बीच हुए द्विपक्षीय बैठक में दक्षिण चीन सागर को लेकर न सिर्फ विस्तृत बातचीत हुई है, बल्कि इस पूरे इलाके में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को किस तरह से रोका जाए, इसकी रणनीति बनाने की तरफ भी संकेत दिए गए हैं। साथ ही अमेरिका भारत को निगरानी करने वाली ड्रोन तकनीकी सिस्टम देने को भी तैयार हो गया है।

ड्रोन के अलावा संयुक्त बयान में एक और तथ्य है जो चीन को काफी नागवार गुजरेगा। पहली बार भारत व अमेरिका ने चीन की वन बेल्ट वन रोड (ओबोर) की तरफ इशारा किया है। संयुक्त बयान में पहली बार भारत और अमेरिका ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को आगाह किया है कि वह अपनी जमीन को इस्तेमाल दूसरे देशों में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिलाने के लिए न करे। साथ ही पाकिस्तान से यह भी कहा गया है कि वह मुंबई हमले और इस तरह अन्य हमलों के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए कदम उठाए। यह कुछ ही घंटो के भीतर पाकिस्तान को दिया दूसरा झटका है। इसी प्रकार हिजबुल आतंकी सैयद सलाउद्दीन को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के अलावा अमेरिका ने अलकायदा, आईएस, हिजबुल, डी-कंपनी, लश्कर, जैश जैसे खूंखार आतंकी संगठनों के खिलाफ भी अपने सहयोग को लगातार मजबूत करने की बात कही है। इसमें चार आतंकी संगठन पाकिस्तान की ही हैं। पहले भी भारत और अमेरिकी सरकार की तरफ से जारी संयुक्त बयान में पाकिस्तान का जिक्र होता था, लेकिन पहली बार अब उसे सीधे तौर पर बोला जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही झटके में आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध को तेजी देने और उन सारे गुटों को निशाना बनाने का इरादा जता दिया, जिनसे खतरे की

आशंका हो। मोदी और ट्रंप की मुलाकात के दौरान एशिया में शक्ति के संतुलन का मुद्दा केंद्र में रहा। दोनो देशों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक जिम्मेदारी के साथ कमान संभालने पर सहमति जताई। इन सभी मसलों पर ट्रंप और मोदी के बीच हुई बातचीत से स्पष्ट होता है कि भारत-अमेरिका के रिश्ते अपेक्षित दिशा में ही आगे बढ़ने वाले हैं।

(186)प्रश्नः राष्ट्र के स्वाभिमान पर हमला और इसकी अस्मिता पर लगातार जो प्रहार हो रहा है, इन चुनौतियों को स्वीकार कर क्या ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाना चाहिए?

उत्तर: हाँ, राष्ट्र के स्वाभिमान पर हमला और इसकी अस्मिता पर लगातार जो प्रहार हो रहा है उसके मद्देनजर इन चुनौतियों को स्वीकार कर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना चाहिए। इसमें तनीक संदेह नहीं कि भारतीय सेना हर चुनौती का जवाब दे रही है और इसके जांबाज जवान शहादतें देकर भी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियाँ पहले से कहीं अधिक गंभीर और जटिल होती जा रही हैं। सीमा पर बैठे पाक के दुश्मन जहाँ एक ओर आतंकी हमले करवा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चीन तनाव बढ़ाने पर आमादा है। हम छद्मयुद्ध को लगातार झेलते आ रहे हैं और षड्यंत्र जारी है। ऐसी स्थिति में सेना हर प्रौद्योगिकी से लैस हो। शास्त्र की रक्षा के लिए शस्त्र जरूरी होते हैं। कहा भी गया है-

'जहाँ शस्त्र बल नहीं,
वहाँ शास्त्र पछताते और रोते हैं
ऋषियों को भी तप में सिद्धि तभी मिलती है,
जब पहरे में स्वयं धनुर्धरराम खड़े होते हैं।'

इस दृष्टिकोण से मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी रक्षा पंक्ति को इजराइल की तरह मजबूत बनाना है। हमारी दिल्ली से भी कम आबादी होने के बावजूद दुश्मन मुस्लिम राष्ट्रों से घिरे इजराइल की ओर कोई आँख उठाने की हिम्मत भी नहीं करता। खतरनाक आतंकी संगठन आईएस ने मुस्लिम देशों को तो तबाह कर दिया, लेकिन उसने इजराइल की कभी बात नहीं की। फिर भारत अपने समक्ष खड़ी चुनौतियों को स्वीकार कर ईंट का जवाब पत्थर से क्यों नहीं दे सकता? विश्वास है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार चुनौतियों को स्वीकार कर अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देगी, क्योंकि फॉब्स के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सबसे अधिक 73 फीसदी लोगों को अपनी सरकार पर भरोसा है।

(187)प्रश्नः डोकलाम विवाद पर चीन के विचित्र व्यवहार से क्या यह नहीं स्पष्ट हो रहा है कि उसे यह बुनियादी समझ भी नहीं कि पड़ोसी देशों से कैसे संवाद किया जाता है? ऐसा क्यों?

उत्तरः हाँ, सिक्किम के निकट भूटान के डोकलाम इलाके में चीनी सेना के साथ जारी गतिरोध और विवाद पर चीन के विचित्र व्यवहार से यही स्पष्ट हो रहा है कि उसे बुनियादी समझ भी नहीं कि पड़ोसी देशों के साथ संवाद कैसे किया जाता है, क्योंकि उक्त गतिरोध को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय और वहाँ के सरकार नियंत्रित मीडिया की ओर से की जा रही बयानबाजी में जिस तरह वहाँ की सेना भी कूद पड़ी उससे उसकी बौखलाहट की नए सिरे से पुष्टि हो गई। यह आश्चर्यजनक है कि चीन के नीति-नियंता इसका अहसास नहीं कर पा रहे हैं कि नित-नई धमकियाँ और उकसावेवाले बयान देने से यदि किसी का माखौल उड़ रहा है तो वह खुद उनका ही है। कम से कम अबतक तो चीन को यह अहसास हो जाना चाहिए कि उसकी धमकियों से भारत की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चीन के गर्दन-तर्जन से तो ऐसा लगता है कि उसका नेतृत्व अभी भी सदियों पुरानी मानसिकता में जी रहा है। बेहतर हो कि चीनी नेता और खासकर उसके विदेश मंत्रालय के नीति-निर्माता अपनी आम जनता से कुछ सबक सीखें, कारण कि चीन की आम जनता जिस विवाद पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं उसे लेकर वहाँ के नेता इतनी आग क्यों उगल रहे हैं?

दुनिया सिर्फ यही देख रही है कि वह डोकलाम विवाद पर किस तरह भारत को धमकाने में लगा हुआ है। विश्व बिरादरी इससे भी परिचित है कि वह दक्षिण चीन सागर पर अपना आधिपत्य कायम करने के लिए अपने तमाम पड़ोसी देशों को आतंकित करने में लगा हुआ है। उसके नेताओं को यह पता होना चाहिए कि विश्व समुदाय अब इस चालबाजी से भली तरह परिचित है कि चीन किस तरह पहले किसी विविादित क्षेत्र को कथित तौर पर ऐतिहासिक रूप से अपना बताता है और फिर उस पर कब्जे के लिए बल प्रयोग की धमकी देने लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि 21वीं सदी में ऐसा देश कभी भी आदर और सम्मान का पात्र नहीं हो सकता।

(188)प्रश्नः क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि शांति का नोबल पुरस्कार प्राप्त ली शाओबो लोकतंत्र की लड़ाई में बलिदान हो गए और तानाशाह चीन में शांतिदूत का अवसान हो गया?कैसे?

उत्तर: हाँ, मैं भी महसूस करता हूँ कि शांति का नोबल पुरस्कार विजेता ली शाओबो लोकतंत्र की लड़ाई में बलिदान हो गए और तानाशाह चीन में शांतिदूत का अवसान हो गया, क्योंकि ली शाओबो के बलिदान को जब दुनिया जानेगी, तो चीन की खतरनाक, अमानवीय, अराजक, क्रूर, बर्बर, हिंसक शासन पद्धति को भी जान लेगी। नि:संदेह चीन लोकतंत्र विरोधी है तथा पड़ोसियों की संप्रभुता को कुचलने वाला देश है। इसलिए कि चीन में अभिव्यक्ति की आजादी है ही नहीं, मीडिया की आजादी प्रतिबंधित है और समाचार चैनल एवं अखबार तानाशाही नियंत्रित है, क्योंकि वह वही खबर देने के लिए बाध्य है जो खबर चीनी तानाशाही कम्युनिस्ट सरकार चाहती है। सोशल मीडिया पर भी तानाशाही का पहरा बैठा हुआ है। आखिर तभी तो ली शाओबो के बारे में दुनिया के आम लोगों की जानकारी ली शाओबो से संबंधित पूरी जानकारियाँ सामने नहीं आने के कारण कम है। फिर भी दुनिया के सजग लोकतांत्रिक ली शाओबो को लेकर चीनी की बर्बर और हिंसक चेहरा देखकर दंग है और ली शाओबो को महान लोकतांत्रिक सेनानी का दर्जा दे रहे हैं।

चीन में राजनीतिक सुधारों लोकतंत्र की अलख जगाने के लिए और चीनी तानाशाही के खिलाफ खड़ा होने के लिए ली शाओबो को 2010 में शांति का नोबल पुरस्कार मिला था। जब ली शाओबो को शांति का नोबल पुरस्कार मिला था तब चीन ने काफी हो हल्ला मचाया था, नोबल पुरस्कार कमिटी को आँख दिखाई थी और कहा था कि यदि ली शाओबो को शांति का नोबल पुरस्कार देने का निर्णय नहीं पलटा गया तो फिर उसके नतीजे बहुत बुरे होंगे, मगर चीन की इस गीदड़भभकी के सामने नोबल पुरस्कार कमिटी ने झुकने से इन्कार कर दिया था। दरअसल, शाओबो एकल पक्षीय कम्युनिस्ट शासन को खत्म करना चाहते थे।

आपको यह जानकर आश्चर्य के साथ-साथ प्रसन्नता भी होगी कि 1989 में बीस लाख लोगों ने थ्येनआनम्यान चौक पर कम्युनिस्ट तानाशाही से आजादी और लोकतंत्र की स्थापना की माँग को लेकर एकत्रित हुए थे और वे कई दिनों तक भूखे-प्यासे थे। निहत्थे और शांतिपूर्ण लोकतंत्र के आंदोलन को कुचलने के लिए चीन की तानाशाही ने रेल पटरियों को जाम कर बैठे लोकतंत्रवादियों पर न केवल रेल चलायी थी, बल्कि आंदोलनकारियों पर टैंक चलाई थी और सेना उतारकर गोलियाँ एवं मिसाइलें तक चलायी थीं जिसमें 20 हजार से अधिक लोगों की मौत हुई थी और करीब एक लाख से अधिक

युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में उनकी हत्या कर दी गयी थी। ली शाओबो भी थ्येनआनम्यान चौक के आंदोलनकारियों में से एक थे। उस समय वे अमेरिका में पढ़ रहे थे और पढ़ाई के दौरान ही ली शाओबो लोकतंत्र की स्थापना की लड़ाई लड़ने के लिए चीन लौटे थे। उसके बाद से ही ली शाओबो को चीन की तानाशाही ने चीन की जेल में सड़ने और मरने के लिए 1989 में बंद कर दिया था। मेरा तो यहाँ तक मानना है कि यदि ली शाओबो साधारण लोकतांत्रिक सेनानी होते तो उन्हें सीधे मौत के घाट उतार दिया होता और दुनिया जानती तक नहीं। ली शाओबो की मौत चीनी तानाशाही की जेल में उत्पीड़न और ज्यादतियों से उपजी हुई कैंसर की बीमारी से हुई थी। जब कैंसर से पीड़ित होने की जैसे ही खबर आई थी, तो दुनिया की लोकतांत्रिक सेनानियों और कई राष्ट्रध्यक्षों ने ली शाओबो को रिहा करने और उनका इलाज विदेश में कराने की अपील की थी जिसे चीनी तानाशाहों ने खारिज कर दी थी और अंतत: जेल में ही उनकी मौत हो गई विगत 13 जुलाई, 2017 को।

ली शाओबो की पत्नी शिया भी चीन की जेल में बंद हैं और चीन शिया को भी रिहा करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है कि चीन में घोर मानवाधिकार हनन को लेकर दुनिया के नियामकों को सजग और क्रियाशील होना समय की माँग है। यही नहीं, चीन के खिलाफ प्रतिबंधों को भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। ली शाओबो की संघर्ष गाथा व्यर्थ नहीं जाएगी, कभी न कभी चीन में लोकतंत्र का सूर्योदय होना निश्चित है, जैसे सोवियत संघ के पतन के बाद लोकतंत्र का उदय हुआ था।

(189)प्रश्न: 'पनामागेट' कांड में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा वहाँ के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अयोग्य घोषित करने के ऐतिहासिक फैसले के बाद उपजे माहौल पर भारत की चिंता के क्या कारण हैं?

उत्तर: 'पनामागेट' कांड में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा वहाँ के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बर्खास्तगी के बाद उपजे हालात से भारत की चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि नवाज शरीफ को अयोग्य घोषित करने के ऐतिहासिक फैसले के बाद उपजे माहौल में पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने से वहाँ की सेना के हस्तक्षेप बढ़ने के आसार हैं। भारत की आशंका है कि वहाँ की अस्थिरता कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले संगठनों को नई ऊर्जा दे सकती है।

सबसे अहम तो यह है कि मजबूत राजनीतिक नेतृत्व न होने से पाक सेना बेलगाम होगी। पाक सेना किसी भी सूरत में भारत के साथ बेहतर रिश्तों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी वजह यह है कि अगले साल यानी 2018 में होने वाले चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दल भारत विरोधी तेवरों को और तल्ख कर सकते हैं। इस वजह से भारत विरोधी आतंकी संगठनों मसलन जैश-ए-मोहम्मद या तहरीक-ए-आजादी को वहाँ अपनी गतिविधियों को और बढ़ाने का मौका मिल सकता है। तीसरी वजह यह है कि पाक सेना कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने की नई कोशिश कर सकती है।

भारत की तात्कालिक चिंता पाक सेना की तरफ से बंदी बनाए गए भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलीभूषण जाधव को लेकर भी है, क्योंकि सेना की अपीलीय कोर्ट उनके आवेदन को ठुकरा चुकी है। अब उन्होंने सेना प्रमुख कमर बाजवा के पास गुहार लगाई है। वैसे इस मामले की सुनवाई अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भी चल रही है, लेकिन पाक सेना का कोई भरोसा नहीं है। इसके अतिरिक्त मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान के साथ रिश्तों को सुधारने की अगर कोई बची खुची उम्मीद थी तो अब उसके भी खत्म होने के आसार हैं। पठानकोट व उड़ी के हमले के बाद दोनों देशों के रिश्तों में लगातार तल्खी बढ़ी है। भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने की लगातार कोशिश कर रहा है, जबकि सीमापार से भी कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। पाक सेना के साए में रिश्ते सुधारने की बात बेमानी है।

पाक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर इस नतीजे पर भी पहुँचा जा सकता है कि अब पाकिस्तान में ताकतवर भ्रष्ट तत्वों की खैर नहीं, मगर पाकिस्तान में लोकतंत्र दयनीय दशा में इसलिए है कि इस देश में जो शासक सेना की मनमानी को सहन करने के लिए तैयार नहीं होगा उसका हश्र नवाज शरीफ जैसा ही होगा। आखिर यह एक तथ्य है कि पाकिस्तान में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। कभी वह तख्तापलट का शिकार हुआ और कभी वैसे संवैधानिक प्रावधानों को जो अलोकतांत्रिक हैं और जिनकी मनमानी व्याख्या की जा सकती है। पाकिस्तानी सेना के समक्ष वहाँ का सुप्रीम कोर्ट भी लाचार नजर आता है, क्योंकि एकाध अपवाद को छोड़ दें तो वह सैन्य तानाशाहों और भ्रष्ट जनरलों के खिलाफ असहाय ही रहता है। मेरा ख्याल है कि पाक शायद ही निरंकुश और भ्रष्ट सेना के दबाव से मुक्त हो सके। पाकिस्तान की ऐसी स्थिति न तो उसके

लिए हितकारी है और न ही भारत के लिए। इसलिए वहाँ के हालात से और सतर्क रहने में ही भारत की भलाई है।

(190)प्रश्न: क्या आपको भी ऐसा लगता है कि साम्यवादी लबादे में चीन के साम्राज्यवादी सलीकों को दुनिया अच्छी तरह पहचान चुकी है? आखिर कैसे?

उत्तर: हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि साम्यवादी लबादे में चीन के साम्राज्यवादी सलीकों को दुनिया अच्छी तरह पहचान चुकी है, क्योकि चीन कर्ज को ब्याज सहित वसूलना बहुत अच्छे से जानता है। उसके लिए रिश्ते से ज्याद मायना उसके फायदे रखते हैं।

अपने देश की बढ़ती आबादी के लिए ज्यादा से ज्यादा स्थान दिलाने, ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने, राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा को ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए चीन किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। चीन की साम्राज्यवादी नीति में पहल हमेशा मदद से होती है। कलाई पकड़कर गिरेबां तक पहुँचना उसे अच्छे से आता है।

दरअसल, पिछले दिनों पाकिस्तान स्थित चीनी दूतावास में 1 अगस्त, 2017 को आयोजित चाइना पिपुल्स लिबरेशन आर्मी के 90वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत कर रहे पाक आर्मी सेनाध्यक्ष जनरल बाजबा ने मंच से कहा कि विभिन्न मुद्दों पर चीन से मिले समर्थन के वह कर्जदार हैं। जनरल बाजवा काफी खुश दिखे, क्योंकि उस वक्त दुश्मन-दुश्मन, दोस्त-दोस्त खेल चल रहा था जिस मुल्क को पाक आर्मी प्रमुख अपना दुश्मन मानते हैं इत्तेफाक से चाइना भी कई मुद्दों पर उस मुल्क का विरोधी है। ऐसे में दोनों की गलबहियाँ बढ़ गई हैं। दोनों एक दूसरे के जरिए अपने हित साध रहे हैं।

खुदगर्जी की नींव पर परवान चढ़ रही पाक-चीन की दोस्ती किसके फायदे में होगी, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जनरल बाजवा शायद इतिहास विषय में थोड़े कमजोर हैं। इसलिए वह खुद को कर्जदार तो बता बैठे, लेकिन ये भूल गए कि चीन कर्ज को ब्याज सहित वसूलना बहुत अच्छे से जानता है।

सच तो यह है कि फिक्र वो करें जो चीन के कर्जदार हैं, क्योंकि चीन ने जिस भी मुद्दे पर पाकिस्तान के हितों के लिए आवाज बुलन्द की उसके पीछे उसके अपने हित छुपे हुए हैं। लेकिन इस याराना में पाकिस्तान फायदे में रहेगा या नुकसान में, ये आने वाले वक्त में उसे भी समझ आ जाएगा। तब शायद जनरल बाजवा न रहें। कोई और पाकिस्तान आर्मी और

उसके पीछे आईएसआई की कमान संभाल रहा हो। लेकिन चीन के हर कर्ज को पाकिस्तान के पूरे अवाम को ही चुकाना पड़ेगा।

(191)प्रश्नः क्या आपको ऐसा लगता है कि आर्थिक घेराबंदी कर चीन को शिकस्त दिया जा सकता है?

उत्तरः हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि आर्थिक घेराबंदी कर चीन को शिकस्त दिया जा सकता है। इधर हाल के दिनों में चीन के सरकारी मीडिया द्वारा लगातार भारत को युद्ध की धमकी दी जा रही है। आप इस बात से अवगत हैं कि चीन की विस्तारवादी नीति शुरू से ही रही है और उसकी इस विस्तारवादी मंसूबों से उसके कई अन्य पड़ोसी देश भी परेशान हैं, भारत तो परेशान है ही। ऐसी स्थिति में चीन के नापाक इरादों को ध्वस्त करने का एक तरीका यह भी है कि चीनी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, क्योंकि चीन से हजारों करोड़ रुपए के चीन निर्मित समान दिवाली और गणेशोत्सव के अवसर पर इस देश में आता है। चीन की ऐसी वस्तुओं ने भारतीय बाजार पर कब्जा कर लिया है जिसके दुष्परिणामस्वरूप धीरे-धीरे हमारे स्वदेशी घरेलू उद्योग चौपट हो रहे हैं और लघु व कुटीर उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

चीन के लिए भारतीय बाजार अहम है। वर्ष 2011 में भारत में निवेश करने वाले देशों में चीन 37वें स्थान पर था, लेकिन अब यह 17वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन गया है। ऐसे में यदि हम चीनी माल के बहिष्कार की नीति अख्तियार करते हैं, तो इससे चीनी अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा। आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2016-17 में भारत चीन व्यापार 71.47 अरब डॉलर का रहा। चीन को भारत से 10.19 अरब डॉलर मूल्य के निर्यात किए गए, जबकि चीन से आयात का मूल्य 61.28 अरब डॉलर रहा। इस प्रकार व्यापार घाटा 47.68 अरब डॉलर का रहा।

यहाँ यह भी आपको बता दूँ कि चीन से कुछ आयात नियंत्रण का सफल प्रयोग पिछले 2016 में दिखा है। वस्तुतः सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद चीन के द्वारा पाकिस्तान का साथ दिए जाने की वजह से उस वक्त चीनी माल का बहिष्कार भारत के उपभोक्ताओं के द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ था।

हालांकि यह भी उल्लेखनीय है कि भारत और चीन दोनों विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य हैं, ऐसे में भारत विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत चीनी माल पर टैरिफ या गैर टैरिफ प्रतिबंध

लगाकर चीनी माल को रोक नहीं सकता है, लेकिन यदि आयातित वस्तुएँ घरेलू नियम-कानून, तकनीक ब्योरे, गुणवत्ता और पर्यावरण संबंधी सुरक्षा मानकों के मुताबिक न हों, तो उन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है। विश्व व्यापार संगठन के नियमों का हवाला देते हुए चीन ने बोवाइन मीट, फल, सब्जियों, बासमती चावल और कच्चे पदार्थों के भारत से आयात पर बाधाएँ उत्पन्न की हैं। ऐसे में भारत भी चीन द्वारा लागत से कम मूल्य पर माल भेजकर भारतीय बाजार पर कब्जा करने का आधार देकर चीन के कई तरह के माल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर उसे हतोत्साहित कर सकता है।

मुझे लगता है कि चीन की हेकड़ी और धमकियों के मद्देनजर देश के करोड़ों उपभोक्ता चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की डगर पर अगर बढ़ें और केंद्र सरकार घटिया चीनी समान को रोकने तथा चीनी आयात को हतोत्साहित करने के उपाय करे, तो निश्चित ही इससे आर्थिक सुस्ती से जूझ रहे चीन पर दबाव बढ़ेगा और इस प्रकार आर्थिक घेराबंदी कर भारत चीन को शिकस्त दे सकता है।

(192)प्रश्नः क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन की बढ़ती आतंकी गतिविधियों की पृष्ठभूमि में हिजबुल पर अमेरिका का बैन देर से ही सही, लेकिन दुरूस्त फैसला कहा जाएगा? आखिर क्यों?

उत्तरः हाँ, मैं भी यह महसूस करता हूँ कि आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन की बढ़ती आतंकी गतिविधियों की पृष्ठभूमि में हिजबुल पर अमेरिका का बैन देर से ही सही, लेकिन दुरूस्त फैसला है। आपको याद होगा कुछ माह पहले आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन को अमेरिका वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था। और अब अमेरिका ने इसे आतंकी संगठन भी घोषित कर दिया है। इस बैन के बाद भारत में होने वाले आतंकी हमलों पर असर पड़ेगा, साथ ही अब न सिर्फ इस संगठन की अमेरिका में मौजूद संपत्तियाँ जब्त होंगी, बल्कि अब यह फंड भी नहीं जुटा पाएगा। अमेरिकियों से कहा जाएगा कि वे इस आतंकी संगठन से किसी भी तरह का लेन-देन न करें। यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि हिजबुल जैसे आतंकी संगठन फंड जुटाकर उन लोगों को उपलब्ध कराते हैं जो भारत व कश्मीर में आतंक फैलाने का ठेके लिए हैं।

आपको याद होगा अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि सितंबर 2016 में सलाहुद्दीन ने कश्मीर मसले की

किसी शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश को बाधित करने का संकल्प लिया था।, अधिक से अधिक कश्मीरी युवाओं को आत्मघाती हमलावर बनाने की चेतावनी दी थी और कश्मीर घाटी को भारतीय सुरक्षा बलों के लिए कब्रगाह में तब्दील करने का संकल्प लिया था। इतना ही नहीं, सलाहुद्दीन के नेतृत्व में हिजबुल ने जम्मू-कश्मीर में अप्रैल-2014 में हुए बम विस्फोट सहित अनेक आतंकवादी हमलों की जिम्मेदारी ली। ऐसे में अगर यह फैसला पहले लिया जाता तो शायद आज हालात इतने खराब न होते और इस संगठन के आतंक से कुछ लोग बच भी पाते, मगर जो हो देर से सही अमेरिका द्वारा इस आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को बैन करने का फैसला दुरूस्त कहा जाएगा, क्योंकि इस फैसले के बाद अब पाक पर इसके खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ जाएगा और खुद अमेरिका अपने नागरिकों और वैश्विक संस्थाओं से मिलने वाले फंड्स की जाँच करेगा।

(193)प्रश्न:भूटान के दावेवाले डोकलाम में भारत और चीन की सेनाओं के बीच जारी तनातनी जिस तरह खत्म हुई क्या आप इसे भारतीय कूटनीति की एक बड़ी कामयाबी मानते हैं और क्यों?

उत्तर: हाँ, शाहिद जी, भूटान दावेवाले डोकलाम में भारत और चीन की सेनाओं के बीच जारी तनातनी जिस तरह खत्म हुई उसे मैं भारतीय कूटनीति की एक बड़ी कामयाबी इसलिए मानता हूँ, क्योंकि इससे न केवल भारत का अंतरराष्ट्रीय कद बढ़ेगा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की छवि एक ऐसे नेता के तौर पर उभरेगी जो भारतीय हितों की रक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। भारत ने राजनीतिक एवं कूटनीतिक परिपक्वता का प्रशंसनीय प्रदर्शन करने के साथ संयम और दृढ़ता का जो परिचय दिया उसकी वजह से ही चीन अपने मनमाने रवैए को छोड़ने के लिए विवश हुआ। दोनों देशों के समझौते के मुताबिक जहाँ भारत डोकलाम से अपनी सेनाएँ वापस बुलाएगा, वहीं चीन सड़क बनाने का काम रोकेगा। भारत जो चाहत था उसे मानने के लिए चीन राजी हुआ और यह इसलिए विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि पहले दिन से ही ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे भारत उसके समक्ष कुछ भी नहीं। चीन यह जो जाहिर कर रहा था कि डोकलाम विवाद का समाधान तो उसकी ही शर्तो पर होगा वैसा कुछ नहीं हुआ और बावजूद इसके नहीं हुआ कि चीन ने भारत को धमकाने के लिए हर तरह के जतन किए।

भारत ने चीन पर जो कूटनीतिक जीत हासिल की उसका संदेश उसके पड़ोसी देशों के साथ-साथ समूची विश्व बिरादरी को भी जाएगा। चीन ने जिस तरह अपना चेहरा बचाते हुए अपने कदम पीछे खींचे उसका एक मनोवैज्ञानिक लाभ यह भी होगा कि भारत की आम जनता 1962 की कड़वी यादों को भूलकर आत्मविश्वास से लैस होंगी। अब नरेन्द्र मोदी चीन में होने जा रहे ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में कहीं अधिक सिर ऊँचा कर जा सकेंगे। इन सबके बाजजूद चीन से सतर्क रहने में ही समझदारी है।

आखिरकार आपने देखा नहीं विगत 5 सितम्बर, 2017 को चीन के शहर शियामिन में एशिया के दो ताकतवर पड़ोसी देशों चीन और भारत के क्रमशः राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तरफ से मतभेदों को विवाद नहीं बनने देने का संकल्प लेते हुए कहा गया कि सीमा पर शांति व स्थायित्व बनाए रखना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ महीनों के दौरान भारत व चीन के द्विपक्षीय रिश्तों में आए तनाव के मद्देनजर मोदी और जिनपिंग की इस मुलाकात को काफी अहम इसलिए माना जा रहा है कि बैठक में दोनों नेताओं का नजरिया आगे बढ़ने वाला था। इसमें माना गया कि सीमा क्षेत्रों में शांति व स्थिरता भारत-चीन संबंधों के विकास की पूर्व शर्त हैं, दोनों ने यह महसूस किया कि दोनों देशों के रक्षा व सैन्य विभागों से जुड़ें अधिकारियों के बीच ताल्लुकात और गहरे होने चाहिए।

(194)प्रश्नः रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार से भाग कर भारत क्यों आ रहे हैं? राजनीतिक पार्टियाँ नेशनल कान्फ्रेंस और पीडीपी दोनों ही इन रोहिंग्यों मुसलमानों को लेकर अचानक इतनी द्रवित क्यों हो रही हैं? रोहिंग्या म्यांमार से इतना लंबा सफर तय करके केवल जम्मू में ही क्यों पहुँचते हैं?

उत्तरः विजय जी, आपके इन तीनों सवालों के जवाब देने के पूर्व मैं आपको यह बताना लाजिमी समझता हूँ कि रोहिंग्या मुसलमान हैं कौन और कहाँ के रहने वाले हैं। पहली बात तो यह कि रोहिंग्या बांग्लादेश की चिटगाँव पहाड़ियों में रहने वाला समुदाय है। जब भारत में ब्रिटिश सरकार का कब्जा हुआ तो म्यांमार में सस्ते मजदूरों की तलाश में लगे अँग्रेजों का ध्यान रोहिंग्या मुसलमानों की ओर गया और वह इन्हें म्यांमार में अरकान के पर्वतीय इलाकों में बसाने लगे। अब वहाँ इनकी आबादी तकरीबन दस लाख है।

जहाँ तक रोहिंग्या मुसलमानों के म्यांमार से भाग कर भारत आने के कारणों का सवाल है पहली बात तो यह कि म्यांमार में वहाँ की सेना रोहिंग्या

मुसलमानों के मानवीय अधिकारों का हनन कर रही हैं, उनकी औरतों के साथ बलात्कार कर रही हैं, उनके घरों को जलाकर उन्हें देश के बाहर धकेल रही है। इन्हीं सब वजहों से रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थी बनकर भारत आ रहे हैं। भारत में इस्लामी हमलों के वक्त इन रोहिंग्या समुदायों को बलपूर्वक मुसलमान बना लिया गया था और इन्हें शुद्ध इस्लाम सिखाने के नाम पर उनको उनकी पारंपरिक जड़ों से ही काटने का प्रयास किया गया और सऊदी अरब के पैसे के बल पर अराकान की पहाड़ियों में बहाबी आंदोलनकारियों ने अराकार रोहिंग्या मुक्ति सेना स्थापित कर, म्यांमार देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। सच तो यह है कि रोहिंग्या मुसलमानों की यह आतंकीवादी सेना वहाँ के बौद्ध मतावलंबी स्थानीय लोगों को खदेड़ कर वहाँ इस्लामी राज्य स्थापित करना चाह रही है। हजारों म्यामारियों को मारा गया और बाकी बचे लोगों को वहाँ से भगा दिया गया। यह काम वहाँ अब भी चल रहा है।

रोहिंग्या मुसलमान मूलतः बंगलादेश के रहने वाले हैं और म्यांमार से बंगलादेश नजदीक है फिर भी वे बंगलादेश न जाकर भारत क्यों आ रहे हैं और उन्हें जम्मू-कश्मीर में लेकर कौन आ रहा है तथा वहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ नेशनल कान्फ्रेंस और पीडीपी दोनों ही इन रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर अचानक इतनी द्रवित क्यों हैं जबकि जम्मू-कश्मीर में तो स्थायी निवासी के अतिरिक्त कोई भारतीय नागरिक भी नहीं बस सकता, फिर यह भी आश्चर्य की बात है कि इन रोहिंग्या मुसलमानों को कश्मीर घाटी तक जाने की बजाय जम्मू में ही रूक जाने को क्यों कहा जा रहा है जिसका कोई न कोई जवाब तो नेशनल कान्फ्रेंस और पीडीपी के पास तो होना ही चाहिए।

मुझे ऐसा लगता है कि कहीं रोहिंग्या संकट का लाभ उठाकर कुछ संघटन किसी योजना और रणनीति के तहत जम्मू का जनसांख्यिकी अनुपात को बदलना नेशनल कान्फ्रेंस और पीडीपी के नेताओं की मंशा तो नहीं है? इसी के ख्याल से रोहिंग्या मुसलमानों को जम्मू-कश्मीर में पहुँचाकर वहाँ के वहाबी संघटनों के माध्यम से उन्हें जम्मू में बसाने की वकालत करता है। वहाबी संघटनों का एक समूह यह भी चाहता है कि भारत सरकार रोहिंग्या मसले को लेकर म्यांमार सरकार और वहाँ के सुरखा बलों की निन्दा का अभियान चलाए, ताकि प्रतिक्रिया में म्यांमार एक बार फिर चीन की गोद में जाकर बैठ जाए। नेशनल कान्फ्रेंस के नेता फारूख अबदुल्ला और पीडीपी नेताओं के जो बयान आ रहे हैं वे जम्मू-कश्मीर के आतंकियों को उकसाने

और उसके समर्थन में दिखते हैं। इसके मद्देनजर भारत सरकार को रोहिंग्या के मामले में देशहित में सही रणनीति-कूटनीति अपनानी होगी।

(195)प्रश्न: *क्या आपको ऐसा लगता है कि मुंबई ब्लास्ट के आरोपित अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम की ब्रिटेन स्थित 43 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त किए जाने की प्रक्रिया से भारत को इस माफिया डॉन के खिलाफ पाकिस्तान पर दबाव बनाने में और मदद मिलेगी?*

उत्तर: हाँ, डॉ. वधान साहब, मुझे भी ऐसा लगता है कि मुंबई ब्लास्ट के आरोपित अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम की ब्रिटेन स्थित 43 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त किए जाने की प्रक्रिया से भारत को इस माफिया डॉन के खिलाफ पाकिस्तान पर दबाव बनाने में और मदद मिलेगी। उल्लेख्य है कि भारत सरकार के अनुरोध पर ब्रिटेन ने दाउद इब्राहिम की ब्रिटेन स्थित होटलों, घरों और वाणिज्यिक तकरीबन 43 हजार करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। बताया जाता है कि दाउद ने अपनी काली कमाई का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन और दुबई में लगा रखा है। संयुक्त राष्ट्र संघ दाउद को अलकायदा से जुड़ा अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित कर चुका है। ऐसे में दुनिया के सभी देशों की उसकी संपत्ति होने की स्थिति में जब्त करने का अधिकार है।

इस लिहाज से देखा जाए तो यह दाउद और उसके पाकिस्तानी सरपरस्तों के लिए एक करारा झटका है। 1993 में मुंबई ब्लास्ट की साजिश रचने का अरोप दाउद पर है। पिछले दिनों ही मुंबई ब्लास्ट के अभियुक्तों यथा दाउद के पूर्व साथी अबू सलेम को इसी मामले में सजा सुनाई गयी है। अब दाउद पर एक्शन से भारत को इस माफिया डॉन के खिलाफ पाकिस्तान पर दबाव बनाने में और मदद मिलेगी। पाकिस्तानी जिस तरह से भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को संरक्षण देता रहा है, वह अब उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है।

(196)प्रश्न : क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वैश्वीकरण के दौर में राष्ट्रवाद के विरोध के बहाने उदार लोकतंत्रवादी और साम्यवादी दोनों ने साथ, मिलकर पूरी दुनिया के अर्थतंत्र, बौद्धिक जगत, अकादमिक जगत और मीडिया पर कब्जा कर लिया है? ऐसा क्यों?

उत्तर: हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि वैश्वीकरण के दौर से राष्ट्रवाद के विरोध के बहाने उदार लोकतंत्रवादी और साम्यवादी दोनों ने साथ

मिलकर पूरी दुनिया के अर्थतंत्र, बौद्धिक जगत, अकादयिक जगत और मीडिया पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि 1989 में सोवियत संघ के विघटन और साम्यवाद के बिखराव के बाद दुनिया में पूर्व और पश्चिम का वैचारिक संघर्ष खत्म हो गया है और पश्चिम की उदार लोकतंत्रवादियों की जीत हो गई है। चूंकि पश्चिम का लोकतंत्र स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत पर टिका है, इसलिए माना गया कि किसी को एतराज नहीं होगा।

इसी परिकल्पना से वैश्वीकरण के सिद्धांत को बल मिला। वैश्वीकरण के लिए जरूरी था कि राष्ट्रवाद टूटे, क्योंकि वही इसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा थी। पूंजीवाद मुक्त बाजार को पसंद करता है, लेकिन वास्तव में वह इसके बहाने समाज के प्रभु वर्ग के लिए बाजार में हेराफेरी करता है। वैश्वीकरण कहता है कि दुनिया में जहाँ कच्चा या सस्ता माल मिले वहाँ से लो। जहाँ मजदूर सस्ता मिले वहाँ विनिर्माण करो और जहाँ लोगों में खरीदने की शक्ति हो वहाँ बेचो। इस व्यवस्था में उस देश के लोगों के रोजगार के बारे में कोई विचार नहीं होता। साम्यवाद के खात्मे के बाद भारत और दुनिया के साम्यवादियों के लिए कोई आसरा नहीं रह गया। राष्ट्रवाद के पहले भी खिलाफ थे। सो साम्यवादी यूरोप और अमेरिका की पूँजी से चलने वाले लोग एनजीओ में चले गए। इस प्रकार वैश्वीकरण के दौर में राष्ट्रवाद के विरोध के बहाने उदार जनतंत्रवादी को साम्यवादियों का साथ मिल गया। दोनों ने मिलकर पूरी दुनिया के अर्थतंत्र, बौद्धिक जगत, अकादमिक जगत और मीडिया पर कब्जा कर लिया।

सच तो यह है कि वैश्वीकरण का पहला कार्यक्रम ही राष्ट्रवाद खत्म करना था। इस गठजोड़ ने एक झूठ को दुनिया प्रचारित किया कि साम्यवादी-उदार जनतंत्रवादी के अलावा दुनिया का कोई भविष्य नहीं है। इतिहास खत्म हो चुका है, इस झूठ को प्रचारित करते-करते वे उस पर यकीन करने लगे। कुछ साल तक दुनिया में लोग वैश्वीकरण की चकाचौंध से औंधियाए रहे, फिर धीरे-धीरे उन्हें अहसास होने लगा कि वैश्वीकरण ने उनकी आजीविका छीन ली, राष्ट्रीय पहचान खत्म हो रही और लोग बाजार एवं उपभोक्ता बनकर रह गए। जबतक लोग चुपचाप सहते रहे, लगता रहा सबकुछ ठीक है। फिर धीरे-धीरे लोगों की राष्ट्रवाद की आकांक्षा जगी और बदलाव का दौर शुरू हुआ। इसी का असर भारत पर भी पड़ा और पिछले चार साल से बदलाव स्पष्ट दिख रहा है। साम्यवाद और उदार लोकतंत्रवादी अपने आखिरी पैर पर खड़े हैं। भारत में यह लड़ाई दिग्भ्रमित करने के लिए पहले बहुसंख्यकवाद के खतरे का हौवा खड़ा

किया गया। मगर यहाँ के आमजन चेत गए हैं। काँग्रेस और साम्यवादी एक साथ खड़ी हैं पर राष्ट्रवादी भावना के उभार से वे सभी पस्त हैं।

(197)प्रश्नः क्या अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के प्रति रवैया सख्त करने से आतंकी घटनाओं में कमी आएगी?

उत्तरः हाँ, अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के प्रति रवैया सरल करने से निश्चित रूप से आतंकी घटनाओं में कमी आएगी और पाकिस्तान अलग-थलग पड़ सकता है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन के शीर्ष सूत्र के मुताबिक वाइट हाउस की ओर से पाकिस्तान को दी जा रही आर्थिक मदद पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। अमेरिका अब आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को किसी भी तरह से बख्शने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों और आतंकी संगठनों पर निशाना साधने के बाद अब अमेरिका की मंशा पाकिस्तान को दी जा रही आर्थिक मदद पर रोक लगाने की है। पाकिस्तान पर यह रोक तबतक जारी रहेगी, जबतक वह अपने देश में मौजूद आतंकियों के सुरक्षित ठिकानों पर कार्रवाई शुरू नहीं कर देता। ऐसे में अब पाकिस्तान पर दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भी अलग-थलग पड़ने का खतरा मंडरा रहा है।

हक्कानी नेटवर्क को लगातार इस्लामाबाद सरकार की ओर से मिल रहे समर्थन और 6 साल से जेल में कैद शकील अफरीदी नाम के डॉक्टर, जिसने ओसामा बिन लादेन का पता लगाने में अमेरिका की मदद की थी, को रिहा न करना जैसे कई मुद्दों को इस बार वाइट हाउस ने गंभीरता से लिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अपने भाषण में भी डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों को सख्त संदेश दिया। ट्रंप ने कहा कि हमें आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों के खिलाफ खड़ा होना होगा, उन्हें किसी देश से मिल रही फंडिंग और दूसरी मदद को भी बंद करना होगा।

(198)प्रश्नः क्या उत्तर कोरिया की भड़काऊ हरकतों के जवाब में जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने कमर कसना शुरू कर दिया है? आखिर कैसे?

उत्तरः हाँ, उत्तर कोरिया की भड़काऊ हरकतों के जवाब में जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने कमर कसना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र संघ ने अबतक किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति से ऐसे बोल नहीं सुने थे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने आमसभा के अपने पहले संबोधन में सुनाए। ट्रंप ने आतंकवाद और उत्तर कोरिया पर अपने नजरिए से

यह स्पष्ट कर दिया कि आने वाला समय दुनिया के लिए और भी कठिन होगा। ट्रंप ने यह माना कि आतंकवादी हर जगह सिर उठा रहे हैं, लेकिन शांति संभव है। उन्होंने कहा, 'सीधे कहा जाए तो हम एक ऐसे समय में मिल रहे हैं, जब अपार वादे और बड़े खतरे दोनों हैं। आतंकवादी और चरमपंथी दोनों ने ताकत हासिल की है और वे धरती पर हर जगह फैल गए हैं।' ट्रंप ने यह भी कहा, 'हम कट्टर इस्लामिक आतंकवाद को रोकेंगे, क्योंकि हम उसे अपने देश को, वाकई में पूरी दुनिया को तहस-नहस नहीं करने दे सकते। हमें अपने देशों से उन्हें हर हालत में खदेड़ना चाहिए। यह उन देशों को बेनकाब करने और जिम्मेदार ठहराने का वक्त है जो अलकायदा, हिजबुल्ला, तालिबान जैसे आतंकवादी संगठनों को सहयोग पहुँचाते हैं और पैसा उपलब्ध कराते हैं।'

लैटिन अमेरिका, यूरोप, खाड़ी देश और दक्षिण एशियाई देशों के बाद उत्तर कोरिया का जिक्र करते हुए ट्रंप आक्रामक हो गए और उसके नेता किम जोंग उन के लिए नए विशेषण का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा, रॉकेटमैन खुद अपने लिए और परमाणु हथियारों से लैस अपने शासन के लिए आत्मघाती बन रहा है। ऐसे में अमेरिका तैयार है, उसमें इच्छाशक्ति है और वह सक्षम है, वह अपना और अपने सहयोगियों का बचाव करने को मजबूर है। ऐसे में हमारे पास उत्तर कोरिया को पूरी तरह नष्ट कर देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी जरूरत ही ना पड़े।

ऐसे में जब उत्तर कोरिया ने एक महीने से भी कम समय में 6 परमाणु परीक्षण करने के साथ ही दो मिसाइलें जापान के ऊपर से दाग दी हैं और समय आने पर जापान को समुद्र में 'डुबो' देने की धमकी दी है, तब ट्रंप के इस बयान के काफी मायने हैं। जापान ने अपने उत्तरी द्वीप होक्काई में पैट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी-3 मिसाइल रक्षा प्रणाली के अलावा एक और मिसाइल रक्षा प्रणाली तैयार किया है।

हथियारों की नई दौड़ में हो सकता है कि आने वाले वक्त में दक्षिण कोरिया और जापान भी शामिल हो जाएँ और परमाणु परीक्षण करने लगें। जाहिर है बमों के जखीरे पर बैठ कर शांति की बात नहीं हो सकती। समझना तो दोनों ही पक्षों को होगा। यह दुनिया तीसरे विश्वयुद्ध के लिए तैयार नहीं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर कोरिया की हरकतों के मद्देनजर जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने कमर कसना शुरू कर दिया है।

(199)प्रश्नः शहीद-ए-आजम भगत सिंह को ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सान्डर्स की हत्या के मामले में बेगुनाह साबित करने के लिए याचिका दायर करने वाले पाकिस्तानी वकील राशिद कुरेशी की आखिर क्या मंशा है?

उत्तरः शहीद-ए-आजम भगत सिंह को ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सान्डर्स की हत्या के मामले में बेगुनाह साबित करने के लिए पाकिस्तान के वकील राशिद कुरैशी ने लाहौर अदालत में जो याचिका दायर की है उस केस को दोबारा खोलने का मकसद यही है कि ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भगत सिंह को दी गई सजा गलत मानी जाए और खुद ब्रिटिश हुकूमत गलती मानते हुए भगत सिंह को सम्मान करे, क्योंकि उनका तर्क है कि न तो शहीद भगत सिंह का नाम एफआईआर में दर्ज था और न ही किसी भी तरह की बहस की गई। फिर कैसे कोर्ट किसी को फाँसी जैसी सजा दे सकती है। ये कानून का उल्लंघन है।

वकील राशिद कुरैशी का यह भी कहना है कि आयरलैंड के रोजर कैसमेंट आयरलैंड के एक बड़े क्रांतिकारी थे और जब आयरलैंड ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था, तब रोजर को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने और आयरलैंड की क्रांति में योगदान देने के लिए मौत की सजा दी गई थी, लेकिन उनकी मौत के बाद ब्रिटिश सरकार ने ही उनके नाम को सम्मान दिया था, तो शहीद भगत सिंह के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता?

वकील कुरैशी का यह भी कहना है कि उस समय भगत सिंह को लाहौर की कोर्ट ने सजा सुनाई जिस समय हम पर ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी और हम आजाद नहीं थे, लेकिन आज तो हम आजाद हैं, पहले से ज्यादा मजबूत हैं और वैश्विक रूप से हमारी पहचान है। तो हम फिर आज इस मामले को उठाकर उनकी सजा को गलत क्यों नही साबित कर सकते। आज हमारी न्याय व्यवस्था मजबूत है। देश में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक को कोर्ट का सम्मान करना पड़ता है। बड़े-बड़े पदों पर आसीन लोगों को कोर्ट ने सजा दी है, फिर फैसले पलटे हैं। ऐसे-ऐसे फैसले आए हैं जो मिसाल बने हैं, तो फिर शहीद भगत सिंह के मामले में दोबारा सुनवाई कर उन्हें निर्दोष क्यों नहीं साबित किया जा सकता।

भले ही आज भगत सिंह हमारे बीच नहीं हैं, भले ही उन्हें शहीद हुए 86 साल हो गए, लेकिन अब लड़ाई इस बात की है कि उन्हें सजा गलत दी गई। कुछ इसी ख्याल से पाकिस्तानी वकील कुरैशी द्वारा इस

मुकदमों को दोबारा खुलवाने का मकसद यही है कि ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भगत सिंह को दी गई सजा गलत मानी जाए, खुद ब्रिटिश हुकूमत गलती मानते हुए भगत सिंह का सम्मान करे। भगत सिंह अगर भारत के लिए शहीद हैं तो वह पाकिस्तान का बेटा भी है। ऐसे में दोनों देशों के हुकुमरानों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मुद्दे को उठाते हुए उनकी सजा को गलत साबित करने की जंग करे।

(200)प्रश्नः क्या भारत-जापान की दोस्ती से एशिया में भारत की स्थिति और मजबूत होगी?

उत्तरः हाँ, भारत-जापान की दोस्ती से एशिया में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। अभी-अभी आपने देखा नहीं विगत 14 सितंबर, 2017 को भारत और जापान की द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पीएम नरेन्द्र मोदी और जापानी पीएम शिंजो आबे की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच पन्द्रह समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और दोनों के साझा बयान में दोनों देशों ने आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा रूख अपनाते हुए पाकिस्तान पर हमला बोला। दोनों नेताओं ने पाक से मुंबई हमले और पठानकोट के गुनहगारों को सजा देने को कहा है। इसके अतिरिक्त आतंकी संगठनों अलकायदा, आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के खिलाफ साझा सहयोग को और मजबूत बनाने पर जोर देने की बात की है। दोनों देश के नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर जोर देते हुए सभी देशों को इनको पनाह देने वाले देश, फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क के खिलाफ काम करने को कहा है। इसके अलावा सुरक्षा और मैरीटाइम के क्षेत्र में पाइरेसी से मुकाबले को लेकर अपनी बचनबद्धता दोहराते हुए समुद्री डाकूओं से लड़ने और अन्य तरह के संगठित अपराध से निपटने के लिए क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मैकेनिज्म बनाने की बात कही है।

मोदी और आबे ने कड़े शब्दों में उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार बनाने और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की आलोचना की। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ जापान इंडिया कंसल्टेशन को आगे बढ़ाने की बात कही है।

इसके पूर्व दोनों देशों की दोस्ती की बुलेट रफ्तार में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने 14 सितम्बर, 2014 को अहमदाबाद-मुंबई के बीच चलने वाले देश के पहले हाई स्पीड बुलेट ट्रेन नेटवर्क की नींव रखी और प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। बुलेट ट्रेन परियोजना ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें तेज गति

भी है, तेज प्रगति भी और सुविधा भी है तथा सुरक्षित भी। यह प्रोजेक्ट रोजगार भी लाएगा और व्यापार भी।

वैसे भी एशिया में चीन के उभार और अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से बनी अनिश्चितता के मद्देनजर भारत–जापान को तेजी से नजदीक आना एक अनिवार्यता है। यह निकटता न सिर्फ भारत की आर्थिक तरक्की की रफ्तार बढ़ाएगी, बल्कि जापान और भारत दोनों के लिए रणनीतिक सुरक्षा और चौकसी का आधार भी प्रदान करेगी। जब चीन वन बेल्ट वन रोड की परियोजना को तेजी से मूर्त रूप दे रहा हो और डोकलाम में लंबे समय के तनाव बाद लौटी शांति के स्थायी शांति होने की कोई गारंटी न हो तब भारत को एशिया में अपना नया दोस्त ढूँढ़ना जरूरी था। आखिर तभी तो भारत–जापान ने हाल ही में चीन को चेताया कि हिंद से प्रशांत तक किसी की मनमानी नहीं चलेगी। भारत–जापान की दोस्ती और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के साझा बयानों और चेतावनी भरे लहजों से तो स्पष्ट है कि एशिया में भारत की स्थिति मजबूत होगी।

(201)प्रश्नः क्या भारत-जापान रक्षा रणनीति शांति के लिए कारगर सिद्ध हो पाएगी अथवा इससे स्थितियाँ और बिगड़ेंगी?

उत्तरः पिछले दिनों जापान के प्रधानमंत्री शिंजों आबे के भारत दौरे के साथ जिस नयी साझेदारी की शुरुआत हुई है उसे भारत और जापान की मीडिया इस दोस्ती को चीन के खिलाफ एक अहम कदम के रूप में देखने की कोशिश के रूप में प्रदर्शित किया है। भारत और जापान के शीर्ष नेताओं की मुलाकात को चीन के बढ़ते प्रभुत्व को रोकने की कोशिश बतायी है। चीन जिस तरह से हिंद महासागर में अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा है, ऐसे में भारत और जापान के नेता मिलकर अपनी समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना चाह रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं कि चीन जिस तरह से हिंद महासागर में अपनी गतिविधियाँ चला रहा है, वह भारत के लिए सामरिक चुनौती की तरह है, इसलिए भारत हर हाल में चीन को काउंटर करना चाहेगा। यदि जापान के साथ 'टू प्लस टू' रणनीति सफल हो जाती है तो भारत अपने इस उद्येश्य में सफल हो जाएगा।

सनद रहे कि 'टू प्लस टू' डायलॉग भारत और जापान के बीच सुरक्षा सहयोग संबंधी पहल है जो यह संकेत करता है कि अब भारत और जापान सुरक्षा सहयोग में 'टू प्लस टू' डायलॉग द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय मैरीटाइम एक्सरसाइज तथा हथियारों की बिक्री शामिल होगी। जापान उत्तर

कोरिया की उदंडता को देखते हुए इस डायलॉग को जल्द ही संपन्न करने का इच्छुक है। दरअसल, उत्तर कोरिया ताकतवर हाइड्रोजन बम के जरिए कम से कम अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहता है। जापान भारत के साथ मजबूत साझेदारी चाहता है। हिंद महासागर में चीन के विस्तार के मद्देनजर यह काफी अहम है। भारत के लिए जरूरी है कि चीन को हिंद महासागर में नियंत्रित करे और जापान के लिए आवश्यक है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीनी गतिविधियों को रोके।

इस प्रकार कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत-जापान रक्षा रणनीति शांति के लिए इसलिए कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि चीन और उत्तरी कोरिया की उदंडता को देखते हुए एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीनी गतिविधियों को रोकने के साथ-साथ उत्तर कोरिया की हैंकड़ी को दुरुस्त करने की रणनीति है। एक तरफ चीन जहाँ एशिया प्रशांत में उत्तरी कोरिश के जरिए अपने मकसद पूरे करना चाहता है, वहीं पाकिस्तान के जरिए दक्षिण एशिया में। ऐसी स्थिति में भारत-जापान-ऑस्ट्रेलिया-अमेरिका रणनीतिक चतुर्भुज का निर्माण बेहद जरूरी है, ताकि शक्ति संतुलन बना रहे और युद्ध की नौबत न आने पाए। इस दृष्टि से भारत-जापान रक्षा रणनीति शांति के लिए कारगर सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

(202)प्रश्न: देश में रह रहे अवैध शरणार्थी रोहिंग्या मुसलमान से क्या देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा नहीं है? आखिर क्यों?

उत्तर: हाँ, देश में रह रहे अवैध शरणार्थी रोहिंग्या मुसलमानों से देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा है, क्योंकि एक तो रोहिंग्या मुसलमान अवैध शरणार्थी हैं और दूसरे कि इनमें से कुछ आतंकी संगठनों से जुड़ें हैं जिनकी संख्या 40 हजार से ज्यादा बताई जा रही है। सरकार ने गैरकानूनी घुसपैठियों को वापस भेजने के मसले को नीतिगत मामला बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर कर इसमें दखल न देने का अनुरोध भी किया है। 16 पृष्ठों के इस हलफनामें में गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि रोहिंग्या शरणार्थियों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत देश में कहीं भी आने-जाने और बसने जैसे मूलभूत अधिकार नहीं दिए जा सकते। ये अधिकार सिर्फ इस देश के नागरिकों के लिए ही हैं। इन अधिकारों के लिए रोहिंग्या मुसलमान सर्वोच्च न्यायालय में गुहार भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वे इसके दायरे में नहीं आते हैं। उसपर भी खासतौर पर जम्मू-कश्मीर में तो और भी नहीं वे बस सकते, क्योंकि वहाँ तो इस देश के नागरिकों को अपनी

जमीन खरीदकर बसने का अधिकार नहीं है। इसलिए रोहिंग्या मुसलमानों का इस देश में रहना इसकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।

आपको याद होगा 2012 से देश में रोहिंग्या मुसलमानों ने अवैध तरीकों से प्रवेश किया और उनमें से कई ने तो पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र भी बनवा लिए हैं। सरकार ने भी माना है कि एजेंटों और दलालों के जरिए संगठित रूप से गैर कानूनी रोहिंग्याओं की म्यांमार से भारत में घुसपैठ कराई जा रही है। यह घुसपैठ पश्चिम बंगाल के बेनापोल हरिदासपुर और दिल्ली तथा त्रिपुरा के सोनामीरा के अलावा कोलकाता और गुवाहाटी से कराई जाती है।

सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक याचिका की सुनवाई पर रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में चाहे जिस नतीजे पर पहुँचे, पर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या अवैध रूप से भारत आने वालों को भी भारतीय नागरिकों जैसे अधिकार प्राप्त हो गए हैं? यह बात ठीक है कि भारत की पहचान एक ऐसे देश की है जिसने हर किसी को शरण दी और बिना भेदभाव के स्वीकार किया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हो सकता है कि वह खुद को धर्मशाला में तब्दील कर ले और दुनिया में जो भी कहीं प्रताड़ित या फिर वह परेशान न हो, इसलिए उसे भारत आने की सुविधा दे दी जाए। कारण कि इसमें कोई संदेह नहीं कि रोहिंग्या मुसलमान देश की सुरक्षा और सामाजिक ताने-बाने के लिए कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि उनके बीच अतिवादी तत्व सक्रिय हो सकते हैं।

और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बांग्लादेश भी रोहिंग्या मुसलमानों को अपने यहाँ नहीं रखना चाहता है, क्योंकि बांग्लादेश की सुरक्षा के लिए भी उनसे खतरा है। उनके यहाँ पूर्व में घटनाएँ घट चुकी हैं। यही कारण कि रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर वहाँ की सरकार सावधान है। सच तो यह है कि रोहिंग्या मुसलमानों से किसी भी देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा इसलिए भी है, क्योंकि इनके पाकिस्तान में मौजूद आतंकी गुटों से रिश्ते हैं। एक अहम बात यह भी है कि भारत स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी कन्वेंशन (1951 और 1967) का हिस्सा नहीं है, न ही इस पर भारत ने दस्तखत किए हैं। लिहाजा इससे जुड़े कानून या शर्त भी मानने के लिए भारत मजबूर नहीं है।

आपने यह भी देखा कि म्यांमार की सेना से बदला लेने के लिए भारत में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को ट्रेनिंग देकर तैयार करने की साजिश

के लिए भारत आए अलकायदा आतंकी को यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया। आतंकी मॉड्यूल के सफाए में लगी दिल्ली पुलिस की विशेष सेल ने बांग्लादेशी मूल के इस ब्रिटिश नागरिक को विगत 17 सितंबर, 2017 को पकड़ा। पहले उसने अपना नाम शामन हक बताया। बिहार के किशनगंज से जारी पहचान पत्र दिखाया। लेकिन असलियत में वह समिउन रहमान उर्फ राजू भाई निकला। वह जुलाई, 2017 में ही भारत आया था।

ऐसी स्थिति में अगर रोहिंग्या मुसलमानों को रहने दिया गया, तो भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रभावित होंगे। स्थिरता को नुकसान पहुँच सकता है और सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। अब तो ऐसी स्थिति आ गयी है कि रोहिंग्या को पाकिस्तान भी शरण देने को तैयार नहीं है। अमीर मुस्लिम देश भी उन्हें शरण नहीं दे रहे। यहाँ तक कि जो देश मुसलमानों के लिए मातम मनाते हैं उन्होंने भी उनसे मुँह फेर लिया है। मुस्लिम कट्टरपंथी देश रोहिंग्या को लेकर शोर तो मचा रहे हैं, पर वे उन्हें शरण नहीं दे रहे। मुस्लिम देश आम तौर पर शरणार्थियों को शरण नहीं देते। अरब के लाखों असहाय शरणार्थियों के लिए अरब देशों के ही दरवाजे बंद होने पर वे यूरोप के देशों में शरण ले रहे हैं। मुस्लिम शरणार्थियों को आश्रय गैर इस्लामिक देश देते हैं।

जिस तरह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई खुंखार आतंकी संगठन आईएस के साथ-साथ भारत विरोधी आतंकी संगठन लश्कर और जैश की तरफ से रोहिंग्या मुसलमानों को लुभाने की कोशिश हो रही है, भारत की चिंता स्वाभाविक है। इसके मद्देनजर भारत सरकार को अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि निश्चित रूप से अवैध शरणार्थी रोहिंग्या मुसलमानों से देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। वैसे भी रोहिंग्या के प्रति सहानुभूति दिखा रहे लोगों को इसे नहीं भूलना चाहिए कि आज शरण माँगने वाले लोग कल को आँखे दिखाने लगेंगे। जब कश्मीरी पंडितों को धारा-370 के कारण अधिकार नहीं मिला, तो फिर रोहिंग्या शरणार्थियों को कैसे दिया जा सकता है?

(203)प्रश्नः संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक महाधिवेशन के इतर ब्रिटेन और इटली द्वारा 'ऑनलाइन आतंकवाद' विषय पर आयोजित बैठक में इंटरनेट के इस्तेमाल और ऑनलाइन फंडिंग पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई करने की जरूरत क्यों बताई गई?

उत्तर: संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के वार्षिक महाधिवेशन के इतर पिछले दिनों ब्रिटेन और इटली द्वारा 'आतंकियों को इंटरनेट के इस्तेमाल से रोकना' विषय पर आयोजित बैठक में आतंकी गतिविधियों के लिए हो रहे इंटरनेट के इस्तेमाल और ऑनलाइन फंडिंग पर चिंता जताते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई करने की जरूरत इसलिए बताई गई, क्योंकि कट्टरता फैलाना, आतंकियों की भर्ती और धन जुटाने में इंटरनेट के बेजा इस्तेमाल की बात पहले ही साबित हो चुकी है। इसलिए भारत के विदेश सचिव जयशंकर के अतिरिक्त ब्रिटिश की प्रधानमंत्री टेरीजा मे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैन्युएल और इटली के प्रधानमंत्री पाओली जेंटीलोनी ने बैठक में हिस्सा लेकर कहा कि 'आतंक के खिलाफ हर जगह समान तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अलग-अलग मानक कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इन देशों के प्रतिनिधियों ने कहा कि आतंक के सवाल पर खासकर इंटरनेट के बेजा इस्तेमाल पर हाथ पर हाथ धरे नहीं रह सकते। इसलिए यह मंच इस समस्या पर ज्यादा सक्रियता के साथ प्रहार करने का प्रयास है। उल्लेख्य है कि इस्लामिक स्टेट इंटरनेट के माध्यम से बड़ी तादाद में न केवल लोगों को आतंकी बनाने में सफल रहा है, बल्कि धन भी जुटाया है। इसके मद्देनजर ऑनलाइन आतंक पर कार्रवाई की जरूरत है।

(204)प्रश्न: भारतीय सेना द्वारा म्यांमार सीमा पर नगा उग्रवादियों के खिलाफ अचानक किए गए ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिये जाने को आप कितना अहम मानते हैं और क्यों?

उत्तर: डॉ. गोपाल जी, भारतीय सेना द्वारा पिछले दिनों म्यांमार सीमा पर नगा उग्रवादियों के खिलाफ अचानक किए गए ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिए जाने को मैं इसलिए अहम मानता हूँ, क्योंकि ये ऑपरेशन एक तो दुनिया को यह बता देने के लिए काफी है कि भारत की सीमा के पार जाकर भी हम दुश्मनों को उनकी हश्र तक पहुँचाने का मादा रखते हैं। भारत को अबतक शांत देश ही समझा जाता रहा है। दुनिया ने महात्मा गाँधी के अहिंसा मात्र को हमारे देश की मजबूरी मान लिया, लेकिन यह भूल गए कि गाँधी के इस देश में क्रांतिकारियों की फौज भी हुआ करती थीं जिन्हें दुश्मनों को उनकी ही भाषा में जवाब देना आता था।

विगत 27 सितंबर, 2017 को भारतीय सेना के इस ऑपरेशन में नेशनल सोशलिस्ट कांउसिल ऑफ नगालैंड से जुड़े उग्रवादियों को भारी नुकसान पहुँचा है जबकि यह सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था, क्योंकि सेना ने

बॉडर क्रॉस नहीं किया था। अपनी सरहद में रहते हुए ही उग्रवादियों को निशाना बनाकर भारी नुकसान पहुँचाया गया है। गौर से देखा जाए तो हमारे जवानों को ये ऑपरेशन जोश और गर्व से भरनेवाला है तथा देश की सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह जायज है, क्योंकि देश और यहाँ के नागरिकों को नुकसान पहुँचाने वाले ऐसे उग्रवादियों को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(205)प्रश्नः क्या आपको ऐसा लगता है कि 1993 मुंबई बम धमाकों के मुख्य आरोपी दाउद इब्राहिम को भारत सरकार उसे भारतीय कानून के प्रावधानों के तहत सजा दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है? आखिर कैसे?

उत्तरः हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि 1993 मुंबई बम धमाकों के मुख्य आरोपी दाउद इब्राहिम जिसका पाकिस्तान मुख्य ठिकाना हो गया और पाकिस्तान की सेना एवं उसका खुफिया एजेंसी आईएसआई दाउद की सबसे बड़ी रक्षक है, को भारत सरकार उसे भारतीय कानून के प्रावधानों के तहत सजा दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि दाउद केंद्र की पिछली सरकारों और हमारे कुछ राजनेताओं के सरकारी संरक्षण के चलते एक छोटा-सा स्मगलर बड़ा आतंकवादी बन गया। अभी आपने देखा नहीं पिछले दिनों दाउद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर की मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में यह कहते हुए सियासत को गरमा दिया कि दाउद तो खुद भारत लौटना चाहता है, लेकिन मोदी सरकार उसकी वापसी का श्रेय लूटना चाहती है। राज ठाकरे यहीं नहीं रुके, उन्होंने इसी आशय का एक कार्टून चित्र भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। राज ठाकरे जैसे भाषण कला और ताकत के लिए जाने जाते नेता राजनीति में अब पिट चुके हैं और उत्तर भारतीयों से नफरत एवं मराठी बनाम गुजराती का मुद्दा राजनीति से गायब हो चुका है। इसलिए भारत सरकार ऐसे राजनेताओं के चक्कर में न पड़कर दाउद को भारतीय कानून के प्रावधानों के तहत सजा दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि ऐसे खूंखार अपराधियों को सबक मिल सके।

(206) प्रश्नः क्या आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के प्रमुख राजनीतिक दल 'पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज)' पर अस्तित्व का संकट है?

उत्तरः हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के प्रमुख

राजनीतिक दल 'पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज)' पर अस्तित्व का संकट है, क्योंकि पाकिस्तान की राजनीति में जिस प्रमुख दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग(नवाज) की बड़ी हैसियत थी वह नवाज शरीफ को पनामागेट घोटाला कांड पर पाक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री के पद से हटाए जाने की वजह से देश का राजनीतिक वातावरण ही बदल गया है। हालांकि यह भी सच है कि पिछले दिनों लाहौर स्थित नवाज शरीफ के हटने पर जो सीट खाली हुआ उसपर हुए उपचुनाव में नवाज शरीफ की पत्नी कुलसुम नवाज शरीफ की जीत हुई। चुनाव के वक्त लंदन स्थित एक अस्पताल में अपने कैंसर का इलाज कराने के लिए वह गई हुई थी। इस उपचुनाव के साथ ही पाकिस्तान की राजनीति में उथल-पुथल तेज हो गई।

नवाज शरीफ की कैंसर से पीड़ित पत्नी कुलसुम नवाज की जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। यह हालात पाकिस्तान के प्रतिष्ठित राजनीतिक घराने के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अगले वर्ष यानी 2018 में वहाँ आम चुनाव होने को है।

इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने लाहौर स्थित उस सीट पर डॉ. यास्मीन राशिद को उपचुनाव में उतारा था। वे स्त्रीरोग विशेषज्ञ हैं और क्षेत्र में विश्वसनीय बनकर उभरी हैं। लोग इमरान खान को भविष्य का प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं, क्योंकि 2013 में पाक में हुए आम चुनाव में इमरान की पार्टी पीटीआई दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। साथ ही उसने चार में से एक खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में नियंत्रण हासिल कर लिया था। उम्मीद है कि वर्ष 2018 में होने वाले आम चुनाव में इमरान की पार्टी पीटीआई नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) के लिए खतरा बनकर उभरे। पाकिस्तान को दो प्रधानमंत्री दे चुकी भुट्टो परिवार की पार्टी पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी(पीपीपी) अपने ही सिंध प्रांत में अप्रासंगिक हो गई है।

इमरान खान को लोग ईमानदार और सच्चे मुसलमान समझते हैं। इनका वादा है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आने के पहले ही दिन पाकिस्तान में भ्रष्टाचार मिटाना शुरू कर देंगे। नवाज शरीफ की पार्टी के पास संसद में अभी बहुमत है, लेकिन अगले चुनाव में उसकी जीत सुनिश्चित नहीं है। इसलिए उनकी पार्टी पीएमएल(एन) पर अस्तित्व का संकंट है।

(207)प्रश्न: चीन के इंटरप्रेन्योर्स की साहसी, प्रतिभाशाली और वैश्विक सोच रखने वाली आज की पीढ़ी अब ड्राइविंग फोर्स क्यों है? चीनी इंटरप्रेन्योर्स में बिजनेस तेजी से बढ़ाने के आत्मविश्वास के कौन से कारण हैं?

उत्तर: कुल साल पहले चीन इनोवेशन का मतलब था नकल और फर्जी चीजें, लेकिन अब ड्राइविंग फोर्स है इंटरप्रेन्योर्स की साहसी, प्रतिभाशाली और वैश्विक सोच रखने वाली आज की पीढ़ी, क्योंकि हाल ही में सिलिकोन वैली की टेक्नोलॉजी पब्लिशर फर्म द्वारा आयोजित 'टेक क्रंच' सम्मेलन में इकट्ठे चीन के सबसे होनहार इंटरप्रेन्योर चीन से 'उबर' को भगाले वाली दीदी चुशिंग और बाइक शेयरिंग स्टार्टअप 'ओफो' के सामने इंटरनेट की दिग्गज कंपनियाँ बाइद, अलीबाबा और टेनसेन्ट फीकी पड़ गई। कहा जाता है कि ये चीन से उभर रही इन्भेंटिव कंपनियों की नई लहर का हिस्सा है जिनपर निवेशक टूट पड़े हैं। आखिर तभी तो 2014 से 2016 के बीच करीब 77 अरब डॉलर का वेंचर कैपिटल निवेश हुआ है, जबकि 2011-2013 में यह सिर्फ 12 अरब डॉलर ही था। चीन की यूनिकॉर्न 350 अरब डॉलर से ऊपर की है, जो अमेरिका के कुल वेल्यूएशन के करीब है। नतीजा यह है कि चीन में 609 अरबपति हैं, जबकि अमेरिका में 552 ही हैं।

चीन में इंटरपेन्योर्स में बिजनेस तेजी से बढ़ाने के आत्मविश्वास के तीन कारण हैं-पहला तो वहाँ अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है कि घरेलू बाजार में ही सफल होकर कंपनी बड़ा आकार ले लेती हैं। यूरोप की तुलना में भाषा व संस्कृति अधिक समान है। अमेरिका के विपरीत मूलभूत ढाँचा जैसे सड़कें व वायरलेस ब्राडबैंड नया और श्रेष्ठ है। दूसरा, चीनी खरीददार नई चीजों का प्रयोग करता है। अच्छे प्रोडक्ट पर नए ब्रैंडवाली कंपनी को इससे फायदा मिलता है। फिर नई तकनीक को गले लगाने के लिए भी वे असाधारण उत्सुकता दिखाते हैं। चीन बहुत तेजी से कैशलेस हो रहा है। तीसरी बात यह है कि दूरसंचार से बैंकिंग और स्वास्थ्य तक सरकारी उद्योग बहुत ही अक्षम व ग्राहकों के प्रति दुर्व्यहार करने वाले हैं। इससे नई टेक्नोलॉजीवाली और ग्राहकों को सबसे पहले रखने वाली नई कंपनियाँ फुर्ती से आगे बढ़ती हैं। सरकार चाहे ठीक से उद्योग न चला पाती हों, लेकिन नई कंपनियों को समर्थन देकर वह संतुलन ला देती हैं। इससे परिवहन जैसे क्षेत्र में इनोवेशन तेज हुआ है। बिजली के वाहनों की संख्या और चार्जिंग सुविधाओं में चीन अमेरिका से बहुत आगे है।

हाल ही में पेट्रोल इंजन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा से विद्युत वाहनों के वैश्विक बाजार में आगे रहने में मदद मिलेगी।

(208)प्रश्न: ए.के.-47 रायफल के आविष्कारक मिखाइल कलाश्निकोव को खुद उस पर क्यों पछतावा हुआ?

उत्तर: हाँ, भाई उमेश्वर जी, ए.के.-47 रायफल के आविष्कारक मिखाइल कलाश्निकोव को बाद में खुद पछतावा हुआ, क्योंकि उनका कहना था कि यह हथियार आतंकियों और विद्राहियों के लिए नहीं बना था। सेना में इंजीनियर एवं हथियार डिजाइनर कलाश्निकोव यूक्रेनी मूल के किसान परिवार से थे और वे रूसी सेना में जनरल रहे थे तथा उनको दुनिया उनके प्रमुख अविष्कार ए.के.-47 रायफल के लिए जानती है। वे कहते थे मैं एग्रीकल्चर मशीनरी बनाना चाहता था, लेकिन जर्मन नाजियों ने मुझे गन डिजाइनर बना दिया। उनका आदर्श वाक्य था कि 'मैं हथियार इसलिए बनाता हूँ, ताकि मातृभूमि और सीमाओं की रक्षा कर सकूँ।'

दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान 1941 में फिल्ड पर घायल कलाश्निकोव ने अस्पताल में ही ए.के.-47 के डिजाइन का स्कैच बना दिया था। दिसम्बर, 2013 में इस दुनिया से गुजर जाने के छह माह पहले कलाश्निकोव ने रशियन आर्थोडॉक्स के चर्च को पत्र लिखकर कहा था-'मेरी पीड़ा असहनीय है। अगर एके-47 से लोगों की जान जाती है, तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। फिर भले ही वे दुश्मन ही क्यों न हों। आज ये हथियार गलत हाथों में हैं तो उसके जिम्मेदार नेता हैं।' मॉस्को के गार्डन रिंग रोड पर कुछ ही दिन पहले रूसी सरकार द्वारा स्थापित कलाश्निकोव की 9 मीटर ऊँची प्रतिमा के अनावरण पर संस्कृति मंत्री ब्लादिमीर मेदिन्स्की ने कहा था-कलाश्निकोव 'मेरेशिन मैन' के सभी गुण थे और उनकी रायफल परफैक्ट 'कल्चरल ब्रैंड' है।

(209)प्रश्न:क्या नारियों के अधिकारों पर सख्ती बरतने वाले सऊदी अरब राजतंत्र ने महिलाओं की आजादी में विश्वास करना शुरू कर दिया है?

उत्तर: मुझे ऐसा लगता तो नहीं। भले ही सऊदी अरब ने महिलाओं के गाड़ी चलाने पर जारी प्रतिबंध को हाल में हटा लिया है और महिलाएँ अब 24 जून, 2018 से गाड़ियाँ चला सकेंगी। यह खुशखबरी जरूर लगती है, मगर मुझे लगता है कि महिलाओं द्वारा ड्राइविंग पर पूरी दुनिया विशेषकर यूरोप और अमेरिका सऊदी अरब की निंदा में मुखर रहे हैं। इस ख्याल से सऊदी अरब को नारी उत्पीड़नवाले देश के रूप में देखा जाता रहा है।

संभवत: सऊदी अरब की राजतंत्र सरकार ने निर्णय लिया है कि महिलाओं को भी गाड़ी चलाने दिया जाए। संभव है, अपनी छवि बदलने के लिए उसने यह फैसला किया हो।

वैसे देखा जाए तो अब तक सऊदी के पुरुषों के मन से महिला के प्रति विद्वेष कम नहीं हो सका है, क्योंकि सऊदी अरब के एक मंत्री का कहना है कि महिलाएँ गाड़ी चलाएँगी तो उनके पेट को नुकसान होगा। इसी प्रकार कुछ दिन पहले सऊदी के एक इमाम ने कहा था कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में एक चौथाई ही दिमाग होता है, लिहाजा महिलाओं का गाड़ी चलाना प्रतिबंधित है। यही कारण है कि महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति की खबर आते ही सऊदी में कुछ कट्टर सोचवाले लोगों ने विरोध भी शुरू कर दिया है। वे लोग कह रहे हैं कि इस कानून को लोग लागू नहीं होने देंगे। महिलाओं को व्यभिचारी नहीं बनने देंगे। ऐसी कट्टर सोचवालों का कहना है कि गाड़ी चलाते समय महिलाएँ पुरुष से बात करेंगी और ऐसे में वे व्यभिचारी हो जाएँगी यह उनका दृढ़ विश्वास है।

ऐसी मानसिकता में लगता नहीं है कि सऊदी अरब में महिला विरोध की कुसंस्कृति इतनी जल्दी समाप्त हो जाएगी। वहाँ के लोग जैसे हैं काफी समय तक वैसे ही बने रहेंगे। अभी भी वहाँ बुर्का अनिवार्य है। सिर के दो बाल भी दिख जाएँ तो आफत आ जाती है। सिर से पांव तक बुर्का पहनकर ही महिलाएँ कहीं आ जा सकती हैं। चाहे वे पैदल चलें या गाड़ी चलाएँ। इसलिए मुझे लगता है कि जून, 2018 से भले ही महिलाएँ गाड़ी चलाने लगेंगी, मगर महिला विरोधी सभी कानून बदस्तूर जारी रहेंगे। सऊदी का अधिकांश पुरुष समता, समान अधिकारवाला समाज तैयार करने के पक्ष में नहीं है। पुरुषों की इन सभी गतिविधियों और मानसिकता के मद्देनजर ऐसा नहीं लगता कि सऊदी अरब राजतंत्र ने महिलाओं की आजादी में विश्वास करना शुरू कर दिया है।

(210) प्रश्न : अमेरिका के लास वेगास शहर में पिछले दिनों हुई गोलीबारी की घटना से क्या ऐसा नहीं लगता कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद 'श्वेत सर्वोपरि है' की भावना अमेरिकी समाज में तेजी से गहराने लगी है? कैसे? क्या वास्तविक अर्थों में अमेरिकी समाज भीतर से डरा हुआ है?

उत्तर: हाँ, अमेरिका के लास वेगास शहर के होटल में आयोजित

गीत–संगीत कार्यक्रम में गोलीबारी की घटना से ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद 'श्वेत सर्वोपरि है' की भावना अमेरिकी समाज में तेजी से गहराने लगी है, क्योंकि अमेरिकी समाज में बदलाव का पहिया तेजी से घूम रहा है और वहाँ कई तरह की कुंठाएँ अक्सर वीभत्स रूप में सतह पर आ जाती हैं जिसका और चाहे जो कारण हो, मगर वहाँ के समाज में बढ़ रही नस्लीय भावना भी प्रमुख कारण है। खासतौर से 2008 की आर्थिक मंदी के बाद से वहाँ यह सोच लगातार गहराती जा रही है कि अप्रवासी न सिर्फ उनकी नौकरियाँ छीन रहे हैं, बल्कि उनकी संस्कृति को भी गंभीर नुकसान पहुँचा रहे हैं। मंदी की वजह से विशेषकर मध्य पश्चिम में कई कारखाने बंद हो गए जिसका दुष्प्रभाव अमेरिकी श्वेत कामगारों पर पड़ा और उनकी नौकरियाँ खत्म हुईं। नतीजतन, पहले उनकी तनातनी अप्रवासियों के साथ बढ़ी, फिर बाद में श्वेत व अश्वेत अमेरिकियों के बीच यह प्रवृत्ति पनपने लगी। हाल के वर्षो में जिस तरह से श्वेत अमेरिकी पुलिस अधिकारियों द्वारा अश्वेत नागरिकों के मारे जाने की खबरें आई है, वे इसी की कड़ी हैं।

दूसरी बात यह है कि लास वेगास में ही जिस शख्स ने गोलीबारी कर 58 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 515 लोगों को घायल किया उसकी पहचान 64 वर्षीय स्टीफन पैडॉक के रूप में हुई वह श्वेत है और अमेरिकी भी। इसलिए संभव है कि वह उसी कट्टर ईसाइयत की भावना में जी रहा हो, जो इन दिनों अमेरिका में उदार विचारों के खिलाफ हैं। हमलावर की संभवत: यह मंशा रही होगी कि पर्यटकों व अप्रवासियों में डर का माहौल पैदा किया जाए, ताकि वे यहाँ पर न आएँ।

अमेरिकी समाज का दूसरा विद्रूप वहाँ की 'बंदूक संस्कृति' है। हमलावर स्टीफन पैडॉक के कमरे में भी आठ बंदूकें मिली हैं। वहाँ की 'गन लॉबी' खासकर कैलिफोर्निया जैसे राज्यों मे 'राइट टू वेपन' (हथियार रखने का अधिकार) की पूरजोर वकालत करती है। वह इसे अपना मौलिक अधिकार मानती है। स्थिति यह है कि जैसे भारत में हम बाजार में आलू–टमाटर–प्याज खरीदते हैं, ठीक वैसे ही अमेरिका में किसी दूकान पर जाकर बंदूकें खरीदी जा सकती हैं। बस इसके लिए आपके पास कोई अधिकृत पहचान पत्र होना चाहिए। मगर सच्चाई यह है कि पिछले आठ–दस वर्षो में वहाँ नस्ल के बहाने या किसी और कारण से ऐसी गोलीबारी की घटनाएँ काफी बढ़ गई हैं और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद 'श्वेत सर्वोपरि

है' की भावना अमेरिकी समाज में तेजी से गहराने लगी है। इस सोच को खत्म करने का फिलहाल कोई रास्ता नहीं दिख रहा, मगर इतना जरूर है कि अगर लोगों को जागरूक किया जाए, तो तस्वीर बदल सकती है।

सच कहा जाए तो अमेरिका विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तरक्की करके भले ही दुनिया का सर्वशक्तिशाली देशों में शुमार हो गया है, लेकिन वास्तविक अर्थों में भीतर डरा हुआ और कायर लोगों का समाज है, क्योंकि सभ्य और निर्भीक समाज अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों पर निर्भर नहीं करता। डरा हुआ व्यक्ति न तो अपनी और न अपने देश की रक्षा कर सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार आत्मरक्षा के मुकाबले अपराध करने के उद्येश्य से अमेरिका में हथियारों को इस्तेमाल 10 गुना ज्यादा बार किया गया है। इसलिए अमेरिकी समाज में हथियार रखना एक बड़ी समस्या के रूप में उभरकर सामने आया है। सबसे खतरनाक और चिंता की बात तो यह है कि घातक हथियारों के शिकार सबसे ज्यादा बच्चे हो रहे हैं। इसलिए अमेरिका में घातक स्वचालित हथियार रखने के आसान कानून पर सवाल उठते रहे हैं। अमेरिका के लास वेगास में एक संगीत समारोह के दौरान पिछले दिनों हुए भीषण गोलीबारी के पहले भी जून, 2016 में औरलैंडो के नाइट क्लब में हुई गोलीबारी में 49 लोग मारे गए थे। दरअसल, अमेरिकी समाज में जब व्यापक स्तर पर हथियार रखने की आजादी मिली हुई है, तो इसका बेजा इस्तेमाल किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

(211)प्रश्नः संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक महाधिवेशन के इतर ब्रिटेन और इटली द्वारा 'ऑनलाइन आतंकवाद' विषय पर आयोजित बैठक में इंटरनेट के इस्तेमाल और ऑनलाइन फंडिंग पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई करने की जरूरत क्यों बताई गई?

उत्तर: संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के वार्षिक महाधिवेशन के इतर पिछले दिनों ब्रिटेन और इटली द्वारा 'आतंकियों को इंटरनेट के इस्तेमाल से रोकना' विषय पर आयोजित बैठक में आतंकी गतिविधियों के लिए हो रहे इंटरनेट के इस्तेमाल और ऑनलाइन फंडिंग पर चिंता जताते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई करने की जरूरत इसलिए बताई गई, क्योंकि कट्टरता फैलाना, आतंकियों की भर्ती और धन जुटाने में इंटरनेट के बेजा इस्तेमाल की बात पहले ही साबित हो चुकी है। इसलिए भारत के विदेश सचिव जयशंकर के अतिरिक्त ब्रिटिश की प्रधानमंत्री टेरीजा मे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैन्युएल

और इटली के प्रधानमंत्री पाओली जेंअीलोनी ने बैठक में हिस्सा लेकर कहा कि 'आतंक के खिलाफ हर जगह समान तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अलग-अलग मानक कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इन देशों के प्रतिनिधियों ने कहा कि आतंक के सवाल पर खासकर इंटरनेट के बेजा इस्तेमाल पर हाथ पर हाथ धरे नहीं रह सकते। इसलिए यह मंच इस समस्या पर ज्यादा सक्रियता के साथ प्रहार करने का प्रयास है।' उल्लेख्य है कि इस्लामिक स्टेट इंटरनेट के माध्यम से बड़ी तादाद में न केवल लोगों को आतंकी बनाने में सफल रहा है, बल्कि धन भी जुटाया है। इसके मद्देनजर 'ऑनलाइन आतंक' पर कार्रवाई की जरूरत है।

(212)प्रश्न: क्या चीन को भारत की सांस्कृतिक ताकत से पिछड़ने की चिंता सता रही है? आखिर क्यों?

उत्तर: हाँ, चीन को भारत की सांस्कृतिक ताकत से पिछड़ने की चिंता सता रही है, क्योंकि उसे लगता है कि भारत सांस्कृतिक स्तर पर उससे कहीं आगे है और वह भारत से लगातार पिछड़ता जा रहा है जबकि पिछले दशक में आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक दृष्टि से चीन ने अभूतपूर्व तरक्की हासिल की है और उसने अपना प्रभाव पश्चिमी देशों तक पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

दरअसल, कुछ महीने पहले चीन के सिनेमाघरों में भारतीय फिल्म 'दंगल' रिलीज हुई थी और दो महीने में उसने 1300 करोड़ रुपए का कारोबार किया। इसके पहले कोई भारतीय फिल्म वहाँ इतनी हिट नहीं हुई थी। उसमें न तो कम्प्यूटराइज्ड एक्शन सीन थे, न तो तेज रफ्तारवाली कारें थीं और न बड़े-बड़े युद्ध के दृश्य। फिर भी दंगल को चीनी दर्शकों ने बहुत पसंद किया जब फिल्म में भारतीय ध्वज राष्ट्रगान के साथ दिखाया जाता है। दंगल सफलता ने चीनी दर्शकों का ध्यान पश्चिम से पूर्व की ओर कर दिया है। अब चीनी कंपनियाँ बॉलीवुड को गौर से देख रही है, इसमें पार्टनरशिप और डिस्ट्रीब्यूशन के अधिकार, भारतीय डायरेक्टरों एवं स्क्रीन राइटरों से बातचीत भी शामिल है। चीन और भारत में क्षेत्रीय प्रभाव और नेतृत्व को लेकर प्रतिस्पर्धा रही है।

उल्लेखनीय है कि कुछ ही महीने पहले एशिया की ये दोनों ताकतें- चीन और भारत हिमालय के पठार डोकलाम में आमने-सामने थीं। इसके अतिरिक्त दोनों ताकतें सीमाओं के अतिरिक्त एक और क्षेत्र में आमने-सामने हैं, वह है 'सांस्कृतिक प्रभाव' और 'दंगल' फिल्म की सफलता के बाद चीन

इसे लेकर चिंतित है। सच तो यह है कि भारत अपनी संस्कृति के विस्तार में कोई कसर बाकी नहीं रखता, जिसमें बौद्ध परंपराएँ एवं योग भी शामिल है। यही नहीं चीनियों को भारतीय लोकतंत्र देखकर खुशी होती है, वे बातें करते हैं कि भारत से अधिक आबादी होने के बावजूद चीन लोकतंत्र के लिए तैयार क्यों नहीं है। चीनियों के बीच भारत के प्रति धारणा बनाने का काम वहाँ के सरकारी मीडिया ने किया है। वह बताता है कि भारत में जाति व्यवस्था कैसे काम करती है और भारतीय समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है आदि।

प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक 26 फीसदी चीनी नागरिक भारत के प्रति अच्छे विचार रखते हैं जबकि भारत के बारे में प्यू रिसर्च की रिपोर्ट कहती है कि 31 फीसदी भारतीय चीन के प्रति अच्छे विचार रखते हैं। अब भारत के बारे में चीन में दो तरह के विचार हैं-पहला यह कि भारत बहुत सादगीपूर्ण और अच्छा देश है, दूसरा यह कि भारत में अराजकता बहुत है। चीनियों में एकधारणा यह भी है कि भारत अस्वच्छ और असुरक्षित है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में भारत अपनी संस्कृति दुनिया भर में पहुँचाने की प्राथमिकताएँ तय की हैं। अब प्रचार किया जाता है कि भारत भगवान बुद्ध और योग की जन्मस्थली है। भारतीय उपन्यासकार, साहित्यकारों को दुनिया भर में पहचाना जाने लगा है। बॉलीवुड भी दुनिया भर में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है और चीन के अलावा अन्य देशों में भी वहाँ की फिल्में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि चीन भी सांस्कृतिक स्तर पर अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके प्रयासों को कई बार गहरा झटका लगा है। इसलिए चीनी फिल्म उद्योग दुनिया में अपनी छाप नहीं छोड़ पा रहा है। आलोचक इसमें बचाव करते हुए कहते हैं कि चीनी फिल्म उद्योग अभी युवावस्था में है, लेकिन 'दंगल' की सफलता ने चीन की चिंता बढ़ाने का काम किया है।

(213)प्रश्नः चीन के सरकारी समाचार पत्र 'ग्लोबल टाइम्स' में प्रकाशित लेख से क्या आपको ऐसा लगता है कि चीन की पाक के प्रति सोच में बड़ा बदलाव आया है?

उत्तरः यह दिखावा है या सच्चाई यह तो भविष्य ही बताएगा, मगर चीन के सरकारी पत्र 'ग्लोबल टाइम्स' में प्रकाशित लेख से मुझे बहरहाल ऐसा लगता है कि चीन की पाक के प्रति सोच में बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स में पाक को आतंकवाद का पोषक मानना और यह भी

स्पष्ट करना कि आतंकवाद को फैलाना, पाक में आतंकी गतिविधियों का लगातार होना खतरनाक साबित हो सकता है।

उल्लेख्य है कि ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित लेख से पाकिस्तान में जबर्दस्त खलबली और बेचैनी जैसे हालात नजर आने लगे हैं। कई मंचों के सांथ संयुक्त राष्ट्र महासभा के खास मौके पर पाक को समर्थन एवं बचाव के कारण चीन की छवि वैसे भी खराब होती नजर आ रही है, जिसकी वजह से भी संभव है चीन के दृष्टिकोण में बदलाव और सकारात्मक परिवर्तन आया हो। विश्व के समक्ष आतंकवाद खतरनाक रूप में प्रकट हो चुका है और इस समय चीन को अपनी छवि को आतंकवाद के मामले में स्पष्ट करना जरूरी था और पाक के आतंकवाद प्रेम को संरक्षण देना जो नजर आ रहा है, उससे अपने को अलग करना आवश्यक हो गया था।

दुनिया में हर देश अपनी ताकत को बढ़ाने की होड़ में लगा है। पाक भी बता चुका है कि उसके पास भी परमाणु बम हैं। संयुक्त राष्ट्र की यह राय कि कश्मीर विवाद को भारत-पाक को अपने स्तर पर हल कर लेना चाहिए। इससे पाक को कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने की कोशिश को बड़ा झटका लगा है। वैसे भी महाशक्तियाँ भारत के साथ हैं। ऐसी स्थिति में चीन की सोच में परिवर्तन आना स्वाभाविक लगता है।

(214)प्रश्नः चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 19वीं काँग्रेस में राष्ट्रपति के पद पर शी जिनपिंग के दूसरे कार्यकाल पर मुहर लगने के बाद क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बड़े कद के साथ उनकी वैश्विक महत्वाकांक्षा और बढ़ेगी?

उत्तरः हाँ, चीन की सत्ताधारी कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 19वीं काँग्रेस में राष्ट्रपति पद पर शी जिनपिंग के दूसरे कार्यकाल पर मुहर लगने के बाद मुझे भी ऐसा लगता है कि बड़े कद के साथ उनकी वैश्विक महत्वाकांक्षा और बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने अपने तीन घंटे के अध्यक्षीय भाषण में चीन की खूबियों के साथ वहाँ की समाजवादी व्यवस्था का जो खाका पेश किया और जिस प्रकार उनके विचारों को पार्टी के संविधान में न केवल दर्ज किया, बल्कि उनके कद को पूर्ववर्त्ती माओत्से तुंग के बराबर स्वीकार कर लिया गया, उससे स्पष्ट है कि दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक चीनी महत्वाकांक्षा तो बढ़ने की संभावना है ही, विश्व व्यवस्था की अगुवाई करने की उसकी अकुलाहट में भी तेजी आएगी। यही नहीं, मुझे

तो यहाँ तक उम्मीद है कि भारत समेत तमाम पड़ोसियों के साथ उसके संबंधों में काफी बदलाव आएगा।

यहाँ यह कहना भी समुचित होगा कि भारत के सामरिक हित चीन के हितों से टकराहट है। चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के संदर्भ में उससे हमारे सामरिक संपर्कों का बढ़ना तय है। चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी के संविधान में शी जिनपिंग के चिंतन के साथ ही वन बेल्ट, वन रोड को भी शामिल किया गया जिसको संवैधानिक अहमियत मिलने का अर्थ यह हुआ कि इसे पूरी पार्टी का समर्थन मिल गया तथा अब इसे बगैर किसी ढील के लागू किया जाएगा। मुझे तो लगता है कि भारत की संप्रभुता का अतिक्रमण करने वाले चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को भी अब अधिक आक्रामकता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। रक्षा के मुद्दे पर भी शी के इस बयान से कि 'चीन सीमा क्षेत्र में विकास की गतिविधियाँ तेज करते हुए उनकी सुरक्षा तथा स्थिरता भी सुनिश्चित करेगा', से भी उनकी महत्वाकांक्षा का अंदाजा लगाया जा सकता है।

मुझे नहीं लगता कि चीन की विस्तारवादी नीति और समुद्री सीमाओं में प्रभाव बढ़ाने की लालसा कम होगी। आर्थिक विकास और सामुद्रिक नीति के तहत चीन हिंद महासागर में अपना असर बढ़ाने का प्रयास करेगा, क्योंकि चीन की अधिकतर व्यापारिक गतिविधियाँ हिंद महासागर के रास्ते से ही होती हैं।

(215)प्रश्न:क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत और चीन धीरे-धीरे जलयुद्ध की ओर बढ़ रहा है? यदि हाँ, तो कैसे?

उत्तर: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि भारत और चीन धीरे-धीरे जलयुद्ध की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि चीन को ऐसा लगता है कि यही अकेला ऐसा मुद्दा है, जिससे वह भारत पर भारी पड़ सकता है। भारत ही नहीं, एशिया के बहुत सारे देश तिब्बत से निकलने वाली जलधाराओं पर निर्भर करते हैं। वियतनाम और लायोस जैसे देश भी इसे लेकर चीन की शिकायत करते रहे हैं। यह भी कहा जाता है कि चीन नदियों की अंतरराष्ट्रीय संधियों की परवाह नहीं करता।

अभी-अभी हांगकांग के अखबार 'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' में छपी एक खबर इस समय पूरे भारत के लिए चिंता की वजह बनी हुई है। इस खबर के मुताबिक चीन, तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी से एक हजार किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाएगा, जो सांगपो के पानी को शिनजियांग प्रांत

के रेगिस्तान तक पहुँचाएगी। अखबार ने इस सुरंग की परिकल्पना को चीनी इंजीनियरों के कमाल के रूप में पेश किया है। खबर में यह भी कहा गया है कि जब इसका पानी शिनजियांग के रेगिस्तान में पहुँचेगा, तो वह कैलिफोर्निया की तरह लहलहा उठेगा।

भाई विजय जी, आपको मैं यह बता दूँ कि सांगपो तिब्बत के पठार में मानसरोवर झील से निकलने वाली वह नदी है, जिसे हम भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। यह नदी भारत और बांग्लादेश के एक बड़े हिस्से की जीवन रेखा है। अगर इसका रूख मोड़ा गया, तो भारत की सबसे चौड़े पाटवाली नदी ब्रह्मपुत्र के सूखने का खतरा खड़ा हो जाएगा। साथ ही वह संस्कृति भी खतरे में पड़ जाएगी, जो इस पानी के आसपास विकसित होकर फल-फूल रही है।

हालांकि चीन सरकार के प्रवक्ता ने अगले ही दिन इस पूरी खबर का खंडन कर दिया, लेकिन अखबार में जिस विस्तार से यह खबर छपी है, इसे तुरंत खारिज भी नहीं किया जा सकता। संभव है चीन अभी खुलासा न करना चाहता हो। वैसे अखबार के हिसाब से भी चीन की यह भावी योजना और दुनिया की यह सबसे लंबी सुरंग बनाने से पहले इंजीनियर एक कम लंबी सुरंग का प्रयोग कर रहे हैं। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि चीन के साथ यह ताजा आशंका डोकलाम विवाद के तुरंत बाद खड़ी हुई है, इसलिए इसे भारत पर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में भी देखा जाएगा। इससे आपकी यह आशंका स्वाभाविक है कि भारत और चीन धीरे-धीरे जलयुद्ध की ओर बढ़ रहा है।

(216)प्रश्नः न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में विगत एक नवम्बर, 2017 को आतंकी हमले के बाद क्या यह कबूल नहीं करना पड़ेगा कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला करना किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं है? आखिर कैसे?

उत्तरः हाँ, अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित मैनहट्टन में पिछले दिनों हुए आतंकी हमले के बाद यह कबूल करना पड़ेगा कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला करना किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं है। जो ताकतवर देश और बड़ी ताकतें अब तक दक्षिण एशिया को ही अतिसंवेदनशील विस्फोटक संकट स्थल समझते हुए हमारी जाहिली-काहिली की भर्त्सना करते रहे हैं, वे भी अब अपने दामन में झाँकने को मजबूर होंगे।

न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर से मात्र 10 किलोमीटर दूर आतंकी

फुटपाथ और साइकिल लेन पर ट्रक चढ़ाकर उजबेकिस्तान निवासी हमलावर सैफुल्ला साइपौव ने हमला कर भले ही 8 ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया हो, मगर अमेरिका अब यह दावा करने में असमर्थ होगा कि 9/11 के बाद से सिर्फ सिरफिरे बंदूकधारी ही खुन-खराबे के अभियुक्त रहे हैं। 'यह एक आखिरी मौका पाकिस्तान को दिया जा रहा है' यह सुनते-सुनते भारत के कान पक चुके हैं। अमेरिकी रजामंदी के अभाव में पाकिस्तान का दुस्साहस जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी हिंसा भड़काने का काम नहीं हो सकता। कभी मानवाधिकारों के हनन के आरोप में भारतीय सेना तथा सह सैनिक बलों के जवानों तथा अधिकारियों को अभियुक्त बनाने का अभियान अमेरिकी मीडिया चलाता है, तो कभी यह काम गैर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन करते हैं। अपने ऊपर किसी आतंकी हमले को जिस अधिकार को अमेरिका अपना मानता है, वही भारत जैसे संप्रभु देश का भी है।

इसलिए यह समय का तकाजा है कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का सामना-सफाया करने के लिए वैश्विक पहल जरूरी है। इस काम को टाला नहीं जा सकता। मुझे तो आश्चर्य यह देखकर होता है कि अमेरिका हो, रूस या फ्रांस अथवा जर्मनी हो, कोई भी अपने मित्र देशों तक से ऐसी संवेदनशील जानकारी का साझा नहीं करता, बिना कुछ कीमत वसूल किए। इसके अतिरिक्त अमेरिका तथा अन्य सभी बड़ी ताकतों को संकीर्ण राष्ट्रहित से ऊपर उठकर एकजुट होने की आवश्यकता है, अन्यथा 'दुश्मन' को पछाड़ने के लिए रक्तबीज राक्षस को जन्म देने वाले खुद अपने बनाए भस्मासुरों से भागते घायल होते रहेंगे। रही बात 'अकेले भेड़ियों' की, सो मत भूलिए कि भेड़िया भी किसी खूँखार प्रजाति का जानवर है, जो निरीह बच्चे या छोटे जानवर को ही दबोचता है। वह स्वयंभू नहीं।

(217)प्रश्न: जैश-ए-मुहम्मद का मुखिया मसूद मजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने में चीन द्वारा पुनः रोड़ा अटकाए जाने से क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर और दबाव बढ़ सकता है और इससे उबरना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा? आखिर कैसे?

उत्तर: हाँ, भाई राजवंश जी, जैश-ए-मुहम्मद का मुखिया मसूद मजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने में चीन द्वारा पुनः रोड़ा अटकाए जाने से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर और दबाव बढ़ सकता है और इससे उबरना पाक के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि

इसके लिए चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति का इस्तेमाल करने में पीछे नहीं रहता, जबकि संयुक्त राष्ट्र की सूची में जैश-ए-मुहम्मद आतंकी संगठन है। अमेरिका, फ्रांस ओर ब्रिटेन भारत के पक्ष का समर्थन करते हैं और चीन के रूख से भारत सहित अन्य सभी देश, जो आतंकवाद के खिलाफ अपनी स्पष्ट नीति रखते हैं, उनमें निराशा और क्षोभ का होना स्वाभाविक है। चीन के इस गलत रवैया से न केवल उसकी छवि गिरी है, बल्कि विश्व को भी गलत सन्देश गया है।

जो हो, लेकिन अमेरिका, पाकिस्तान की नकेल कसने की पूरी तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मुहम्मद सहित 20 आतंकी संगठनों की सूची पाकिस्तान की सरकार को सौंप दी है। इससे पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा है और अब आतंकियों पर कार्रवाई से पाकिस्तान का बचना मुश्किल होगा। पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहा है, इसकी निगरानी अमेरिका और भारत मिलकर करेंगे। निगरानी में अमेरिका भारत की मदद करेगा। आतंकवाद के खिलाफ जो रणनीति और कार्ययोजना बन रही है उससे पाकिस्तान और चीन दोनों ही अलग-थलग पड़ जाएँगे। इससे दोनों देशों को क्षति होगी। इसलिए पाकिस्तान को शीघ्र अपना रवैया बदलने की जरूरत है। साथ ही चीन भी अपनी गिरती छवि को सुधारे।

चीन कहता है इस प्रस्ताव में सदस्यों के बीच सहमति नहीं है। उसे किस तरह की सहमति चाहिए यह भी पता चले। इस बार का प्रस्ताव तो अमेरिका, फ्रांस एवं ब्रिटेन द्वारा लाया गया था। ये तीनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। इससे सशक्त प्रयास और क्या हो सकता है? इसकी अवधि 2 नवम्बर, 2017 को समाप्त हो रही थी तो चीन ने फिर अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। उल्लेख्य है कि भारत के पिछले वर्ष के प्रस्ताव पर सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य देशों में 14 सदस्य देशों की सहमति थी। केवल एक सदस्य देश और वह भी चीन ही विरोध में था। जाहिर है चीन सिर्फ अपने कदम को सही ठहराने के लिए बहाना बना रहा है। वह हर बार कोई न कोई तर्क तलाश लेता है। जो हो, आखिर भारत के लिए इतने देशों का समर्थन जुटा लेना सामान्य कूटनीतिक उपलब्धि नहीं है।

(218)प्रश्नः क्या आपको ऐसा लगता है कि घरेलू और वैश्विक घटनाक्रम ने पाकिस्तान को विकल्पहीनता की ऐसी अँधी सुरंग में धकेल दिया है, जहाँ से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हैं?

उत्तर: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि घरेलू और वैश्विक घटनाक्रम ने पाकिस्तान को विकल्पहीनता की ऐसी अँधी सुरंग में धकेल दिया है, जहाँ से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हैं, क्योंकि 1970 के बाद पाकिस्तान अपने अस्तित्व को बचाए रखने की आज सबसे विकट लड़ाई लड़ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को गद्दी छोड़े तीन महीने से अधिक होने के बाद भी पाक की स्थितियाँ उलझी हुई हैं। उनपर मुकदमा चलना प्रारंभ हो गया है और कैंसर से पीड़ित उनकी बेगम कुलसुम नवाज के लंदन अस्पताल में भर्ती होने की वजह से इस्लामाबाद और लंदन के बीच उनकी आवाजाही जारी है। जिस तरह से पाक सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले में असाधारण सक्रियता दिखाई है उससे यह तो स्पष्ट हो ही गया है कि न्यायपालिका उन्हें दंडित करने पर आमादा है। दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना की दिलचस्पी भी उन्हें बचाने में नहीं है।

एक राष्ट्र के रूप में भी पाकिस्तान के समक्ष एक बड़ा संकट खड़ा है, क्योंकि पिछले कई वर्षो का संचित पाप और ताप उससे अपना हिसाब-किताब करना चाहता है। नवाज शरीफ को पदच्यूत करने के अलावे तीन फौरी घटनाओं ने पाक को झकझोर दिया है।

सबसे पहला झटका तो उसे राष्ट्रपति बुश द्वारा घोषित अमेरिका की नई अफगान-पाकिस्तान नीति से लगा, क्योंकि अब जिस 'डू-मोर' की माँग उससे की जा रही है, उसके तहत उसे उन 'नॉन स्टेट एक्टर्स' यानी जेहादियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, जिन्हें बड़े जतन से उसकी फौज ने पाला-पोसा है। राजनीतिक नेतृत्व इस मसले पर ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि बदली वैश्विक परिस्थितियों में पूरी तरह से अलग-थलग पड़ जाने का खतरा समझता है, लेकिन फौज की हठधर्मिता के आगे बेबस है। पाक सेनाध्यक्ष जनरल बाजवा ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान बहुत कर चुका है और अब 'डू-मोर' करने की बारी दुनिया की है।

दूसरी यह कि पाकिस्तान के लिए इस समय सबसे बड़ा संकट आर्थिक है। देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था उसकी सुरक्षा पर भी विपरीत प्रभाव डालेगा। सारे लक्षण बता रहे हैं कि अगले दो-तीन महीनों में ही पाकिस्तान कर्जों की किस्तों के बीच फर्क बढ़ता जा रहा है, विदेशी मुद्रा का उसका भंडार खतरनाक हद तक पहुँच गया है। इसके अलावा वहाँ विदेशी पूँजी भी नहीं आ पा रही है और वित्त मंत्री इशाक डार अदालती कार्यवाही के डर से लंदन के अस्पताल में छिपे बैठे हैं। भारत-अफगानिस्तान के बीच

सड़क मार्ग से व्यापार करने की इजाजत नहीं दिए जाने की धमकी के बाद पाक के ट्रकों को अफगानिस्तान होकर नहीं जाने दिया जाएगा, तो सीपैक का सारा मकसद ही खत्म हो जाएगा।

(219)प्रश्नः समानता और न्याय के साम्यवादी सपने को साकार करने के इरादे से सौ साल पूर्व हुई बोल्शेविक क्रांति में आखिर क्यों जल्दी ही निरंकुशता के लक्षण दिखाई देने लगे थे?

उत्तरः हाँ, आपकी बात से हम सहमत हैं कि समानता और न्याय के साम्यवादी सपने के साकार करने के इरादे से सौ साल पहले यानी 7 नवम्बर, 1917 को बोल्शेविक पार्टी के नेता लेनिन के नेतृत्व में वामपंथी क्रांतिकारियों ने ड्यूमा की सरकार के खिलाफ रक्तहीन क्रांति के जरिए सत्ता पर दबदबा कायम कर लिया था, मगर समानता और न्याय के साम्यवादी सपने को साकार करने के इरादे से यह बोल्शेविक क्रांति में जल्दी ही निरंकुशता के लक्षण दिखाई देने लगे, क्योंकि आज की पीढ़ी के अधिकतर लोग अतीत के साथ किसी जुड़ाव से अपने को स्वेच्छया अलग रखे हैं, जो एक गंभीर कमजोरी है। निःसंदेह गरीबी के अश्लील स्तरों, धन-संपत्ति व अधिकार को लेकर बड़ी असमताओं, बढ़ते सांस्कृतिक निषेधवाद जैसे बढ़ते अन्यायों के साथ पूँजीवाद की जाँच-परख अभी जारी है और इस दृष्टिकोण से क्रांतिकारी मार्क्सवाद के श्रेष्ठ उदाहरणों में व्यक्त समाजवादी लोकतंत्र की प्रासंगिकता अभी बनी हुई है, क्योंकि इसके व्यावहारिक सबक का खासतौर पर भारत जैसे देश में विशेष महत्व है, लेकिन दक्षिण पंथ वर्तमान में सरकारी सत्ता पर काबिज है, जो कि भारत के पूर्ण रूपांतरण के दृष्टिकोण से गहराई से प्रेरित है और जिसके पीछे भारतीय समाज में प्रत्यारोपित भारी अनुपात में कार्यकर्ता बल है। इस अतिवादी दक्षिणपंथ के बढ़ते प्रभाव को दीर्घ अवधि में ऐसी कोई उदार सुधारवादी राजनीति निर्णायक तौर पर कमजोर नहीं कर पाएगी, जो खुद भी एक नव उदार पूँजीवादी व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है।

दरअसल, पिछली सदी की समाजवादी क्रांतियाँ उन देशों में हुई, जहाँ उदारवादी लोकतंत्र की मौजूदगी न थी। वहाँ ये क्रांतियाँ या तो निरंकुश तानाशाहों या फिर साम्राज्यवादी आक्रांताओं के विरूद्ध थीं। अपने इस रूप में वे राजनीतिक क्रांति के साथ-साथ सैन्य अभियान भी थी। सत्ता पर काबिज होने के बाद इन राज्यों ने एकदलीय तानाशाही का स्वरूप धारण कर पार्टी और राज्य का विलय कर डाला, जिसने न केवल असहमति को कुचल

लोकतंत्र को विद्रूप कर दिया, बल्कि नागरिक स्वतंत्रताओं को गला घोट अंततः जनता के विशाल बहुमत का राज्य से पूर्ण अलगाव भी सुनिश्चित कर दिया। इसके अतिरिक्त, संसाधनों के समतामूलक वितरण के साथ तेज आर्थिक प्रगति हासिल करने के लिए वहाँ लाया गया। अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत मॉडल क्रमिक रूप से एक अकर्मण्य नौकरशाही के विकास की वजह बन अंततः सामाजिक आर्थिक जड़ता में तब्दील हो गया।

इसी प्रकार द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद उपनिवेशवाद की समाप्ति की प्रक्रिया तथा 1970 से प्रारंभ वित्तीय भूमंडलीकरण ने समाजवादी व्यवस्था के लिए और अधिक जटिलताएँ पैदा कर दीं। सौ साल पूर्व की बोल्शेविक क्रांति के काल से आज की वैश्विक व्यवस्था बिल्कुल अलग है। अपने-अपने हितों की सुरक्षा के विभिन्न आधारों पर बेहद बढ़ती सामाजिक चेतना ने एक रूढ़िवादी वर्ग आधारित राजनीति को ज्यादा से ज्यादा अप्रासंगिक करार कर दिया है। फिर भी मेरा ख्याल है कि विश्व में एक वैकल्पिक व्यवस्था की स्थापना के प्रथम मानवीय प्रयास के रूप में बोल्शेविक क्रांति हमेशा एक प्रेरणा स्रोत बनी ही रहेगी।

(220)प्रश्नः आप कृपया यह बताइए कि क्या किया जाय कि आम कश्मीरी की जिंदगी से पाकिस्तान बतौर मुद्दा खारिज हो जाए?

उत्तरः भाई उपेन्द्र सागर जी, कश्मीर समस्या का कोई समाधान निकले इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी पक्षों से बातचीत करने वास्ते दिनेश्वर शर्मा को कश्मीर के लिए बतौर प्रतिनिधि नियुक्त किया है। उन्होंने केंद्र के वार्ताकार के तौर पर अपने पहले कश्मीर दौरे का समापन किया है। वह तीन दिन कश्मीर घाटी में रहे और दो दिन जम्मू में। हालांकि पाकिस्तान की भाषा बोलने वाली हुर्रियत क्रांफेंस के नेताओं ने उनसे मिलने से इनकार किया, पर कई राजनीतिक दलों समेत नब्बे से अधिक प्रतिनिधिमंडलों ने उनसे मुलाकात की।

प्रतिनिधि दिनेश्वर शर्मा के पास कठिन काम है, लेकिन यह उम्मीद तो है ही कि शायद उनके नेतृत्व में वार्ता के बिखरे हुए सूत्रों को पकड़ने और नई पहल की संभावनओं की तलाश हो, पर सवाल यह है कि क्या आतंकी संगठनों को लगभग निष्प्रभावी किए जाने के बाद कोई वृहद राजनीतिक भागीदारी की आधारभूमि बनती है या नहीं? मेरा ख्याल है कि हाशिए की ओर जा रहे पाकिस्तान और बदल रहे वैश्विक समीकरण के मद्देनजर कश्मीरी मनोदशा में बदलाव की गुंजाइश कैसे बने? अब यह जरूरी हो चला है कि हुर्रियत जैसे पाकिस्तान परस्त संगठनों के जिहादी छल

से मुक्त राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संगठनों की भी भागादारी की संभावना देखी जाए।

दुनिया रोज बदल रही है। इसी के साथ हमारे दृष्टिकोण और प्रतिमान भी बदल रहे हैं, लेकिन हममें से बहुत से लोग अभी दुनिया को स्थिर मानते रहने पर आमादा हैं। सबसे बड़ी समस्या इस वक्त यह है कि कश्मीर का वर्तमान इतिहास पर भारी है। इसीलिए कश्मीरियों के समक्ष आज यदि कोई समस्या है तो वह है सुरक्षा बलों की मौजूदगी। इससे आगे वहाँ कोई और कुछ बता नहीं पाता। किसी ने बाढ़ के समय सुरक्षा बलों की ओर से किए गए कामों की याद दिलाई तो जवाब मिला कि सुरक्षा बलों ने बाढ़ से बचाकर कोई अहसान नहीं किया हमपर।

सच तो यह है कि कश्मीर घाटी के मानस में यह बात घर कर चुकी है कि भारत सरकार जो भी करती है वह कश्मीरियों को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए ही करती है। इसलिए पाकिस्तान कार्ड खेलना कोई घाटे का सौदा नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि घाटी का मनोविज्ञान कैसे बदला जाए? इसके लिए पाकिस्तान का भूत भगाना जरूरी है। आज जो कश्मीर समस्या है, क्या उसका वही स्वरूप धारा 370 के समापन तक की यात्रा पूरी करने के बाद यह कश्मीर दूसरी तरह का दिखाई देगा। उसे नए मुकाम पर पहुँचने के बाद अलगाववाद की इस मनोवैज्ञानिक समस्या का बेहतर समाधान संभव हो सकेगा।

(221)प्रश्न: क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत-आसियान संबंधों के विकसित होने के पीछे चीन एक बड़ा कारक है? आखिर क्यों?

उत्तर: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि भारत-आसियान संबंधों के विकसित होने के पीछे चीन एक बड़ा कारक है, क्योंकि आसियान समूह के दस देश भारत चीन के विकल्प के रूप में देखते हैं, जिसके जरिए दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में शक्ति-संतुलन बना रहे तथा आयात-निर्यात के लिए समुद्री मार्ग खुला रहे। वहीं दूसरी ओर, भारत को चाहिए कि दस आसियान समूह राष्ट्रों को विश्वास दिलाए कि भारत प्रत्येक परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहेगा। इसके अतिरिक्त, चीन की नकेल कसने के लिए भारत दक्षिण चीन सागर क्षेत्र की शक्ति मुक्त बनाए रखने की जोरदार वकालत करता है। साथ ही, अमेरिका ने जबसे एशिया-प्रशांत क्षेत्र को हिंद प्रशांत क्षेत्र कहकर संबोधित किया है, इससे स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका की एशिया प्रशांतनीति

में भारत सबसे अहम स्थान रखता है। इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता एवं सुरक्षा बनाए रखने में अमेरिका–भारत–जापान–ऑस्ट्रेलिया से निर्मित सामरिक चतुष्क की भी खूब चर्चा है, जिसका जिक्र हाल के दिनों में बार–बार ट्रंप के द्वारा किया जा रहा है।

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि दक्षिण चीन सागर में चीन की विस्तारवादी नीतियों की वजह से चीन की दादागिरी बढ़ती जा रही है। आसियान समूहों के राष्ट्रों में चीन की गतिविधियों को लेकर भय पनप रहा है। चीनी सहायता से उत्तर कोरिया का रवैया और भी आक्रामक हो रहा है, साथ ही उत्तर कोरिया का परमाणु मिसाइल कार्यक्रम इस क्षेत्र में अस्थिरता उत्पन्न करता है। परिणामत: चीन और उत्तर कोरिया इस क्षेत्र में 10 आसियान समूह राष्ट्रों के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। व्यापार निवेश के साथ ही साथ भारत आसियान देशों के साथ रणनीति संबंधों को विकसित करना, चीन के लिए असहजता उत्पन्न करता है। इसके विपरीत, भारत के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए पाकिस्तान की सहायता से चीन ग्वादर बंदरगाह को विकसित कर रहा है, जिससे चीन को हिंद महासागर में प्रवेश करने का मार्ग मिल जाता है। कुछ इन्हीं सब वजहों से भारत–आसियान संबंधों के विकसित होने के पीछे चीन एक बड़ा कारक है।

(222)प्रश्नः जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगावे जैसे एक क्रांतिकारी नेता के खिलाफ सैनिक तख्ता पलट क्या विश्व इतिहास की अनूठी घटना नहीं कही जाएगी? इस रक्तहीन सैनिक कार्रवाई की आखिर क्या वजहें आपकी नजर में हो सकती हैं?

उत्तरः भाई विजय जी, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगावे जैसे एक क्रांतिकारी नेता, जिसने दुनिया में सबसे अधिक दिनों तक शासन किया और श्वेतों के निरंकुश शासन से अपने मुल्क को आजादी दिलाई के खिलाफ सैनिक तख्तापलट निश्चित रूप से विश्व–इतिहास की एक अनूठी घटना कही जाएगी।

विजय जी, मैं आपको जानकारी दूँ कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दो महत्वपूर्ण गढ़ जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका में से रोडेशिया अब जिम्बाब्वे में गोरों के नस्लभेदी शासन के खिलाफ रॉबर्ट मुगाबे के नेतृत्व में क्रांति हुई और दक्षिण अफ्रीका में क्रांति का नेतृत्व नेल्सन मंडेला ने किया था। दोनों अश्वेत नेता वर्षों तक जेल में भी रहे। 1980 में रोडेशिया यानी जिम्बाब्वे

आजाद हुआ जिसका श्रेय निश्चित तौर पर रॉबर्ट मुगाबे को जाता है। यही नहीं उन्होंने भूमि सुधार लागू किया, जिसके चलते कृषि भूमि पर से श्वेतों को बेदखल करके अश्वेतों में वितरित किया गया।

जहाँ तक जिम्बाब्वे में रक्तहीन सैनिक कार्रवाई की वजहों का सवाल है मेरी नजर में पहली बात तो यह कि क्रांति के यह नेता मुगाबे निहित स्वार्थों से ऊपर नहीं उठ पाए, क्योंकि रॉबर्ट मुगावे अपनी दूसरी पत्नी ग्रेसी को जिम्बाब्वे की उपराष्ट्रपति बनाने का सपना पाल रहे थे जिसके लिए उन्हें अपनी क्रांतिकारी साथी और पार्टी के वरिष्ठ नेता और उपराष्ट्रपति रहे इमर्सन मनंगावा को बर्खास्त करने में भी हिचक नहीं हुई। यह दर्शाता है कि श्वेतों के निरंकुश शासन से अपने मुल्क को आजादी दिलाने वाला नायक मुगावे कैसे खुद निरंकुश बना दिया गया। सेना और उनकी अपनी पार्टी ने मुगाबे के इस कदम का समर्थन नहीं किया।

इसके अतिरिक्त मुझे दूसरी वजह यह दिखती है कि कृषि कार्य में अश्वेतों की अकुशलता के कारण आर्थिक व्यवस्था चरमराने लगी। औद्योगिक कुप्रबंधन, खाद्यान्न की कमी, मुद्रा का अवमूल्यन और भ्रष्टाचार से देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। मुगाबे के पतन का यह भी एक बड़ा कारण है।

जो भी हो रॉबर्ट मुगाबे की ऐतिहासिक राजनीतिक पार्टी जानू पीएफ से उनके उत्तराधिकारी के चुनाव की प्रक्रिया तेज होने के बाद मुगाबे की अपनी पार्टी और सेना दोनों ने उनका साथ छोड़ दिया है। मुगाबे को पार्टी के नेता पद से हटाने के बाद उनके उत्तराधिकारी इमर्सन हो गए जिन पर देश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने की चुनौती बड़ी होगी। उन्हें आजादी और आर्थिक सुधार को अपना एजेंडा बनाना होगा।

(223)प्रश्नः नीदरलैंड के हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पैनल के लिए भारतीय प्रतिनिधि दलबीर भंडारी का दोबारा चुना जाना क्या भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत कही जाएगी? आखिर क्यों?

उत्तरः हाँ, नीदरलैंड के हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पैनल के लिए भारतीय प्रतिनिधि दलबीर भंडारी का दोबारा चुना जाना भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत कही जाएगी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में दलबीर भंडारी के दोबारा निर्वाचन के चलते एक तो इस संस्था में पहली बार ब्रिटेन का कोई न्यायाधीश नहीं होगा और दूसरे संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के पाँच में से केवल एक स्थाई सदस्य फ्रांस का ही न्यायाधीश नजर आएगा।

इसका सीधा मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सदस्य सुरक्षा परिषद में विस्तार और सुधार न केवल चाह रहे हैं, बल्कि इसे लेकर वे इस परिषद के स्थाई सदस्यों को चुनौती देने के मूड में भी हैं। आखिर तभी तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 में से 183 और सुरक्षा परिषद के सभी 15 वोट दलबीर भंडारी को मिले। अंतरराष्ट्रीय अदालत के 71 साल के इतिहास में पहली बार ब्रिटेन को बाहर कर दलबीर भंडारी दोबारा न्यायाधीश चुने गए। उनके सामने ब्रिटेन के क्रिस्टोफर ग्रीनवुड थे। जीत के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों में बहुमत जरूरी है।

अंतरराष्ट्रीय सत्ता समीकरणों की वजह से भारत दुनिया की एक महत्वपूर्ण राजनयिक ताकत के रूप में उभर कर सामने आया है। इससे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और उभरती अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत का प्रभुत्व बढ़ता दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे भारत के लिए गौरव का क्षण बताते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के प्रयासों की सराहना के साथ उन्हें बधाई दी है।

दरअसल, भारत ने इसे लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतने दबाव तैयार कर दिए थे कि अंत में ब्रिटेन ने सर ग्रीनवुड का नामांकन वापस ले लिया। हेग की अंतरराष्ट्रीय अदालत के 71 साल के इतिहास में यह पहला मौका है, जब वहाँ कोई ब्रिटेन का न्यायाधीश नहीं होगा। निश्चित रूप से इससे ब्रिटेन की राजनयिक ताकत कम होगी। यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद भारत ब्रिटेन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार बन गया है। कहा जाता है कि ब्रिटेन अपने इस साझेदार को नाराज नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने अपने उम्मीदवार का नाम वापस लिया है।

नीदरलैंड के हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के लिए संयुक्त राष्ट्र में हुई चुनावी जंग में भारत की जीत और ब्रिटेन की हार बदलती दुनिया के बारे में बहुत कुछ कहती है। सचमुच पूरी विश्व व्यवस्था में भारत ने एक अग्रणी भूमिका हासिल कर ली है। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाने की जरूरत है और यह तभी संभव है जब हमारे घरेलू जनप्रतिनिधि या शासक–प्रशासक अपना काम अच्छे से करेंगे।

(224)प्रश्नः कुख्यात आतंकवादी हाफिज सईद की लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा कैद और बढ़ाने से इनकार किए जाने के बाद क्या ऐसा नहीं लगता कि आतंकवाद जिस पाक सरकार की विदेश और रक्षा नीति का अहम

हिस्सा हो, वह दुनिया को दिखाने के लिए भले ही कुछ भी करे, पर अंत में वह आतंकी सरगना को सिर आँखों पर बिठाएगी ही?

उत्तरः हाँ, उपेन्द्र जी, कुख्यात आतंकवादी हाफिज सईद की लाहौर हाईकोर्ट द्वारा उसकी कैद और बढ़ाने से इनकार किए जाने के बाद ऐसा लगता है कि आतंकवाद जिस पाकिस्तान सरकार की विदेश और रक्षा नीति का अहम हिस्सा हो, वह दुनिया को दिखाने के लिए भले ही कुछ भी करे, पर अंत में वह आतंकी सरगना को सिर आँखों पर बिठाएगी ही। साथ ही हमें यह उम्मीद भी ज्यादा नहीं बाँधनी चाहिए कि अमेरिकी दबाव के चलते पाकिस्तान रातों-रात बदल जाएगा और अपने पाले-पोसे आतंकवादियों पर लगाम कसने लगेगा।

यह बात सही है कि पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ माहौल बना है जिससे अंतरराष्ट्रीय दबाव भी कुछ हद तक बनाया जा सकता है, लेकिन इसका असर अभी तक कथनी के स्तर पर ही दिखा है, करनी के स्तर पर नहीं। हाफिज सईद को नजरबंद करना पाकिस्तान की कथनी थी और करनी हम अक्सर देखते रहते हैं। कारण कि हाफिज की नजरबंदी महज दिखावटी थी, पाकिस्तान ने उसके खिलाफ ऐसा कोई मामला नहीं बनाया था जिससे उसे लंबे समय तक कैद रखा जा सके।

जहाँ तक हाफिज सईद को कैद में रहने का सवाल है मैं आपको बताऊँ कि हाफिज सईद अभी तक कैद में न होकर उसे अपने घर पर ही नजरबंद किया गया था। यानी वह उन्हीं सुख-सुविधाओं के बीच था, जिनके बीच वह रहता आया है। पाबंदी बस सिर्फ इतनी ही थी कि वह पूरे पाकिस्तान और कश्मीर में घूमकर सभाएँ नहीं रह सकता था। अपने भाषणों में वैसी आग नहीं उगल सकता था जिसके लिए वह मशहूर है। इसलिए यह नजरबंदी भी सिर्फ दिखावटी ही थी, क्योंकि सरकार ने उसके खिलाफ ऐसा कोई मामला नहीं बनाया था जिससे उसे लंबे समय तक जेल में रखा जा सके। जाहिर है ऐसे में अदालत के सामने उसे बरी करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं रहा होगा। पाकिस्तान सरकार जिसे अदालत का फैसला बता रही है, वह एक तरह से उनकी नीयत की कहानी भी कहता है।

इन सभी बिंदुओं से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इतनी आसानी से हाफिज सईद को सजा देने वाला नहीं है। इसलिए यह ऐसी लड़ाई है, जिसे भारत को हर कदम पर अपने भरोसे से ही लड़ना है।

(225)प्रश्न: क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि जम्मू-कश्मीर के राजौरी-पुंछ सेक्टरों के साथ अन्य क्षेत्रों में पाकिस्तानी गोलाबारी से वहाँ के लोगों का जीना मुहाल हुआ है? आखिर कैसे?

उत्तर: हाँ, मैं भी ऐसा महसूस करता हूँ कि जम्मू-कश्मीर के राजौरी--पूंछ सेक्टरों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी पाकिस्तानी गोलाबारी से वहाँ के लोगों का जीना मुहाल हुआ है, क्योंकि पाक स्थित आतंकवादियों ने सीजफायर के बावजूद पिछले कई सालों से उनकी नींदे खराब कर रखी है और उन्हें घरों से बेघर कर दिया है। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद से सुख-चैन के दिन काटने वाले जम्मू-कश्मीर सीमा के लाखों नागरिकों के लिए स्थिति अब यह है कि उन्हें न दिन का पता है और न रात की खबर है। कब पाकिस्तानी तोपें आग उगलने लगेंगी, कोई नहीं जानता। जिंदगी थम सी गई है उनके लिए। सभी प्रकार के विकास रुक गए हैं। बच्चों का जीवन नष्ट होने लगा है, क्योंकि जिस दिनचर्या में पढ़ाई-लिखाई कामकाज के बतौर शामिल था अब वह बदल गई है और उससे शामिल हो गया है पाकिस्तानी गोलाबारी से बचाव का कार्य।

इतना ही नहीं, पाँच वक्त की नवाज करने वालों की दुआएँ भी बदल गई हैं। पहले जहाँ वह अपनी दुआओं में खुदा से कुछ माँगा करते थे, सुख-चैन और अपनी तरक्की, परन्तु अब उन दुआओं में माँगा जा रहा है कि पाकिस्तानी गोलाबारी से कैसे राहत से दे दी जाए जो बिना किसी उकसावे के तो हैं ही बिना घोषणा के जम्मू-कश्मीर की सीमा पर युद्ध जैसी परिस्थितियाँ बनाए हुए है। सच तो यह है कि पाकिस्तानी तोपों के भय की वजह से वे घरों में नहीं जा पाते तो मौसम उन्हें मजबूर करता है कि वह खतरा बन चुके घरों में लौट आएँ। आगे कुआँ और पीछे खाईवाली स्थिति बन गयी है इन लोगों के लिए।

(226)प्रश्न: क्या आपने कभी सोचा भी था कि हमारी दिनचर्या को प्रभावित करेगी इतनी तेज संचार क्रांति? आखिर कैसे?

उत्तर: हाँ, भाई सुरेश जी, हमने कभी सोचा भी नही था कि इतनी तेज संचार क्रांति हमारी दिनचर्या को प्रभावित करेगी, क्योंकि नई वैज्ञानिक तकनीकें हमें मजबूर कर रही हैं नयी जीवन शैली अपनाने और उसी में जीने के लिए। एक दशक पहले इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले सीमित ही थे, लेकिन आज यही हमारी आवश्यकता हो गया है। आगे आने वाला समय भी हमें नई दुनिया

के क्रियाकलाप की ओर तेजी से ले जाने की कोशिश कर रहा है।

उदाहरण के बतौर अब प्रयोगशालाओं में मांस को तैयार किया जाएगा। यानी पशुओं को पालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार आने वाले समय में वैज्ञानिक उपलब्धि के माध्यम से कार की चालक सीट पर आदमी की आवश्यकता नहीं रहेगी। रत्नों की खुदाई आसमान में होगी और समुद्र के पानी से स्वच्छ ऊर्जा और ईंधन प्राप्त करने की तकनीक को विकसित किया जा रहा है। एक अन्य कार्य होगा कि आने वाले समय में हर व्यक्ति के लिए बैंकिंग जरूरी होगी। इंटरनेट और मोबाइल फोन के जरिए पैसा का लेन-देन होगा। डिजिटल सिस्टम अधिक उपयोग में आएगा। निम्न आय वर्ग के लोग आसानी से छोटे व्यवसाय कर सकेंगे। अभी दुनिया में दो अरब प्रौढ़ लोगों का बैंकों से सीधा वास्ता नहीं है।

ऐसा लगता है कि आने वाला समय पूरी तरह से नई वैज्ञानिक हलचलों के साथ आगे बढ़ेगा। पूराने तौर-तरीके समाप्ति की ओर होंगे। तकनीक पूरी तरह से आम आदमी को चलाएगी। समय की गर्त में बहुत सारी ऐसी संभावनाएँ जन्म ले रही हैं, जो आम आदमी की सोच से बाहर तो हैं, पर समय के साथ उसे उन्हीं तकनीक का दास बनना पड़ेगा।

दरअसल, हमारी आवश्यकताएँ द्रूत गति से विकास की ओर रूख किए हुई हैं, जिनकी भरपाई वैज्ञानिक मस्तिष्क करने के लिए हर समय तैयार है। कहा भी जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। इसलिए पुरानी तकनीकें पीछे छूटती जा रही हैं और नई तकनीक के हम तुरंत गुलाम बनते जा रहे हैं। अब तो हम दूसरे ग्रह को भी अपने रहने योग्य बनाने की फिराक में हैं।

(227) प्रश्नः चाबहार बन्दरगाह के अस्तित्व में आने के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि चीन और पाकिस्तान दोनों को झटका लगा है? आखिर कैसे?

उत्तरः हाँ, भाई मुरारी जी, चाबहार बन्दरगाह के अस्तित्व में आने के बाद मुझे भी ऐसा लगता है कि इससे चीन और पाकिस्तान दोनों को झटका लगा है, क्योंकि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट की वजह से चाबहार पोर्ट भारत के लिए बेहद अहम है। इस पोर्ट को सामरिक दृष्टि से पाकिस्तान और चीन के लिए भारत का करारा जवाब माना जा रहा है। भारत की मदद से ईरान में तैयार चाबहार बन्दरगाह के पहले चरण का ईरान के राष्ट्रपति डॉ. हसन रोहानी ने उद्घाटन किया।

भारत की सफल विदेश नीति और कूटनीति से एक सप्ताह के अन्दर दूसरी बार पाकिस्तान और चीन गठबन्धन को गहरा झटका लगा है, क्योंकि भारत की ताकत बढ़ी है और विश्व को मजबूत संदेश भी गया है। पिछले दिनों भारत ने सिंगापुर से महत्वपूर्ण सामरिक समझौता कर सिंगापुर के चांगी नौसैनिक अड्डे पर भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के रूकने और आवश्यक रक्षा सामग्री के आदान-प्रदान का मार्ग प्रशस्त किया था। इससे दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप का उसे करारा जवाब मिला। इस समुद्री क्षेत्र से लगभग 35 प्रतिशत भारतीय व्यापार होता है। अब भारत ने पाकिस्तान को दरकिनार कर ईरान के रास्ते अफगानिस्तान से जोड़ने वाले चाबहार बन्दरगाह के पहले चरण का परिचालन विगत 3 दिसम्बर, 2017 को औपचारिक रूप से प्रारंभ कर बड़ी सफलता प्राप्त की है। चाबहार बन्दरगाह के माध्यम से भारत पाकिस्तान गए बिना ही अफगानिस्तान और उससे आगे रूस और यूरोप से जुड़ गया। आशा है आने वाले दिनों में इस बन्दरगाह के माध्यम से भारत, ईरान और अफगानिस्तान-इन तीनों देशों की व्यापारिक गतिविधियों को नयी ऊँचाई मिलेगी और तीनों राष्ट्र इससे लाभान्वित होंगे।

चाबहार का शाब्दिक अर्थ है- जहाँ चारों मौसम बसंत के हों। ईरान के सिस्तान-ब्लूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बन्दरगाह की भू-राजनीतिक स्थिति बेहद विशिष्ट है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हर राष्ट्र को अपने हित स्वयं ही साधने होते हैं। इसके लिए सभी राष्ट्र अपनी क्षमताओं के अनुरूप अन्य राष्ट्रों से संबद्धता निर्मित करते हैं। विश्व राजनीति में मित्रता और शत्रुता के भाव स्थाई नहीं होते हैं। स्थाई होते हैं तो सिर्फ राष्ट्रहित। इस वजह से चाबहार बन्दरगाह से हिंद महासागर में भारत की स्थिति मजबूत हुई है।

(228)प्रश्नः जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कूलभूषण जाधव से उनकी माँ और पत्नी की मुलाकात के दौरान माँ और पत्नी के मंगलसूत्र, चूड़ी, बिंदी तक निकलवा लेना क्या यह बेअदबी की इंतिहा नहीं थी? क्या इस अपमान को पूरे हिंदुस्तान का अपमान नहीं कहा जाएगा?

उत्तर: हाँ, जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव से उनकी मां और पत्नी की मुलाक़ात के दौरान उनके मंगलसूत्र, चूड़ी, बिंदी तक निकलवा लेना बेअदबी

की इंतिहा तो थी ही, इस अपमान को पूरे हिंदुस्तान का अपमान कहा जाएगा। आखिर तभी तो पिछले दिनों 28 दिसम्बर, 2017 को भारतीय संसद के दोनों सदनों में पक्ष-विपक्ष ने पाकिस्तान के इस शर्मनाक व्यवहार की निंदा की गई और 'पाकिस्तान शेम शेम' तथा 'पाकिस्तान मुर्दाबाद' के नारे लगे। ऐसा करके सांसदों ने जता दिया कि भले ही राजनीतिक मतभेद हो, लेकिन भारत की किसी महिला का अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत कम ऐसा मौका होता है, जब किसी मुद्दे पर पूरे संसद की एक राय हो।

मेरा ख्याल है कि इस मामले में अब भारत सरकार को पहल करते हुए देश की भावनाओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर ले जाना चाहिए, ताकि आतंक पोषित राष्ट्र पाकिस्तान का एक और घिनौना चेहरा लोगों के सामने आए और दुनिया को यह समझ आए कि कैसे पाकिस्तान जाधव मामले को शुरू से अलग रंग देने में लगा है।

उल्लेख्य की जाधव की माँ मराठी में बात करना चाहती थी, लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी गई और माँ एवं पत्नी की बिंदी, मंगलसूत्र तथा चूड़ी उतरवा कर दोनों सुहागिनों को जाधव के सामने विधवा के रूप में पेश किया गया। भारत के उच्चायुक्त यह नहीं देख सके, क्योंकि जाधव की मां और पत्नी को बिना उच्चायुक्त को बताए पिछले दरवाजे से मुलाकात के लिए ले जाया गया अन्यथा उच्चायुक्त ही ऐतराज जताए होते। पाकिस्तान तो इस बेजा हरकत को मानवीय आधार पर मुलाकात बता रहा है, लेकिन यह न मानवीयता थी और न उदारता। उलटे परिजनों के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया जिसकी पूरा देश निंदा करता है। हालांकि उसके अशिष्ट आचरण पर हैरानी इसलिए नहीं, क्योंकि पाक का इतिहास ऐसी ही नापाक हरकतों और अनगिनत मिसालों से भरा पड़ा है। संभवतः इससे भारत में उस तबके की आँखें भी खुलेंगी जो पाकिस्तान की तमाम नापाक हरकतों के बावजूद उसके साथ बेहतर रिश्तों की हिमायत करता है।

(229)प्रश्न:1617 करोड़ रुपए का आर्थिक मदद रोकने के डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के बाद भले ही पाकिस्तान में हड़कंप हो, लेकिन क्या वह सीनाजोरी से बाज आ रहा है? ऐसा क्यों?

उत्तर: नहीं, आर्थिक मदद रोकने के डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के बाद भले ही पाकिस्तान में हड़कंप हो, लेकिन वह सीनाजोरी से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा अक्सर करता है। आपने देखा नहीं अमेरिका द्वारा

आर्थिक मदद रोकने के बाद पाक के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान की लड़ाई के लिए पाकिस्तान के संसाधनों का इस्तेमाल करता है और उसी की कीमत चुकाता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ट्रंप के नो मोर का कोई महत्व नहीं है और पाकिस्तान इस तानाशाही का नहीं सहेगा। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि अमेरिका फंड को रोके या नहीं, लेकिन पाकिस्तान को इसकी जरूरत नहीं है।

असल में पाकिस्तान का यह बड़बोलापन यूँ ही नहीं है। उसे पूरी उम्मीद है अमेरिका द्वारा किनारे कर दिए जाने के बाद उसे चीन का पूरा सहयोग मिलेगा, क्योंकि चीन हमेशा से आतंकवाद पर भी पाकिस्तान को सहयोग करता रहा है और पाकिस्तान की मदद कर चीन भी अमेरिका को जवाब देना चाहता है। हालांकि यह भी सच है कि अगर पाकिस्तान चीन की शरण में जाता है तो उसके लिए स्थितियाँ और भी खराब हो सकती हैं।

(230)प्रश्न: क्या दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है? क्या 21वीं सदी के इस दशक में हिरोशिमा और नागाशाकी को दोहराया जाएगा?

उत्तर: नए साल 2018 के पहले दिन जिस तरह से उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने जहाँ कहा कि उनके परमाणु बम को लॉन्च करने का बटन उनकी डेस्क पर रहता है, तो वहीं दो दिन बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी डराने वाला ही था। ऐसे में यह जानना आवश्यक होता है कि क्या ऐसा कोई बटन होता है जिसके दबा देने से परमाणु हथियार तबाही मचाना शुरू कर देंगे। वैसे सच कहा जाए तो अमेरिका कभी परमाणु युद्ध नहीं कर पाएगा और ना ही उत्तरी कोरिया के तानाशाह ही परमाणु बम का बटन दबा पाएँगे, क्योंकि दोनों देशों के प्रमुख हिरोशिमा और नागाशाकी के नतीजे से पूर्णत: परिचित हैं। मेरा तो ख्याल यह है कि परमाणु हमले को गोपनीय रखा जाता है। सुरक्षा के लिहाज से उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। भारत भी इन हथियारों के इस्तेमाल में पूर्णत: सक्षम है। परमाणु बम की प्रक्रिया बेहद जटिल है जिसमें सेना के कई अधिकारी शामिल होते हैं और इसके लिए बकायदा युद्ध योजना (War Plan) बनाई जाती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है और न 21वीं सदी के इस दशक में हिरोशिमा और नागाशाकी को दोहराया जाएगा।

♦♦♦

द्वितीय अध्याय

प्रष्टाओं का परिचय

(1)डॉ. एल. एन. शर्मा

जन्म तिथि : 1942

जन्म स्थान : ग्राम+पत्रा.-शम्यागढ़, जिला-पटना

शिक्षा : एम.ए., पीएच.डी., एल.एल.बी.

कार्यक्षेत्र : पूर्व विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र, स्नातकोतर, पटना विश्वविद्यालय, पटना
अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान एसोसियेशन, बिहार

प्रकाशित रचनाएँ : 'द इंडियन प्राइम मिनिस्टर', पौलिटिकल सोसियोलॉजी (अली अशरफ के साथ सहलेखक),'ह्युमन राईट्स एंड राजनीति
समाज शास्त्र: '21वीं शताब्दी के बदलते संदर्भ में'(सह लेखक कृष्ण मुरारी के साथ) 'पौलिटिक्स एंड गुड गवर्नेंस'

अभिरुचि : अध्ययन एवं अकादमिक विचार-विमर्श

वर्तमान पता : ए/32, पिपुल्स कोओपरेटीव सोसाइटी, लोहिया नगर, पटना, दूरभाष-0612-2350140

(२)डॉ. साधु शरण

जन्म स्थान : पटना जिला

शिक्षा : एम.ए.(राजनीति विज्ञान),

कार्यक्षेत्र : पूर्व विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान, जैतपुर महाविद्यालय, बि. आर. अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार

अभिरुचि : अध्ययन, लेखन

वर्तमान पता : गीता भवन, रोड नं.-1, उत्तरी पटेल नगर, पटना

(३)डॉ. मधु वर्मा

शिक्षा : एम. ए. (राजनीति विज्ञान)
कार्यक्षेत्र : पूर्व प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, अरविंद महिला कॉलेज, कदमकुआँ, पटना
अभिरुचि : अध्ययन, लेखन
वर्तमान पता : बी–204, चारमिनार अपार्टमेंट, रोड नं.–12 राजेन्द्र नगर, पटना–16, मो.–9905203796

(४) श्री नरेन्द्रपति तिवारी

जन्मस्थान : बेतिया
शिक्षा : स्नातक
कार्यक्षेत्र : प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय कृषक समाज, बिहार
अभिरुचि : राजनीति,
वर्तमान पता : पाटलीपुत्र कॉलोनी, पटना मो.–7739477925

(5) श्री उपेन्द्रनाथ सागर

जन्मतिथि : 1 अक्टूबर, 1949

जन्मस्थान : भट्ठा बाजार, पूर्णिया-854301
मो.-9931467245, 9162326743

कार्यक्षेत्र : पूर्व सहायक, विधि विभाग, बिहार सरकार
पटना सचिवालय, पटना
पूर्व संस्थापक प्रमुख, अम्बेडकर सेवा सदन, पूर्णिया
संस्थापक सदस्य, कुशवाहा कल्याण परिषद, बिहार, पटना
जनवरी, 1995 में सरकारी सेवा से त्यागपत्र देकर राजनीति में सक्रिय
1995 में बिहार विधानसभा के पूर्णिया क्षेत्र से उम्मीदवार
पूर्व प्रदेश सचिव, जद(यू)
2004 में पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार
2005 में कसबा(पूर्णिया) क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य हेतु राष्ट्रीय लोकदल उम्मीदवार,
बिहार प्रदेश काँग्रेस में शामिल

अभिरुचि : राजनीति एवं समाजसेवा

वर्तमान पता : भट्ठा बाजार, पूर्णिया-854301
मो.-9931467245, 9162326743

(६) श्री विजय कुमार सिंह

जन्मतिथि :

जन्मस्थान :

शिक्षा :

कार्यक्षेत्र : पूर्व प्राध्यापक,
नेता, भारतीय जनता पार्टी, बिहार, पटना

अभिरुचि : राजनीति

वर्तमान पता: यारपुर, पटना

(७) श्री मदन कुमार

जन्मतिथि : 04.04.1976

जन्मस्थान : ग्राम+पत्रा.-नेरूत, थाना-सारे, जिला-नालंदा

शिक्षा : स्नातक (राजनीति शास्त्र)

कार्यक्षेत्र : राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता
प्रोपराइटर, माँ जानकी प्रिंटिंग प्रेस, पटना-2

अभिरुचि : समाजसेवा

वर्तमान पता : न्यू पटना कॉलोनी, बेउर, अनिसाबाद, पटना
मो.-9470629469

(८) श्री शिव बालक प्रसाद

जन्मतिथि : 12 जनवरी, 1953

जन्मस्थान : ग्राम-मिर्जापुर, पत्रा.-बंगपुर,
भाया-परवलपुर, जिला-नालन्दा

शिक्षा : मध्यमा (प्रवेशिकोतीर्ण)

कार्यक्षेत्र : 1977 से सरकारी सेवा, बिहार स्टेट स्मॉल इन्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि., पटना, वर्तमान में दैनिक सेवा के रूप में पदस्थापित।

अभिरुचि : संगीत, नाटक एवं ड्रामा

वर्तमान पता : श्री राम रेसीडेन्सी, निकट साधना होटल, गौड़या मठ के दक्षिण खगौल रोड, पटना
मो.-9504334959

(९) श्री लखन सिंह

जन्मतिथि :

जन्मस्थान :

कार्यक्षेत्र : महासचिव, जिला जनता दल(यू), पटना

अभिरुचि : राजनीति एवं समाजसेवा

वर्तमान पता : मीठापुर बी एरिया, पटना-800001

(१०) श्री मुरारी प्रसाद सिंह

जन्मतिथि: 01.06.1964

जन्मस्थान: पटेल नगर (माधोपुर) पत्रा.-वासुदेव पुर, जिला-मुंगेर, बिहार

शिक्षा: बी.एस.सी.(कृषि) एम.ए., बी.एड. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डवलपमेंट एण्ड पंचायती राज

कार्यक्षेत्र: प्रभारी प्राचार्य, नृपराज राजकीय इण्टर कॉलेज, सरायकेला, सरायकेला-खरझावां, झारखंड

अभिरुचि: अध्ययन तथा कुछ नया करने की ओर अग्रसर

वर्तमान पता: गेस्ट हाउस, वार्ड नं.-9, क्वाटर नं.-सी4/1, सराय केला, पो.+थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला, खरसावाँ, झारखंड-833219

(११)श्री राजवंश सिंह

जन्मतिथि : 04.11.1957

जन्मस्थान : जलालपुर, थाना-करगहर, जिला-रोहतास

शिक्षा : स्नातक, सायंस कॉलेज, पटना
स्नातकोत्तर, जन्तु विज्ञान, कानपुर विश्वविद्यालय

कार्यक्षेत्र : वर्ष 1984 से पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार
वन प्रमंडल पदाधिकारी- देवघर, बिहारशरीफ, सहरसा, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया
वन संरक्षक-गया, भागलपुर, पटना तथा बेतिया में
मुख्य वन संरक्षक सह निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, बिहार

अभिरुचि : पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण तथा साहित्य सेवा

सम्मान : वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बेतिया में व्याघ्र संरक्षण के उत्कृष्ठ कार्य वर्ष 2017 में लोकसभाध्यक्ष द्वारा 'रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड' के 'अर्थ गार्डियन ' एवार्ड से सम्मानित

वर्तमान पता : 402, शिवराधिका कॉम्पलेक्स, शास्त्रिनगर, पटना-800023
मो.-9431082388

(१२) डॉ. शाहिद जमील

जन्म तिथि : 28 फरवरी, 1958 ई.

जन्म स्थान : ग्राम- मोहम्मदपुर बुजुर्ग, पो.- सराय, वैशाली (हाजीपुर)

शिक्षा : एम.ए., पीएच.डी., पटना विश्वविद्यालय

कार्यक्षेत्र : राजभाषा पदाधिकारी, उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार, पटना,

लेखन विधा : कथाकार, पत्रकार, अनुवादक, मंच संचालक

अभिरुचि : मानव-साहित्य सेवा, लेखन, अध्ययन, संवाद, विमर्श

वर्तमान पता : क्वाटर नं- सी/84, बैंक रोड, मस्जिद के निकट, पटना-800001 मो.-9430559161,9931493157

(१३) उमेश्वर प्र. सिंह

जन्म स्थान : बेगुसराय

शिक्षा : स्नातकोत्तर

कार्यक्षेत्र : पूर्व वरीय लेखा परीक्षक, कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना

पूर्व वित्त पदाधिकारी, महावीर कैंसर संस्थान, पटना

अभिरुचि : अध्ययन, लेखन, संगीत

वर्तमान पता : पत्थर रोड, सगुन हॉल के निकट, सरिस्ताबाद, पटना-800001, मो.-09835202663,9334449156

(१४) डॉ. गोपाल शरण सिंह

जन्म स्थान : ग्राम-गोपालबाद, नालन्दा, बिहार

शिक्षा : एम. ए.

कार्यक्षेत्र : समाज सेवा

प्रकाशित रचनाएँ:

अभिरुचि : सामाजिक सेवा एवं साहित्य सृजन

वर्तमान पता : ग्राम+पत्रा.-नालन्दा, जिला-नालन्दा मो.-9709451481

(१५) सुरेश कुमार सिन्हा

जन्म तिथि : 26.12.1948
जन्म स्थान : सीतामढ़ी (बिहार)
शिक्षा : बी.ए., एम.ए.(राजनीति विज्ञान)
एलएलबी, पटना वि.वि.
कार्यक्षेत्र : पूर्व अधिकारी, कार्यालय, महालेखाकार(ले.प.), बिहार, पटना
पूर्व सहायक आयुक्त, भविष्य निधि, कोलकाता
पूर्व सहायक संपादक, 'वाग्वंदना', बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड
अभिरुचि : कला, संगीत, पेन्टिंग, रेखाचित्र, लेखन, खेल एवं अध्ययन
वर्तमान पता : 'घरौंदा' ए-364,ए.जी. कॉलोनी, आशियाना नगर, पटना-25
मो.-9835642504

(१६) डॉ. अमर सिंह वधान

जन्म तिथि : 14 जुलाई, 1947
जन्म स्थान : अमृतसर, पंजाब
शिक्षा : एम.ए. (हिंदी), एम. ए.(अँग्रेजी) तथा
एम.ए.(राजनीति) पीएच.डी, डी.लिट्, पीजीडीसीटी,
सीसीजी
कार्यक्षेत्र : 40 वर्षो तक महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के स्तर पर अध्यापन
प्रकाशित ग्रंथ : मौलिक ग्रंथ-15, संपादित ग्रंथ-15
संप्रति : निदेशक, उच्चतर शिक्षा एवं शोध केंद्र, चंडीगढ़
स्थायी पता : 3150, सेक्टर 24 डी, चंडीगढ़
मो. 9876301085

(१७)प्रो. राज चतुर्वेदी

जन्म स्थान : राजस्थान
शिक्षा : एम.ए.
कार्यक्षेत्र : अध्ययन, अध्यापन
अभिरुचि : शिक्षा एवं संगठन कार्य
स्थायी पता : 'राजहंस',23 चंद्रपथ, सूरजनगर (प.)
जयपुर-6, राजस्थान

(१८) श्री मनोज कुमार

जन्म स्थान : ग्राम-तेलियामय, हिलसा, जिला-नालंदा
शिक्षा : एम. ए.
कार्यक्षेत्र : वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी कार्यालय, महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार वीरचंद पटेल पथ, पटना-1
सदस्य, कार्यकारिणी, पटेल सेवा संघ, बिहार, पटना
संपादक, 'प्रहरी', कार्यालय, महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना
अभिरुचि : पत्रकारिता, समाज सेवा एवं अध्ययन
वर्तमान पता : प्रगतिनगर, सिपारा, पटना

(१९) पल्लवी सिंह चौहान

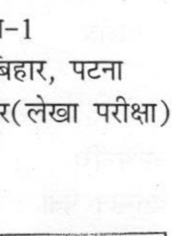

जन्म तिथि : 27 नवम्बर, 1979
जन्म स्थान : बी-39, सोडाना, जयपुर, राजस्थान
शिक्षा : एम.ए.
कार्यक्षेत्र : विकास अधिकारी, वैदिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जयपुर राजस्थान
अभिरुचि : शिक्षा, अध्ययन, समाजसेवा, अध्ययन और सांस्कृतिक सूचिता
वर्तमान पता : बी-39, सोडाना, जयपुर, राजस्थान
मो. 9602922779

(२०) डॉ. कमलानन्द झा 'शास्त्री'

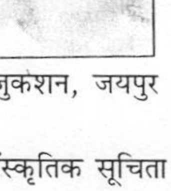

जन्म तिथि : 15.07.1965
जन्म स्थान : ग्राम+पो.-दामोदरपुर, जिला-मधुबनी
शिक्षा : स्नातक, ल.ना. मिथिला वि.वि. दरभंगा
आचार्य(साहित्य), का.सिं.द.सं.वि.वि. दरभंगा
कार्यक्षेत्र : 24 वर्षो तक म.ल.सं.उ. लक्ष्मीपुर आनन्दपुर दरभंगा में आचार्य शिक्षक के पद पर कार्यरत
शिक्षा बोर्ड एवं माध्यमिक बोर्ड, पटना में कार्य का अनुभव
प्रकाशित ग्रंथ : विभिन्न राज्य स्तरीय पत्रिकाओं क्रमशः हिन्दी, मैथिली, संस्कृत में 7 निबंध प्रकाशित एवं 4 प्रकाशाधीन
वर्तमान पता : शास्त्री भवन, बेला चौक, पोस्ट-लालबाग, दरभंगा
मो.-9934849645, 9955247816

प्रधानमंत्री की सूझबूझ और सफल वैदेशिक कूटनीति

प्रस्तुत पुस्तक 'वैश्विक कूटनीति ' के रचयिता सिद्धेश्वर जी की सहजता, उनका खुलापन तथा आत्मीयता ही उनके व्यक्तित्व की विशेषता है जिसका हर कोई कायल है। स्वैच्छिक संस्थाओं तथा उसके आयोजन के प्रति लगाव व समर्पण का भाव जैसा सिद्धेश्वर जी में देखने को मिलता है वह विरले ही किसी ऐसे स्तर के व्यक्ति में होता है। इनके सरीखे बहुआयामी लेखक, जिनके लेख समसामयिक विषयों से लेकर संस्मरण तथा निबंध प्राय: हर पत्र-पत्रिका में सतत पढ़ने को मिलता है। भारतीय राजनीति और वैश्विक कूटनीति पर इनकी पकड़ काफी गहरी है। भारतीय साहित्य के विलक्षण लोकयात्री सिद्धेश्वर जी अपना पूरा जीवन अपनी शर्तो पर जी रहे हैं।

- महेन्द्र प्रसाद सिन्हा

वैश्विक कूटनीति की सफलता पर उत्तरदाता की टिप्पणी अत्यंत मार्मिक और प्रासंगिक

दुश्मन को दोस्त बनाने की कला में माहिर भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विदेश यात्रा के मामले में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को पीछे छोड़ दिया। सोवियत संघ का झुकाव भारत की ओर था तथा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहयोगी अमेरिका था। नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका से ऐसी मित्रता की कि वह पाकिस्तान के विरूद्ध हो गया और उसकी आर्थिक सहायता रोक दी। इसी प्रकार मुस्लिम देशों की नाराजगी के बावजूद मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री को न केवल अपना दोस्त बनाया, बल्कि इजराइल के कई समझौते देशहित में किए। इन सभी घटनाओं का भाई सिद्धेश्वर बड़ी बारिकी से उत्तर देते हुए वैश्विक कूटनीति को सफल बताया है।

- प्रो. (डॉ.) एल. एन. शर्मा

सोचने और कहने की निर्भीकता अद्वितीय

भारतीय समाज के मौजूदा माहौल में व्यावसायिक मानसिकता न रखने वाले सिद्धेश्वर जी का अनिवार्य योगदान साहित्य और उसके जरिए समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए योगदान करना रहा है। वैसे हिंदी साहित्य की कविता, संस्मरण, निबंध आदि विधाओं में तो इनकी अबतक डेढ़ दर्जन पुस्तकें आ चुकी हैं, मगर साक्षात्कार जैसी महत्वपूर्ण विधा में हधर हाल के वर्षो में आई पाँच पुस्तकों में से प्रस्तुत पुस्तक-'इंसानियत की धुँआती आँखें' दूसरी है जिसमें जिज्ञासू विद्वत्‌जनों ने इनसे साक्षात्कार के दौरान सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व आध्यात्मिक, नैतिक, वैचारिक तथा प्राकृतिक विषयों से संबंधित प्रश्न इनके समक्ष उत्तर हेतु प्रस्तुत किए हैं।

- डॉ. साधु शरण

प्रश्नोत्तर में जीवन की उत्कट-तीव्रता और अनुभव की तीव्र-तीक्ष्णता

सिद्धेश्वर जी समाज के प्रबुद्धजनों से लेकर सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं तक के दिलों की धड़कन हैं और आज भी सभा-संगोष्ठियों में मुक्त भावों के साथ सुने जाते हैं, क्योंकि वे उन्हें नेह की डोर से बाँधे हैं। समाज, साहित्य और पत्रकारिता में किया गया इनका योगदान अविस्मरणीय के साथ-ही-साथ प्रतियोगितात्मक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिद्धेश्वर जी अपनी कृतियों में विविध आयामों को दर्शाया है, जिसे पढ़कर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि देश और समाज की दुर्दशा को देखने, परखने और साहित्यिक कृतियों के रूप में पाठकों के समक्ष रखने के लिए इस लेखक के पास एक बहुआयामी और जनोन्मुखी अंर्तदृष्टि है।

- डॉ. लखन लाल सिंह 'आरोही'

लेखक व संपादक

सिद्धेश्वर

प्रकाशक - सरदार पटेल साहित्य प्रकाशन
दिल्ली-92